समाजवादी आन्दोलन में समाजवादी पार्टी की भूमिका

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध - प्रबन्ध

निर्देशक

डॉ० पंकज कुमार

राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शोधकर्ता

सतिराम सिंह यादव

राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद (उ०प्र०)
2002

From the desk of
Dr. Pankaj Kumar
Department of Political Science
Allahabad University
Allahabad

C/o Mr. Krishna Chandra
6, Bank Road, Allahabad-211 002
Ph. : (0532) [redacted]
2641507, 2644073

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि **श्री सतिराम सिंह यादव पुत्र श्री के0 एस0 यादव** शोध छात्र (राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) ने मेरे निर्देशन में अपना शोध-प्रबन्ध पूरा किया है। इनके शोध-प्रबन्ध का विषय **"समाजवादी आन्दोलन में समाजवादी पार्टी की भूमिका"** है। इन्होंने विश्वविद्यालय के शोध नियमों की अर्हता को पूरा करते हुए इलाहाबाद में रहकर अपना शोध-प्रबन्ध पूरा किया है।

मैं डी0 फिल्0 उपाधि हेतु इनके शोध-प्रबन्ध को जमा किये जाने की संस्तुति करता हूँ।

(डा0 पंकज कुमार)
राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

दिनांक : 26-12-2002

विषय सूची

प्रस्तावना

शोधार्थी एक किसान परिवार में पला बढ़ा है, इसलिए वहाँ की संस्कृति, सोच एवं रहन-सहन जेहन में विद्यमान है। शोधार्थी स्कूली शिक्षा भी इसी वातावरण में रहते हुए ग्रहण की है। किसानों की समस्याएं एवं गरीबी को अपने व्यवहारिक जीवन में देखा है एवं महसूस किया है। इसलिए पूरा बचपन ही इसी ग्रामीण परिवेश में बीता है तथा परिवारिक पृष्ठभूमि भी निम्न-मध्यम श्रेणी की है। उसने अपने परिवार से ही समस्याओं से लड़ने, उसका समाधान करने तथा आगे बढ़ने की सीख ली है। शोधार्थी का बचपन शुरु से ही समाजवादी सोच के इर्द गिर्द रहा है। चाहे जाने या अनजाने में, क्योंकि उसकी परिवारिक पृष्ठभूमि भी इसी के इर्द-गिर्द रही है। उसके सोचने, कार्य करने एवं मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के स्तर पर कांग्रेस पार्टी भी समाजवाद की बात करती थी और समाजवादी विचारधारा को सीधे-सीधे आगे बढ़ाने वाले दल भी थे जो जुड़ते-टूटते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे भारतीय राजनीति के केन्द्र में समाजवादी विचारधारा है और बहुतेरे राजनीतिक दल जनता को इसी लुभावने नारे के द्वारा आकर्षित करने का प्रयास करते थे। जागरुक छात्र होने के नाते प्रारम्भ से ही यह जिज्ञासा मन में घर कर गयी कि वास्तव में समाजवाद का दर्शन और विचारा क्या है? सौभाग्य से शोधार्थी का जनपद भी समाजवादी आन्दोलन के विचारधारा का प्रणेता रहा है और इस आन्दोलन के प्रति शायद बचपन से ही आकर्षण ने घर बनाना शुरु कर दिया।

जब उसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो छात्र राजनीति में सक्रिय रहने के कारण सक्रिय वामपंथी, समाजवादी विचारधारा के संगठनों से जुड़ा। राजनीति विज्ञान में शोध छात्र के रुप में पंजीकृत होने से पहले ही उसने अपने शोध-प्रबन्ध को इसी विषय वस्तु पर केन्द्रित करने का निश्चय कर लिया था। सौभाग्य से शोध निर्देशक के रुप में आदरणीय डॉ0 पंकज कुमार का उसे प्रोत्साहन मिला और उन्होंने इस विषय पर हर प्रकार से सहयोग का आश्वासन दिया। यहीं से उसके शोध की औपचारिक शुरुआत शुरु हुई।

इस शोध प्रबन्ध में यह दिखाने की कोशिश की गयी है कि 1977-1990 के बीच भारत में समाजवादी आन्दोलन मृत प्राय हो गया था और समाजवादी विचारधारा के नाम पर अवसर वादियों तथा पिछलग्गुओं की जमात पैदा हो गयी क्योंकि जनता पार्टी के विघटन के बाद चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय लोकदल समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की

किन्तु उनकी मृत्यु के बाद पुनः उसमें फूट पड़ गयी। पुनः लोकदल (अ) तथा लोकदल (ब) बना किन्तु अन्तर्कलह के कारण यह प्रभावशाली नहीं बन पाये और विखर गये। पुनः 11 अक्टूबर 1988 अर्थात जय प्रकाश नारायण के जन्म दिन के अवसर पर जनता दल का निर्माण हुआ। 1989 में केन्द्र में तथा कई प्रान्तों में इसकी सरकार भी बनी लेकिन इसके मूल में कांग्रेसी मानसिकता, अवसरवादिता, पदलोलुपता तथा पिछलग्गुओं की जमात कहीं न कहीं विद्यमान थी। कुछ ही समय बात इसका परिणाम सामने आ गया। इन सारी घटनाओं में सच्चे समाजवादी भी थे लेकिन परिस्थितियों वश उन्हें दमघोटू महौल में समझौता करना पड़ता था। समाजवाद की जो मूल भावना थी उससे उन लोगों ने कभी समझौता नहीं किया। इसी का परिणाम है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी प्रेणता डॉ0 राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चलते हुए इस देश में सच्चे समाजवाद की स्थापना करने के लिए स्वतन्त्र रुप से 4 नवम्बर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन करके साबित कर दिया कि जो समाजवाद की मूल अवधारणा है उसे समाप्त नहीं होने दिया जायेगा चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों? व्यवहार में भी ये बाते साबित हो चकुी हैं।

यह शोध प्रबन्ध विवरणात्मक विश्लेषण, साक्षात्कार तथा तथ्य विश्लेषण पर आधारित है।इतिहास से सम्बन्धित होने के कारण अन्त: विषय उपागम पद्धति का सहारा शोध प्रबंध में लिया गया है।

इस कार्य को पूर्ण करने के लिए शोधार्थी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय लाइब्रेरी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय लाइब्रेरी एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया न्यास, लखनऊ से सहयोग प्राप्त किया है।

आभार

शोध-प्रबन्ध जैसा कठिन, असाध्य और सम्मानित कार्य बिना गुरु के असंभव है। मैंने अपने जीवन में शुरु में यह नहीं सोचा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध कार्य पूरा कर सकूँगा। यह असाध्य कार्य था, लेकिन अपने शोध निर्देशक आदरणीय डा0 पंकज कुमार (राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) के असीम प्रेम, सहयोग एवं प्रेरणा की भावना ने मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा किया जिससे हमने इस कार्य को पूरा किया।शोध निर्देशक की अनुपस्थिति में उनकी धर्म पत्नी आदरणीया डॉ0 अनुराधा कुमार (राजनीति विभाग, इ0 वि0 वि0) ने शोध कार्य हेतु हर प्रकार से सहयोग किया।

अत: मैं दोनो प्रबुद्ध जनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इस महती कार्य के लिए जीवन पर्यन्त ऋणी रहूँगा।

आदरीणय डा0 अलोक पन्त (विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, इ0 वि0 वि0) ने हमेशा मेरे प्रति सहयोगात्मक रुख रखा है। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

राजनीति विज्ञान विभाग, इ0 वि0 वि0 के आदरणीय अध्यायपकों मे, डॉ0 मो0 काजमी, डॉ0 मोहम्मद शाहिद, डॉ0 कृष्णा गुप्ता, डॉ0 असलम डॉ0 वी0 के0 राय, डॉ0 डी0 डी0 कौशिक श्री कार्तिकेय मिश्र तथा श्री अश्विनी दूबे ने मेरे इस शोध कार्य में हमेशा सहयोग एवं प्रोत्साहित करने का कार्य किया। इसलिए हृदय से इन गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूँ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉ0 हर्ष कुमार (प्राचीन इतिहास विभाग), (मनोविज्ञान विभाग, के प्रो0 ए0 के0 दलाल, डा0 योगा नन्द सिन्हा एवं प्रो0 सत्य नारायण, डा0 उमाकान्त यादव (संस्कृत विभाग, इ0 वि0 वि0) तथा सुनील उमराव (पत्रकारिता एवं जनसांचार विभाग, इ0 वि0 वि0,) का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने हर स्तर पर सहयोग किया।

अपने शुभचिन्तकों एवं मित्रों में श्री शालिग्राम यादव, श्री शिवभान यादव,मेरे श्री संग्राम सिंह यादव गुरु भाईयों मे श्री विनोद पाल, श्री सघसेन सिंह, श्री बिजेन्द्र सिंह,श्री प्रमोद मल्ल, सीताराम यादव जी, वीरेन्द्र यादव जी, कौशल किशोर जी, एवं अनिल यादव जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री वासुदेव यादव, (निदेशक, शिक्षा उ0 प्र0 सरकार) का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हर संभव शोध कार्य हेतु सहयोग प्रदान किया।

प्रिय साथी, धर्मेन्द्र यादव जी का मैं विशेष रुप से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने शोध में प्रवेश के समय से ही जल्द से जल्द शोध कार्य पूरा करने के लिए उत्साहित करते रहे तथा हर संभव सहयोग प्रदान किये।

समाजवादी पार्टी उ0 प्र0 के सचिव अदारणीय एस0 आर0 एस0 यादव जी, सांसद श्री अखिलेश यादव जी, सामाजवादी बुलेटिन के संपादक त्रिलोकी नाथ मेहता जी तथा समाजवादी पार्टी उ0 प्र0 कार्यालय एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया न्यास, लखनऊ के सभी कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो शोध-प्रबन्ध हेतु आवश्यक शोध सामग्री उपलब्ध करायी।

अपने पूज्य पिता आदरणीय के0 एस0 यादव जी, माँ आदरणीया बासमती देवी, अग्रज श्री परशुराम यादव एवं भाभी श्रीमती गामा यादव का हृदय से नमन एवं बंदन करता हूँ जिनका हमेशा मुझे स्नेह, प्यार एवं आशीर्वाद मिला। उसी का परिणाम है कि आज इस कठिन कार्य को संभव बना सका।

कंप्यूटर ले-आउट, श्री **गोपेश चन्द्र सोनकर** का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह कार्य संपादित करना संभव नहीं था।

और अंत में एक बार पुनः अपने गुरुजनों मित्रों, शुभचिन्तकों एवं पारिवारिक सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

सतिराम सिंह यादव

(सतिराम सिंह यादव)

शोध छात्र

राजनीति विज्ञान विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

इलाहाबाद

दिनांकः- 25-12-2002

अध्याय—१

विचारधारा के आधार पर समाजवाद का उदय

I - समाजवाद का आशय

समाजवाद की वर्तमान विचारधारा 19वीं शताब्दी में विकसित हुई। सन् 1807 ई0 में रॉबर्ट ओवेन के अनुयायियों के लिए अंग्रेजी भाषा में समाजवादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रान्ति तथा पूंजीवाद ने समाज में इतनी उग्र आर्थिक विषमता पैदा कर दी तथा श्रमिक वर्ग में इतनी अधिक दयनीय दरिद्रता तथा शोचनीय स्थिति पैदा कर दी कि उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद की विचारधारा उत्पन्न हुई। लेकिन इसके कुछ मौलिक विचार जैसे-आर्थिक विषमता का उन्मूलन, पूंजीवादी वर्ग की आलोचना, पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण का विरोध अतिप्राचीन है। इनका सभी कालों तथा सभी देशों में विरोध किया गया है। समाजवाद की विचारधारा भी अपने आप में एक प्रतिक्रियात्मक विचारधारा है। औद्योगिक क्रान्ति के समय में प्रबल होने वाली व्यक्तिवाद की विचारधारा ने इसके प्रादुर्भाव एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीसवीं शताब्दी में विश्व के राजनीतिक और सामाजिक चिन्तन को जिस विचारधारा ने सबसे अधिक प्रभावित किया है, वह समाजवादी विचारधारा है ।[1] वर्तमान में तो समाजवाद एक प्रभावशाली आन्दोलन तथा एक क्रान्तिकारी सिद्धांत के रूप में गतिमान है।[2] लेकिन समाजवाद क्या है? यह स्पष्ट करना एक कठिन कार्य है।[3] इसका कारण यह है कि विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार समाजवाद की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है।[4]अरस्तू से लेकर महात्मा गाँधी तक विचारकों ने समाजवाद के विषय में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये हैं।[5] कुछ विद्वान समाजवाद को

---

1 - पं0 जवाहरलाल नेहरू-विश्व इतिहास की झलक, खण्ड-2, पृष्ठ 760

2 - सी0 ए0 आर0 क्रासलैण्ड- द फ्यूचर आफ सोशलिज्म, द मीनिंग आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 97-117

3 - समाजवाद की जटिलता का उल्लेख शाडवेल निम्नांकित शब्दों में करता है- "मनुष्य के मस्तिष्क को यदि सबसे अधिक किसी प्रश्न ने संक्रमित किया है, तो वह है अनेक रूपी जटिल तथा अस्पष्ट समाजवाद। समाजवाद एक बहुमुखी दैत्य है, जब हम इसके एक सिर को काटने का प्रयत्न करते है, तभी इसका दूसरा सिर निकल आता है"।

4 - वही, पृष्ठ 97-114

5 - फ्रांसिस डब्ल्यू कोकर-रीसेन्ट पोलिटिकल थाट, पृष्ठ 36

व्यक्तिवाद के विरूद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं, कुछ इसे एक राजनीतिक दर्शन मानते हैं, और कुछ के विचार में यह एक महान श्रमिक आन्दोलन हैं, जिसका लक्ष्य श्रमिकों को उनका हक दिलाना है।[6] वास्तविकता यह है कि समाजवादी विचारधारा में आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों में ऐसा समन्वय हो गया हैं कि उन्हें पृथक करना कठिन है। आधुनिक युग में समाजवाद मात्र एक विचारधारा मात्र नहीं है, वरन यह मानव जीवन का एक आदर्श, एक सिद्धांत, एक नीति, एक आस्था और एक जीवन प्रणाली बन गया है।[7]

समाजवाद की परिभाषा-

सी0 ई0 एम0 जोड का विचार है कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है, जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक इसे अपनी इच्छानुसार पहनना चाहता है ।[8] इसकी पुष्टि में रैम्जेम्योर ने भी कहा है कि समाजवाद एक गिरगिट के समान है, जो वातावरण के अनुकूल अपने रंग को बदल लेता है।[9] इस विचारों से स्पष्ट होता है कि समाजवाद की सर्वमान्य परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। जॉन ग्रीफिथ के सर्वेक्षण के अनुसार समाजवाद की 260 से अधिक परिभाषाएं हैं। इलाई ने अपनी पुस्तक में समाजवाद की 400 परिभाषाएं दी है और पेरिस के प्रमुख पत्र "ल फिगारो" के 1891 ई0 के संकलन में 600 परिभाषाएं संकलित की जा चुकी है ।[10] आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जितने विचारकों ने समाजवाद पर विचार किया है, उतनी ही समाजवाद की परिभाषाएं हैं। इसलिए समाजवाद की परिभाषा का प्रश्न अब विवादास्पद विषय बन गया है। इस विषय पर टिप्पणी करते हुए रम्पो पोर्ट नामक विद्वान ने कहा है कि "यदि कोई मुझसे पूछे कि मैं स्वयं समाजवादी हूँ अथवा नहीं, तब मैं उसे

---

6 - सी. ई0 एम. जोड-माडर्न पोलिटिकल थ्योरी- पृष्ठ 3

7 - आर0 ए0 प्रसाद- सोशलिस्ट थाट उन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 5

8 - सी. ई. एम. जोड- माडर्न पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 40

9 - रैम्जेम्योर- लिबरलिज्म एण्ड एन्डस्ट्री, टूवर्डस ए बेटर सोशल अर्डर, अध्याय-1

10 - डब्ल्यू, डी0 पी0 बिलिस- हैण्ड बुक आफ सोशलिज्म (1907), जॉन मार्टिन- एन अटैम्प टू डीफाइन सोशलिज्म-अमेरिकन इकोनामिक एसोसिएशन बुलेटिन, (1911), पृष्ठ 347-359, जान ग्रीफिथ- व्हाट इज सोशलिज्म- (1924), समाजवाद की व्याख्या के आधार पर इसके विभिन्न सम्प्रदायों की गणना की गयी है, जिनमे प्रमुख सम्प्रदाय है- कल्पनावादी समाजवाद, राज्य समाजवाद, इसाई समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फेबियनवाद, संशोधनवाद, श्रेणी समाजवाद,श्रमिक संघवाद,बोल्शेविकवाद आदि । इनके प्रमुख वक्ताओं मे क्रमशः राबर्ट ओवन, सैंट साइमन, स्गोलर बिस्मार्क, किंग्ले गाडरिस, मार्क्स, ऐगेल्स, बर्नाई शॉ, सिडनी वेब, बर्नस्टाइन, कोल, हाब्सन, लेनिन और ट्राट्स्की आदि आते हैं।

ठीक-ठीक उत्तर न देकर स्पष्ट रूप से यह कह दूंगा कि मैं नहीं जानता कि मैं समाजवादी हूँ अथवा नहीं। यह तो उस व्यक्ति की बुद्धि पर आधारित है कि वह समाजवाद का क्या अर्थ लगाता है।[11]

इन मतभेदों के बावजूद भी समाजवाद की कतिपय महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख करना हमारे लिए आवश्यक है, जिनका विवरण निम्नलिखित है --

हूबर्ड ब्लांड[12] "समाजवाद का अर्थ उत्पादन तथा विनिमय के साधनों के समान स्वामित्व से तथा इस प्रकार की व्यवस्था करने से हैं कि सबको समान लाभ हो।"

एमाइल[13] "समाजवाद श्रमिकों का ऐसा संगठन है, जिसका उद्देश्य पूंजीवादी सत्ता में परिवर्तन करने के लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है"।"

हम्फे[14] "समाजवाद एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत जीवन के साधनों पर सम्पूर्ण समाज का स्थायित्व होता है और पूरा समाज सामान्य हित को बढ़ाने के उद्देश्य से उनका विकास और प्रयोग करता है।"

शैफ्ले[15]"समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत तथा खुली प्रतियोगिता के धन को सामूहिक पूंजी में परिवर्तन करना है।"

ह्यूमन[16] "समाजवाद श्रमिक वर्ग का एक आन्दोलन है, जिसका उद्देश्य उत्पादन तथा वितरण के बुनियादी साधनों के सामूहिक स्वामित्व और लोकतांत्रिक प्रबन्ध के द्वारा शोषण का अन्त करना है।"

रैम्जे मैक्डानल्ड[17] - "सामान्य शब्दों में समाजवाद की सर्वोच्च परिभाषा यही है कि इसका उद्देश्य समाज के भौतिक तथा आर्थिक साधनों पर जनता का नियंत्रण है।"जी0 डी0 एच 0 कोल "[18]समाजवाद के अर्थ में चार बातें निहित हैं- समस्त व्यक्तियों का भ्रातृत्व, जिसमें वर्ग भेद का नाम न हो; एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने साथियों से न अधिक धनी हो और न ही अधिक निर्धन, ताकि

---

11 - एच. डब्ल्यू लैडलर-एहिस्ट्री आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 28
12 - डब्ल्यू, डी0 पी0 विलिसन-हैण्ड बुक आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 28
13 - फिगोट एमाइल- उद्धृत-फ्रांसिस, डब्ल्यू कोकर रीसेन्ट -पोलिटिकल थाट एण्ड जान ग्रीफिथ-व्हाट इज सोशलिज्म
14 - हम्फे-उद्धृत-जान ग्रीफिथ-व्हाट इज सोशलिज्म- अध्याय-1, पृष्ठ 34
15 - अल्बर्ट शैफ्ले-उद्धृत-हेनरी डब्ल्यू लैडलर-हिस्ट्रा आफ सोशलिस्ट थाट पृष्ठ 673
16 - लेन्सीलाट हूबन-उद्धृत- हैण्ड बुक आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 30
17 - रैम्जे मैक्डानल्ड- सोशलिज्म एण्ड सोसाइटी, पृष्ठ 13
18 - जी0 डी0 एच0 कोल- सोशल प्योरी, पृष्ठ 7

वे समानता के आधार पर एक दूसरे से मिल सकें, समस्त उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व तथा समस्त नागरिकों को अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार एक दूसरे की सेवा करना है।"

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार-"समाजवाद वह सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य केन्द्रीय जनतान्त्रिक शासन द्वारा एक अच्छी वितरण व्यवस्था और उसके अधीन सम्पत्ति के उत्पादन की अच्छी व्यवस्था करना है।"

अलैक्जेण्डर ग्रे अनुसार-"समाजवाद अधिक से अधिक सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व के उन्मूलन की मांग करता है और चाहता है कि इस प्रकार के हस्तान्तरित सम्पत्ति पर अधिकार और उसका उपयोग पूरे समाज द्वारा किया जाय।"

रॉबर्ट के अनुसार-"समाजवादी कार्यक्रम में वास्तव में एक ही मांग है कि भूमि तथा उत्पादन के अन्य साधन जनता की सामान्य की कम्पनी बना ली जाय।इनके उपयोग एवं प्रबन्धन की व्यवस्था जनता द्वारा जनता के हित के लिए किया जाये।"

बर्ट्रेण्ड रसल के अनुसार- "यदि हम अर्थ, सम्पत्ति और भूमि के सामूहिक स्वामित्व से समाजवाद का अर्थ लें तो हम उसके सारांश के निकट पहुँच जाते है।"

प्रो0 पीगू के अनुसार- "उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार को ही पूंजीवाद और सार्वजनिक अधिकार को समाजवाद कहते हैं।"

रोश्चर के अनुसार-"समाजवादी उन सब प्रवृत्तियों के पक्ष में हैं, जिनमें मनुष्य के व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सार्वजिनक सुख की बात निहित हो।"

प्रो0 ईली के अनुसार- "एक समाजवादी वह है जो कि समाज को एक राजकीय संगठन के रुप में देखता है और जिसका उद्देश्य आर्थिक वस्तुओं का अधिक पूर्ण वितरण तथा मानवता को ऊँचा उठाना है।"

एम.दूगन बोरो विस्की के अनुसार-"समाजवाद की नैतिकता का मौलिक आधार है कि मनुष्य की क्षमता के आदर्श को स्वीकार करना चाहिए।"

पं0 जवाहर नेहरु के अनुसार- "समाजवाद के कई रुप हैं, लेकिन एक बात में सभी सहमत हैं कि इसका उद्देश्य यह है कि उत्पादन के साधनों अर्थात खानों,जमीन, कारखानों आदि पर और रेलों जैसे

साधनों पर और बैंकों जैसी संस्थाओं पर सभी राज्य का प्रभुत्व हो।"[19]

आचार्य नरेन्द्रदेव के अनुसार-"समाजवाद का उद्देश्य एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है, जिसमें न कोई शोषक हो, न शोषित, बल्कि समाज सहकारिता के आधार पर निर्मित व्यक्तियों का एक सामूहिक संगठन हो।"[20]

जय प्रकाश नारायण के अनुसार- "समाजवादी समाज एक ऐसा वर्गरहित समाज होता है, जिसमें सभी समान होते हैं। यह एक ऐसा समाज होता है, जिसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिए मानवश्रम का शोषण नहीं होता, जिसमें समस्त सम्पत्ति वास्तविक रुप में राष्ट्रीय होती है,जिसमें किसी को बिना कुछ किये नहीं मिलता और जिसमें आप की अधिक असमानताएं नहीं होती, तथा जिसमें मानव का संचालन व उसकी उन्नति योजनाबद्ध ढंग से होती है तथा जिसमें सब व्यक्तिगत सबके लिए जीवित रहते है।"[21]

इन परिभाषाओं की समीक्षा करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समाजवाद न केवल एक राजनीतिक दर्शन है वरन् यह एक महान आन्दोलन भी है। यह व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया है। समाजवादी समाज एक ऐसा वर्ग विहीन समाज होता है, जिसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति वास्तविक रुप में राष्ट्रीय सम्पत्ति होती है,जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करने पर ही पारिश्रमिक मिलता है और जिसमें आय की अधिक विषमता नहीं होती है। जिसमें मानव जीवन का संचालन व उसकी प्रगति योजनाबद्ध तरीके से होती है तथा जिसमें सभी व्यक्ति सबके लिए जीवित रहते हैं।

समाजवाद के तत्व-

समाजवादी के सिद्धांत के प्रमख तत्व निम्नवत हैं --

1. समाजवादी समाज वह है जहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का स्वामित्व हो, जहाँ राज्य समाज के प्रतिनिधि के रुप में इन साधनों पर नियंत्रण रखे तथा राज्य केवल व्यवस्था के रुप में स्थित रहे, लेकिन मार्क्सवाद पर आधारित समाजवाद राज्य उन्मूलन के पक्ष में है।

---

19 - पं0 जवाहरलाल नेहरु - विश्व इतिहास की झलक, खण्ड-2, पृष्ठ 761

20 - आचार्य नरेन्द्र देव- राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ 409

21 - जय प्रकाश नारायण- दि फाउन्डेशन ऑफ सोशलिज्म, (1936), बिमला प्रसाद, पृष्ठ 12-13

2. समाजवाद आर्थिक उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण की स्थापना करना चाहता है जिससे इनका उपयोग एक या कुछ व्यक्तियों के हित में नहीं वरन् सम्पूर्ण समाज के हित में है।

3. समाजवादी समाज में आर्थिक प्रगति का अर्थ केवल प्रचुर भौतिक साधन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इनका उपयोग मनुष्य के सुख, विकास, सम्मान और समृद्धि हेतु किया जाय।[22]

4 समाजवादी समाज में राजनीतिक स्वतन्त्रता और आर्थिक स्वतन्त्रता को एक दूसरे का पूरक समझा जाता है। वास्तविकता यह है कि वर्तमान विश्व में समाजवाद से रहित कोई भी वास्तविक लोकतन्त्र नहीं है।[23]

5. समाजवादी समाज में व्यक्ति और समाज के मध्य एक विशेष प्रकार के सम्बन्ध होते हैं। व्यक्ति समाज के आवश्यक यन्त्र के रुप में आर्थिक उपलब्धियों का सामूहिक रुप से उपयोग करता है।[24]

6. समाजवाद का उद्देश्य मनुष्य की भैतिक समस्याओं से मुक्त कराकर उसे वास्तविक स्वतन्त्रता का उपयोग करने और अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का अवसर देना है।[25]

7. समाजवाद का लक्ष्य शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है।[26]

8. समाजवाद जाति-पांति, ऊँच-नीच, वर्ग- भेद आदि में आस्था नहीं रखता है।[27]

2- समाजवादी संकल्पना का अभ्युदय

समाजवादी विचारधारा का विकास क्रम अत्यधिक विस्तृत है।[28] आधुनिक काल में "समाजवाद" शब्द का सर्व प्रथम लिखित प्रयोग इटालियन भाषा में सन् 1803 ई0 में किया गया,

---

22 - आचार्य नरेन्द्र देव- डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन इण्डिया, पृष्ठ 64
23 - वही, पृष्ठ 64
24 - वही, पृष्ठ 62
25 - सी0 ई0 एम0 जोड़- माडर्न पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 49
26 - वही, पृष्ठ 51
27 - आचार्य नरेन्द्र देव-डेमोक्रटिक सोशलिज्म इन इण्डिया, पृष्ठ 62, पृष्ठ 63, राममनोहर लोहिया- विल टू पावर, पृष्ठ 120

28 - फ्रांसिस डब्ल्यू कोकर- रीसेन्ट पोलिटिकल थाट, पृष्ठ 36

तत्पश्चात् सन् 1827 में राबर्ट ओवेन ने सहकारिता के सिद्धांतों के सन्दर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया ।[29] 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में आक्सफोर्ड डिक्शनरी में "समाजवादी" और "सामजवाद" शब्दों को संकलित किया गया। इसी समय अलैक्जेण्डर जैक्स ने अपनी पुस्तक में "समाजवाद", साम्यवाद, समूहवाद आदि शब्दों का प्रयोग किया ।[30] इसके बाद विश्व के कुछ देशों में "समाजवाद" निरन्तर लोकप्रिय होता गया।

<u>पाश्चात्य राजदर्शन में समाजवादी चिन्तन</u>

पाश्चात्य राजदर्शन में समाजवाद के उद्गम की कल्पना प्लेटो के यूनानी राजदर्शन में की गयी थी ।[31] कई राजनीतिक विशारदों ने प्लेटो के "रिपब्लिक" में समाजवाद के कुछ तत्वों का समावेश पाया है ।[32] लेकिन प्लेटो ने जिस साम्यवादी धारण का प्रतिपादन किया था, वह सम्पत्ति के सामूहिक वितरण पर आधारित न होकर शासकों तथा सैनिकों तक ही सीमित थी । अतः प्लेटों का साम्यवाद वर्तमान समाजवाद से भिन्न प्रतीत होता है ।[33] लैडलर, प्लेटो के सिद्धान्त को "अभिजात साम्यवाद" की संज्ञा देता है ।[34] स्टोइक दर्शन में प्लेटो के समान ही एक आध्यात्मिक समाजवाद की कल्पना मिलती है ।स्टोइक के अनुसार विश्व नागरिकता का अधिकार सभी व्यक्तियों को है और संसार का जीवन चक्र समानता व कल्याण की भावना से संचालित होता है ।

कुछ इटेलियन विचारकों के ग्रन्थों में समाजवाद विषयक आंशिक भाव उपलब्ध होते है।[35] मध्ययुगीन ईसाई लेखकों की कृतियों में, जिन आर्थिक विचारों का प्रतिपादन किया गया

---

29 - वही, पृष्ठ 36, फुट नोट 2, सन् 1833 में "पुअर मैन गार्जियन" नामक पत्र में भी समाजवाद शब्द प्रयुक्त किया गया था ।

30 - वही पृष्ठ 36, फुट नोट 2 व 3

31 - दि रिपब्लिक आफ प्लेटो (अनुवाद-कार्नफोर्ड), पृष्ठ 106

32 - दि रिपब्लिक आफ प्लेटो (डेवीज), पृष्ठ 125, प्लेटो की रिपब्लिक, पृष्ठ 107-108, ज़ी0 डी0 एच0 कोल-सोशलिस्ट थाट, जिल्द-1, पृष्ट 2, अलैक्जेण्डर ग्रे-दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 3, बार्कर- ग्रीक पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 61, डनिंग- हिस्ट्री आफ पोलिटिकल थ्योरीज, पृष्ठ 88

33 - मैक्सी- पोलिटिकल फिलासफीज, पृष्ठ 55, बार्कर-ग्रीक पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 213, टेलर-प्लेटो, पृष्ठ 226

34 - दि रिपब्लिक आफ प्लेटो (डेवीज), पृष्ठ 28, कोकर-रीसेन्ट पोलिटिकल थाट पृष्ठ 36

35 - हैरी डब्ल्यू लैडलर-हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट, पृष्ठ 14

है, उनमें समाजवादी विचारों की झलक मिलती है ।[36] आधुनिक समाजवादी लेखकों का मत है कि समाजवादी विचारधारा का विकास 1789 ई0 की फ्रांसीसी राज्य क्रान्ति के समय से हुआ था ।[37]

राज्य क्रान्ति से पूर्व फ्रांस की राजनीतिक ,आर्थिक और सामाजिक दशा अत्यधिक शोचनीय थी और जन साधारण में राजतन्त्र के विरुद्ध घोर असन्तोष व्याप्त था। इस असन्तोष का विस्फोट 5 मई 1789 ई0 को हुआ, इनमें निम्न विचारों की स्थापना की गयी। उनका प्रभाव न केवल फ्रान्स वरन सम्पूर्ण यूरोप में स्थापित परम्परागत व्यवस्था पर पड़ा। फ्रांस के क्रान्तिकारियों द्वारा उद्‌घोषित "स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व" के नारे से समाजवादी चिन्तकों को बड़ी प्रेरणा मिली। इसके साथ ही 1775 ई0 की अमेरिकी क्रान्ति और इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति ने भी समाजवादी चिन्तन को एक नयी दिशा प्रदान की।

19वीं शताब्दी में समाजवादी विचारधारा के विकास के कारण-

18वीं शताब्दी तक समाजवादी आन्दोलन प्रभावशाली न बन सका, किन्तु 19वीं शताब्दी से इस आन्दोलन में तीव्रता और प्रखरता आने लगी। उसका मूल कारण औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न होने वाली विशेष परिस्थितियाँ थी। उसने कई कारणों से उस आन्दोलन को प्रोत्साहित किया ।[38]

1. उसने समाज में स्पष्ट रुप से कारखानों में, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वाले पूंजीपति वर्ग को उत्पन्न किया । मध्यकाल से चली आने वाली गिल्ड व्यवस्था (Guild system) को उस पूंजीवादी व्यवस्था ने समाप्त कर दिया था । मध्य युगीन श्रमिक वर्ग का उत्पादन के साधनों पर श्रम के अलावा भी आधिपत्य था, किन्तु अब मशीनों द्वारा उत्पादन के होने के कारण श्रमिक उत्पादन के साधनों से वंचित हो गया । वह केवल मशीनों को अपने हाथ से चलाने वाला सामान्य मजदूर बन गया । यह श्रमिक पहले के श्रमिकों से भिन्न था । एक साथ कार्य करने के कारण एकता की भावना

---

36 - इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, जिल्द 18, इंग्लैण्ड के क्रान्तिकारी प्रोटेस्टेण्ट विचारक जान बाइक्लिफ ने भी समानता और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया इन्हें "राजतन्त्रवादी साम्यवादी" की उपाधि दी गयी है, लैडलर-ए हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट, पृष्ठ 23

37 - जी0 डी0 एच0 कोल-सोशलिस्ट थाट, दि फारनर्स, पृष्ठ 11, डनिंग- दि हिस्ट्री आफ पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 398, भगवान दास- ऐन्सीएन्ट वर्सेज माडर्न साइन्सटिफिक सोशलिज्म (1934),पृष्ठ 13, अलैक्जेण्डर ग्रे-दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन (1946), पृष्ठ 28

38 - थामस किरकप- हिस्ट्री आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 20

का विकास होने लगा । अपनी श्रेणी के कष्टों को दूर करने की,उसके लिए पूंजीपतियों के प्रति रोष प्रकट करने की तथा अपनी शिकायतें दूर करने के लिए संघ बनाने की प्रवृत्तियों उत्पन्न होने लगी।

2. उससे संबंधित दूसरा कारण पूंजीवाद का उत्कर्ष था । औद्योगिक क्रान्ति के विकास एवं प्रगति के साथ-साथ मशीनीकरण के विकास की संभावनाएं भी बढ़ने लगी तथा दूसरी ओर उद्योगों का विकास होने से श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने लगी । उन सब कारणों ने पूंजीवाद के विकास में काफी योगदान दिया । श्रमिक वर्ग में उस पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति विरोध की भावना विकसित होने लगी ।

3. जैसे-जैसे उद्योगों में अधिक पूंजी लगायी जाने लगी वैसे-वैसे उद्योगों का स्वामित्व भी अल्प पूँजीवादियों के हाथों में जाने लगा। यह पूँजीपति वर्ग अपने स्वार्थ तथा हितों की दृष्टि से उद्योगों का संचालन तथा स्वार्थो को प्राथमिकता देने लेगे।पूंजीपतियों द्वारा मजदूर वर्ग के हितों की उपेक्षा की जाने लगी। उससे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से समाजवादी आन्दोलन को प्रेरणा मिली, उन्हें यह विश्वास होने लगा कि पूँजीपति वर्ग अपने स्वार्थो तथा हितों को कभी नहीं छोडेंगे उत्पादन के साधन उनसे बल पूर्वक छीनकर समाज के स्वामित्व और प्रभुत्व में लाये जाने चाहिए।

औद्योगिक क्रान्ति से ये परिस्थितियाँ सर्वप्रथम पश्चिमी यूरोप के देशों-फ्रांस और इंग्लैण्ड के देशों में उत्पन्न हुई, अतः समाजवादी विचारों का विकास भी सर्वप्रथम उन्हीं देशों में हुआ। समाजवादी विचारधारा के विकास में सबसे अधिक योगदान व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रतिक्रियात्मक शक्ति थी । औद्योगिक क्रान्ति के साथ एक नवीन विचारधारा का विकास होने लगा था। व्यक्तिवाद की विचारधारा औद्योगिक क्रान्ति की देन थी ।इंग्लैण्ड में बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति के अधिकारों का उग्र समर्थन किया। जे0 एस0 मिल बेन्थम से भी आगे गये, वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के इतने उग्र समर्थक थे कि वे उसमें किसी प्रकार के अवरोध को अमान्य ठहराते थे तथा हर्बर्ट स्पेन्सर ने योग्यतम की विजय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्ति को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हुए राज्य "समाज" के कार्यक्षेत्र को अत्यधिक सीमित और संकुचित कर दिया। इस व्यक्तिवाद की विचारधारा के विपरीत बुद्धिजीवी वर्ग में एक प्रतिक्रिया हुई, इस प्रतिक्रिया के

फलस्वरुप एक नवीन विचारधारा का विकास होने लगा, जिसने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व दिया तथा समाज अथवा राज्य को व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना।

वर्तमान समय में समाजवाद का केन्द्र बिन्दु रुस को माना जाता है। परन्तु समाजवादी विचारधारा का विकास सर्वप्रथम फ्रांस और इंग्लैण्ड में हुआ। इस विचारधारा के वैज्ञानिक स्वर देने का श्रेय जर्मनी के विचारकों को है। 19वीं शताब्दी के समाजवादी विचारधारा को विकास को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है- कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती विचारक तथा उसके बाद के विचारक।कार्ल मार्क्स ने अपने से पूर्व के विचारकों को कल्पनावादी विचारक की संज्ञा दी थी, क्योंकि उन्होंने उसे स्थापित करने के लिए कोई व्यवहारिक योजनाएं प्रस्तुत नहीं की थी। सर्वप्रथम समाजवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव एवं विकास फ्रांस में हुआ, उसके बाद इग्लैण्ड में, क्योंकि उन्हीं देशों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ ही विषमताओं से परिपूर्ण थीं।

3-कल्पनावादी समाजवाद-

टामस मूर (1478-1535ई0)-फ्रांस की राज्य क्रान्ति से पूर्व ही 16वीं शताब्दी में सर टामस मूर ने इंग्लैण्ड की दुर्दशा से दुःखी होकर 1616 ई0 में प्रकाशित 'यूटोपिया' नामक ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ में समाजवाद के अनेक तत्वों का उल्लेख मिलता है, विशेष रुप से इस ग्रन्थ का दूसरा भाग टामस मूर के समाजवादी चिन्तन पर प्रकाश डालता है, जिसमें उसने तत्कालीन निरंकुश राजतन्त्र और सामन्तशाही की कटु आलोचना की है एवं एक ऐसे काल्पनिक समाज का चित्रण किया है- जिसे हम वर्ग विहीन और विशेषाधिकार हीन समाज की संज्ञा दे सकते है।[39]टामस मूर को आधुनिक राजदर्शन के इतिहास में कल्पनावादी समाजवादा का जनक माना जाता है। टामस मूर के बाद फ्रांसिस बेकन ने उसके समाजवादी विचारों को वैज्ञानिक रुप प्रदान किया। बेकन ने अपने न्यू एटलाटिंस में एक ऐसे द्वीप का वर्णन किया, जिसमें वैज्ञानिक साधनों को समानता, स्वतन्त्रता एवं बन्धुत्व युक्त जीवन के निर्माण में प्रयोग किया गया था। इसी समय जर्मन यात्री एण्ड्रियास ने "क्रिश्चियन नोपोलिस" में तथा इटली के "मान्क कैम्पानेला" ने अपने "सिटी आफ दि सन" में काल्पनिक साम्यवाद का उल्लेख किया।17वीं शताब्दी में जॉन लाक और डिमर्स ने भी कल्पनावादी

---

39 - अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 61-62

समाजवाद का पक्ष पोषण किया।18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मेबल (1709-1785ई0) ने अपने समानता और सम्पत्ति संबंधी विचारों में समाजवाद को एक दिशा प्रदान की।[40]

4-फ्रांस के कल्पनावादी समाजवादी विचारक

फ्रांस में सर्वप्रथम समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ। इसका कारण फ्रांस की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ थी। फ्रांस की अपेक्षा अन्य यूरोपीय देशों में सामाजिक विषमता उतनी उग्र नहीं थी जितनी फ्रांस में। फ्रांस के सर्वप्रथम समाजवादी विचारक नोयल वावेफ थे। उनके समय की मजदूरों की स्थिति का वर्णन थामसन किरकुप ने बहुत स्पष्ट शब्दों में किया है। किन्सले, जो उस समय के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे, उस समय की सामाजिक दशा तथा श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है।[41]

फ्रांसिस नायल वावेफ-(1764-1797 ई0)

फ्रांसिस नायल वावेफ फ्रांस की क्रान्ति के समय हुए थे। उस क्रान्ति ने सब मनुष्यों के समान होने की घोषणा की थी, किन्तु फ्रांस के समाजवादी विचारक यह मानते हैं कि सभी मनुष्यों को राजनीतिक समता के साथ-साथ आर्थिक समता भी मिलनी चाहिए। उसमें वावेफ को प्राचीन तथा अर्वाचीन समाजवाद का विभाजक और आधुनिक साम्यवाद का निर्माता कहा जाता है। रोवेस्पियर के पतन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि क्रान्ति का सबसे अधिक लाभ निजी भूमि रखने वालों को हुआ है, साधारण जनता को उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। सन् 1790 ई0 में उसने लिखा था कि-"जब मैं देखता हूँ कि गरीबों के शरीर पर न कपड़े है और न पैरों में जूते, गरीब लोग ही कपड़े और जूते बनाते हैं, पर उन्हें ही वे इस्तेमाल के लिए नहीं मिलते; और जब मैं उन लोगों का विचार करता हूँ, जो स्वयं भी कुछ कार्य नहीं करते, पर जिनके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं है तो मेरा यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि राज्य भी जन साधारण के विरुद्ध कुछ लोगों का षड़यन्त्र है।" वह समाज में आर्थिक विषमता का अन्त करके समानता स्थापित करना चाहता था। उसका विश्वास था कि निजी सम्पत्ति

---

40 - अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 87-90

41 - थामसन किरकुप-हिस्ट्री आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 23

गृह युद्ध और विषमता को उत्पन्न करती है, अतः उसका उन्मूलन होना चाहिए। उसका यह प्रस्ताव था कि मृत व्यक्तियों की सम्पत्ति पर राज्य अधिकार कर ले और इस प्रकार पचास वर्ष में राज्य ही सब प्रकार की सम्पत्ति का स्वामी बन जायेगा। उसके विचार में सब व्यक्तियों से समान रुप से काम लेना चाहिए, कार्य का समय कानून द्वारा निश्चित होना चाहिए। उसने उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार सम्पत्ति के वितरण पर बल दिया।

वावेफ से पूर्व समाजवादियों ने केवल एक नवीन समाज की कल्पनाएं की थी, किन्तु इसकी यह विशेषता थी कि इसने उसकी उपयुक्त योजना बनाने के साथ-साथ उसे व्यावहारिक रुप देने के लिए भी क्रान्तिकारी पद्धति का विकास किया। इस विषय में ऐसे तरीकों का प्रतिपादन किया, जिनका अनुसरण समाजवादी दल आज तक कर रहे हैं। इसने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए समानता चाहने वाले व्यक्तियों का षड़यंन्त्र (Conspiracy of equals) किया। इसने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए सर्वप्रथम कम्यूनिस्ट पत्र "दि ट्रिव्यून आफ द पीपुल" की स्थापना की। सेना की पुलिस में अपने समर्थकों के गुप्त गुटों का निर्माण किया, तथा बलपूर्वक सत्ता हथियाने की योजना बनायी। वावेफ का विचार था कि पूंजीपति वर्ग कभी भी स्वेच्छापूर्वक अपनी शक्ति नहीं छोड़ेंगे, उसे उनसे जबरदस्ती छीनना पड़ेगा। उसका विचार था कि एक बार विद्रोह करने से कम्यूनिस्ट लोकतंत्र की स्थापना होने तक एक अधिनायक तन्त्र की स्थापना करना आवश्यक है। किन्तु वावेफ की योजना सफल नहीं हुई। सन् 1796 ई0 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और अगले वर्ष उसे मौत की सजा दी गयी। किन्तु उसकी योजना और विचारों का भावी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। नार्मन मैकेन्जी के शब्दों में किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा उसने लेनिन का तथा सन् 1917 ई0 की बोल्शेविक क्रान्ति का अधिक मात्रा में पथ-प्रदर्शन किया।[42] वह पहला महत्वपूर्ण समाजवादी था जिसने यह घोषणा की थी कि बड़ी सावधानी पूर्वक तथा योजना के साथ की जानी वाली सैनिक कार्यवाही की भाँति सम्पन्न होने वाली क्रान्ति द्वारा ही श्रमिक वर्ग राजनैतिक सत्ता हस्तगत कर सकता है।[43]

---

42 - नारमन मैकेन्जी-सोशलिज्म, पृष्ठ 20

43 - एच0 डब्ल्यू0 लैडलर,-इकोनामिक सोशल मूवमेन्ट, पृष्ठ 58

<u>सेंट साइमन (1760-1825) ई0</u>

सेंट साइमन सम्भवतः प्रथम व्यक्ति था, जिसने औद्योगिक सभ्यता के महत्व को समझा और उसने नये युग को "संगठन के युग" की संज्ञा दी ।[44]उसका पूरा नाम "Claude-Henry de Rouvroy, saint simon" था। वह 1760 ई0 में फ्रांस के एक सामन्तवादी परिवार में उत्पन्न हुआ था। उसका जीवन बड़ा रोमांचकारी था । वह फ्रांस की राज्य क्रान्ति का समर्थक था, और निरंकुश राजतन्त्र, दूषित आर्थिक तन्त्र और भ्रष्ट समाज में अमूल चूल परिवर्तन करना चाहता था ।[45] साइमन को इस बात का गहरा विश्वास हो चुका था कि समाज के संगठन और निर्देशन में बौधिक तत्व की प्रधानता होनी आवश्यक है।उसकी यह मान्यता थी कि समाज का नियन्त्रण कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हाथों में है, उन्हें समाज में विशेषाधिकार प्राप्त है और वे जीवन का पूर्ण आनन्द उठातें है, दूसरी ओर कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो दिन रात कठिन परिश्रम करते है, फिर भी उन्हें दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं ।[46]

साइमन समाज की इस विषमता को मिटाकर एक नवीन समाज की स्थापना करना चाहता था। वह विज्ञान की सहायता से जन साधारण का हित करना चाहता था।[47] वह समाज का नियन्त्रण वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों तथा टेक्नीशियनों के हाथों में रखने का पक्षपाती था। लेकिन साइमन सम्पत्ति के समाजीकरण के पक्ष में नहीं था । उसका मत था कि सम्पत्ति से जन साधारण का हित होना चाहिए और धन के उत्पादन में प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुसार ही पारितोषिक प्राप्त होना चाहिए । साइमन की जन हितकारी भावना से स्पष्ट होता है कि वह लोकतन्त्र की स्थापना में विश्वास रखता था परन्तु वास्तव में वह लोकतन्त्रवादी न ही था और नही वह जन साधारण के हाथों में शासन सत्ता देने के पक्ष में था ।[48] साइमन की यह धारणा थी कि यदि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को समाज का नेतृत्व दे दिया जायेगा तो ट्रस्टी के रुप में अपने कार्यो को सम्पादित करेंगे । वे जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाकर निम्न स्तर के लोगों में पर्याप्त सुधार ला देंगे । इसके परिणाम

---

44 - अशोक मेहता- डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ 18 मैक्सी-पोलिटिकल फिलासफीज, पृष्ठ-543-44

45 - हैरी डब्ल्यू लैडलर-हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट- (1927), अध्याय 14, थामस किरकप-हिस्ट्री आफ सोशलिज्म-(1913),अध्याय 5

46 - अलैक्जेण्डर ग्रे-दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 152

47 - अशोक मेहता-स्टडीज इन सोशलिज्म, पृष्ठ 19-20

48 - इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज-पृष्ठ 507-508

स्वरुप उत्पादन में वृद्धि होगी तथा समाज की विषमता का धीरे-धीरे अन्त हो जायेगा और श्रमिक तथा उद्योगपतियों के मध्य किसी संघर्ष की संभावना तक न रहेगी ।

सेंट साइमन के मूल सिद्धान्तों में समाजवाद के तत्व बहुत कम हैं उसने अपने समय में कई समाजवादी केन्द्र स्थापित किये उसके अनुकरण कर्ताओं ने संघों के माध्यम से उसके विचारों का प्रचार कार्य प्रारम्भ किया तथा फ्रांस में वह प्रबल समाजवादी विचारक समझा जाने लगा । इस रुप में परवर्ती विचारकों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा ।मैक्सी ने लिखा है कि-"जर्मनी में उसने विस्मार्क तथा कार्ल मार्क्स को प्रेरणा प्रदान की, फ्रांस में अगन्तलोन्टे तथा लुई ब्लांक का सैद्धांतिक गुरु था, इंग्लैण्ड में राबर्ट ओवेन तथा अन्य समाजवादी विचारकों को प्रभावित किया । सेंट साइमन ने प्रथम बार विज्ञान का औद्योगिक उन्नति के साथ अर्न्तसम्बन्ध बताते हुए ऐतिहासिक विकास की उस पद्धति की ओर संकेत किया जिसके आधार पर विभिन्न समयों (कालों) के मनुष्य-समाज की प्रगति की व्याख्या की जा सकती हैं । इस प्रकार इतिहास की आर्थिक व्याख्या में वह कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का पूर्ववर्ती है।[49]

<u>चार्ल्स फोरियर-(1772-1837 ई0)</u>

चार्ल्स फोरियर की गणना कल्पनावादी समाजवाद के आधार स्तम्भों में की जाती है। साइमन के समान वह भी एक फ्रांसीसी विचारक था । वह साइमन का अनुयायी था, तथापि साइमन के कुछ विचारों से वह असहमत था । फोरियर बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे उद्योगों की स्थापना को उपयुक्त समझता था ।[50] वह उत्पादन में अपव्यय तथा प्रतिस्पर्धा का विरोधी था ।वह एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता था, जो तत्कालीन दोषों से रहित हो ।

फोरियर के अनुसार नवीन समाज में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता मिलेगी । इस नवीन समाज में सबसे छोटी इकाई एक व्यावसायिक समूह होगी इस समूह में सात सदस्य होंगे जिनकी रुचियां और हित समान होंगे ।पांच या कुछ अधिक समूह मिलकर एक सीरीज बनायेंगे और

---

49 - थामस किरकप- हिस्ट्री आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 28

50 - अशोक मेहता- डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ 19, मैक्सी- पोलिटीकल फिलासफी, पृष्ठ 520-21

पच्चीस सीरीजों से मिलकर एक फ्लैक्स का निर्माण होगा जो नवीन समाज की सबसे बड़ी इकाई होगी ।[51]

प्रत्येक फ्लैक्स में श्रमजीवी, उद्योगपति, डाक्टर, इन्जिनियर आदि विभिन्न पेशों के लोग सम्मिलित होंगें । फ्लैक्स के सभी सदस्य आन्तरिक सहायता तथा सहयोग के द्वारा एक आत्मनिर्भर इकाई का निर्माण करेंगे। इसके प्रमुख तीन धन्धे- कृषि, पशुपालन तथा भोजन निर्माण होंगे । फोरियर के अनुसार नवीन समाज में लोग निजी सम्पत्ति रख सकेंगे और सम्पत्ति का उत्तराधिकार भी वंशानुगत रहेगा । फ्लैक्स के संगठन से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो जायेगी । स्त्री और पुरुषों के एक साथ करने से एक उच्चतम श्रम विभाजन सम्भव हो सकेगा ।

लुई ब्लांक-(1713 ई0)

लुई ब्लांक पहला विचारक था जिसने समाजवादी विचारों को राज्य की सहायता से क्रियात्मक रुप देने का विचार रखा था । लुई ब्लांक की पुस्तक "परिश्रम का संगठन" सन् 1839 में प्रकाशित हुई । उसने फ्रांस के सर्वहारा वर्ग में चेतना का संचार किया । वह पहला विचारक था जिसने मजदूर किसानों को अपने कल्याण के लिए राजनीतिक सत्ता हाथ में लेने का सुझाव रखा । उसका प्रथम सिद्धांत था कि हमारे सामाजिक प्रयत्नों का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति तथा उसका विकास होना चाहिए । विकास का अभिप्राय यह है कि मानव के पास अपनी उच्चतम मानसिकता, नैतिक और शारीरिक प्रगति करने के लिए तथा उत्तम व्यक्ति का निर्माण करने के लिए उपयुक्त साधन होने चाहिए ।लुई ब्लांक के विचारों का आदर्श एक औद्योगिक सरकार थी, जो कि राष्ट्र के औद्योगिक यन्त्र का प्रबन्ध करे। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक कारखानों (सोशल वर्कशाप)का विचार रखा । आदर्श समाज बनाने के लिए प्रत्येक सदस्य को कार्य देना आवश्यक है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य को सामाजिक उद्योगों का निर्माण करना चाहिए। प्रारम्भिक अवस्था में यह व्यक्तिगत अधिकार में होंगे, तथा शनैः -शनैः समाज के अधिकार में आ जायेगे । राज्य को उसका संचालन सार्वजनिक तथा सामान्य हित की दृष्टि से करना होगा । इस प्रयत्न से धीरे-धीरे समाजवादी समाज की स्थापना से और समाज अग्रसर होगा । इन सभी कार्यो को प्रजातन्त्र

---

51 - सेलेक्शन्स फ्रांम दि वर्क्स आफ फोरियर- सोशल साइन्स सीरीज, खण्ड 3 व 6

के आधार पर करना होगा ।समाजवादी समाज में इन उद्योगों में प्रबन्ध और परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को यह अधिकार होना चाहिए कि अपने-अपने व्यवसाय के प्रबन्ध का चुनाव कर सकें । तथा अपने व्यवसाय में होने वाले लाभ को परस्पर सहयोग के आधार पर विभाजित करें एवं उद्योगों के विकास का प्रयत्न करें ।

लुई ब्लांक उत्पादन पर व्यक्तिगत अधिकार को समाज के लिए हितकर नहीं समझता था । सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण तथा सामाजिक अधिकार में लाने का सर्वप्रथम विचार ब्लांक ने रखा था। सरकार को और उद्योगों की स्थापना स्वयं की करना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत उद्योग स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे ।

ब्लांक ने एक अन्य सिद्धांत समाज के सामने रखा । प्रत्येक को अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार समाज की सेवा करनी चाहिए तथा उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाज की सेवा करनी चाहिए तथा उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समाज से प्रतिफल मिलना चाहिए । शक्ति और ज्ञान का मानवहित की दृष्टि से पूर्ण सदुपयोग किया जाना आवश्यक है । ब्लांक से पूर्ववर्ती विचारक व्यक्ति से उसकी योग्यतानुसार कार्य लेने में एक मत थे । परन्तु पारिश्रमिक देने में भिन्न मत रखते थे । सेंट साइमन के अनुयायी यह मानते थे कि व्यक्ति का वेतन काम के अनुसार होना चाहिए । फोरियर ने उसके बारह हिस्से करके उन्हें पूंजीपति, मजदूर और कुशल श्रमिकों में विभिन्न अनुपात में बाँटा था । ब्लांक ने उन दोनों मतों को न मानते हुए इस मत को प्रतिपादित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को वेतन उसके आवश्यकतानुसार दिया जाना चाहिए ताकि वह अपनी शक्ति और गुणों का विकास कर सके । ब्लांक ने ही समाजवाद के प्रसिद्ध सिद्धांत को जन्म दिया कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लिया जाना चाहिएं, और उसकी आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए । "From each according to his ability, to each according to his needs".

फ्रांस की क्रान्ति से (सन् 1789 ई0) सत्ता हस्तान्तरण जनता के हाथ में नहीं आयी । राजसत्ता सामन्त शाही के हाथों से निकलकर उच्च मध्यम वर्ग के हाथों में चली गयी । उसके बाद भी फ्रांस में क्रान्ति के अनेकों प्रयास हुए उन क्रान्तिकारियों ने प्रजातन्त्र और समाजवाद के क्षेत्र में विशेष

योगदान दिया। ब्लांक के प्रभाव के कारण उसकी समकालीन सरकार ने, जिसका वह भी एक सदस्य था, सम्पत्ति के समाजीकरण के अनेक प्रयास किये, जो पूर्णतया सफल नहीं हो पाये।

पी0 जे00 प्राउधों (P.S.Proudhon)-(1809-1865 ई0)

यह फ्रांस के सभी समाजवादियों में सबसे उग्र विचारक था। इसने अब तक के सभी विचारकों की अपेक्षा अधिक उग्रता तथा प्रबलता के साथ निजी सम्पत्ति का विरोध किया। आर्थिक विपन्नता ने प्राउधों को पूँजीवादी समाज का उग्र विरोधी बना दिया। सन् 1840 ई0 में उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (What is Property?) "सम्पत्ति क्या है ?" प्रकाशित की। उसमें निजी सम्पत्ति की व्यवस्था का उग्रतम खण्डन है। छः वर्ष बाद प्राउथों ने निर्धनता की विवेचना करने वाला एक ग्रन्थ "दरिद्रता का दर्शन" प्रकाशित किया, इसमें समाजवादी और साम्यवादी सिद्धांतों की कड़ी आलोचना की और अपनी योजना को विस्तार पूर्वक प्रचारित करने के लिए उसने "न्याय और धर्म की भावना" (1858) में प्रकाशित की। चर्च तथा प्राचीन आदर्शों की उसने कड़ी आलोचना की, इसी वजह से उसे कड़ा दण्ड दिया गया।[52]

प्राउधों का प्रथम और सबसें महत्वपूर्ण सिद्धांत निजी सम्पत्ति का विरोध है। उसके आदर्श समाज में सम्पत्ति की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह सम्पत्ति को चोरी समझता था। उसका विचार था कि श्रम ही सम्पत्ति को पैदा करने का प्रधान साधन है। यदि श्रम न किया जाय तो भूमि और पूँजी से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं की जा सकती। मनुष्य जब स्वयं कोई श्रम किये बिना अपनी भूमि तथा पूँजी पर दूसरे व्यक्तियों का श्रम लगाकर उसका लगान अथवा लाभ प्राप्त करता है तो वह चोरी होती है, क्योंकि उस श्रम पर मजदूरों का अधिकार होना चाहिए।[53]

यद्यपि प्राउधों समाजवादी होने की अपेक्षा शासम हीन व्यवस्था (अराजकतावाद) का अधिक समर्थक था, परन्तु फिर भी उसने ऐसे विचारों को प्रतिपादित किया जिन्हें मार्क्स ने अपने सिद्धांतों में सम्मिलित किया, तथा एक ठोस नींव तैयार करने में सहायक तत्व का कार्य किया।[54] प्राउथों पहला विचारक था जिसने इस ओर संकेत किया कि श्रमिक वर्ग के साधन हीन होने के

52 - थामस किरकप-हिस्ट्री आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 52

53 - वही, पृष्ठ 53

54 - प्रो0 यशपाल- मार्क्सवाद, पृष्ठ 20

कारण उन्हें अपने श्रम का पूर्ण मूल्य नहीं मिलता तथा साधनों का स्वामी परिश्रमों के बिना ही श्रम के फल पर अपना आधिपत्य जमा लेता है । मार्क्स ने 'अतिरिक्त मूल्य' के जिस सिद्धांत की स्थापना की उसका पहला अविकसित संकेत हम यहीं पाते हैं ।

प्राउधों के विचारों में जिस आर्थिक विचारधारा का वर्णन है, वह प्रजातन्त्र के आधार पर ही सफल हो सकती है । उसके विचारों में न्याय, स्वतन्त्रता, एवं समानता के तत्वों का समिश्रण है। उसने जिस समाज की कल्पना की है उसके आधार में भी स्वतन्त्रता, समानता तथा न्याय ही मौजूद है ।[55] सरकार के संगठन के संबंध में, वह किसी भी प्रकार के शासन का विरोधी था, क्योंकि शासन में व्यक्ति को अपने विकास के लिए पूर्ण अवसर नहीं प्राप्त होते । प्राउधों के समय में समाज की व्यवस्था के साथ, धर्म-विश्वास का गहरा सम्बन्ध माना जाता था । समाज व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए परम्परागत सामाजिक नियमों तथा धर्म-विश्वासों को अमान्य किये बिना सम्भव नहीं था । प्राउधों ने उस कार्य में पहल की तथा परम्परागत सामाजिक नियमों की कटु आलोचना की ।

यद्यपि फ्रांस के प्रारंभिक समाजवादी विचारक सेंट साइमन, नोयल वावेल, फोरियर इत्यादि धार्मिक प्रभाव से मुक्त नहीं थें । उन्होंने धार्मिक -विश्वासों और सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया था । प्राउधों के विचारों ने समाज में एक नई चेतना पैदा की सर्व साधारण को उसके विचारों में आचार हीनता की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी । उसका विचार था कि स्त्री-पुरुष के आचार सम्बन्धी नियमों को केवल धर्मिक भय से न मानकर वैक्तिक विकास का साधन और व्यवस्था के लिए आवश्यक समझना चाहिए । उसके इन विचारों को क्रियात्मक रुप समाज में प्रदान किया गया ।

फ्रांस विश्व में पहला देश था जिसमें सर्वप्रथम समाजवादी विचारों का उदय हुआ तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

5-ब्रिटेन के समाजवादी विचारक

समाजवादी विचारधारा का विकास फ्रांस के समानान्तर इंग्लैण्ड में भी हुआ । औद्योगिक क्रान्ति सर्वप्रथम ब्रिटेन में सम्पन्न हुई थी ।अतः यहाँ समाजवादी विचारधारा का अभ्युदय एवं विकास सर्वथा स्वाभाविक था । इंग्लैण्ड में समाजवादी विचारकों में दो समान विचारधाराओं का

---

55 - थामस किरकप- हिस्ट्री आफ सोशलिज्म पृष्ठ 54

विकास हुआ; एक शाखा गाडविन के अराजकतावादी विचारों की थी तथा दूसरी विचारधारा रिकार्डो के इस सिद्धांत पर आधारित थी कि किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस पर लगाये गये श्रम के आधार पर किया जाता है। ब्रिटेन की समाजवादी विचारधारा ने आधुनिक समाजवाद के प्रवर्तक मार्क्स को भी प्रभावित किया।

यद्यिप फ्रांस और इंग्लैण्ड में एक समान ही सामाजिक तथा आर्थिक विषमतांए मौजूद थी। परन्तु फ्रांस की अपेक्षा इंग्लैण्ड की समाजवादी विचारधारा में नैतिकता का मिश्रण अधिक था। यद्यपि यहाँ फ्रांस की अपेक्षा पूंजीवाद अधिक विकसति तथा समर्थ था। इंग्लैण्ड में कुलीनतंत्र फ्रांस की अपेक्षा कम पनप रहा था। यद्यपि लॉक तथा एडम.स्मिथ के उदारवादी विचारों ने समाजवाद की नींव तैयार कर दी थी। दोनों ही विचारकों ने मजदूरी और मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में स्मिथ ने यह विचार रखा था कि राज्यों को वस्तुओं का उत्पादन तथा भूमि संबंधी नियम तथा उत्पादन का संग्रह, जो मजदूरों द्वारा उत्पादित किया जाता हैं, नियंत्रण तथा नियमन करना चाहिए।[56]

समाजवादी विचारधारा के अभ्युदय का कारण सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएं होती हैं। यह विचार सर्वमान्य विचार है। इस विषमता का सबसे अधिक प्रभाव समाज के सबसे निम्नवर्ग (श्रमिक वर्ग) पर पड़ता है। एक विचारक ने इंग्लैण्ड के श्रमिकों को आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में लिखा है कि---

1. किसानों और मजदूरों का निर्वाह उन्हें मिलने वाली मजदूरी से सम्भव है।
2. उनके निवास स्थानों की दशा अत्यन्त सोचनीय है।
3. पूँजीपति एवं जमींदार वर्ग लगातार मजदूरी घटाने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए पुरुषों के स्थान पर स्त्रियों तथा बच्चों को कार्य पर लगाया जाता है, जिनसे कार्य उनकी क्षमता भर लिये जाता है तथा मजदूरी आधी या उससे भी कम दी जाती है। इस कारण से मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ जाती है।

---

56 - इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज,- वैल्यूम 7, पृष्ठ 193

4. शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें अवसर नहीं है ।[57]

ब्रिटेन की समाजवादी विचारधारा अपने सही रुप में राबर्ट ओवन से प्रारम्भ होती है । परन्तु उससे पूर्व भी कुछ विचारकों का प्रादुर्भाव हो चुका था ।

जैसे- गाडविन, रिकार्डो इत्यादि ।

विलियम गाडविन -(1756-1836 ई0)

विलियम गाडविन ब्रिटेन में अराजकतावाद का प्रबल समर्थक और वैक्तिक सम्पत्ति का उग्र विरोध करने वाला प्रथम महत्वपूर्ण विचारक था । फ्रांस की क्रान्ति के समय सन् 1793 ई0 में उसकी प्रसिद्ध पुस्तक व राजनीतिक न्याय के विषय में अन्वेषण (इन्क्वायरी कन्सर्निंग पोलिटिकल जस्टिस) ने इसे कीर्ति के चरम शिखर पर पहुंचा दिया । उसके विचार इतने क्रान्तिकारी थे कि इंग्लैण्ड की सरकार को उसकी पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा ।

उसका प्रथम मौलिक सिद्धांत है कि शासन अथवा राज्य एक आवश्यक बुराई है और उसका उन्मलून होना चाहिए । उसकी वह पुष्टि निम्नलिखित परम्परा के आधार पर करता है।उसके विचारानुसार मानव के मन में कोई नैसर्गिक धारणएं अथवा विचार नहीं है । वह केवल क्रान्तियों से प्राप्त होने वाले अनुभवों (संसेशन्स) को ग्रहण करता है और उसमें तर्क करने की शक्ति है, उससे वह अपने अनुभवों को विचारों में बदल लेता है । किसी वस्तु का नैतिक अथवा अनैतिक होना हमारे विचार पर निर्भर है । विचार परिस्थितियों पर निर्भर है। यदि सामाजिक संस्थाएं और परिस्थितियां न्याय पर आधारित हों तो मनुष्य के विचार अच्छे होंगे तथा विकास भी समुचित तरीके से होगा । किन्तु सरकार शक्ति तथा हिंसा का माध्यम है, वह समाज में आर्थिक विषमताओं को स्थाई बनाती है। सामाजिक कल्याण की दृष्टि से उनका उन्मूलन होना चाहिए । गाडविन निजी सम्पत्ति के उन्मूलन का उग्र समर्थक था । सामाजिक असमानता का मुख्य आधार वैक्तिक सम्पत्ति ही है । समाज में वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण समानता के आधार पर होना चाहिए । गाडविन ने ब्लांक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की नींव इंग्लैण्ड में रखी कि "प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाना चाहिए।" चौथा सिद्धांत नई व्यवस्था को लाने में शक्ति के स्थान पर बुद्धि के

---

57 - थामस किरकप, ऐन इन्क्वायरी इन्टू सोशलिज्म पृष्ठ 48

साधन पर बल देना था । फ्रांस क्रान्ति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हिंसा के माध्यम से व्यक्ति को नहीं बदला जा सकता है ।

रिकार्डो --यद्यपि कि यह पूंजीवाद का समर्थक था, परन्तु उसके दो सिद्धान्तों ने समाजवाद के विकास पर गहरा प्रभाव डाला । पहला सिद्धांत मूल्य विषयक है । रिकार्डो का यह मत था कि एक वस्तु का विनिमय मूल्य (एक्सचेंज वैल्यू) उस पर लगाये गये श्रम पर आधारित है। किसी वस्तु के उत्पादन करने में जितना समय लगता है, उसी से उस वस्तु का मूल्य निश्चित होता है । मार्क्स ने इस सिद्धांत को पूंजीवादी व्यवस्था के लिए प्रयुक्त किया । दूसरा है मजदूरी सिद्धांत--(थियरी आफ वेजेज); उसके अनुसार मजदूरी मजदूर द्वारा पैदा की हुई वस्तु से निश्चित नहीं होती वरन उसकी स्थिति के तत्वों के अनुसार होनी चाहिए ।

राबर्ट ओवेन -(1771-1858 ई0)

राबर्ट ओवेन, सेंट साइमन और फोरियर का समकालीन था । उसका जन्म 1771 ई0 मे इंग्लैण्ड के एक सम्पन्न परिवार में हुआ था । उसे अंग्रेजी कल्पनावादी समाजवाद का जनक माना जाता है। ओवन प्रारम्भ से ही श्रमिकों की दयनीय दशा के प्रति सहानिभूती रखता था । इसलिए उसने अपनी पूंजी श्रमिकों के हितार्थ नियोजित की । ओ़वन का विश्वास था कि मानव की प्रगति उसकी परिस्थतियों पर आधारित होती है । यदि मनुष्य को अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध करा दी जाये, तो वह स्वयं उन्नति के शिखर पर पहुँच जायेगा । ओवन ने गरीबी को मनुष्य के विकास में बाधक बताया । गरीबी का मूल कारण आलस्य है, इससे मनुष्य की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और समाज गरीबी के प्रकोप का शिकार हो जाता है ।[58] ओवन का मत था कि औद्योगिक क्रान्ति द्वारा गरीबी को दूर किया जात सकता है ।[59]

समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग सन् 1807 ई0 में राबर्ट ओवन ने ही किया था ।ओवन समाज की उस अवस्था के अर्न्विरोध से परेशान था कि समाज में उत्पादन के साधन उन्नति कर रहे हैं और पूंजी में वृद्धि हो रही है, परन्तु समाज में मजदूरों की दशा अवनति की ओर है। ब्रिटेन

58 - विलियम एबन्सटीन- जी0 डी0 एच0 कोल आन ओवन इन पोलिटिकल थाट इन पर्सपेक्टिव, पृष्ठ 454, राबर्ट ओवेन- ए न्यू व्यू आफ सोसाइटी थर्ड ऐज ईवरी मैन, पृष्ठ 45

59 - वही पृष्ठ 37

में समाजवादी विचारधारा को क्रियात्मक रुप देने वाला वह प्रथम विचारक था[60] राबर्ट ओवन एक राजनीतिक विचारक की अपेक्षा सुधारवादी अधिक था ।इंगलैण्ड के औद्योगिक संस्थानों में सुधार की योजनाएं राबर्ट ने ही प्रस्तुत की थी । वह अपना उद्देश्य सामाजिक अवस्था में परिवर्तन समझता था । उस समय इंग्लैण्ड के औद्योगिक मजदूर वर्ग की दशा काफी शोचनीय थी, तथा उसने श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा बनाने वाले कानूनों में विशेष सहयोग दिया । सन् 1813 तक राबर्ट एक सुधारक के रुप तक ही सीमित रहा, तथा उसी समय उसने 'समाज का नया दृष्टिकोण'(A New view of society (1813) नामक पुस्तक का सम्पादन किया ।, परन्तु 1817 ई0 से उसके विचारों में कुछ उग्रता आने लगी । सबसे पहले संसद में पेश गरीब सहायक कानून (पुअर ला) पर उसने लिखा कि-" मजदूरों की निम्न अवस्था का कारण, मशीनों द्वारा उनके परिश्रम का मूल्य घटा देना है ।[61]

ओवेन हड़ताल तथा क्रान्ति का पोषक होकर भी हिंसा और वर्ग संघर्ष में कोई आस्था नहीं रखता था । वह संवैधानिक उपायों का समर्थक था । वह समाजवाद को सहयोग पर आधारित करना चाहता था । वह घृणा का विरोधी तथा प्रेम का उपासक था । वह श्रमिकों को उनके परिश्रम का समुचित पारितोषिक देने के पक्ष में था, परन्तु वह श्रमिकों द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही करने तथा राजनीति में हस्तक्षेप का प्रबल विरोधी था । वह राज्य की अपेक्षा समाज में परिवर्तन लाने का इच्छुक था [62] इस प्रकार ओवेन का समाजवाद कार्ल मार्क्स के समाजवाद से भिन्न था ।फिर भी मार्क्सवाद के अनेक तत्व ओवेन के समाजवाद में छिपे थे । स्वयं मार्क्स ने भी उसे परोपकारी सुधारक की संज्ञा दी है ।

इन समाजवादियों के अतिरिक्त लुई ब्लांक (1813-1882 ई0) विलियम थामस और थामस हाग्सकिन (1787-1869 ई0) आदि समाजवादी विचारकों ने भी अपने समाजवादी चिन्तन का प्रतिपादन किया । लुई ब्लांक को आधुनिक "लोकतांत्रिक समाजवाद" का अग्रवर्ती,[63] और श्रमिक समाजवाद का प्रतिनिधि[64] माना जाता है ।विलियम थामस की गणना वैज्ञानिक समाजवाद के

---

60 - थामस किरकप- हिस्ट्री आफ सोशलिज्म, पृष्ठ 60
61 - वही ,पृष्ठ 64
62 - एम0 बीयर- ए हिस्ट्री आफ ब्रिटिश सोशलिज्म खण्ड 1, पृष्ठ 60
63 - जी0 डी0 एच0 कोल- ए हिस्ट्री आफ पोलिटिकल थाट, जिल्द 3, पृष्ठ 169
64 - अलैक्जैण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 219

संस्थापकों में की जाती है [65] और उसे ब्रिटिश समाजवादी चिन्तन का प्रवर्तक माना जाता है ।[66] थामस हांगसकिन की गणना मार्क्स के पूर्ववर्ती समाजवादी विचारकों में की जाती है ।[67] तथा उसके विचारों में व्यक्तिवाद और अराजकतावाद दोनों का समिश्रण मिलता है ।[68]

सन् 1830 ई0 में ओवेन ने तत्कालीन स्थिति का पूर्ण विश्लेषण करते हुए अपनी साम्यवादी योजना प्रस्तुत की । उसके सम्बन्ध में उसने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने का एकमात्र उपाय साम्यवाद की स्थापना है । उस योजना के प्रारुप का वर्णन करते हुए, ओवन ने यह विचार रखा कि इस योजना को पहले छोटे-छोटे समुदायों में विभक्त करके सफल बनाया जायेगा । इसके लिए 1000 से 1500 एकड़ तक की भूमि हो तथा जनसंख्या 500 से 2000 तक की होनी चाहिए । यह समुदाय सभी साधनों से परिपूर्ण होगा ।यहाँ कृषि तथा उद्योगों से होने वाली आय का संयुक्त रुप से उपयोग करेंगें तथा कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं रहेगा । एक समुदाय का भूमि तथ उद्योगों पर एवं उत्पादन पर संयुक्त रुप से अधिकार होगा ।[69] यह योजना न्यू लेनार्क की योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई ।फ्रांस के समाजवादी फूरियर ने सम्भवतः उसी के आधार पर अपनी फ्लैंक्स (Phalanxes)की योजना बनायी थी परन्तु संसद ने ओवेन की योजना को स्वीकार नहीं किया तथा सन् 1817 ई0 में श्रमिकों ने उसका विरोध किया । उसका मुख्य कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के ऊपर कुछ प्रतिबन्धों का संकेत उसने अपनी योजना में किया था । श्रमिक वर्ग स्वतन्त्रता के ऊपर प्रतिबन्ध के घोर विरोधी थे । तथा दूसरा कारण धर्म को भी ओवेन ने प्रगति के मार्ग में अवरोधक बताया था । इससे धार्मिक व्यक्ति भी ओवेन की योजना का विरोध करने लगे ।

सन् 1819 ई0 में उसने मजदूरों के सम्मुख भाषण (अड्रेस टू द वर्कमेन) में इस बात पर बल दिया कि श्रमिक वर्ग, शासक वर्ग के प्रति हिंसा की भावना का त्याग करे, तथा सहयोग का रास्ता अपनाये । सन् 1821 ई0 में उसने सामाजिक पद्धति (सोशल सिस्टम) नामक पुस्तक लिखी, इसमें उसने पूर्ण साम्यवादी स्थिति स्वीकार करते हुए व्यक्तिगत सम्पत्ति का उग्र विरोध किया तथा

---

65 - मेन्जर- दि राइट टू दि होल प्रोड्यूस आफ-लेबर, उद्धृत-अलैक्जेन्डर दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 264

66 - डा0 केयल कमल - समाजवादी चिन्दन, पृष्ठ 55

67 - वही, पृष्ठ 59

68 - वही, पृष्ठ 63

69 - एच0 डब्ल्यू लैडलर- सोशल इकोनामिक मूवमेन्ट, पृष्ठ 93

समाज में समानता लाने के लिए वितरण की समुचित व्यवस्था आवश्यक है, । इस पर बल दिया । ओवेन ने पूंजीवाद की सबसे बड़ी बुराई, वितरण में असमानता की ओर संकेत किया ।

ओवेन की इस योजना को, ओवन के निर्देशन में ही सर्वप्रथम अमेरिका में क्रियात्मक रुप देने का प्रयास किया गया । परन्तु सन् 1827 ई0 में उसकी यह योजना असफल सिद्ध हुई ।

मैक्सी के अनुसार- "काल्पनिक समाजवाद का विकास ओवेन के साथ ही साथ समाप्त हो गयी"।

राबर्ट के विचारों से हम विकास का स्पष्ट क्रम देख सकते है । उसकी पुस्तक गरीबों का संरक्षण (पुअरमेन गार्जियन) (1835) में उन विचारों का स्पष्ट उल्लेख करती है ।जिन्हे अतिरिक्त मूल्य (सरप्लस वैल्यू) के वैज्ञानिक सिद्धान्तों की स्पष्ट भूमिका कहा जा सकता है । ओवन के अनुसार सम्पूर्ण पैदावार मजदूर और किसानों के श्रम से ही होती है ।सहयोग द्वारा उत्पादन की पद्धति के प्रारम्भिक विचारों का श्रेय भी राबर्ट को ही है । जिसका आज विश्व के सभी देशों में सर्वमान्य प्रचार है । "सोशलिज्म' शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग राबर्ट द्वारा ही स्थापित सम्पूर्ण समाजवादी राष्ट्रों की सम्पूर्ण श्रेणियों के सहयोग की संस्था (एसोसिएशन आफ आल क्लासेज आफ आल नेशन्स) के वाद-विवादों में भी हुआ था ।[70]

राबर्ट की आरम्भिक सफलता का कारण उसके द्वारा चलाये गये सहायक आन्दोलन की जड़ में भी धार्मिकता तथा मनुष्यता की भावना ही प्रधान थी इस आन्दोलन में धनिक वर्ग एवं सम्पन्न श्रेणियों के आत्माभिमान के भावना की पूर्ण होने की काफी संभावनाएं थी इसलिए राबर्ट को इन वर्गो का काफी समर्थन मिला परन्तु जैसे ही उसने पूंजीवादी व्यवस्था को सुरक्षित रखने वाले कारणों पर कठोर प्रहार किया, उसके विचारों का समाज में विरोध होने लगा एवं उसके संगठन के तत्व बिखरने लगे तथा उसका साम्यवादी आन्दोलन स्वयं ही बिखर गया । राबर्ट का आन्दोलन समाप्त हो जाने पर भी श्रमिक वर्ग के अन्दर अपने अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ती गयी तथा क्रिश्चियन सोशलिस्ट मूवमेन्ट के रुप में सन् 1848-52 ई0 में एक सुधारवादी आन्दोलन हुआ इस आन्दोलन का आधार तथा उद्देश्य समाज में नैतिकता तथा अध्यात्मिकता के क्षेत्र में समानता स्थापित करना था । इस आन्दोलन

---

70 - थामस किरकप- हिस्ट्री आफ सोशलिज्म- पृष्ठ 67

ने मजदूरों में 'सहयोग के सिद्धांत' का समर्थन किया। इस आन्दोलन के नींव में भी राबर्ट के सहयोग सिद्धान्त के विचार निहित थे।

यद्यपि राबर्ट को अपने विचारों को क्रियात्मक रुप प्रदान करने में सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके विचारों का समाजवाद के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है राबर्ट के साथ ही आधुनिक समाजवाद की विचारधारा का इंग्लैंड में उदय हुआ एवं उसने प्रथम बार क्रियात्मक रुप देने का प्रयास किया परन्तु असफल रहा। लेकिन भविष्य के समाजवादी विचारकों के लिए उसने एक निर्देशक तत्वों की श्रृंखला जोड़ दी कि इन विचारों को भी क्रियात्मकरुप प्रदान किया जा सकता है।जॉन ग्रे, जो एक समाज सुधारक थे, उन्होंने उत्पादन को मजदूरी के सिद्धांत के आधार पर विश्लेषित किया। जॉन फ्रांसिस ने, जो कि ओवेन की शिक्षा का समर्थक था, उसने पूंजीवाद की आलोचना की तथा संवाद (Synthesis) के कारणों की व्याख्या एवं समाजवाद के विकास की श्रृंखला में सहयोग प्रदान किया।[71]

6-जर्मनी के समाजवादी विचारक

19वीं शताब्दी के आरम्भ में समाजवादी विचारों का जो विकास इंग्लैण्ड और फ्रांस में तीव्र गति से हुआ वह कोई स्थाई परिणाम के बिना ही 19वीं शताब्दी के मध्य में कुछ समय के लिए दब सा गया । इसके बाद इस विचारधारा का विकास जर्मनी में बहुत तीव्र गति से हुआ क्योंकि वहाँ के समाज संगठन का ढ़ांचा परम्परावादी तथा सामन्तवादी व कुलीनतंत्री आधार पर संगठित तथा। इस विचारधारा के विकास में पूर्व के विचारकों ने काफी सहयोग दिया।

1. जर्मनी के आदर्शवादी दर्शन में जिसके प्रवर्तक कान्ट तथा फिक्टे थे,तथा हिगल जो उस समय के सबसे बड़े आदर्शवादी समझे जाते थे, उसने राष्ट्रीय समाजवाद के तत्वों को जन्म दिया। उनके विचारों में गिल्ड समाजवाद के तत्व भी मौजूद थे। फिक्टे ने एक नवीन आर्थिक योजना प्रस्तुत की कि राज्य को विदेशी व्यापार करना चाहिए तथा समाज संगठन व्यवसाय के आधार पर होना चाहिए।

---

71 - इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज, वैल्यूम 7, पृष्ठ 195

2. दूसरा कारण, मार्क्स का उद्भव वास्तव में जोकि आधुनिक समाजवाद के जनक समझे जाते हैं, मार्क्स की विचारधारा की सबसे अधिक लुडविख फेवरबाख (Ludwing Feuerbach) ने अधिक प्रभावित किया ।

3. आदर्शवादी विचारधारा, उस समय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया मात्र थी, जो उस समय समाज में मौजूद थी । यह विचारधारा पूंजीवादी विचाधारा के विरुद्ध थी इसने भी जर्मन समाजवाद के विकास में सहयोग प्रदान किया । मुख्य रुप से फ्रेन्ज़ वान बोडर तथा एडम मूलर ने पूंजीवादी व्यवस्था के दुस्परिणाम के कारणों की ओर संकेत किया ।

4. उस समय के आर्थिक अनुसंधानों ने समाजवाद की विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया । वैज्ञानिक कारण भी, जो अपने प्राथमिक रुप में थें परन्तु उन्हें मान्यता नहीं मिली थी । आर्थिक, नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों का भी समाजवाद के विकास में काफी योगदान रहा [72]

जर्मनी के समाजवादी इतिहास में, कार्ल मार्क्स तथा लैस्सली एवं राडवर्ट्स के नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय है ।

कार्ल मार्क्स (मार्क्सवाद)

कार्ल मार्क्स से पूर्व का समाजवाद काल्पनिक समाजवाद कहा जाता है,क्योंकि वह इतिहास के किसी दर्शन पर आधारित नहीं था ।वेपर के अनुसार "उन्होंने सुन्दर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की परन्तु गुलाब के फूलों के लिए कोई भूमि तैयार नहीं की ।[73]

समाजवादी विचारधारा को वैज्ञानिक स्वरुप प्रदान करने में कार्ल मार्क्स और एंग्जेल्स का काफी योगदान रहा है । मानव समाज की नवीन व्याख्या उसके द्वारा ही की गयी । लेकिन मार्क्स ने किसी नवीन विचार का प्रतिपादन नहीं किया बल्कि पूर्व सिद्धांतों की वैज्ञानिक व्याख्या ही प्रस्तुत की ।[74]

जिन सिद्धांतों की मार्क्स ने व्याख्या प्रस्तुत की उसका प्रतिपादन पूर्व में हो चुका था । जैसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत; टगर्ट,गाडविन,थामसन इत्यादि विचारक पहले ही कर चुके थे ।

---

72 - इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज, वैल्यूम 7, पृष्ठ 196

73 - सी0 एल0 वेपर- राजदर्शन का स्वाध्ययन, पृष्ठ 207

74 - इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज, वैल्यूम 7, पृष्ठ 197

पूंजीवाद की व्याख्या फोरियर तथा ब्लांक ने तथा वर्ग संहर्ष की व्याख्या ब्लांक, वान स्टेन, (Van Stain), थैरी (Theiry) तथा गुजाट के द्वारा की जा चुकी थी । तथा पूंजीवाद की प्रतिक्रिया के रुप में नये सर्वहारा वर्ग का उदय होगा, राडवर्ट्स द्वारा की गयी थी ।[75]

जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक था ।[76] उसे श्रमिकों का मसीहा और उसके ग्रन्थ "दास कैपिटल" को आधुनिक बाइबिल कहा जाता है । मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर समाजवाद के वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन करके उसे आधुनिक रुप प्रदान किया ।[77]

मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए कहा गया है कि उसने एक ऐसा आन्दोलन चलाया जिसका एक निश्चित सिद्धांत था । उस समय चल रहे निराधार समाजवादी आन्दोलन को एक आधार प्रदान किया । सेंट साइमन, फोरियर और ओवर ने भले ही ऐसे सत्यों को प्रकट किया था जो बाद में मार्क्स द्वारा उपेक्षित हुए परन्तु उनके सिद्धांत केवल बौधिक आधार रखते थे ।मार्क्स ने समाजवादी आन्दोलन के लिए वही कार्य किया,जो मैकियावली ने राज्य सिद्धांत के लिए किया था । मार्क्स से पूर्व श्रमजीवी आन्दोलन एक विरोध तथा भावना तक सीमित था । मार्क्स के बाद उसे एक वैज्ञानिक आधार मिल गया श्रमजीवी आन्दोलन का लक्ष्य तथा उद्देश्य निश्चित हो गया, उसमें एक निश्चित संगठन उत्पन्न हो गया तथा पूंजीवाद पर आक्रमण करने के लिए एक सैनिक शक्ति उसमें उत्पन्न हो गयी । समाजवाद को वैज्ञानिक रुप देना मार्क्स के सिद्धांतों में से था । उसने केवल समाजवाद को केवल वैज्ञानिक आधार ही प्रदान नहीं किया, वरन उसे विशाल शक्ति भी प्रदान की ।[78] वास्तव में मार्क्स ने समाजवाद को कोलाहल से उठाकर एक सशक्त आन्दोलन का रुप दे दिया, ऐसे आन्दोलन का जो समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित है मार्क्स ने श्रमिकों को, जो असंगठित और बिखरे हुए थे, एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रुप में बदल दिया ।[79] मार्क्सवादी समाजवाद में पूर्व की समाजवादी विचारधाराओं के अनेक तत्व मौजूद होने के कारण.भी उसकी वैज्ञानिक व्याख्या मार्क्स

---

75 - वही, पृष्ठ 197

76 - सी0 सी0 मैक्सी- पोलिटिकल फिलासफीज, पृष्ठ 698

77 - हैरी डब्ल्यू लैडलर-हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट (1927), अध्याय 19, थामस किरकप-हिस्ट्री आफ सोशलिज्म- (1913), पृष्ठ 5,6, फ्रांसिस डब्ल्यू कोकर-रीसेन्ट पोलिटिकल थाट, पृष्ठ 46

78 - सी0 सी0 मैक्सी-पोलिटिकल फिलासफीज, पृष्ठ 698-99

79 - लास्की-कम्यूनिज्म, पृष्ठ 32

द्वारा ही की गयी। सन् 1847 ई0 में घोषणा की थी कि समाजवाद बुर्जुवा वर्ग का आन्दोलन है, लेकिन साम्यवाद मजदूर वर्ग का आन्दोलन है। समाजवाद को प्रारम्भ से ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, जबकि साम्यवाद एक विरोधी विचारधारा थी, श्रमिक वर्ग उसका समर्थन क्रान्ति के आधार पर करता था। सर्वहारा वर्ग के समक्ष दो रास्ते थे या तो उस विचारधारा को तथा उसके साधनों का चुनाव करें अथवा उसका परित्याग।

मार्क्स से पूर्व जो समाजवादी विचारधाराएं थी, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से उन पर धार्मिक अथवा भौतिक प्रभाव अवश्य था। जब समाजवाद वैज्ञानिक रुप में सामने आया तब जनता धर्म-विश्वासों से विमुख होने लगी थी, जिसने मार्क्सवादी विचारधारा के विकास में महत्व पूर्ण योगदान दिया।

मार्क्स से पूर्व के विचारकों ने समाज के भविष्य के लिए आर्थिक संस्थओं का विचार स्पष्ट रुप से नहीं रखा था। मार्क्स ने इस कमी को काफी सीमा तक दूर किया।

पूर्व की समाजवादी विचारधारा काल्पनिक तत्वों से परिपूर्ण थी एवं इतिहास को विकास का परिणाम मानती थी। एंगेल्स ने घोषणा की थी कि मार्क्स ने डार्विन के "विकासवाद" के आधार पर ही, जिस प्रकार प्रकृति का विकास होता है उसी प्रकार मानवीय इतिहास का भी विकास होता है, उस सिद्धान्त का निर्माण किया। यह विचार दो विभिन्न विचारधाराओं के समिश्रण से बना था, प्रथम विकासवादी विचारधारा तथा क्रान्तिकारी विचारधारा से। इन्ही आधारों पर उसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की।

इस प्रतिवादी विचारधारा का उदय अंग्रेजी दर्शन के अन्दर हो चुका था। 17वीं व 18वीं शताब्दी में लॉक के दर्शन में व भौतिकवादी विचार दर्शन फ्रांस की क्रान्ति (1789 ई0) में मिल जाता है।[80] मार्क्स ने इस सत्य को स्वीकार किया है कि वह दर्शन आदर्शवादी विचारकों, कांट, फिक्टे तथा हिगल के दर्शन से प्रभावित था। स्पेंगलर का विचार है कि पेरुसियन की विचारधारा ने मार्क्स को काफी प्रभावित किया। लेविस 'चेतना के विचार' ने मार्क्सवाद को एक नई शक्ति प्रदान की। जैरो-वाकूनिन और सोम्बार्ट ने भी मार्क्स को प्रभावित किया। सन् 1848 ई0 में साम्यवादी

---

80 - इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज, वैल्यूम 7, पृष्ठ 198

घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ। यह पुस्तक मार्क्स तथा एंगेल्स की संयुक्त कृति है। इस पुस्तक में मार्क्स के सभी सिद्धांतों का समावेश है। यह एक प्रकार से उसकी विचारधारा का संग्रह है तथा साम्यवाद का आधार मानी जाती है। सन् 1860 ई0 में मार्क्स की पुस्तक "दास कैपिटल" प्रकाशित हुई।यह पुस्तक आर्थिक व्यवस्था के सिद्धांतों तथा नीतियों का विश्लेषित संग्रह है। इस पुस्तक में पूंजीवादी व्यवस्था का बड़ा गंभीर विश्लेषण किया गया है। इसके बाद के दो भागों को एंगिल्स ने पूर्ण किया।[81]

कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा को स्वयं वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा दी थी। यह विचार पूर्ववर्ती समाजवादी विचारकों से स्वयं मार्क्स को पृथक करती है। उसने अपने मत को स्वयं वैज्ञानिक इसलिए कहा है कि उसने एक वैज्ञानिक के समान समाज के स्वरुप एवं विकास के नियमों की खोज करने का प्रयास किया है।

कार्ल मार्क्स अपने समाजवादी विचारों में हिगल, फ्रांसीसी व ब्रिटिश समाजवादियों के विचारों से काफी प्रभावित था।[82] इसलिए उसके विचारों को एकदम मौलिक नहीं कहा जा सकता तथापि उसके द्वारा समाजवाद को एक दर्शन मिला और एक नयी दिशा मिली।[83]

मार्क्सवादी चिन्तन बड़ा विस्तृत और क्रमबद्ध है। कार्ल मार्क्स के क्रान्तिकारी कदम वर्ग-संघर्ष के सिद्धांत पर है वर्ग संघर्ष अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर,अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इतिहास पर तथा द्वन्दात्मक भौतिकवाद आध्यात्मिक विद्या पर आधारित है।[84]
इस प्रकार मार्क्सवादी चिन्तन के चार प्रमुख तत्व हैं।

1. द्वन्दात्मक भौतिकवाद।
2. इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या।
3. वर्ग संघर्ष का सिद्धांत।
4. अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत।

इन तत्वों की संक्षिप्त व्याख्या निम्नवत् है।

---

[81] - हेनरी, वी0 माया-इन्ट्रोडक्शन टु मार्क्स सिस्ट थियोरी, पृष्ठ 22
[82] - सेबाइन- राजनीतिक दर्शन का इतिहास, पृष्ठ 703
[83] - अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडिशन, पृष्ठ 295
[84] - लास्की- कम्यूनिज्म, पृष्ठ 103, मैक्सी-पोलिटिकल फिलासफीज, पृष्ठ 672

द्वन्दात्मक भौतिकवाद

द्वन्दात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी चिन्तन की आधार शिला है। कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वन्दवादी सिद्धांत को ग्रहण किया था। हीगल का मत था कि मानव का सामाजिक विकास अबाध गति से होता रहता है, और इस विकास के साथ ही साथ मनुष्य में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। इस विकास प्रक्रिया को ही हीगल द्वन्दवाद की संज्ञा देता है।हीगल का विश्वास है कि वाह्य विश्व आन्तरिक विचारों का ही प्रतिरुप होता है। हीगल की द्वन्दात्मक प्रणाली भाव प्रणाली कही जाती है। मार्क्स ने हीगल के द्वन्दवाद को स्वीकार तो किया, परन्तु उसको उसने अपनी इच्छानुसार संशोधित कर लिया। मार्क्स ने स्वयं ही दास कैपिटल में लिखा है-

"मैंने हीगल के द्वन्दवाद को सिर के बल खड़ा पाया,इसलिए मैंने उसे सीधाकर पैरों के बल खडा कर दिया।[85]

मार्क्स ने हीगल को कल्पनावादी बताकर उसके द्वन्दवाद के भाव पक्ष को त्याग कर भौतिक पक्ष को स्वीकार कर लिया। उसने यह स्पष्ट किया कि "वाह्य विश्व का प्रभाव ही आन्तरिक विचारों का निर्माण करता है। मार्क्स ने बताया कि विचार तथा विचार-वस्तु का अटूट सम्बन्ध होता है, और उन दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। विचार या चेतना शक्ति का प्रादुर्भाव मस्तिष्क में होता है, जो भौतिक तत्वों की सर्वोच्च कृति है। भैतिक तत्व मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं और आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन सम्भव नहीं है।इसलिए मनुष्य के लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मार्क्स पृथ्वी, वृक्ष,पर्वत तथा शरीर आदि को सत्य मानता था और आत्मा को असत्य तथा अनिश्चित कहता था। उसकी मान्यता थी कि आत्मा पर आधारित दर्शन कभी भी स्पष्ट और सत्य नहीं हो सकता, अपितु भौतिक वस्तुओं पर आधारित दर्शन ही सत्य और स्पष्ट होता है।[86] इस प्रकार मार्क्स का द्वन्दात्मक सिद्धांत भौतिकवाद पर आधारित है।उसके अनुसार भौतिक वस्तु सदैव परिवर्तन शील होती है। और उसमें स्थिरता का अभाव होता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में कुछ तत्व नष्ट होते रहते हैं और कुछ का विकास होता रहता है। विकास प्राकृतिक पदार्थो में एक अभयंतारिक विरोध रहता है, जो कि भौतिक जगत के विकास का मूलाधार है।

---

85 - कार्ल मार्क्स-पूंजी, खण्ड 1, पृष्ठ 28

86 - वी0 अफनास्येव- मार्क्सवादीदर्शन, पृष्ठ 18

मार्क्स का मत है कि भौतिक जगत का विकास क्रमबद्ध न होकर भी अबाध गति से निरन्तर होता रहता है। इस विकास प्रक्रिया में वाद, प्रतिवाद तथा संवाद का क्रम निरन्तर जारी रहता है। इनमें से प्रत्येक अपने पूर्वगामी का विरोधी होता है। मार्क्स सम्पत्ति का उदाहरण देकर स्पष्ट करता है कि सम्पत्ति के जन्म के साथ ही सर्वहारा वर्ग की उत्पत्ति होती है। पूंजीवादी वर्ग और सर्वहारा वर्ग में संघर्ष चलता है। अन्त में क्रान्ति द्वारा सामूहिक स्वामित्व की स्थापना हो जाती है।इस प्रक्रिया में पूंजीवादी वर्ग वाद, सर्वहारा वर्ग प्रतिवाद और सामूहिक स्वामित्व सम्वाद होता है।[87] इस प्रकार मार्क्स अपने द्वन्दवाद द्वारा वर्ग संघर्ष को अनिवार्य बना देता है। सेबाइन ने लिखा है कि- "मार्क्स की अधिक रुचि इस बात में थी कि वह द्वन्दात्मक प्रणाली को ठोस परिस्थितियों में लागू करें, विशेषकर इस उद्देश्य से कि उसके आधार पर क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग के लिए किसी कार्यक्रम की खोज की जा सके।सन् 1848 में एंगेल्स और उसके साम्यवादी घोषणा पत्र, जो समस्त युगों की एक बड़ी क्रान्तिकारी पुस्तक बन गयी है, में वर्ग संघर्ष को अब तक के समस्त समाजों का मूलमंत्र माना है।[88]

इस प्रकार मार्क्स के अनुसार द्वन्दवादी भौतिकवाद का वाद, प्रतिवाद तथा सम्वाद विचार न होकर आर्थिक वर्ग है। मार्क्स के द्वन्दवाद का अन्तिम लक्ष्य वर्गविहीन तथा शोषण विहीन समाज की स्थापना करना है।यह अन्तिम लक्ष्य संवाद है। जिसमें से प्रतिवाद का जन्म नहीं होगा। वर्गविहीन समाज की स्थापना के साथ ही वर्ग संघर्ष की द्वन्दवादी प्रक्रिया भी रुक जायेगी।

ऐतिहासिक भौतिकवाद-

मार्क्सवादी चिन्तन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद है। मार्क्स ने अपने द्वन्दवादी भौतिकवाद के औचित्य को सिद्ध करने के लिए इतिहास की नवीन रुप में व्याख्या की है। वेपर ने उसके सिद्धांत को "इतिहास की आर्थिक व्याख्या" का नाम दिया है।[89] मार्क्स की मान्यता है कि भौतिक पदार्थ, जो इतिहास के विकास में निर्णायक तत्व है, वास्तव में उत्पादन शक्ति है। अतः मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद आर्थिक नियतिवाद है, अर्थात् मनुष्य जो भी कुछ करता

---

87 - मार्क्स व एंगेल्स- संकलित रचनाएं, भाग 3, पृष्ठ 53

88 - सेबाइन- राजनीतिक दर्शन का इतिहास, पृष्ठ 713

89 - कोल- हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट, पृष्ठ 18

है, उसका निर्माण आर्थिक या भौतिक कार्यो द्वारा होता है, क्योंकि मनुष्य पूरी तरह से आर्थिक शक्तियों का दास है।[90] मार्क्स के द्वन्दवादी भौतिकवाद के अनुसार इतिहास का प्रत्येक युग वर्ग संघर्ष का इतिहास है।[91] मार्क्स ने इतिहास के युगों का विभाजन इस प्रकार किया है।-

1. आदि मानव युग
2. दास युग
3. सामन्तवादी युग
4. पूंजीवादी युग
5. समाजवादी युग
6. साम्यवादी युग

वर्ग संघर्ष-

मार्क्स की वर्ग संघर्ष की धारणा समकालीन इंग्लैण्ड की परिस्थितियों पर आधारित है।उस समय इंग्लैण्ड के उत्पादन में भारी वृद्धि हो रही थी, पूंजीपति वर्ग दिन प्रतिदिन धनी हो रहा था तथा श्रमिक वर्ग की निर्धनता निरन्तर बढ़ती जा रही थी। मार्क्स ने पूंजीपति के शोषण तथा श्रमिक वर्ग के कष्टों को देखकर एक कल्पना के आधार पर वर्ग संघर्ष की धारणा बनायी और कल्पना के आधार पर पूंजीवादी व्यवस्था के विनास तथा समाजवाद की स्थापना का स्वप्न देखा।[92]

वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या साम्यवादी पार्टी के घोषणा पत्र में की गयी है। इस घोषणा पत्र में मार्क्स ने लिखा है कि सम्पूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्षो का इतिहास है।[93] मार्क्स के पूर्ववर्ती टामस मूर, सैंट साइमन, फोरियर, राबर्ट ओवन आदि सभी समाजवादी विचारको ने भी यह स्वीकार किया है कि समाज में दो वर्ग पूंजिपति व श्रमिक है।तथा पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करके वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता है फलस्वरुप दोनों वर्गो में संघर्ष चलता रहता है। लेकिन ये विचारक इस संघर्ष का कारण बताने में असफल रहे। इस कार्य को कार्ल मार्क्स ने कर दिखाया उसने स्पष्ट किया कि इन दोनों वर्गो के मध्य संघर्ष का मूल कारण भौतिक

---

90 - ग्रीफिथ-चेंजिंग फेस ऑफ कम्यूनिज्म, पृष्ठ 26
91 - मार्क्स व एंगल्सि- संकलित रचनाएं, भाग 3, पृष्ठ 354
92 - जी0 डी0 एच0 कोल- हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट, पृष्ठ 20
93 - मार्क्स व एंगेल्स-कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र, पृष्ठ 80

उत्पादन है ।मार्क्स ने कहा कि पूंजीपति वर्ग उत्पादन के लाभ से श्रमिकों को वंचित करके उनका शोषण करता है और श्रमिक अपनी श्रम शक्ति को पूँजीपति के हाथों बेचने के लिए विवश है ।[94] अतः दोनो वर्ग में संघर्ष अनिवार्य है, और यह निरंतर संघर्ष पूंजीवादी समाज की प्रकृति है । इस स्थिति में सर्वहारा वर्ग को पूंजीवादी व्यवस्था का अन्त करके एक वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना पड़ेगा और एक सशस्त्र क्रान्ति के द्वारा ही सम्भव हो सकेगा ।

मार्क्स की धारणा है कि पूंजीवाद ने स्वयं ही अपनी कब्र खोद रखी है, उसी कब्र में वह एक दिन जीवित दफन हो जायेगा और वर्ग संघर्ष उसकी मृत्यु का प्रतीक बनेगा ।[95] अशोक मेहता ,[96] नरेन्द्रदेव[97] और आचार्य कृपलानी[98] ने मार्क्स के संघर्ष की मूलभूत मान्यताओं पर प्रकाश डाला है । मार्क्स का विचार है कि प्रत्येक युग में अर्थोपार्जन के कोई न कोई प्रमुख साधन होते है और जिस वर्ग का उन साधनों पर आधिपत्य होता है वही वर्ग समाज में शक्तिशाली वर्ग होता है और उसी के हाथों में राजनीतिक शक्ति होती है । तथा दूसरे साधनहीन वर्ग उसके अधीन होते है । प्राचीन काल में स्वामी और दास, मध्यकाल में सामन्त और कृषक तथा आधुनिक युग में पूंजीपति औ सर्वहारा दो विरोधी वर्ग संघर्षरत है । मार्क्स वर्ग संघर्ष को समाज परिवर्तन का साधन मानता है ।[99]

मार्क्स का मत है कि वर्गो के स्वरुप में काल के अनुसार चाहे परिवर्तन होता रहे लेकिन समाज में सदैव दो वर्ग मौजूद रहे है ।एक वर्ग साधनों का स्वामी तथा दूसरा साधनहीन सर्वहारा ।[100] एक शोषक वर्ग होता है तथा दूसरा शोषित वर्ग, दोनों सदैव एक दूसरे के विरोध में खडे होकर कभी प्रत्यक्ष तथा कभी परोक्ष रुप से संघर्ष करते रहते हैं ।

कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरुप सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व तथा वर्गहीन समाज की कल्पना की थी ।लेकिन मार्क्स की इस कल्पना से उसके द्वन्दात्मक सिद्धांत का साम्य

94 - मार्क्स व एंगेल्स-संकलित रचनाएं,भाग 4, पृष्ठ 91
95 - हेराल्ड जे0 लास्की-कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो, सोशलिस्ट लैण्डमार्क, पृष्ठ 111
96 - अशोक मेहता-स्टडीज इन सोशलिज्म, पृष्ठ 120
97 - नरेन्द्र देव - राष्ट्रीयता और समाजवाद
98 - जे0 बी0 कृपलानी-वर्ग संघर्ष, पृष्ठ 2-3
99 - एव0 डब्ल्यू लैडलर-सोशल इकोनामिक. मूवमेंट, पृष्ठ 162-163
100 - कार्ल मार्क्स-कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र पृष्ठ 33-34

किस प्रकार किया जाय । मार्क्स ने द्वन्दात्मक तत्व की कल्पना की, दूसरी ओर वर्गहीन समाज का आदर्श प्रस्तुत किया । इन दोनों सिद्धांत में विरोधाभाष है ।[101]

अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत [102]

मार्क्स के मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के मूल्य के सिद्धांत से प्रभावित है । मार्क्स ने पूंजीवाद के विकास और सामाजिक परिणामों की व्याख्या की है, इसमें उसकी मुख्य बात उसका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है जिसे उसने श्रम सिद्धांत के आधार पर स्थिर किया है । अपनी पुस्तक "दास कैपिटल" में मार्क्स ने लिखा है कि किसी तैयार माल का विनिमय मूल्य या बाजार में प्राप्त होने वाला मूल्य वह श्रम है जो उस वस्तु के तैयार करने में और विक्री योग्य बनाने में लगाया जाता है अर्थात् पूंजीपति ऐसी वस्तु तैयार करवाता है जिसकी कीमत बेचने पर उस व्यय से अधिक होती है जो उसने कारखाने को चलाने, रखने और श्रमिकों को उनका पारिश्रमिक देने में किया होता है अर्थात् ,"उत्पादित वस्तु के विनिमय- अर्थ और श्रमिक को दिये जाने वाले श्रम के मूल्य का यह अन्तर ही अतिरिक्त अर्थ कहा जाता है ।" अतिरिक्त अर्थ का जन्म श्रमिक के परिश्रम के बाद होता है । लेकिन इसे पूँजिपति जो उसे काम पर लगाता है, स्वयं हड़प लेता है, वस्तुतः अतिरिक्त मूल्य वह श्रम है जिसका पूँजिपति कोई मूल्य नहीं देता है ।[103] वास्तव में यह अतिरिक्त मूल्य श्रमिकों को मिलना चाहिएं किन्तु पूँजीपति श्रमिकों की निर्धनता का लाभ उठाकर इस अतिरिक्त मूल्य को लेकर दिन प्रतिदिन पूँजीपति होता जाता है । और श्रमिकों को पेटभर भोजन नहीं मिलता है, उसी कारण पूँजिपति वर्ग और श्रमिक के मध्य घृणा की भावना बढ़ती जाती है और वर्ग संघर्ष निरंतर जारी रहता है ।[104] इस सिद्धांत के अनुसार मार्क्स पूँजिपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण के औचित्य को सिद्ध करता है।[105]

---

101 - सी0 ई0 एम0 जोड- मार्डन पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 44

102 - इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में अंग्रेज विचारक विलियम पेरी ने किया था, बाद में एड्म स्मिथ, और डेविड I रकार्डो ने इसमें संशोधन किये, अलैक्जेण्डर ग्रे-दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 309

103 - सी0 ई0 एम0 जोड़- आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत प्रवेशिका (अम्बादत्त पन्त), पृष्ठ 37

104 - कोकर- आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 50, वेपर -राजदर्शन का इतिहास, पृष्ठ 214

105 - कार्ल मार्क्स -पूंजी, खण्ड, 1 पृष्ठ 238

इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्क्स से पूर्व कल्पनावादी विचारकों ने जिस समाजवादी चिन्तन का प्रारम्भ किया था वह अपनी शिथिलता के कारण असफल हो गया, परन्तु मार्क्स ने अपने भाषणों लेखों और वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा समाजवादी चिन्तन को एक नया जीवन प्रदान कर दिया ।उसने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र के प्रकाशन, सम्मेलनों तथा सभाओं के आयोजनों द्वारा श्रमिकों में एक नये उत्साह और एक असीम उत्तेजना का संचार कर दिया । इसके बाद समाजवादी दर्शन निरन्तर विकासमान होता गया ।

ब्लादिमीर इलियच लेनिन (1870-1924 ई0)

मार्क्स के बाद समाजवादी चिन्तन के विकास में लेनिन का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । लेनिन की महत्ता इस बात में निहित है कि उसने रुस के सन्दर्भ में मार्क्स के विचारों की व्याख्या की तथा उन्हें रुस की परिस्थितियों के अनुरुप बनाया ।[106] स्टालिन ने लिखा है कि "लेनिन ने मार्क्सवाद को आधुनिक रुप प्रदान किया । उसने मार्क्स के पूंजीवादी समाज के विकास को अवलोकित करके और उन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, जिनका मार्क्स ने केवल प्रारम्भ ही देखा था । उसकी नीति और सिद्धांत का पुर्नस्थापना किया ।[107] 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रुस में सिद्धांतों के बीच यह विवाद का विषय था कि रुस में पूँजीवादी व्यवस्था है या नहीं वहाँ के कई विचारकों के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था रुस के हितों के अनुरुप नहीं थीं ।लेनिन ने अपनी पुस्तक "दि डेवलपमेन्ट आफ कैपिटलिज्म" में रुस की इस व्यवसथा का विश्लेषण किया और पूँजीवादी व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है कि "यह वह व्यवस्था है जिसमें न केवल उत्पादित वस्तुओं का क्रय -विक्रय किया जाता है,वरन मानव श्रम भी क्रय-विक्रय की वस्तु बन जाती है" ।उस रुस में भी मानवश्रम का क्रय-विक्रय किया। जा रहा था, इसी दृष्टि से उस समय रुस भी एक पूंजीवादी देश था ।[108]

किसी भी देश की वास्तविक परिस्थितियों के सन्दर्भ में लेनिन ने मार्क्स के विचारों के परीक्षण का पहला प्रयास किया और रुस में एक अस्थिर पूँजीवादी शासन होते हुए भी उसने वहाँ

106 - स्टालिन-फाउन्डेशन आफ लेनिनिज्म, पृष्ठ 3
107 - नील हार्डिग-लेनिन के राजनीतिक विचार, पृष्ठ 98
108 - नील हर्डिंग- लेनिन के राजनीतिक विचार, पृष्ठ 81

पर समाजवादी क्रान्ति को सफल बनाया ।[109] इतना ही नहीं लेनिन ने एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के पिछड़े हुए देशों के लिए भी मार्क्सवाद की स्थापना का पथ -प्रशस्त कर दिया और उन्हें सर्वहारा क्रान्ति करने की एक सशक्त प्रेरणा प्रदान की ।[110]

20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में एडवर्ड बर्नस्टाइन जैसे संशोधनवादियों ने इस प्रश्न को उठाया कि मार्क्स की भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध नहीं हुई, अतः मार्क्स के विचारों में संशोधन की आवश्यकता है । संशोधनवादियों के मतानुसार मार्क्स ने ये भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद का निकट अन्त था लेकिन वास्तव में पूंजीवाद के अन्त होने के कोई लक्षण नहीं थें । लेनिन ने संशेधनवादियों के इस विचार को स्वीकार नहीं किया ।लेनिन के अनुसार पूंजीवाद का अन्त अवश्य होगा । और मार्क्स की भविष्यवाणी सिद्ध होगी । लेनिन के अनुसार पूँजीवाद के विकास की वर्तमान अवस्था साम्राज्यवाद की अवस्था है । यह पूँजीवाद की सबसे विकसित अवस्था है । इसके बाद पूँजीवाद का विनाश होगा ।[111] इस प्रकार लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों में पूरी आस्था प्रकट की,तथापि उसने मार्क्सवादी चिन्तन में उसने संशोधन अवश्य किये ।[112] लेनिन ने संशोधन वादियों द्वारा दबाये गये मार्क्स के सिद्धांतों का पुनरुद्धार किया ।[113] इस अर्थ में लेनिनवाद मार्क्स के मार्क्सवाद का विस्तार है ।[114] इस प्रसंग में स्टालिन का महत्वपूर्ण वाक्य उद्धृत किया जा सकता है कि "लेनिनवाद साम्राज्यवाद और श्रमिक क्रान्ति के युग का मार्क्सवाद है ।[115]

मार्क्सवाद के विकास में लेनिन का विशिष्ट अनुदार दल सम्बन्धी सिद्धांत है [116] अपनी पुस्तक "राज्य व क्रान्ति" में लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रुप में विशद रुप से विचार किया है ।मार्क्स के विचारों में इतने विस्तार से विचार नहीं मिलते हैं । कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों में वर्ग चेतना के निर्माण पर अधिक जोर दिया तो लेनिन ने दलीय संगठन को, उसका विचार था कि

---

109 - हिस्ट्री आफ कम्युनिस्ट पार्टी आफ द सोवियत यूनियन, पृष्ठ 209 कोकर-रीसेन्ट पोलिटिकल थाट, पृष्ठ 195

110 - वही पृष्ठ, 216

111 - लेनिन-इम्पीरियलिज्म, द हाइयेस्ट स्टेज आफ कैपिटलिज्म, पृष्ठ 241

112 - सेबाइन- ए हिस्ट्री आफ पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 748

113 - लेनिन- संकलित रचनाएं, भाग 3, पृष्ठ 135

114 - अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 460

115 - स्टालिन- फाउण्डेशन आफ लेनिनिज्म, पृष्ठ 14

116 - डेविड मैकलेनन-मार्कसिज्म आफटर मार्क्स, पृष्ठ 87-90, नील हार्डिंग-लेनिन के राजनीतिक विचार, पृष्ठ 138-158

कोई भी क्रान्ति एक सुदृढ़ और संगठित दल सेना के बिना संभव नहीं । लेनिन पार्टी की सदस्यता सीमित रखने के पक्ष में था उसके अनुसार श्रमिक वर्ग के सभी सदस्यों में इसकी क्षमता नही होती है कि वह वर्ग चेतना का पूर्ण विकास कर सके, अतः दल के नेतृत्व का यह कर्त्तव्य है कि वह वर्ग चेतना के विकास में सहायक हो । उसका यह विश्वास था कि श्रमिक वर्ग में दल के नेतृत्व द्वारा वर्ग चेतना का विकास किया जा सकता है। मार्क्स ने साम्यवादी आन्दोलन को श्रमिक वर्ग के लिए छोड़ दिया था । लेकिन लेनिन ने ऐसे दल के निर्माण पर जोर दिया जिसका सैनिक अनुशासन हो, एवं जो सर्वहारा वर्ग का केवल क्रान्ति के दिनों में ही वे नेतृत्व न करें बल्कि इसके उपरान्त भी श्रमिक सरकार बनाकर क्रान्ति के शत्रुओं का सफाया कर दे । इस प्रकार लेनिन ने दल सम्बन्धी सिद्धांत को लेकर मार्क्सवाद में सुधार किया ।[117]

लेनिन के अनुसार क्रान्ति का अर्थ[118] केवल शक्ति का एक वर्ग से दूसरे वर्ग को स्थानान्तरण नहीं हैं, बल्कि शक्ति का एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का रास्त है क्योंकि इसमें श्रमिक अपना शासन स्वयं चलाते हैं । लियो ट्रॉट्स्की के अनुसार एक हाथ से दूसरे हाथ में शक्ति के जाने का मतलब यह नहीं है कि एक नयी शक्ति बन जाती हैं, बल्कि इस शक्ति के प्रयोग करने का अधिकार उस व्यकित को दे दिया जाता है जो श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है न कि श्रमिक को दिया जाता है ।सन् 1917 ई0 में रुसी क्रान्ति का ट्रॉट्स्की एवं लेनिन ने नेतृत्व किया और साम्यवादी दर्शन को व्यावहारिक दृष्टि से पूर्ण बनाने का प्रयास किया । लेनिन ने मार्क्स के सपनों के अनुसार समाज स्थापित करने के लिए क्रान्ति को अत्यन्त आवश्यक बताया । लेनिन ने उन परिस्थितियों का पुनः स्पष्टीकरण दिया जिनके आधार पर किसी भी देश में क्रान्ति हो सकती थी, उसके अनुसार समाजवादी क्रान्ति के लिए आवश्यक है-

1. देश में दृढ़ विचार वाले क्रान्ति की भावना से सम्पन्न लोग हों, जो अपने ध्येय के प्रति सचेत रहें ।
2. इन क्रान्तिकारियों को अधिकांश मजदूर वर्ग की पूर्ण सहायता एवं समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

---

117 - डेविड मैकलेनन मार्क सिज्म , आफ्टर मार्क्स पृष्ठ 86-97

118 - नील हार्डिंग- लेनिन के राजनीतिक विचार, पृष्ठ 21-95

3. क्रान्ति का विगुल उस समय बजाया जाना चाहिए जब पूंजीवादी व्यवस्था कमजोर हो तथा परस्पर संघर्ष में व्यस्त रहे ।

इस प्रकार लेनिन ने मार्क्स के प्रारम्भिक कृतियों में पाये जाने वाले उग्र क्रान्तिकारी विचारों का पुनरुद्धार किया । यह कथन कि,"साम्राज्यवाद पूँजीवाद की अन्तिम अवस्था है " लेनिन की ऐतिहासिक उक्ति हो गयी । सम्भवतः यह मार्क्सवाद को उसकी महती देन है ।

वास्तव में लेनिन का स्थान एक विचारक और कर्मठ व्यक्ति के रुप में इतिहास में सुरक्षित है । आधुनिक साम्यवादी सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही उसका ऋणी है । उसने मार्क्सवाद को धरातल पर उतारा, इसकों जीवन और स्फूर्ति प्रदान की । उसकी शक्ति एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने में निहित थी और इसे प्राप्त करने के लिए वह कठोर उग्र एवं कठिबद्ध था ।[119] उसके सहयोगी ट्राटस्की ने उसे बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीयवादी माना है । उसके अनुसार लेनिन का अन्तर्राष्ट्रवाद ऐतिहासिक घटनाओं का व्यवहारिक मूल्यांकन है तथा यह अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों हेतु अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक क्रियान्वित भी है । रुस और उसका भाग्य इस ऐतिहासिक संघर्ष में केवल एक तत्व है और इसकी उपलब्धि पर ही समस्त मानवता का भाग्य निर्भर करता है ।[120]

लेनिन ने निम्नलिखित सुधार मार्क्स के सिद्धांतों में किये-

1. मार्क्स के अनुसार पूँजीवाद की चरम अवस्था के बाद ही साम्यवादी क्रान्ति सम्भव है लेकिन लेनिन ने उसे क्रान्ति के लिए आवश्यक नहीं समझता था ।उसका प्रत्यक्ष प्रमाण रुस है, जो औद्योगिक दृष्टि से अविकसित देश था, में साम्यवादी क्रान्ति सम्पन्न हुई।

2. मार्क्स की आर्थिक नियतिवाद (इकोनामिक डिटरमिनिज) के अनुसार पूँजीवाद आन्तरिक विरोधों के माध्यम से पतन की ओर अग्रसर होगा यह पतन स्वाभाविक है, इसके लिए प्रयास किया जाय या न किया जाय । मार्क्स के ठीक विपरीत लेनिन का विचार है कि क्रान्ति आर्थिक घटनाओं के माध्यम से स्वतः नहीं आयेगी। उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है।

3. मार्क्स की घोषणा के अनुसार साम्यवादी क्रान्ति के बाद उत्पादन के साधनों-भूमि तथा उद्योग पर राज्य का स्वामित्व होगा, लेकिन लेनिन ने क्रान्ति के बाद.भूमि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित

---

119 - अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 458

120 - ट्राटस्की, लेनिन- दि पोलिटिकल थाट इन पर्सपेक्टिव बाइ बर्नस्टीन, पृष्ठ 563

नहीं किया ।इससे क्रान्ति की भावनाओं के प्रति अविश्वास होना स्वाभाविक था । लेकिन देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कुछ बातों में पूँजीवादी व्यवस्था से समझौता करने के लिए नवीन आर्थिक नीति (न्यू इकोनामिक पालिसी) को अपनाया ।

4. मार्क्स क्रान्ति के बाद संक्रमण काल तक सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता को आवश्यक मानता था ।उसके बाद शासन का ढांचा लोकतंत्र के स्वरुप को लिए हुए होगा । लेकिन लेनिन उसे अधिनायकता के विरुद्ध शक्ति पर आधारित मानता है ।

5. क्रान्ति की सफलता तथा नेतृत्व सर्वहारा वर्ग करेगा । परन्तु लेनिन ने विचार व्यक्त किया कि श्रमिक वर्ग की प्रवृत्ति श्रमिक संधवाद के माध्यम से अपने अधिकारों तथा आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने की होती है ।ऐसी अवस्था में सर्वहारा वर्ग में विरोध की भावना कुछ कमजोर पड़ जाती है। लेनिन ने क्रान्ति की सफलता के लिए पेशेवर क्रान्तिकारी संगठन का निर्माण किया ।

जोसेफ वी0 स्टालिन (1879-1953 ई0)

स्टालिन ने लेनिनवाद में कुछ संशोधन करके मार्क्सवादी चिन्तन के विकास में एक नई कड़ी जोड़ दी। उसने "एक देशीय समाजवाद" का सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि समाजवाद की स्थापना एक ही देश में सम्भव है ।इस सिद्धांत के बल पर स्टालिन रुस का एक निरंकुश तानाशाह बन गया और उसने रुस को एक सर्वाधिकार पूर्ण राज्य के रुप में परिभाषित कर दिया । स्टालिन का दूसरा सिद्धांत क्रान्ति सम्बन्धी था, वह देशीय समाजवाद का पोषक होकर भी विश्व क्रान्ति की धाराण में गहरी आस्था रखता था ।[121] वह मार्क्स के अनुसार ही क्रान्ति द्वारा समाजवाद लाना चाहता था, परन्तु वह लेनिनवाद के विरुद्ध पूँजीवादी देशों से घिरे देशों में शान्ति पूर्ण ढंग से समाजवाद लाने के पक्ष में था।

माओ-त्से-तुंग (माओ जेदोंग) (1893-1976 ई0)

रुस की साम्यवादी क्रान्ति की सफलता से प्रेरित होकर माओत्सेतुंग ने 1 अक्टूबर 1949 ई0 को चीन में साम्यवादी चीनी गणराज्य की स्थापना की। माओ ने चीन की परिस्थितियों के अनुसार मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों में संशोधन किया ।मार्क्स के समान माओं भी क्रान्ति पर

---

121 - वेपर-पोलिटिकल थाट- पृष्ठ 231

विशेष बल देता था ।वह किसानों द्वारा सशस्त्र क्रान्ति कराकर साम्यवाद की स्थापना करने का इच्छुक था और चीन में उसने कृषक क्रान्ति को ही सफल बनाया था ।[122] माओ का मत था कि क्रान्ति का नेतृत्व श्रमिकों के हाथों में न होकर कृषक वर्ग के हाथ में होना चाहिए ।[123] इस प्रकार माओं ने मार्क्सवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

7-समाजवाद के अन्य रुप-

20वीं शताब्दी में समाजवादी विचारधारा अपने कई रुपों में विकसित हुई ।यद्यपि उन समाजवादी विचारधाराओं को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं ।

. मार्क्सवादी समाजवाद -

मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा सबसे अधिक रुस में विकसित हुआ । रुस में लेनिन तथा स्टालिन ने, मार्क्सवादी विचारधारा में कुछ संशोधन करके उसे रुस की परिस्थितियों के अनुसार कार्य रुप में परिणित किया ।चीन में इसका विकास माओत्सेतुंग के नेतृत्व में हुआ लैटिन अमेरिकन देशों में इसका विकास लियों ट्राट्स्की के नेतृत्व में हुआ । पाश्चात्य देशों में नव मार्क्सवाद का भी विकास हुआ है ।इसके नेताओं में जॉज ल्यूकाच, एंटोनियो ग्राम्सी फ्रांज फैनन आदि विचारक हैं ।

2. प्रजातान्त्रिक समाजवाद

दूसरी विचारधारा प्रजातान्त्रिक समाजवाद के रुप में विकसित हुई ।यद्यपि ये विचारधारा भी मार्क्स से परोक्ष रुप में प्रभावित थी, साथ ही साथ इसने कई दृष्टियों से लोकतान्त्रिक मान्यताओं को स्वीकार किया । विकासवादी समाजवाद के समर्थकों ने लोकतन्त्र को न केवल एक साधन के रुप में माना वरन एक साध्य के रुप में भी माना ।[124] 20वीं शताब्दी के प्रजातान्त्रिक समाजवाद को हम जिन रुपों में पाते हैं उनका विवरण निम्नवत् है-

---

122 - सेलेक्टेड वर्क्स आफ माओत्सेतुंग, खण्ड 1, पृष्ठ 25

123 - चेयरमैन माओत्सेतुंग की विचारोक्तियां, पृष्ठ 88

124 - वर्न्स-आइडियाज इन कनफ्लिक्ट, पृष्ठ 164-168

फेबियनवाद [125] -

इंग्लैण्ड में जार्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, सिडनी ओलिवर और ग्राहम वैलास आदि विचारकों ने 1884 ई0 में रोमन सैनिक "फेबियस" के नाम पर फेबियन सोसाइटी की स्थापना की और 1887 ई0 में यह घोषणा की कि व्यक्तिगत सम्पत्ति और वर्ग संघर्ष का अन्त करके ही जन साधारण को अधिकाधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है।

सितम्बर 1884 ई0 में फेबियन सोसाइटी घोषणा पत्र में कहा गया कि भूमि का राष्ट्रीयकरण करके इस पर व्यक्तिगत अधिकार समाप्त कर दिया जाना चाहिए।[126] सन् 1887 ई0 के घोषणा पत्र में कहा गया है कि फेबियन समाज, समाजवादियों का समाज है। अतः इसका उद्देश्य समाज का नव निर्माण करना है।यह नया संगठन भूमि तथा उद्योग धन्धों को व्यक्तिगत तथा वर्ग स्वामित्व से पृथक कर समाज को उसका स्वामी बनाकर किया जायेगा, जिससे वह सामान्य लाभ के लिए कार्य करे।[127]

फेबियनवादी समाजवाद को युग की सम्पूर्ण संस्कृति से परिपूर्ण मानते हैं। वे समाजवाद की स्थापना संवैधानिक साधनों द्वारा करके पूंजीवाद का अन्त करना चाहते हैं।उनका सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में विश्वास नहीं हैं, वे लोकतन्त्र और समाजवाद को एक दूसरे का पूरक बताकर समाज में व्याप्त शोषण व वर्ग संघर्ष का अन्त करना चाहते हैं।[128]

समष्टिवाद अथवा राज्य समाजवाद-

विकासवादी समाजवाद का दूसरा रुप समष्टिवाद अथवा राज्य समाजवाद है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार, "समष्टिवाद अथवा राज्य समाजवाद वह नीति अथवा सिद्धांत है, जो लोकतान्त्रिक राज्य द्वारा सम्पत्ति के अन्त की अपेक्षा अधिक अच्छे वितरण और

---

125 - फेबियनवाद एक विशुद्ध अंग्रेजी विचारधारा है, जार्ज बर्नार्ड शॉ और सिडनी वेब इस विचारधारा के प्रवर्तक थे और ग्राहम वैलास, एच0 जी0 वेल्स, श्रीमती एनी बेसेन्ट, कार्ल जे0 लास्की, विलियम क्लार्क और जे0 आर0 मेकडानल्ड आदि विद्वानों ने इसका विकास किया। एडवर्ड आर0 पीस की " हिस्ट्री आफ फेबियन सोसाइटी जार्ज बर्नार्ड शॉ की "दि फेबियन सोसाइटी तथ जी0 डी0 एच0 कोल की "फेबियन सोशलिज्म नामक पुस्तकों में फेबियन बाद के सम्बन्ध में प़र्याप्त सामग्री मिलती है।

126 - बर्नार्ड शॉ का घोषणा पत्र (सितम्बर 1884 ई0)

127 - कोकर- आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 110

128 - बार्कर- पोलिटिकल थाट इन इंग्लैण्ड, पृष्ठ 16, बर्न्स- आइडियाज इन कनफ्लिक्ट, पृष्ठ 67-68 कोकर-रीसेन्ट पोलिटिकल थाट, पृष्ठ 98-107

उत्पादन में विश्वास करता है ।समाजशास्त्र के विश्वकोष के अनुसार " समष्टिवाद व्यक्तिवाद के विरोधी सिद्धांतों का सामान्य नाम है "।[129] इस विचारधारा के समर्थक राज्य के सहयोग से समाजवाद लाना चाहते हैं। राज्य समाजवादी मार्क्स के समान राज्य को एक आवश्यक बुराई तथा उद्योगों को राज्य के नियन्त्रण में रखना चाहते हैं ।समष्टिवाद का अभिप्राय समाज से संबंधित है।

समष्टिवादी व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देते हैं ।वे उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में हैं । वे पूंजीवाद को समूल नष्ट करना नहीं चाहते, अपितु पूंजीपतियों की सम्पत्ति छीनकर उन्हें उचित मुआवजा भी देना चाहते हैं ।उनका मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में विश्वास नहीं है, वे समाज के समस्त वर्गो का हित करने के पक्ष में है । राज्य समाजवादी लोकतान्त्रिक तथा वैधानिक उपायों से समाजवाद की स्थापना करना चाहते है ।जोड ने इस विचारधारा का समर्थन किया है ।[130]

समष्टिवाद के मूलभूत आधार जर्मन समाजवाद तथा अंग्रेजी समाजवाद (फेबियनवाद) है । समष्टिवाद को लोकतान्त्रिक समाजवाद भी कहते हैं । क्योंकि यह वाद लोकतान्त्रिक तरीके से भूमि तथा उद्योग पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त करके उन्हें राज्य के अधिकार में लाना चाहता है । यह वह नीति अथवा सिद्धांत है जो केन्द्रीय प्रजातान्त्रिक सत्ता द्वारा आजकल की अपेक्षा श्रेष्ठतम वितरण तथा उसके अधीन श्रेष्ठतम उत्पादन की व्यवस्था करना चाहता है ।[131]

इस विचारधारा के सिद्धांत और स्वरुप मार्क्सवाद आदि अन्य वादों के समान स्पष्ट और सुनिश्चित नहीं है ।इस विचारधारा के मानने वालों को उदार (लिबरल), उदार लोकतन्त्रीय (लिबर लडेमोक्रैट), सामान्य जनता के हित पर बल देने वाले तथा प्रगतिवादी कहते है ।[132] उनका कोई संगठित आन्दोलन नहीं है । इनके सिद्धांतों अथवा मत का कोई निश्चित संस्थापक नहीं है और इनके सुनिश्चित सिद्धांत नहीं है ।वे सामाजिक न्याय, उदारवाद, आर्थिक उदारवाद, आर्थिक लोकतन्त्र, तथा औद्योगिक लोकतन्त्र के सिद्धांतों पर बल देते है ।

---

129 - बर्न्स-आइडियाज इन कनफ्लिक्ट, पृष्ठ 161-164

130 - सी0 ई0 एम0 जोड़-इन्ट्रोडक्शन टु माडर्नपोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 42

131 - सी0 ई0 एम0 जोड-माडर्न पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ 54

132 - कोकर- रीसेन्ट पोलिटकल थाट, पृष्ठ 595

पुनर्विचारवाद अथवा संशोधनवाद-[133]

विकासवादी समाजवाद का एकरुप पुनर्विचारवाद है, जिसे संशोधनवाद भी कहा जाता है।[134] जर्मन विचारक एडवर्ड बर्नस्टाइन आरम्भ में मार्क्स का अनुयायी था,किन्तु इंग्लैण्ड तथा जर्मनी की परिस्थितियों से प्रभावित होकर उसने कुछ दृष्टियों से मार्क्स के विचारों में संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया। 20वीं शताब्दी के वर्षो में उसके विचारों के फलस्वरुप एक समाजवादी आन्दोलन हुआ जिसे संशोधनवाद का नाम दिया गया। बर्नस्टाइन ने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत और इतिहास की भौतिकवाद की आलोचना की और मार्क्स के पूंजीवादी व्यवस्था के सिद्धांत तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आदि सिद्धांतों में संशोधन किया।[135]

वह उद्योगों को समाज के नियन्त्रण में रखकर लोकतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था।[136] इस विचारधारा के समर्थकों में जीन जोरस, एडवर्ड अनासीले, विस्लोलाटी, कार्ल ब्रेटिंग तथा तुगन बेरोनस्की आदि प्रमुख थे।[137] कोकर ने लिखा है कि संशोधनवाद फेबियनवाद और मार्क्सवाद दोनों के मध्य की विचारधारा है वे क्रान्ति को प्रारम्भिक साधन मानकर अन्तिम साधन मानते है।[138]

श्रम संघवाद[139]

आधुनिक युग में श्रमिक संघवाद से अभिप्राय इन क्रान्तिकारियों के सिद्धांत एवं साधनों से है, जो पूँजीवाद को नष्ट करने तथा समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए औद्योगिक संघों

---

133 - जिन विचारकों ने मार्क्सवाद में संशोधन किया उनमे जर्मनी के बर्नस्टाइन के अतिरिक्त फ्रांस के जीन जारी, इटली के कियोलाटी, बेल्जियम के एडवर्ड अनसीले और रुस के केरोनस्की के नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं।लैडलर- एहिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट, पृष्ठ 294

134 - बर्नस्टाइन की मूल पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद सन् 1909 मे ईवोल्यूशनरी सोशलिज्म के नाम से इडिथ सी0 हार्वे द्वारा प्रकाशित हुआ। संशोधनवादियो की अन्य रचनाएं सन् 1906 और 1910 मे क्रमश : मिर्लेड मिण्टर्न और रेडमाउण्ट द्वारा "स्टडीज इन सोशलिज्म," माडर्न सोशलिज्म, इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेन्ट शीर्षकों से अनुदित हुई।

135 - दि प्रिकसर एडवर्ड बर्नस्टाइन इन रिविनिज्म, लियोबोल्ड लेहेज्ड द्वारा सम्पादित (1962), पृष्ठ 41, अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 404-406

136 - एडवर्ड बर्नस्टाइन-विकासवादी समाजवाद (अंग्रेजी अनुवाद) हूचेज्स, पृष्ठ 8-9

137 - लैडलर- ए हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट, पृष्ठ 296

138 - कोकर-रीसेन्ट पोलिटिकल थाट, पृष्ठ 71

139 - श्रम संघवाद का अंग्रेजी रुपान्तर सिंडीकेलिज्म है, जो फ्रेंच शब्द सिंडीकेट से निकला है। इसका अर्थ श्रम संघ है लेकिन अंग्रेजी में सिंडीकेट शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है।अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 408

की आर्थिक शक्ति का प्रयोग करना चाहते है ।संघवादी वर्ग संघर्ष और श्रमिक वर्ग की सत्ता को ही समाजवाद की स्थापना का मौलिक तत्व मानते हैं ।संघवादी राज्य विरोधी हैं और मार्क्स के समान वे भी राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं ।

श्रम संघवाद का प्रादुर्भाव फ्रांस में हुआ। फ्रांस सरकार की श्रमिक विरोधी नीति से क्षुब्ध होकर वहाँ का श्रमिक वर्ग असंतोष से भर उठा और वह राज्य को घृणा की दृष्टि से देखने लगा। संघवादियों ने संसदीय शासन और प्रतिनिधि शासन की कटु आलोचना की और उन्होंने श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनायी ।संघवादी क्रान्तिकारी कार्यक्रम रखते हैं और वे हड़ताल,तोड़ फोड़, बहिष्कार आदि साधनों द्वारा क्रान्ति लाकर समाजवाद की स्थापना करना चाहते है ।[140] श्रम संघवाद के प्रमुख नेताओं में सोरल (1847-1922) तथा पिलेव्यिर के नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं

श्रम संघवाद श्रमिक संघों का स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर स्थापित करना चाहता है ।[141] संघवादी प्रत्यक्ष कार्यवाही एक राज्यविहीन, शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते है ।[142] लैडलर ने लिखा है कि-"20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में श्रम संघ वादियों ने समाजवादी विचारधारा पर व्यापक प्रभाव डाला ।उन्होंने तत्कालीन संसदीय शासन के दोषों को उजागर किया और राजनीतिज्ञों को श्रमिकों के कष्टो की ओर आकर्षित किया ।[143]

श्रेणी समाजवाद

श्रेणी समाजवाद,श्रेणी समाजवाद का अंग्रेजी संस्करण है । इसे ब्रिटिश फेबियनवाद और फ्रांसीसी संघवाद का बुद्धिजीवी शिशु कह सकते हैं ।[144] श्रेणी समाजवाद के प्रमुख प्रवर्तक ऐ0 जे0 पेण्टी, ए0 आर0 आरेन्ज, एस0 जी0 हाब्सन तथा जी0 डी0 एच0 कोल हैं । श्रेणी समाजवाद समष्टिवाद और श्रम संधवाद दोनों की त्रुटियों को दूर कर मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है ।[145]

---

140 - सेबाइन- ए हिस्ट्री आफ पोलिटिकल थ्योरी ,पृष्ठ 582 , हैरी डब्ल्यू लैडलर- सोशल एण्ड इकोनामिक मूवमेण्ट्स, पृष्ठ 632

141 - लुडविग वान मिजेज- सोशलिज्म, पृष्ठ 270 ,महादेव प्रशाद शर्मा-आधुनिक राजनीति के विभिन्न वाद, पृष्ठ 230

142 - अलैक्जेण्डर ग्रे - दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 417

हैरी डब्ल्यू लैडलर- सोशल एण्ड इकोनामिक मूवमेण्ट्स, पृष्ठ [illegible]

- रोक्को-कन्टेम्प्रेरी पोलिटिकल थाट आन ओल्ड इंग्लैण्ड, पृष्ठ 150

145 - हैरी डब्ल्यू लैडलर-सोशल एण्ड इकोनामिक मूवमेन्ट्स, पृष्ठ 610

श्रेणी समाजवाद का प्रवर्तक इंग्लैण्ड निवासी आर्थर जोसेफ पेन्टी था। लेकिन कोल ने श्रेणी समाजवाद को लोकप्रिय बनाया। कोल का मत था कि उद्योग धन्धों के संचालन पर श्रमिको का नियन्त्रण होना चाहिए, लेकिन वह उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं था और उत्पादन कार्य में राज्य के हस्तक्षेप का विरोधी था।[146] श्रेणी समाजवादी हाब्सन का कहना था कि श्रमिक संघों को समाज की आर्थिक व्यवस्था पर नियन्त्रण करके उद्योगों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।[147]

सन् 1915 में श्रेणी समाजवाद को व्यवहारिक रुप देने के लिए आक्सफोर्ड के दो विद्वानों विलियम मेलोर और मोरिस रेकिट ने एक- "नेशलन गिल्डस लीग" की स्थापना की। उसका उद्देश्य मजदूरी पद्धति को समाप्त करके उद्योगों में श्रेणियों द्वारा स्वशासन की स्थापना करना था।[148] लेकिन इस लीग को विशेष सफलता न मिल सकी और श्रेणी समाजवादी आन्दोलन अल्प काल में ही समाप्त हो गया। लैडलर, ने लिखा है कि "पूँजीवादी व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक जटिल समाज में मध्यकालीन श्रेणी व्यवस्था को लागू करना असम्भव सा है।मध्ययुग में ही गुटबाजियों के कारण श्रेणी व्यवस्था का पतन हो गया, तो वर्तमान युग में गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं हो सकता है।[149] इस प्रकार श्रेणी समाजवादी विचारधारा अपनी अव्यवहारिकता के कारण अल्प समय तक ही जीवित रह सकी तथपि इसने इंग्लैण्ड और अमेरिका की राजनीति को अवश्य प्रभावित किया।

गिल्ड समाजवादी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीकों में एक मत नहीं है,। कुछ लोग कहते है कि उस अन्तिम व्यवस्था में वैध उपायों से ही शेष स्वत्व श्रमिकों के हाथ में आ जायेंगे,दूसरे लोगो का विचार है कि अनुकूल स्थिति में क्रान्तिमय उपायों से काम लेना होगा और उनके लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए।[150] कुछ गिल्ड समाजवादी सीधे उपायों का पक्ष लेते है लेकिन कोल का विचार है कि-शीघ्रता से क्रान्ति लाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है-

---

146 - अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 451

147 - कोकर-रीसेन्ट पोलिटिकल थाट, पृष्ठ 272

148 - अलैक्जेण्डर ग्रे- दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन, पृष्ठ 257

149 - हैरी डब्ल्यू लैडलर-सोशल एण्ड इकोनामिकल मूवमेन्ट्स, पृष्ठ 658

150 - डा0 सम्पूर्णानन्द- समाजवाद, पृष्ठ 295

विकासवाद के मार्ग द्वारा उन सब शक्तियों को दृढ़ करना जिससे आने वाली क्रान्ति गृह युद्ध न होकर समाज में क्रियाशील प्रवृत्तियों का एक अन्तिम परिणाम न प्राप्त तथ्य सा मालूम हो ।150 [151]

लोकतान्त्रिक समाजवाद

समाजवाद के जिस रुप को 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक मान्यता मिली, उसे लोकतान्त्रिक समाजवाद कहा जाता है । समाजवाद का यह रुप उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है । यह व्यक्तिवाद और पूंजीवाद के स्थान पर संसदीय प्रणाली द्वारा एक नयी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता है ।लोकतान्त्रिक समाजवाद स्वस्थ प्रतियोगिता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय आर्थिक समानता तथा विश्व-बन्धुत्व का पोषक है ।इसमें नियोजित अर्थ व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाता है ।[152] लोकतान्त्रिक समाजवाद भी इंग्लैण्ड की देन है और इसके प्रवर्तकों में आर0 क्रासमैन, फ्रांसिस विलियम,आर0 एच0 टानी, इवान डार्विन, क्लीमेण्ट एटली क्रासमैन आदि विशेष रुप से उल्लेखनीय है ।[153]विश्व के अनेक देशों में लोकतान्त्रिक समाजवाद के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण किया गया हैं ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद के चिन्तन का स्वरुप विविध पक्षीय है। यह अधिनायकवाद और फासीवाद का विरोध करता है और लोकतान्त्रिक उपायों द्वारा समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का हामी है ।[154] लोकतान्त्रिक समाजवादी सीमित व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने के समर्थक हैं ।और आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में हैं ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद आज एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन बन गया है और भारत में भी यही समाजवाद विकासमान है ।भारतीय समाजवादी जय प्रकाशनारायण अपने समाजवादी दल का लक्ष्य ही लोकतान्त्रिक समाजवाद लाना बताते है ।[155]

डा0 राममनोहर लोहिया कहते हैं कि लोकतान्त्रिक समाजवाद तानाशाही साम्यवादी का विरोधी है ।[156] आचार्य नरेन्द्र देव समाजवाद और लोकतन्त्र को एक दूसरे का पूरक मानते है ।[157]

---

151 - जी0 डी0 एच0 कोल-गिल्ड सोशलिज्म, पृष्ठ, 183,187

152 - इवान डार्विन-पालिटिक्स आफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म,पृष्ठ 135

153 - एबन्सटीन-मास्टर्स आफ पोलिटिकल थाट पृष्ठ 581-582

154 - पं0 जवाहरलाल नेहरु-कुछ पुरानी चिट्ठियां, पृष्ठ 199

155 - जय प्रकाश नारायण-डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पृष्ठ 4

इस प्रकार समाजवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन बन गया । आज हमे समाजवाद के अनेक रुप दिखाई पड़ते हैं ।समाजवाद के इन विभिन्न रुपों में कुछ दृष्टियों से समानताएं दिखाई पड़ती है जैसे ये सभी शोषण विहिन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, श्रम की महत्ता को महत्व देते हैं तथा श्रम के उचित उपयोग पर बल देते हैं तथा समाज में समानता, स्वतन्त्रता,भ्रातृत्व जैसे मूल्यों का विकास करना चाहते है, ताकि सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार समाज की सम्पूर्ण उपलब्धियों का उपभोग कर सके, और एक आदर्श समाज की स्थापना हो सके ।

156 - डा0 राम मनोहर लोहिया- मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म ,पृष्ठ 895

157 - नरेन्द्र देव- राष्ट्रीयता और समाजवाद पृष्ठ 142

अध्याय—२

भारत में समाजवाद का उदय, प्रभाव व विकास

अध्याय–2

भारत में समाजवाद का उदय, प्रभाव व विकास

1- भारतीय समाजवादी चिन्तन का विकास

भारत में समाजवाद की संकल्पना अति प्राचीन है। वैदिक ग्रन्थों में कहा गया है कि सभी प्राणियों की सहज समानता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुत्व सामाजिक संगठन का मूलाधार होती है।[1] बौध ग्रन्थ भी मानव एकता और भ्रातृत्व पर बल देते हैं।[2] महाभारत में भी इस प्रकार के विचार मिलते हैं कि प्रारम्भिक काल में व्यक्तियों के मध्य भेदभाव की भावना का अभाव था, तथा उसे धर्म के अनुरुप माना गया है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में भी समाजवादी विचारों के मूल तत्व विद्यमान थे फिर भी आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के दर्शन के रुप में समाजवाद भारत में पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरुप ही विकसित और लोकप्रिय हुआ।[3]

आधुनिक भारतीय समाजवाद की झलक सर्वप्रथम श्री अरविन्द द्वारा 1893 ई0 में प्रकाशित लेखों में मिलते हैं।[4] इन लेखों में उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति की आलोचना करते हुए देश के सर्वहारा वर्ग की दशा सुधारने की अपील की थी।

लाला लाजपत राय को ऐसा प्रथम भारतीय माना जा सकता है, जिन्होंने समाजवाद तथा बोल्शेविकवाद के सम्बन्ध में कुछ लिखा।[5] तथापि यह निर्विवाद है कि उन्होंने पाश्चात्य बोल्शेविकवाद के प्रति सहानुभूति का रुख नहीं अपनाया था।[6] लाला लाजपत राय ने सन् 1920

---

1 - छान्दोग्य उपनिषद् 5/11/5 वैदिक ग्रन्थ

2 - बौध ग्रन्थ- धम्मपद

3 - महाभारत, शक्तिपर्व-59/14

4 - अरविन्द घोष-पत्रिका 'इन्दु प्रकाश' तथा लेख "पुरानों के बदलें नये दीपक 1893 ई0

5 - लाला लाजपत राय-दि फ्यूचर आफ इण्डियन पालिटिक्स, पृष्ठ 104

6 - मानवेन्द्र नाथ राय मेमायर्स-इनका मत है कि लाला लाजपत राय एक बुर्जवा राजनीतिज्ञ थे और उन्हें समाजवाद से कोई सहानुभूति नहीं थी।

में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का सभापतित्व भी किया था ।[7] भारतीय पुनर्जागरण के समय स्वामी विवेकानन्द ने "समाजवाद" के अर्थ को स्पष्ट किया ।[8] तथा बाद में डा0 सम्पूर्णानन्द ने वेदान्ती समाजवाद की वकालत की ।[9] सन् 1921-23 में मानवेन्द्र नाथ राय ने "इण्डिया इन ट्रांजीशन" और "इण्डियन प्रोब्लम" नामक पुस्तकें लिखीं। इन रचनाओं में उन्होंने कांग्रेस पर भारतीय पूंजीपतियों के प्रभुत्व की कटुआलोचना की । इस समय देशबन्धु चितरंजन दास ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में सन् 1917 की साम्यवादी क्रान्ति को विश्व की एक महान घटना बताया, तथपि उन्होंने साम्यवादियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं व्यक्त की, फिर भी उन्होंने भारत में श्रम संघ या ट्रेड यूनियन आन्दोलन को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

सन् 1926 में पहली बार पं0 मोती लाल नेहरु और पं0 जवाहर लाल नेहरु सोवियत संघ की यात्रा पर गयें पं0 जे0 एल0 नेहरु ने रुस की नई आर्थिक नीति और 1921 ई0 तक उसकी शानदार उपलब्धियों का उल्लेख अपनी पुस्तक 'सोवियत रशिया' में किया और बाद में उसने "अपनी आत्म कथा"[10] और "विश्व इतिहास की झलक"[11] नामक रचनाओं में भी मार्क्स की वैज्ञानिक तथा आर्थिक प्रणाली की काफी प्रसंशा की । मई 1925 में भारत में ***साम्यवादी दल*** की स्थापना हुई। इसी समय से भारत में समाजवादी विचारधारा लोक प्रिय होने लगी।

सन् 1929 ई0 में में पं0 जवाहरलाल नेहरु ने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार समाजवाद संबंधी अपने कार्यक्रम की रुपरेखा प्रस्तुत की ।[12] सन् 1931 में करांची कांग्रेस अधिवेशन में मूल अधिकार संबंधी जो मूल संकल्प पारित हुआ, उसमें भी समाजवादी विचारधारा के बीज निहित थे।[13] सन् 1934 में पं0 नेहरु के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना और सन् 1937 में फैजपुर कृषि कार्यक्रम का निर्धारण समाजवाद की दिशा में महत्वपूर्ण

---

7 - श्री नारायण मल्हार जोशी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है । उन्होंने 1909 में गोखले की सर्वेंट्स आफ इण्डियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और 1917 में बम्बई में "सोशल सर्विस लीग" की नींव डाली

8 - दि कम्पलीट वर्क्स आफ स्वामी विवेकानन्द-जिल्द 5, पृष्ठ 144, (अल्मोड़ा अद्वैत आश्रम)

9 - सम्पूर्णा नन्द- इण्डियन सोशलिज्म

10 - पं0 जवाहर लाल नेहरु-मेरी कहानी, पृष्ठ 48

11 - पं0 जवाहर लाल नेहरु - विश्वइतिहास की झलक, खण्ड 2, पृष्ठ 753

12 - कांग्रेस प्रेसीडेन्शल एड्रेसेज (सं.) खण्ड 2,

13 - अखिलेन्द्र प्रसाद राय- सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 72

अग्रगामी कदम थे ।[14] मई 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना भारत में समाजवाद के संगठनात्मक विकास की एक महत्वपूर्ण घटना थी ।[15] इस दल की स्थापना से बिहार समाजवादी दल (1931 ई0), बम्बई समाजवादी गुट (1934 ई0) आदि अनेक प्रान्तीय संगठनों और गुटों को एक अखिल भारतीय आधार तथा मंच प्राप्त हो गया । देश के प्रमुख समाजवादी नेताओं का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 17 मई 1934 को पटना में आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में हुआ । इस दल की स्थापना में जय प्रकाश नारायण का महत्वपूर्ण योगदान था और यूसूफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन तथा अशोक मेहता ने इस कार्य में अत्याधिक सहायता भी थी ।[16] इस समय से भारतीय समाजवाद तेजी के साथ फलने-फूलने लगा ।

वस्तुत : भारतीय समाजवाद आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्निर्माण की एक योजना के रुप में ही नहीं अपितु साम्राज्यवादी शोषण से मुक्ति एवं राष्ट्रीय आन्दोलन की एक विचारधारा के रुप में विकसित हुआ है ।[17] भारतीय समाजवाद के प्रणेताओं में पं0 जवाहरलाल नेहरु, आचार्य नरेन्द्र देव, जय प्रकाश नारायण, डा0 राम मनोहर लोहिया, डा0 सम्पूर्णनन्द और अशोक मेहता आदि प्रमुख नेता थे ।

2- भारतीय समाजवाद की पृष्ठभूमि

भारतीय समाजवाद की पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन की शोषण नीति में निहित थी ।सन् 1757 ई0 में अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में विजयी होकर भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की और सन् 1857 ई0 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम तक सम्पूर्ण भारत ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया । ब्रिटिश सरकार की शोषण नीति व पक्षपात पूर्ण नीति के विरोध में भारतीयों ने सन् 1857 ई0 में एक सशक्त विद्रोह किया, यद्यपि इस विद्रोह में भारतीयों को सफलता नहीं मिली, फिर भी पाश्चात्य विचारों के देश में आगमन, औद्योगीकरण, संचार व परिवहन के साधनों के विकास के फलस्वरुप भारत में नवजागरण प्रारम्भ हो गया ।

---

14 - पटटाभि सीता रमैया -कांग्रेस का इतिहास, खण्ड 2, पृष्ठ 36, रजनी पाप दत्त - आज का भारत, पृष्ठ 523

15 - डा0 वी0 पी0 वर्मा- आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 418

16 - अशोक मेहता-डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एण्ड स्टडीज इन एशियन सोशलिज्म,

17 - डा0 वी0 पी0 वर्मा- आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 419

महात्मा गाँधी ने लिखा है कि "समाजवाद ही नहीं साम्यवाद भी हर्षोपनिषद के पहले मंत्र में स्पष्ट है । इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है कि जगत में जो कुछ है, वह सब ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए उसके नाम से त्याग करके तू भोग करता जा, किसी धन के प्रति लालसा न रख"[18]

भारतीय विचारक कौटिल्य का राज्य निश्चित रुप से लोक कल्याणकारी था। उनके विचारों में हमें समाजवाद का अभास होता है यद्यपि कौटिल्य के राज्य में सामाजिक संगठन वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है, परन्तु राज्य एवं राजा के कर्त्तव्य पालन के श्रेष्ठता पर बल दिया गया है ।राज्य को समस्त जनों की शिक्षा व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है । वह चाहता था कि राज्य की ओर से समस्त परोपकारी कार्य सम्पादित हों । राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह वृद्धों, अपंगों, असहाय स्त्रियों, अनाथों,रोगियों और दुखियों की सहायता करें।

अतः यह स्पष्ट है कि कौटिल्य के राज्य की अवधाराणा 'कल्याणकारी राज्य' पर आधारित है क्योंकि राज्य व्यक्ति के सभी पहलुओं से संबद्ध कार्यों का संपादन करता है। वह प्रजा की रक्षा और पालन नहीं करता, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य है 'योगक्षेम' की स्थापना 'योग' का अर्थ यदि किसी वस्तु की सफलतापूर्वक उपलब्धि है, तो 'क्षेम' का अर्थ शान्ति पूर्वक उस वस्तु का उपयोग करना है ।'योगक्षेम' का दूसरा अर्थ है, जो नहीं है, उसे प्राप्त करना और जो है, उसकी सुरक्षा करना ।

इस प्रकार 'योगक्षेम' में लोक कल्याणकारी राज्य के भाव निहित हैं, जिनके द्वारा राज्य प्रजा के सुख, कल्याण और आनन्द के लिए प्रयासरत है । कौटिल्य का कथन है कि-

प्रजा सुखे सुखं राज्ञ : प्रजानां च हिते हितम् ।

तात्म प्रिय हितं राज्ञ : प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥

(अर्थ शास्त्र,पहला अधिकरण, अठारहवाँ अध्याय)

अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित है । अपने आप को अच्छे लगने वाले कार्यों को करने में राजा का हित नहीं, बल्कि उसका हित तो प्रजाजनों को अच्छे लगने वाले कार्यों का संपादन करने में है ।

महात्मां गाँधी- हरिजन, 20 जनवरी सन् 1937 के अंक से

निष्कर्षत : यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य के राज्य का उद्देश्य पुलिस-राज्य के समान न तो केवल शांति और व्यवस्था बनाये रखना है और न केवल करों की वसूली करना है। वस्तुतः उसका राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है जो प्रजा के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने दायित्वों को निभाने के लिए सदा क्रियाशील रहता है । ***के0 मोटवानी ने*** अपनी पुस्तक मनु धर्मशास्त्र में लिखा है कि "मनु के निर्देशन में राज्य द्वारा बनाये जाने वाले अनेक कानून वर्तमान-कालीन राजशास्त्र के विद्यार्थी को समाजवादी प्रतीत होंगे"।

आधुनिक युग में महात्मा गांधी और बिनोवा भावे ने इसी सर्वमंगल या सर्वोदय के प्रवर्तन का प्रयास किया है । इस प्रकार से भारत में वैदिक काल से आधुनिक काल तक सर्वोदय का वास्तविक समाजवाद की प्रतिष्ठा के लिए सदैव ही प्रयास होता रहा है । प्राचीन समाजवाद की धारणा अध्यात्म और सत्य पर प्रतिष्ठित है । इस मौलिक समाजवाद में वास्तविक अध्यात्मिक चेतना प्राप्त करने के लिए निर्गुण और सगुण की पूजा, निष्काम कर्म, ज्ञान आदि साधन माने गये हैं, जिनके सम्यक अनुष्ठान में समत्व बुद्धि प्राप्त होती है। इस समाजवाद का लक्ष्य था अनाशक्ति और अपरिग्रह ।परन्तु जब से भारतीय समाजवाद पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव पड़ा, इसका उद्देश्य जन शक्ति या विधि द्वारा सम्पत्ति की संस्था को समाप्त करने का हो गया है। डा0 लोहिया ने उचित ही लिखा है कि "समाजवादी आन्दोलन की शुरुआत भारत में और विश्व में एक अर्थ में बहुत पहले ही हो जाती है, वह है अनाशक्ति का, मिल्कियत और ऐसी चीजों के प्रति लगाव समाप्त करने का, मोह घटाने का । किन्तु जब से समाजवाद के ऊपर कार्ल मार्क्स की छाप पड़ी तब से एक दूसरा अर्थ सामने आ गया । वह है सम्पत्ति की संस्था को समाप्त करने का, सम्पत्ति रहे ही नहीं, चाहे कानून से, चाहे जनशक्ति से ।"[19]

3- <u>उन्नीसवीं शताब्दी में समाजवाद</u>

19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आन्दोलन का भारत की राजनीति में विशेष स्थान है ।इसके बहुमुखी स्वरुप एवं व्यापकता की दृष्टि से इस आन्दोलन को संघर्ष पूर्ण आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जा सकता है । इस आन्दोलन ने भारत की तत्कालीन जड़ता को समाप्त किया और देश के जन जीवन को झकझोर दिया । इसने

---

19 - डा0 लोहिया -समाजवादी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ 1

जहाँ एक ओर धार्मिक तथा सामाजिक सुधारों का आह्वान किया वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्म सम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की । धार्मिक उपदेशों के साथ-साथ आन्दोलन के नेताओं ने स्वतन्त्रता और समानता का भी उपेदश दिया ।"भारत में समसामयिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस स्वतंत्रता का अर्थ मात्र बौद्धिक चिन्तन की स्वतन्त्रता से ही नहीं, बल्कि असमानता, शोषण और अत्याचार से मुक्ति भी था"। [20]

भारत पर अंग्रेजों की विजय ने भारतीय समाज की कमजोरियों एवं गिरी हुई हालत को स्पष्ट कर दिया ।अतः कुछ विचारशील और बुद्धिमान भारतीयों ने देश की दुर्दशा, पिछड़ेपन, और विदेशियों के समक्ष अपनी पराजय के कारणों की खोज बीन शुरु की तथा देश के उद्धार के लिए प्रयत्न करने लगे । वैसे अधिकांश भारतीय अभी भी परम्परागत विचारों, रीति-रिवाजों एवं संस्थाओं में विश्वास जमायें बैठे थे, लेकिन उनमें से कुछ ने सम्पर्क में आते ही पश्चिम के नये विचारों एवं ज्ञान के महत्व को पहचाना । पश्चिम के वैज्ञानिक ज्ञान, बुद्धिवाद (Rationlism) के सिद्धांत और मानववाद (Humanitarianism) का इन प्रबुद्ध भारतीयों पर गहरा प्रभाव पड़ा । वे इस नये ज्ञान एवं सिद्धान्तों की सहायात से अपने समाज की भलाई में लग गये । इसमें समाज के विभिन्न वर्गों को अपना निजी हित भी नजर आया ।"नये सामाजिक वर्ग जैसे पूँजिपति वर्ग, श्रमजीवी वर्ग और आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग पाश्चात्य विचारों एवं ज्ञान को इसलिए अपनाना चाहते थे ताकि उनसे देश का आधुनिकीकरण हो और इन विभिन्न सामाजिक वर्गों की स्वार्थ सिद्धि हो सके । धीरे-धीरे बाकी भारतीयों पर इस पाश्चात्य विचारों का प्रभाव पड़ा क्योंकि भारतीय उत्तरोत्तर यह महसूस करते गये कि पश्चिमी विचार केवल पश्चिमी समाज के लिए ही नहीं बल्कि भारत सहित सम्पूर्ण मानव जाति के लिए भी उपयोगी थे।[21]"

भारत में समाजवाद का विकास राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि पर हुआ ।जिन प्रारम्भिक चिन्तकों ने राष्ट्रवादी पृष्ठभूमि तैयार करने में प्रमुख भूमिका अदा की उनमें राजाराममोहन राय,

---

20 - रामलखन शुक्ला "आधुनिक भारत का इतिहास " (सं.) हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय - 1998, पृष्ठ 342

21 - वही, पृष्ठ 343

[22] दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण परमंहस के नाम उल्लेखनीय है।इस दिशा में ब्रह्म समाज,[23] आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन तथा थियोसोफिकल सोसाइटी जैसी सुधारवादी संस्थओं का भी योगदान बड़ा प्रसंशनीय और महत्वपूर्ण है ।[24] आधुनिक काल में भारतीय समाजवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने में भारतीय कांग्रेस का भी बड़ा योगदान रहा है ।

I-दयानन्द सरस्वती (1824-1883 ई0)

10 अप्रैल सन् 1975 ई0 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की । यद्यपि दयानन्द एक महान समाज सुधारक थे, लेकिन उनके विचारों में समाजवादी धारणा और दर्शन के प्रमुख बिन्दु मिलते है । जहां एक ओर उन्होंने मानव समानता पर बल दिया वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज के दलित तथा गिरे हुए वर्गो के उद्धार करने का हर संभव प्रयास भी किया।उनका उद्देश्य मानव मात्र की मुक्ति करना था । मानव को किसी भी बन्धन में रहना उनको प्रिय नहीं था ।दयानन्द की शिक्षाओं में मानवतावादी सार्वभौमवाद के अंश देखने को मिलते हैं । उन्होंने लिखा है "समाज का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य जाति की शारीरिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक दशा को सुधारकर समस्त विश्व का कल्याण करना है ।मैं उस धर्म को स्वीकार करता हूँ जो सार्वभौम सिद्धान्तों पर आधारित है, और जिसमें वह सब समाविष्ट है, जिसको मनुष्य जाति सत्य समझकर सदैव से मानती आयी है और जिसका वह आगे के युगों में भी पालन करती रहेगी । इसी को मैं धर्म कहता हूँ सनातन नित्य धर्म जिसका विरोधी कोई भी न हो सके । मैं उसी को मानने योग्य मानता हूँ जो सब मनुष्यों के द्वारा और सब युगों में विश्वास करने योग्य हो।[25] दयानन्द मानते थे कि सामाजिक तथा राजनीतिक कर्म और भौतिक समृद्धि का अपना मूल्य और महत्व है । इनके समाज सुधार तथा पुनः स्थापना, दलिताद्धार तथा मानव असमानता को दूर करने के प्रयास तथा कार्यक्रम की योजना भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक प्रगति की

---

22 - राजाराम मोहन राय इंग्लैण्ड में एक बार कल्पनावादी समाजवादी राबर्ट ओवेन से भेट की ।इस भेट वार्ता से स्पष्ट होता है कि वे समाजवादी विचारों से परिचित थे ।यू0 एम0 देसाई- भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ 114

23 - बी0 आर0 पुरोहित- हिन्दू रिवाइवलिज्म एण्ड इण्डियन नशेनलिज्म, पृष्ठ 116,ब्रजेन्द्रनाथ गील- राममोहनराय दि यूनिवर्सल मैन, भाग-2, पृष्ठ 101-109

24 - विपिन चन्द्र पाल- बिगर्निंग आफ फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया, पृष्ठ 50

25 - दयानन्द सरस्वती- 'सत्यार्थ प्रकाश', सार्वदेशिक प्रकाशन लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली, अध्याय 6 पृष्ठ 125

पूर्वगामी सिद्ध हुई। उनके इस सन्देश का भी महान राष्ट्रीय मूल्य है कि किसी को (अछूतो तथा विश्वभर के लोगों को भी) वेदों का ज्ञान प्राप्त करने तथा वेदाध्ययन का समान अधिकार है।

II- **स्वामी विवेकानन्द (1863-1902 ई0)**

स्वामी विवेकानन्द-हबर्ट स्पेन्सर और जॉन स्टुअर्ट मिल से प्रभावित थे। वे शैली के सर्वात्मवाद और वर्डस्वर्थ की दार्शनिकता के प्रेमी एवं हीगेल के वस्तु-निष्ठात्मक आदर्शवाद पर अनुरक्त थे, फ्रांसीसी राज्य क्रान्ति का प्रभाव, उस समय साहित्य के माध्यम से जोरों से फैल रहा था, विवेकानन्द भी उसके स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धान्त त्रय में बड़े उत्साह से विश्वास करते थे।[26] स्वामी विवेकानन्द अद्वैत वेदान्ती थे। वे जीव को तत्वत : ब्रह्मा ही मानते थे। एक सच्चे अद्वैत वादी की भाँति उनका विश्वास था कि अन्तोगत्वा सब जीव ब्रह्मा ही हैं अतः प्रत्येक मनुष्य के अन्दर ईश्वर विद्यमान है। मनुष्यों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। स्वामी विवेकानन्द के हृदय में गरीबों और दलितों के लिए अत्यधिक सहानुभूति थी। इस लिए वे गाँधी के काफी करीब और उनके विचारों से काफी प्रभावित थे। वे सबसे बड़े समाजवादी थे क्योंकि उन्होंने अमीरी तथा गरीबी दोनों को दर किनार कर पद-दलितों को सीने से लगाने का सन्देश देते थे और अपने कार्यों से अपने मिशन में यह करके दिखाया। उनका विचार था- गरीब,पीड़ित अभावग्रस्त, पद दलित, सब आओ। हम सभी लोग रामकृष्ण की शरण में एक हैं। हम पूजा के इस आडम्बर को जैसे-देव मूर्ति के सामने संखबजाना, घण्टा बजाना, और आरती करना छोड़ दें, हम शास्त्रों के पठन-पाठन और व्यक्तिगत मोक्ष के लिए सब तरह की साधनाओं को छोड़ दें तथा गाँव-गाँव जाकर गरीबों और पीड़ितों की सेवा करने का बीड़ा उठा लें।[27]

विवेकानन्द जी ने शिक्षितों को कहा कि "जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में गोते खा रहे हैं, तब तक मैं हर आदमी को एक विश्वासघातक मानता हूँ, जिसने उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे से शिक्षा पायी है और अब उन्हीं पर कोई ध्यान नहीं देता।[28] विवेकानन्द ने अमीरों को उनके कपट, शोषण और अनाचार के लिए फटकारा। उन्होंने बड़े दुख भरे शब्दों में कहा कि "भारत वर्ष में हम लोग गरीबों को, साधारण लोगों को,पतितों को क्या समझते है? उनके लिए न कोई

---

26 - रामधारी सिह 'दिनकर-' 'संस्कृति के चार अध्याय" लोक भारती प्रकाशक, एम0 जी0 मार्ग इलाहाबाद (1999)" पृष्ठ 500

27 - ताराचन्द- 'भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास' (दूसराखण्ड), नई दिल्ली, पृष्ठ 368

28 - स्वामी विवेकानन्द पत्रावली, प्रथम भाग, पृष्ठ 83 (अद्वैत आश्रम अल्मोड़ा)

उपाय है,न बचने की राह और न उन्नति के लिए कोई मार्ग ही ।भारत के दरिद्रों का,पतितों का कोई साथी नहीं, उन्हें कोई सहायता देने वाला नहीं, वे कितनी ही कोशिश क्यों न करें,उनकी उन्नति का कोई उपाय नहीं, वे दिन पर दिन डूबते जा रहे हैं। राक्षस जैसा नृशंस समाज पर जो लगातार चोटें कर रहा है, उसका अनुभव तो वे खूब कर रहे हैं, पर वे यह नहीं जानते कि ये चोटें कहाँ से आ रही हैं ।[29] इसके साथ ही विवेकानन्द को यह विश्वास था कि जब पद दलित वर्ग, जनता का साधारण वर्ग उठ खड़ा होगा तो उसकी प्रगति को रोकने का साहस कोई नहीं करेगा। गरीबों की सर्वसाधारण शक्ति को जगाते हुए विवेकानन्द ने कहा-"ऊँचे पद वालों या धनिकों का भरोसा मत करना, उनमें जीवन शक्ति नहीं है, वे तो जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। भरोसा तुम लोगों पर है, गरीब, पद-मर्यादा रहित किन्तु विश्वास भी तुम्ही लोगों पर है"[30]

यूरोप में विकसित हो रहे पूँजीवाद की गलत प्रवृत्ति से विवेकानन्द अत्यधिक निराश हुए। वे नये क्रान्तिकारी विचारों की ओर आकर्षित हुए जो भी प्रारम्भिक चरण या अवस्था में थे। वे रुस के क्रान्तिकारी और अराजक्तावादी विचारक प्रिन्स क्रोपाटिकिन से मिले। समाजवादी विचारों ने उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने स्वयं को समाजवादी कहना प्रारम्भ कर दिया। वे गरीबों व पद दलितों के प्रति अत्यधिक संवदेनशील थे ।समाज में उन्होंने उनके लिए समुचित स्थान दिये जाने की जबरदस्त वकालत की और जन साधारण के उत्थान को अपने कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग बनाया ।उन्होंने कहा कि राष्ट्र का गौरव महलों से सुरक्षित नहीं रह सकता ।झोपड़ियों की दशा भी सुधारनी होगी तथा गरीबों को उनके दीन हीन स्तर से ऊँचा उठाना होगा ।देश भक्त बनने की दशा में सबसे पहला कदम यही है कि हम भूख और अभाव से पीड़ित करोड़ों व्यक्तियों के प्रति वास्तविक संवदेना का अनुभव करें और उनके उत्थान की दिशा में कुछ करके दिखाएँ। यदि गरीबों और शूद्रों को दीन हीन ही रख गया तो देश और समाज का कोई कल्याण नहीं हो सकता"[31] विवेकान्द के समाजवादी हृदय इन शब्दों में चित्कार किया-"मैं उस भगवान या धर्म पर विश्वास नहीं करता जो न विधवाओं के आँसू पोंछ सकता है

29- वही, पृष्ठ 368
30 - स्वामी विवेकानन्द प्रत्रावली, प्रथम भाग, पृष्ठ 369 (अद्वैव आश्रम अल्मोड़ा)
31 - द कम्पलीट वर्क्स आफ स्वामी विवेकानन्द (अद्वैत आश्रम अल्मोड़ा), जिल्द 6, पृष्ठ 389

और न अनाथों के मुँह में एक टुकड़ा रोटी ही पहुँचा सकता है"।[32] पूंजीवादी और शोषणवादी अमीरों के बारे में उन्होंने कहा कि "वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और राजसी ठाट-बाट से अकड़कर चलते हैं, वे उन 20 करोड़ देश वासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं, यदि कुछ न करें, तो वे लोग घृणा के पात्र हैं।[33]

"विवेकानन्द भारत के पहले विचारक थे जिन्होंने भारतीय इतिहास की समाजशास्त्रीय दृष्टि से यथार्थवादी व्याख्या की। उन्होंने राजनीतिक उथल-पुथल के प्रलयकारी विप्लवों के मूल में सामाजिक संघर्षो का निरंतर सूत्र ढूँढ निकाला।उन्होंने भारत की जो व्याख्या की वह स्वरुप में अंशतः मार्क्सवादी भी है, किन्तु वह उनके अपने ढंग की मार्क्सवादी है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने 'दि कैपिटल' (पूँजी) अथवा दि कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ी थी।[34] विवेकानन्द के अनुसार प्राचीन भारत में राजशक्ति तथा ब्रह्मशक्ति के बीच संघर्ष चला करता था। बौध धर्म क्षत्रियों का विद्रोह था। उसके कारण पुरोहितों की शक्ति का ह्रास और राजशक्ति का उत्कर्ष हुआ। आगे चलकर कुमारिल, शंकर और रामानुज ने पुरोहित शक्ति के उत्कर्ष का प्रयत्न किया। उदरम्भि ब्राह्मण पुरोहितों ने मध्ययुगीन राजपूती सामंतवाद से मेल करके अपनी शक्ति को कायम रखने की चेष्टा की, किन्तु मुस्लिम शक्ति की प्रगति के कारण पुरोहित वर्ग के उत्कर्ष की सम्पूर्ण आशाएं ध्वस्त हो गयी, और न ही पुरोहित लोग विदेशी ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत ही अपनी शक्ति के पुनरुत्थान का स्वप्न देख सकते थे।"[35] भारतीय इतिहास की यह समाजशास्त्रीय व्याख्या अंशतः मार्क्सवादी है और अंशतः विल्फ्रेडो पैरेटो के सिद्धांत से मिलती जुलती है।यह मार्क्सवादी इस अर्थ में है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय निरंतर जनता के शोषण में लगे रहे दलित वर्ग के शोषण की धारणा मार्क्सवादी है। किन्तु विवेकानन्द का सिद्धांत पैरोटो की धारणा से इस अर्थ में मिलता-जुलता है कि उन्होंने शोषक वर्गो के बीच संघर्ष की धारण का प्रतिपादन किया।जिसे पैरेटो भाषा में 'विशिष्ट वर्ग का चक्रावर्तन' कहते हैं।[36]" इसी प्रकार

---

32 - वही, पृष्ठ 389

33 - वही, पृष्ठ 390

34 - वी0 पी0 वर्मा -'आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन (लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा 1995-96), पृष्ठ 148

35 - विवेकानन्द- "माडर्न इण्डिया", (द कम्पलीट वर्क्स आफ विवेकानन्द), जिल्द, 4 पृष्ठ 394-95

36 - वी0 पी0 वर्मा- 'आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन' पृष्ठ 148-49

विवेकानन्द के अनुसार भारतीय इतिहास में दो सामाजिक प्रवृत्तियाँ रही हैं ।पहली ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच निरंतर संघर्ष की प्रवृत्ति है ।कभी-कभी ऐसे भी अवसर आये जब दोनों वर्गों ने परस्पर सहयोग किया। दूसरे पुरोहितों ने अपनी धार्मिक क्रियाओं के द्वारा और क्षत्रियों तथा बाद में राजपूतों ने तलवार के बल पर जनता का निरन्तर शोषण किया । श्रमिक वर्ग के प्रति विवेकानन्द की गहरी सहानुभूति थी। उनके जीवनकाल में भारत में श्रमिक वर्ग का आन्दोलन अथवा संगठन मौजूद नहीं था,क्योंकि उस समय इस वर्ग की स्वयं रचना हो रही थी ।लेकिन एक महान क्रान्तिकारी की भांति विवेकानन्द ने श्रमिक वर्ग के प्रति अडिग आस्था प्रकट की और अपनी मातृभूमि के महान भविष्य के लिए, न केवल स्वतन्त्रता की वरन् समाजवाद की भविष्यवाणी की ।वास्तव में उन्होंने भारत में समाजवाद का नारा रुस में समाजवादी क्रान्ति के दो दशक पूर्व ही दे दिया । इन्होंने एक भविष्य दृष्टाकी भाँति देख लिया था कि किसी न किसी रुप में समाजवाद निकट आ ही रहा है, और वह दिन दूर नहीं जब शूद्र के रुप में ही शूद्र शासक वर्ग बन जायेंगे ।

स्वामी विवेकानन्द उस अर्थ में समाजवादी नहीं थें जिस अर्थ में हम आधुनिक किसी राजनीतिक दार्शनिक को समाजवादी कहते हैं ।उनकी दृष्टि में समाजवाद कोई एकदम निर्दोष या आदर्श व्यवस्था नहीं थी ।उन्होंने लिखा था-''मैं समाज़वादी हूँ इसलिए नहीं कि मैं इसे पूर्ण रुप से निर्दोष व्यवस्था समझता हूँ, परन्तु इसलिए कि रोटी न मिलने से आधी रोटी ही अच्छी है । अन्य व्यवस्थाओं को आजमाया जा चुका है ।और वे विफल अथवा दोष युक्त सिद्ध हुई हैं । अब इसकी (समाजवाद की) भी परीक्षा होने दो, यदि और किसी कारण से नहीं तो केवल नवीनता के लिए ही सही ।[37] विवेकानन्द को दो अर्थो में समाजवादी कहा जा सकता है । प्रथम, इसलिए कि उनमें यह समझने की ऐतिहासिक दृष्टि थी कि भारतीय इतिहास में दो उच्च जातियों-ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का आधिपत्य रहा है। क्षत्रियों ने गरीब जनता का अर्थिक तथा राजनीतिक शोषण किया और ब्राह्मणों ने उसे नवीन तथा जटिल धार्मिक क्रिया कलाप और अनुष्ठानों के बन्धन में जकड.कर रखा । उन्होंने खुले तौर पर जातिगत उत्पीड़न की भर्त्सना की

---

37 - 'द कम्पलीट वर्क्स आफ स्वामी विवेकानन्द', जिल्द 6, पृष्ठ 389

और आत्मा तथा ब्राह्मा में आस्था रखने के नाते मनुष्य तथा मनुष्य के बीच सामाजिक बन्धनों को अस्वीकार कर दिया "[38]

विवेकानन्द की रचनाओं में सामाजिक समानता का जो समर्थन देखने को मिलता है वह प्रबल पुरातनवाद तथा ब्राह्मणों की स्मृतियों में व्याप्त सामाजिक ऊँच-नीच के सिद्धांत का सबल प्रतिवाद है। उनका सामाजिक समानता का सिद्धांत तत्वतः समाजवादी है।

दूसरे, विवेकानन्द समाजवादी इसलिए थे कि उन्होंने देश के सब निवासियों के लिए 'समान अवसर के सिद्धांत' का समर्थन किया।[39] उन्होंने लिखा-"यदि प्रकृति में असमानता है,तो भी सबके लिए समान अवसर होने चाहिए अथवा यदि कुछ को अधिक और कुछ को कम अवसर दिया जाय तो दुर्बलों का सबलों से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए' दूसरे शब्दों में- ब्राह्मण को उतनी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है जितनी की चण्डाल को। यदि ब्राह्मण को एक अध्यापक की आवश्यकता है तो चण्डाल को दस की है। क्योंकि जिनकों प्रकृति ने जन्म से सूक्ष्म बुद्धि नहीं दी है उसे अधिक सहायात दी जानी चाहिए। पद-दलित,दरिद्र और अज्ञानी इन्हीं को अपना देवता समझो"[40] समान अवसर का सिद्धांत निश्चय ही समाजवादी दिशा का द्योतक है।

स्वामी विवेकानन्द तथा आधुनिक समाजवादी दार्शनिकों में आधारभूत अन्तर है।प्रथम, विवेकानन्द का, मार्क्स के समान, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में विश्वास नहीं था और न ही उन्होंने मार्क्स तथा उनके अनुयायियों की भांति वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को मानव इतिहास को समझने की कुंजी माना था।विवेकानन्द आध्यात्मिक पुरुष थे, वेदान्ती थे और वेदान्त पर आधारित किसी भी सामाजिक दर्शन में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। द्वितीय, विवेकानन्द का अन्य समाजवादी दार्शनिकों के समान वर्गविहीन समाज के सिद्धांत में विश्वास नहीं था। यद्यपि उन्होंने तत्कालीन भारतीय जाति प्रथा का विरोध किया था लेकिन जातियों के उन्मूलन की बात नहीं की बल्कि यह माना कि हर समाज में किसी न किसी प्रकार के वर्ग अवश्य ही होने चाहिए।तृतीय, विवेकानन्द ने केवल मात्र आर्थिक समानता को ही सर्वाधिक

---

38 - वी० पी० वर्मा -"आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन", पृष्ठ 149

39 - वही, पृष्ठ 149

40 - " द कम्पलीट वर्क्स आफ स्वामी विवेकानन्द", जिल्द 6, पृष्ठ 321

महत्व नहीं दिया वरन उनका आदर्श तो एक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भ्रातृत्व था जिसमें आर्थिक समाजवाद के अतिरिक्त नैतिक तथा बौद्धिक आत्मीयता भी होगी।

III- महात्मा गाँधी-(1869-1948 ई0)

सन् 1920 से 1947 ई0 तक भारतीय राजनीति का युग गाँधी युग कहलाता है[41] महात्मा गाँधी ने सन् 1920 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन एवं कांग्रेस की नीतियों को एक नयी दिशा प्रदान की।[42]

सन् 1934 में जब पटना में कांग्रेसी समाजवादियों का सम्मेलन हुआ, उस समय उनके समक्ष समाजवादी कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के प्रति गाँधी जी ने अपनी प्रतिक्रियाएं पं0 जवाहर लाल नेहरु को पत्रों के माध्यम से स्पष्ट की। जिससे पता चलता है कि उनके अन्दर समाजवाद के प्रश्न पर संघर्ष चल रहा था।[43] लेकिन गांधी जी आत्मा से एक समाजवादी थे।[44] गाँधी जी की जीवनी में तेंदुलकर ने लिखा है कि गांधी ने तो समाजवाद का सिद्धांत उस समय स्वीकार कर लिया था जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे।[45]लेकिन वे समाजवाद के वर्ग संघर्ष और हिंसात्मक क्रान्ति के सिद्धांत को नहीं मानते थे। पं0 जवाहर लाल नेहरु ने गाँधी जी की समाजवादी भावना के विषय में लिखा है-" कभी-कभी वह अपने को समाजवादी भी कहते हैं, लेकिन वह समाजवाद का प्रयोग एक ऐसे अनोखे अर्थ में करते हैं, जो खुद उनका लगाया हुआ है और जिसका उस आर्थिक ढाँचे से कोई सरोकार नहीं है, जो सामान्यतया समाजवाद के नाम से पुकारा जाता है। वे समाजवाद को और उससे भी अधिक विशेषत : मार्क्सवाद को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह हिंसा से संबंधित है।"[46] उल्लेखनीय है कि पं0 नेहरु वैज्ञानिक समाजवाद के पक्षधर थे और गाँधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त, औद्योगीकरण का विरोध, राजनीति के आध्यात्मिकरण और खादी आन्दोलन को उन्होंने पूरा समर्थन नहीं दिया था। तथापि वे गाँधी

---

41 - पट्टाभिसीता रमैया- कांग्रेस का इतिहास, खण्ड 1 पृष्ठ 161

42 - पं0 जवाहरलाल नेहरु - मेरी कहानी, पृष्ठ 75, पी0 डी0 कौशिक- दि कांग्रेस आइडियोलाजी एण्ड प्रोग्राम, पृष्ठ 35

43 - पं0 जवाहर लाल नेहरु- कुछ पुरानी चिट्ठियाँ, पृष्ठ 155,- हरिजन, 20 सितम्बर, 1940 ई0 गाँधी जी, नेहरु के इस मत से सहमत नही थे कि औद्योगीकरण से समाजवाद की स्थापना सम्भव हो सकती हैं

44 - डा0 वी0 पी0 वर्मा - पोलिटिकल फिलास्फी आफ गाँधी एण्ड सर्वोदय, पृष्ठ 120, पं0 जवाहर लाल नेहरु- आत्म कथा, पृष्ठ 518

45 - डी0 जी0 तेन्दुलकर - महात्मा, खण्ड 7, पृष्ठ 476

46 - पं0 जवाहरलाल नेहरु - मेरी कहानी (अध्याय -विकट समस्याएं,) पृष्ठ 717

जी के महान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत से कांग्रेसी भी 'समाजवाद' शब्द का प्रयोग करने लगे।[47] देश के प्रमुख समाजवादी नेता जैसे नरेन्द्र देव, जय प्रकाश,सम्पूर्णानन्द, अशोक मेहता, राममनोहर लोहिया आदि गाँधी जी के समाजवादी चिन्तन से प्रभावित थे।कांग्रेस के अन्दर भी समाजवादी और गाँधीवादी गुटों में अनेक बार वैचारिक मतभेद हुए, जिनकी मध्यस्थता गाँधी जी ने की और उनके मतभेदों का निराकरण भी किया।[48] राय अखिलेन्द्र प्रसाद भी स्वीकार करते हैं कि गाँधी जी का समाजवादियों से घनिष्ठ सम्बन्ध था।[49] और उन्हीं के प्रयत्नों का यह परिणाम था कि सन् 1948 तक समाजवादी नेता इच्छा रखते हुए भी कांग्रेस से अपना सम्बन्ध विच्छेद न कर सके।

वस्तुतः गाँधी जी का समाजवाद मार्क्सवादी विचारधारा से हटकर एक अहिंसक समाजवाद था। राममनोहर लोहिया ने भी लिखा है कि "आर्थिक प्रश्नों पर गाँधी जी के विचारों का उपयोग समाजवाद के लिए किया जा सकता है।[50]

गाँधी जी के समाजवादी चिन्तन पर विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये हैं। तेंदुलकर का मत है कि "गाँधी जी ने 1920 में लंका में दिये गये अपने भाषण में कहा था कि आप कोष दरिद्र नारायण के लिए खोल दो[51] इस कथन से उनके समाजवादी दर्शन का आशय स्पष्ट होता है। उन्होंने समयानुकूल अपने विचारों को प्रकट किया। इस सन्दर्भ में किशोरी लाल मशरुवाला ने लिखा है कि वास्तव में गाँधी जी का समाजवाद हिंसा रहित साम्यवाद के अधिक निकट है।[52] गाँधी जी के समाजवादी चिन्तन का मूल आधार सत्य और अहिंसा का सिद्धांत है। इस सन्दर्भ में नरेन्द्रदेव ने लिखा है "उनकी अंहिसा का सिद्धांत भी केवल व्यक्तिगत आचरण का उपदेश मात्र था, किन्तु सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अंहिसा को एक उपकरण बनाना और राजनीति के क्षेत्र में अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए उसका सफल प्रयोग करना महात्मा गाँधी का ही काम था और चूँकि वह संसार में अंहिसा को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इसलिए

---

47. डा0 शोभा शंकर- आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, पृष्ठ 75-76
48. पी0 डी0 कौशिक- दि कांग्रेस आइडियोलाजी एण्ड प्रोग्राम पृष्ठ 132
49. दि सेमीनार आन सोशलिज्म इन इण्डिया, खण्ड 1 (सं.), पृष्ठ 339 राय अखिलेन्द्र प्रसाद- सोशलिस्ट थाट इन मार्डन इण्डिया पृष्ठ 58
50. डा0 राममनोहर लोहिया- मार्क्स-गाँधी एण्ड सोशलिज्म पृष्ठ -135
51. डी0 जी0 तेन्दुलकर- महात्मा, खण्ड 2, पृष्ठ 385
52. डा0 शोभाशंकर- आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, पृष्ठ 79-80

उनके अंहिसा की व्याख्या भी अद्भुत, बेजोड़ और निराली थी ।[53] गाँधी जी के सत्य और अंहिसा पर विचार व्यक्त करते हुए हरिभाऊ उपाध्याय ने भी लिखा है कि-गाँधीवाद के दो ध्रुव सत्य हैं, जिन्हे गाँधी जी क्रमशः सत्य और अहिंसा कहा करते हैं । यही गाँधीवाद के पथ-प्रदर्शक सिद्धांत हैं ।"[54] इस प्रकार सत्य है कि गाँधी जी का चिन्तन सत्य और अहिंसा पर आधारित है ।सत्य को वे ईश्वर समझते थे और अंहिसा को एक व्यापक वस्तु बताते थे ।[55] उन्होंने सत्य की खोज में ही राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया,[56] और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह नामक एक अनोखे हथियार का प्रयोग किया ।[57] मार्क्सवाद-लेनिनवाद से हटकर गाँधी जी ने साधनों की पवित्रता पर बल दिया और समाजवाद की स्थापना के लिए रक्त रंजित क्रान्ति के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी ।[58]

गाँधी जी ने जिस स्वराज की कल्पना की, उसका आशय शोषण हीन समाज से है । उनके स्वराज का अर्थ था निर्धनों के लिए भोजन और वस्त्र तथा सभी को अपना सर्वांगिण विकास करने का अवसर।[59]

गाँधी जी ने स्वयं अपनी पुस्तिका "हिन्द स्वराज" में उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के अमानवीय शोषण को स्वीकार किया है और उन्होंने स्वालम्बी बनने हेतु लोगों को चरखा चलाने की शिक्षा दी है । वे शारीरकि श्रम के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि इसके बल पर ही व्यक्ति स्वालम्बी बन सकता है ।[60]

गाँधी जी के समाजवादी चिन्तन का आधार श्रम पर आधारित उनका सर्वोदय समाज है ।[61] सर्वोदय की प्रेरणा उन्होंने रस्किन की पुस्तक "आन टू दि लास्ट" [62] से ग्रहण की थी। सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ सबका उदय अर्थात समाज के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति और

---

53 - नरेन्द्र देव- राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ 473
54 - हरिभाऊ उपाध्याय- गाँधीवादी समाजवाद, पृष्ठ 25
55 - गाँधी जी- आत्मकथा ,पृष्ठ 356
56 - पट्टाभि सीता रमैया-कांग्रेस का इतिहास, खण्ड 2 पृष्ठ 463
57 - पं0 जवाहरलाल नेहरु हिन्दुस्तान की कहानी, पृष्ठ 233
58 - महात्मा गाँधी सेलेक्टेड वर्क्स, खण्ड 42, पृष्ठ 355
59 - पट्टाभि सीता रमैया- कांग्रेस का इतिहास, जिल्द 1 पृष्ठ 246
60 - बी0 बी0 रमन मूर्ति- (सं.) गाँधी, पृष्ठ 716
61 - डा0 वी0 पी0 वर्मा -पोलिटिकल फिलास्फी आफ महात्मागाँधी एण्ड सर्वोदय पृष्ठ 279-80
62 - गाँधी जी ने रस्किन की पुस्तक "आन टू दि लास्ट" का अनुवाद हिन्दी भाषा में 1904 में किया था

विकास है । सर्वोदय सिद्धांत के आधार पर गाँधी जी का विचार था कि समाज में कोई वर्ग भेद नहीं होना चाहिए । उनका कहना था कि मनुष्य को, प्रेम, दया, सहयोग आदि नैतिक गुण प्रकृति से प्राप्त होते हैं । अतः स्वार्थ और ईर्ष्या के आधार पर समाज का विभाजन करना अनुचित है । समाजवाद और सर्वोदय में केवल यही अन्तर है कि समाजवाद भौतिक हितों पर बल देता है, जबकि सर्वोदय में अध्यात्मिक हितों का पोषण किया जाता हैं तथा दोनों के उद्देश्य समान हैं, दोनों ही समाज में शोषण का उन्मूलन कर मानव जाति को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं । लेकिन सर्वोदय मार्क्सवाद के समान क्रान्ति द्वारा समाजवाद नहीं स्थापित करना चाहता, वरन् सर्वोदय नैतिकता के आधार पर मनुष्य के हृदय परिर्वतन का पक्षपाती है । इस प्रकार अन्य समाजवादी विचारकों की अपेक्षा गाँधी जी का सर्वोदय सिद्धान्त विशुद्ध नैतिकता पर आधारित है। गाँधी जी सर्वोदय के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखे हैं कि सर्वोदय का लक्ष्य मनुष्य और मनुष्य के मध्य खाई को समाप्त करना है ।[63]

सर्वोदयी समाज की स्थापना के लिए गाँधी जी ने ग्रामोंद्धार, ग्रामीण पुनर्निर्माण, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, आर्थिक विकेन्द्रीकरण आदि का समर्थन किया और आर्थिक समानता की आवश्यकता पर बल दिया ।[64] वे सत्य, प्रेम और अहिंसा पर आधारित एक शोषणविहीन सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के पक्ष में थें । मार्क्स के समान वे भी व्यक्तिगत सम्पत्ति का विरोध करते थे और अपरिग्रह का समर्थन करते थे ।उनका कहना था कि अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना चोरी है । लेकिन जहाँ मार्क्सवादी व्यक्तिगत सम्पत्ति का उन्मूलन क्रान्ति द्वारा करना चाहते हैं वहाँ गाँधी जी अहिंसक उपायों द्वारा पूँजीपतियों का हृदय परिवर्तन करके और उन्हें उत्पादन के साधनों का ट्रस्टी ।[65] बनाकर व्यक्तिगत सम्पत्ति की बुराई को समाप्त करने के पक्ष में थे । इस प्रकार गाँधी जी का समाजवादी चिन्तन आदर्शवादी है, जबकि मार्क्सवाद यथार्थ पर आधारित है ।इसी सन्दर्भ में गाँधी जी "रोटी के लिए श्रम का

---

63 - हरिभाऊ उपाध्याय- गाँधीवादी, समाजवाद पृष्ठ 27

64 - महात्मां गाँधी-विलेज रिक -स्ट्रक्शन, पृष्ठ 4

65 - गाँधी जी के अनुसार ट्रस्टी का अर्थ मालिक नहीं, वरन समाज की ओर से उस वस्तु का रक्षक है, मालिक तो सम्पूर्ण समाज है ।

सिद्धान्त प्रतिपादित किया और स्वयं को भी एक 'श्रमिक' बताये।[66] गाँधी जी अन्य समाजवादी चिन्तकों के समान आर्थिक असमानता को वर्गीय क्रान्ति द्वारा समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, वरन वे नैतिकता द्वारा स्वेच्छापूर्वक मनुष्य का हृदय परिवर्तन कर आर्थिक समानता लाने के पोषक थे ।[67] गाँधी जी का लक्ष्य सबके लिए सामाजिक-न्याय व आर्थिक अवसर की समानता को प्राप्त करना है । इस दृष्टि से गांधी जी को एक समाजवादी और गाँधीवाद को समाजवाद का एक विशिष्ट रुप समझा जा सकता है । किन्तु उनका समाजवाद दूसरे व्यक्तियों के समाजवाद से सर्वथा भिन्न था, वह मार्क्स अथवा किसी अन्य पश्चिमी विचारक से नहीं लिया गया था । उसका मूल था अंहिसा में अदम्य विश्वास । उन्होंने लिखा है कि समाजवाद का जन्म उस समय नहीं हुआ था जबकि पूँजीपतियों द्वारा पूंजी के दुरुपयोग का पता चला ।जैसा कि मैं कह चुका हूँ, समाजवाद यहाँ तक कि साम्यवाद भी, 'इशोपनिषद' के प्रथम श्लोक में झलकता है । सत्य तो यह है कि जब कुछ सुधारकों को हृदय परिवर्तनों के साधनों में विश्वास आता रहा तो उस चीज का जन्म हुआ जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं । मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हुआ हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है।[68]

गाँधी जी समाजवाद को सुन्दर शब्द मानते हैं । समाजवाद में सभी सदस्य समान हैं- न कोई नीचा, न कोई ऊँचा । व्यक्ति के शरीर में सिर इसलिए ऊँचा नहीं है कि वह शरीर के ऊपर है, न पैर के तलवे इस कारण निचे हैं कि ये जमीन को छूते हैं । जैस-शरीर के अंग समान है वैसे ही समाज के सदस्य भी । यह समाजवाद है ।[69] गाँधी जी बोल्शेविकवाद के सम्बन्ध में कहते हैं कि यह निजी सम्पत्ति के उन्मूलन में विश्वास करता है, एक प्रकार से यह सिद्धांत अपरिग्रह के नैतिक आदर्श का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किया गया प्रयोग है ।लेकिन अपने वर्तमान रुप में बोल्शेविकवाद अधिक दिनों तक नहीं चल सकता क्योंकि वह हिंसा पर आधारित

---

66 - महात्मां गाँधी कैपिटल-एण्ड लेबर, पृष्ठ 46

67 - अनेक विद्वानो ने गाँधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को अव्यवहारिक बताया पं0 नेहरु तक ने इस सिद्धांत का समर्थन नहीं किया और विनोबभावे और जय प्रकाश नारायण तक इस सिद्धांत को कार्य रुप न दे सके ।नारायण सिंह- मार्क्स और गाँधी का साम्यदर्शन, पृष्ठ 488

68 - यंग इण्डिया 20.1 1920

69 - हरिजन-13.7 1947

है, हिंसा पर आधारित कोई विचार अधिक दिन तक नहीं टिक सकता ।[70] गाँधी जी ने वर्ग संघर्ष के मार्क्सवादी विचार को स्वीकार नहीं किया । वे पूँजी तथा श्रम में कोई नैसर्गिक विरोध नहीं मानते । वे श्रम तथा पूँजी को समान स्तर पर रखने की आवश्यकता पर बल दते हैं । पूँजीपतियों को केवल श्रमिकों की भौतिक आवश्यकता का ही ध्यान नहीं रखना है, अपितु उसका नैतिक कल्याण भी करना है । वे न्यासी के रुप में श्रमिकों के हित का पालन करें । लड़ाई पूँजी से नहीं अपितु पूँजीवाद से है । गाँधी जी के अनुसार सम्पत्ति के निजी स्वामित्व के नष्ट करने के स्थान पर उसके उपभोग पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है ताकि अमीर एवं गरीब के बीच की खाई को मिटाया जा सके ।[71]

गाँधी जी की मान्यता है कि यदि जनता अहिंसा को जीवन का आधारभूत सिद्धांत बना ले तो वर्ग संघर्ष असंभव हो जायेगा । इसके द्वारा पूँजीपति को नष्ट करने के स्थान पर पूंजीवाद को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है । पूँजीपति न्यासी के रुप में पूंजी का उत्पादन संग्रह एवं संबर्धन करने के लिए आमान्त्रित हैं ।श्रमिकों को पूँजीपति के ह्रदय परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करती है । यदि पूँजी शक्ति है तो श्रम भी दोनो ही शक्तियाँ रचनात्मक अथावा विध्वंसात्मक कार्य में प्रयुक्त हो सकती है । श्रमिकों में अपनी शक्ति का बोध जागृत होते ही वे पूँजी की साझेदारी की बात सोचेंगे न कि पूँजीपतियों के दास बने रहने की । प्रत्येक मनुष्य को जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का समान अधिकार प्राप्त है । श्रमिकों को अपने शरीर से श्रम करने के कर्त्तव्य का निर्वाह करना है, और उन व्यक्तियों से असहयोग करना है जो श्रम का शोषण करते हैं । मूलभूत समानता में विश्वास रखते हुए पूँजीपति एवं श्रमिक को एक ही धरातल पर देखना है । पूँजीपति को नष्ट करने के स्थान पर उसा ह्रदय परिवर्तन करना है ।[72]

आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने की उनकी तकनीकि तथा समाजवादियों एवं साम्यवादियों की तकनीकि में अन्तर है । गाँधी जी, इस सम्बन्ध में कहते है कि "समाजवादी तथा साम्यवादी यह कहते हैं कि वे आर्थिक समानता लाने के लिए आज कुछ नहीं कर सकते । वे इसके पक्ष में प्रचार करते रहेंगे और अन्त में उनके अनुसार घृणा उत्पन्न होगी

---

70 - यंग इण्डिया 15.11 1928

71 - वही, इण्डिया-21.11.1929

72 - वही, 26.3.1931

और बढ़ेगी । वे कहते हैं कि जब उनको राज्य पर नियंत्रण प्राप्त हो जायेगा वे समता लागू करेंगे । मेरी योजना के अनुसार, राज्य व्यक्ति की आकांक्षा की पूर्ति के लिए रहेगा न कि उनको अपने निर्देशों के अनुसार कार्य करने अथवा बाध्य करने के लिए । मैं अहिंसा द्वारा आर्थिक समानता की स्थापना कँरुगा, जनता को अपने विचारों के अनुरुप परिवर्तित कँरुगा, घृणा के स्थान पर प्रेम की शक्ति का उपयोग कँरुगा । मेरे विचारों के अनुरुप समाज को बनाने तक मैं प्रतीक्षा नहीं कँरुगा अपितु मैं स्वयं से ही इसका प्रारम्भ कर दूँगा । यदि मैं पचास मोटर कारों अथवा दस बीघा जमीन का भी मालिक हूँ तो यह सत्य है कि मैं अपने विचारों की आर्थिक समानता नहीं ला सकता इसके लिए मुझे स्वयं को निर्धन से निर्धनतम स्तर तक अपने आपको घटाना होगा। मैं गत पचास वर्षों से यही करने का प्रयास कर रहा हूँ और इस कारण से मैं अपने आपको अग्रणी साम्यवादी कहने का दावा करता हूँ हालाँकि मैं धनिकों द्वारा प्रस्तुत कार एवं अन्य सुविधाओं का उपयोग करता हूँ उनका मेरे पर प्रभाव नहीं है और जनहित की मांग पर मैं उन्हें एक क्षण में त्याग सकता हूँ ।[73] वास्तव में गाँधीवादी विचारधारा एक समग्र जीवन दर्शन प्रस्तुत करती है ।उसमें जीवन के सभी पक्षों, आध्यात्मिक,सामाजिक, राजनैतिक आदि का विवेचन हुआ है । यह व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा,विकास और महत्व पर बल देती है । उसका उद्देश्य राज्यशक्ति को क्षीण और व्यक्ति को सबल बनाना है। इसमें शोषण को शन्ति पूर्ण उपाय से समाप्त करने का जो प्रयास (न्यास पद्धति) किया गया है वह एक आदर्शवादी धारणा है और सिद्धांत रुप में समाजवादी वर्ग-संघर्ष का एक विकल्प है । वस्तुतः मार्क्स न पूँजीपति और मजदूर के बीच संघर्ष को काफी बढ़ा-चढ़ाकर अंकित किया है । गाँधी जी उसे शाश्वत मूल्य व्यवस्था के अन्तर्गत लेकर सहयोग और नैतिकता का आयाम प्रदान करते हैं, वे आर्थिक और लौकिक समस्याओं को आध्यात्मिक तथा पारलौकिक दृष्टियों से देखते हैं । इस आदर्श को व्यवहार में प्राप्त न मानकर भी नैतिकता की दृष्टि से अनुगमन योग्य मानते हैं ।[74]

इस प्रकार स्पष्ट है कि गाँधीजी की समाजवादी कल्पना का मूलआधार नैतिक है । उनका समाजवाद मानवीय समाजवाद है जो कि वैज्ञानिक समाजवाद (मार्क्सवाद-लेनिनवाद) से

---

73 - एन0 के0 बोस- 'सेलेक्शन्स फ्राम गाँधी', बम्बई, पृष्ठ 37 38

74 - डा0 एस0 एल0 वर्मा- "समकालीन राजनीतिक चिन्तन" मीनाक्षी प्रकाशन (मेरठ) 1989, पृष्ठ 237-238

भिन्न है ।[75] उनके समाजवाद में वर्ग-संघर्ष हिंसात्मक क्रान्ति और औद्योगीकरण का गौण स्थान है।[76] वे समाजवाद की स्थापना के लिए सत्य, प्रेम, अंहिसा, सत्याग्रह ग्रामोद्धार,ग्रामीण पुनर्निर्माण, ट्रस्टीशिप आदि बातों को विशेष महत्व देते हैं ।

भारतीय समाजवादी चिन्तन के विकास में महात्मागाँधी का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। देश के प्रमुख समाजवादी नेताओं और चिन्तकों पर गाँधीवाद की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है।[77] उन्होंने जिस समाजवादी विचारधारा को विकसित किया वह सर्वथा भारतीय परिस्थितियों पर आधारित है । यद्यपि इनकी रामराज्य की अवधाराण काल्पनिक प्रतीत होती है । तथापि भारत की शोषित और पीड़ित जनता के उद्धार के लिए और देश में सच्चे समाजवाद की स्थापना के लिए उनके द्वारा निर्मित सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग प्रकाश स्तम्भ के समकक्ष है । उनका यह कथन भारत के समाजवादियों के लिए बड़ा ही प्रेरणावर्द्धक है कि "यदि समाजवाद का अर्थ दूसरों को मित्र बनाना है यहाँ तक कि अपने शत्रुओं को भी, सच्चे समाजवादियों को समाजवाद मुझसे सीखाना चाहिए तभी हम मजदूरों और किसानों का सच्चा राज्य स्थापित कर सकते हैं ।[78]

iv- <u>पं0 जवाहर लाल नेहरु</u>[79] (1989-1964 ई0)

पं0 जवाहर लाल नेहरु को कांग्रेसी नेताओं में प्रमुख समाजवादी के रुप में स्वीकार किया जाता हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में इंग्लैण्ड में रहकर वे फेबियनवादी समाजवाद के संपर्क में आये, तथापि वे मूलतः राष्ट्रवादी ही रहे ।[80]

नेहरु के संस्कारों पर ही कुलीनता का प्रभाव था और यह प्रभाव उनकी विचारधारा में भी जीवन पर्यन्त तक बना रहा । नेहरु जी ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा है-" मैं

---

75 - डा0 शोभा शंकर- आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, पृष्ठ 93

76 - लुई फिशर (अनु0 लेख राम) गाँधी और स्टालिन पृष्ठ 93

77 - राममनोहर लोहिया - मार्क्स , गाँधी एण्ड सोशलिज्म ,पृष्ठ 118

78 - डी0 जी0 तेन्दुलकर- महात्मा, खण्ड 8, पृष्ठ 41

79 - पं0 जवाहर लाल नेहरु ने अपने विचार अनेक पुस्तकों में व्यक्त किये है जिनमें, "ऐन आटोबायोग्राफी", "गिलिम्पसेज आफ वर्ल्ड हिस्ट्री," और" डिस्कवरी आफ इण्डिया विशेषरुप से उल्लेखनीय है

80 - पं0 जवाहर लाल नेहरु -मेरी काहानी ,पृष्ठ 62

आदर्श बुर्जुवा हूँ तथा वह सभी पूर्वाग्रह जो बुर्जवा वातावरण में बड़े होने में सीख रुप में मिलते हैं, मुझमें है।[81]

नेहरु जी को सन् 1926 में यूरोप प्रवास का अवसर मिला और वह प्रवास उनका कुछ अधिक समय तक रहा। उन्हें वहाँ बहुत से समाजवादी और साम्यवादियों से संपर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। सन् 1927 ई0 में नेहरु जी रुस की यात्रा की और वहाँ पर साम्यवादियों की उलब्धियों को प्रत्यक्षतः देखा।[82] इसी समय नेहरु जी की समाजवाद के प्रति रुचि बढ़ने लगी।[83] ब्रुसेल्स में 10 फरवरी 1927 ई0 को साम्राज्यवाद विरोधी अर्न्तार्ष्ट्रीय कांग्रेस में नेहरु जी द्वारा दिये गये भाषण के कुछ अंश उनके समाजवादी विचारों पर प्रकाश डालते हैं।[84] नेहरु जी के लेखों और भाषणों से ज्ञात होता है कि 1917 की रुस की मार्क्सवादी राज्य क्रान्ति के पश्चात नेहरु जी मार्क्सवादी विचारों से अधिक प्रभावित थे लेकिन धीरे-धीरे प्रजातांन्त्रिक समाजवाद की ओर झुकते चले गये। उन्होंने कार्ल मार्क्स को उन्नीसवीं शताब्दी का एक प्रभावशाली विचारक बताया,[85] और मार्क्सवाद के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से काफी प्रभावित हुए।[86]

इसके साथ ही साथ इस समय उन पर प्राचीन भारतीय वेदान्त दर्शन का भी प्रभाव दिखलाई पड़ता है। उन्होंने अपनी पुस्तक "भारत की खोज" में न केवल विज्ञान की महानता पर बल दिया वरन आध्यात्मिकता को भी मानव जीवन के लिए आवश्यक माना है। समाजवाद के सन्दर्भ में उन्होंने साम्यवाद की आलोचना की तथा गाँधी जी की ही भाँति साधनों की पवित्रता पर बल दिया।यद्यपि उन्होंने कई दृष्टियों से साम्यवाद की आलोचना की तथा अंत तक वे कुछ

---

81 - पं0 जवहार लाल नेहरु -ऐन आटोबायोग्राफ, पृष्ठ 526

82 - सेवियत रुस की उपलब्धियों का विवरण नेहरु जी ने अपनी पुस्तक "सोवियत एशिया" मे दिया है। यह पुस्तक उन्होंने 1928 ई0 में लिखी थी।सोवियत एशिया -पृष्ठ-50-74

83 - पं0 जवाहर लाल नेहरु ने अपनी पुस्तक "विश्व इतिहास की झलक" में रुसी क्रान्ति की काफी प्रशंसा की हैं और यह भी स्पष्ट किया है कि समाजवाद के आगमन, कार्ल मार्क्स व मजदूर संगठनों के प्रति आपकी गहरी रुचि थी। विश्व इतिहास की झलक- खण्ड 3 पृष्ठ 761-62, मेरी कहानी- पृष्ठ 105

84 - नेहरु जी के इन भाषणों का संकलन "नेहरु- व्यक्तित्व और विचार" नाम पुस्तक मे किया गया है। यह पुस्तक 1965 में प्रकाशित हुई थी

85 - पं0 जवाहर लाल नेहरु "विश्व इतिहास की झलक', खण्ड 2, पृष्ठ 753, नेहरु- व्यक्तित्व और विचार (सं.) पृष्ठ 366

86 - राय अखिलेन्द्र प्रशाद - सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 72

दृष्टियों से मार्क्स के विचारों से प्रभावित रहे।जैसे- अन्त तक इन्होंने शोषण का विरोध किया तथा साम्राज्य वादियों की आलोचना की। कार्नफ्लिट ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया है कि यह नहीं कहा जा सकता हैं कि नेहरु जी ने गाँधी जी के सभी विचारों को मान लिया था।कई दृष्टियों से उनके मतों में भिन्नता दिखाई पड़ती है।[87] नेहरु जी के समाजवादी चिन्तन का क्रमबद्ध विकास सन् 1929 के लाहौर अधिवेशन से प्रारम्भ होता है, जिसमें कांग्रेस ने "पूर्ण स्वाधीनता" का प्रस्ताव पारित किया है लाहौर अधिवेशन में नेहरु जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि मैं स्पष्ट रुप से यह स्वीकार करता हूँ कि मैं समाजवादी और लोकतन्त्र वादी हूँ और राजा महाराजाओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, और नहीं मेरी उस प्रणाली में निष्ठा है जिसमें जिसके परिणाम स्वरुप उद्योगों में आजकल के राजा (पूँजीपति) पैदा होते हैं।[88] इस भाषण से स्पष्ट होता है कि नेहरु जी की समाजवाद में निष्ठा थी, पर देश की परिस्थितियों को देखकर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारे समक्ष तीन बड़ी समस्याएं हैं अल्पसंख्यक,देशी नियासतें और मजदूर तथा किसान।इन समस्याओं पर नेहरु जी ने समाजवादी तरीके से विचार किया और इन्हें हल करने का भी प्रयत्न किया।[89]

झांसी प्रान्तीय राजनीतिक अधिवेशन (27 अक्टूबर 1927 ई0) में नेहरु जी ने अपने समाजवादी चिन्तन का स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा कि "हम लोगों के सभी बुराईयों का एक ही निदान है और यह है समाजवाद। इसलिए हमारा ध्येय समाजवाद होना चाहिए।समाजवाद की स्थापना एक दिन में नहीं हो सकती, किन्तु धीरे-धीरे नीति का निर्धारण करके अमीर-गरीब की दूरी कम की जा सकती है और अर्थिक शोषण तथा आर्थिक विषमता को समाप्त किया जा सकता है।इस समय देश में औद्योगीकरण का विकास हो रहा था, इसलिए नेहरु जी ने श्रमिकों की समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया और उन्हें अनेक सुविधाएं देने की बात कही।[90]

87 - डोरोथी नार्मन - नेहरु, खण्ड 1, पृष्ठ 377

88 - कांग्रेस प्रेसीडेन्सल एड्रेसेज (सं.) खण्ड 2, पृष्ठ 395-897, दिसम्बर 1929

89 - नेहरु जी ने अपने समाजवादी विचारों को कार्यरुप देने का प्रयत्न किया। उन्होंने देशी रियाशतों के उन्मूलन, उद्योगों के विकास व कृषि सुधार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया। नेहरु -व्यक्तित्व और विचार (सं.), पृष्ठ 402

90 - नेहरु-व्यक्तित्व और विचार, (सं.) पृष्ठ 392

नेहरु जी ने अपने समाजवादी चिन्तन का निरन्तर विकास किया। सन् 1934 में जब कांग्रेस में एक समाजवादी दल बना तो नेहरु जी ने उसकी सदस्यता स्वीकार न करते हुए उस दल के समाजवादियों का समर्थन प्राप्त किया। मई 1934 में नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में समाजवादी दल का पहला अधिवेशन पटना में हुआ जिससे नरेन्द्र देव के अलावा, जय प्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन सम्पूर्णनन्द, अशोक मेहता आदि प्रमुख समाजवादियों ने भाग लिया।[91] विभिन्न विद्वानों का मत है कि अब तक नेहरु जी मार्क्सवाद से प्रभावित थे और अपने लेखों तथा भाषणों में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, पूँजीवाद, वर्ग-संघर्ष, औद्योगिककरण आर्थिक असमानता आदि प्रश्नों पर मार्क्सवादी तरीके से विचार रखते थे।[92] राय अखिलेन्द्र प्रसाद ने इस सम्बन्ध नेहरु जी द्वारा लिखित "भारत किधर" नामक लघु पुस्तिका का उल्लेख किया, जिसमें नेहरु जी ने [93] उस समय के अपने समाजवादी विचारों को व्यक्त किया है। नेहरु जी पर गाँधी के व्यक्तित्व के प्रभाव को इंगति करते हुए एम.एन.राय [94] और सुभाष चन्द्र बोस ने उनका विरोध किया है। सुभाष चन्द्र बोस ने लिखा है- नेहरु अपने को समाजवादी क्रान्तिकारी कहते हैं, पर वे व्यवहार में महात्मा गाँधी के वफादार अनुयायी हैं।सम्भवतः यह कहना कठिन होगा कि उनकी बुद्धि वामपंथियों के साथ है, पर हृदय महात्मा गाँधी के साथ [95]

सन् 1936 के बाद नेहरु जी के समाजवादी चिन्तन में एक नया मोड़ आया। लखनऊ कांग्रेस के 49वें अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा "समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत है।वह समाज में उत्पादन, वितरण तथा अन्य क्रियाओं को संगठित करने का एक तरीका है, इसके समर्थकों के अनुसार समाज की मौजूदा बुराइयों से मुक्ति दिलाने का उपाय है।[96] नेहरु जी का विश्वास था कि भारत की आर्थिक असमानता को समाजवाद की स्थापना करके ही दूर किया जा सकता है। वे कहते हैं कि "मैं उस मूल आर्थिक सिद्धांत में विश्वास रखता

---

91 - एम. एन. दास -दि पोलिटिकिल फिलास्फी आफ पं0 जवाहरलाल नेहरु, पृष्ठ 129

92 - पट्टाभि सीता रमैया- कांग्रेस का इतिहास, खण्ड 1, पृष्ठ 455

93 - नेहरु जी के जीवनी लेखक सर्वपल्ली गोपाल ने लिखा है कि नेहरुजी के प्रारम्भिक समाजवादी विचार अस्पष्ट थे। 1929 ई0 के बाद वे मार्क्सवाद- लेनिनवाद के निकट आ गये और उन्होने गाँधी जी के खादी कार्यक्रम तथा ट्रस्टीशिप सिद्धांत की आलोचना की थी।सर्वपल्ली गोपाल-'जवाहर लाल नेहरु 'खण्ड 1, पृष्ठ 52-55,1933

94 - रायअखिलेन्द्र प्रसाद-सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 72 नेहरु "भारत किधर"(-नेहरु आन सोशलिज्म में संकलित), पृष्ठ 712-715

95 - सुभाष चन्द्र बोस- दि इडियन स्ट्रगल, पृष्ठ 39

96 - डोरोथी नार्मन-(सं.), नेहरु दि फर्स्ट सिक्सटी ईयर्स, पृष्ठ 450

हूँ जो रुस के सामाजिक ढ़ाँचे का आधार है। मैं यह भी सोचता हूँ कि रुस ने सांस्कृतिक और औद्योगिक यहाँ तक कि आध्यात्मिक दृष्टि से उल्लेखनीय प्रगति की है।[97] वे मार्क्सवादी लेनिनवादी व्यवस्था को पूर्ण रुप से स्वीकार करने के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने विजयलक्ष्मी पण्डित को एक पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि मैं रुस में जो कुछ हुआ उसे ज्यों का त्यों न तो स्वीकार करता हूँ और न ही समर्थन देता हूँ। मैं रुस का अन्धानुकरण नहीं करना चाहता, इसलिए मैं साम्यवाद के स्थान पर समाजवाद शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त समझता हूँ।[98] इससे स्पष्ट है कि नेहरु जी भारत के लिए साम्यवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना उपयुक्त मानते हैं। उनका विश्वास था कि भारत में गरीबी और बेकारी की जटिल समस्या को हल किये बिना समाजवाद की स्थापना असम्भव है। वे भारत की समस्या का एक मात्र समाधान समाजवाद को ही मानते हैं, इसलिए उसने अपने समाजवाद का आधार भारत की आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि को बनाया। उनका विचार था कि मैं समाजवाद के अतिरिक्त कोई अन्य दूसरा मार्ग नहीं देखता, जो गरीबी, अपमान और दासता से भारत के लोगों को मुक्ति दिला सके। लेकिन नेहरु जी ने अपने समाजवादी विचारों को कांग्रेस पर जबरन थोपने[99] का प्रयास नहीं किया फिर भी उन्होंने यह प्रयत्न अवश्य किया कि कांग्रेस अपने कार्यक्रमों का संचालन समाजवादी ढ़ाँचे के अनुरुप ही करे।

नेहरु ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के आलोचक हैं, वे कहते हैं कि ब्रिटिश पूंजीवाद का अन्त किये बिना समाजवाद की स्थापना सम्भव नहीं है। वे फासीवाद को विचित्र खिचड़ी बताकर उसका कड़ा विरोध करते है।[100] अपनी पुस्तक "विश्व इतिहास की झलक" में उन्होंने साम्राज्यवाद और फांसीवाद दोनों की कड़ी आलोचना की है।

नेहरु जी के समाजवादी चिन्तन की यह विशेषता रही है कि उन्होंने समाजवाद और राष्ट्रीयता में समन्वय स्थापित किया। समाजवाद के मुद्दे पर उनका गाँधी के अतिरिक्त, नरेन्द्र

---

97 - लियोनाद मिटोनिक (सं.) इण्डियाज ग्रेटसन्, पृष्ठ 7

98 - डोरोथी नार्मन (सं.), नेहरु फर्स्ट सिक्सटी ईयर्स, पृष्ठ 410

99 - नेहरु- व्यक्तित्व और विचार, पृष्ठ 403

100 - पं0 जवाहरलाल नेहरु- विश्व इतिहास की झलक खण्ड 2, पृष्ठ 1136-37

देव, जय प्रकाश नारायण, सुभाष चन्द्र बोस, डा0 राजेन्द्र प्रसाद, बल्लभ भाई पटेल, एम0 एन0 राय आदि नेताओं से उनका वैचारिक मतभेद हुआ।[101]

नेहरु जी ने अपने निबन्ध "लखनऊ से त्रिपुरी तक" में सन् 1936 ई0 से 1939 ई0 तक की देश की राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डाला है[102] इसमें हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन (1938) का विवरण शामिल है, जिसमे सुभाष चन्द्र बोस गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। इसी समय से नेहरु और कांग्रेसी समाजवादियों के बीच टकराहट आरम्भ हो गयी और एक बार उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि "स्वाधीनता से पहले कोई समाजवाद नहीं हो सकता। वास्तव में नेहरु जी ने गांधीवादियों और समाजवादियों दोनों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया"। उन्होंने लिखा है कि-मैंने इसकी पूरी कोशिश की कि पुराने नेताओं और नये समाजवादी गुट में कोई समझौता करा सकूँ, क्योंकि मेरा ऐसा विचार है कि साम्राज्यवाद से लड़ने में दोनों की जरुरत है।[103] इस प्रकार नेहरु जी ने कांग्रेस के अन्दर की दोनों विचारधाराओं को एक साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया, फिर भी उनमें मेल कराने में सफल नहीं हो सके।

स्वाधीनता के बाद भी नेहरु जी के समाजवादी चिन्तन में प्रजातांत्रिक समाजवाद की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जिन आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को दूर करने का आवश्वास दिया उनके मूल में उनकी समाजवादी भावना निहित है। इन समस्याओं में आर्थिक विषमता का उन्मूलन, गरीबी का निकास, किसानों और मजदूरों को सुविधाएं जन साधारण के लिए भोजन, आवास व वस्त्र आदि की उपलब्धता आदि मुख्य है।[104]

सन् 1950 में नेहरु जी ने अपने समाजवादी विचारों को व्यवहारिक रुप देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यक्रम प्रारम्भ किया।योजना आयोग[105] द्वारा प्रथम योजना (1951-56) बनायी गयी जिसमें मुख्यतः अधूरे काम पूरा करने का प्रयत्न किया गया। साथ ही युद्ध के

---

101 - पं0 जवाहरलाल नेहरु- कुछ पुरानी चिट्ठियाँ पृष्ठ 150-152, वाई0 जी0 कृष्णमूर्ति -जवाहरलाल नेहरु, पृष्ठ 27-28

102 - नेहरु जी का यह निबन्ध "दि युनिटी आफ इण्डिया" नामक पुस्तक में संकलित है।

103 - वही, पृष्ठ 95-98

104 - डोरीथी नार्मन- नेहरु दि फर्स्ट सिक्सटी ईयर्स, खण्ड 2, पृष्ठ 338

105 - योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ई0 को की गयी जिसके पहले अध्यक्ष पं0 जवाहर लाल नेहरु थे।

बाद की स्थिति से जटिल संकट का सामना करने का भी प्रयत्न किया गया। आजादी देश विभाजन के साथ मिली, और इसलिए सारे देश में भारी अफरा-तफरी मच गयी इतिहास का सबसे बड़ा जनसंख्या हस्तान्तरण हुआ और बड़े पैमाने पर शरणार्थियों के आने से समस्या और गंभीर हो गयी ।इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर नेहरु अपनी नीतियों से समझौता करते गये । कांग्रेस दल के समाजवादी भी इन्हीं सब कारणों से नाराज हुंए, उन्हें लगा कि समाजवाद के आदर्शों को जानबुझकर के नाकारा जा रहा है । दूसरे यह भी कि मन्त्रिमंडल में बल्लभ भाई पटेल के होने के कारण नेहरु अपने चरम लक्ष्य को कार्य रुप में प्रदान करने में अपने को असमर्थ पा रहे थे। पटेल जी के निधन के उपरान्त समाजवादी दल ने अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर कांग्रेस से सहयोग करने का निश्चय किया, परन्तु नेहरु ने इस संबन्ध में अपनी असमर्थता प्रकट की । यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पटेल की मृत्यु के बाद नेहरु जी स्वयं चार वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे । परन्तु कांग्रेस के किसी भी प्रस्ताव में उन समाजवादी आदर्शो का कोई संकेत मात्र नहीं था जिसके संबंध में नेहरु जी सन.1927 से चर्चा करते आ रहे थे ।दूसरी योजना (1956-61) में प्रसिद्ध नेहरु-महालनोबिस विकास रणनीति लागू की गयी जो तीसरी योजना (1961-66) में भी जारी रही । प्रो0 पी0 सी0 महालनोबिस ने द्वितीय योजना तैयार करने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । इस रणनीति का एक मूलतत्व भारी तथा मूल वस्तुओं के उद्योगों का विकास था, जो मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रों में होना था ।[106] भारी उद्योगों के विकास के साथ-साथ श्रम-गहन छोटे और गृह उद्योगों का विकास भी तय पाया गया ताकि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके ।यह समझा गया कि सामुदायिक विकास योजनाओं के तहत कृषि में सामुदायिक कार्यक्रम के जरिये श्रम का अधिकाधिक उपयोग करेंगे और पूँजी का उत्पादन करेंगे। इनमें कृषि सहकारिताओं की अपनी भूमिका होगी ।[107] लेकिन बेकारी की समस्या के समाधान हेतु कोई समुचित उपाय नहीं ढूंढ़ा गया ।

नेहरु-महालनोबिस रणनीति का एक और महत्वपूर्ण अंग विकास और समानता पर जोर था । इसलिए उद्योग और खेती में संकेन्द्रण और वितरण के प्रश्न पर काफी

106 - बिपिन चन्द्र पाल (सं.)- "आजादी के बाद भारत" (1947-2000), पृष्ठ 455

107 - विपिन चन्द्र पाल (सं0) "आजादी के बाद भारत "(1947-2000), पृष्ठ 455-56

ध्यान दिया गया, हालांकि इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली।रणनीति में विकास तथा समानता को एक दूसरे का विरोधी नहीं समझा गया। यह माना गया कि उच्चतर विकास से समानता के उच्चतर स्तरों तक पहुँचा जा सकता है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी वही नीति अपनायी गयी जो पहली योजना में थी। इसमें कृषि के स्थान पर उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान की गयी, परन्तु सामाजीकरण और राष्ट्रीय करण की नीति के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी,बल्कि जिस विचार को उन्होंने पहली योजना में रखा था,उसी को फिर दोहराया गया।

सन् 1955 ई0 में अवाड़ी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें यू0 एन ढेबर की अध्यक्षता में नेहरु सहित कांग्रेस ने, समाजवादी समाज की रचना का लक्ष्य स्वीकार किया। परन्तु इसके विपक्ष में कुछ समाजवादी और साम्यवादियों ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि यह मात्र मत प्राप्त करने का तरीका है। इस सिद्धांत में इस लक्ष्य को स्वीकार किया गया कि उत्पादन, सामाजिक स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में होगा तथा उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि और राष्ट्रीय आय का समता के आधार पर वितरण किया जायेगा। लेकिन समाजवाद और समाजवादी आधार पर समाज की रचना में काफी अन्तर है इस सम्बन्ध में नेहरु जी का प्रश्न नकारात्मक है, अप्रैल 1955 में नेहरु जी ने कहा था कि जनता को समाजवाद के सिद्धान्तों और समाजवादी आधार पर समाज की स्थापना में कुछ विशेषता ही मिलेगी, न कि अन्तर। दोनों वस्तुएं एक ही है इसमें किसी भी प्रकार का सूक्ष्म अन्तर नहीं है, लेकिन दोनों की व्याख्या करना कोई आसान कार्य नहीं है। किसी भी सिद्धांत की व्याख्या करना एक कठिन कार्य होता है और उस व्याख्या की चरम स्थिति एक ऐसे स्थान पर पहुँच जाती है जहाँ वह सिद्धांत ही शुष्क और धूमिल पड़ने लगता है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं होता कि हम समाजवादी समाज के सिद्धान्तों का विश्लेषण ही नहीं करेंगे। यह सत्य है कि इस सिद्धांत को वास्तविक क्रियात्मक रुप प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता तो अवश्य ही एक अच्छे मार्ग का निर्माण हो सकता था।

सन् 1954 में अपनी चीन यात्रा के दौरान नेहरु ने वहाँ की आर्थिक प्रगति को देखा तथा उसी प्रकार की तीव्र प्रगति की कल्पना भारत के सन्दर्भ में भी करने लगे। लेकिन नेहरु को चीन की शासन व्यवस्थ और भारतीय शासन व्यवस्था में स्पष्टतः भिन्नता दिखाई पड़ी। फिर भी वे

इस बात पर सोचने को मजबूर हो गये कि संसदीय (प्रजातान्त्रिक) प्रणाली से अधिक आर्थिक उन्नति की जा सकती है या साम्यवाद व्यवस्था के अन्तर्गत। नेहरु अपने समाजवादी समाज की स्थापना जनतान्त्रिक आधारों पर करना चाहते थे। इस समय तक नेहरु जी के विचारों में काफी भिन्नता आ गयी थी। अब नेहरु किसी आर्थिक सिद्धांत की घोषणा न करके मध्यम वर्ग का अनुकरण करने लगे थे। सन् 1958 ई0 में उन्होंने कहा था कि मैं किसी प्रकार के राज्य समाजवाद को पसन्द नहीं करता हूँ, जिसमें राज्य ही सर्वे-सर्वा हो तथा व्यवहार में प्रत्येक क्रिया पर शासन करे। राज्य राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली होता ही है। मेरा समाजवाद के सम्बन्ध में विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होने चाहिए।[108]

सन् 1964 ई0 में कांग्रेस के भुवनेश्वर अधिवेशन में नेहरु जी ने जो वक्तव्य दिया,[109] उससे स्पष्ट होता है कि उनके समाजवादी चिन्तन में एक नया मोड़ आ गया है। अब वे लोकतान्त्रिक समाजवाद के हामी बन गये जो कि व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक न्याय पर आधारित है।[110] इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके अनुसार लोकतंत्र और उसकी विचार धारा समाजवाद का साधन है। समाजवाद के इस नये रुप को विद्वानों ने नेहरु का समाजवाद कहकर पुकारा है। जिसमें व्यक्ति का सम्मान,लोकतान्त्रिक व्यवस्था और मानवतावादी दृष्टि की प्रधानता है।[111]

नेहरु जी का समाजवादी चिन्तन विकासमान रहा है।[112] प्रारम्भ में वे एक कल्पनावादी समाजवादी के रुप में, हमारे सामने आते हैं, पुनः मार्क्सवाद-लेनिनवाद से प्रभावित होकर वे वैज्ञानिक समाजवाद का समर्थन करने लगते हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध शुरु होने के बाद वे गाँधीवाद से प्रभावित होकर अपने समाजवादी चिन्तन में आध्यात्मिकता को प्रथम स्थान देने लगते है और स्वाधीनता के बाद वे लोकतान्त्रिक समाजवाद समर्थक हो जाते हैं। नेहरु जी के समाजवादी

---

108 - माइकेल ब्रेचर -"ए पोलिटिकल बायोग्राफी आफ जवाहर लाल नेहरु," पृष्ठ 204

109 - भुवनेश्वर अधिवेशन में नेहरु जी ने स्पष्ट रुप से कहा था कि भारत एक समाजवादी राज्य होगा। अभय राव, बी0 जी0 राव- सिक्स थाउजेन्ड डेज, पृष्ठ 20

110 - डा0 शोभा शंकर- आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, पृष्ठ 122

111 - सोशलिज्म इन इण्डिया (सं.), पृष्ठ 18

112 - पी0 डी0 कौशिक ने स्वाधीनता के पूर्व की कांग्रेस की समाजवादी विचारधारा के विकास को तीन चरणों 1920-1929, 1929-1934 और 1934-1937 में बाँटा हैं। स्वाधीनता के बाद इसके दो चरणों अवाड़ी अधिवेशन से पूर्व और अवाड़ी अधिवेशन के बाद और जोड़े जा सकते हैं। दि कांग्रेस आइडियोलोजी एण्ड प्रोग्राम, पृष्ठ 127 डा0 शोभाशंकर- आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन पृष्ठ 123

विचारों की समीक्षा करते हुए अनेक विद्वानों ने यह मत व्यक्त किये हैं कि स्वाधीनता से पूर्व नेहरू जी के समाजवादी विचार जितने प्रखर थे उतने प्रधान मंत्री बनने के बाद नहीं रहे।[113] नम्बूदरीपाद जैसे कुछ साम्यवादी नेताओं ने नेहरू के समाजवादी विचारों की आलोचना की है।[114] माइकेल ब्रेचर ने उनके समाजवादी चिन्तन को उलझन भरा बताया है ।[115] लेकिन इस आलोचनाओं में सत्यता कम है, वास्तव में नेहरू जी ने अपने समाजवादी चिन्तन को अपने लेखन द्वारा स्पष्ट करने की चेष्टा की है ।वे मुख्यतः एक लोकतान्त्रिक समाजवादी हैं और वे लोकतान्त्रिक मूल्यों के आधार पर नये भारत का निर्माण करना चाहते हैं ।[116]

V- आचार्य नरेन्द्र देव :(सन् 1889-1956 ई0)

आचार्य नरेन्द्र देव समाजवाद के प्रारम्भिक चिन्तकों में से थे । बीसवीं शताब्दी के प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् जब समाजवादी विचारों का हमारे देश में विकास होने लगा तब नरेन्द्र देव ने इसे न केवल स्वीकार किया वरन् आगे बढ़ाने में भी अग्रणी रहें । प्रारम्भ में वे कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और उन्होंने कांग्रेस में रहकर समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाने की सफल कोशिश की लेकिन बाद में उन्होंने यह अनुभव किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियां उनकी समाजवादी धारणओं से भिन्न थी । अतः भारत के स्वतन्त्रता के पश्चात् वे कांग्रेस से अलग हो गये तथा कांग्रेस से पृथक होकर समाजवादी आन्दोलन को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील हो गये । कांग्रेस के साथ रहकर और कांग्रेस से पृथक होकर उन्होंने अनेकों गतिविधियों का संचालन किया ।

नरेन्द्र देव पर अपने विद्यार्थी जीवन से ही देश की राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों का प्रभाव पड़ने लगा था ।[117] 1906 में जब उन्होंने मेयो सेन्ट्रल कालेज में प्रवेश लिया तो वहाँ का हिन्दू बोर्डिग हाउस उग्रवादी विचारों का केन्द्र बना हुआ था । वहाँ की उग्रवादी विचारधाराओं ने

---

113 - अभय राव, बी0 जी0 राव- सिक्स थाउजेन्ड डेज, पृष्ठ 5

114 - रफीक जकारिया-ए स्टडी आफ नेहरु, पृष्ठ 272

115 - माइकेल ब्रेचर (सं.)-नेहरु पोलिटिकल बायोग्राफी, पृष्ठ 597

116 - जवाहर लाल नेहरु-यूनिटी आफ इण्डिया, पृष्ठ 110 वही- इन्डीपेन्डेन्स एण्ड आफ्टर, पृष्ठ 231 नेहरु के भाषण-(1949-1953) वही,- (1953-1957) इन भाषणों में नेहरु जी के लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारों की झलक मिलती है ।

117 - राय अखिलेन्द्र प्रसाद -सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 89

उन्हें प्रभावित किया ।[118] आचार्य नरेन्द्र देव ने अपना राजनीतिक जीवन तिलक एवं अरविन्द के अतिवादी राष्ट्रवाद के अनुयायी के रुप में शुरु किया । गाँधी जी द्वारा असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने पर वे उसमें सम्मिलित हुए । सन् 1934 ई0 में उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी के उद्घाटन का सभापतित्व किया। आचार्य नरेन्द्र देव की गणना भारत के प्रमुख समाजवादी बुद्धिजीवियों तथा प्रचारकों में की जाती है ।[119] उनकी भारतीय किसान आन्दोलन में भी काफी गहरी रुचि थी । वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापकों में से थे । दो बार उनको इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया । वे कई वर्ष तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे ।वे इस पक्ष में नहीं थे कि समाजवादी कांग्रेस से पृथक हों,किन्तु दल के निर्णय के आगे उन्हें झुकना पड़ा ।[120]

नरेन्द्र देव जी गाँधी जी से प्रभावित थे, गाँधी जी के साथ उनका घनिष्ठ संबन्ध था और गाँधी जी पर उनका व्यक्तिगत स्नेह भी था।नरेन्द्र देव जी नैतिक समाजवादी थे इस कारण वे नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देते थे । वे समाजवाद को एक सांस्कृतिक आन्दोलन भी मानते थे, इसलिए उन्होंने समाजवाद के मानववादी आधार पर बल दिया ।उन्होंने हिन्दू तथा बौध चिन्तन का गंभीर अध्ययन किया था, जिसके फलस्वरुप मूल्यों की पवित्रता में उनकी आस्था अधिक गहरी हो गयी थी ।[121] उन्होंने सत्य की व्यवहारवादी कसौटी को स्वीकार करने से स्पष्टत : इन्कार कर दिया । उनकी दृष्टि में सत्य प्राथमिक तथा बुनियादी चीज थी किन्तु इसके बावजूद वे गाँधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को समग्र रुप में मानने के लिए तैयार नहीं थें ।[122]

नरेन्द्र देव जी विचारधारा की दृष्टि से मार्क्सवादी थे । यद्यपि उन्होंने द्वन्दात्मक भौतिकवाद के दर्शन की विशद व्याख्या नहीं की फिर भी उन्होंने उसके सामान्य सिद्धांतों का विवेचन किया। उनका कहना था कि वास्तविकता जटिल है, किन्तु द्वन्दात्मक पद्धित वास्तविकता

---

118 - जी0 एस0 भार्गव- लीडर्स आफ दि लेफ्ट, पृष्ठ-25-26

119 - विश्वनाथ प्रसाद वर्मा-"आधुनिक भारतीय राजनीति चिन्तन", पृष्ठ 530

120 - नरेन्द्र देव ने कहा कि अगस्त 1947 तक कांग्रेस एक राष्ट्रीय मोर्चा थी, अब वह अपने इस रुप को खो बैठी है और एक पार्टी बन गयी हैं । उन्होंने कांग्रेस की सत्तावादी तथा केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों की आलोचना की। आचार्य नरेन्द्र देव-"राष्ट्रीयता और समाजवाद" पृष्ठ 317-19

121 - "विश्वनाथ प्रसाद वर्मा -"आधुनिक भारतीय राजनीति चिन्तन" पृष्ठ 531

122 - विश्वनाथ प्रसाद वर्मा-"आधुनिक भारतीय-राजनीति चिन्तन, पृष्ठ 531

को उसके समग्र तथा जटिल रुप में समझने का प्रयत्न करती है ।[123] वे द्वन्दवाद के सिद्धांत तथा पद्धित को स्वीकार करते थे, किन्तु उसमें सन्देह है कि वे मार्क्सवादी के रुप में भौतिकवाद के समग्र दर्शन को अंगीकार करने के लिए उद्धत थे। फिर भी वे मार्क्सवाद को भौतिकवादी एकत्ववाद वे रुप में मानते थे और गति की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते थे,जिसका अर्थ है कि विश्व एक प्रक्रिया है । नरेन्द्रदेव जी वैज्ञानिक समाजवादी होने का दावा करते थे ।उनका कहना था,"हमारे सामने जो काम है उसे हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम समजावाद के सिद्धांत और उद्देश्यों को हृदयगम कर लें तथा परिस्थितियों को सही ज्ञान के लिए मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वन्दात्मक पद्धति को समझें और उसे अपने कार्यकलाप का आधार बनाने का प्रयत्न करे । हमें वैज्ञानिक समाजवाद का आश्रय लेना चाहिए,और यूटोपियाई समाजवाद अथवा सामाजिक सुधारवाद से बचने का प्रयास करना चहिए। विद्यमान सामाजिक व्यवस्था का क्रान्तिकारी रुपांतर ही परिस्थितियों की आवश्यकता को पूरा कर सकता है । उससे कम किसी चीज से काम नहीं चल सकता ।[124]

नरेन्द्र देव जी बुखारिन की प्रसिद्ध पुस्तक "हिस्टोरिकल मैटीरियलिज्म" (ऐतिहासिक भौतिकवाद) से काफी प्रभावित थे । उन्होंने बुखारिन की वर्गो की कसौटी तथा विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया। उसकी भाँति वे भी मानते थे कि समाज में पूँजीपतियों तथा सर्वहारा के अतिरिक्त अन्य वर्ग भी होते हैं, जैसे-मध्यमवर्ग, संक्रमणवर्ग तथा मिश्रित वर्ग ।[125] लोकतान्त्रिक समाजवाद के समर्थक होने के नाते नरेन्द्र देव राज्य के नौकरशाही हस्तक्षेप के विरुध थें। इसलिए उनका प्रस्ताव था कि मजदूरों का एक वर्ग के रुप में उद्योग के प्रबन्ध में साझा होना चाहिए । यद्यपि उनका गांधी जी से घनिष्ठ सम्बन्ध था,फिर भी उन्होंने वर्ग-संघर्ष के सिद्धांत का परित्याग नही किया[126] नरेन्द्र देव जी ने भारत की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को

---

123 - नरेन्द्र देव -सोशलिज्म एण्ड नेशनल रिवोल्यूशन, पृष्ठ 148

124 - वही, पृष्ठ 24-25

125 - वही, पृष्ठ 417-19

126 - नरेन्द्र देव ने यहाँ तक कह दिया कि गाँधीवादी हिंसा वर्ग विहीन समाज में अन्ततः पर्यवसित होने की क्षमता रखती है।"अंहिसा ब्रत के अपने इस अनुसंधान से गाँधीवाद को यह तथ्य मिला है कि वर्ग भेदों और सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को मिटाये बिना समाज में से हिंसा का उन्मूलन संभव नहीं है । अतः वर्ग विहीन समाज इसका ध्येय है और समत्व युक्त समाज की एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था इसे करनी है जिससे जनतन्त्र का भाव नष्ट न हो जाये और मनुष्य की

वर्ग संघर्ष की दृष्टि से समझने का प्रयत्न किया । वे इस पक्ष में थे कि निम्न मध्यम वर्गो तथा सामान्य जनता के बीच मैत्री सम्बन्ध कायम किये जाय । उनका कहना था कि साधारण जन समुदाय अनुसंघनीय अधिकारों तथा लोक प्रभुत्व के सामान्य सिद्धान्तों से आकृष्ट नहीं हो सकता । उसमें वर्ग चेतना तभी उत्पन्न हो सकती है जबकि उससे आर्थिक हितों की भाषा में बात किया जाय।[127]

समाजवादी क्रान्ति के सम्बन्ध में नरेन्द्र देव जी लेनिन के विचार से सहमत थे । लेनिन के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि समाजवादी क्रान्ति पहले उस देश में हो जो औद्योगिक दृष्टि से सबसे अधिक विकसित है वह तो उस देश में होगी जहाँ साम्राज्यवादी शृखला सबसे दुर्बल है।[128] नरेन्द्र देव जी श्रमिक वर्ग को साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष का हिरावल (अग्रगामी टुकड़ों) तथा किसानों और बुद्धिजीवियों को उसका सहायक मानते थे ।[129] उन्हें कोरे सुधारवाद और संविधानवाद से सहानुभूति नहीं थी ।[130] उनका कहना था कि "जन समुदाय को क्रियाशील बनाने तथा देश को लोकतन्त्र के लिए तैयार करने का एक मात्र उपाय यह हैं कि किसी लोक हितकारी आर्थिक विचारधारा को अंगीकार करके राष्ट्रीय संग्राम का समाजीकरण किया जाय।[131]

नरेन्द्र देव जी ने समाजवादी आन्दोलन तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे चाहते थे कि समाजवादियों को राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में सम्मिलित होकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए । यदि वे अपने को राष्ट्रीय आन्दोलन से पृथक रखते हैं तो उनका यह कार्य आत्म हत्या करने के समान होगा । उन्होंने समाजवादियों को यह मानने की सलाह दी कि एक औपनिवेशिक देश के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता समाजवाद के मार्ग में एक अपरिहार्य अवस्था है ।[132]

सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो ।" (नरेन्द्रदेव- राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ 740, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा -आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 532 से उद्धृत)

127 - नरेन्द्र देव- "सोशलिज्म एण्ड नेशनल रिवोल्यूशन, पृष्ठ 8

128 - वही, पृष्ठ 22-23

129 - वही, पृष्ठ 23

130 - वही, पृष्ठ 28

131 - वही, पृष्ठ 29-30

132 - नरेन्द्र देव- "सोशलिज्म एण्ड नेशनल रिवोल्यूशन" पृष्ठ 4

नरेन्द्र देव जी ने कांग्रेस के अगस्त 1948 के प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि यह प्रस्ताव स्वतन्त्रता के सामाजिक पहलू की व्याख्या करता है ।[133] वह खेतों तथा कारखानों की सम्पूर्ण शक्ति को श्रमिक वर्ग में निहित करना चाहता है । उनकी दृष्टि में अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य जन साधारण की सर्वोच्चता स्थापित करना था ।

नरेन्द्र देव जी जन समुदाय की एकता के समर्थक थे। वे चाहते थे कि जन समुदाय की क्रान्तिकारी भावना को तीव्र किया जाय और उन्होंने स्वयं जनता को क्रान्तिकारी कार्यवाही के लिए उत्तेजित करने का कार्य किया ।[134]उनका विचार था कि सामाजिक तथा आर्थिक मुक्ति के जिस कार्य को पश्चिमी यूरोप में अठारहवीं शताब्दी में पूँजीपतियों ने किया था, उसे भारत में शोषित जनता के संगठन के द्वारा सम्पादित करना होगा ।[135] उनकी दृष्टि में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के आधार को व्यापक बनाने के लिए जनता में रचनात्मक कार्य करना आवश्यक था ।[136] भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद देशी राजाओं, पूँजीपतियों तथा सामन्तों की सहायता से अपनी जड़ों को मजबूत करने का प्रयत्न कर रहा था । इस प्रकार शोषण की व्यवस्था के स्तम्भों को दृढ़ बनाया जा रहा था ।पूँजीपतियों ने भी जमीदारों के साथ समझौता कर लिया था । प्रति क्रान्तिकारी शक्तियों के इन गठबन्धनों ने शोषित जनता के कार्य को भी कठिन बना दिया था। उसे देश की राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार की मुक्ति के लिए संघर्ष करना था। ऐसी स्थिति में औद्योगिक मजदूरों, किसानों तथा निम्न मध्यम वर्ग का संयुक्त मोर्चा आवश्यक हो गया था ।इसी प्रकार आर्थिक तथा राजनीतिक संघर्ष सफलता की अधिक आशा के साथ चलाया जा सकता था ।इसीलिए नरेन्द्र देव जी ने देश के स्वाधीनता संग्राम के आधार को मजबूत बनाने पर बल दिया । उन्हें आशा थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त संसार में अनेकों जन क्रान्तियाँ होंगी।[137]

नरेन्द्र देव जी भारतीय कृषकों के बहुत हिमायती थे । वे उनका पुनिर्निमाण करना चाहते थे । इसलिए उन्होंने किसानों के आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए किसान सभाओं को

---

133 - वही, पृष्ठ 167
134 - वही,पृष्ठ 149
135 - वही, पृष्ठ 68-69
136 - वही, पृष्ठ 87
137 - विश्वनाथ प्रसाद वर्मा," आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन," पृष्ठ 533

संगठित किया । उनका आग्रह था कि सभी प्रकार के किसानों की शक्तियों को एक जुट किया जाय ।भारत में किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की समस्याएं बड़ी विकराल थी ।जो जन समुदाय खेती-बाड़ी में लगा हुआ था उनका अत्यधिक गरीबी से किसी न किसी प्रकार से उद्धार करना आवश्यक था । इसके लिए देहाती जीवन के पुनर्निर्माण की एक क्रान्तिकारी योजना की आवश्यकता थी ।नरेन्द्र देव, स्टालिन की इस बात से पूर्णतः सहमत थे कि किसानों के विशाल समुदाय को समाजवादी विचारधारा से अनुप्रमाणित करना आवश्यक है ।[138] बहुसंख्यक किसानों को देश के समाजवादी पुनर्निर्माण की योजना से सम्बद्ध करने के लिए सहकारी समितियों को संगठित करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना अति आवश्यक था ।नरेन्द्र देव जी ने कृषि को सहकारी आधार पर संगठित करने का समर्थन किया। उनका आग्रह था कि ऋण निरस्त कर दिये जाए और किसानों के लाभ के लिए सस्ते ब्याज पर ऋण की व्यवस्था की जाय ।[139]

भूमि व्यवस्था का क्रान्तिकारी रुपान्तर करने के लिए आवश्यक था कि वास्तविक कृषकों तथा राज्य के बीच जो बहुत से बिचौलिये थे उनका उन्मूलन कर दिया जाय । किन्तु नरेन्द्र देव जी राष्ट्रीय समस्याओं को किसानों के वर्गगत दृष्टिकोंण से देखने के लिए तैयार नहीं थे । उन्होनं 'किसानवाद' की निन्दा की उसे एक प्रकार का ऐसा ग्रामवाद बताया जो किसानों की विचारधारा को आवश्यकता से अधिक महत्व देता था ।इस बात का भय था कि किसानवाद से कहीं देहात तथा नगरों के बीच हानिकारक संघर्ष न उत्पन्न हो जाय।नरेन्द्र देव जी इस पक्ष में थें कि गाँवों में सहकारी व्यवस्था[140] कायम करके लोकतान्त्रिक ग्राम सरकार की स्थापना की जाय। जनता के पिछड़ेपन को दूर करने तथा उसे नवीन आदर्शों और आकांक्षाओं से अनुप्रमाणित करने के लिए नरेन्द्रदेव जी ने इस बात का समर्थन किया कि भारत के गाँवों मे किसी न किसी रुप में नवीन जीवन आन्दोलन प्रारम्भ किया जाय ।[141] भारत के समाजवादी चिन्तकों में आचार्य नरेन्द्र देव का विशेष स्थान रहा है । उनकी गणना भारतके प्रमुख समाजवादी बुद्धिजीवियों तथा प्रचारकों में की जाती है । गाँधी जी के घनिष्ठ समर्थक होते हुए भी विचारों से वे मार्क्सवादी थे ।

---

138 - नरेन्द्र देव- "सोशलिज्म एण्ड नेशनल रिवोल्यूशन," पृष्ठ 87

139 - वही, पृष्ठ 161

140 - वही, पृष्ठ 54

141 - वही, पृष्ठ 183

वे मार्क्स के द्वन्दात्मक भौतिकवाद में द्वन्दवाद का समर्थन करते थे ।किन्तु भौतिकवाद में उरनकी आस्था नहीं थी। वे वैज्ञानिक समाजवाद के समर्थक थे । नरेन्द्र देव एक ओर लोकतान्त्रिक समाजवाद के समर्थक थे तो दूसरी ओर वे वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त के भी ।वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त के माध्यम से उन्होंने भारत की आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया ।सामान्य जनता में वर्ग चेतना का संचार करने के लिए उनकी दृष्टि में निम्न मध्यम वर्ग तथा साधारण वर्ग में मधुर संबंधों की स्थापना आवश्यक थी । वे कृषकों,बुद्धिजीवियों के सहयोग से श्रमिक वर्ग को समाजवाद विरोधी संघर्ष का अग्रगामी मानते थे ।वे भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम को आर्थिक आधार प्रदान कर उसका सामाजीकरण चाहते थे । वे किसानों को समाजवादी विचारधारा से अनुप्रमाणित करना चाहते थे । उनका कृषक को पुनर्निर्माण का कार्यक्रम सहकारी समितियों के संगठन पर आधारित था। वे कृषी भी सहकारिता के आधार पर उन्नत करना चाहते थे तथा कृषकों और ग्राम विकास के लिए सस्ते ऋण की व्यवस्था के पक्षपाती थे । वे गांवो में लोकतान्त्रिक सरकार के पक्ष में थें ।

vi- डा0 राम मनोहर लोहिया (1910-1967 ई0)

भारतीय समाजवाद के प्रणेताओं में डा0 राममनोहर लोहिया को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है । वे एक लड़ाकू व्यक्तित्व वाले प्रखर समाजवादी नेता माने जाते हैं ।लोहिया ने जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय में "नमक और सत्याग्रह" नामक शोध प्रबन्ध पर पी0 एच0 डी0 की उपाधि ग्रहण की । जर्मनी में ही उन्हें समाजवाद की प्रेरणा प्राप्त हुई ।[142] उनके प्रारम्भिक समाजवादी चिन्तन पर हीगल और मार्क्स का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है । वे गाँधी जी के यक्तित्व से भी काफी प्रभावित थे । उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल एक ऐसा समाजवाद लाने का प्रयास किया जो एशिया के सभी अविकसित देशों में स्थापित किया जा सके । उन्होंने स्वयं लिखा है-यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि [143] भारत का समाजवादी आन्दोलन अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकता है या उसे सदैव दक्षिण या वामपंथी बैसाखियों की जरुरत पड़ती

---

142 - राय अखिलेन्द्र प्रसाद "सोशलिस्ट थाट इन माईन इण्डिया," पृष्ठ 124 राय अखिलेन्द्र प्रसाद ने लिखा है कि लोहिया जर्मनी के लोकतान्त्रिक समाजवादी शूमचर तथा ब्रिटिश समाजवादी वेल्स फोर्ड के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे आये थे और उनके विचारों से काफी प्रभावित थे ।

143 - डा0 शोभाशंकर -"आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन", पृष्ठ 155

रहेगी। वास्तव में लोहिया न केवल भारत के लिए वरन् एशिया के सभी [144] पिछड़े देशों के लिए एक नये समाजवाद को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, यही तथ्य उनके समाजवादी चिन्तन का आधारभूत तत्व है।

लोहिया ने सर्वप्रथम अपने समाजवादी विचारों का प्रतिपादन एक सम्पादक के रुप में किया।[145] उन्होंने लिखा कि "समाजवादियों को साम्यवादियों या उदारवादियों के साथ मित्रता के संबंध रखने चाहिए । केवल इसी तरह विश्वभर में और भारत में एक सहज और सृजनात्मक समाजवाद की रचना होगी।[146] द्वितीय विश्वयुद्ध में लोहिया ने अपना एक चार सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध किया।[147] सन् 1940 से 1947 तक राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन में लोहिया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और वे कई बार जेल भी गये [148] उन्होंने देश के विभाजन का प्रबल विरोध किया।[149].

स्वाधीनता के बाद मार्च 1948 में स्वतन्त्र समाजवादी दल की स्थापना में लोहिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने समाजवादी दल से सदैव यह अपेक्षा की कि वह एक लड़ाकू मंच के रुप में कार्य करे। उन्होंने स्वाधीन भारत में जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए कई जन आन्दोलन चलाये और जेल यात्रा भी की।उनहोंने पूर्वी उत्तर प्रदेश, चम्पारन, मैसूर विन्धय प्रदेश आदि जन आन्दोलनों का समर्थन किया।[150] उनकी अध्यक्षता में 25 फरवरी 1950 ई0 को रीवां (मध्य प्रदेश) किसान पंचायत के प्रथम सम्मेलन में सर्वप्रथम "गरीबी हटाओं कार्यक्रम" बनाया गया। सन् 1953 में जब समाजवादी दल और किसान मजदूर प्रजा पार्टी को

---

144 - राम मनोहर लोहिया-"समाजवादी एकता" पृष्ठ 12

145 - सन् 1935 में "कांग्रेस सोशलिस्ट" नामक पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से प्रारम्भ हुआ, जिसके सम्पादक लोहिया बनाये गये थे।

146 - सन् 1936 मे लोहिया को पं0 जवाहर लाल नेहरु ने कांग्रेस के परराष्ट्र विभाग का कार्य सौपा। इस पद पर रहकर उन्होंने एशिया व भारत की राजनीति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने साम्यवादियों और समाजवादियों के वैचारिक मतभेद का अनुभव किया और निष्कर्ष निकाला कि समाजवादी आन्दोलन की सफलता के लिए सभी समाजवादियो मे एकता का होना आवश्यक है।राम मनोहर लोहिया,- समाजवादी एकता, पृष्ठ 17, कांग्रेस समाजवादी दल के अन्दर साम्यवादियों की निन्दनीय भूमिका का वर्णन एम0 आर0 मसानी ने भी किया है।
एम0 आर0 मसानी, "दि कम्युनिष्ट पार्टी आफ इण्डिया, पृष्ठ 69

147 - इन्दुमति केलकर-लोहिया, सिद्धांत और कर्म, पृष्ठ 74

148 - ओंकार सरद ने लोहिया की आत्मकथा में उनके राजनीतिक जीवन का विस्तृत विवरण दिया है।

149 - ओंकार शरद (सं.)-लोहियाके विचार, पृष्ठ 243-244

150 - लोहिया ने दाम बॉधो, जाति तोड़ों, हिमालय बचाओं, अंग्रेजी हटाओं जैस जन आन्दोलन चलाये।

मिलाकर प्रजा समाजवादी दल की स्थापना हुई, तब लोहिया बड़े असंतुष्ट हुए[151] क्योंकि वे समझौतावादी नीति के विरुद्ध थे । इसी के परिणाम स्वरुप 28 दिसम्बर 1955 ई0 को हैदराबाद में उन्होंने समाजवादी दल की पुनर्स्थपना की। [152] सन् 1963 से 1967 तक लोहिया ने लोक सभा में अन्दर रहकर कांग्रेस सरकार की कटु आलोचना की और समाजवादी एकता को ध्यान में रखकर संयुक्त समाजवादी दल को अपना पूरा समर्थन दिया ।[153]

लोहिया के समाजवादी चिन्तन पर गाँधी जी का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है । गाँधी जी भी लोहिया से विशेष लगाव रखते थे [154] सन् 1941 में जब लोहिया जेल में थे, गाँधी जी ने कहा था-"जब तक राममनोहर लोहिया जेल में हैं, तब तक मैं खामोश नहीं बैठ सकता, उनसे ज्यादा बहादुर और सरल आदमी मुझे मालूम नहीं "[155] लोहिया गाँधी जी को राष्ट्रपिता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते थे । उन्होंने गाँधी जी के अहिंसा सिद्धांत को अपने क्रान्ति दर्शन और अहिंसात्मक सत्याग्रह के सिद्धांत को अपने सिविल नाफरमानी के सिद्धांत में स्वीकार किया है । उनके अनुसार "सिविल नाफरमानी या अन्याय से शान्ति पूर्वक लड़ना अपने आप में कर्त्तव्य है "[156] लेकिन लोहिया "गाँधीवाद और समाजवाद" में गाँधीवाद के अन्तर्विरोधों का उल्लेख किया है । उनका मत था कि गाँधी जी ने जीवन के भौतिक और अर्थिक आधार की ओर ध्यान नहीं दिया ।[157] लोहिया गाँधीवादी हृदय परिवर्तन में भी आस्था नहीं रखते थे और अन्याय का विरोध करने के लिए घेराव के सिद्धांत का समर्थन किया और श्रम क्रान्ति का आवह्न किया।[158]

इतना होने पर भी लोहिया गाँधी जी के प्रभाव में सदैव रहे। उनके अनुसार गाँधी जी ने हमें वह मार्ग दिखाया, जिसके जरिए साधारण लोग भी सुकरात या प्रहलाद जैसे बन सकते हैं,

---

151 - लोहिया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को "लकवा मार" कहते थे और उसमें लड़ाकूपन कमी बताये लोहिया -समाजवादी एकता, पृष्ठ 18

152 - इस समाजवादी दल मे मधुलिमये, राजनारायण, मनीराम बागड़ी लाडली मोहन निगम, रविराय, बालेश्वर दयाल, बद्री विशाल आदि समाजवादी नेता शामिल थे ।

153 - सन् 1956 में समाजवादी दल और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मिलन के फलस्वरुप संयुक्त समाजवादी दल का निर्माण हुआ

154 - ओंकार शरद ने राम मनोहर लोहिया और गाँधीजी के सम्बन्धों का विस्तृत विवरण दिया है । ओकार शरद-'लोहिया', पृष्ठ 106-113

155 - लोहिया- सिविल नाफरमानी सिद्धांत और अमल पृष्ठ 7

156 - लोहिया "मार्क्स गाँधी एण्ड सोशलिजम" पृष्ठ 133

157 - लोहिया -क्रान्तिकरण पृष्ठ 39

158 - इन्दुमति केलकर- जन का लोहिया अंक पृष्ठ 128

वह कष्ट उठाने का हथियार सिविल नाफरमानी था ।[159] गाँधी जी के निधन पर स्वयं लोहिया ने अपने को अनाथ घोषित किया[160] और गाँधी जी के समाजवाद को अपने चिन्तन के अनुकूल ढालकर उसे यथार्थ रुप में प्रस्तुत किया। विद्वानों ने लोहिया को गाँधीवाद का विकसित उत्तराधिकारी बताया ।[161] इन्दुमति केलकर के अनुसार गाँधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों ने तो गाँधीवाद का एक करुणा का बाजू पकड़ा और क्रोध का दूसरा बाजू छोड़ दिया ।इससे उनके द्वारा भी गाँधीवाद की रक्षा न हो सकी । लेकिन इनके दगा देने के बाद भी गाँधीवाद जिन्दा रहा और लोहिया ने उसे बचाया । लोहिया ने गाँधीजी के मूल सिद्धान्तों को जीवित रखा, आगे बढ़ाया और नये सिद्धान्तों के जन्म दिया ।[162]

भारत के अन्य समाजवादियों के समान लोहिया भी मार्क्सवाद से प्रभावित हुए । उन्होंने भी कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समजावाद का महान व्याख्याकार माना है [163] और अपने अनेक लेखों में अपने मार्क्सवादी सिद्धांतों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने मार्क्सवाद की पूंजी संचय संबन्धी सिद्धांत और पूँजीवादी एकाधिकारवाद तथा श्रम के समाजीकरण को स्वीकार किया, तथा वर्ग-संघर्ष और विश्वक्रान्ति को ये मान्यता नहीं देते है ।[164] लोहिया मार्क्सवाद के आर्थिक विश्लेषण को भी ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किये और लेनिन के इस विचार से सहमत थे कि साम्राज्यवाद पूँजीवाद की अन्तिम मंजिल है ।[165] उनके अनुसार"साम्राज्यवाद केवल पूँजीवाद के प्रथम चरण में दिखाई ही नहीं देता, बल्कि वह उसके साथ विकसित भी होता जाता है । [166] मार्क्स के द्वन्दात्मक भौतिकवाद का विश्लेषण करते हुए लोहिया ने मार्क्स और हीगल की तुलना की है और कहा है कि मार्क्स की व्याख्या यूरोपीय परिवेश की उपज है और यही उसकी सीमा है ।[167]

---

159 - ओकारशरद -"लोहिया के विचार", पृष्ठ 231
160 - डा0 शोभाकर शंकर-"आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन", पृष्ठ 160
161 - यह बात सन् 1957 में जापान में समाजवादी नेता याशिकी होशिवो ने कही थी ।
162 - इन्दुमति केलकर- 'जन' का कालोहिया अंक, पृष्ठ 25
163 - लोहिया-"व्हील आफ हिस्ट्री, पृष्ठ 23
164 - लोहिया- "मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म, पृष्ठ 9,
165 - डा0 शोभाशंकर-"आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन," पृष्ठ 162
166 - लोहिया-मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म, पृष्ठ 13
167 - लोहिया-"व्हील आफ हिस्ट्री, पृष्ठ 23, लोहिया- आस्पेक्ट्स आफ सोशलिस्ट पालिसी, पृष्ठ 76

मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष सिद्धांत और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को भी लोहिया पूर्णतया स्वीकार नहीं करते। उनका कहना था कि मानव सभ्यता के इतिहास में जाति संघर्षो की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।[168] इस प्रकार लोहिया मार्क्सवाद के बारे में विचार करके भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढ़ालने के पक्षधर रहे हैं।

नरेन्द्र देव के समान ही लोहिया का समजावादी चिन्तन राष्ट्रीयता को साथ लेकर चलता है तथापि उसका आधार व्यापक है। उनके अनेक लेखों में राष्ट्रीयता और समाजवाद का समन्वय दिखाई देता है।[169] इसलिए उन्होंने तिब्बत पर चीन के आक्रमण और भारत पर चीन के आक्रमण की कड़ी निन्दा की। वास्तव में लोहिया की राष्ट्रीयता उनकी समाजवादी विचारधारा की पोषक है।[170]

वस्तुतः लोहिया ने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल एक नया समाजवादी चिन्तन विकसित करने का प्रयास किया।[171]

उनके समाजवादी चिन्तन के प्रमुख आधार हैं जो कि मौलिक हैं। लोहिया ने क्रान्तिकरण,[172] सात क्रान्तियाँ[173] चौखम्भायोजना,[174] निजी और सार्वजनिकक्षेत्र,[175] जाति प्रथा

---

168 - लोहिया-मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म, पृष्ठ 366-67 लोहिया व्हील आफ हिस्ट्री, पृष्ठ 13

169 - लोहिया ने अपने राष्ट्रीयता संबंधी विचारों का प्रतिपादन "भारत-चीन और उत्तरी सीमाएं नामक पुस्तक में किया है। उसके कई खण्ड हैं, हिमालय कश्मीर, डर्वसीअम, नेपाल, तिब्बत नीति, दस्तावेज आदि। इस पुस्तक के लेखों को ओंकार शरद ने "लोहिया के विचार "नामक पुस्तक में संकलित किया।

170 - डा0 शोभाशंकर "आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन," पृष्ठ 165

171 - लोहिया का समाजवादी चिन्तन उनके अनेक ग्रन्थो, लेखो, भाषणो आदि मे बिखरा पड़ा है, जिसका विस्तृत विवेचन यहाँ अपेक्षित नहीं है, फिर भी सन्दर्भित ग्रन्थों का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है।

172 - लोहिया-क्रान्तिकरण (लघु पुस्तिका)

173 - लोहिया-सात क्रान्तियाँ (लघु पुस्तिका), इस पुस्तक मे लोहिया ने जातियो की बराबरी, हरिजन आदिवासियो के लिए समान अवसर, रंग भेद की समाप्ति, नर-नारी समानता, हथियारो का विरोध, मूल्य की बराबरी, जीवन की आजादी के लिए क्रान्ति का आवाह्न किया है।

174 - चौखम्भा योजना, लोहया के समाजवादी चिन्तन के अन्तर्गत इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गाँधी जी के विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। लोहिया आसपेक्ट्स आफ सोशल पालिसी, पृष्ठ 17, लोहिया क्रान्ति के लिए संगठन, पृष्ठ 12

175 - लोहिया- "निजी और सार्वजनिक क्षेत्र," इस पुस्तक मे लोहिया ने निजी सम्पत्ति का विरोध और सार्वजनिक सम्पत्ति का समर्थन किया है। वे उद्योगो के राष्ट्रीयकरण के स्थान पर उसके समाजीकरण के पक्ष मे थे। लोहिया-समाजवाद की अर्थ नीति, पृष्ठ 13-15

उन्मूलन,[176] नारी समस्या,[177] सामप्रदायिकता [178] आदि अनेक सामाजिक प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं।

अपने आर्थिक चिन्तन में लोहिया [179] ने दाम बाँधों, आय-व्यय की सीमा, [180] खर्च पर नियंत्रण [181] आदि पर विचार प्रस्तुत किये है। लोहिया ने एशिया और अफ्रीका पर भी दृष्टि डाली है और रंगभेद नीति का विरोध किया है।[182] गाँधी के समान उन्होंने कुटीर उद्योगों का समर्थन किया और अन्न बाँटो आन्दोलन चलाया। भूमि वितरण की समस्या पर भी उनके विचार काफी प्रखर हैं। सारांशतः लोहिया के समाजवादी चिन्तन में राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए है।[183]

वास्तव में लोहिया भारतीय समाजवाद के इतिहास में एक बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न समाजवादी विचारक थे। उन्होंने विश्व बन्धुत्व के आदर्श को अपने समाजवादी चिन्तन का आधार बनाया[184] और विद्रोही क्रान्तिकारी, सन्यासी और, अजेयजन प्रहरी के रुप में विख्यात हुए। वे जन्मजात समाजवादी थे और जीवन पर्यन्त समाजवादी ही रहे।

vii- डा0 सम्पूर्णानन्द

सम्पूर्णानन्द की गणना कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापकों में की जाती हे।वे भातरीय संस्कृति के आदर्श से अनुप्रेरित होने के कारण मार्क्सवाद और लेनिनवाद को स्वीकार नहीं किये। उनके ऊपर गाँधीवाद का गहरा प्रभाव था, और वे गाँधीवाद और साम्यवाद में समन्वय स्थापित करने के इच्छुक थे। उनका मत था कि गाँधीवाद और साम्यवाद के समन्वय

---

176 - लोहिया 'जाति प्रथा' की इस पुस्तक में लोहिया ने यह विचार व्यक्त किया है कि भारत मे समाजवाद लाने के लिए जाति प्रथा का उन्मूलन करना आवश्यक है।

177 - लोहिया ने नारियों को भी पिछड़ी जातियों में शामिल किया और उन्हे सम्मान के लिए उन्हे क्रान्ति करने के लिए प्रेरित किया। लोहिया-क्रान्तिकरण, पृष्ठ 39

178 - लोहिया ने साम्प्रदायिकता का प्रबल विरोध किया है। लोहिया-धर्म पर एक दृष्टि लोहिया-हिन्दू और मुसलमान

179 - लोहिया-कांचन मुक्ति

180 - लोहिया-खर्च पर सीमा

181 - लोहिया विश्व समाजवाद के पोशक और समतावादी दर्शन के प्रणेता थे। उन्होंने ने विश्वसरकार का स्वप्न देखा और संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था में परिवर्तन की मांग की।

182 - लोहिया-विल टू पावर, पृष्ठ 80, डा0 वी0 पी0 वर्मा -आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 430 डा0 शोभा शंकर आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, पृष्ठ 184

183 - लोहिया (सं.)- जीवन और दर्शन, पृष्ठ 44

184 - "जन" लोहिया अंक पृष्ठ 161

का प्रयत्न विश्व के लिए एक महान सन्देश हो सकता है ।[185] सम्पूर्णानन्द गाँधीवाद के आधार पर अपने समाजवादी चिन्तन का विकास किया ।[186] उन्होंने भौतिकवाद को अस्वीकार करके मोक्ष, ब्रह्मधर्म व चेतना जैसे शब्दों का प्रयोग अपने चिन्तन में किया, लेकिन ये शब्द समाजवाद की शब्दावली में नहीं आते हैं । उनके समाजवादी विचारों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे भारतीय समाजवाद की एक ऐसी रुपरेखा बनाना चाहते थे, जिसमें प्राचीन भारतीय आदर्शों और मूल्यों का भी स्थान हो ।वे भारतीय साम्यवादियों की यह कहकर आलोचना किये कि उनका चिन्तन स्वतन्त्र रुप से विकसित नहीं हुआ है ।और वे बदले हुए सत्ता समीकरण में उन्हें अनेक बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ।[187]

वास्तव में सम्पूर्णनन्द मार्क्सवादी न होकर पूर्णतया गाँधीवादी हैं और उनका चिन्तन विशुद्ध भारतीय आदर्शों से परिपूर्ण है ।[188]

सम्पूर्णानन्द अपने समाजवादी चिन्तन में समाजवाद के स्थान पर सर्वोदय शब्द का प्रयोग करना उचित समझते थे । उनके अनुसार समाजवाद केवल मात्र शोषण का अन्त करने का एक राजनीतिक या आर्थिक चिन्तन नहीं है, वरन वह तो मानव के सम्पूर्ण जीवन की दृष्टि है। वे समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देते थे ।[189] उनके अनुसार' मनुष्य को सच्चा मानव बनाने के लिए उसमें उदारता, सहानुभूति, सहनशीलता, परोपकार तथा दया आदि गुणों का विकास करना होगा ।[190]

सम्पूर्णानन्द भारतीय साम्यवादियों की कार्य पद्धति के आलोचक थे । वे साम्राज्यवाद का विरोध करते थे और साम्यवादी साम्राज्यवाद को 'सनकीपन' की संज्ञा देते थे । गाँधी जी के समान उन्होंने अपने चिन्तन को नैतिकता पर आधारति किया, उन्होंने समाजवाद की स्थापना के लिए रक्त पूर्ण क्रान्ति के स्थान पर अहिंसात्मक उपायों के प्रयोग का समर्थन किया। लोकतन्त्र में

185 - सम्पूर्णानन्द गाँधीवाद-समाजवाद, पृष्ठ 158

186 - सम्पूर्णानन्द का समाजवादी चिन्तन उनकी पुस्तक "इण्डियन सोशलिज्म" में निहित है ।

187 - सम्पूर्णानन्द-"इण्डियन सोशलिज्म" पृष्ठ 50

188 - सम्पूर्णानन्द का चिन्तन रामायण, महाभारत मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा शुक्राचार्य के नीतिसार से प्रभावित है ।राय अखिलेन्द्र प्रसाद- "सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया" ,पृष्ठ 99, सम्पूर्णानन्द मेमायर्स एण्ड रिफ्लेक्शन्स, पृष्ठ 50

189 - डा0 शोभा शंकर "आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन," पृष्ठ 206

190 - सम्पूर्णानन्द- इण्डियन सोशलिज्म, पृष्ठ 7

उनका दृढ़ विश्वास था ।उनके अनुसार लोकतन्त्र और समाजवाद के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं है । उन्होंने लोहिया के विचार से सहमति रखते हुए कहा कि "समाजवाद न आने पर फासीवाद आयेगा या साम्यवाद[191] उनका यह भी मानना था कि "विश्व में कोई शान्ति नहीं होगी जब तक कि विचार और कर्म में सच्चे समाजवाद को स्वीकार नहीं कर लिया जाता[192] विद्वानों ने सम्पूर्णानन्द के समाजवादी चिन्तन को 'वेदान्ती समाजवाद' की संज्ञा दी है ।[193]

viii -अशोक मेहता

अशोक मेहता सन् 1932 में नासिक जेल मे जय प्रकाश व अन्य समाजवादी नेताओं के संपर्क में आये। उन्होंने जय प्रकाश जी से मार्क्सवाद का पहला पाठ सीखा ।[194] जेल से बाहर आकर मेहता एक समाजवादी बन गये । उन्होंने सामाजिक लोकतन्त्र और लोकतान्त्रिक समाजवाद को भारतीय समाजवाद का आधार बनाया ।[195] सन् 1946 तक मेहता ने अनेक मजदूर आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया ।[196] सन् 1950 में मेहता ने समाजवादी दल के आठवें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की ।इस अवसर पर उन्होंने अपने समाजवादी विचारों को व्यक्त करते हुए कहा "समाजवाद में सामाजिक, आर्थिक के साथ नैतिक दृष्टि भी होना चाहिए ।[197] भारतीय समाजवादी एकता स्थापित करने के लिए मेहता ने प्रजा समजावादी दल को संगठित किया और कई वर्षो तक इसके अध्यक्ष भी रहे । मेहता 1952 और 1957 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 1966 में राज्य सभा के सदस्य चुने गये । कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया ।[198]

---

191 - डा0 शोभा शंकर-आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन, पृष्ठ 208

192 - सम्पूर्णानन्द इण्डियन -सोशलिज्म, पृष्ठ 35

193 - राय अखिलेन्द्र प्रसाद- "सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 102 सम्पूर्णानन्द-समाजवाद (पुस्तिका), पृष्ठ 39

194 - राय अखिलेन्द्र प्रसाद; सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 135

हरिकिशोर सिंह के अनुसार मेहता के विचार पाश्चात्य लोकतान्त्रिक समाजवाद से प्रभावित है । ए हिस्ट्री आफ प्रजासोशलिस्ट पार्टी, पृष्ठ 20

196 - जी0 एस0 भार्गव-"लीडर्स आफ दि लेफ्ट" पृष्ठ 66

197 - समाजवादी दल का आठवाँ वार्षिक अधिवेशन (मद्रास,1950), पृष्ठ 29-32

198 - राय अखिलेन्द्र प्रसाद,सोशलिस्ट थाट इन माडर्न इण्डिया, पृष्ठ 138-139

1968 में चेकोस्लोवाकिया के प्रश्न पर मन्त्री पद से त्याग पत्र दे दिया ।[199] कुछ समय तक मेहता संगठन कांग्रेस के साथ रहे, बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गये ।

मेहता लोकतान्त्रिक समाजवाद के समर्थक थे। वे पूँजीवाद को एक बुराई के रुप में स्वीकार करते थे ।उनका आर्थिक चिन्तन काफी समृद्ध था ।[200] वे योजना बद्ध आर्थिक कार्यक्रम द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे । वे गाँधी जी के इस तर्क से असहमति रखते थे कि केवल देश में कुटीर उद्योग का विकास करना ही उचित होगा ।[201] वे आर्थिक क्रान्ति के प्रवर्तक थे और उसे वे जीवन की पुर्नव्यवस्था की संज्ञा देते थे ।[202] भारतीय समाजवाद के इतिहास मे मेहता एक पत्रकार, अर्थशास्त्री और लोकतान्त्रिक समाजवादी के रुप में महत्वपूर्ण स्थान रखते है ।[203]

भारतीय समाजवाद के चिन्तकों में युसूफ मेहर अली, एम0 आर0 मसानी, अच्युत पटवर्धन, कमला देवी चटोपाध्याय, श्री प्रकाश, एस0 एम0 जोशी और एन0 जी0 गोरे की गणना की जाती है ।[204]

ix- जय प्रकाशनारायण (1902-1979 ई0)

जय प्रकाश नारायण पर उन नवीन तत्वों एवं विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उनकी विचार धारा के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।प्रत्येक विचारक अपने काल की परिस्थितियों की उपज होता है । जे0 पी0 भी उसके अपवाद नहों हो सकते हैं । जे0 पी0 के विचारधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक संमानान्तर रेखा में न होकर वह विभिन्न मोड़ों से होकर गुजरी है। ये विभिन्न मोड़ विभिन्न विचारधाराओं की ओर संकेत करते हैं । जे0 पी0 का सम्पूर्ण दर्शन मूलरुप से तीन सिद्धांतों, स्वतन्त्रता, समता और बन्धुत्व पर टिका हुआ है । इन्हीं सिद्धांतो के आधार पर जे0 पी0 के सम्पूर्ण चिन्तन का निर्माण हुआ है ।वे एक ऐसी

---

199 - सन् 1963 में भारत सरकार ने चेकोस्लोवाकिया पर सोवियत संघ के आक्रमण का खण्डन नहीं किया , जिससे क्षुब्ध होकर मेहता ने मन्त्री पद से त्याग पत्र दे दिया ।

200 - अशोक मेहता के आर्थिक विचार "डेमोक्रेटिक सोशलिज्म," "स्टडी इन एशियन सोशलिज्म," "इकोनामिक प्लानिंग इन इण्डिया" आदि पुस्तकों में संग्रहित है ।

201 - एम0 वी0 सिन्हा; दि लेफ्ट विंग इन इण्डिया पृष्ठ 379

202 - एम0 एन0 सरीन; स्टडीज आफ इण्डियन लीडर्स, पृष्ठ 13

203 - एस0 एम0 जोशी : "संयुक्त समाजवादी दल के अध्यक्ष और एन0 जी0 गोरे कांग्रेस समाजवादी दल के अध्यक्ष रहे । अच्युत पटवर्धन समाजवाद का मार्ग छोड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र मे प्रविष्ट हो गये एम0 आर0 मसानी ने स्वतन्त्र दल की स्थापना की कमला देवी चटोपाध्याय समाज सेविका बन गयी ।

सामाजिक व्यवस्था की खोज में हैं जो इन तीन मूल्यों पर आधारित हों ।इसी खोज में वे कभी मार्क्सवाद की ओर मुड़े, कभी गाँधीवाद की ओर और अन्त में इसी खोज में उन्होंने मार्क्सवाद, गाँधीवाद एवं लोकतन्त्र के सिद्धांत का समन्वय कर एक ऐसी विचारधारा के निर्माण का प्रयास किया जो व्यवस्था को सबल आधार प्रदान करने की क्षमता रखती है ।

मार्क्सवाद में जे0 पी0 की पूर्ण आस्था थी । जे0 पी0 ने समाजवाद के सम्बन्ध में कहा था कि "समाजवाद का केवल एक रुप है, एक सिद्धांत है, और वह मार्क्सवाद है [205] वे स्वीकार करते थे कि विभिन्न समाजवादी विचारधाराओं के मध्य प्रक्रिया और व्यूह रचना के प्रश्न को लेकर मतभेद हैं । परन्तु जे0 पी0 मानते थे कि अभी तक केवल साम्यवादियों ने ही अपने महान और विलक्षण सफलता के द्वारा, व्यूह रचना करके अपने सिद्धांतों की सार्थकता प्रमाणित की हैं ।

निश्चय ही रुस में समजावाद का मार्क्सवादी प्रतिपादन है । समजावाद सामाजिक पुनर्निर्माण की पद्धति होता है । आदर्शवादियों का कोई भी वर्ग सत्ता पर आधिपत्य किये बिना समाजवाद की स्थापना नहीं कर सकता ।[206] समाजवाद के इसी ध्येय को लेकर उन्होंने "समाजवाद ही क्यों" (सन् 1936 ई0), "संघर्ष की ओर "(1948 ई0),"नेशन विल्डिंग इन इण्डिया" इत्यादि पुस्तकों की रचना की ।

जे0 पी0 के ऊपर गाँधी जी के व्यक्तित्व का काफी प्रभाव पड़ा । स्वतन्त्रता का आकाशदीप जे0 पी0 को उन्नीस वर्ष की अवस्था में ही तभी मिल गया जब उन्होंने सन् 1922 में गाँधी जी के आग्रह पर पटना कालेज का परित्याग कर असहयोग आन्दोलन में भाग लिया था । जे0 पी0 को अगर स्वतन्त्रता का ध्येय गाँधी जी से मिला तो समता का ध्येय मार्क्स से । उनके चिन्तन के विकास में दोनों दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान है । स्वतन्त्रता के ध्येय की पूर्ति के लिए तो जे0 पी0 कांग्रेस में गये, लेकिन वह समता के ध्येय के लिए तत्पर रहे, ताकि दोनों ध्येयों के लिए साथ-साथ कार्य किया जा सके ।इसी आधार पर सन् 1934 में अन्य समाजवादी साथियों सहित कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की, उस समय उनकी विचारधारा पूर्ण रुपेण मार्क्सवाद पर आधारित थी । सन् 1936 ई0 में कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा प्रकाशित अपनी

---

205 - डॉ0 लक्ष्मी नारायण लालः 'जय प्रकाश नारायण पृष्ठ 24

206 - डा0 लक्षिम नारायण पृष्ठ 64-65

पुस्तक "समाजवाद ही क्यों " में जे0 पी0 ने लिखा है कि "और पहले से कही अधिक स्पष्ट तौर पर यह कहना संभव है कि समाजवाद का एक ही रुप व एक ही सिद्धांत है- मार्क्सवाद[207]

जे0 पी0 और लोहिया के विचारों में काफी साम्यता है । दोनों विचारक चुनाव प्रक्रिया को जातिगत विषमता को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। जे0 पी0 भी जाति प्रथा की अनुदार प्रवृत्ति के लिए ब्राह्मण वर्ग को ही जिम्मेदार ठहराते हैं । क्योंकि ब्राह्मण वर्ग ही समाज में सबसे अधिक शिक्षित वर्ग था ।[208] वर्तमान समय में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है, समाज की प्रत्येक क्रिया किसी न किसी रुप में जातिवाद के प्रभाव से सम्पन्न होती है । भारत की चुनाव प्रक्रिया भी इससे विमुक्त नहीं है। इस समस्या की ओर जे0 पी0 ने संकेत करते हुए उन दलों की भर्त्सना की जो इनका सहारा लेते हैं ।[209] जे0 पी0 ने अपने को केवल समाजवादी रुप तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि एक सामाजिक पर्यवेक्षक के रुप में सामाजिक समस्याओं के सुधार के लिए सामाजिक बुराईयों को समाप्त करना अनिवार्य समझा ।[210] जय प्रकाश नारायण ने अछूत समस्या को एक विनाशकारी समस्या के रुप में चित्रित किया है । इन्होंने काफी समय पहले ही कहा था कि " भारत में अछूत समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसका निराकरण करना हमारा परम कर्त्तव्य है । निम्न कार्यो से छुटकारा दिलाया जाय तथा उनके व्यवसायों में भी सुधार किया जाये, तभी समाज का कल्याण हो सकता है ।[211] जे0 पी0 भी नेहरु एवं लोहिया के समान ही अस्पृश्यता को विकास के मार्ग में बाधक समझते हैं तथा अस्पृश्यता की समस्या का यदि समाधान नहीं किया जाता तो भविष्य में राष्ट्र और समाज के लिए खतरा बन सकती है । जे0 पी0 ने लिखा है कि आज हिन्दुस्तान में प्राथमिक सुधार की आवश्यकता है । यह हिन्दू समाज एवं राष्ट्र के स्वतन्त्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा है ।[212] जे0 पी0 की विचारधारा में नये परिवर्तन समय के अनुसार हुए । उन नवीन विचारधाराओं के ग्रहण करने से साध्य में कोई परिवर्तन नही हुआ लेकिन साधनों में परिवर्तन आना स्वाभाविक था ।

---

207 _ जय प्रकाश नारायण :"समाजवादी ही क्यों" पृष्ठ 64

208 _ जय प्रकाश नारायण ; नेशन बिल्डिंग इन इण्डिया," पृष्ठ 17

209 _ मीनू मसानी : "जे0 पी0 मिशन पार्टी एकम्पिलश्ड पृष्ठ 56

210 _ वही, पृष्ठ 56

211 _ जय प्रकाश नारायणः"मेरी विचार यात्रा" भाग-2 पृष्ठ 85, (सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी)

212 _ जय प्रकाश नारायणः"नेशन बिल्डिंग इन इण्डिया" पृष्ठ 190

जे0 पी0 ने हृदय परिवर्तन पर आधारित सर्वोदय आन्दोलन की विफलता को स्वीकार किया तथा पुनः वह मार्क्सवादी साधनों में आस्था रखते हुए क्रान्ति को समस्त समस्याओं के समाधान का मूल मानने लगे। जे0 पी0 ने सर्वोदयी विचारधारा को ग्रहण करने के पूर्व लिखा था कि हमें सामाजिक क्रान्ति करनी हैं, गरीबी, सामन्तशाही, पूँजीवाद और जातिभेद को मिटाये बिना हम उन्नति नहीं कर सकते। यदि हिन्दुस्तान में समाजवाद कायम करना है तो ऊँच-नीच, जाति-पाँति का भेद मिटाना होगा।[213]

राष्ट्र की उन्नति किसी एक वर्ग विशेष का कार्य नहीं है।उसमें सभी वर्ग विशेष का सहयोग होना अति आवश्यक है।सभी वर्गो का सहयोग तभी ही हो सकता है जब समाज में समता हो।यदि राष्ट्र की उन्नति करनी है तो सामाजिक क्रान्ति और आर्थिक क्रान्ति के द्वारा न्याय होना आवश्यक है।क्योंकि आर्थिक क्रान्ति की सफलता सामाजिक क्रान्ति पर निर्भर होती है। सामाजिक ऊँच-नीच के भेद-भाव को समाप्त किये बिना सामाजिक न्याय नहीं रह सकता।[214] जे0 पी0 चुनाव प्रक्रिया को एवं मताधिकार को अस्पृश्यता की समस्या के समाधान के लिए साधन के रुप में देखतें हैं। उनका मत है कि "चुनाव इन वर्तमान वस्तु योजनाओं के चुनौती के रुप में आया है"।[215]

जे0 पी0 ने वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता को स्वीकार्य करते हुए युवा वर्ग का आवाह्न किया कि वह हरिजनों एवं भूमिहीनों को वर्ग के आधार पर संगठित करने का बीड़ा उठायें। इस विचार से यह ध्वनि निकलती है कि उनकी विचारधारा एक नये दौर से गुजरी है। गरीबी एक सामाजिक अभिशाप है, उसको समाज से जब तक समाप्त नहीं किया जाता तब तक सामाजिक सुधार और क्रान्ति सफल नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति या सामाजिक जीवन के किसी भी पहलू को सामाजिक क्रान्ति की लहर से पृथक नहीं रखा जा सकता। इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने शिक्षा प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन करने का सुझाव दिया। हिन्दू समाज वर्ग और जाति

---

213 - रामवृक्ष बेनी पुरी : "जय प्रकाश की विचारधारा" पृष्ठ 423

214 - जय प्रकाश नारायण : "नेशन विल्डिंग इन इण्डिया" पृष्ठ 423

215 - रामवृक्ष बेनी पुरीः "जय प्रकाश की विचारधारा पृष्ठ 295

भिन्नता से परिपूर्ण है। वास्तविक शिक्षा वही होगी जो इन असमनताओं को मिटा दे और मानव समाज में सहयोग की भावना का विकास करें।[216]

जय प्रकाश नारायण ने वर्गों के प्रादुर्भाव में सामाजिक विषमता को आर्थिक तत्व से सम्बद्ध किया है। आर्थिक तत्व वर्ग अभ्युदय के लिए केवल पूर्ण रुपेण केवल उत्तरदायी नहीं हो सकता। समाज की दूसरी असमनताएं भी उद्भव के लिए उतनी ही उत्तरदायी है जितनी आर्थिक विषमता वर्ग अभ्युदय के सम्बन्ध में डॉ0 लोहिया एवं जे0 पी0 में काफी साम्यता है। जे0 पी0 के अनुसार "हमारी सामाजिक मूल विषमताओं का कारण यह है कि हम सामाजिक रुप से कभी अलग नहीं हुए हैं, हमारे मानस में अब भी सामन्तवाद की मान्यताएं मौजूद हैं।ये सामजिक जीवन को बहुत कुछ प्रभावित करती है। हमारे यहाँ अभी भीं वर्ग व्यवस्था मौजूद है जो पहले कर्म के आधार पर थी और अब जन्म के आधार पर ग्रहण कर ली गयी है। इस जन्म के आधार के कारण समाज में वर्गों का निर्माण एवं बिखराव उत्पन्न हो गया है। समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो गया है। जो व्यक्ति निम्न वर्ग के हैं वही आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। आर्थिक वर्गो और सामाजिक वर्गो में ऐसा सम्बन्ध स्थापित हो गया है जो कि एक दीर्घ प्रक्रिया का परिणाम है।जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे वही सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए बन गये। इन वर्गो में विषमता बढ़ती गयी।[217]

जे0 पी0 ने वर्ग उन्मूलन के सम्बन्ध में संघर्षपूर्ण और शान्ति पूर्ण दोनों साधनों को ग्रहण किया, जो उनकी परिवर्तित विचारधारा की सूचक है। जे0 पी0 जब मार्क्सवादी थे तब मार्क्सवाद के ही आधार पर भारत में भारत की संस्कृति एवं समाज के अनुकूल समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन 80 के दशक में जैसे नयी परिस्थितियाँ और समस्याएं देश के समक्ष आती गयी उनके अनुसार वे अपने विचार और कार्यक्रम में परिवर्तन करते गये।वे अहिंसा को एक मात्र कामचालऊ अस्त्र मानते थे, हिंसा ही अन्तिम रुप से अस्त्र होगा[218]

80 के दशक से जे0 पी0 की विचारधारा पर पुनः मार्क्सवादी विचार दृष्टिगोचर होने लगा था। उन्होंने असमानता दूर करने के लिए वर्ग-संघर्ष को पुनः मान्यता प्रदान की और हृदय

---

216 _ जे0 पी0 :"समाजवाद क्यों और कैसे," पृष्ठ 325

217 _ जे0 पी0: "संघर्ष की ओर," पृष्ठ 20.

218 _ 8 अगस्त 1977, "सामाजिक क्रान्ति" धर्मयुग के अंक से

परिवर्तन पर आधारित सर्वोदय आन्दोलन की विफलता को स्वीकार करते हुए वर्ग संघर्ष को अनिवार्य बतलाया और युवा वर्ग का आवाह्न किया कि वह हरिजनों एवं भूमिहिनों को वर्ग के आधार पर संगठित करने का बीड़ा उठा ले ।[219] इस तर्क से यही अर्थ निकलता है कि वर्ग संघर्ष एवं वर्ग संगठन की उस पूर्ण भूमिका पर जिसे वह काफी समय पूर्व त्याग चुके थे, उस पर पुनः वापस लौट आयें ।

हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था के कारण उत्पन्न वर्गो ओर अर्थिक समानता के कारण यह संभव है कि भारत में वर्ग उन्मूलन के प्रयास किये जायें यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और शान्ति पूर्ण ढंग से समाज परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया तो अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है और वर्ग-संघर्ष हो सकता है । जे0 पी0 वर्ग उन्मूलन और समाज में समानता लाने के लिए प्रारम्भ से ही प्रयत्नशील रहे है । जे0 पी0 के शब्दों में-मैं और मेरे साथियों के मस्तिष्क में एक स्वच्छ विचार है कि सामाजिक,आर्थिक,राजनीतिक और सांस्कृतिक आन्दोलनों को चलाने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाय ।[220]

जे0 पी0 की औद्योगीकरण की नीति मध्यममार्गी है । औद्योगीकरण के संबंध में उनके विचार नेहरु के नजदीक है । उनके अनुसार "समाजवादी भारत में बड़े और छोटे पैमाने पर चलने वाले दो प्रकार के उद्योग धन्धे होंगे । सभी बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्योग धन्धों का स्वामित्व संघ सरकार अथवा प्रान्तीय सरकारों का होगा ।[221]

जे0 पी0 भारी उद्योग के साथ लघु उद्योगों को नेहरु के समान आवश्यक मानते थे । यह उद्योग सहायक उद्योग होंगे । लघु उद्योगों के संबंध में इनका कहना था कि " छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योग-धन्धों का स्वामित्व समितियों के हाथ में होगा । इन समितियों के संचालन संबंधी नियम बनाने के अतिरिक्त राज्य उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा । राज्य द्वारा संचालित तथा उत्पादक समितियों द्वारा संचालित उद्योग-धन्धों के अतिरिक्त शहर की नगर पालिकाओं

219 - जे0 पी0 का भाषण- 'पॉँच जन्य', 4 सितम्बर 1977
220 - अवध बिहारी लाल- "सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्रधार-लोकनायक जय प्रकाश" पृष्ठ 115
221 - जे0 पी0 का भाषण- 14 सित0 1977 पटना

द्वारा संचालित उद्योग धन्धे भी होंगे । नगर महापालिका बड़े उद्योग-धन्धों को तो नहीं लेकिन मध्यम और लघु उद्योगों का संचालन तो कर ही सकती है ।[222]

जे0 पी0 के लघु उद्योगों के संबंध में विचार नेहरू के विंचारों से भिन्न है । जहाँ पर नेहरू जी लघु उद्योगों का स्वामित्व निजी हाथों में प्रदान करने के पक्षधर थें वहाँ पर जे0 पी0 वैक्तिक स्वामित्व के स्थान पर सहकारी तत्व को अधिक महत्व देते थे । जे0 पी0 राज्य एकाधिकार को भी अनुचित मानते थें, लेकिन उद्योगों की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए उनका प्रबन्ध राज्य के अधीन ही करना उचित समझतें हैं । जे0 पी0 ने जिस सहकारी तत्व को अनिवार्य बताया है उससे उनका अभिप्राय वैक्तिक एकाधिकार पर पाबन्दी लगाना था, जिससे विकेन्द्रण के आधार पर उत्पादन का लाभ सम्पूर्ण समाज को हो सके । लघु उद्योगों की ओर संकेत करते हुए तथा उनके आधुनिकीरण की ओर जे0 पी0 का विचार है कि "छोटे और सहायक उद्योग वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे । किसान एवं मध्यम वर्ग का आर्थिक जीवन वास्तव में सुखी हो जायेगा तथा एक प्रगति का मार्ग निश्चित होगा, ग्रामीण और छोटे-छोटे कुटीर उद्योग धन्धों को पुनजीवित करने की भी आवश्यकता होगी। इस विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन का बहुत जरूरी है । लेकिन स्थूल सिद्धांत तो निश्चित किये ही जा सकते है ।[223]" जे0 पी0 ने इन उद्योगों के सम्बन्ध में संकेत किया कि जहाँ तक सम्भव हो सभी उद्योग धन्धे औद्योगिक सहयोग के अन्तर्गत चलाये जायें । उद्योगों से उत्पादन और तकनीकि में उन्नति करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । गाँव वालों को विशेषतया उत्साहित करने के लिए उन्हीं उद्योगों को चलाना चाहिए जिनकी तकनीकि विस्तृत उतपादन की मशीनी तकनीकि से दूर न हो । ग्राम में सहयोग मूलक धन्धों को कायम करना सम्भव है ।[224]

जे0 पी0 भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उद्योगों की स्थापना करना चाहते थे नेहरू जी रूस की भौतिकवादी सम्पन्नता एवं आर्थिक विकास से बहुत प्रभावित थे । वे आधुनिक तकनीकि के आधार पर भारत का तीव्र गति से औद्योगीकरण करना चाहते थे । इसके लिए वे देशी एवं विदेशी, दोनों साधनों को अनिवार्य समझते थे ।लेकिन जे0 पी0 भारतीय परिस्थितियों

---

222 - मीनू मसानी- "जे0 पी0 मिशन पार्टी एकम्पिलश्ड" पृष्ठ 49

223 - जय प्रकाश नारायण-"समाजवाद क्यों और कैसे," पृष्ठ 27

224 - जय प्रकाश नारायण-"सामजवाद क्यों और कैसे,", पृष्ठ 132

के अनुरूप एवं आवश्यकता के अनुसार उद्योगों को प्राथमिकता देते हैं। जे0 पी0 भारी उद्योगों को सीमित एवं लघु उद्योगों को अधिक प्राथमिकता देना चाहते थे, क्योंकि परिस्थितियां इसी के अनुकूल थी। वे नेहरू जी के समान छोटे पैमाने की उत्पादन इकाइयों में आधुनिक तकनीकि एवं विज्ञान का प्रयोग करना चाहते थे। जे0 पी0 ने अपनी पुस्तक "समाजवाद से सर्वोदय की ओर" में प्रो0 हक्सले का कथन व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा व्यक्तिगत विचार और समस्त विकेन्द्रीकरण के समर्थकों का विचार है कि जब तक शुद्ध विज्ञान के निष्कर्षो का प्रयोग बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण करने वाली उद्योग व्यवस्था को मंहगे मूल्य पर अधिक विस्तृत और अधिकाधिक विशिष्ट बनाने में होता रहेगा तब तक सत्ता का थोड़े से हाथों में विकेन्द्रीकरण के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के इस विकेन्द्रीकरण के परिणाम स्वरूप जनता निरन्तर अपनी नागरिक स्वतन्त्रता, अपनी व्यक्तिगत स्वायत्ता और स्वशासन के अवसरों सें वंचित रहेगी।[225]

जे0 पी0 राष्ट्रीयकरण को सम्पत्ति के समान वितरण के लिए अति आवश्यक मानते थे। जे0 पी0 के अनुसार" मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि सम्पत्तिक असमानताओं का मूल कारण इस वास्तविकता में है कि प्रकृति की देन, जो मानव जाति के लिए जो सम्पत्ति की दाता है, साथ ही उत्पादन के कल-पूर्जो को अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों ने वैक्तिक अधिकार में कर रखा है, आर्थिक शोषण का यही कारण है। यानि मजदूर जितना उत्पादन करते हैं, उसमें से उतने ही छोड़कर जितना एक निर्धारित जीवन माप के अनुसार गुजर के लिए आवश्यक समझा जाता है, सबका सब उसमें दबा लिया जाता है।[226] जे0 पी0 के अनुसार इस समस्या का समाजवादी हल यह है कि उत्पादन के साधनों पर से वैक्तिक स्वामित्व का उन्मूलन कर दिया जाये और इन साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व स्थापित किया जायें।[227] उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत आधिपत्य के ह्रास और सामाजिक आधिपत्य की स्थापना होने से आर्थिक शोषण का लोप हो जायेगा।दूसरे शब्दों में कहा जायें तो वर्तमान समाज के मूलभूत विकार का नाश हो जायेगा।

---

225 - जय प्रकाश नारायण-"समाजवाद क्यों और कैसे," पृष्ठ 132

226 - जय प्रकाश नारायण-"समाजवाद क्यों और कैसे," पृष्ठ, 133

227 - जय प्रकाश नारायण समाजवाद से सर्वोदय की ओर" पृष्ठ 55-56

समाजवाद के मौलिक सिद्धांत की ओर इंगति करते हुए जे0 पी0 ने कहा कि समाजवाद का मौलिक सिद्धान्त यही है कि "उत्पादन के साधानों का सामाजीकरण हो । समाजवादी निर्माण के किसी भी प्रयत्न के समय उत्पादन के साधनों पर से व्यक्तिगत आधिपत्य का अन्त करना ही होगा । आर्थिक शोषण जब समाप्त होगा तो आर्थिक असमानता ही नहीं रह जायेगी।[228]

जे0 पी0 मूल रूप से उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करना चाहते थे । उनका मत है कि समाज में व्याप्त असमान्ता को कैसे दूर किया जाये ? इसके संबन्ध में उन्होंने कुछ सुझाव रखे । उनके मतानुसार समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने के दो ही उपाय हैं कि उत्पादन के साधनों पर सबका अधिकार हो और उसमें सबकों उपभोग की गारण्टी हो और जो कुछ पैदा होगा उसका बँटवारा पहले काम के रुप में और बाद में परिणाम के रुप में होगा । किन्तु पुनः धीरे-धीरे सबसे योग्यता के अनुसार काम लेने और अवश्यकतानुसार देने की व्यवस्थ की जायेगी । पैदावार का बँटवारा करते समय कुछ अंश राज्य और रक्षा के लिए तथा आर्थिक विकास के लिए रख दिया जायेगा । उन्होंने कहा कि "समाजवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है ? उत्पादन के सभी साधनों पर समाजभर का अधिकार हो ।समाजवाद की मूलभित्ती यही है ।[229] समाजवादी ढंग पर समाज का पुनर्निर्माण तब तक सम्भव नहीं है, जब तक उत्पादन के साधनों पर से व्यक्तिगत अधिकार समाप्त नहीं कर दिया जयेगा ।"[230] यदि कोई राज्य समाजवाद का संगठन करना चाहता है तो सम्भव है कि वह तुरन्त स्थापित करने में समर्थ न हो सकेगा । लेकिन यदि उसे सफल होना है तो उत्पादन के उन सभी बड़े साधनों पर सामाजिक अधिकार कायम करना होगा । जो देश के आर्थिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रखते है । विकसित समाज में उत्पादन के साधनों के साथ ही विनिमय और वितरण के साधन भी उन्नतिशील होते रहते हैं ।उन पर भी सामाजिक अधिकार होना चाहिए । उद्योगों का राष्ट्रीयकरण मात्र ही समाजवाद नहीं है । जे0 पी0 के अनुसार " समाजवाद केवल पूँजीवाद नहीं है, न राज्यवाद है । उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और कृषि

---

228 - जय प्रकाश नारायण-"संघर्ष की ओर,"पृष्ठ 75-76

229 - जय प्रकाश नारायण-" संघर्ष की और," पृष्ठ 78

230 - जय प्रकाश नारायण-"समाजवाद क्यों और कैसे" पृष्ठ 1-8

का सामूहिकरण समाजवादी अर्थ रचना के महत्वपूर्ण पहलू हैं, परन्तु वे अपने आप में समाजवाद नहीं है ।[231]

भारतीय कृषि व्यवस्था के संबंध में जे0 पी0 कृषि के स्वामित्व पर सामाजिक अधिकार को अधिक उचित मानते थे ।इस संबंध में उनका कहना था कि "यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाये तो इस संबंध में हम पायेंगे कि समाजवादी आधार पर हिन्दुस्तानी जिन्दगी को ढ़ालने के किसी प्रयत्न की सफलता के लिए खेती में समाजवाद अर्थात सहकारी और सामूहिक किसानी की नितान्त आवश्यकता है ।"[232] प्रायः सहकारी कृषि कें सबंध में आक्षेप किया जाता है तथा समाजवादी राज्य में जो कृषि व्यवस्था अपनायी जाती है उस पर व्यक्तिगत स्वामित्व के समर्थक उसकी आलोचना करते हैं कि इसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन किया जाता है । जे0 पी0 का इस संबंध में विचार था कि "मुख्य प्रश्न समाजवाद की स्थापना की संभवना के संबध में नहीं है, किन्तु यह है कि समाजवाद के द्वारा हिन्दुस्तानी काश्तकारी हिन्दुस्तानी किसान और हिन्दुस्तानी राष्ट्र का कितना हित होगा और इस प्रश्न का हमारे पास प्रबल उत्तर है। हमारे हृदय में तनिक भी संदेह नहीं है कि केवल समाजवाद ही भारतीय किसानों की बरबादी और दिवालियापन से बचा सकता है । अकेला यही राष्ट्र को शक्ति संपन बना सकता है ।[233]

जे0 पी0 ने जहाँ कृषि समस्याओं की ओर संकेत किया वहाँ उन्होंने सुझाव भी रखे उनका विचार है कि-"इसका तो एक मात्र हल यही है कि भूमि के जोतों के शोषण में किसी भी प्रकार से सहायक होने वाले निश्चित स्वार्थो का सफाया कर दिया जाये ।अराजियों का राष्ट्रीयकरण करके सहयोगी और सामूहिक किसानी की स्थापना की जाये । कर्ज देने और मण्डियों की व्यवस्था सरकार और सहयोग समितियों के हाथों में रहे तथा सहयोग समितियों द्वारा सहायता प्राप्त उद्योग धन्धों की स्थापना की जाये ।[234]

जे0 पी0 असमानता का एक मुख्य कारण भूमि का असमान वितरण मानते थे । उनका विचार था कि भूमि के पुनर्वितरण के बिना अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते ।

---

231 - वही," पृष्ठ 17

232 - वही," पृष्ठ 18-19

233 - डा0 लख्मी नारायण लाल-"जय प्रकाश नारायण" पृष्ठ 18

234 - जय प्रकाश नारायण -"संघर्ष की ओर,"पृष्ठ 98

उन्ही के शब्दों में "सार्वजनिक स्वामित्व हमारा लक्ष्य है अतएव यह बात की हम किसानों को फिर से जमीन बाँटने की सोचे, एक अजीब सी मालूम होती है। इसलिए सार्वजनिक स्वामित्व और जमीन की काश्त की तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए हमें जमीन पर किसानों के स्वामित्व की बात को पहले लेना पड़ेगा।[235] उन्होंने आगे कहा कि "इस समय किसानों को मिली हुई आराजी में घोर विषमता है।जहाँ तक कुछ अराजियाँ सैकड़ों एकड़ की हैं वहाँ दूसरी एक एकड़ भी नहीं हैं। इसलिए एक बड़े फर्क को मिटाने के लिए हम जमीन का फिर से बँटवारा करने की तजबीज पेश करते है।[236]

जे0 पी0 नेहरु के समान ही जमींदारी प्रथा को कृषि के विकास मे बाधक समझते थे। इनका विचार था कि जमीदारी प्रथा की मौजूदगी में हम कृषि व्यवस्था का विकास नहीं कर सकते। हमारी कृषि व्यवस्था वास्तव में असमानता के आधार पर आधारित है। समाजवाद कृषि की स्थापना के सिलसिले में सहयोग तथा सामूहिक कृषि की दो प्रणालियाँ हैं। जमींदारी प्रथा की समाप्ति के बाद ज्यादा बड़ी जोतों को तोड़ने और बिल्कुल छोटी जोतों को इतनी बड़ी बनाने के उद्देश्य से कि उन पर खेती करना आर्थिक दृष्टि से अलाभकर हो, भूमि का फिर से बँटवारा करना जरुरी होगा। गाँव की जमीन पर मालिक कानून की दृष्टि से अलग-अलग न होकर समूचा गाँव ही होगा। और अलग व्यक्तियों के साथ खेत का बन्दोबस्त करना राज्य के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ग्राम पंचायतों का कार्य होगा। इस प्रकार बन्दोबस्त की गयी जमीन पर किसानों का एक प्रकार मालिकाना हक होगा। उन जमीनों को छोड़कर जिनसे बडी या छोटी होने के कारण घोर विषमता को दूर करने की दृष्टि से बँटवारा करना जरुरी हो जायेगा।[237]

सन् 1952 ई के आम चुनाव के उपरान्त जे0 पी0 की विचारधारा में एक नया मोड़ आया। सन् 1951 ई0 से विनोबा के नेतत्व में चलते हुए भूदान ग्रामदान आन्दोलन ने जे0 पी0 के नये चिन्तन को एक ठोस आधार प्रदान किया। इसके प्रति उनका आकर्षण बढ़ गया कि उन्होंने सन् 1954 ई0 में बोध गया के सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर भूदान ग्राम-दान आन्दोलन के लिए अपना जीवन दान करने की घोषणा कर दी तथा प्रजा समाजवादी दल से त्याग पत्र दे दिया। उन्हे

235 - वही, पृष्ठ 94
236 - वही, पृष्ठ 95
237 - जय प्रकाश नारायण" संघर्ष की और", पृष्ठ 13

अपने लक्ष्य की प्राप्ति इसी विचारधारा में दिखाई देने लगी । उन्होंने कहा कि किसी एक पक्ष द्वारा भू-वितरण का आन्दोलन चलाने की अपेक्षा, विनोबा जी का पक्षातीत आन्दोलन चलाने का रास्ता मुझे ज्यादा सही लगा । धीरे-धीरे मुझे यहाँ तक प्रतीत होने लगा कि विनोबा जी ने केवल हमारे सामने भू-समस्या का हल रखा, बल्कि भूदान आन्दोलन अहिंसक तरीके से सामाजिक क्रान्ति तथा समाज के नव निर्माण का पहला कदम है ।[238]

जे0 पी0, नेहरु जी के समान ही भूमि के पुनर्वितरण में तथा जमीदारी प्रथा के उन्मूलन में विश्वास रखते है । उन्होंने न केवल सैद्धान्तिक क्षेत्र में ही बल्कि व्यवहार में भी भूमि पुनर्वितरण के लिए कार्य किया । उन्होंने भूदान आन्दोलन के अन्तर्गत जमीदार वर्ग से जमीन लेकर भूमिहीन किसानों में वितरण किया ।

जे0 पी0 का आगमन भारतीय राजनीति में एक मार्क्सवादी के रुप में हुआ । परन्तु उद्देश्य की अपूर्णता और मार्क्सवादी असफलता ने जे0 पी0 को सर्वोदय की ओर आकर्षित किया । सन् 1954 ई0 में उन्होंने मार्क्सवाद से संबंध विच्छेद कर लिया और भूदान आन्दोलन में अपनी आस्था व्यक्त की और उसे शान्ति पूर्ण क्रान्ति का नाम दिया, परन्तु उसमें भी जे0 पी0 को अपना उद्देश्य पूर्ण होने में शंका हुई । जे0 पी0 ने सन् 1974 ई0 में सम्पूर्ण क्रान्ति की घोषणा की ।

सत्तर के दशक में जे0 पी0 की विचारधारा में एक नया मोड़ आने लगा था । वे प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए क्रान्ति की अनिवार्यता को महसूस करने लगे थे ।5 जून 1974 को पटना के गाँधी मैदान की विशाल सभा में उन्होंने पहली बार सम्पूर्ण क्रान्ति शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि " यह आन्दोलन छात्र संघर्ष समिति की मात्र 10-12 मांगों की पूर्ति के लिए ही नहीं, यह सम्पूर्ण क्रान्ति की शुरुआत है । इसके उद्देश्य बहुत दूरगामी हैं, भारतीय लोकतन्त्र को वास्तविक तथा सुदृढ़ बनाना, जनता का सच्चा राज कायम करना, समाज से अन्याय शोषण आदि का अन्त करना, एक नैतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्रान्ति करना, नया भारत बनाना ।"[239] जे0 पी0 ने नेहरु एवं लोहिया के समान ही समस्या के विरुद्ध आन्दोलन को मान्यता प्रदान की तथा नेहरु के समान एक ऐसे संगठन का विचार रखा जिसमें व्यक्ति

---

238 - वही, पृष्ठ 13

239 - जय प्रकाश नारायण-"समाजवाद क्यों और कैसे," पृष्ठ 24

स्वेच्छापूर्वक अपना योगदान दे। व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक संगठन बनाये जिसमें शिक्षण संस्थाएँ तथा राजनैतिक दल एवं प्रत्येक नागरकि इसमें संयुक्त रुप से हिस्सा लें। प्रत्येक नवयुवक का यह राष्ट्रीय कर्त्तव्य है कि वह इस सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शान्तिपूर्ण साधनों और यदि आवश्यक हो तो हिंसात्मक साधनों से भी पूर्ण करें।[240]

सम्पूर्ण क्रान्ति से जे0 पी0 का अभिप्राय था कि समाज में आमूल परिवर्तन हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक परिवर्तन।"[241] इस प्रकार की क्रान्तियाँ यहाँ मिलकर सम्पूर्ण क्रान्ति होगी। सात की इस संख्या को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। उदाहरणार्थ-सांस्कृतिक क्रान्ति में शैक्षिणिक क्रान्ति सन्निहित हो सकती है और यदि कल्चर का एन्थ्रोपोलिजिकल अर्थ लिया जाये तो उसमें लगभग सब कुछ आ जाता है किन्तु जो प्राथमिक समाज के सन्दर्भ में लिया जाता है उसी प्रकार यदि सामाजिक क्रान्ति को भी मार्क्सवाद की भूमिका में 'सामाजिक क्रान्ति' जैसा अर्थ लिया जाये तो आर्थिक राजनैतिक क्रान्तियाँ उसमें अवश्य आ जाती है, अन्य बहुत कुछ भी इसमें समा सकता है। यदि इसकी संख्या को बढ़ाना है तो उदाहरण स्वरुप आर्थिक क्रान्ति में से ही औद्योगिक क्रान्ति, कृषि से संबंधित क्रान्ति व यान्त्रिक क्रान्ति इत्यादि भेद किये जा सकते हैं।

आर्थिक क्रान्ति समाज की आर्थिक रचना तथा आर्थिक संस्थाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन और उनका नया क्रान्ति-कृत रुप अर्थात क्रान्ति शब्द से परिवर्तन और नव निर्माण दोनों ही अभिप्रेरित है। आर्थिक क्रान्ति में स्वामित्व और प्रबन्ध में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन आ ही जाता है। स्वामित्व और प्रबन्ध के नाते हर हालत में राज्य प्रबन्ध ही हो यह आवश्यक नही है, स्वामित्व राज्य का भी हो सकता है। व्यक्ति या व्यक्तियों की कम्पनी या रजिस्टर्ड सोसाइटी इनके मिश्रित रुपों का भी जैसे सहयोग समिति, स्थानीय समिति, ग्राम सभा, ग्राम समूह, समूह सभा, प्रखण्ड सभा, जिला परिषद आदि का भी हो सकता है, और इनके कई मिश्रित रुप भी हो सकते है। यानी स्थानीय स्वामित्व तथा पूर्व वर्णित स्वामित्वों का समिश्रण, उपभोक्ता का स्वामित्व, उत्पादकों का स्वामित्व आदि। सामाजिक परिवर्तन ऐसा हो

240 - जय प्रकाश नारायण-"जीवन दान" पृष्ठ 9

241 - जय प्रकाश नारायण-" सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में मेरी विचार यात्रा" (स0), सव्र सेवा संघ प्रकाशन वाराणसी, पृष्ठ 86

कि सामाजिक कुरीतियाँ दूर हों। इसमें से नया समाज निकले जिसमें सभी सुखी हो, धनी-गरीब का भेद न हो, शोषण न हो।

राजनैतिक क्रान्ति का अभिप्राय है, भारतीय लोकतन्त्र को लोकभिमुखी तथा सुदृढ़तर बनाना, जनता का राज्य कायम करना, सर्वोपरि सत्ता जनता के हाथ में होना सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब है, सामज में त्याग-बलिदान, प्रेम, अहिंसा भाइचारा आदि सद्गुणों का विकास। जे0 पी0 के अनुसार "सम्पूर्ण क्रान्ति में व्यवस्था भी बदलेगी और व्यक्ति भी इनमें कोई आगे पीछे नहीं, साथ-साथ होगा। व्यक्ति समूह के लिए जिये और समूह व्यक्ति के लिए। यह मानवीय क्रान्ति होगी,ऐसी क्रान्ति जिसमें भारत का आध्यात्म व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में उतर जायेगा। तब व्यक्ति अपने हितों का दर्शन समूह के हितों में करने लगेगा।इस क्रान्ति के बिना न समाजवाद आयेगा न साम्यवाद।"[242] सम्पूर्ण क्रान्ति के सारे परिवर्तन मौटे तौर पर महात्माँ गाँधी की विचारधारा के अनुरुप होंगे, सर्वोदय इस क्रान्ति का दूसरा नाम है।

जे0 पी0 इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सामूहिक हितों की रक्षा सामूहिक चेतना ही कर सकती है। इसी सामूहिक चेतना को वह सम्पूर्ण क्रान्ति द्वारा जगाना चाहते थे। जे0 पी0 के शब्दों में "हमें सामान्य जनता का राज्य चाहिए इसलिए हिंसा का मार्ग तो हमारे लिए सर्वथा त्याज्य है।जहाँ कानून निष्फल हो जाता है वहाँ अहिंसा से ही आगे बढ़ना होता है।कोई कहे कि अहिंसक क्रान्ति से रक्तपूर्ण क्रान्ति जल्दी होंती है तो भ्रम है, दुनियाँ की क्रान्तियाँ देखने से ऐसा लगता है, पुराने समाज को तोड़ने में हिंसा क्रान्ति लम्बे अरसे के बाद सफल होती है। और उसके बाद नये सामाजिक निर्माण में और अधिक समय लगता है।"[243] लेकिन अहिंसक क्रान्ति में पुराने समाज को बदलने और नये समाज के गठन का काम साथ-साथ होता है। अहिंसक प्रक्रिया में यह सबसे बड़ा गुण है कि परिवर्तन और नवर्मिाण दोनों साथ-साथ चलते है।

जे0 पी0 गाँधी जी के ही मार्ग पर चलकर इस देश में राजनीतिक, सामाजिक क्रान्ति एवं आर्थिक-सांस्कृतिक परिवर्तन लाना चाहते थे। इसी को उन्होंने "सम्पूर्ण क्रान्ति" का नाम दिया। सम्पूर्ण क्रान्ति का विचार जे0 पी0 का अपना मौलिक विचार नहीं है। डा0 लोहिया ने सप्त क्रान्ति

---

242 - जय प्रकाश नारायण-" सम्पूर्ण क्रान्ति खोज में मेरी विचार यात्रा"(सं.) सेवा संघ, प्रकाशक वाराणसी,पृष्ठ 86

243 - अवध बिहारी लाल-"सम्पूर्ण क्रान्ति के सूत्राधार-जय प्रकाश" पृष्ठ 8

की कल्पना की थी जिसमें वे सभी तत्व मौजूद हैं जिसकी कल्पना जे0 पी0 करते है । जे0 पी0 ने सम्पूर्ण क्रान्ति के कारणों की ओर संकेत किया क्योंकि सम्पूर्ण क्रान्ति होनी चाहिए । आजादी मिलने के बाद से भारतीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढ़ांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आजादी मिलने से लेकर आजतक राजनीतिक, सार्वजनिक और व्यावसायिक नैतिकता का ह्रास भी होता रहा है ।

कुछ अंशों में जय प्रकाश नारायण अपने ध्येय में सफल भी हुए । सन् 1977 ई0 का सत्ता परिवर्तन उन्हीं के परिणामों का प्रयास रहा है । नेहरु एवं जे0 पी0 की क्रान्ति संबंधी अवधारणा में काफी साम्यता है । दोनों ही विचारक अहिंसक क्रान्ति के पक्षपाती है । जबकि भिन्नता यह है कि नेहरु का सोचने विचारने का तरीका पाश्चात्य विचारकों से ओत-प्रोत था जबकि जे0 पी0 विदेशी विचारों को ग्रहण करने के बाद उसका भारतीयकरण कर देते थे । वे अधिकतर गाँधी जी के सविनय अवज्ञा सिद्धांत को मानते थे जो कि अहिंसक क्रान्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है । वे मार्क्सवादी विचारों में आस्था रखते हुए भी मार्क्सवादी साहित्य की सबसे बड़ी देन हिन्सात्मक क्रान्ति से हमेशा दूर रहे ।[244]

244 - जय प्रकाश नारायण-"सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में मेरी विचार यात्रा," पृष्ठ 112

अध्याय — ३

भारत में दलीय समाजवाद

भारत के समाजवादी दल

1. कांग्रेस समाजवादी दल

(i) स्थापना व लक्ष्य-सन् 1848 के साम्यवादी घोषणा पत्र को सामाजिक और आर्थिक समानता संबंधी घोषणा[1] का भारत के समाजवादी नेताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरुप सन् 1922 से 1939 की अवधि में भारत में समाजवादी आन्दोलन की गति काफी तीव्र रही[2] और देश में अनेक समाजवादी तथा साम्यवादी दलों की स्थापना हुई।[3]

मई 1934 में कांग्रेस समावादी दल की स्थापना भारत में समाजवाद के संगठनात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी ।[4]कांग्रेस के प्रगतिशील नेताओं में अधिकारिक नेतृत्व के दक्षिणपंथी नीतियों एवं कार्यवाहियों के विरुद्ध असंतोष की ज्वाला सुलग रही थीं। गाँधी की सरकार के समक्ष घुटनाटेक गाँधी-इर्विन समझौते की कार्यवाही से प्रज्वलित हुई। और इन नेताओं ने कांग्रेस में ही एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की जो समाजवादी एवं प्रगतिशील रुझानों से प्रतिबद्ध हो। प्रगतिशील नेताओं की इसी इच्छा की परिणति अनतः कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में हुई।

गाँधी के नेतृत्व के विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएँ आरम्भ हुई और जिसकें कारण कांग्रेस के प्रगतिशील (वामपंथी) नेताओं में असन्तोष फैला उसका विश्लेषण आवश्यक है। सन् 1927 के कांग्रेस महासम्मेलन में यह बात स्पष्ट हो गयी कि कांग्रेस पर गाँधी का नेतृत्व निर्विवाद नहीं है। जवाहर लाल नेहरु तथा सुभाष चन्द्र बोस ने सर्वप्रथम सम्पूर्ण स्वतन्त्रता से संबंद्ध जो प्रस्ताव रखा, वहाँ गाँधी के विरोध के बावजूद पारित हो गया और कार्यकारिणी समिति में बोस, नेहरु तथा उस0 कुरैशी ले लिए गये। उसके साथ ही मद्रास कांग्रेस के दौरान इस बात की प्रमाणिक

---

1. मार्क्स एंगेल्स-कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, पृष्ठ 65
2. डा0 राम मनोहर लोहिया- समाजवादी आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ 12
3. एम0 आर0 मसानी- दि कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया, पृष्ठ 2
4. जब मई 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, समाजवादियों ने उसे 'वामपंथी सुधारवाद' बताया तथा उसकी निन्दा की ।

डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति ही अपना उद्देश्य मानता है तथा दूसरा सम्पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के उद्देश्य से ओत प्रोत है। गाँधी इससे सन्तुष्ट नहीं थे क्योंकि वे पहले तत्व के प्रबलतम समर्थक थे और येन केन प्रकारेण वह चाहते थे कि कांग्रेस डोमेनियन स्टेट्स का ही समर्थन करे। नवम्बर 1928 में कलकत्ता कांग्रेस के दौरान उन्होंने इससे सम्बद्ध प्रस्ताव भी रखा जिसका वामपंथी नेताओं (तत्वों) द्वारा डटकर विरोध हुआ। बोस और नेहरु ने प्रस्ताव का डटकर विरोध करते हुए उसमें संशोधन पेश किया, जिसमें यह कहा गया था कि सम्पूर्ण स्वतन्त्रता तथा ब्रिटिश सरकार से सम्पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद की बात स्वीकार की जाए। जब संशेधन पर मतदान हुआ तो अधिकांश सदस्यों ने गाँधी के मौलिक प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस संशोधन प्रस्ताव को रद्द कर दिया। संशोधन के पक्ष में 973 मत पड़े जबकि विरोध में 1350 मत गाँधी की हठधर्मिता यहां स्पष्ट थी कि येन-केन प्रकारेण, उन्होंने मद्रास प्रस्ताव को बदलवा दिया। इतना ही नहीं जिन लोगों ने संशोधन के विरोध में मतदान किया था, उन्होर्ने भी यह कहा कि वे संशोधन के विरुद्ध इतना नहीं है, जितना उन्हें इस बात का डर है कि यदि संशोधन पारित हो जाता तो गाँधी कांग्रेस से पृथक हो जाते जो कांग्रेस के लिए अन्ततः घातक सिद्ध होता। इससे स्पष्ट होता है कि गाँधी ने इस प्रकार की धमकी भी दी थी। गाँधी की इस कुटिल योजना से वामपंथी तत्वों का खिन्न होना स्वाभाविक था। किन्तु इससे एक बात स्पष्ट हो गयी कि कांग्रेस में इन तत्वों की स्थिति नगण्य नहीं थी।जिसे सरकार ने भी अपने दस्तावेज में स्वीकार किया। इसी अवधि के दौरान नेहरु ने विदेश यात्रा की और ब्रुसेल्स में साम्यवादियों द्वारा प्रेरित "उत्पीड़ित जातीयताओं की कांग्रेस" में भाग लिया। समाजवादी व मार्क्सवादी शिक्षाओं और सिद्धांतों से वे काफी प्रभावित हुए तथा भारत लौटने पर वे इन मूल्यों के समर्थक बन गये थे। इसके बावजूद वे उदारवादी परम्परा से इतना अधिक प्रभावित थे कि उससे नाता तोड़ना उसके लिए संभव नहीं था। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए नेहरु के विषय में बोस ने लिखा कि वे मस्तिष्क से तो वामपथियों के साथ है परन्तु हृदय से महात्मां गाँधी के अन्यतम समर्थक हैं। सुभाष चन्द्र बोस का यह कथन बाद में सन् 1929 ई0 में लाहौर कांग्रेस के दौरान सच्चा साबित हुआ। गाँधी ने नेहरु को कांग्रेस की अध्यक्षता प्रदान करने की पेशकश की। वामपंथियों ने गाँधी की नीतियों को समझा तथा उन्होंने यह आशंका व्यक्त की कि नेहरु गाँधी के हाथों में खिलौना मात्र बन जायेंगे। नेहरु अध्यक्ष बने लेकिन वह नाम मात्र के लिए अध्यक्ष थे। निर्णय गाँधी की इच्छानुसार ही होते थे। लाहौर कांग्रेस

के दौरान गाँधी ने एक और कुटनीतिक चाल खेली । सम्पूर्ण स्वतन्त्रता के सिद्धांत का समर्थन करते हुए बहुत से वामपंथी सदस्यों को गाँधी ने अपने खेमें में ले लिया अर्थात गाँधी ने वामपंथी तत्वों को बड़ी चतुराई से विखण्डित करने का प्रयास किया जिसमें तत्कालिक तौर पर उन्हें सफलता प्राप्त हुई और वामपंथी खेमें में उदासीनता छा गयी।

लाहौर कांग्रेस के दौरान गाँधी का बोल बाला रहा। इस कांग्रेस में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया था कि वायसराय को ईश्वरीय इच्छा के फलस्वरुप बम विस्फोट से बच निकलने पर बधाई दी जाये। वामपंथियों ने इसे निरर्थक और अनावश्यक माना, लेकिन गाँधी के प्रयत्नों से यह प्रस्ताव थोड़े से बहुमत से पारित हो गया। बोस का वह प्रगतिशील प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया। जिसमें समान्तर सरकार व किसानों, मजदूरों और युवकों के स्तर पर संगठन बनाने की बात की गयी थी। इतना ही नहीं, गाँधी अपनी इस कूटनीति में भी सफल रहे कि अधिक से अधिक वामपंथी तत्वों को संगठनात्मक दायित्वों से निकाल फेंका जाए । सुभाष चन्द्र बोस एवं श्रीनिवास आयंगर को कार्यकारिणी समिति से इस आधार पर निष्काषित कर दिया गया कि परस्पर विरोधी विचार वालों को कमेटी में नहीं रखना चाहिए । इस निष्कासन का यद्यपि घोर विरोध हुआ लेकिन कांग्रेस को एक जुट बनाये रखने के नाम पर वामपंथी तत्वों को इसे भी स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा । इस तरह लाहौर कांग्रेस में सारा मैदान गाँधी के हाथ रहा और वामपंथी तत्वों को असफलता एवं विवशता का सामना करना पड़ा । गाँधी व वामपंथी तत्वों के मध्य अन्तर्विरोध बढ़ रहा था यह स्पष्ट है ।[5]

मार्च 1931 में कांग्रेस की बैठक जब करांची में हुई उस समय राजनीतिक वातावरण में काफी परिवर्तन हो चुका था । इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गाँधी-इर्विन समझौते का स्वागत करना था । नागरिक अवज्ञा आन्दोलन का प्रथम चरण समाप्त हो चुका था । इस आन्दोलन के दौरान जन साधारण में जो अद्वितीय राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई थी, उससे दक्षिणपंथी नेतृत्व भयग्रस्त हो गया था।जबकि वामपंथी तत्वों को अपनी बात व्यापक रुप से कहने का अवसर प्राप्त हुआ । नागरिक अवज्ञा आन्दोलन उठा लिये जाने के कारण जन साधारण में असन्तोष उत्पन्न हो गया था जो निश्चय ही गाँधी एवं दक्षिपंथी नेतृत्व के विरोध में अधिक था । जन साधारण के असन्तोष का दूसरा कारण और भी गम्भीर था। स्वतन्त्रता संग्राम के तीन सेनानियों

---

5 - सत्या राय (संपादिका)-"भारत में राष्ट्रवाद" पृष्ठ 262

(क्रान्तिकारियों)भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा भुगतनी पड़ी। गाँधी को बोस ने समझौता वार्ता आरम्भ होने पूर्व यह सम्मति दी थी कि यदि सरकार इन तीनों क्रान्तिकारियों की रिहाई की मांग को स्वीकार नहीं करती है तो वे (गाँधी) समझौता वार्ता को भंग कर दें। गाँधी ने इस सम्मति को स्वीकार नहीं किया तथा समझौता वार्ता जारी रही और सरकार ने इन क्रान्तिकारियों को फाँसी की सजा दे दी। गाँधी भले ही, इस सजा के पक्ष में प्रत्यक्षतः न रहे हों, लेकिन वे निर्दोष नहीं कहे जा सकते। इस घटना से जन साधारण व उनके नेतृत्व से अत्यन्त क्षुब्ध था, जिसके फलस्वरुप जब गाँधी व निर्वाचित अध्यक्ष बल्लभ भाई पटेल कराँची अधिवेशन में भाग लेने पहुँचे तो उन्हें जबरदस्त जन आक्रोश एवं प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। खुले अधिवेशन में भगत सिंह व उनके साथियों के बलिदानों का स्वागत करते हुए जब प्रस्ताव रखा गया तो गाँधी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, वहाँ भी उन्हें गंभीर जन आक्रोश का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रस्ताव संशोधित रुप में पारित हुआ तथापि गाँधी की छवि धूमिल हुई। इसमें कोई सन्देह नहीं वामपंथी तत्वों का यह विचार था कि गाँधी-इर्विन समझौते को समर्थन न मिले तथापि पार्टी की एकता को बनाये रखने तथा सरकार की इस नीति को असफल बनाने के लिए कांग्रेस में विभाजन न हो और न विघटन स्पष्ट रुप से सामने आ जाए, उन्होंने इसका विरोध खुलकर नहीं किया और समझौते के स्वागत से सम्बद्ध प्रस्ताव पारित हो जाने दिया। इसके बावजूद वामपंथी तत्वों का प्रभाव कांग्रेस रणनीति एवं नीति-निर्धारण पर व्यापक रुप से पड़ा तथा दक्षिणपंथी गुट को (जिसके नेता गाँधी थे) सुरक्षात्मक नीति अपनानी पड़ी।[6]

दक्षिणपंथी तत्वों ने गाँधी की इच्छा के प्रतिकूल करांची में, वामपंथी तत्वों की विजय इस बात में भी रही की वे मौलिक अधिकारों व आर्थिक नीति से संबद्ध प्रस्ताव को पारित करवा लेने में सफल रहे। जिसमें मोटे तौर पर इस बात पर बल दिया गया था कि जन साधारण के शोषण को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता अनिवार्य रुप से वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता से आबद्ध हो। बड़े-बड़े उद्योगों और सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की मांग वास्तव में प्रगतिशील तो थी ही, जो गाँधी समेत दक्षिण गुट को मान्य नहीं थी। करांची में यह सिद्ध हो गया कि कांग्रेस का वामपंथी तत्व सर्वथा नगण्य नहीं है, उसका अपना प्रभाव है और कांग्रेस नेतृत्व उसे दृष्टि से ओझल नहीं कर सकता। इससे इस तथ्य की भी पुष्टि हुई कि गाँधी व उनका

---

6 - सत्या राय (संपादिका)-"भारत में राष्ट्रवाद" के "कांग्रेस समाजवादी पार्टी तथा अन्य वामपंथी दल" नामक अध्याय वी0 पी0 पाण्डये द्वारा लेखबद्ध किया गया।

नेतृत्व ही कांग्रेस नहीं है, उसमें ऐसे भी तत्व हैं जिनका स्वतन्त्र राजनीतिक चिन्तन है और ये तत्व कांग्रेस में पर्याप्त तथा व्यापक प्रभाव रखते हैं जिनसे कांग्रेस नेतृत्व विमुख नहीं हो सकता ।

कांग्रेस की गैर प्रगतिशील नीतियों एवं कठमुल्लावादी नीति से असन्तुष्ट कुछ कांग्रेसियों ने सन् 1931 ई0 में सर्व प्रथम उत्तरी बिहार में समाजवादी संघों की स्थापना की । सन् 1932-33 के दौरान नासिक केन्द्रीय कारागार में रखे गये कुछ कांग्रेसियों ने (जिसमें जय प्रकाश नारायण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी) अखिल भारतीय समाजवादी दल का खाका तैयार किया जिसे बाद में उत्तर प्रदेश और बम्बई के क्षेत्रों में लोकप्रियता प्राप्त होती गयी । धीरे-धीरे समाजवादी विचारों से प्रभावित कांग्रेसी समाजवादी पार्टी की स्थापना की । इस तरह सन् 1934 ई0 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन.सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई तथा बम्बई में अक्टूबर-नवम्बर के दौरान इसकी नीतियाँ एवं कार्य प्रणाली तय की गयी । इस तरह कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में जिस नेताओं नें सक्रिय योगदान दिया उनमें निम्नलिखित थे- जय प्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेन्द्रदेव, अच्युत पटवर्धन, एम0 आर0 मसानी0, डा0 राम मनोहर लोहिया, एन0 जी0 गोरे, एस0 एम0 जोशी, पुरुषेत्तम विक्रमदास, यूसूफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि ।[7]बाद में जिन अन्य कांग्रेसी व अन्य विचारधाराओं से सम्बद्ध नेताओं ने इसकी सदस्यता ग्रहण की उनमें मुख्य थे- ई0 एम0 एस0 नम्बूदरी पाद, रायवादी चार्ल्स मतकारेन हास, रजनी मुखर्जी, धर्मदास गुणवर्धन, मनी बेनकर, आर0 एम0 एन0 ए0 खेड़मिकर, एम0 आर0 शेट्टी, बी0 एम0 तारकुण्डे, एच0 आर0 महाजनी, जी0 पी0 खेर, आर0 के0 खडिलकर, अहमदाबाद में ठाकुर प्रसाद पंड्या, डी0 एम0 ठक्कर तथा दक्षिण के ए0 के0 पिल्लई (जो प्रसिद्ध राय्यवादी थे) आदि । जिन दो राष्ट्रीय नेताओं का इस पार्टी को आशीर्वाद था और जो इसकी नीतियों का खुलेआम समर्थन भी करते थे, लेकिन इससे सक्रिय रुप से सम्बद्ध नहीं हो पाये थे, वे थे पं0 जवाहर लाल नेहरु तथा सुभाष चन्द्र बोस, गाँधी के अन्यतम विश्वास पात्र होने के कारण सम्भवतः नहेरु समाजवादी पार्टी से अपने को सम्बद्ध नहीं कर पाये । लेकिन सन् 1929 में उन्होंने जो घोषणा की थी वह समाजवादी नीतियों से काफी ओत-प्रोत लगती थी । बाद में वह भी समाजवाद से अपनी सम्बद्धता का प्रलाप

---

7 - अशोक मेहता- "डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एण्ड स्टडीज इन एशियन सोशलिज्म"

करते रहे, लेकिन सक्रिय रुप से इसे अपना नहीं पाये । सुभाष चन्द्र बोस सम्भवतः गाँधी के जबरदस्त विरोधी होने के कारण इस संस्था से अपने को सक्रिय रुप से सम्बद्ध नहीं कर सके, हालांकि उस पार्टी की नीतियों से वे काफी सीमा तक आबद्ध रहे । गाँधी कंग्रेस समाजवादी पार्टी के सदैव विरोधी रहे क्योंकि उनके लिए वर्ग संघर्ष सदैव असहमति का विषय ही बना रहा तथा वर्ग सहयोग की कामना उनका एक आदर्श लक्ष्य था, जिसकी प्राप्ति तो नहीं हो सकी और नही यह संभव था ।

एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि वह कांग्रेस पार्टी से ही सम्बद्ध रहे और कोई ऐसा कार्य न करे जो कांग्रेस की नीतियों का विरोध करता हो ।उनका सीधा लक्ष्य था कि कांग्रेस को समाजवादी मूल्यों से आबद्ध किया जाये तथा इसकी बुनियादी नीतियों को बनाये रखा जाये ।इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कांग्रेस समाजवादी दल के लोग समाजवाद की वैज्ञानिक मान्यताओं को स्वीकार करने के स्थान पर कांग्रेस की नीतियों में समाजवादी सुधारों के लिए कृत संकल्प थें । अर्थात वे कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी मूल्यों से ओत-प्रोत तो करना चाहते थें लेकिन कांग्रेस को समाजवादी नीतियों के बनाने के प्रबल समर्थक नहीं थे।

बहुत थोड़े लोग थे जो इस विचार के थे । उनकी संख्या इतनी कम थी कि यदि ऐसा करने का प्रयास किया जाता तो कांग्रेस समाजवादी दल बनने से पहले ही टूट जाता । पार्टी के संस्थापकों की राजनीतिक विचारधारा समान नहीं थी अर्थात वे पृथक-पृथक राजनीतिक विचारधाराओं से प्रतिबद्ध थे, जिसका प्रभाव पार्टी के नीतिनिर्धारण आदि क्रियाकलापों पर स्पष्ट रुप से पड़ा ।चूँकि पार्टी की नीतियाँ सदस्यों के पूर्वाग्रहों से ग्रसित राजनीतिक मान्यताओं से निर्धारित हुई । इसलिए पार्टी अन्त तक सार्वजनिक, शाश्वत एवं मौलिक नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्धारण में असफल रही । यहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी से सम्बद्ध शीर्षस्थ नेताओं की राजनीतिक पृष्ठ भूमि का अवलोकन संदर्भवश, युक्ति संगत तो है ही, काफी दिलचस्प व भ्रामक भी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के घटक तत्वों की प्रकृति का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि पार्टी के संगठक तत्व आरम्भ में भिन्न-भिन्न राजनीतिक अवधारणओं से जुड़े हुए तो थे ही बाद में भी यह स्थिति बनी रहीं और इन विभिन्न तत्वों ने सदैव इस बात को ध्यान में रखा कि उनकी मौलिक राजनीतिक अवधारणा न केवल अप्रभावित रहे, बल्कि पार्टी की छत्रछाया में ही

फूले-फूले । प्रमुख रुप से जिन राजनीतिक विचारधाराओं को पार्टी में प्रतिनिधित्व प्राप्त था उसमें मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधारा (कम गम्भीर और अधिक आकर्षक), फेबियन विचारधारा और उदारवादी समाजवादी विचारधारा । इन तीनों विचारधाराओं के लोग अपनी आस्था के प्रति सजग रहे व इस चेष्टा में रहे कि पार्टी के माध्यम से क्रमशः उनकी अपनी विचारधारा का प्रचार व प्रसार हो जिसके कारण इन संगठक तत्वों के मध्य गंभीर राजनीतिक मतभेद हमेशा ही बना रहा । एम0 एन0 राय को यह आशंका थी कि चूँकि यह पार्टी अपने उद्देश्यों के प्रति स्पष्ट नहीं है । अतः यह बुर्जुआ-संसदवाद व सुधारवादी प्रवृत्तियों में आत्मसात हो सकती है । उनकी राय यह भी थी कि ऐसे सुधारवादी दलों के विघटन के बिना शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण नहीं हो सकता । अपने इन उद्देश्यों को प्रमुखता प्रदान करते हुए उन्होंने अपने अनुयायियों को यह हिदायत दी थी कि वे पार्टी में सम्मिलित तो हों लेकिन इससे अपने को आबद्ध न करें । इसे आगे बढ़ाने के साधन के रुप में प्रयुक्त करें । अर्थात राय व उनके अनुयायी पार्टी के माध्यम से अपनी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार चाहते थे। राय ने मीनू मसानी व विक्रमदास आदि नेताओं कों हमेशा सन्देह की दृष्टि से देखा और कमला देवी तथा मेहर अली को प्रगतिशील माना ताकि पार्टी के नेताओं में अन्तर्विरोध बना रहे । जैसे ही राय को यह लगने लगा कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति में पार्टी बाधाएँ डाल रहीं हैं, उन्होंने उसे तोड़ने की हर संभव चेष्टा की । कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े लोगों या कम्युनिस्टों को यद्यपि पार्टी में प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन मसानी व विक्रमदास आदि उदारवादियों ने उन्हें सदैव सन्देह की दृष्टि से देखा तथा वे हमेशा इस प्रयत्न में रहे कि कम्युनिस्टों को पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त न हो । आलोचना के बावजूद जब मसानी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए तो उन्होंने सन् 1939 में पार्टी को ही छोड़ दिया । उनके साथ ही अशोक मेहता, डा0 लोहिया, अच्युत पटवर्धन आदि नेताओं ने भी पार्टी की कार्यकारिणी से संबंध-विच्छेद कर लिया । लेकिन इससे पहले कम्युनिस्टों के विषय में कुछ अपमानजनक निर्णय पार्टी द्वारा लिए जा चुके थे । जैसे- सन् 1937 में पार्टी ने यह निर्णय लिया कि अब कम्युनिस्टों को पार्टी में प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन जो पहले से पार्टी के सदस्य हैं, वे बने रह सकते हैं । कांग्रेस समाजवादी पार्टी की इस नीति से कम्युनिस्टों का असन्तुष्ट होना स्वाभाविक था जिसका परिणाम यह हुआ कि मई 1940 के आते-आते उन्होंने भी पार्टी छोड़ने के विषय में गंभीर रुप से सोचना आरम्भ कर दिया । जवाहरलाल नेहरु व सुभाष चन्द्र बोस को

पार्टी अपनी नीतियों से ओत-प्रोत मानती थी और उसकी गतिविधियों में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ भी थीं, लेकिन औपचारिक रुप से इनमें से किसी ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पार्टी के विभिन्न घटकों में इतने गम्भीर मतभेद हो गये थे कि अब आगे एक साथ बने रहना उनके लिए असम्भव हो गया। पर्दे के पीछे कार्य करने वाले नेताओं (नेहरु और बोस) के अन्तर्विरोध भी इस बात पर स्पष्ट हो गये कि विश्वयुद्ध में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसलिए आदि से अन्त तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संघटक तत्वों में राजनीतिक मतभेद व गतिरोध बने रहे, जिसके कारण पार्टी का विघटन, अन्ततः एक स्वाभाविक अनिवार्यता बन गया और उसका विघटन भी हो गया।

जय प्रकाश नारायण व आचार्य नरेन्द्र देव मार्क्सवादी चिन्तन से प्रभावित थे। जय प्रकाश नारायण ने तो अपनी पुस्तक "समाजवाद ही क्यो"[8] समाजवादी नीतियों का भरपूर गुणगान किया है।

जय प्रकाश नारायण ने हमेशा यह स्वीकार किया कि उन्हें मार्क्सवादी चिन्तन से आबद्ध करने में एम0 एन0 राय का ही प्रमुख योगदान था। यह एक वास्तविकता है कि राय ने मार्क्सवाद को अपनी स्वतन्त्र दृष्टि से देखा और उसे अपने राजनीतिक हितों के लिए सुविधाजनक रुप में अपनाया। अन्त में वे एक कांग्रेसी के रुप में काल-कलवित हुए।

अतः इन नेताओं की राजनीतिक समझदारियों के अध्ययन से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के दौरान इन लोगों में परस्पर राजनीतिक मतभेद थे। इन मतभेदों का प्रभाव पार्टी पर पड़ा जिसके फलस्वरुप पार्टी न तो किसी

---

[8] - सन् 1936 में "सामाजवाद ही क्यों ?" का गुणगान करने वाले जय प्रकाश नारायण इस शताब्दी के पाचवें दशक में गाँधीवाद से इतना प्रभावित हुए कि गाँधीवाद ही उन्हे सभी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के समाधान में राम वाण औषधि के रुप में दिखाई पड़ने लगा।इतना ही नहीं सन् 1954 में सक्रिय राजनीति से सन्यास लेने की घोषणा करके वह विनोबा भावे के भूदान महायज्ञ से सम्बद्ध हो गये ताकि भारतीय दरिद्र नारायण की समस्या का समाधान हो सके। भूदान महायज्ञ की विफलता ने उन्हें पुनः राजनीति में सक्रिय किया और सन् 1974-75 के दौरान उनके नेतृत्व मे सम्पूर्ण क्रान्ति का आह्वान हुआ जो सन् 1977 में जनता पार्टी के गठन में परिणत हुआ और जो विलोम राजनीतिक विचारधाराओं का गठबन्धन होने के कारण पाँच वर्ष की अवधि भी सत्ताधारी दल के रुप मे पूरा न कर सका। जनता पार्टी के विघटन व श्रीमती इन्दिरा गाँधी के सत्ता में पुनरागमन से जय प्रकाश नारायण का राजनीतिक भ्रमं टूटना ही था, जो मृत्यु के समय स्वयं भी देख सके।इसका अर्थ यह है कि जय प्रकाश नारायण की राजनीतिक विचारधारा प्रतिबद्धता और अनन्यता का जो अभाव दिखाई देता है, उसका प्रभाव कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नीति निर्धारण पर पड़ना स्वाभाविक ही था। मीनू मसानी ने सन् 1939 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया व सन् 1959 में स्वतन्त्र पार्टी की स्थापना में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। स्वतन्त्र पार्टी घोर प्रतिक्रियावादी व प्रारम्भिक पूँजीवादी मूल्यों की समर्थक थी, इसमें संदेह नहीं।समाजवादी से पूँजीवादी विचारधारा के अपनाने वाले नेता की राजनीतिक मनः स्थिति को सहज आंका जा सकता है।अशोक मेहता ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से सन् 1962 में सम्बन्ध विच्छेद किया तथा कांग्रेस के सदस्य बन गये। वे श्रीमती गाँधी की सरकार में सन्1966 में योजना मंत्री के पद पर आसीन हुए। इसी तरह डा0 लोहिया को 1955 मे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया और अन्ततः उन्होंने संयुक्त समाजवादी दल की स्थापना की जिसका राजनीतिक परिणाम सर्व विदित है।

राजनीतिक विचारधारा से पूर्ण रुप से सम्बद्ध हो पायी और न ही वह ऐसे कार्यक्रम तय कर पायी जिनके माध्यम से उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो पाती जिनका उल्लेख पार्टी ने सर्वप्रथम किया था। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे-

1- ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को सम्पूर्ण आजादी मिले।

2- भारतीयों को अपने भविष्य के लिए स्वतन्त्रता पूर्वक संविधान बनानें का अधिकार प्राप्त हो।

3- स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो ताकि भारतीय समाज से शोषण की वीभत्स संस्था का उन्मूलन हो सके।

4- निजी सम्पत्ति का उन्मूलन हो ताकि समाज के दो वर्गों में व्याप्त खाई को पाटा जा सके।"इस उद्देश्य का समर्थन नेहरु ने सन् 1936 में लखनऊ कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए किया, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि भारतीय समस्याओं का समाधान समाजवादी रास्ते से ही हो सकता है जिसके लिए भारत की सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है, जैसे निजी समपत्ति की संस्था की समाप्ति (सीमित रुप में) तथा वर्तमान लाभ कमाने की व्यवस्था के स्थान पर सहकारिता के सिद्धांत की स्थापना आदि "।[9]

5- कांग्रेस समाजवादी दल की सदस्यता के लिए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता का होना अनिवार्य है। इस उद्देश्य में हालांकि बाद में संशोधन हुआ जिसके फलस्वरुप अन्य दलों के सदस्यों को भी इस पार्टी की सदस्यता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ।

6- स्थापना के प्रारम्भिक काल में पार्टी के दो मोटे उद्देश्य थे, जो अंत तक बने रहें। पहली,कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को यह बतलाना कि राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें भाग लेने वाले मजदूरों और किसानों की सहभागिता को अधिक विस्तृत किया जाये। दूसरा, भारतीय जन-साधारण में इस बात का प्रचार करना कि उनकी वास्तविक समस्याओं के समाधान का प्रश्न उस राजनीतिक संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। अतः उन्हें इस संघर्ष में सक्रिय भाग लेना चाहिए।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी के इन उद्देश्यों का अध्ययन यदि ध्यान पूर्वक किया जाय तो

---

9 - जे0 पी0 हेथ्काक्स-"कम्युनिज्म एण्ड नेशनेलिज्म इन इण्डिया," पृष्ठ 22

ज्ञात होता है कि इसका वास्तविक लक्ष्य कांग्रेस को मजबूत करना तो था ही, भारतीय जन साधारण पर कांग्रेसी नेतृत्व की निरन्तरता को बनाये रखना भी था। कांग्रेस दक्षिण पन्थियों के नेतृत्व में थी। यदि जन साधारण उसके नेतृत्व को स्वीकार करता जो कभी भी उसकी समस्याओं का समाधान करने का पक्षधर नहीं था। जिसका प्रमाण इतिहास में भरा पड़ा है। गाँधी का भी तो यही उद्देश्य था।

अन्तर्विरोधी नीतियों के कारण पार्टी की सफलता निश्चय ही सन्देहास्पद थी। गाँधी तथा उसके अनुयायियों ने पार्टी की हर उस नीति और कार्यक्रम का विरोध किया जो समाजवादी के पक्ष में था।[10] उदाहरण के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी जहाँ जमींदारी तथा निजी सम्पत्ति की संस्था के उन्मूलन का आह्वान कर रही थी, एवं इसकी पूर्ति के लिए कार्य क्रम बनाने में मशगूल थी, वहाँ गाँधी ने इसका खुलकर विरोध किया। इसी तरह जब समाजवादियों ने कांग्रेस महासमिति के गठन के बारे में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनाव-प्रक्रिया की वकालत की तथा सदस्यों की संख्या में वृद्धि की मांग की तब गाँधी ने मनोनयन तथा सदस्य संख्या घटाने पर जोर दिया।[11] उन्होंने इस बात का विरोध करते हुए कांग्रेस समिति से अपील की कि बैठकों में सूत काटने को कांग्रेस की सदस्यता प्राप्ति के लिए आवश्यक बना दि जाये तथा कांग्रेस की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या छः हजार से एक हजार कर दी जाये।[12] आखिर गाँधी का यह विचार किस बात का द्योतक कहा जा सकता है? उत्तर साफ है कि वह कांग्रेस संगठनों में समाजवादियों के बढ़तें प्रभाव से क्षुब्ध थे तथा उन्हें येन-केन प्रकारेण प्रभावहीन बनाना चाहते थे। इन प्रस्तावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें यह स्पष्ट कहा गया कि इन प्रस्तावों का एक मात्र उद्देश्य कांग्रेस में समाजवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना है।[13]

बम्बई महाधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की आधार शिला रखी गयी और पार्टी के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों की घोषणा हुई। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुछ संगठनात्मक तथा

---

10 - सत्य, एम0 राय (सं0),"भारत में राष्ट्रवाद" पृष्ठ 269

11 - सन् 1934 में ही उ0 प्र0 के जमींदारों को गाँधी ने यह कहकर आश्वासन दिया,"मैं सम्पत्तिवानों को सम्पत्तिहीन करने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य तो उनका हृदय परिवर्तन करना है ताकि वे सम्पत्ति को धरोहर मानकर उसका प्रयोग सम्पत्ति विहिनों के कल्याणार्थ करें। मेरा अन्तिम उद्देश्य पूँजी और श्रम तथा मालिक और किरायेदारों के मध्य सामंजस्य तथा सहयोग की स्थापना करना है। कांग्रेस की कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे जमींदारो को डरने की जरूरत हो।"

12 - 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक (वर्धा) में डा0 राजेन्द्र प्रसाद के अध्यक्षीय भाषण से उद्धृत, पृष्ठ 15

13 - जे0 एस0 शर्मा-"भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस" पृष्ठ 565

राजनीतिक निर्णय भी लिये गये। सम्पूर्ण स्वतत्रंता प्राप्ति तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का जो निर्णय हुआ, उसमें कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक आकांक्षाएँ भी अन्तर्निहित थी। सम्पूर्ण स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह बतलाया गया कि एक स्वतन्त्र भारत की स्थापना होगी और किसी भी स्तर पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद से समझौता नहीं किया जायेगा।[14] ब्रिटिश साम्रज्यवाद से किसी भी स्तर पर समझौता न करने के आह्वान में यह विश्वास अन्तर्निहित था कि तालमेल और समझौते के आधार पर स्वतन्त्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तालमेल और समझौते के आधार पर प्राप्त की गयी स्वतन्त्रता वास्तविक स्वतन्त्रता नहीं हो सकती। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का हमेशा यह विश्वास बना रहा और उसके इस विश्वास को भी साम्यवादियों तथा अन्य वामपंथी घटकों का समर्थन भी प्राप्त था।[15] संगठनात्मक पक्ष के विषय में जो निर्णय लिये गये वे लोकतान्त्रिक पद्धति से ओत-प्रोत थे। महाधिवेशन में यह पारित हुआ कि-

1- सर्वोच्च नीति-निर्धारण शक्ति वार्षिक महाधिवेशन में सन्निहित होगी, जिसमें प्रान्तीय इकाईयों के सदस्य प्रतिनिधि के रुप में सम्मिलित होंगे।

2- वार्षिक महाधिवेशन में एक कार्यकारिणी समिति निर्वाचित की जायेगी, जिसमें एक महामंत्री चार संयुक्त मन्त्री और ग्यारह साधारण सदस्य होंगे।

3- पार्टी की सदस्यता केवल उन्हीं लोगों को प्रदान की जायेगी जो कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध तथा प्रान्तीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सदस्य होंगे।

4- साम्प्रदायिक संगठन से सम्बद्ध लोग सदस्य के रुप में अग्राह्य होंगे।

5- किसी अन्य ऐसे राजनीतिक संगठन से सम्बन्धित लोगों को सदस्यता प्रदान नहीं की जायेगी, जिसकी नीतियाँ, पार्टी की दृष्टि में, पार्टी से मेल नहीं खाती अथवा उसकी अपनी नीतियों के विरुद्ध हो।[16]

संगठन संबंधी इन निर्णयों को देखने से यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस से येन-केन प्रकारेण सम्बद्ध लोगों को ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी में प्रवेश पाने का अधिकार प्राप्त

---

14 - कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पहले सम्मेलन की रिपोर्ट

15 - एल0 पी0 सिन्हा-"लेफ्ट विंग इन इण्डिया" पृष्ठ 325

16 - कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पहले सम्मेलन की रिपोर्ट

था । जिसकी महत्वूपर्ण कीमत बाद में पार्टी को चुकानी पड़ी और अन्ततः यह कांग्रेस की पिछलग्गू ही बनी रही ।

(ii) **कांग्रेस समाजवादी दल के कार्यक्रम तथा उपलब्धियाँ**

कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अस्तित्व सन् 1934 से 1947 तक रहा । इस अवधि में जन साधारण की समस्याओं के समाधान, समाजवादी समाज की स्थापना, सम्पूर्ण स्वतन्त्रता के सिद्धांत, मार्क्सवादी विचारधारा के विकास तथा संविधान संभा कें संगठन आदि से सम्बद्ध राष्ट्रीय समस्याओं के (संदर्भ में उसकी भूमिका निर्णायक नहीं रही तथापि) उसकी कुछ सकारात्मक भूमिकाएं अवश्य रहीं । यह स्प्ष्ट है कि कांग्रेस समाजवादी दल ने कभी भी समाजवाद के वैज्ञानिक दृष्टिकोंण को अपनाने का प्रयास नहीं किया, वह भी व्यवहारिक रुप में तों बिल्कुल ही नहीं । सम्भवतः इसका प्रमुख कारण इसके प्रवर्तकों के अलग-अलग राजनीतिक विचार थे । जिसका प्रतिनिधित्व हमेशा ही होता रहा । कांग्रेस समाजवादी पार्टी विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से सम्बद्ध राजनीतिज्ञों की जमात ही बनी रही और उसके पृथक-पृथक विचारों की अभिव्यक्ति का एक राजनीतिक रंगमंच अथवा साधन । मार्क्सवाद, उदारवादी समाजवादी व गाँधीवादी के परस्पर विरोधी आदर्शो से सम्बद्ध इस पार्टी से किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रचार एवं प्रसार की आशा न तो न्याय संगत थी और न व्यवहारिक ही थी । कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरंचना समिति की प्रकृति के आधार पर न तो किसी हो राजनीतिक उद्देश्य की स्थापना ही संभव थी और न एक स्वतंत्र राजनीतिंक दल के रुप में कार्य करने की आशा ही थी । ठोस राजनीतिक कार्यक्रम के अभाव में, कांग्रेस से बधे रहना इसके लिए स्वाभाविक था जिसे वह कभी भी नजर अंदाज नहीं कर सकी ।इसका एक मात्र उद्देश्य, कांग्रेस को उन सभी लोकप्रिय राजनीतिक सिद्धांतों से सम्बद्ध करना था ताकि जन आन्दोलनों और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम का नेतृत्व उसके हाथ में बना रहे, तथा अन्य कोई राजनीतिक दल उस पर अधिकार न जमा ले । जब कभी इस दिशा में दूसरे राजनीतिक दलों ने प्रयास किया तब कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने केवल उनका साथ ही नहीं दिया बल्कि भरसक उनका विरोध भी किया । रायवादियों तथा कम्युनिस्टों के प्रति इस दल के रवैये से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि बड़े पैमाने पर इस दल से रायवादियों और कम्युनिस्टों का निष्कासन इसी बात का परिचायक है ।

उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पार्टी ने जिस भूमिका का निर्वाह किया, उसे निःसन्देह इसकी सफलताओं और उपल्बिधयों का प्रतीक कहा जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस पार्टी के द्वारा समय-समय पर जो कदम उठाये गये। उसका संक्षिप्त विवरण आवश्यक एवं प्रासंगिक भी है।

कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं एवं गाँधी के हठधर्मिता के फलस्वरुप जन-आन्दोलन, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संघर्ष, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग तथा प्रमुख संस्थाओं पर से कांग्रेस का नेतृत्व कम होता जा रहा था जिसकी पुनः प्राप्ति के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी द्वारा उठाये गये कदम निःसन्देह कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से उपलब्धि की श्रेणी में आते हैं। यह अलग बात है कि इस पार्टी के सिद्धांत और व्यवहार में पर्याप्त अन्तर था। इस पार्टी ने लोकप्रिय समाजवादी नारों की इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयोग किया। इसने यह प्रचार किया कि स्वतन्त्रता संग्राम में जनसाधारण को अधिकाधिक मात्रा में भाग लेना चाहिए तभी उसकी वास्तविक समस्याओं का समाधान हो सकेगा। कांग्रेस आधिकारिक नेतृत्व को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने इसका भरपूर लाभ उठाया। गाँधी की 'दरिद्र नारायण' की पूजा को वैज्ञानिक जामा पहनाया गया। 'किसान सभा' में इस बात का प्रचार किया गया कि उसे कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतन्त्रता संग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। इसमें इस दल को सफलता भी प्राप्त हुई जिसके फलस्वरुप कांग्रेस के परम्मपरावादी व दक्षिणपंथी नेतृत्व ने फैजपुर-कृषि कार्यक्रम को सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। समाजवादियों की इस नीति से किसान वर्ग पर कांग्रेस नेतृत्व की आंशिक स्थापना हुई, मजदूर वर्ग पर यद्यपि अत्यधिक प्रभाव न पड़ा क्योंकि उस पर कम्युनिस्टों का व्यापक प्रभाव बना रहा। परन्तु यह वर्ग समाजवादियों की इस नीति से बिल्कुल अप्रभावित भी न रहा। अतः यह कहा जा सकता है कि जन साधारण में कांग्रेस के गिरते प्रभाव को पुनः स्थापित करने में कांग्रेस समाजवादी दल सफल रहा।[17]

युवा आन्दोलन के नेतृत्व पर भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया। तत्कालिक राजनीतिक वातावरण में युवा वर्ग पर समाजवाद के सिद्धान्तों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, जिसे लेकर कांग्रेस बड़ी चिन्तित थी। युवा वर्ग का नेतृत्व उनके हाथों से निकलता जा रहा था। युवा समाज से सम्बद्ध लोग रायवादियों से प्रभावित हो रहे थे अथवा

17. सत्या एम० राय (सं०) "भारत में राष्ट्रवाद", पृष्ठ 271-272

कम्युनिस्टों का प्रभाव उन पर बढ़ रहा था । और अधिकांश युवा वर्ग गाँ तथा कांग्रेस की प्रतिक्रियावादी नीतियों से निराश होता जा रहा था । ऐसे समय में, कांग्रेस स जवादी दल ने उस पर प्रभाव जमाने का प्रयास किया तथा उसके द्वारा दिये जाने वाले अति त्साही नारे प्रभाव जमाने में काफी कामयाब रहे । युवा जगत को कांग्रेस समाजवादी पार्टी क प्रगतिशील नारे आकर्षित करने लगे जिसके फलस्वरुप उसके नेतृत्व पर इस दल का प्रभाव पड़ा जो अन्ततः स्वयं कांग्रेस पार्टी के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हुआ । यदि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना न होती और कांग्रेसी मंच से प्रगतिशील नारे न दियें जाते तो यह लगभग तय था कि कांग्रेस एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल न बन पाती जिसे चहुमुखी समर्थन प्राप्त हो सके । इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस की नीतियों से तत्कालीन युवा वर्ग को सम्बद्ध करने का श्रेय समाजवादी दल को ही दिया जा सकता है जिसने कांग्रेस की डूबती नैय्या को सुदृढ़ पतवार प्रदान की ।

अपने उपर्युक्त दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 15 सूत्रीय कार्य निर्धारित किया जिसे अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कहा जा सकता है । इन कार्यक्र [illegible] पार्टी प्लेटफार्म से की गयी तथा इसके विषय में लिया गया निर्णय लगभग सर्वसम्म था । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 15- सूत्रीय कार्यक्रम में सन्निहित नीतियाँ भारत में सम [illegible] की स्थापना व उद्देश्य से अधिक ओत-प्रोत तथा आकर्षक थी । 15 सूत्रीय कार्यक्र में निम्नलिखित बाते सन्निहित थी-

1- उत्पादक जन साधारण में सभी शक्तियों का हस्तान्तरण हो ।

2- देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित तथा नियन्त्रित हो ।

3- प्रमुख उद्योगों का सामाजीकरण (जैसे-इस्पात,सूत,जूट,रेल, जहाजरानी, तथा खान आदि उद्योग) तथा उत्पादन के साधनों के वितरण तथा विनिमय का सामाजीकरण ।

4- विदेश व्यापार पर राज्य का एकाधिकार ।

5- उत्पादन,वितरण और सार्वजनिकरण के दोनों क्षेत्रों में सहकारी सं [illegible] संयोजन ।

6- राजाओं तथा जमींदार वर्ग तथा अन्य शोषक वर्गो का बिना किसी क्षतिपूर्ति के उन्मूलन ।

7- किसानों में भूमि का पुनर्वितरण ।

8- सहकारिता तथा सामूहिक खेती को राज्य द्वारा प्रोत्साहन तथा नियन्त्रण ।

9- किसानों और श्रमिकों पर ऋणों की समाप्ति ।

10- काम पाने के अधिकार को मान्यता ।

11- आर्थिक वस्तुओं का प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार अंततः वितरण ।

12- वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की स्थापना ।

13- किसी भी धर्म के विषय में राज्य द्वारा भेदभाव किये जाने की मनाही तथा जाति और साम्प्रदायिक आधारों पर मान्यता प्रदान करने का निषेध ।

14- लिंग के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव करने की मनाही ।

15- तथा कथित सार्वजनिक ऋण की समाप्ति ।

कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा घोषित उपर्युक्त15-सूत्रीय कार्यक्रम में अन्तर्निहित नीतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साम्राज्यवादी शासन के दौरान प्रगतिशील व वामपक्षीय सिद्धान्तों को इसमें पर्याप्त मान्यता प्रदान की गयी । कार्यक्रम अत्यन्त आकर्षक एवं प्रगतिशील थे जिनके प्रति जनसाधारण में श्रद्धा के भाव जागृत होना स्वाभाविक था । कांग्रेस के इस वामपंथी घटक को पर्याप्त जन समर्थन प्राप्त हुआ भी ।इस घटक के शीर्षस्थ नेताओं को व्यापक जन समर्थन मिलने के बावजूद ये कार्यक्रम लागू न हो सके और न ही भारतीय संविधान के निर्माण पर इसका कोई मौलिक प्रभाव ही पड़ा । यदि कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस कार्यक्रम को हृदय से लागू करने का प्रयास करती तो भारत का जो आज रुप है वह उससे काफी सीमा तक भिन्न होता तथा भारत में समाजवादी समाज की स्थापना संभव हो सकती थी ।लेकिन स्वयं पार्टी में व्याप्त पर्याप्त अन्तर्विरोधों के कारण इस क्रान्तिकारी कार्यक्रम का लागू होना न तो संभव था और न यह तत्कालीन नेतृत्व को स्वीकार्य ही था । इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं [illegible] प्रतिक्रियावादी तत्वों से गठजोड़ बनाये रखने की उत्कंठ इच्छा तथा आपसी कलह आदि व्यवधान अन्तर्निहित थे, जिससे नेतृत्व उबर न सका और पार्टी अन्ततः पतन की ओर अग्रसर हुई ।

(iii) कांग्रेस समाजवादी पार्टी की असफलता तथा समीक्षा

कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जिस राजनीतिक वातावरण में हुई उसका व्यौरा पहले दिया गया है । प्रगतिशील, दक्षिणपंथी तथा जनसाधारण की समस्याओं के प्रति इमानदारी

बरतने की नीतियों से बराबर प्रतिबद्ध कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जहाँ कांग्रेस पर छा जाना चाहिए था, वहाँ वह असफल हुई और अन्ततः पतन की ओर अग्रसर हुई। इसके कारणों की तह में जाने पर ही सही स्थिति का स्पष्टीकरण हो सकता है।मोटे तौर पर इन कारणों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है। **पहला** वैचारिक तथा सैद्धान्तिक, **दूसरा** कांग्रेस पार्टी से अन्यतम सम्बन्ध तथा **तीसरा** कांग्रेस समाजवादी दल व अन्य वामपंथी विचारधाराओं वाले राजनीतिक संगठनों की इसके प्रति संदेहास्पद धारणाएँ। इन कारणों की संक्षिप्त व्याख्या से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अन्ततः कांगेस समाजवादी दल का काल के गर्त मे जाना अथवा समाप्त होना स्वाभाविक ही था।

कांग्रेस समावादी पार्टी की स्थापना निश्चय ही वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण हुई। इसके साथ ही पार्टी ने सदैव ही इस बात को ध्यान में रखा कि कांग्रेस के बाहर उसका कोई अस्तित्व न तो है और न ही इस बात की वह चेष्टा ही करेगा। दल के शीर्षस्थ नेताओं की उद्घोषणाओं से इस तथ्य की पुष्टि स्वतः ही होती है।कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सैद्धान्तिक एवं वैचारिक अवधारणओं का उल्लेख प्रो0 एल0 पी0 सिन्हा ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है जो काफी सीमा तक आधिकारिक माना जा सकता है। प्रो0 सिन्हा के अनुसार "कांग्रेस समाजवादी ऐसी मन : स्थिति के शिकार थे, जहाँ वे हृदय से गाँधी के साथ थे लेकिन सिर मार्क्स से प्रभावित था। हालांकि गाँधीवाद का प्रभाव अधिक था लेकिन मार्क्सवादी प्रभावों से वे मुक्त न हो सके।[18] यह ठीक है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति तथा समाजवादी समाज की स्थापना था, लेकिन इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन सिद्धांत और वैचारिक मान्यताओं को उन्होंने स्वीकार किया, उसमें पर्याप्त अन्तर्विरोध मौजूद थे, जिसके कारण उद्देश्य प्राप्ति का मामला हमेशा संदिग्ध ही बना रहा। कांग्रेस पार्टी के प्रति लगातार उनके पूर्वाग्रहों के बने रहने से इस धारणा को ठोस आधार मिलता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। कांग्रेस पार्टी का तत्कालीन नेतृत्व तथा गाँधी ने केवल समाजवादियों से सहमत नहीं थें अपितु उनके घोर आलोचक एवं विरोधी भी थे। और गाँधी की यह धारणा निरन्तर बनी रही। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इस वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ नही था तथापि वह इस आशावाद से हमेशा ग्रस्त रहा कि वह कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेतृत्व को यह समझाने और मनवाने

18 - एल0 पी0 सिन्हा-"लेफ्ट विंग इन इण्डिया", पृष्ठ 507

में सफल हो जायेगा कि पूर्ण स्वतन्त्रता और समाजवाद के द्वारा ही भारतीय समस्याओं का मौलिक समाधान हो सकेगा। दक्षिणपंथी नेतृत्व अनजाने में समाजवाद का घोर विरोधी होता तो यह संभव हो पाता। लेकिन वस्तुस्थिति इसके विपरीत थी, क्योंकि वह बहुत सुनियोजित ढंग से समाजवादी मूल्यों एवं अवधारणओं के विरुद्ध था, जिसका प्रमाण कांग्रेस महासमिति द्वारा पारित उस प्रस्ताव से मिलता है जो कांग्रेस समाजवादी दल के गठन के साल में ही लाया गया, इस प्रस्ताव के द्वारा समाजवादी मूल्यों को स्पष्ट नकारा गया।

जून 1934 में पारित उस प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया कि निजी सम्पत्ति का उन्मूलन तथा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कांग्रेस पार्टी की अहिंसात्मक संस्कृति के ठीक विपरीत है।[19] इस प्रस्ताव के दौरान दक्षिणपंथी नेतृत्व ने यह विचार व्यक्त किया कि कांग्रेस समाजवादी दल पहले अन्तर्राष्ट्रीयतावादी है, इसलिए राष्ट्रीय मुक्ति कें संघर्ष में उनपर पूर्णरुपेण निर्भर नहीं किया जा सकता।[20] गाँधी तथा दक्षिणपंथी नेतृत्व के इस रवैये के विपरीत कांग्रेस समाजवादी पार्टी की उक्ति थी कि कांग्रेस नेतृत्व द्वारा ही स्वतन्त्रता संग्राम का सफल नेतृत्व संभव है, तथा कांग्रेस के बिना इस संघर्ष में विजय प्राप्त करना असम्भव है। जे0 पी0 के शब्दों में "कांग्रेस समाजवादी दल का गठन कांग्रेस पार्टी के समानान्तर तथा उसके विरुद्ध नहीं हुआ बल्कि इसलिए हुआ कि कांग्रेस में रहते हुए उसे मजबूत किया जाये और उसकी नीतियों में परिवर्तन एवं संशोधन किया जाएं।[21] कांग्रेस की शक्ति एवं महत्ता का गुणगान करते हुए जे0 पी0 ने लिखा कि "कांग्रेस ही केवल ऐसा संगठन है जिसकें नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष संभव है, तथा राष्ट्रीय एकता को बनाये रखा जा सकता है। कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी युद्ध का सर्वशक्तिशाली मोर्चा है, और साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष यदि आरम्भ होता है तो वह कांग्रेस के तिरंगे झण्डे के नेतृत्व में ही होगा। किसान सभा, मजदूर संगठन तथा छात्रसंघ इस संघर्ष के आरम्भ में निर्णायक भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकते तथा कांग्रेस ही इस संघर्ष की निर्विवाद शक्ति है।[22] कांग्रेस पार्टी की भूमिका राष्ट्रीय संघर्ष में अद्वितीय है जिसे मानते हुए जय प्रकाश नारायण ने भावात्मक घोषणा की, "कांग्रेस ही देश का एक मात्र विस्तार है। याद रखना चाहिए कि कांग्रेस का तात्पर्य पूरे से हे, भाग से नहीं।

---

19 - "इण्डियन एनुअल रजिस्टर "(कलकत्ता), भाग-1, पृष्ठ 300

20 - आचार्य नरेन्द्र देव- "सोशलिज्म एण्ड दि नेशनल रिवोल्यूशन" पृष्ठ 66

21 - वही, पृष्ठ 137

22 - नरेन्द्र देव- "सोशलिज्म एण्ड दि नेशनल रिवोल्यूशन", पृष्ठ 139

पूरे शरीर से कटा हुआ कोई हिस्सा न तो शक्तिशाली होता है और न ही स्वयं में सक्षम, अंततः यह मृत्यु को प्राप्त होता है।[23]

उपर्युक्त ब्यौरे से स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व दक्षिणपंथी गुट में सन्निहित था जिसका सैद्धान्तिक तथा वैचारिक विरोध दल के वामपंथी तत्वों ने किया जिसकी परिणति कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना में हुई। यह ठीक है कि दल अति प्रगतिशील नीतियों को पार्टी के कार्यक्रम में स्थान दिया, लेकिन दक्षिणपंथी नेतृत्व की उदासीनता तथा इन प्रगतिशील कार्यक्रमों की उपेक्षा व खुलकर विरोध के कारण, ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी को ग्राह्य न हो सके। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की इस सतत् हठधर्मी ने कि कांग्रेस को प्रगतिशील बनाया जा सकता है, पार्टी को असफलता की ओर अग्रसर होने के लिए बाध्य कर दिया। वस्तुस्थिति यह थी कि कांग्रेस नेतृत्व इन प्रगतिशील सिद्धांन्तों और [illegible] को मानने के लिए कदापि भी तत्पर नहीं था, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर कांग्रेस से सम्बन्ध-विच्छेद को तैयार नहीं थी, भले ही उसे अपनी इन प्रगतिशील नीतियों के कार्यान्वियन में बेमेल समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ता। परिणाम स्वाभविक था और वही हुआ भी। कांग्रेस का नेतृत्व दक्षिणपंथी हाथों में बराबर रहा और कांग्रेस समाजवादी [illegible] अपेक्षित परिवर्तन और संशोधन कांग्रेस की नीतियो में न तो होने थे और न हुए ही। जिसके परिणाम-स्वरुप पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा की भावना उत्पन्न हुई। जिन्होंने दक्षिणपंथी नेतृत्व को स्वीकार किया वे कांग्रेस में बने रहे। जिसने उसका विरोध किया वे पार्टी से निकाल दिये गये, और जो ढुलमुल रहे वे या तो पार्टी को छोड़ गये अथवा चुप बैठने को बाध्य हुए। दक्षिण पंथी नेतृत्व ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी को तब तक सहन किया जब तक उसके लिए आवश्यक था। अतः कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस समाजवादी दल के सिद्धांतों व नीतियों में पर्याप्त अन्तर्विरोध था। जिसका बहुत दिनों तक चलना न तो संभव ही था और न स्वाभाविक ही। फलतः कांग्रेस समाजवादी दल की बदनामी हुई जिसके परिणाम स्वरुप न तो उसे कांग्रेस [illegible] मिला और नहीं वह अन्य उभरने वाले वामपंथी दलों की सहमति प्राप्त करने में सफल हो सका। इस तरह सैद्धान्तिक और वैचारिक नीतियों, व्यावसायिक कार्य प्रणालियों में व्याप्त अन्तर्विरोधों के कारण दल की असफलता एवं पतन स्वाभाविक तथा अवश्यंभावी था।

---

23 - वही, पृष्ठ139-40

कां0 स0 पार्टी की असफलता और पतन का कारण निश्चय ही कांग्रेस पार्टी से इसका घनिष्ठ संबन्ध होना था, जिसे पार्टी किसी भी स्थिति में छोड़ने को तैयार नहीं हुई। सन् 1934 से 1947 तक की अवधि (जब तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अस्तित्व रहा) के दौरान कांग्रेस समाजवादी पार्टी की यह कार्यनीति निरन्तर बनी रही कि कांग्रेस पार्टी से उसके संबंध बिगड़े नहीं, भले ही गौण रुप में भी कार्य करने को बाध्य क्यों न होना पड़े। दक्षिणपंथी नेतृत्व के कट्टर पंथी के बावजूद कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस हठधर्मी पर डटी रही कि वह कांग्रेस का अभिन्न अंग है, और कांग्रेस का अभिन्न अंग रहते हुए वह कांग्रेस की नीतियों व कार्यक्रमों में क्रान्तिकारी परिवर्तन व संशोधन की चेष्टा करती रहेगी। जिसकी सफलता सदैव संदिग्ध रही जो सच है। एक ओर कंाग्रेस समाजवादी नेता कांग्रेस को समाजवादी बनाने के लिए जहाँ दृढ़-प्रतिज्ञ थे और इसे भारत में लोकतान्तित्रक व्यवस्था की स्थापना का प्रतीक मानते रहे।[24] वहीं दूसरी ओर गाँधी और दक्षिणपंथी नेतृत्व इस पार्टी की नीतियों के खुल्लम-खुल्ला विरोधी थे। गाँधी और दक्षिण पंथी नेतृत्व ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नीतियों की स्पष्ट आलोचना की और इसका प्रचार भी किया। गाँधी की दृष्टि में, "कांग्रेस के भीतर समाजवादी गुट का निर्माण स्वागत योग्य था लेकिन उसके कार्यक्रम असह्य तथा अस्वीकार्य थे।" गाँधी का यह विचार था कि "समाजवादियों द्वारा प्रचारित वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त हिंसानिष्ठ था और यह कांग्रेस के मौलिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत था।"[25] गाँधी की इस स्पष्ट उक्ति के बावजूद, कांग्रेस समाजवादियों का कांग्रेस मोह ज्यों का त्यों बना रहा।

कांग्रेस समाजवादियों की दृष्टि में कांग्रेस,यद्यपि राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्यधारा थी फिर भी प्रतिक्रियावादियों के प्रभाव का इस पर इतना जोर था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध होने वाले संघर्ष के नेतृत्व में यह सक्षम नहीं थी।निःसन्देह यह भारतीय जन साधारण की राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व करती थी, परन्तु इसके संविधान व कार्यक्रम प्रताड़ित व शोषित जन साधारण के हितों के अनुकूल नहीं थें। इसलिए तात्कालिक आवश्यकता इस बात की थी कि नेतृत्व एवं पार्टी के कार्यक्रमों में आमूल परिवर्तन किये जाय ताकि यह साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के मोर्चे के रुप में कार्य कर सकें। अतः कांग्रेस समाजवादियों ने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि

---

24 - आचार्य नरेन्द्र देव, "सोशलिज्म एण्ड दि नेशनल रिवोल्यूशन, पृष्ठ 115-16.

25 - इण्डियन एनुअल रजिस्टर (कलकत्ता), भाग-2

कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेतृत्व को पार्टी के क्रान्तिकारी तत्वों द्वारा स्थानापन्न किया जाए ।[26] इस उद्देश्य में उन्हें न सफलता मिलती थी न मिली क्योंकि कांग्रेस से बँधे रहना उनका सर्वोच्च लक्ष्य बना रहा । उनकी अपनी स्थिति क्या थी ? उन्होंने कांग्रेस से अलग संगठन क्यों नहीं बनाया ? इन प्रश्नों का उत्तर आचार्य नरेन्द्र देव के शब्दों में-"हमने कांग्रेस से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से हम ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध होने वाले राष्ट्रीय संघर्ष से अलग-थलग पड़ जाते जिसका प्रतीक कांग्रेस थी ।"[27] आचार्य नरेन्द्र देव और जयप्रकाश नारायण की कांग्रेस संबंधी इन भावनात्मक उद्घोषणाओं का अध्ययन करने पर यह तथ्य स्वमेव सिद्ध हो जाता है कि समाजवादी कांग्रेसियों का कांग्रेस से बँधें रहना एक मजबूरी थी, जिससे छुटकारा पाना, उन्होंने न कभी सोचा और न ठीक ही समझा । यह भावनात्मक संबंध सुनियोजित रणकौशल का प्रतीक था अथवा समाजवादी सिद्धांतों के प्रति ढुलमुल नीति का, इस पर विद्वानों में व्यापक मतभेद है । लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेसी समाजवादी, कांग्रेस से इस सीमा तक बँधे रहने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि समाजवाद के शाश्वत मूल्यों की वैज्ञानिकता को भी नकारने के लिए तैयार थे, जिसके कारण उन्हें न तो कभी कांग्रेस के दक्षिपंथी नेतृत्व का विश्वास प्राप्त हो सका और न ही अन्य वामपंथी दल उनकी समाजवादी सिद्धान्तों के प्रति आस्था को स्वीकार कर सके । फलतः कांग्रेस समाजवादी पार्टी की असफलता व पतन निश्चित हो गया । कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो लोग समाजवादी सिद्धान्तों के प्रति सतत् आस्थावान बने रहे, उन्होंने या तो नये वामपंथी दल की स्थापना कर डाली अथवा किसी वामपंथी दल में मिल गये । कांग्रेस और कांग्रेस समाजवादी दल की नीतियों में मौलिक अन्तर्विरोध थे जिनके कारण दोनों दलों की सदस्यता (एक साथ ही) अधिक दिनों तक नहीं चल सकती थी । कांग्रेस पूर्व थी तो समाजवादी कांग्रेस पश्चिम (कम से कम सिद्धांतों और नीतियों की दृष्टि से) जिनमें अवांछनीय मेल की कल्पना मात्र थी अर्थात यथार्थ से अत्यधिक दूर ।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी की असफलता और पतन काफी सीमा तक वामपंथी दलों से उसके संबंधों के कारण भी हुई । दक्षिण पंथी तत्व उसे सन्देह की दृष्टि से देखते थे, तथा वामपंथी दल उसे वैज्ञानिक समाजवाद से अत्याधिक दूर मानते थे । कांग्रेस समाजवादियों की राजनीतिक विचारधाराएँ भी एक नहीं थी । यह कई विचारधाराओं के राजनीतिक मनीषियों की जमघट थी

---

26 - एस0 राय चौधरी-"लेफ्टिस्ट मूवमेंट इन इण्डिया," (1917-47), पृष्ठ 173

27 - नरेन्द्र देव-"सोशलिज्म एण्ड दि नेशनल रिवोल्यूशन," पृष्ठ 4

जिसके कारण सर्वसम्मत निर्णय न तो संभव ही था और न स्वाभाविक ही । कांग्रेस समाजवादी पार्टी में कम से कम तीन प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं के मानने वाले लोग तो थे ही । मार्क्सवादी समाजवादी, फेबियनवादी समाजवाद और उदारवादी समाजवाद के समर्थकों में एकबद्धता के अभाव का बने रहना स्वाभाविक तौर पर अनिवार्य था । वामपंथी दलों से इसके संबंधों की विवेचना यहां आवश्यक है । सुभाष चन्द्र बोस ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के कारणों का विश्लेषण करते हुए लिखा, "कांग्रेस की दक्षिणपंथी नीतियों के प्रतिक्रिया स्वरुप कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना का प्रयास वैध और स्वाभाविक था ।यदि यह प्रतिक्रिया न हुई होती तो कांग्रेस का पतन निश्चित था । कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना सर्वथा न्याय संगत थी, लेकिन इसकी नीतियों में स्पष्टता का अभाव था ।[28] कहना न होगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने सुभाष चन्द्र बोस को पार्टी की सदस्यता प्रदान करने का भरसक प्रयास किया लेकिन बोस इसकी नीतियों से न तो पूर्णरुप से सन्तुष्ट थे और न उन्हें पार्टी द्वारा किसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाये जाने की ही आशा थी । कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर असामयिक तथा अप्रसांगिक प्रभावों पर व्यंग करते हुए बोस पार्टी की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा, "ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी फेबियन समाजवाद से प्रभावित है जो 50 वर्ष पूर्व इंग्लैण्ड में एक फैशन बन गया था ।तब से अब तक टेम्स और गंगा में काफी पानी प्रवाहित हो चुका है ।विश्व के विभिन्न भागों में, प्रथम विश्वयुद्ध के बाद महत्वूपर्ण घटनाएं घटित हो चुकी हैं और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक नये अनुशंधान हो चुके हैं, कोई भी आधुनिक पार्टी यूरोप के 50 वर्ष पूर्व के अनुभवों के आधार पर सफलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती ।"[29] बोस के इस मत से यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को पूर्णत : वह आधुनिक समाजवादी संगठन मानने को तैयार नहीं थे । सम्भवतः इसी कारण इस पार्टी में सम्मिलित न होते हुए भी उन्होंने एक अन्य वामपंथी राजनीतिक पार्टी की स्थापना की जो "फारवर्ड ब्लाक" के नाम से प्रसिद्ध हुई ।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी की प्रकृति के विषय में एक आम वामपंथी धारणा थी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबद्ध लोग इतने दीर्घ काल तक गाँधी के प्रभाव में रहे कि उनसे यह आशा करना व्यर्थ था कि समाजवाद को यथार्थत : अपनी संस्कृति मान लेते । एम0 एन0 राय व

---

28 - सुभाष चन्द्र बोस-" द इण्डियन स्ट्रगल," पृष्ठ 363-64

29 - वही, पृष्ठ 384

उनके अनुयायी इस धारणा के मजबूत स्तम्भ थे कि इस पार्टी द्वारा समाजवादी लड़ाई वास्तविक अर्थों में नहीं लड़ी जा सकती, इस धारणा से सन्तुष्ट होकर उन्होंने यह प्रयत्न करना आरम्भ किया कि यह पार्टी जितनी जल्दी हो सके टूट जाये। कुछ रायवादी पार्टी से निकल गये और कुछ को निकाल दिया गया। जैसे- बी0 एम0 तारकुण्डे का मोहभंग बाद में हुआ, तब उन्होंने स्वयं ही पार्टी सदस्यता का परित्याग कर दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि पार्टी की वामपंथी प्रकृति और अधिक संदग्धि होती गयी।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी के विरूद्ध वामपंथियों का दूसरा गंभीर आरोप यह था कि इस पार्टी का निर्माण कांग्रेस पार्टी व बुर्जुआजी के मध्य हुए गुप्त समझौते का परिणाम था ताकि जन साधारण को धोखे में रखा जा सके और उसके द्वारा किये जाने वाले संघर्ष में व्यवधान उत्पन्न किया जा सके।[30] इस आलोचना पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का नेतृत्व बहुत ही तिलमिलाया और उसके शीर्ष नेताओं जैसे-आचार्य नरेन्द्र देव ने इस आलोचना एवं आरोप को बेबुनियाद बतलाया तथा मूर्खतापूर्ण माना। उन्होंने यह घोषणा की कि यह आरोप बेबुनियाद है और इतना मूर्खतापूर्ण है कि इस पर गंभीरता पूर्वक सोचने की भी आवश्यकता नहीं है।[31] काफी संभव है कि यह आरोप बेबुनियाद हो, लेकिन इसमें दम दिखाई देता है। कांग्रेस समाजवादी दल का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि अपनी नीतियों को कांग्रेस द्वारा पूर्णरुपेण अस्वीकार किये जाने तथा आलोचना के बावजूद उसके अधिकांश नेताओं का मोहभंग नहीं हुआ। वे कांग्रेस द्वारा किये गये इस दुर्व्यवहार को शालीनता पूर्वक स्वीकार करतें रहे। इसका तात्पर्य हालांकि यह नहीं निकालना चाहिए कि इस पार्टी के सारे लोग कूटनीति के समर्थक व पक्षधर थे लेकिन इसके विपरीत निष्कर्ष निकाला भी जैसा कि आचार्य नरेन्द्र देव का अभिमत था, जिसे युक्ति संगत एवं आधिकारिक नहीं माना जा सकता। पार्टी में कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थकों के प्रेवश के सन्दर्भ में आचार्य नरेन्द्र देव ने जो आशंका व्यक्त की उसे निष्पक्ष आशंका नहीं कहा जा सकता। उनकी दृष्टि में, कम्युनिस्ट लोग पार्टी में समाजवादी एकता के उद्देश्य से प्रेवश लेने के लिए आतुर नहीं थें। बल्कि वे उन क्षेत्रों में अपने प्रभाव जमाने के लिए आतुर थे जिनका प्रभाव नगण्य था। उनके प्रवेश का विरोध करते हुए उन्होंने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक ही साथ, दो दलों की नीतियों के प्रति आस्थावान बने रहना असम्भव है। वैचारिक अन्तरों से पार्टी का

---

30 - एस0 राय चौधरी -"लेफ्टिस्ट मूवमेंट इन इण्डिया" (1917-47), पृष्ठ 171

31 - नरेन्द्र देव-"सोशलिज्म एण्ड दि नेशनल रिवोल्यूशन" पृष्ठ 66

विकास होता है लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं हो सकता कि हम ऐसे लोगों को पार्टी में प्रवेश दें, जो प्रत्यक्षत : किसी अन्य दल से निर्देशन ग्रहण करते हों ।[32] नरेन्द्र देव के इस मत में निहित सच्चाई स्वत : स्पष्ट है कि कांग्रेस व कांग्रेस समाजवादी दल की नतियों में मौलिक अन्तर्विरोध के बावजूद एक सूत्र में बने रहना संभव था जबकि दूसरे दलों का समर्थन प्राप्त होना फिर संभव नहीं हो सकता था । येन-केन प्रकारेण कांग्रेस पार्टी से अपने को आबद्ध रखना कांग्रेस समाजवादी पार्टी की यही नीति थी (जो स्पष्ट भी है) तो उपर्युक्त आरोप को आसानी से काट पाना उसके लिए मुश्किल था, भले ही उसकी चेष्टा भरपूर हुई हो । कांग्रेस समाजवादी पार्टी के आदर्श की घोषणा करते हुए नरेन्द्र देव ने कहा था, "कांग्रेस समाजवादियों का आदर्श है कि भारत में एक वर्गहीन समाज की स्थापना हो, जहाँ शोषण, बेरोजगारी और भुखमरी की समस्याओं का सर्वथा अभाव हो ।" यदि वास्तव में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का यही आदर्श था तो [illegible] आर्युक्त मत को युक्ति संगत नहीं माना जा सकता, और यदि पार्टी का उद्देश्य इस लक्ष्य [illegible] क्त कुछ और था तो आरोप फिर बेबुनियाद नहीं माना जा सकता । तत्कालीन कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अधिकाशं नेता सन् 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध रहे और कांग्रेस शासन के अधीन उपर्युक्त समस्याओं का समाधान कितना हुआ यह सर्व विदित है । कांग्रेस समाजवादी दल के नेता इससे मुक्त नहीं कहे जा सकते ।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी की दोहरी, भ्रामक व अन्तर्विरोधी नीतियों का प्रमाण उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं से प्राप्त होता है ।जिनमें से दो का उल्लेख इस बात की पुष्टि करता है । सन् 1939 ई0 में त्रिपुरा अधिवेशन के दौरान सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के समस्त वामपंथी तत्वों के मेल के सिद्धान्त को समाजवादी नेतृत्व ने अपना सहयोग प्रदान नहीं किया जो इसकी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रतीत होता था । सुभाष चन्द्र बोस ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की इस डगमगाहट को विश्वासघात घोषित किया [illegible] यह मत व्यक्त किया कि वह पार्टी कांग्रेस के सम्पूर्ण नेतृत्व और अनुशासन से इतनी अधिक आबद्ध थी कि वह अपनी पूर्व निर्धारित नीतियों का खुलेआम उल्लंघन सहने को भी तैयार थी ।[33] इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि पार्टी ने सुभाष चन्द्र बोस को अपना सहयोग प्रदान किया होता तो इनकी नीतियों का काफी हद तक लागू होना सम्भव था । पार्टी के इस रवैये से क्या अभीष्ट था, यह स्पष्ट नहीं

32 - आचार्य नरेन्द्र देव- "सोशलिज्म एण्ड दि नेशालन रिवोल्यूशन", पृष्ठ 109

33 - सुभाष चन्द्र बोस-"क्रास रोडस" पृष्ठ 113

होता और उसकी ढुलमुल नीति साफ परिलक्षित होती है। इसी तरह द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान युद्ध में भारतीय सहभागिता का पार्टी ने डटकर विरोध किया और यह घोषणा की कि भारत को इस युद्ध में किसी भी रुप में भाग नहीं लेना चाहिए। जे0 पी0 ने पार्टी के इस रुख को सन् 1940 में इन शब्दों में व्यक्त किया," भारत इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता क्योंकि जर्मन नाजीवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद दोनों ही अपने-अपने स्वार्थों से आबद्ध है ताकि विजय व आधिपत्य के माध्यम से शोषण और उत्पीड़न कर सके। ग्रेट ब्रिटेन नाजीवाद की समाप्ति के लिए नहीं लड़ रहा, क्योंकि इसी की देखरेख में उसका उत्थान हुआ। बल्कि इस लिए लड़ रहा है ताकि इन दोनों की होड़ में वह अपना सर्वोच्च स्थान कायम रख सके और साम्प्रज्य की शक्ति तथा कीर्ति को सुरक्षित रख सके। भारतीय साम्राज्य को बनाये रखना उसका प्रथम उद्देश्य है।[34] आचार्य ने भी इस कथन की पुष्टि की।[35] युद्ध में भारतीय सहभागिता के इस तीखे विरोध का हस्र यह हुआ कि पहले तो बिना किसी शर्त के वे (कांग्रेस समाजवादी) इसके विरोध में थे लेकिन बाद में सशर्त सहभागिता को अपनी सहमति प्रदान कर दी।[36] सम्भवत : पार्टी के रुख में इस बदलाव का कारण यही था कि उसके लिए कांग्रेस का तत्कालीन नेतृत्व व एकता सर्वोच्च थी, जिसके लिए वे अपनी स्वनिर्धारित नीतियों को भी ताक पर रखने के लिए कृत संकल्प थे। भारतीय जन साधारण के समक्ष उसके इस दोहरे चरित्र का पर्दाफाश होना स्वाभाविक था, और जो हुआ भी, अत : इसके प्रति जन साधारण में उदासीनता घर करती गयी और अन्ततः पार्टी का पतन सुनिश्चित हो गया।

2- समाजवादी पार्टी (कांग्रेस के बाहर)

कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कानपुर अधिवेशन में यह निश्चय किया गया कि "कांग्रेस" को पार्टी के नाम से हटा दिया जाय। इस निश्चय के परिणाम स्वरुप समाजवादी पार्टी एक स्वतन्त्र पार्टी के रुप में संगठित करने की पृष्ठभूमि तैयार हो गयी। समाजवादी पाटी के नासिक अधिवेशन से पूर्व महात्मा गाँधी के शहीद हो जाने के बाद कांग्रेस में सरदार बल्लभ भाई पटेल का वर्चस्व स्थापित हो गया। कांग्रेस के संविधान संशोधन के बाद समाजवादी पार्टी के सामने कोई विकल्प नहीं रह गया और पाटी को कांग्रेस से बाहर आने पर मजबूर होना पड़ा।

---

34 - जय प्रकाश नारायण-"टुअईस स्ट्रगल" पृष्ठ 203

35 - नरेन्द्र देव-"सोशलिज्म एण्ड नेशनल रिवोल्यूशन," पृष्ठ 144

36 - एस0 राय चौधरी-"लेफ्टिस्ट मूवमेंट इन इण्डिया," (1917-47), पृष्ठ 175-76

समाजवादी पार्टी का नासिक सम्मेलन आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में 1948 में हुआ उसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से बाहर निकाले जाने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नाम से "कांग्रेस" शब्द हटा दिया जाये और पार्टी में गैर कांग्रेसी सदस्यों को शामिल करने पर कोई रोक न रखी जाये। उनका कहना था कि ऐसा करने के बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस में बनी रह सकेगी। हमने उनके सुझाव के अनुरुप समाजवादी पार्टी के नाम से "कांग्रेस" शब्द हटा दिया। अब ऐसी स्थिति है कि हमें कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है। यह हमारे लिए सुखद नहीं है। मैं 30 वर्षो से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं इस पुराने सम्बन्धों को छोड़ रहा हूँ राजनीति अजीब है, इसमें मित्र शत्रु बन जाते है।[37]

नासिक सम्मेलन के निर्णय के अनुसार आचार्य नरेन्द्र देव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधान सभा से 12 समाजवादी विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया। बाद में उपचुनाव में केवल एक समाजवादी जीता है। आचार्य नरेन्द्र देव भी पराजित हो गये। उनके विरुद्ध चुनाव प्रचार में पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त ने यह आरोप लगाया कि यदि समाजवादी जीत गये तो भारतीय संस्कृति नष्ट हो जायेगी। कांग्रेसी प्रत्यासी बाबा राघवदास को रामभक्त बताकर धार्मिक और साम्प्रदायिक भावनाओं को उकसाया गया था। कांग्रेस उस समय केन्द्र और राज्यों में सत्ता में थी। बम्बई कारपोरेशन के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 26 सदस्य चुने गये। उस समय उसमें कुल 49 स्थान थे। इसके बाद श्री युसूफ अली मेहर भी चुने गये।

समाजवादी पार्टी के नासिक सम्मेलन में पार्टी के स्वरुप, संगठन और उसकी रीति-नति के सम्बन्ध में विचार किया गया था। किसानों, मजदूरों, छात्रों और युवा लोगों को संगठित करने पर विचार किया गया। पार्टी की वैदेशिक नीति को स्थिर करने के लिए डा0 राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में एक समिति गठित हो गयी थी।

समाजवादी पार्टी का 1949 में पटना में अधिवेशन हुआ। उसमें पार्टी की नीति निर्धारित करने के लिए जो वक्तव्य तैयार किया गया था उसमें कहा गया था कि परिस्थितियों के अनुसार सत्ता पर अधिकार करने के लिए शान्तिपूर्ण अथवा सशस्त्र क्रान्ति के मार्ग को अपनाया जा सकता है। उस समय समाजवादियों की धारणा थी कि सत्ता पर अधिकार सशस्त्र संघर्ष और

---

37 - 1948 में नासिक अधिवेशन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्षीय भाषण के कुछ अंश

लोकतान्त्रिक दोनों तरीकों से किया जा सकता है । लोकतान्तित्रक तरीकों में संसदीय और गैर संसदीय दोनों कार्य शामिल हैं । इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के रुप में कहा गया कि लोकतान्त्रिक तरीके उसी स्थिति में अपनाये जा सकते हैं जब देंश में लोकतान्त्रिक पद्धति का पूर्ण रुप से प्रयोग हो और जब मजदूर, किसान और निम्न मध्यम श्रेणी के लोगों को राजनीतिक दृष्टि से ठीक से संगठित किया गया हो और उनको अपने वर्ग स्वार्थों के आधार पर राजनीतिक दल के रुप में संगठित किया गया हो ।[38]

समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जुलाई 1947 में ट्रेड यूनियनों को कम्युनिस्टों और कांग्रेस के प्रभाव से मुक्त रखकर संगठित करने पर जोर दिया गया थ।अशोक मेहता को ट्रेड यूनियन क्षेत्र में पार्टी के काम काज की देखभाल करने का अधिकार दिया गया था। उन्होंने मजदूरों को इस प्रकार संगठित करने पर जोर दिया जिसके आधार पर समाजवादी पार्टी को सुदृढ़ बनाया जा सके । समाजवादी पार्टी को लोकतान्त्रिक प्रणाली के आधार पर देश की सामजिक व्यवस्था की पुनर्रचना का प्रयास करना चाहिए । इसी सिद्धांत के आधार पर हिन्द मजदूर सभा संगठित की गयी । श्री रुइकर ने उसमें सहयोग किया । बाद में इण्डियन फेडरेशन आफ लेबर के विघटित होने पर सर्व श्री बी0 बी0 कर्णिक और श्रीमति मणिबेन राय ने हिन्द मजदूर सभा के साथ सहयोग किया । 1947 से 1949 तक जे0 पी0 रेलवे मेन्स फेडरेशन, डाकतार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे । एस0 एम0 जोशी रक्षा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे । उन दिनों समाजवादियों ने दिल्ली, बम्बई, कानपुर तथा बिहार के अनेक क्षेत्रों में मजदूर संघर्ष चलाये। 1949 में डाकतार और रेल कर्मचारियों की हड़ताल की नोटिश दी गयी ।लेकिन बाद में जय प्रकाश नारायण ने उन्हे वापस ले लिया । कहा जाता है कि कम्युनिस्टों की अतिवादी नीति के कारण उनसे बचने के लिए जे0 पी0 ने ऐसा किया था ।

समाजवादी पार्टी के नासिक सम्मेलन में किसानों को संगठित करने के लिए एक उपसमिति बनायी गयी थी । किसान सभा पर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था। । 1947-1949 तक समाजवादी पार्टी की ओर से किसानों की मांगों के लिए अनेक संघर्ष पूर्ण आन्दोलन किये गये । उत्त प्रदेश, विन्धय प्रदेश में किसानों पर अत्याचारों और उनकी बेदखली के विरुद्ध आन्दोलन में जब जमींदारों की ओर से हिंसापूर्ण दमन का सहारा लिया गया तो पार्टी की ओर से जवाबी हिंसा

---

38 - "समाजवादी पार्टी का नीति वक्तव्य-" 1951 बम्बई

और हिंसा के प्रयोग की धमकी दी गयी । 30 नवंबर 1949 को लखनऊ विधान सभा के समक्ष एकलाख किसानों का प्रदर्शन किया गया । 3 जून 1951 में दिल्ली में समाजवादी पार्टी की ओर से विशाल प्रदर्शन किया गया ।

कांग्रेस सरकारों द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का सिलसिला 1948 से शुरु होकर 1951-52 तक चलता रहा । जमींदारी उन्मूलन के बाद समाजवादी पार्टी का किसान क्षेत्र में प्रभाव घटने लगा । गन्ना किसानों की मांगों के लिए गेंदा सिंह ने उत्तर प्रदेश में कई आन्दोलन चलाये । लेकिन बाद में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों अर्थात् बड़े और मध्यम किसानों के विरोध के डर से समजावादी पार्टी ने खेतिहर मजदूर और भूमिहीन किसानों को संगठित करने का प्रयास नहीं किया जो समाजवादी सिद्धांत के अनुसार एक अनिवार्य आवश्यकता थी ।

समाजवादी पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य करने के उद्देश्य से फरवरी 1951 में बिहार के 'देकुली' में ग्रामीण रचनात्मक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया । उस समय समाजवादी पार्टी ने श्रमदान और "एक घंटे देश को दो" का अभियान चलाया ।

अगस्त क्रान्ति के प्रभाव के कारण 1944 में "स्टूडेण्ट्स कांग्रेस" नामक संस्था गठित की गयी थी ।उसमें समाजवादियों का प्रभाव अधिक था ।उस समय "स्टूडेण्ट्स फेडरेशन" कम्युनिस्टों के प्रभाव में था । स्टूडेण्ट्स कांग्रेस का सम्मेलन हैदराबाद में हुआ, और कांग्रेस तथा समाजवादियों के पारस्परिक विरोध के कारण वह छिन्न-भिन्न हो गयी । 1950 में ब्रिटेन की भाँति भारत में नेशनल यूनियन आफ स्टूडेण्ट्स संगठित की गयी । इस संगठन को राजनीति से अलग रखने का प्रयास किया गया ।बाद में सत्ता के प्रभाव के कारण इस संगठन पर कांग्रेस का ही प्रभाव हो गया ।

1950 में समाजवादी युवजन सभा अथवा सोशलिस्ट यूथ लीग की स्थापना की गयी । इसको देश के अनेक प्रदेशों में संगठित किया गया ।महाराष्ट्र में राष्ट्र सेवा दल नामक युवाओं का संगठन समाजवादी पार्टी के प्रभाव में काम कर रहा था ।

1949 में पटना में समाजवादी पार्टी का सम्मेलन आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में हुआ। जय प्रकाश नारायण ने संगठन की रिपोर्ट प्रस्तुत की । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को नये आधार पर जन संगठन के रुप संगठित किया जाना चाहिए ।

आचार्य नरेन्द्र देव ने यह सुझाव दिया कि पार्टी में ट्रेड यूनियन, किसान पंचायत, समाजवादी यूथ लीग तथा सहकारी संस्थाओं को सम्बद्ध करके उनकों पार्टी में प्रतिनिधित्व देना चाहिए ।

रामचन्द्रन मिश्र और श्रीमती अरुणा आसफ अली ने समाजवादी पार्टी को सक्रिय क्रान्तिकारियों की पार्टी बनाने पर जोर दिया और यह विवाद काफी लम्बा चला । अन्ततः आचार्य नरेन्द्र देव के आग्रह से सम्मेलन में समाजवादी पार्टी को खुले जन संगठन के रुप में गठित करने के लिए जय प्रकाश नारायण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया । इस विवाद में मार्क्सवाद की सैद्धान्तिक बहस उठी और कहा गया कि संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर उसकी समर्थक बनकर रहती है ।दूसरी ओर से कहा गया कि लेनिन की बाल्शेविक पार्टी भी संसदीय पद्धति का अनुसरण करती थी । अतः समाजवादी पार्टी को अपने लक्ष्य और सिद्धान्त के अनुरुप समाज की रचना के लिए प्रत्येक क्षेत्र में काम करके अपना प्रभाव बढ़ाना चाहिए । जय प्रकाश नारायण ने उस समय यह दावा किया था कि उनका प्रस्ताव पूर्ण रुप से मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुरुप है ।

"लोकतान्त्रिक समाजवाद" नामक पुस्तक में जय प्रकाश नारायण ने इस संबंध में कहा था कि भारत में इस समय केवल लोकतान्त्रिक उपाय ही सबसे अधिक उपर्युक्त है । यदि देश में लोकतान्त्रिक आचार-व्यवहार का विकास होता है तो भारत में समाजवाद की स्थापना के अन्तिम दौर में भी लोकतान्त्रिक ढंक को अपनाना उचित होगा ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उस समय तक कांग्रेस में सरदार पटेल का प्रभाव अधिक था। केन्द्रीय सरकार में पूँजीवादी तत्व, सामन्तवादी प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में, सरकारी तन्त्र में अपसर साही के प्रभाव के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में पूँजीवादी सामन्ती व्यवस्था ही चल रहीं थी ।राष्ट्रीय अहमान्यता और साम्प्रदायकिता के प्रभाव के कारण फासिस्टवादी प्रवृत्तियाँ प्रकट हो रही थीं ।

1950 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में सरदार पटेल ने राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन को अपना प्रत्याशी बनाया था । पं0 जवाहर लाल नेहरु ने आचार्य जे0 बी0 कृपलानी को अपना प्रत्याशी बनाया जो चुनाव में पराजित हो गयें ।कांग्रेस के भीतर "डेमोक्रेटिक फ्रन्ट" नाम से एक सम्मेलन दिल्ली में किया गया, जिसमें पं0 जवाहर लाल नेहरु, मौलाना अबूल कलाम आजाद और पश्चिम बंगाल के प्रफूल्ल चन्द्र घोष आदि ने हिस्सा लिया । बाद में जून 1951 में

पटना में एक सम्मेलन के बाद आचार्य जे0 बी0 कृपलानी ने "किसान मजदूर प्रजा पार्टी" संगठित की । रफी अहमद किदवई भी उस सम्मेलन में शामिल हुए थे । बाद में उन्होंने उससे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया ।

1951 के आरम्भ में सरदार बल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद कांग्रेस में आन्तरिक संकट उत्पन्न हो गया। पं0 जवाहर लाल नेहरु ने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन द्वारा गठित कार्य समिति में रहने से इन्कार कर दिया । कांग्रेस महासमिति के बंगलौर अधिवेशन में एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो गयी । उसके बाद राजर्षि टण्डन ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और पं0 जवाहर लाल नेहरु को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया ।[39] वे 1955 तक कांग्रेस के अध्यक्ष और देश के प्रधान मंत्री थे तथा राष्ट्रीय नेतृत्व उनके हाथ में आ गया था ।1952 के आम चुनाव के समय पं0 जवाहर लाल नेहरु का एक छत्र प्रभाव था ।

समाजवादी पार्टी का आठवाँ सम्मेलन मद्रास में हुआ । सन् 1950 में पार्टी की सदस्य संख्या एक लाख उन्तीस हजार चार सौ सैंतालीस थी । हिन्द मजदूर सभा की सदस्य संख्या सात लाख थी और उससे पार्टी में 19,146 प्रतिनिधि थे ।किसान पंचायत की सदस्य संख्या पाँच लाख थी । और उससे संबंधित 339 पार्टी सदस्य प्रतिनिधि थे । छात्र और युवा संगठन उस समय उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे ।

समाजवादी पार्टी के 1950 के मद्रास सम्मेलन में इस बात की पुनः स्पष्ट रुप से घोषणा की गयी कि समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिक आधार और व्यवहार के लिए पूरी तौर से प्रतिबद्ध है और उसकी आस्था है कि भारत में सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन लोकतान्त्रिक तरीकों से सम्भव है । इस कार्यपद्धति को पूर्णतः मार्क्सवादी कहा गया था ।मद्रास सम्मेलन में डा0 राम मनोहर लोहिया ने जय प्रकाश नारायण के कार्य पद्धति की कटु आलोचना की थी ।जिससे खीझकर जय प्रकाश नारायण पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पद को छोड़ने के लिए तत्पर हो गये थे ।

कलकत्ता में एशियन यूथ्स और कम्युनिष्ट पार्टी ने फरवरी 1948 में अति उग्रवादी नीति अपनायी थी । पूर्ण चन्द्र जोशी के स्थान पर वी0 टी0 रणदिवे कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी चुने गये थे।उस समय अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट नेता जेडे नोव की थीसिस के अनुसार नव

39 - चन्द्रोदय दीक्षित-" भारतीय समाजवादी आन्दोलन", पृष्ठ 99

स्वतंत्र पूँजीवादी देशों में मजदूर-किसान आदि के सहयोग से क्रान्ति का प्रयास किया जाना चाहिए। इस नीति के कारण 1948 से 1950 तक तेलंगाना में कम्युनिस्टों ने किसान विद्रोह चलाने का प्रयास किया। इसके प्रतिउत्तर में आचार्य विनोबा भावे ने अपना सर्वोदय आन्दोलन और भूदान के लिए देश भर की पद यात्रा का अभियान चलाया जिसे सत्ता रुढ कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला और भूदान का व्यवहारिक रुप देने के लिए भूमि कानूनों में भी संशोधन किये गये।

समाजवादी पार्टी के नासिक सम्मेलन में डा0 राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में एक वैदेशिक समिति बनायी गयी थी। उन्होंने उस समय गुट-निरपेक्ष राजनीति का समर्थन किया था। उन्होंने अनेक देशों का दौरा कर सभी एशियाई देशों के समाजवादियों को एशियाई सोशलिस्ट कान्फ्रेन्स के रुप में संगठित करने का प्रयास किया। 1953 में रंगून में एशियाई सोशलिस्ट सम्मेलन भी किया गया था। उस समय डा0 लोहिया का कहना था कि एक विश्व सरकार की स्थापना तभी सम्भव होगी जब विभिन्न देशों की जनता को आर्थिक बराबरी का दर्जा मिले। सभी देशों के निवासियों के मौलिक अधिकारों और अवसर की समानता के आधार पर शोषण मुक्त समाज संगठित किया जा सकता है। संसार के उत्पीड़ित और शोषित लोग ऐसे समाज की स्थापना के लिए लालायित हैं।

समाजवादी पार्टी ने 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस से बाहर आने के बाद पहली बार हिस्सा लिया। ज्ञात है कि भारतीय संविधान 1950 से लागू हो गया था। 3 जून 1947 के पूर्व समाजवादियों ने संविधान सभा में इसलिए हिस्सा नहीं लिया क्योंकि संविधान सभा को सार्वभौमता प्राप्त नहीं थी। और भारत में अंग्रेजी शासन और फौजें बरकरार थी। 3 जून 1947 के बाद जय प्रकाश नारायण ने पं0 जवाहर लाल नेहरु को सूचित किया कि समाजवादी संविधान सभा में अब भाग ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी समाजवादियों ने अपने पारस्परिक मतभेद के कारण संविधान सभा में नहीं पहुँच सके। संविधान सभा में केवल तीन समाजवादी शामिल हुए थे। उत्तरप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते दामोदर स्वरुप सेठ संविधान सभा के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त दो अन्य सदस्य थे, उनमें उड़ीसा के शारंग दास और उत्वा के हरेश्वर गोस्वामी शामिल थे। बाद में समाजवादी सदस्यों को यह आदेश दिया गया कि वे लोग संविधान पर अपने हस्ताक्षर न करें।

नये संविधान के अनुसार संसद और विधान मण्डलों के लिए चुनाव की तैयारियाँ 1951 से शुरु हो गयी थी। उस समय देश में सत्तारुढ़ कांग्रेस के अतिरिक्त समाजवादी पार्टी, किसान, मजदूर प्रजा पार्टी एवं जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त छोटी बड़ी अनेक पार्टियाँ थी। समाजवादी पार्टी के नेतागण विशेष रुप से जे0 पी0, आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 लोहिया, अच्युत पटवर्धन, युसूफ मेहर अली, अशोक मेहता, एस0 एम0 जोशी तथा एन0 जी0 गोरे आदि राष्ट्रीय आन्दोलन के राष्ट्रीय नेताओं में गिने जाते थे।समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विकल्प की दावेदार थी। इस दृष्टि से प्रथम आम चुनाव में उसका भाग लेना अत्यन्त महत्वपूर्ण था। कांग्रेस के भीतर समाजवादी प्रभाव के कारण उसमें वामपंथी झुकाव हो जाता था और जनता में क्रान्तिकारी छवि बनाने में भी सहायक थे। लेकिन कांग्रेस संगठन पर पुराने दक्षिणपंथी नेताओं का प्रभाव था। जो 1947 से 1950 तक सरदार बल्लभ भाई पटेल की छत्रछाया में काम करते थे। बाद में उन्होंने पं0 जवाहर लाल नेहरु के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। 1947 से 1950 तक कांग्रेस ने संसदीय लोकतंत्र को स्थापित करने के लक्ष्य को अपनाया जिसे पूँजीवादी लोकतन्त्र भी कहा जाता है। बाद में पं0 जवाहर लाल नेहरु ने सहकारी सामाजिक व्यवस्था (कोआपरेटिव कामन वेल्थ) की चर्चा की। 1952 के आम चुनाव में जनता में वामपंथी प्रवृत्ति को देखकर उन्होंने 1955 में समाजवादी सामाजिक ढांचे की चर्चा कराना शुरु कर दिया था। संसद में भी एक प्रस्ताव पासकर समाजवाद के लक्ष्य को स्वीकार किया गया और बहुत बाद में तो संविधान की प्रस्तावना में भी "समाजवाद" को रखा गया।

पाकिस्तान की स्थापना और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत के बाद देश के राजनीतिक सन्तुलन में मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा जैसी संस्थाओं की स्थिति नगण्य हो गयी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने 1950 के बाद अपनी अतिवादी नीति छोड़ी थी।उसका प्रभाव मद्रास, हैदराबाद और पश्चिम बंगाल में ही सीमित था। समाजवादी पार्टी का प्रभाव अखिल भारतीय स्तर पर सार्वजनिक प्रदर्शनों और आन्दोलनों में स्पष्ट रुप से दिखाई देता था। परन्तु चुनाव में इनकी सफलता बड़ी ही सीमित रही। इसके 12 प्रत्याशी ही चुनाव जीत सके और मत भी 10.6 प्रतिशत ही ये प्राप्त कर सके।

3. प्रजा समाजवादी पार्टी का उदय और विकास

1952 में समाजवादी पार्टी का सम्मेलन पंचमढ़ी में डा0 राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में हुआ। उस सम्मेलन में डा0 राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी पार्टी की नीतियों का निरुपण करने का प्रयास किया। उनका आग्रह था कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से समान दूरी रखनी चाहिए। और उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। अशोक मेहता समाजवादी आन्दोलन के प्रमुख अर्थशास्त्री माने जाते थे। वे समाजवादी पार्टी द्वारा संसदीय लोकतन्त्र में हिस्सा लेने पर जोर देते थे। उनका कहना था कि देश के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण समाजवादी पार्टी को सत्ता रुढ़ कांग्रेस दल के साथ सहयोग करने के क्षेत्रों को ढूढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जे0 पी0 का मार्क्सवाद के प्रति मोहभंग हो गया था और वे गाँधीवाद के प्रभाव में अधिक आ रहे थे। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आन्दोलन में अधिक रुचि ली और बाद में भूदान और सर्वोदय आन्दोलन में पूरी तौर से जुटकर काम करने के लिए उन्होंने भूदान आन्दोलन के गया अधिवेशन में जीवनदान की घोषणा कर दी।

समाजवादी पार्टी में उच्च आदर्शों से प्रेरित भारतीय नेताओं की कमी नहीं थी, लेकिन पार्टी का संगठन और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। 1952 के आम चुनाव में पार्टी की विफलता का यही कारण था। लन्दन से प्रकाशित "दि टाइम्स" ने समाजवादी पार्टी की विफलता पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि भारत में शक्तिशाली दल को अधिक शक्ति मिलती है। पंचमढ़ी सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के सिद्धांत निरुपित करने का प्रयास किया गया। समाजवादी पार्टी को लोकतान्त्रिक और प्रगतिशील विपक्ष की भूमिका का भी निर्वाह करना था उस सम्मेलन में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से अलग रहते हुए देश में छोटे उद्योगों की तकनीकि विकसित करने और समजावाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा के उपायों का परित्याग करने पर जोर दिया गया। जे0 पी0 ने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुरुप साध्य-साधन दोनों के पवित्र रखने पर जोर दिया। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी को केवल वामपंथी शक्तियों को एकत्र करने का ही प्रयास नहीं करना चाहिए वरन् सभी लोकतान्त्रिक वामपंथी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहिए। उन्होंने परिगणित जाति संघ (अम्बेडकरवादी), क्षारखण्ड पार्टी और किसान मजदूर पार्टी का सहयोग लेने का सुझाव दिया।

1 जून 1952 को संसद में श्रीमती सुचेता कृपलानी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और किसान-मजदूर प्रजा पार्टी का संयुक्त गुट "समाजवादी प्रजा गुट"के नाम से गठित किया गया।

उस गुट के लिए न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार किया गया जिसमें न्याय संगत सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण, बड़े उधोगों का राष्ट्रीयकरण, स्वतन्त्र मजदूर संघों की स्थापना, नागरिक अधिकारों की रक्षा, त्यागपूर्ण जीवन, स्वदेशी की भावना, बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों के गुटों से अलग रहना (गुट-निरपेक्षता), सेना में कमी, राष्ट्रीय सेना (मिलेशिया) के गठन की बातें शामिल थी। बाद में इस गुट के आधार पर समाजवादी पार्टी और किसान-मजदूर प्रजा पार्टी का विलय करके प्रजा समाजवादी पार्टी की स्थापना की गयी। आचार्य कृपलानी ने सितम्बर 1952 में समाजवादी दल और किसान-मजदूर प्रजा पार्टी को मिलाकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने एक 14 सूत्रीय समाजवादी कार्यक्रम निर्मित किया लेकिन नेहरु जी ने इस कार्यक्रम को स्वीकार नहीं किया, फलस्वरुप इस दल के साथ कांग्रेस की न बन सकी।[40] और प्रजा समाजवादी पार्टी भी नेहरु के समाजवाद को छल प्रपंच की संज्ञा देते रहे।[41]

मद्रास में किसान-मजदूर प्रजा पार्टी वहाँ के गैर कांग्रेसी लोकतान्त्रिक मोर्चे में शामिल थी। जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। टी0 प्रकाशम उस मोर्चे के नेता थे, और उसमें समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त सभी विपक्षी दल शामिल थे। समाजवादी पार्टी उसमें इसलिए शामिल नहीं हुई क्योंकि उसमें कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी। उस समय मद्रास विधान सभा में समाजवादी गुट के 13 सदस्य थे और उनके नेता डा0 के0 वी0 मेनन थे। मद्रास विधान सभा में 1952 के आम चुनाव में 375 सदस्य थे, जिनमें से कम्युनिस्ट पार्टी के 62, किसान मजदूर प्रजा पार्टी के 35, अन्य दलों के 61 तथा निर्दलीय 62 सदस्य थे। मद्रास की किसान-मजदूर प्रजापार्टी का सुझाव था कि समाजवादी पार्टी भी लोकतान्त्रिक मोर्चे में शामिल हो, लेकिन जय प्रकाश नारायण और अशोक मेहता ने इसका विरोध किया। अन्त में मद्रास के किसान-मजदूर प्रजा पार्टी के विधायकों को लोकतान्त्रिक मोर्चे में शामिल रहने की छूट दी गयी और समाजवादी विधायकों को अपना गुट अलग रखने की आजादी दी गयी।

समाजवादी पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय की आरम्भिक वार्ता उस समय हुई थी जब पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव एक प्रतिनिधि मण्डलन में चीन गये हुए थे। लौटने पर जब विलय वार्ता सुनी तो वे इस बात से दुःखी हुए कि समाजवादी पार्टी के

---

40 - हरि किशोर सिंह-" ए हिस्ट्री आफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी," पृष्ठ-180-82

41 - डा0 शोभा शंकर "आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन", पृष्ठ 55

विलय समर्थक नेताओं ने इतनी जल्दबाजी से काम लिया । बाद में उन्होंने विलय का समर्थन किया । प्रो0 मुकुट बिहारी लाल और श्रीमती शीला परेटा ने विलय की आलोचना करते इसे अवसरवादी और अलोकतान्त्रिक बताया क्योंकि इस संबंध में नेताओं ने ऊपरी तौर से निर्णय लिया था और दोनों दलों के साधारण सदस्यों की राय जानने का प्रयास ही नहीं किया गया था।

24-25 अगस्त 1952 को लखनऊ में किसान-मजदूर प्रजा पार्टी की ओर से आचार्य जे0 बी0 कृपलानी और समाजवादी पार्टी की ओर से आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता ने बातचीत की और दोनों दलों के विलय और प्रजा समाजवादी पार्टी के गठन का समझौता किया । इसके बाद इस विलय की पुष्टि के लिए बम्बई में सम्मेलन किया गया । यह भी निश्चय किया गया कि समाजवादी पार्टी का विधान नयी पार्टी का विधान मान लिया गया । आचार्य नरेन्द्र देव ने विलय के सम्बन्ध में अपने वक्तव्य में कहा कि गैर साम्प्रदायिक और गैर कम्युनिस्ट गुटों की एकता की ओर यह विलय पहला कदम है । अशोक मेहता ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्र में यह नवजीवन की आधार शिला बन सकती है जिसके आधार पर कांग्रेस का विकल्प तैयार हो सकता है।

प्रजा समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय आचार्य जे0 बी0 कृपलानी अध्यक्ष , डा0 राम मनोहर लोहिया जनरल सेक्रेटरी, सर्वश्री अशोक मेहता, मधु लिमये और सादिक अली ज्वाइन्ट सेक्रेटरी बनाये गये । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों में सर्वश्री आचार्य नरेन्द्र देव, जय प्रकाश नारायण, हरेश्वर गोस्वामी, के0 के0 मेनन, एम0 जी0 गोरे, पी0 सी0 घोष, बालेश्वर दयाल, चेन्नादुराई, के0 आर0 कारन्थ, श्रीमती लीला राय, पट्टम थानु पिल्लई, प्रेम भसीन, तथा पी0 बी0 राजू आदि । इस पार्टी की सदस्य संख्या 2 लाख 70 हजार थी। लोकसभा में 27, राज्य सभा में 8, राज्यों की विधान सभाओं में 209 प्रजा समाजवादी सदस्य थे ।उस समय तर्क यह प्रस्तुत किया गया था कि 1952 के चुनाव फल के आधार पर 16.31 प्रतिशत मत मिले थे जो कांग्रेस के बाद दूसरा स्थान था ।

प्रजा समाजवादी पार्टी की स्थापना के समर्थक लोगों में इतना अधिक उत्साह था कि वे अपने को कांग्रेस का विकल्प मानने लगे थे ।दूसरी ओर ऐसे लोग थे जो इस बात से दुःखी थें कि समाजवादी पार्टी ने मार्क्सवाद और समाजवाद के प्रति अपनी निष्ठा को दूषित कर लिया ।उस

समय जे0 बी0 कृपलीन का कहना था कि राजनीतिक दल के लिए सिद्धांत (आइडियोलाजी) कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

फरवरी 1953 में कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधान मंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरु ने जय प्रकाश नारायण को कांग्रेस और प्रजा समाजवादी पार्टी में शासन और बाहर सहयोग के आधार ढूढ़ने के लिए बातचीत हेतु आमन्त्रित किया । उस समय डा0 लोहिया जेल में थे और आचार्य नरेन्द्र देव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था । जिसमें जय प्रकाश जी डा0 लोहिया से परामर्श ही न कर सके और नरेन्द्र देव जी को केवल सूचना भर दे सके । इससे इनमें आपसी कटुता बढ़ी । उधर जे0 पी0 ने कांग्रेस से सहयोग के लिए 14 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया परन्तु उस पर नेहरु सहमत न हो पाये, जिससे दोनों के मध्य वार्ता विफल रही ।यही नही इस बातचीत का विरोध दोनों पक्षों में भी व्यापक रुप से रहा । जहाँ कांग्रेस में इसके नेता केशव देव मालवीय थे वही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में डा0 लोहिया व उनके समर्थक प्रमुख थे ।[42]

इसके बाद प्रजा समाजवादी पार्टी में दो धर्म संकट सामने आये । आन्ध प्रदेश के 'स्थापना की घोषणा'[43] के बाद वहाँ संयुक्त सरकार बनाने की दिशा में प्रजा समाजवादी पार्टी ने आन्ध्र प्रदेश के स्थापना आन्दोलन के जनक टी0 प्रकाशम को नये राज्य में संयुक्त सरकार की स्थापना की दिशा में उचित कदम उठाने का अधिकार सितम्बर 1953 मे सौंप दिया लेकिन कांग्रेस द्वारा टी0 प्रकाशम का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए यह शर्त रखी गयी कि वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से वे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लें ।25 सितम्बर, 1953 को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर वे कांग्रेस के सदस्य बन गये ।[44] प्रजा समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी ने टी0 प्रकाशम के इस आचरण को नैतिकताहीन बताकर इसकी कटु आलोचना की ।

प्रजा समाजवादी पार्टी का दूसरा धर्मसंकट त्रावनकोर-कोचीन में उपस्थित हुआ। पहले आमचुनाव में कांग्रेस को विधान सभा में क्षीण बहुमत प्राप्त हुआ। जिसकें फलस्वरुप वहाँ सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो अस्वीकृत हो गया । जिसके बाद मुख्यमंत्री ने विधान सभा को भंग कर नये चुनाव कराने की मांग की । फलस्वरुप 1954 में वहाँ चुनाव हुए

---

42 - बेतुल सम्मेलन में प्रजा समाजवादी पार्टी की नीति निश्चित करने के लिए नीति आयोग स्थापित किया गया, जिसमें अशोक मेहता और डा0 राम मनोहर लोहिया को सेक्रेटरी बनाया गया ।

43 - 25 मार्च, 1953 को पं0 जवाहर लाल नेहरु ने यह घोषण की थी ।

44 - टी0 प्रकाशम ने 25 सितम्बर 1953 को अपने अनुयायियों के साथ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़कर "प्रजा पार्टी" की स्थापना की ।

जिसमें किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अतः प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने गैर कम्युनिस्ट दलों से सहयोग कर सरकार बनाया। पट्टमथानु पिल्लई सरकार के मुखिया बने। परन्तु सरकार बनने के कुछ समय के भीतर अगस्त 1954 में वहाँ गोलीकाण्ड हो गया। इस पर डा0 लोहिया ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से पिल्लई को तयागपत्र देने का आदेश दिया, जिसे मानने से पिल्लई ने इन्कार कर दिया, इस पर डा0 लोहिया ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया।और जे0 पी0 तथा अशोक मेहता के विरुद्ध कांग्रेस से साठ-गाठ करने का आरोप लगाया। प्रजा समाजवादी पार्टी के इस आन्तरिक संकट पर विचार करने के लिए एक विशेष अधिवेशन नागपुर में आचार्य जे0 पी0 कृपलीन की अध्यक्षता में आहुत की गयी। इसमें 303 सदस्यों में से 217 डा0 लोहिया के पक्ष में थे। अतः पार्टी विभाजन के कगार पर आकर खड़ी हुई। आचार्य कृपलानी व जयप्रकाश नारायण दोनों ने ही ऐसी राजनीतिक घटना के लिए जिसके लिए मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष रुप से उत्तर दायी न हो, उसकी निन्दा करना अनुचित माना और विवाद बढ़ने पर आचार्य कृपलानी ने अधिवेशन के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। जिससे प्रजा समाजवादी पार्टी कुछ समय तक बिना नेता के नेतृत्व के ही रही।[45] परन्तु आचार्य नरेन्द्र देव ने कुछ समय बाद नेतृत्व का कार्यभार स्वयं संभाल लिया।

4. प्रजा समाजवादी पार्टी का विभाजन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1955 में अबाड़ी नामक स्थान पर हुआ। इसमें कांग्रेस ने समाजवादी ढांचे की सामाजिक व्यवस्थ की स्थापना करना अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के बाद प्रजा समाजवादी पार्टी में कांग्रेस से सहयोग करने के प्रश्न पर विवाद तेजी से उभरा। मधु लिमयेन कांग्रेस के नये प्रस्ताव की कटु आलोचना करते हुए उसे मतदाताओं को धोखा देने का प्रयास बतलाया। दूसरी ओर बम्बई की प्रजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अशोक मेहता और नौ अन्य सदस्यों ने अध्यक्ष से कांग्रेस से सहयोग करने के प्रश्न पर पुनर्विचार शुरु कराने की मांग की। मधु लिमये ने यह आरोप लगाया कि अशोक मेहता और उनके सहयोगी कांग्रेस के आबाड़ी प्रस्ताव का स्वागत करना चाहते हैं। और वे कांग्रेस से सहयोग करने के लिए आतुर हैं। प्रजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव ने मधुलिमयें से

---

45 - प्रजा समाजवादी पार्टी के प्रमुख पत्र "जनता" ने उस स्थिति की आलोचना करते हुए लिखा था कि कुछ समय तक प्रजा समाजवादी पार्टी का जहाज बिना कप्तान, बिना नेता के रह गया, और साधारण कार्यकर्ता अपने आपको अनाथ अनुभव करने लगे थे।

कहा कि वे अपने आरोपों के लिए अशोक मेहता से माँफी मांगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्येक सदस्य को अपनी बात कहने की पूरी स्वतन्त्रता है, लेकिन मेरे मत से किसी भी स्वाभिमानी राजनीतिक दल को बिना मांगे कांग्रेस से सहयोग करने की बात चलाना, सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार की बातचीत पार्टी के प्रति विश्वासघास है। इससे अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती है।

मधु लिमये ने आचार्य नरेन्द्र देव की बात नहीं मानी फिर भी उन्होंने बम्बई की पार्टी को उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने की सलाह दी। परन्तु बम्बई प्रजा समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी ने मधु लिमये के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित कर दिया और बाद में उन्हें व उनके 21 सहयोगियों को पार्टी से निल्मबित कर दिया।[46] आचार्य नरेन्द्र देव इस निलम्बन को रद्द कराना चाहते थे, तथा डा0 लोहिया ने तो इस निम्बन के विरोध में आलोक मेहता एवं बम्बई कार्यकारिणी की निन्दा भी की। उधर उ0 प्र0 में डा0 लोहिया का समर्थन अधिक था, अतः प्रदेश पार्टी अधिवेशन में उन्होंने मधु लिमये को आमान्त्रित किया, जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपना अपमान माना और कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से आचार्य नरेन्द्र देव ने गाजीपुर अधिवेशन पर[47] रोक लगा दिया।लेकिन इसके बावजूद सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें डा0 लोहिया के निर्देश से केन्द्रीय नेतृत्व की निन्दा की गयी। इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने 3 जून 1955 को उ0 प्र0 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष गोपाल नारायण सक्सेना को निलम्बित करके उ0 प्र0 प्रजा समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी के स्थान पर तदर्थ नियुक्ति कर दी। डा0 लोहिया को भी निलम्बित कर दिया गया।

प्रजा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने 15-22 जुलाई 1955 तक जयपुर में पार्टी के प्रान्तीय अध्यक्षों, सचिवों, का शिविर आयोजित किया। जिसमें डा0 लोहिया ने हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा डा0 लोहिया के निलम्बन की पुष्टि के बाद उनके समर्थकों ने सामूहिक रुप से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इस्तिफा दे दिया।

दिसम्बर 1955 में डा0 राममनोहर लोहिया ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और वे स्वयं उसके अध्यक्ष बने। और इसके बाद प्रजा समाजवादी पार्टी का पूर्ण रुप से विभाजन हो गया। आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में अधिकाशं सदस्य प्रजा समाजवादी पार्टी में में बने रहे, लेकिन तरुण कार्याकर्ता डा0 लोहिया के प्रभाव में अधिक थे।

---

46. 26 मार्च 1955 को बम्बई प्रजा समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी ने मधु लिमये के निलम्बन की पुष्टि की।
47. 23 मार्च 1955 को प्रजा समाजवादी पार्टी का गाजीपुर में अधिवेशन सम्पन्न होना था।

डा0 लोहिया समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय सत्ता में आने के लिए सात वर्ष की अवधि निश्चित की थी। लेकिन 1957 के आम चुनाव में लोक सभा में समाजवादी पार्टी के 7 सदस्य चुने गये थे, तथा 1962 के आम चुनाव में उसे 6 स्थानों पर ही सफलता मिली। 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 19 सदस्य लोक सभा में पहुँचे थे तथा 1962 में उनकी सदस्य संख्या 12 तक पहुँच गयी। इस प्रकार दोनों ही समाजवादी पार्टियाँ आम चुनावों में बुरी तरह विफल रहीं तथा मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल नहीं हुए। विधान सभाओं में भी उनके सदस्यों का हाल करीब-करीब यही रहा। इस प्रकार 1962 तक डा0 राम मनोहर लोहिया और उनकी समाजवादी पार्टी सत्ता से उतनी ही दूर थी जितनी अपने जन्म काल के समय थी। 1963 में समाजवादी पार्टी का सम्मेलन कलकत्ता में हुआ,जिसमें डा0 लोहिया ने व्यवहारिक राजनीति अपनाने का नारा दिया। और जन संघर्षों तथा चुनावों में विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रस्ताव किया। कम्युनिस्टों के तिरस्कार की नीति छोड़ दी गयी। इसी नीति के कारण डा0 लोहिया ने समाजवादियों की एकता का नारा दिया और विपक्षी दलों की एकता के लिए गैर-कांग्रेसवाद का नारा लगाया।

1964 में डा0 लोहिया ने समाजवादी पार्टी और प्रजा समाजवादी पार्टी के विलय का सुझाव रखा था लेकिन विफल हो गया। बाद में जब अशोक मेहता अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गये तो बनारस में प्रजा समाजवादी पार्टी और समजावादी पार्टी के विलय के लिए विशेष सम्मेलन किया गया और उसके बाद संयुक्त समाजवादी पार्टी का उदय हुआ और एस0 एम0 जोशी को उसका अध्यक्ष तथा राजानारायण को सचिव बनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी फिर से अलग हो गयी।[48] जार्ज फर्नांडिस व मधु लिमये समाजवादी पार्टी को सैद्धान्तिक आधार देना चाहते थे। उन लोगों राजनारायण को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद चरण चौधरी द्वारा संगठित भारतीय क्रान्ति दल में शामिल होने का निश्चय किया।

प्रजा समाजवादी पार्टी के गया अधिवेशन[49] के दो महीने के भीतर आचार्य नरेन्द्र देव के निधन (1956) से समाजवादी आन्दोलन ने मुख्य विचारक और सिद्धांत वेत्ता खो दिया। गया

48 - 12 अक्टूबर 1967 को डा0 लोहिया का निधन हो गया। इसके बाद पार्टी में पुनः फूट पड़ी।

49 - दिसम्बर 1955 में प्रजा समावादी पार्टी का अधिवेशन गया में आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें पार्टी के लिए लोकतान्त्रिक समावाद के सैद्धान्तिक पक्ष पर "गया थीसिस" स्वीकार की गयी।

अधिसवेशन में जो सिद्धांत पत्र स्वीकार किया गया था ।उसके अनुसार प्रजा समजावादी पार्टी को कांग्रेस का शिष्ट और शालीन विरोध करने का मार्गदर्शन दिया था । विरोध के लिए विरोध और विपक्षी दलों के तालमेल की नीति को अस्वीकार कर दिया गया था । पार्टी के लिए राष्ट्रीयता, लोकतन्त्र और सामाजिक परिवर्तन की प्रतिबद्धता को आवश्यक माना गया था ।

आचार्य नरेन्द्र देव के निधन के बाद आचार्य जे0 बी0 कृपलानी प्रजा समजावादी पार्टी के अध्यक्ष बने और अशोक मेहता जनरल सेक्रेटरी बने ये दोनों नेता आचार्य नरेन्द्र देव द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के विरुद्ध थे । आचार्य नरेन्द्र देव ने समाजवादी आन्दोलन के लिए वर्ग-संघर्ष और सत्याग्रह को अपरिहार्य मानते थे, लेकिन आचार्य जे0 बी0 कृपलानी वर्ग-संघर्ष के परम विरोधी थे, और उन्होंने वर्ग-संघर्ष के विरुद्ध एक पुस्तिका प्रकाशित की, इसके साथ ही "गया थीसिस" को एक किनारे रख दिया गया । मधु दण्डवते ने अपनी पुस्तिका "एवोलूशन आफ दि सोशलिस्ट पालिटिक्स एण्ड पर्सपेक्टिव" में लिखा है कि प्रजा समाजवादी पार्टी ने "गया थीसिस" का उल्लघन करने में ही अपना कर्त्तव्य पालन समझा ।1957 के आम चुनाव के पूर्व दिस0 1956 में प्रजा समाजवादी पार्टी का अधिवेश बंगलौर में हुआ और उसमें प्रजा समजावादी पार्टी ने चुनाव में ताल-मेल की नीति अपनायी जिसको "गया थीसिस" में अस्वीकार कर दिया गया था ।

प्रजा समाजवादी पार्टी के बंगलौर अधिवेशन में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र स्वीकार किया गया । उसमें शासन और सत्तारुढ़ दल के अधिनायकवादी प्रवृत्तियों की आलोचना करते हुए कहा गया था कि सत्तारुढ़ कांग्रेस अपनी पार्टी के हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तन्त्र का उपयोग करती है और उसमें सत्ता का केन्द्रीकरण इतना बढ़ गया कि हर मामले में ऊपर से आदेश दिये जाते हैं और स्वशासन का आधार क्षेत्र विस्तृत होने के स्थान पर संकुचित होता जा रहा है । प्रशासन में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, भूमि सीमा निर्धारण और भूमि के पुनर्वितरण पर जोर दिया गया ।किसानों को लाभन्वित करने के लिए सहकारी विपणन, ऋण और विकास समितियों को गठित करने का सुझाव दिया गया था । मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ट्रेड यूनियन अधिकारों का समर्थन किया गया ।

प्रजा समाजवादी पार्टी ने बैंकों, खनिज उद्योग और बागानों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। विदेशों से थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का भी सुझाव दिया गया । शासन के आर्थिक और वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए आर्थिक सेवा संगठित करने का भी सुझाव दिया गया था ।कर

व्यवस्था में सुधार और बड़े उद्योगों तथा उद्योग घरानों पर पूँजीगत लाभ के लिए कर अधिक लगाने का सुझाव भी दिया गया । प्रिवीपर्स[50] को समाप्त करने पर भी जोर दिया गया था ।विदेश नीति के संबंध में पाकिस्तान से सम्बन्धों को सुधारने की सलाह सरकार को दी गयी थी ।

प्रजा समाजवादी पार्टी ने गोवा की समस्या को सुलझाने पर जोर दिया था । हंगरी के आन्तरिक विद्रोह का सोवियत संघ द्वारा दमन की नीति की निन्दा करते हुए रुस के सन्दर्भ में भारत द्वारा अपनायी गयी नीति की भी आलोचना की गयी ।1957 के आम चुनाव के पूर्व जय प्रकाश नारायण ने प्रजा समजावादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की एकता का प्रयास किया जो सफल नहीं हुआ । इसी बीच 1957 में संयुक्त महाराष्ट्र समिति का आन्दोलन हुआ उसमें प्रजा समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, पीजेन्ट एण्ड वर्कर्स पार्टी तथा अन्य वामपंथी लोग शामिल थे। समाजवादी पार्टी ने मई 1957 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन और हिन्दी आन्दोलन चलाया था।

20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया । 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरु ने राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया । 26 अक्टूबर को देश में संकट कालीन स्थिति की घोषणा कर दी गयी और राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना की गयी । 31 अक्टूबर को तत्कालीन रक्षा मंत्री बी0 के0 कष्णा मेनन रक्षा विभाग के मंत्री पद से हट गये और पं0 नेहरु रक्षा विभाग भी अपने पास रख लिये । प्रजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाते अशोक मेहता ने पं0 नेहरु की भारत-चीन मैत्री की नीति की भी आलोचना की ।

1963 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का अधिवेशन भोपाल में हुआ । उसमें चुनाव में दूसरी पार्टियों से तालमेल की नीति को छोड़ा गया और पार्टी को समाजवादी पार्टी के रुप में गठित करने, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्प्रदायिक दलों और दूसरी प्रतिक्रियावादी दलों से किसी प्रकार का संबंध न रखने का निश्चय किया गया । एस0 एम0 जोशी को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया थ।[51] दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का 1963 का अधिवशेन कलकत्ता में हुआ । जिसमें "सात वर्ष में सत्ता" का नारा उस अधिवेशन में छोड़ दिया गया और व्यवहारिक राजनीति के नाम चुनाव और संघर्ष में विपक्षी दलों से एकता करने की रणनीति अपनायी गयी ।[52]

---

50 - प्रिवी पर्स- "भारतीय नरेशों के भत्ते।

51 - भोपाल अधिवेशन में कांग्रेस का विरोध बढ़ा और पं0 जवाहर लाल नेहरु से रक्षा के मामले में विफलता के लिए त्याग पत्र की मांग की गयी ।

52 - इस नीति के अन्तर्गत जहां एक ओर प्रजा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के विलय के चर्चा की गयी और दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य दलों से मेल जोल बढ़ाने की शुरुआत की गयी ।

भोपाल अधिवेशन के दो महीने के भीतर प्रजा समाजवादी पार्टी में अशोक मेहता द्वारा पार्टी में रहते हुए योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनने के कारण विवाद उठ खड़ा हुआ । प्रजा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अशोक मेहता के आचरण की कटु आलोचना की और उनके कांग्रेस से ताल-मेल के प्रयास को पार्टी विरोधी कार्यवाही माना। अशोक मेहता द्वारा त्याग पत्र न देने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, इस पर अशोक मेहता प्रजा समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गये ।

अशोक मेहता और उनके साथियों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद डा0 राम मनोहर लोहिया ने बिना शर्त दोनों समाजवादी पार्टियों के विलय का प्रस्ताव रखा । कुछ कठिनाइयों के बाद दोनों पार्टियों का वाराणसी के विशेष अधिवेशन में विलय कर संयुक्त समाजवादी पार्टीके गठन का निश्चय किया गया ।[53] इसके अक्ष्यक्ष एस0 एम0 जोशी बनाये गये । संयुक्त समाजवादी पार्टी (संसोपा) ने लोकतान्त्रिक और शान्तिमय उपायों से समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य स्वीकार किया, जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण और एक देश द्वारा दूसरे देश के शोषण को समाप्त करने की नीति घोषित की गयी । यह भी कहा गया कि संसोपा शान्तिपूर्ण ढंग से क्रान्तिकारी,वर्ग-संघर्ष और जनसंघर्षो को आयोजित करके सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाये। संसदीय तरीकों को अपनाकर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा । पूँजीवादी,सामन्तवादी शोषण और अन्याय को मिटाने के लिए संसोपा निरंतर प्रयास करेगी ।

लेकिन वाराणसी अधिवेशन में डा0 राम मनोहर लोहिया के अनुयायियों की हठवादिता के कारण प्रजा समाजवादियों का मोह भंग हुआ, प्रजा समाजवादी पार्टी के 800 प्रतिनिधियों में से 650 ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और कुछ समय के भीतर प्रजा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखने का निश्चय 31 जनवरी 1965 को किया गया । इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहा गया कि प्रजा समाजवादी पार्टी और संयुक्त समाजवादी पार्टी दो स्वतन्त्र पार्टियाँ हैं, जिनमें कार्य पद्धति और आचरण में गंभीर मतभेद हैं ।ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों को अलग रहकर अच्छे पड़ोसी की भाँति सद्भावना और सहयोग विकसित करने का प्रयास करना चाहिए ।

---

53 - 31 जनवरी ,1965 को संयुक्त समजावादी पार्टी (संसोपा) का गठन हुआ ।

5-समाजवादी आन्दोलन (1964 -1974 ई0) तक

1964 से 1974 तक का दशक भारत में समाजवादी आन्दोलन घटना प्रधान रहा है। इसके पूर्व लोक सभा के उपचुनाव[54] में डा0 राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद से और आचार्य जे0 बी0 कृपलानी अमरोहा से चुने गये। लोक सभा में पहुँचने के बाद डा0 लोहिया नें पं0 जवाहर लाल नेहरु एवं साधारण किसान के दैनिक व्यय के अन्तर को उठाते हुए कहा कि जहाँ प्रधान मंत्री पर प्रतिदिन 25 हजार रुपये व्यय होते है, वहाँ गरीब किसान तीन आने व्यय करता है।आय के अन्तर का प्रश्न उठाते हुए उन्होंने कहा कि देश से गरीबी मिटाना चाहिए। डा0 लोहिया ने "मूल्य बाँधों" और "गरीबी हटाओ" के नारे दिये। उन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों को प्रभावित करने की नीति अपनायी। अशोक मेहता, गेंदा सिंह, चन्द्रशेखर, नारायण दत्त तिवारी आदि प्रजा सोशलिस्ट नेताओं के कांग्रेस में जाने के बाद डा0 राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विलय की बात चलायी। जनवरी 1965 में प्रजा समाजवादी पार्टी के वाराणसी के विशेष अधिवेशन में डा0 लोहिया विशेष रुप से राजनारायण के साथियों की हठवादिता से सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। फिर भी उस सम्मेलन के कथित निश्चय के आधार पर संयुक्त समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। लेकिन प्रजा समाजवादी पार्टी को उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निश्चय के अनुसार पुनर्जीवित किया गया और नारायण गणेश गोरे (एन0 जी0 गोरे) को अध्यक्ष बनाया गया तथा प्रेम भसीन को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया।

सन् 1967 के आम चुनाव के पूर्व डा0 लोहिया ने नया नारा दिया "कांग्रेस को हटाओ और देश को बचाओ"। कांग्रेस को 1967 के आम चुनाव में तो बहुत मिल गया लेकिन आठ राज्यों में उसका बहुमत समाप्त हो गया। कांग्रेस से इस्तीफा देने और विपक्ष में जाने वाले कांग्रेसी नेताओं को ही संयुक्त विधायक दलों का नेता चुना गया और संयुक्त विधायक दलों का विघटन होने में करीब-करीब एक-डेढ़ वर्ष का समय लग गया।

1967 के आम चुनाव के सम्बन्ध में जारी घोषणा-पत्र[55] में (संसोपा के) कहा गया कि राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों की स्थापना का प्रयास किया जाय। केन्द्र और राज्य संबंधों को फिर से परिभाषित करने का भी सुझाव दिया गया। भू-राजस्व (लगान) को समाप्त कर उसके स्थान पर कृषि आयकर लगाने, सात वर्षीय सिंचाई योजना कार्यान्वित करने और राज्य

54 - 1963 के लोकसभा के उप चुनाव में।

55 - 1967 के आम चुनाव के संबंध में 29 नवम्बर 1966 को जारी संसोपा का घोषणा पत्र।

सरकारों द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का सुझाव दिया गया जिसमें औसत उत्पादन न होता हो ।व्यक्तिगत आय को 1500 रुपये मासिक तक सीमित करने पर जोर दिया गया था । और यह सुझाव दिया गया था कि इससे आय को 25 से 30 वर्ष तक की अवधि के लिए जबरन जमा कराने की व्यवस्था की जाये । वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में अमेरिका और सोवियत संघ किसी भी गुट के साथ विशेष सम्बन्ध न रखने पर विशेष जोर दिया गया था ।इसके साथ ही भारत की प्राकृतिक सीमाओं को पुनः स्थापित करने का भी सुझाव घोषणा पत्र में दिया गया था।भारत-पाकिस्तान महासंघ बनाने, तिब्बत की स्वतन्त्रता, पश्चिम जर्मनी, इजराइल तथा ताइवान को मान्यता देने की चर्चा की गयी थी ।

घोषणा पत्र में संसदीय लोकतन्त्र के माध्यम से ही लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना पर बल दिया गया । साथ ही समाजवाद के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए संसद और विधान मण्डलों के बाहर वर्ग-संघर्ष के आधार पर किसानों, मजदूरों, और दूसरे जन आन्दोलनों का भी संचालन किया जाना चाहिए ।

संयुक्त समाजवादी पार्टी ने भूमि सुधारों, भूमि सेना के गठन, बंजर भूमि पर खेती के लिए सरकारी प्रयास, सहकारी खेती और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभाव को धीरे-धीरे बढ़ाये जाने पर जोर दिया गया था ।सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं का बड़े पैमाने का उत्पादन करके मूल्यों को स्थिर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ।पार्टी ने आगे यह स्पष्ट कर दिया कि उत्पादन के सभी साधनों के राष्ट्रीयकरण की वह समर्थक नहीं है । तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों और व्यापार के क्षेत्र स्पष्ट रखे जाने चाहिए । इस बात पर भी जोर दिया गया कि समाजवाद का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति को पहल करने की और उद्यम आरम्भ करने की भावना को ही कुंठित कर दिया जाय।करों के निर्धारण के बाद अथवा अन्तर एक और दस गुने से अधिक नहीं होना चाहिए ।

1967 के आम चुनाव तक कांग्रेस ने समाजवादी सिद्धांतों को काफी दूर तक स्वीकार कर लिया था ।यही कारण है कि प्रजा समाजवादी पार्टी के लोगों में कांग्रेस के प्रति शत्रुता की भावना नहीं थी लेकिन डा0 राम मनोहर लोहिया और संयुक्त समाजवादी पार्टी ने तो "कांग्रेस हटाओं और देश बचाओं" का नारा लगाकर उसकों ही लोकतन्त्र और समाजवाद का शत्रु घोषित कर दिया था ।

संसोपा के पटना अधिवेशन[56] में पार्टी के अन्दर उमड़े मतभेद को बड़ी मुश्किल से नियंत्रित किया गया और पार्टी की एकता बचायी जा सकी ।जार्ज फर्नाडिस एवं राजनारायण के गुटों के बीच मतभेद उग्ररुप में प्रकट हुए । पटना के बाद उ0 प्र0 में जब राजनाराण ने संसोपा का प्रादेशिक सम्मेलन करने का प्रयास किया तो जार्ज फर्नाडिस ने उस पर रोक लगा दी । साथ ही उन्होंने राजनारायण गुट को दण्डित करने का प्रयास किया ।इस पृष्ठ भूमि में संसोपा और प्रजा समाजवादी पार्टी दोनों के विलय की बातचीत शुरु की गयी । संसोपा के सोनपुर अधिवेशन[57] में दोनों पार्टियों के विलय के सुझाव का समर्थन किया गया, लेकिन इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया जा सका । दोनों पार्टियों में इस बात पर मतभेद था कि कांग्रेस के प्रति क्या रवैया रखा जाय । संसोपा कांग्रेस को अपना पहला शत्रु मानती थी । और प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता एन0 जी0 गोरे का विचार था कि कांग्रेस में जो समाजवादी लोग हैं उनसे मेल किया जा सकता है।

सन् 1967 और 1969 के बीच उ0 प्र0, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा, मैसूर, पाण्डिचेरा और मणिपुर में संयुक्त विधायक दलों की सरकारे स्थापित हुई। पंश्चिम बंगाल में अजय मुखर्जी के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे की सरकार स्थापित हुई थी । लेकिन दो वर्ष के भीतर दल बदलुओं और पारस्परिक मतभेदों के कारण संयुक्त विधायक दलों की सरकारें गिर गयी ।

1969 में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पंश्चिम बंगाल और नागालैण्ड विधान सभाओं के मध्यावधि चुनाव कराये गये जिनमें संयुक्त विधायक दल में शामिल अधिकाशं पार्टियों की स्थिति पहले से कमजोर हो गयी । प्रजा समाजवादी पार्टी और संसोपा दोनों को अधिक क्षति हुई। उत्तर प्रदेश विधान, सभा में 1967 के चुनाव में 11 विधायक थे, 1969 के मध्यावधि चुनाव में केवल तीन प्रजा समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गये । 1967 के चुनाव में मैसूर में प्रजा समाजवादी पार्टी के 20 विधायक थे । इसी प्रकार 1971 के चुनाव में उड़ीसा विधान सभा में प्रजा समाजवादी पार्टी विधायकों की संख्या 21 से घटकर 4 रह गयी । संसोपा के अनेक विधायक उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस में चले गये । इसी प्रकार मैसूर में प्रजा समाजवादी पार्टी विधायक कांग्रेस में चले गये । इस पृष्ठ भूमि में प्रजा समाजवादी पार्टी और संसोपा के विलय का प्रयास फिर से शुरु किया गया ।

---

56 - अप्रैल 1967 में संसोपा का पटना में अधिवेशन सम्पन्न हुआ ।

57 - संसोपा का सोनपुर अधिवेशन 1968 में ।

प्रजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एन0 जी0 गोरे ने देश में नये ध्रवीकरण की संभावनाओं की ओर संकेत करते हुए कहा कि कांग्रेस का विभाजन होने पर नये ध्रवीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। वे लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्तियों की एकता पर जोर देते थे।1967 के बाद पश्चिम बंगाल और केरल के वामपंथी मोर्चे में शामिल सी0 पी0 आई0 और सी0 पी0 आई0 एम0 के नीतियों की आलोचना करते हुए एन0 जी0 गोरे का कहना था कि इन मोर्चो और श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों में बहुत कम अन्तर है। उनका यह भी कहना था कि श्री मोरार जी देसाई और श्रीमती गाँधी के बीच विचारों की समानता नहीं के बराबर है। इसी आधार में श्री एन0 जी0 गोरे ने समाजवादी विशेष रुप से "लोकतन्त्र और समाजवाद" में विश्वास करने वाले लोगों की एकता पर जोर दिया था।

अगस्त 1969 में जब बंगलौर में कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस में एकता रखने और विभाजन को रोकने के प्रयास में एक प्रस्ताव पास किया, तो श्री एन0 जी0 गोरे को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने ने एक वक्तत्य में कहा कि यह तो घटनाक्रम का नतीजा है।1969 के सितम्बर महीने में प्रजा समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रेम भसीन ने गैर-कांग्रेसी लोकतान्त्रिक दलों की एकता पर जोर दिया। इस प्रकार के प्रयास में उन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी, संसोपा, बिहार के लोकतान्त्रिक दल, बंगाल कांग्रेस, फारवर्ड ब्लाक, महाराष्ट्र की पीजेन्ट्स वर्कर्स पार्टी को शामिल करने का सुझाव दिया।

प्रजा समाजवादी पार्टी कांग्रेस को पूरी तरह समाजवादी पार्टी नहीं मानती थी, लेकिन उसका यह विचार था कि भातरीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), नक्सलवादी आदि, अति उग्रवादी तत्वों द्वारा उत्पन्न संकटों का सामना करने के लिए कंाग्रेस और अन्य लोकतान्त्रिक प्रगतिशील तत्वों का सहयोग आवश्यक है।1967 और 1969 के बीच जो संयुक्त विधायक दल बने थे, उनमें परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारों का गठबन्धन हुआ था। उससे भी प्रजा समाजवादी नेतागण दुःखी थे। उन गठबन्धों में प्रजा समाजवादी और समाजवादी तत्वों का प्रभाव भी नगण्य था।

1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद सत्तारुढ़ कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के सामने यह सुझाव रखे कि अगले चुनाव में उन्हे कम्युनिस्ट पार्टी अथवा प्रजा समाजवादी पार्टी से ताल-मेल करना चाहिए। उन दिनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री पाद अमृत डांगे

थे । जो श्रीमती इन्दिरा गाँधी की नीतियों के समर्थक थे ।श्रीमती गाँधी ने 1971 में लोक सभा मध्यावधि चुनाव कराने का निश्चय किया । उस समय उन्होंने जनता से कांग्रेस को सत्ता सौंपने की अपील की । उस चुनाव में उन्होंने कुछ स्थानों पर कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों के विरुद्ध अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किये ।

1971 के लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में प्रजा समाजवादी पार्टी और संसोपा दोनों की शक्ति पहले से भी क्षीण हो गयी ।1969 में प्रजा समाजवादी पार्टी को यह आशा थी कि कांग्रेस के विभाजन के बाद नये ध्रवीकरण के द्वारा समाजवादी शक्तियों की एकता बढ़ेगी और उसका प्रभाव बढेग़ा । यह दोनों ही बात भ्रांतियां ही सिद्ध हुई ।

अगस्त 1971 में प्रजा समाजवादी पार्टी और संसोपा का विलय करके फिर से समाजवादी पार्टी का गठन नये सिरे से किया गया इसके पूर्व 1971 में लोक सभा के चुनाव के समय कांग्रेस के विरुद्ध "ग्राण्ड एलायन्स" (महान गठजोड़) स्थापित किया गया था ।उसमें जनसंघ, संगठन कांग्रेस,स्वतन्त्र पार्टी और संसोपा शामिल थी ।चुनाव में इस बड़े गठबन्धन को पराजय का मुँह ही देखना पड़ा था ।उस समय तक प्रजा समाजवादी पार्टी की सहानुभूमि सत्तारुढ़ कांग्रेस के साथ ही आधिक थी ।

नयी समाजवादी पार्टी के जन्म के समय से उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ आयीं । उड़ीसा में प्रजा समाजवादी नेता सुरेंद्र द्विवेदी और बांके बिहारी दास कांग्रेस को शत्रु नहीं मानते थे, और उन्होंने उस नयी समाजवादी पार्टी में शामिल हाने से इन्कार कर दिया ।गुजरात में प्रजा समावादी पार्टी और संसोपा के अधिकाशं सदस्य भी नयी पार्टी में शामिल नहीं हुए । ये सभी लोग श्री राजनारायण की कार्यपद्धति और उदण्डता से रुष्ट थे तथा गैर-कांग्रेसवाद के सिद्धांत के भी विरोधी थे । पश्चिम बंगाल के संयुक्त समाजवादी श्रीमती गाँधी का अन्धविरोध करने और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के विरुद्ध थे । अतः पश्चिम बंगाल कें संयुक्त समाजवादियों ने एक विशेष अधिवेशन[58] करके कांग्रेस में शामिल होने का निश्चय किया ।

1971 के घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बातें, पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण, पाकिस्तान का विभाजन, और स्वतन्त्र बंगलादेश का जन्म, थी । इसके पूर्व भारत-सोवियत

---

[58] - अक्टूबर 1971 में पश्चिम बंगाल में संयुक्त समाजवादियों का एक विशेष अधिवेशन ।

सहयोग और मैत्री-सन्धि अगस्त 1971 में हो चुकी थी।[59] इन सब कारणों से 1971 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस दो तिहाई (करीब 350 सीटे) जीती तथा बहुमत से भी अधिक मत प्राप्त कर लिया। परन्तु इनके विरोधयों के महान गठबन्धन को विफलता ही हाथ लगी।समाजवादी पार्टी की भी स्थिति अच्छी नहीं रही। और उसके केवल तीन सदस्य ही लोक सभा में पहुँच सके।

राजनीतिक निराशा के वातावरण में विभिन्न राजनीतिक दलों और गुटों ने अनेक प्रकार के आन्दोलन शुरु किये। 1973 में जे0 पी0 अपनी पत्नी श्रीमती प्रभावती के निधन के बाद राजनीति से एक वर्ष के सन्यास पर थे। सर्वोदय आन्दोलन भी शीथिल पड़ गया था। और उसमें आचार्य विनोबा भावे तथा जे0 पी0 के अनुयायियों में मतभेद उत्पन्न हो चुके थे।

1973 में गुजरात में छात्रों और युवा वर्ग की नव निर्माण समिति ने मूल्य वृद्धि और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया। संगठन कांग्रेस के नेता मोरार जी देसाई ने उस आन्दोलन के समर्थन और गुजरात विधान सभा को भंग करके, विधान सभा के नये चुनाव कराने की मांग के लिए अनशन शुरु किया। इस पर केन्द्र सरकार गुजरात विधान सभा भंग करके नये चुनाव कराने की घोषणा की। गुजरात के छात्रों और युवा वर्ग के आन्दोलन का प्रभाव देश के अन्य भागों पर भी पड़ा, यद्यपि उनकी सफलता क्षणिक ही रही।

1973 में समाजवादी पार्टी का अधिवेशन बुलन्दशहर में हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी को समाजवादी सिद्धान्तों और निष्ठा के अनुसार कार्य करने पर जोर दिया गया। जार्ज फर्नांडिस अखिल भारतीय रेलवे मेन्स फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गये। उन्होंने द्वितीय समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय संघ से संबंध स्थापित किया।

1973 में उत्तर प्रेदश में छात्र आन्दोलन की लहर चल पड़ी। उस वर्ष प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के विद्रोह और लखनऊ विश्वविद्यालय में हुए अग्निकाण्ड के समय तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमला पति त्रिपाठी ने अपने सरकार की अक्षमता के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और बाद में हेमवती नंदन बहुगणा को उत्तर प्रेदश का मुख्यमन्त्री बताया गया।[60]

---

59 - 9 अगस्त, 1971 को भारत-सोवियत संघ मैत्री एवं सहयोग सन्धि को भारतीय गुट-निरपेक्षता पर एक गहरा प्रहार अनेक पाश्चात्य पत्र-पत्रिकाओं ने माना, और यह आरोप लगाया कि इस सन्धि के बाद भारत साम्यवादी गुट की ओर झुक गया है, अतः अपनी गुट निरपेक्षता की नीति से दूर हो गया है।

60 - इस परिवर्तन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं पड़ी, क्योंकि विधान मण्डल में सत्तारुढ़ कांग्रेस का बहुमत था।

इन आन्दोलनों की सफलता को देखकर जय प्रकाश नारायण ने 1974 में बिहार में छात्र और युवा वर्ग के सहयोग से भ्रष्टाचार और मंहगाई के विरोध में आन्दोलन चलाया। इस आन्दोलन को जन समर्थन मिलता गया और उसका प्रभाव बढ़ता गया । जे0 पी0 ने यह भी नारा दिया कि वे भ्रष्ट विधायकों के विरुद्ध सत्याग्रह चलायेंगे और विधान सभा को काम नहीं करने देगें ।एक ओर वे उपचुनाव कराने का विरोध करते थे तथा दूसरी ओर विधान सभा भंग कराने पर जो दे रहे थे । जे0 पी0 के नेतृत्व में चलने वाले आन्दोलन में आर0 एस0 एस0, जनसंघ, भू-दान और सर्वोदय आन्दोलन के लोग तथा समाजवादी लोग भी थे । अपने आन्दोलन के प्रभाव को बढ़ते देखकर जे0 पी0 ने सम्पूर्ण क्रान्ति का आह्वान किया ।यद्यपि उन्होंने इस क्रान्ति को परिभाषित नहीं किया ।

1974 में उ0 प्र0 के विधान सभा के चुनाव में जे0 पी0 ने कांग्रेस विरोधी शक्तियों का समर्थन किया, लेकिन उस चुनाव में उ0 प्र0 विधान सभा में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत हो गया और पुनः हेमवती नंदन बहगुणा को प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया गया ।

1974 के अगस्त महीने में श्री चरण सिंह के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय लोकदल की स्थापना हुई । इसमें चरण सिंह के नेतृत्व वाले भारतीय क्रान्ति दल (बी0 के0 डी0) के अतिरिक्त, स्वतन्त्र पार्टी, राजनारायण के नेतृत्व वाली संसोपा बीजू पटनायक का उत्कल कांग्रेस, किसान मजदूर पार्टी, राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक दल और पंजाब खेतिहर जमींदार सभा शामिल हुई ।

6-समाजवादी आन्दोलन-जन आन्दोलन (1974-1977 ई0)

1974 में उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर और पाण्डिचेरी विधान सभाओं के चुनाव कराये गये इसके बाद उ0 प्र0 में हेमवती नंदन बहगुणा, उड़ीसा में श्रीमती नंदिनी सतपथी कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री बनाये गये । पाण्डिचेरी में डी0 एम0 के0 रामास्वामी नायकर मुख्यमंत्री बने । मणिपुर में अलीमुद्दीन का मन्त्रिमण्डल बना, जिसने जुलाई में त्याग पत्र दिया ।गुजरात विधन सभा 15 मार्च 1974 को भंग कर दी गयी ।

श्री जय प्रकाश नारायण ने 15 मार्च 1974 को "सिटीजन्स फार डेमोक्रेसी"[61] की स्थापना की । बिहार में उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन को बढ़ाते हुए उसने बिहार विधान सभा को भंग करने की मांग की ।इस आन्दोलन का समर्थन करने के लिए सभी विपक्षी दलों का

---

61 - जे0 पी0-"लोकतान्त्रिक समाजवाद"

समर्थन या सहयोग मांगा। पश्चिम बंगाल में नये चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पराजित हो जाने पर कांग्रेस का बहुमत हो गया था ।और वहां सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री थे। सी0 पी0 आई0 एम0 के नेता ज्योति बसु ने जे0 पी0 से अपनी पार्टी के कार्यकताओं की रक्षा करने के लिए शरण मांगी । उन्होंने ने जे0 पी0 के आन्दोलन का समर्थन करना भी स्वीकार कर लिया ।

20 अगस्त 1974 को श्री फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति चुने गये और श्री वासप्पा दास जत्ती (बी0 डी0 जत्ती) उपराष्ट्रपति चुने गये ।

1974 में ही देवकान्त बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाये गयें । उसके पहले जगजीवन राम और शंकर दयाल शर्मा को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था ।श्री बरुआ ने नरौरा में कांग्रेस जनों का शिविर चलाकर उनसे श्री जे0 पी0 द्वारा संचालित आन्दोलन का राजनीतिक आधार पर सामना करने का आह्वान किया। जे0 पी0 ने बिहार में मोर्चे का नेतृत्व संभालकर आम हड़ताल की घोषणा कर दी । दिसम्बर 1974 में श्रीमती सुचेता कृपलानी का निधन हो गया ।

1975 के दौरान देश का घटना क्रम तेजी से घूम रहा था । समस्तीपुर में आयोजित समारोह[62] में ललित नारायण मिश्र का निधन हो गया ।फरवरी 1975 में शेख मो0 अब्दुल्ला को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया तथा महाराष्ट्र में श्री वी0 पी0 नायिक की जगह एस0 बी0 चव्हाण को वहाँ का मुख्य मंत्री बनाया गया ।

1975 के पूर्वाद्ध[63] में ही जे0 पी0 संसद के समक्ष प्रदर्शन किया और लोक सभा के अध्यक्ष को जन आन्दोलन की मांगों के संबंध में ज्ञापन दिये । 18 मार्च को जे0 पी0 ने बिहार विधान सभा के सामने जनता का मोर्चा लगाया ।

जून 1975 में राजनीतिक घटना क्रम ने झंझावत का रुप धारण कर लिया । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री जगमोहन नाथ सिन्हा ने श्रीमति गाँधी के चुनाव के विरुद्ध श्री राजनारायण की याचिका को स्वीकार करके श्रीमती इन्दिरा गाँधी के 1971 के रायबरेली से लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर उनकी सदस्यता को भी अवैध घोषित कर दिया । श्री जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले को एक महीने तक लागू न करने का भी आदेश दिया जिससे उस फैसले पर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सके ।

---

62 - 2, जनवरी, 1975 को समस्तीपुर में आयोजित समारोह में बम बिस्फोट हुआ, जिसमें ललित नारायण मिश्र का निधन हो गया ।

63 - 12 जून, 1975

जून के आखिरी सप्ताह[64] में उच्चतम-न्यायालय के अवकाश कालीन न्यायमूर्ति श्री वी0 के0 कृष्ण अय्यर ने श्री जगमोहर लाल सिन्हा के फैसले को उच्चतम-न्यायालय में अपील की सुनवाई तक के लिए स्थगित रखने का आदेश दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि श्री जगमोहन सिन्हा ने जिस कानूनी आधार पर फैसला किया है वह सही है।लेकिन संसद को इस कानून में संशोधन करने का अधिकार है। यदि संसद कानून में आवश्यक संशोधन कर दे तो श्रीमती गाँधी का चुनाव वैद्य माना जा सकता है। लेकिन जब तक अपील का फैसला न हो जाय श्रीमती गाँधी प्रधानमंत्री रह सकती हैं। लेकिन लोक सभा में मतदान में भाग नहीं ले सकती। बाद में उच्चतम- न्यायालय ने चुनाव कानून में हुए नये संशोधन के आधार पर श्रीमती गाँधी के चुनाव को अवैध धोषित करने वाले इलाहाबाद उच्चन्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया।

लेकिन श्रीमती, इन्दिरा गाँधी के विरुद्ध इलाहाबाद उच्चन्यायालय के फैसले के बाद जे0 पी0 और विपक्षी दलों के नेताओं ने श्रीमती गाँधी के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने की मांग के लिए 29 जून से देशव्यापी सत्याग्रह चलाने की घोषणा की। इससे पूर्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में 24 जून को जे0 पी0 ने अपने भाषण में कहा था कि श्रीमती गाँधी का प्रधानमंत्री बने रहा अनैतिक है। उन्होंने सेना और पुलिस बल तथा राज्य कर्मचारियों से सरकार के गैर कानूनी आदेशों का पालन न करने की अपील की। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आन्तरिक संकटकाल की घोषणा कर दी। 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के बाद देश में वाह्य संकटकाल की घोषणा लागू थी। 27 जून 1975 को श्रीमती गाँधी, जगजीवन राम, यशवन्त राव चव्हाण, एच0 आर0 गोखले, के0 ब्रह्मानन्द और ओम मेहता की संकट कालीन समिति बनायी गयी।

संकटकालीन स्थिति लागू होते ही श्री जय प्रकाश नारायण और 600 विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और समाचार पत्रों पर गिरफ्तारी अथवा आन्दोलन संबन्धी समाचारों के प्रकाशन पर रोग लगा दी गयी। विपक्षी दलों में भारतीय लोक दल, संगठन कांग्रेस, सर्वोदय और भूदान आन्दोलन के जय प्रकाश नारायण के प्रभाव वाले कार्यकर्ता, जनसंघ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भीतर श्रीमती गाँधी के आलोचक (श्री शेखर कपूर, चन्द्रशेखर, और मोहन धारिया) और अन्य आन्दोलन कारी नेताओं को गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिया गया था।इस

---

64 - 24 जून, 1975

समय ऐसा प्रतीत होता था कि देश विप्लव के ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है ।संकटकालीन स्थिति की घोषणा के बाद सरकार की ओर से आन्दोलन को समाप्त कर दिया गया था । देशभर में करीब 30 हजार राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया ।

जुलाई माह में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने देश के आर्थिक विकास के लिए बीस-सूत्रीय[65] कार्य-क्रम की घोषणा की । संविधान में 39वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के विरुद्ध न्यायालयों में विवाद उठाने पर रोक लागा दी गयी। चुनाव कानून में भी आवश्यक संशोधन किया गया ।इसके फलस्वरुप उच्चतम न्यायालय में श्रीमती गाँधी के चुनाव को अवैध घोषित किये जाने के विरुद्ध दायर अपील स्वीकार कर ली गयी।

अक्टूबर माह[66] में आन्तरिक सुरक्षा कानून (मीसा) संसद ने पास किया । इसके आधार पर नजरबंदी के विरुद्ध न्यायालयों में विवाद उठाने पर रोक लगा दी गयी थी । इसी कानून के द्वारा तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने का भी अधिकार सरकार को मिल गया था ।11 नवम्बर 1975 को जय प्रकाश नारायण को "पैरोल" पर रिहा कर दिया गया और 16 नवम्बर को उन्हे पुनः नजरबन्द कर दिया गया । 4 दिसम्बर 1975 को उन्हें रिहा कर दिया गया । 8 दिसम्बर को सरकार की ओर से तीन नये अध्यादेश जारी किये गये, जो नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात ही था ।

जनवरी, 1976[67] को बलिराम भगत लोकसभा के नये स्पीकर बनाये गये । 8 जनवरी को लोकसभा ने संविधान की धारा 19(8) के अन्तगर्त मिले अधिकारों को स्थगित करने का प्रस्ताव पास कर दिया । लोकसभा के उसी अधिवेशन में लोकसभा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गयी ।

नवम्बर माह[68] में संसद ने 42वाँ सविधान संशोधन विधेयक पास कर दिया ।उसके आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह उल्लेख किया गया कि "भारत समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र" है ।उस संशोधन में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया ।इधर कांग्रेस में संजय गाँधी और उनके

---

65 - पहली जुलाई, 1975

66 - 17 अक्टूबर, 1975

67 - 5 जनवरी, 1976 को बलिराम भगत को लोक सभा का स्पीकर चुना गया ।

68 - 2 नवम्बर, 1976 को 42वाँ सविधान संशोधन संसद ने पास कर दिया ।

अंतरंग साथियों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे संकटकालीन स्थिति के आठ-दस महिनों में अनुशासन और काम काज में जो चुस्ती आयी थी, वह समाप्त हो चुकी थी और तानाशाही के दुर्गण प्रत्येक रुप में दिखाई देने लगे थे, चाहे वह "नसबन्दी" अभियान हो या गन्दी बस्तियों की सफाई के नाम पर बस्तियों के तोड़-फोड़ और सड़कों को चौड़ा करने की बात हो,सभी क्षेत्रों में अधिनायकवादी दमन और क्रुरता का बोलबाला हो गया था, समाचार पत्रों पर नियंत्रण और अंकुश के कारण जन-भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही थी ।

दिसम्बर 1976 में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने लोकसभा के चुनाव कराने की जिस समय घोषणा की थी, उस समय जय प्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और चरण सिंह जेलों से बाहर आ चुके थे, बहुत से राजनीतिक कार्यकर्ता भी नजरबन्दी काटकर अथवा "पैरोल" पर जेलों के बाहर आ चुके थे । कुछ समीक्षकों का कहना है कि देश में आर्थिक क्षेत्र में प्रगति से प्रधान मंत्री श्रीमती गाँधी को विश्वास हो गया था कि चुनाव में उनकी विजय होगी । कहा जाता है कि उन्होंने अपने विश्वासपात्र राजनीतिज्ञों, अफसरों और गुप्तचर संस्थाओं से रिपोर्ट पायी । उसमें भी उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से सही स्थिति का उनको पता नहीं चलने दिया गया ।

लोक सभा के चुनाव की घोषणा के बाद संकट कालीन स्थिति में भी ढ़ील दी गयी । विपक्षी दलों और उनके नेताओं की रिहाई होने पर उनको एक मंच पर लाने की कार्यवाही तेजी से की गयी । सत्तारुढ़ दल को यह उम्मीद थी कि भारतीय लोकदल के नेता श्री चरण सिंह सौदेबाजी करके सत्तारुढ़ कांग्रेस का समर्थन करेंगे । इसी उद्देश्य से चौ0 चरण सिंह और श्रीमती गाँधी में कुछ मंत्रणा भी हुई । लेकिन लोकदल में पीसू मोदी और श्री राजनारायण भी नेता थे, जिनका श्रीमती गाँधी से शत्रुतापूर्ण विरोध किसी से छिपा नहीं था ।

इसके साथ ही जय प्रकाश नारायण ने एड़ी-चोटी का पसीना एक करके संकटकालीन दमन के शिकार सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर और चुनाव के लिए जनता पार्टी में शामिल कराने में सफलता पायी । संगठन कांग्रेस और कांग्रेस के असंतुष्ट नेतागण (मोरारजी देसाई, अशोक मेहता और चन्द्रशेखर) एक साथ आ गये । जनसंघ और समाजवादी पार्टी के लोग भी जनता पार्टी के साथ थे । बाद में चौ0 चरण सिंह अपने भारतीय लोकदल के साथ जनता पार्टी में शामिल हो गये । अकाली दल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी विपक्षी ताल मेल में

सहायक बन गये। चुनाव की घोषणा होने के बाद जगजीवन राम ने मन्त्रिमण्डल और कांग्रेस से त्याग पत्र देकर "कांग्रेस फार डेमोक्रेसी" की स्थापना की । हेमवती नंदन बहगुणा इस संस्था के जनरल सक्रेटरी थे। इन लोगों ने भी जनता पार्टी के साथ चुनाव का ताल मेल किया।

1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। लोक सभा के 539 निर्वाचित सदस्यों में से 297 जनता पार्टी के थे। 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी के सदस्यों को अचार्य जे0 बी0 कृपलानी और जय प्रकाश नारायण ने गाँधी जी की समाधि के निकट नई पार्टी और गाँधी जी के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। मोरार जी देसाई को चौ0 चरण सिंह और राजनारायण ने मिलकर जनता संसदीय पार्टी का नेता चुनवाने में सफलता प्राप्त की।कुछ लो ग जगजीवन राम को जनता पार्टी का नेता बनवाने के पक्ष में थे लेकिन चौ0 चरण सिंह ने इसका विरोध किया। देसाई जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने । उन्होंने चौ0 चरण सिंह को गृह मंत्री बनाया।

जनता पार्टी की सरकार ने 27 मार्च को वाह्य संकट कालीन स्थिति (जिसे 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय लागू किया गया था) को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने "निर्भय बनो" का नारा दिया ।यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने "मानव अधिकारों की रक्षा" का जो अभियान चलाया था उसके अन्तर्गत भारत की संकटकालीन स्थिति की कटु आलोचना की गयी थी ।[69]

जनता पार्टी में आन्तरिक मतभेद जो इसके जन्मकाल से ही परोक्ष रुप में था, अब समक्ष आया,[70] जबकि गृहमंत्री चौ0 चरण सिंह ने जनता पार्टी की कार्यकरिणी से इस्तीफा दे दिया । प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और पार्टी अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर से उनका मतभेद था । 29 जून को सर्व श्री चरण सिंह, राजनारायण, नरसिंह यादव जगवीर सिंह, रामकिंगर और जनेश्वर मिश्र ने मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिये जिन्हें पहली जुलाई को स्वीकार कर लिया गया। बाद में जनवरी 1979[71] में, चौ0 चरण सिंह को पुनः उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री बनाया गया । परन्तु जुलाई 1979 में चौ0 चरण सिंह जनता पार्टी से अलग हो गये । 15 जुलाई को अपना बहुमत खो देने के बाद श्री देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया । 16 जुलाई को चौ0 चरण सिंह ने

69 - आपात काल को लेकर पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी भारत विरोधी प्रचार तेजी से चलाया गया ।

70 - अप्रैल 1978.

71 - 24 जनवरी, 1979 को चौ0 चरण सिंह को पुनः उप प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री बनाया गया ।

अपना सेक्यूलर (धर्म निरपेक्ष) पार्टी गठित की और 17 जुलाई को वे प्रधानमंत्री बने ।तथा जगजीवन राम संसदीय दल के नेता के रुप में विपक्ष के नेता बने ।

लोक सभा का अधिवेशन अगस्त 1979 में बुलाया गया । लोकसभा की बैठक आरम्भ होने से पूर्व जब चौ0 चरण सिंह को यह विश्वास हो गया कि लोकसभा में उन्हें बहुमत का समर्थन नहीं मिलेगा तो उन्होंने राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने और नये चुनाव कराने की सिफारिस की। श्री नीलम,संजीव रेड्डी प्रधानमंत्री, श्री चौ0 चरण सिंह की सिफारिस स्वीकार कर ली और जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता जगजीवन राम को नयी सरकार गठित करने का अवसर नहीं दिया । राष्ट्रपति ने चौ0 चरण सिंह को काम चलाऊँ सरकार चलाते रहने के लिए प्रधानमंत्री बने रहने का परामर्श दिया । इस प्रकार चौ0 चरण सिंह लोकसभा में बिना विश्वास अर्जित किये ही प्रधान मन्त्री बने रहे ।उन्होंने स्वतः ही अपने जीवन की महत्वाकांक्षा पूरी कर ली। चौ0 चरण सिंह ने इसके बाद अपने मन्त्रिमण्डल से हेमवती नंदन बहगुणा और ब्रह्मानंद रेड्डी को हटा दिया । बाद में हितेन्द्र देसाई भी हट गये ।

जनवरी 1980 ई0 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस (आई), कांग्रेस (यू) तथा लोकदल जिसे एक नई पार्टी के रुप में चरण सिंह और समाजवादियों ने खड़ा किया था जनता पार्टी जिसमें मूलरुप से जनसंघ और जगजीवन राम एवं चन्द्रशेखर जैसे कुछ कंग्रेसी बचे हुए थे तथा सी0 पी0 आई0 और सी0 पी0 एम0 जिसका पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर कहीं भी तसवीर में नहीं थी, के बीच लड़ा गया । जनता पार्टी की शासन विहीनता, दूरदर्शिता का अभाव तथा लगातार चलने वाले आपसी झगड़ों से उबकर लोग एकबार फिर से कांग्रेस और इन्दिरा की तरफ देखने लगे । लोगों ने इन्दिरा गाँधी की कांग्रेस को ही असली कांग्रेस समझा।[72]

जनता पार्टी ने अपना मुख्य मुद्दा इस चेतावनी को बनाया कि यदि इंदिरा गाँधी फिर से सत्ता में आई तो लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को खतरा पैदा हो जायेगा ।चरण सिंह ने किसान राज की बात की, इंदिरा गाँधी ने जनता पार्टी की शासन विहीनता पर ध्यान केन्द्रित किया और लोगों से कहा कि वे काम करने वाली सरकार को वोट दें । लोगों ने एक बार फिर 1971 और 1977 की तरह ही जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठते हुए इस बार कांग्रेस (आई) को भारी जनादेश दिया जिसमें कांग्रेस ने 539 सीटों में से 353 यानी दो-तिहाई बहुमत प्राप्त किया ।

---

72. विपिन चन्द्र, मृदला मुखर्जी, आदिय मुखर्जी-"आजादी के बाद का भारत 1947-2000," प्रथम संस्करण-2002, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय,पृष्ठ 353

लोकदल 41, जनता पार्टी 31 और कांग्रेस (यू) 13 सीटों के साथ काफी पीछे रह गया। सी0 पी0 एम0 और सी0 पी0 आई0 ही अकेले कांग्रेस की इस लहर के खिलाफ टिक पायी, जिन्होंने क्रमशः 36 और 11 सीटे जीतीं। चुनावों के बाद जनता पार्टी में एक बार फिर विभाजन हुआ और जनसंघ के पुराने नेता गणों ने इसे छोड़कर 1980 के अंत में भारतीय जनता पार्टी बनायी और जगजीवन राम कांग्रेस में शामिल हो गये।[73]

31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गाँधी को प्रधानमंत्री बताया गया। समय से पहले यानी 24 से 27 दिसम्बर 1984 को आम चुनाव कराये गये जिसमें कांग्रेस को अब तक सबसे बड़ा बहुमत मिला। यदि पंजाब और आसाम के बाद में हुए चुनावों में जीती सीटें भी जोड़ ली जाएं तो पार्टी को 543 लोकसभा की सीटों में से 415 मिलीं। स्वयं राजीव अमेठी से भारी बहुमत से जीत गये। उन्होंने मेनाका गाँधी को हराया। कांग्रेस का चुनाव अभियान भारत की एकता और अखण्डता पर केन्द्रित था। इंदिरा गाँधी की मृत्यु के बाद लोगों ने यह खतरा बढ़ता देखा। भारी बहुमत का मतलब ऊंची आशाएं, यहां तक की अवास्तविक अपेक्षाएं भी थी, जिन्हें एकबार राजीव ने खुद 'डरा देने वाली' बताया था।[74]

यह राजीव गाँधी ही थे जिन्होंने इक्कीसवीं सदी का विचार भारतीयों के मस्तिष्क में डाला। जब उन्होनें दूसरी बार 1989 के आम चुनाव में भाग लिया तो देश के बारे में उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए मात्र एक दशक बचा था। इस बीच 1987 में कांग्रेस से अपने निष्कासन के बाद वी0 पी0 सिंह द्वारा लगभग अकेले ही चलाया गया अभियान जनता को छू गया।निम्न स्तरों पर अफसर शाही में भ्रष्टाचार नागरिकों के दिन-ब-दिन के जीवन का प्रश्न था,चाहे वे गरीब थे या अमीर लोग यह महसूस कर रहे थे कि उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार निचले स्तरों पर उसे बढ़ावा देता है। वी0 पी0 सिंह ने कोशिश की और व्यापक तबकों का समर्थन हासिल किया, जिसमें सर्वोदय कायकर्ता, दत्ता सामंत जैसे ट्रेड यूनियन नेता महाराष्ट्र में शरद जोशी के नेतृत्व में किसान आन्दोलन और कुछ कांग्रेस-विरोधी मूलगामी बुद्धिजीवियों के तबके शामिल थे। इस भावनात्मक प्रश्न को उठाने के अलावा वी0 पी0 सिंह ने राजीव तथा कांग्रेस को अलग करने की एक विस्तृत रणनीति तैयार की। वे सबसे पहले उन कांग्रेसियों के साथ मिले जो किसी न किसी कारण से असंतुष्ट थे।वी0 पी0 सिंह आरिफ मोहम्मद और अरुण नेहरू तथा

---

73 - वही, पृष्ठ 353

74 - निकाल्स नूगेंट, राजीव गाँधी-सन आफ ए डाइनेस्टी, नई दिल्ली, 1991, पृष्ठ 54

इनके साथ मिलकर रामधन, वी0 सी0 शुक्ला, शतपाल मालिक और दूसरे कांग्रेसी असन्तुष्टों ने 2 अक्टूबर 1987 को जनमोर्चा बनाया । इसके इर्द-गिर्द वी0 पी0 सिंह ने एक राजीव विरोधी राजनीतिक मोर्चा बनाना आरम्भ किया ।[75]

वी0 पी0 सिंह ने वामपंथियों को अपना स्वाभाविक सहयोगी बताया और सम्प्रदायवाद के विरुद्ध बयान देते रहे । लेकिन उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भाजपा उनके साथ रहे, वे उसके मंचों पर से भाषण देते रहे और वाजपेयी तथा आडवाणी के साथ गहरे संबंध बनाये रखे । लेकिन वी0 पी0 सिंह की रणनीति से बढ़कर यह वामपंथी तथा भाजपा का स्वाभविक कांग्रेस-विरोधवाद था, जिसने उन दोनों को वी0 पी0 सिंह के समर्थन में ला खड़ा कर दिया । इलाहाबाद के जून 1988 के उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ उनकी भारी जीत हुई । इसमें बोफोर्स तोप एक प्रकार से अनौपचारिक चुनाव-चिन्ह बन गया । वी0 पी0 सिंह को विश्वास हो गया कि कांग्रेस का वे ही जवाब है ।वामपंथी हमेशा भाजपा के साथ मित्रता के आरोप से इनकार करते रहे, खासकर तब जब यह स्पष्ट हो चला कि भाजपा को 1989 के चुनाव समझौतों से सबसे अधिक फायदा हुआ है । लेकिन साथ ही, वे भाजपा के साथ वी0 पी0 सिंह के तालमेल के प्रति पूरी तरह वाकिफ थे । इलाहाबाद की जीत की खुशी में आयोजित एक जन-सभा में, जिसमें वी0 पी0 सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक ही मंच पर भाषण दिया, ज्योतिबसु की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए वी0 पी0 सिंह की जीवन-लेखिका सीमा मुस्तफा के अनुसार "इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि वी0 पी0 सिंह अकेले ही भाजपा के साथ 'समझौते के लिए जिम्मेदार नहीं थे,और छिपे तौर पर उन्हें वामपंथी का समर्थन हासिल था । वास्तव में, वाम पार्टियों ने वी0 पी0 को बताया कि वे भाजपा के साथ उनके समझौते का विरोध नहीं करेंगे । तथा वे इसका खुलकर समर्थन भी नहीं कर पायेंगे ।[76]

वामपंथी और वी0 पी0 सिंह समझते थे कि 1977-79 के समान भाजपा को अधिक फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोई स्वतन्त्र शाक्ति नहीं थी । दूसरी ओर भाजपा साथ बनी रही । इसके लिए उसने ऐसे अपमान के घूँट भी पी लिए जिसे एक कम अनुशासन वाली पार्टी के कार्यकर्ता पीने में असमर्थ होते । भाजपा को विश्वास था कि सत्ता पाने के लिए कांग्रेस को हटाया जाना जरुरी था । वाम और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ सहयोग ने इसे वह सम्मान दिया

---

75 - बिपिन चन्द्र "आजादी के बाद का भारत,1947-2000" पृष्ठ 378-379

76 - सीमा मुस्तफा, द लोनली प्रोफेट - वी0 पी0 सिंह, एक पोलीटिकल बायोग्राफी, नई दिल्ली, 1995, पृष्ठ 120

जो इसके पास नहीं था, इससे संप्रदायवाद का दाग मिटाने में मदद मिली । इस दाग ने भाजपा को भारतीय राजनीति के हाशिये तक ही सीमित कर रखा था । यह दाग इसे आजादी के संघर्ष के दिनों से ही इस पर धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवादियों ने लगाया था । भाजपा ने अपनी सीटें 1984 में 2 से 1989 में 86 तक बढ़ा ली ।इससे वह सत्ता के रास्ते पर आ गयी, जो उसे 1998 में मिली।"1989 में विकसित सहयोग बिना शक भाजपा के उदय के लिए जिम्मेदार कारकों में एक था ।"[77]

विरोधी पक्ष की एकता की रणनीति को तीन चरणों में देखा गया । प्रथम मंजिल गैर-कांग्रेस धर्मरिपेक्ष राष्ट्रीय पार्टियों की एकता थी, दूसरी मंजिल सभी गैर-वामपंथी धर्मनिरपेक्ष स्थानीय और राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण थी, और तीसरी मंजिली थी वाम पार्टियों एवं भाजपा के साथ सीटों का तालमेल । दूसरी मंजिल पहले पूरी हुई ।इसमें सात पार्टियों के राष्ट्रीय मोर्च का निर्माण 6 अगस्त 1988 को हुआ । 11 अक्टूबर 1988 अर्थात जय प्रकाश नारायण के जन्म दिन के अवसर पर "जनता दल " का निर्माण हुआ । यह जनमोर्चा, कांग्रेस(एस), जनता पार्टी और लोकदल के विलय से बना । तीसरी मंजिल तब आयी जब जनता दल के नेतृत्व वाले राष्ट्री मोर्चा और भाजपा ने उन 85 सीटों पर आपस में नहीं लड़ने का निर्णय किया जहाँ वे अन्यथा लड़ते । कुछ सीटों पर इसी प्रकार का इन्तजाम राष्ट्रीय मोर्चा और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच हुआ ।

7-राष्ट्रीय मोर्चा सरकार :(1989-90 ई0)

1989 के आमद चुनाव में कांग्रेस को करारी चोट लगी थी, फिर भी वह सबसे बड़ी पार्टी थी, और उसे 197 सीटें तथा 39.5 फीसदी वोट मिले थे ।राजीव गाँधी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस को सरकार बनाने कोई दिलचस्पी नहीं है । वाम पार्टियों और भाजपा ने तुरन्त घोषणा कर दी कि वे बाहर से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को समर्थन देंगे ।इस प्रकार आजादी के बाद दूसरी गैर-कांग्रेस सरकार के निर्माण की तैयारी हो गयी । राष्ट्रीय मोर्चे को 146 सीटें मिली और उसे भाजपा के 86 तथा वामपंथी पार्टियों के 52 सदस्यों का समर्थन मिला ।

शुरुआत अच्छी नहीं रही । चन्द्रशेखर, वी0 पी0 सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के बिल्कुल खिलाफ थे, और देवी लाल ने जोर दिया कि उन्हें कम से कम उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। चुनाव

---

77 - वही, पृष्ठ 129.

समाप्त होने के बाद हर तरह के मतभेद, विरोधी स्वार्थ, अति-अहं, विचारधारात्मक हित, उभर आये और बुरी तरह टकराने लगे। वी0 पी0 सिंह ने 2 दिसम्बर 1989 को बड़ी कठिनाई से प्रधान मंत्री की शपथ ली, और देवी लाल उप-प्रधान मंत्री बने। आपस में विश्वास की कमी बाद में खुलकर सामने आ गई। शपथ-ग्रहण समारोह में देवीलाल ने एक तरह से अपना मजाक ही बनाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शपथ में 'उप-प्रधानमंत्री' अवश्य जोड़ा जाए, मानों उन्हें विश्वास नहीं था कि प्रधान मंत्री अपने वादे पर टिके रहेंगे। राष्ट्रपति ने हल्के से उन्हें समझाया कि उन्हें 'मंत्री' ही कहना है।

वी0 पी0 सिंह ने बड़े ही ताम-झाम के साथ अपना काम शुरु किया। वे पंजाब गये, स्वर्णमन्दिर के दर्शन किये, और खुले जीप में घूमें, मानों दिखाना चाहते हो कि वे राजीव के समान भारी सुरक्षा में नहीं घूमते। कांग्रेस की नीतियों को बदलने के लिए काफी हल्ला-गुल्ला किया। लेकिन यह उनके प्रशासन की विशेषता रही कि भारी-भरकम शब्दों के कोई नतीजे नहीं निकले। उनके शासन काल के अन्त तक पंजाब की स्थिति वैसी ही बनी रही, और कश्मीर तो और भी बुरी हालत में पहुंच गया।उन्होंने जार्ज फर्नाडिस को कश्मीर मामलों की समिति का अध्यक्ष बनाया। लेकिन अरुण नेहरु और मुफ्ती मोहम्मद सईद को हस्तक्षेप करने की इजाजत देते रहे। और फिर बिना किसी से सलाह-मशवीरा के जगमोहन को कश्मीर का गवर्नर बना दिया। स्वाभाविक था कि कश्मीर के मुख्यमंत्री डा0 फारुख अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया।यह जगमोहन ही थे जिन्होंने 1983 में उनके खिलाफ विधायकों को तोड़कर उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अपनी आदत के अनुसार जगमोहन ने विधान सभा भंग कर दी। फिर बिना किसी से सलाह किये, वी0 पी0 सिंह ने उन्हें वापस बुला लिया, और उन्हें खुश करने के लिए राज्य सभा का सदस्य बना दिया' सच तो यह है कि श्रीलंका से भारतीय सेनाओं की वापसी पूरी करने तथा नेपाल के साथ व्यापार और आने-जाने संबंधी झगड़ों को निबटाने के अलावा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार अधिक कुछ न कर पाई। भाजपा और मुस्लिम नेताओं के साथ अपने संबंधो का इस्तेमाल भी वह अयोध्या विवाद के हल के लिए न कर पाई। उल्टे, लाल कृष्ण आडवाणी की रथयात्रा ने, सांप्रदायिक भावनाएँ भड़काने का काम किया, वैसे ही जैस मण्डल कमीशन ने जातीय भावनाएं असाधारण रुप से फैलाई।

सरकार को चल पाने में शायद इसलिए अधिक दिक्कत हो रही थी कि आन्तरिक मतभेदों को हल करने में इसकी शक्ति अधिक खर्च हो रही थी। चन्द्रशेखर ने प्रधान मंत्री के प्रति अपना विरोध नहीं छिपाया। फारुख अब्दुल्ला द्वारा इस्तीफा देते ही उन्होंने उसे समर्थन प्रदान किया। चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह को देवी लाल पसन्द नहीं करते थे। और देवी लाल को चन्द्रशेखर के अलावा लगभग सभी नापसन्द किया करते थे।देवी लाल ने 1967 में सबसे पहले उत्तरी भारत में किसान हितों को विशेष महत्व दिया। लेकिन वे अपने पुत्र ओमप्रकाश चौटाला को इतना पसन्द करते थे कि उन्हें स्वयं उप-प्रधान मंत्री बनने पर अपनी जगह हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। "महम" से चौटाला द्वारा चुनाव लड़ने की कोशिश में घोटाला हुआ। पूछताछ से पता चला कि चुनावों में बड़े पैमाने परे गड़बड़ी हुई, और वोटरों को डराया-धमकाया गया। चुनाव आयोग ने चुनाव खारिज कर दिया। चौटाला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तिफा दे दिया, लेकिन उन्हें दो महीने बाद फिर से पदासीन कर दिया गया। कम से कम आरिफ और अरुण नेहरु को यह ज्यादती लगी और उन्होंने सरकार से इस्तिफा दे दिया। इसका ध्यान रखकर वी० पी० सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन चौटाला के हटने के आश्वासन के बाद वे बने रहे। लेकिन 'ताऊ' देवी लाल की चाले खत्म नहीं हुई थी।उन्होंने आरिफ और अरुण नेहरु पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने 1987 में वी० पी० सिंह द्वारा राष्ट्रपति को कथित रुप से लिखा पत्र पेश किया जिसमें उन पर बोफोर्स कांड में शामिल होने का उल्लेख था वी० पी० सिंह ने घोषण की कि यह पत्र पूरी तहर जालसजी का कार्य था, उन्होंने 1 अगस्त 1990 को देवी लाल को बर्खास्त कर दिया।

देवी लाल चुप रहने वाले नहीं थें उन्होंने 9 अगस्त को नई दिल्ली में एक बड़ी किसान रैली का आवाह्न किया तांकि वे वी० पी० सिंह को अपनी ताकत दिखा दें। हालांकि वी० पी० सिंह ने इस बात से इन्कार किया कि वे इससे विचलित हो गये, और समझा जाता है कि इस स्थिति में उन्होंने अपने शासन का सबसे विवादास्पद निर्णय लिया। 7 अगस्त को उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट संसद में पेश की। यह कमीशन जनता सरकार (1977-79) ने नियुक्त किया था और इन्दिरा गांधी ने इसकी चुपचाप उपेक्षा कर दी थी। मण्डल की सिफारिशों में सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्रों में 27 फिसदी आरक्षण 'पिछड़ी जातियों' के लिए रखा गया। इस प्रकार आरक्षित श्रेणी 22.5 फीसदी से बढ़ाकर 49.5 हो गइ। पहले यह 22.5 फिसदी आरक्षण

जनजातियों या दलितों एवं आदिवासियों के लिए था ।सिफारिशों में दूसरा चरण भी था जिसमें आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं और पदोन्नति के लिए था ।[78]

इस घोषणा से व्यापक प्रतिक्रिया और गुस्सा पैदा हुआ । वे भी जो सिद्धांत रुप में इसके निर्णयों से असहमत नहीं थें, इस अचानक और मनमाने निर्णय से चकित थे । घोषणा करने से पहले वी0 पी0 सिंह ने अपने नजदीकी सहयोगियों तक से सलाह नहीं की । किसी न किसी कारण से इस निर्णय से बीजू पटनायक, आर0 के0 हेगड़े, यशवंत सिन्हा और अरुण नेहरु असंतुष्ट थे । वामपंथी पार्टियाँ और भाजपा नाराज थी क्योंकि इस निर्णय का उन्हें पता तक न था। देवी लाल और चन्द्रशेखर ने तीव्र भर्त्सना की । आलोचनाएं कई कारणों से की गयी : निर्णय का समय, सहमति बनाने की कोशिश का न होना, इसका विभाजनकारी चरित्र और पिछड़ी जातियां तय करने का गलत तरीका । सी0 पी0 एम0 चाहती थी कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो । इस विचार का समर्थन हेगड़े समेत कई नेताओं ने किया । प्रमुख समाजशास्त्रियों का विचार था कि पिछड़ी जातियों की पहचान का तरीका पुराना था, और आजादी के बाद हुए सामाजिक ढ़ांचागत परिवर्तनों का ध्यान नहीं रखा गया था । रिपोर्ट में जिन तबकों को 'पिछड़ी जातियां' कहा गया, वे भूमि सुधारों और हरित क्रान्ति से प्रमुख रुप से फायदे में रहे थे । इसलिए पिछड़ेपन के आधार पर उनका दावा शायद ही बनता था । इसमें शक नहीं कि कुछ अन्य तबके आर्थिक और सामाजिक रुप से पिछड़ी जातियों से अलग नहीं थे । उन्हें विशेष सुविधाएं देने की जरुरत थी । लेकिन उनकी पहचान अलग से और बड़ी सावधानी से करनी जरुरी थी,क्योंकि यदि उन्हें उन लोगों के साथ मिला लिया जाता तो जो केवल नाम के पिछड़े थे, तो उन्हें फायदा न होता ।[79]

मण्डल निर्णय का सबसे घातक पहलू इसका सामाजिक रुप से विभाजन कारी होना था। सामाजिक न्याय के नाम पर इसने जाति को जाति के विरुद्ध खड़ा कर दिया । इस कदम से जिन्हें हानि पहुँचती थी, उन्हें यह समझाने का प्रयास नहीं किया गया कि उन्हें व्यापक हित में इसे क्यों स्वीकार करने चाहिए ।इसने उन फायदे पाने वाले लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे विरोधियाँ को उच्च वर्गीय हितों का प्रतिनिधि बताएं इसने समाज के उन क्षेत्रों में भी जाति को सिद्धांत एवं पहचान के रुप में लागू किया जहाँ से वह लुप्त हो चुकी थी । इसके अलावा,यह अपेक्षा की जा रही थी कि संविधान में जनजातियों के लिए आरक्षण लागू करने के

[78] - बिपिन चन्द्र -"आजादी के बाद का भारत-1947-2000", पृष्ठ 381-82

[79] - विपिन चन्द्र- "आजादी के बाद का भारत" 1947-2000 , पृष्ठ, 383 ,

चालीस साल के बाद इसे आगे जारी रखने के संबंध में कम से कम कुछ विचार-विमर्श और बहस होती। इन आपत्तियों पर विचार करना आवश्यक था कि आरक्षण का जारी रहना जिन्हें जरुरत है उनके लिए नहीं बल्कि इन जातियों के विशेष ऊपरी तबकों के हक में था, सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए आरक्षण एकमात्र रास्ता नहीं था, बल्कि दूसरी रणनीतियां भी अपनायी जा सकती थी।[80] जाति पहचान की राजनीति जाति व्यवस्था से पीड़ित लोगों के बजाए नेताओं को फायदा पहुंचाती हैं-ये सभी विचारणीय विषय थे। इन प्रश्नों पर सामाजिक परिवर्तन संबंधी कदम उठाने से पहले व्यापक विचार-विमर्श करने की जरुरत थी।इसकी पुष्टि उत्तर भारत[81] में छात्र-समुदाय की तीव्र प्रतिक्रिया से हुई। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां छात्रों की बड़ी संख्या के लिए भविष्य है। अभी भी इसमें धन और प्रभाव की जरुरत नहीं होती। भर्ती प्रतियोगी परिक्षाओं के जरिए होती है। ऐसी स्थिति में आरक्षण के नाम पर करीब आधी सीटों को एका एक बंद किया जाना अन्याय पूर्ण था। उनकी नजरों में ऐसे कई लोग जिन्हें फायदा पहुंचता, आर्थिक और सामाजिक रुप से उनके बराबर या उनसे बेहतर थे। यह जनजातियों के आरक्षण से काफी अलग था उनकी सामाजिक एवं आर्थिक अक्षमता में कोई शक नही था, और आजादी के संघर्ष के दिनों से ही इस प्रश्न पर सामाजिक एक मत थे। इसके अलावा, छात्र इस निर्णय के पीछे छिपे राजनीतिक उद्देश्यों को पहचानते थे, क्योंकि इन पर स्वयं राष्ट्रीय मोर्चे के नेताओं के बीच बहस हो रही थी। मण्डल विरोधी आन्दोलन ने सार्वजनिक सम्पत्ति को बर्बाद करने, बसों के जलाने, रैलियों, सभाओं तथा प्रेस में बहस इत्यादि का रुप धारण किया। इसमें छात्र आगे थे, और अकसर ही उनका समर्थन समाज के अन्य तबके कर रहे थे, जैसे-अध्यापक, आफिस कर्मचारी और गृहणियां। उत्तर भारत के गाँवों और शहरों में कई घटनाएं घटी। दिल्ली, गोरखपुर वाराणसी, कानपुर तथा अन्य स्थानों में गोलीकाण्ड हुए। यह पाकर कि ये विरोध-प्रदर्शन प्रभावहीन साबित हो रहे हैं, सिम्बर के मध्य में कुछ छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की दोनों ओर गुस्सा तेज होने लगा। जो मण्डल के पक्ष में थे वे इसे बर्बर,कृत्रिम, यहाँ तक की दिखवटी बताने लगे, जो विरुद्ध थे वे इस प्रश्न पर संवेदना और समझदारी की कमी से चकित हो गयें। प्रधानमंत्री की अपीलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ समय तक मण्डल-विरोधी आन्दोलन का बड़ा हिस्सा जातिवाद के प्रभाव से मुक्त रहा। वास्तव में यह जाति को प्रमुख कारक मानने के

80 - ज्यो द्रेने और अमर्त्स सेन, इण्डियाः इकोनामिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपार्चुनिटी, दिल्ली, 1996, पृष्ठ 96-97

81 - बिपिनचन्द्र- "आजादी के बाद का भारत, 1947-2000", पृष्ठ 383-84

विरुद्ध था । लेकिन बाद में नकारात्मक रुझान पैदा हो गये । इसका एक कारण उन्हें ऊपरी जातियों से प्रेरित बताया जाता था । ऊपरी जाति के छात्र 'ऊपरी जाति संगठनों' में संगठित होने लगे । कालेजों एवं होस्टलों में तथा मेसों में जातिवादी व्यक्तियों का आदान प्रदान होने लगा । जो संस्थाएं कभी जातीय पहचान लुप्त होने का केन्द्र थीं, उन्ही में इसका पुनर्जन्म होने लगा । विरोध तब समाप्त हुआ जब उच्चतम न्यायालय ने 1 अक्टूबर 1990 को मंडल रिपोर्ट लागू करने पर रोक लगा दी ।[82]

इस बीच भाजपा अपनी योजना पर काम कर रही थी और मण्डल ने उसे बेहत मौका दे दिया । मण्डल का व्यापक विरोध देखकर भाजपा ने अपना समर्थन वापस लेने की बात शुरु कर दी । 25 सिम्बर को लालकृष्ण आडवाड़ी 6000 मील लंबी रथयात्रा पर निकले ।यह गुजरात में सोमनाथ से शुरु हुई, और राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए अयोध्या पहुंचनी थी । लेकिन 23 अक्टूबर को बिहार के मुख्य मन्त्री श्री लालू प्रसाद यादव समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार करवा लिये । गिरफ्तारी के साथ ही उनकी रथयात्रा समाप्त हो गयी । भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया । वी0 पी0 सिंह यदि भाजपा को संतुष्ट करते तो अपनी ही पार्टी ओर वामपंथी सहयोगियों को नाराज कर देते । इसलिए उन्होंने भाजपा के साथ संबंध तोड़ लेने का फैसला लिया । उत्तर प्रदेश में जब श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में उस भीड़ पर गोलियां चलायी गयी जो कानून को अपने हाथ में लेते हुए राममन्दिर के शिलान्यास तक उन्मादी तरीके से पहुंचना चाह रहे थे । आडवाणी की रथयात्रा और गिरफ्तारी तथा अयोध्या गोलीकाण्ड ने साम्प्रदायिक भावनाएं भड़का दी ।उत्तर भारत में कई जगह सांम्प्रदायिक दंगों में कई लोग मारे गये । 5 नवम्बर को जनता दल में फूट पड़ गयी । 58 सांसदों ने चन्द्रशेखर को अपना नेता चुना । 7 नवम्बर को गैर-कांग्रेस सरकार चलाने की दूसरी कोशिश ग्यारह महीनों बाद समाप्त हो गयी । 10 नवम्बर 1990 को चन्द्रशेखर की अल्पकालिक सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी । 5 मार्च 1991 को कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया तथा इसी के साथ 19 मई 1991 को चुनाव की घोषणा कर दी गयी ।

---

82 - बिपिन चन्द्र- "आज़ादी के बाद का भारत, 1947-2000", पृष्ठ 384-85

अध्याय—४

समाजवादी आन्दोलन का पुनर्गठन एवं सपा की भूमिका

अध्याय 4

समाजवादी आन्दोलन का पुनर्गठन एवं सपा की भूमिका

1-श्री मुलायम सिंह यादव का मुख्यमंत्री पद और कार्यक्रम

बोफोर्स और एच0 डी0 डब्ल्यू पनडूब्बी विवाद के चलते राजीव गांधी से अलग हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके जनमोर्चा के साथियों के विपक्ष में शामिल होते ही कांग्रेस विरोधी खेमे में नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह अपने क्रांति रथ के साथ विपक्षी एकता का प्रयोग कर रहे थे।इसी की देखा-देखी राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल का प्रयोग हुआ। इससे राजनीति की संभावनाएं खुलीं, पर कुछ चिंताजनक पहलू भी सामने आए।

विपक्षी एकता राष्ट्रीय राजनीतिक संकट को हल करने का एक फौरी नुस्खा था। 1987 के मार्च में इस राजनीतिक संकट की नींव पड़ी थी। जून तक आते-आते प्रतिरक्षा घोटालों ने राजीव सरकार को संदेह के दायरे में ला दिया। इस दौर की प्रमुख घटनाओं को इस तरह देखा जा सकता है-

30 जून 1987- हरियाणा चुनाव के बाद, "राजीव हटाओं" अभियान शुरू करते हुए लोकदल-भाजपा गठबंधन की दिल्ली रैली, जिसमें जनता पार्टी और तेलुगू देशम के नेता भी शामिल हुए।

16 अगस्त 1987- चार वामपंथी पार्टियों- सी0 पी0आई0, सी0 पी0 एम0, आर0 एस0 पी और फारवर्ड ब्लॉक की संयुक्त बैठक में राजीव गांधी के इस्तीफे और मध्यावधि चुनाव की मांग को लेकर धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के साथ संयुक्त अभियान चलाने का फैसला।

11 सितंबर 1987- कलकत्ता में सी0 पी0 एम, लोकदल (ब) और वी0 पी0 सिंह ग्रुप को साझा बैठक में विकल्प-निर्माण के सवाल पर विचार विमर्श।

23 सितंबर 1987- हरियाणा के सूरजकुंड में लगभग तमाम गैर-वामपंथी विपक्षी पार्टियों का सम्मेलन।

2 अक्टूबर 1987- वी0 पी0 सिंह ग्रुप द्वारा 'जन मोर्चा' नामक 'गैर-राजनीतिक' फोरम का गठन।

12 अक्टूबर 1987- वाममोर्चा की शक्तियों द्वारा दिल्ली में सांप्रदायिकता व पृथकतावाद विरोधी कन्वेंशन, जिसमें लोकदल (ब), तेलुगू देशम, कांग्रेस (स), जनमोर्चा और जनवादी पार्टी के लोग भी शमिल हुए।

12 नवंबर 1987- पटना में लोकदल (ब) की रैली, जिसमें भाजपा, जनमोर्चा, जनता पार्टी, असम गण परिषद और तेलुगू देशम के नेता भी शरीक हुए।

28 नवंबर 1987- जन मोर्चा, जनता पार्टी, लोकदल (अ) और कांग्रेस (स) द्वारा मिलजुल कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे का गठन।

9 दिसंबर1987- राजीव गांधी के इस्तीफे और मध्यावधि चुनाव की मांग के साथ, वाममोर्चा की शक्तियों द्वारा दिल्ली में रैली।

21 जनवरी 1988- वाममोर्चे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे की पार्टियों की साझा बैठक में 'भारत बचाओ दिवस' और 'भारत बंद' आयोजित करने का निश्चय।

23 जनवरी 1988- उपर्युक्त पार्टियों द्वारा राष्ट्रीय पैमाने पर 'भारत बचाओ दिवस' आयोजित। जिला और ब्लाक स्तर प्रदर्शन और रैली।

9 मार्च 1988- राजीव गांधी के इस्तीफे की मांग के साथ,लोकदल-भाजपा गठबंधन की दिल्ली रैली।

15 मार्च,1988- वाम मोर्चे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे के आह्वान पर 'भारत बंद', जिसे भाजपा को छोड़कर लगभग तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला।

6 अगस्त, 1988- को सात पार्टियों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चे का निमार्ण किया।

11 अक्टूबर, 1988- जय प्रकाश नारायण के जन्म दिन के अवसर पर 'जनता दल' का का निर्माण हुआ। यह जनमोर्चा कांग्रेस (एस), जनता पार्टी और लोकदल के विलय से बना।

इस घटनाक्रम से जाहिर है कि हिंदी इलाकों में मुलायम सिंह का संगठन लोकदल (ब) ही विपक्षी एकता का केंद्र था। जनता पार्टी और लोकदल (ब) नई एकीकृत पार्टी का मजबूत आधार बनी और जन मोर्चा व लोकदंल (अ) भी उसमें शामिल किए गए। हालांकि जनमोर्चा गुट अपनी अवसरवादी नीतियों के कारण कांग्रेस (इ) से टूट कर आया हुआ गुट था और उस पर यथास्थितिवाद की कांग्रेस विचारधारा ही हावी थी, किंतु परिवर्तन की आवश्यकता और जनभावना का सम्मान करते हुए उसें भी जनता दल में शामिल करना पड़ा। इस गुट में कुटिल

और चालबाज राजनीतिज्ञों की भरमार थी, जिन्होंने गठन के आरंभ में तो चुनावी फायदे के लिए बीजू पटनायक, देवीलाल, मुलायम सिंह, आदि जनाधार वाले नेताओं को आगे रखा, पर चुनाव के बाद अपनी जोड़तोड़ की राजनीति के माध्यम से दल पर अपना शिकंजा कसना और मुलायम सिंह यादव जैसे-वरिष्ठ समाजवादी व सिद्धांतनिष्ठ नेताओं के विरूद दुष्प्रचाार करना शुरू कर दिया। लेकिन समाजवादी नेताओं में राजनीतिक कौशल व जनाधार की कमी नहीं थी, इसलिए वे इस गुट की कुटिलतापूर्ण राजनीति को विफल बनाने में सक्षम थे।[1]

जनमोर्चा गुट की राजनीति का पहला उदाहरण नवंबर 1989 में चुनावी विजय के बाद राष्ट्रीय मोर्चा संसदीय दल के नेता पद का चुनाव ही था। यह चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से नहीं कराया गया और छल-प्रपंच से विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री पद पर आसीन कर दिया गया। नेपथ्य से खेले जा रहे सारे खेल की कमान अरूण नेहरू के हाथ में थी, जो पार्टी पर अपना शिकंजा कसने के लिए लगातार प्रयासरत थे। वे एक समय में राजीव गांधी के विश्वासपात्र रह चुके थे और उन पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप थें। उन्हें राजनीति में 'थैलीशाही' की स्थापना के लिए भी जिम्मेदार माना जाता था। ऐसे नेताओं का कोई जनाधार नहीं था पर परिस्थितियों के फेर से वे पार्टी राजनीतिज्ञों की अपनी पंक्ति में आ गए थे और सुयोग्य समाजवादी नेता उपेक्षित पड़े थे। उनकी गतिविधियों से दल में अविश्वास और संदेह की एक विभाजन रेखा खिंच गई थी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन से ही यह बात स्पष्ट हो गई कि जन मोर्चा गुट पार्टी को सामूहिक आधार पर चलने के बाजय अपनी जेब में रखना चाहता है। हालांकि जनता पार्टी व लोकदल की तुलना में जन मोर्चा की राजनीतिक शक्ति जनता दल के गठन से पहले तक बहुत कम थी, किंतु केद्रीय मंत्रिमंडल में जनमोर्चा गुट के सर्वाधिक 15 मंत्री लिए गए। इनमें प्रधानमंत्री के साथ-साथ गृह, विदेश, रक्षा, वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री शामिल थे। पार्टी संगठन में भी जन मोर्चा नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर बिठा दिया गया था।

विधानसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश व बिहार में नेता चुनने के सवाल पर भी जनमोर्चा गुट ने राजनैतिक शतरंज की गोटियां खेलनी चाही। अरूण नेहरू व आरिफ मोहम्मद खां को उत्तर प्रेदश व बिहार में अपनी सुविधा वाले व्यक्तियों को विधायक दल का नेता चुनवाने के लिए भेजा गया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव व लालू प्रसाद यादव को नेता चुने जाने से रोकने

---

1 - डा0 आर0 पी0 त्रिपाठी- मुलायम सिंह यादव रचना और संघर्ष, पृष्ठ 69
डा0 लोहिया ट्रस्ट का प्रकाशित द्वितीय संस्करण 1996, 1- विक्रमादित्य मार्ग, लखनाऊ

की हर संभव कोशिश की। उत्तर प्रदेश में अजित सिंह को मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में पेश किया गया। लेकिन वे अपने षड़यंत्र में सफल नहीं हो सके और दोनों राज्यों के विधायकों ने क्रमशः मुलायम सिंह व लालू प्रसाद यादव के पक्ष में स्पष्ट निर्णय दिया। उत्तर प्रदेश में जनता दल इकाई का अध्यक्ष चुने जाने के मामले में भी स्पष्ट, पक्षपात किया गया। हर राज्य में प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके लिए बाकायदा चुनाव कराए गए। यह बात और है कि मुलायम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनने से फिर भी नहीं रोका जा सका।

पांच दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ के दिग्विजय सिंह बाबू स्टेडियम में हजारों आम लोगों की उपस्थिति में शपथ ली। उनके सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गौरवपूर्ण सिंहासन था और आगे का रास्ता बहुत आसान नहीं था। उन्हें अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारों से एक बदहाल उत्तर प्रदेश विरासत में मिला था। ऐसा राज्य, जिसमें अपने आकार की ही तरह विशाल समस्यओं की भरमार थी गरीबी, पिछड़ापन, बेकारी, अराजकता, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता आदि। सबसे बड़ी और निरंतर भयानक रूप लेती हुई समस्या थी सांप्रदायिकता की। पर पद संभालने के पहले ही दिन से श्री यादव की दृष्टि स्पष्ट थी। उन्हें अपने उत्तरदायित्वों का पूरा अहसास था और मुख्यमंत्री के रूप में उनका लगभग डेढ़ वर्ष का कार्यकाल यह साबित करता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को कितनी सफलता से निभाया।

मुख्यमंत्री के रूप में श्री यादव के सामने जनता की उन सब तकलीफों को दूर करने का स्वर्णिम अवसर था जिन्हें वे बरसों से देखते आए थे। जनता के प्रति अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों से बेखबर कांग्रेसी सरकारों के शासन काल में इन तकलीफों को दूर न होना श्री यादव को निरंतर विचलित करता रहा । ग्रामीण पृष्ठभूमि का होने और शोषित वर्ग की तकलीफों को करीब से जानने-समझने के कारण उन्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करने में विशेष परेशानी नहीं हुई। शासन में आने से पहले भी विपक्ष के नेता के रुप में उन्होंने पिछड़े और गरीब तबके के लिए निरंतर आवाज उठाई थी। इस वर्ग के विरूद्ध होने वाली किसी भी प्रमुख घटना की खबर मिलने पर वे संबंधित स्थान का दौरा करते थे और पीड़ित वर्ग का पक्ष मजबूती से सरकार के समक्ष रखते थे। सत्ता में आने के बाद भी उनके जनसेवा के इस दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं आया।

मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले ही भाषण से श्री यादव का नजरिया स्पष्ट हो गया। वे उन राजनीतिज्ञों में से नहीं थे जिनके जनता के प्रति सीमित सरोकार है और जो सत्ता में आते ही

जनता को भूल जाते हैं। गांव-गांव से आए हजारों उत्साहीं लोगों को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा था," आज लोहिया जी का सपना पूरा हो गया। किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है। मैं संपूर्ण क्षमता से इन भोले-भाले लोगों का कल्याण करने का प्रयास करूगा।"

जिस समय श्री यादव ने मुख्यमंत्री पद संभाला उससे पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दंगे हो चुके थे और सांप्रदायिक व पुनरूत्थानवादी ताकतों ने पूरे देश को विवेकहीन सांप्रदायिक उन्माद की ओर धकेल दिया था।

लंबे अरसे से ठंडे पड़े अयोध्या विवाद को नए सिरे से उठाया गया था। इतना ही नहीं, उसे हिंदू समाज की अस्मिता का प्रश्न बनाकर प्रदेश के लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा था। ये शक्तियां अपने एक पक्षीय व हठधर्मितापूर्ण रवैए पर अड़ी हुई थीं और अपने आपको कानून की परिधि से भी ऊपर मानने लगी थीं। पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकार ने भी राजनैतिक स्वार्थ वश उन्हें परोक्ष प्रोत्साहन दिया।

मुख्यमंत्री के रूप में कानून और व्यवस्था संबंधी जिन जटिल समस्याओं से श्री यादव को जूझना था उनमें महेंद्र सिंह टिकैत का तथाकथित किसान आंदोलन भी एक था। कुछ वर्ष पहले किसानों की कुछ समस्याएं उठाने के नाम पर शुरू हुआ यह आंदोलन तब तक विकृत और अनियंत्रित रूप ले चुका था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में टिकैत के समर्थकों ने एक नये किस्म का उग्रवाद शुरू कर दिया था और प्रशासन के अधिकारों को ही नकारने लगे थे। अराजकता का आलम यह था कि उस क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों के घूसने तक पर टिकैत के लोगों ने रोक लगा दी थी।

श्री यादव की सरकार को पिछली सरकारों से और भी अनेक समस्याएं उपहार में मिलीं। ये समस्याएं समाज के लगभग हर वर्ग से जुड़ी हुई थीं। इनमें बेरोजगारी की समस्या सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य मे, जो जनसंख्या की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा राज्य है, बेरोजगारी की संख्या भी किसी अन्य राज्य से कम नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी वजहें अशिक्षा, सरकारी नौकरियों के प्रति अनावश्यक लालसा, पर्याप्त अवसरों का अभाव और सरकारी प्रोत्साहन का अपर्याप्त होना था। युवकों का एक बहुत बड़ा वर्ग सुशिक्षित होने के बावजूद दर-दर भटकने पर मजबूर था। राज्य के इतने विशाल व शक्तिशाली जन संसाधानों का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। इस वर्ग का आक्रोश अपराधों में वृद्धि के रूप में सामने आ रहा था।

पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की स्थिति दयनीय थी, दलित वर्ग को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं था और उस पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। आर्थिक दृष्टि से भी वह अत्यंत निर्बल था और राजनीतिक दृष्टि से भी किसानों की हालत भी कोई बहुत संतोषजनक नहीं थी। बिजली की पर्याप्त आपूर्ति न होने और सिर पर कर्ज का भारी बोझ होने से वे परेशान थे। दूसरी ओर उन्हें अपनी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पा रहा था।

गाँवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच विष्मताएं मौजूद थीं। विशेषतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की गति बहुत कमजोर थी। वहां सड़कों, विद्यालयों, अस्पतालों जैसी आवश्यक सुविधाएं भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थीं। कई इलाकों में पेयजल व राशन संबंधी कठिनाइयां थीं। इसी परिप्रेक्ष्य में वहां पृथक राज्य के निमार्ण के लिए उत्तराखंड आंदोलन शुरू हो गया था और राजनैतिक स्वार्थवश कई राजनैतिक शक्तियों ने उसे समर्थन भी दे दिया था। गांवों की हालत बदतर थी तो शहरों के हाल भी बहुत अच्छे नहीं थे।

इस सरकार को भ्रष्टचार की समस्या से भी निपटना था। प्रायः हर विभाग से कर्मचारियों व अधिकारियों के भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने की शिकायतें मिल रही थीं। जनता के प्रति पुलिस का दृष्टिकोंण 'सेवक' का नहीं था, बल्कि वह आतंक का पर्याय बन चुकी थी। श्री यादव ने ऐसे समय पर राज्य की बागडोर संभाली थी जब उनके सामने चुनौतियों व समस्याओं के सिवाय कुछ भी नहीं था। यह परिस्थिति किसी भी नए मुख्यमंत्री का उत्साह भंग कर देने के लिए काफी थी, पर मुलायम सिंह ने चुनौतियों से डर कर पीछे हटना नहीं सीखा। उन्होंने महात्मा गांधी, जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए तमाम चुनौतियों को जीवटता से स्वीकार किया। इससे पहले 1977 में सहकारिता मंत्री के रूप में भी उन्होंने ऐसी चुनौतियों का प्रभावशाली जवाब दिया था और अपने कामकाज की विलक्षण शैली की छाप छोड़ी थी मुलायम सिंह ने इन भारी चुनौतियों का सामना कैसे किया ? इसका जवाब पाने के लिए उनके एक कट्टर आलोचक समीक्षक की कलम से लिखा गया सरकार के चार महीने के ब्यौरे का कुछ अंश देखिए-

"उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की जनता दल सरकार ने आखिरकार चार महीने पूरे कर लिए। ये चार महीने शांति से नहीं गुजरे। इनमें वह सब कुछ हुआ जो घटकवाद में गले

तक डूबी जनता दल सरकार में संभव था। फिर भी जनता दल सरकार चल रही है। यह मुलायम सिंह यादव का सौभाग्य और उपलब्धि दोनों है। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से अपनी सरकार का कामकाज दिखाने के लिए कम से कम छह महीने मांगे थे, लेकिन शायद ही कोई राजनीतिक प्रेक्षक हो जो यह मानता हो कि पिछले चार महीने में जद सरकार की जो कार्यशैली थी, वह अगले दो महीने में बदल जाएगी। वास्तव में जनता दल के अंदर उन्हें वास्तविक चुनौती लोकदल (अजित) घटक से ही मिलती रही है। अजित सिंह को हराकर उन्होंने कई विवादों को उठाने और लंबे समय तक दल के अंदर से चुनौती मिलने से खुद को बचा लिया। इससे उनका दल में दबदबा बढ़ा और खुद का संघर्षशील आत्मविश्वास मजबूत हुआ।

"मुलायम सिंह ने जब कुर्सी संभाली तो उतने तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से राजनीतिक प्रेक्षकों ने यही सवाल पूछा कि केंद्र सरकार की तरह यह सरकार कितने दिल चल पाएगी। यह ठीक है कि टिकाऊपन के बारे में जितने ज्याद और तीखे सवाल केंद्र के बारे में हैं, उतने लखनऊ की सरकार के बारे में नहीं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि लखनऊ की सरकार का भविष्य अनिवार्य तौर पर दिल्ली के भविष्य से जुड़ा हुआ है।उत्तर प्रदेश ही वह नया कुरूक्षेत्र है जहां दिल्ली और लखनऊ के भविष्य को तय होना है। इसलिए यह मानना भूल होगी कि दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियों, दांवपेंच, घात-प्रतिघात और उठापटक का सीधा असर लखनऊ पर नहीं पड़ेगा।

"आज जनता दल की जो स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। एक दल के रूप में वह खस्ताहाल है। किसी सांगठनिक ढांचे के बगैर वह आज तक घटकवाद के सहारे चल रहा है। जनता दल के राज्य अक्ष्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाए रखने की लड़ाई में फिलहाल, उन्होंने वी0 पी0 सिंह के दांव राजपूजन पटेल को देवीलाल, अजित सिंह और चंद्रशेखर के सहयोग से चित कर दियां घटकों की आपसी लड़ाई में जैसे दिल्ली में वी0 पी0 सिंह 'सर्वमान्यता' का कवच धारण किए हुए हैं वैसे ही लखनऊ में मुलयाम सिंह, वह खुद को 'कठपुतली' सरकार में नहीं बदलना चाहते, वह अपनी स्वतंत्र छवि और स्वतंत्र आधार के निर्माण के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें आपस में जूझते नरेशों और कमजोर केंद्र के कारण इसका मौका भी मिल रहा है और दिक्कतें भी झेलनी पड़ रही हैं।

"बेशक, मुलायम सिंह लंबे संघर्ष के बाद लखनऊ की कुर्सी तक पहुंच पाए हैं। इटावा के डाकू पीड़ित इलाके का एक शिक्षक धीरे-धीरे उतार-चढ़ाव के बीच यहां तक पहुंचा। वे गर्व से बताते हैं कि वे लोहिया और चरण सिंह के शिष्य हैं। आज से तीन वर्ष पहले जब मुलायम सिंह लोकदल पर कब्जे के सवाल को लेकर हुए संघर्ष में चौधरी साहब के परिवार के खिलाफ खड़े हुए और नतीजे में विपक्षी दल के नेता का पद खोना पड़ा, तबसे अब तक उनका संघर्ष ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लाया। उन्होंने ही चौधरी साहब के आधार पर अपना नेतृत्व स्थापित किया। इसीलिए वे नेता पद के चुनाव में नौसिखिए अजित सिंह को चित्त करने में सफल हुए।

"उन्होंने नेता पद का चुनाव जीतने के बाद जो 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया, वह हालांकि घटकों के प्रतिनिधित्व पर बना है, लेकिन शायद ही उसमें से कोई मंत्री उनके कद का है। अधिकांश की निष्ठा मुलायम सिंह के साथ है और मंत्रिमंडल पर उनकी छाप है। उनमें से कोई उन्हें चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। वे खुद 44 विभागों को देख रहे हैं और साथ ही अन्य मंत्रियों पर भी कड़ी नजर रखते है। महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाएं खुद करते हैं। जैसे उन्होंने 26 मार्च को जब अग्रेजी हटाने' जैसी महत्वपूर्ण नीतिगत घोषाणएं की तो उनके बारे में शिक्षामंत्री सच्चिदानंद वाजपेयी को कोई सूचना तक नहीं थी। बिजली, गृह, उद्योग, वित्त, परिहवन जैसे महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने अपने कब्जे में रखे हैं।[2] वाराणसी के छात्र नेता आनंद प्रधान मुलायम सिंह के प्रशंसकों में से नहीं है। 'समकालीन जनमत' (बिहार) में छपी उनके द्वारा लिखी इस आवरण कथा के अंश बताते हैं कि उन दिनों मुलायम सिंह से सिद्धांतः सहमत ने होते हुए भी उनकी आलोचना करना कितना काम था।

दरअसल मुलायम सिंह यादव की सरकार व्यवस्था परिवर्तन और विकास का संकल्प लेकर सत्ता में आई थी। प्रेदश की जनता ने सहकारिता मंत्री व विपक्ष के नेता के रूप में उनके प्रभावशाली कार्यों व जनसेवा के प्रति वास्तविक समर्पण को देखते हुए उन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ सत्ता के सिंहासन पर बिठाया था। मुलायम सिंह ने कुछ ही महीनों के भीतर राज्य का कायाकल्प प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सांप्रदायिकता की समस्या पर काबू किया, जो प्रदेश के विकास की राह में बहुत बड़ी बाधा थी। इसके बाद तो प्रदेश में जन कल्याण और विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। अपने सत्तारूढ़ होने के तीन-चार महीनों में ही मुलायम सिंह सरकार ने

---

2 - डा0 आर0 पी0 त्रिपाठी- मुलायम सिह यादव, रचना और संघर्ष,- पृष्ठ 76

प्रदेश की सामाजिक, प्रशासनिक, औद्योगिक व आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन कर दिखाया। उन्होंने समाज के निचले से निचले वर्गों और प्रदेश के उपेक्षित क्षेत्रों को भी विकास-प्रक्रिया में शामिल किया और उनकी समस्याओं का निदान किया। सरकार ने चुनाव से पूर्व जनता से किए गए वायदे पूरे करने की दिशा में भरपूर प्रयास किया। हालांकि सांप्रदायिकता, समाज परिवर्तन की विरोधी और जोड़तोड़ की क्षुद्र राजनीति में संलग्न शक्तियों ने समय-समय पर समस्याएं उत्पन्न कर प्रदेश में विकास के चक्र को अवरूद्ध, करना चाहा। किंतु इससे श्री यादव की कर्त्तव्य भावना और दृढ़ संकल्प में कोई कमी नहीं आई।

सांप्रदायिकता निवारण की मुहिम के अंतर्गत मुलायम सिंह यादव ने दंगों को होने से पहले ही रोकने के प्रयास किए। उन्होंने घोषणा की कि दंगों के लिए उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा। यह उनकी दिखावटी चेतावनी ही नहीं थी, बल्कि मार्च 1991 में उन्होंने गोंडा के डीएम और बिजनौर के एसएसपी को भी इसी कारण हटाया था, सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मुअत्तल भी कर दिया था। सरकार ने इन दोनों अधिकारियों की लापरवाही की जांच के लिए अलग-अलग जांच भी बैठा दी।

14 जनवरी को प्रतापगढ़ में हुइ एक 'फर्जी मुठभेड़' में पुलिस वालों ने तीन ग्रामीणों को मार डाला था। राज्य सरकार ने इस घटना के दोषी 12 पुलिस कर्मचारियों को, जिनमें एक पुलिस उप अधीक्षक भी था, मुअत्तल कर दिया।

प्रदेश सरकार ने जनवरी 1991 में भारत में पहली बार दंगे रोकने के लिए विशेष शांति सुरक्षा बल के गठन का फैसला किया। इसमें सात बटालियनें तैनात की जानी थीं। इस पुलिस बल को 'सामाजिक, जातीय और सांप्रदायिक तनाव क़ी चुनौतियों' का सामना करना था और इस पर 56 करोड़ रूपये की लागत आनी थी। शांति सुरक्षा बल को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसका पर्यवेक्षण कार्य राज्य के पुलिस महानिदेशक को सौंपा गया और इसमें भर्ती होने वाले जवानों की सेवा अवधि 45 वर्ष की उम्र तक की रखी गई। उत्तर प्रदेश के इस फैसले की देश भर में सराहना की गई और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक दंगा विरोधी सुरक्षा बल के गठन का प्रस्ताव आया।

प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया गया और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को दंडित किया। गया प्रशासन को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी और कर्त्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए योग्य व ईमानदार अधिकारियों कों पदोन्नतियाँ व पुरस्कार दिए गए।

मुलायम सिंह के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र से वर्ष 1990-91 के लिए वार्षिक योजना के लिए 33 अरब 70 करोड़ रूपये की राशि मंजूर कराने में सफलता प्राप्त की, जबकि इससे पिछले वर्ष में यह राशि 29 अरब 70 करोड़ रूपये ही थी। योजना राशि में से 52 प्रतिशत परिव्यय ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु निर्धारित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों का पिछड़ापन मिटाने और वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए। डा0 राममनोहर लोहिया का सपना पूरा करने के लिए खेतिहर मजदूरों और भूमिहीनों में भूमि के विवरण के लिए 16 जिलों में भूमि सेना का गठन किया गया। इसके तहत बंजर, ऊपर व बीहड़ भूमि का विकास किया जाना था।[3]

मुलायम सिंह सरकार महात्मा गांधी, डा0 राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण चौधरी चरण सिंह के सपनों को पूरा करने की दिशा में कार्यरत थी। इसीलिए उसने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और किसान, खेतिहर मजदूर व दस्तकार वर्ग के कल्याण के लिए अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए और कई घोषणाएं की। राज्य सरकार ने किसानों, खेतिहार मजदूरों व दस्तकार वर्ग के कल्याण के लिए अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए और कई घोषाएं की। राज्य सरकार ने किसानों, खेतिहार मजदूरों व दस्तकारों को दस हजार रूपये तक के ऋण माफ कर दिए जिससे सरकारी खजाने पर लगभग एक हजार करोड़ रूपये तक का बोझ पड़ा। इसका लाभ 49.66 लाख व्यक्तियों को मिला। एक अप्रैल 87 से 30 नवंबर 89 तक 32 माह की अवधि के निजी नलकूप मालिकों के करीब 200 करोड़ रूपये के बिजली बकाए माफ कर दिए गए। बिजली की कमी के बाजूद ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई।

किसानों की लंबे समय से चली आई मांगे पूरी करते हुए प्रदेश सरकार ने गन्ने के खरीद मूल्य में भारी वृद्धि आठ रूपये प्रति क्विंटल और 1991 में तीन रूपये प्रति कुन्तल रही। इससे 29 लाख गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचा। गन्ना किसानों को चीनी मिल से गन्ने के मूल्य का

---

3 - डा0 आर0 पी0 त्रिपाठी- मुलायम सिंह यादव, रचना और संघर्ष पृष्ठ 80

समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया। 1990 के पेराई सत्र में 1256 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया, जबकि इससे पिछले सत्र में 713 करोड़ रुपए ही दिए गए थे।

दिसंबर 1989 के पश्चात उत्तर प्रेदश में लगभग 52 हजार भूमिहीनों को 17.8 हजार हेक्टेयर भूमि वितरित की गई। इसी अवधि में एक लाख से अधिक परिवारों को आवास स्थल भी आवंटित किए गए। 90 करोड़ रूपये की दैवी आपदा निधि की स्थापना की गई एवं ओला वृष्टि से फसल के नुकसान पर काश्तकारों को 300 रूपये प्रति एकड़ की दर से राहत राशि का भुगतान किया गया। कृषि क्षेत्र में शोध कार्य को सुनियोजित ढंग से संपादित कराने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का गठन किया गया।

मुलायम सिंह सरकार ने प्रदेश में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए भी प्रयास किए। जिन क्षेत्रों में विकास की गति कमजोर थी और जो बरसों से उपेक्षित पड़े थे, उनके लिए राज्य सरकार ने 1990-91 और 1991-92 के बजट में विशेष प्रावधान किए। पूर्वांचल विकास निधि में 1990-91 में 20 करोड़ व अगले वर्ष 30 करोड़ :पए की राशि की व्यवस्था की गई। पूर्वांचल के मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, बहराइच व इलाहाबाद के जमुनापार (नैनी क्षेत्र को छोड़ कर) में स्थापित की जाने वाली निर्दिष्ट औद्योगिक इकाइयों को बिजली के बिलों में 20 प्रतिशत की छूट दी गई। बुंदेलखंड में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों को पांच वर्ष के लिए बिजली के बिलों में 50 प्रतिशत की छूट दी गई।

राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को भी प्राथमिकता के तौर पर लिया। इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत का आरक्षण किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 90-91में 330 करोड़ रूपये और 91-92 में 375 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया। 610 मीटर से अधिक़ ऊंचाई पर स्थापित होने वाली औद्यौगिक इकाईयों को पांच वर्ष के लिए बिजली के बिलों में एक तिहाई छूट दे दी गई। पर्वतीय क्षेत्र के पारंपरिक ऊन उद्योग के विकास के लिए ऊन बैंक की स्थापना की गई, जिसमें 12 हजार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए। पर्वतीय क्षेत्रों में रेशम उद्योग के विकास के लिए देहरादून जनपद में विश्व बैंक की सहायता से 4.5 करोड़ रूपये की परियोजना लगाई गई। इन इलाकों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए नए पर्यटन नगर विकसित करने की दूरगामी योजना तैयार की गई।

मुलायम सिंह सरकार सामाजिक न्याय के वायदे के साथ सत्ता में आई थी। उसने अपना वायदा निभाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जिनमें पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में 27 प्रतिशत अरक्षण की व्यवस्था करना शामिल है। इतना ही नहीं, सामान्य जातियों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को भी राज्य सरकार की नौकरियों में 8 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई। महिलाएं लंबे समय से उपेक्षित रही हैं। मुलायम सिंह सरकार ने देश में पहली बार उनके लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की । पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई।

शासकीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कोटे को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। डा0 अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के लिए सौ करोड़ रूपए की राशि मंजूर की गई। 9,563 अनुसूचित जाति बहुल गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए 'अंबेडकर ग्राम' योजना चलाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के परिवारों हेतु एक लाख से अधिक आवास उपलब्ध कराए गए। अनुसूचित जाति-जनजाति के सौ-सौ छात्र-छात्राओ को हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर डा0 अंबेडकर निधि से 250 रूपये व 350 रूपये की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। इन जातियों की छात्राओं को 240 रूपये मासिक की दर से भरण-पोषण अनुदान मंजूर किया गया। इस तरह प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अल्पसमय में ही आशाजनक कार्य हुआ जिसकी देशभर में प्रशंसा की गई।

मुलायम सिंह सरकार ने निर्बल वर्गों को सामाजिक सुरक्षा दिलाने की दिशा में कई कदम उठाए। विधवाओं,विकलांगों व वृद्धों को मिलने वाली पेंशन की दर 60 रुपए की जगह सौ रूपए प्रतिमाह कर दी गई। 12,46,772 निराश्रित विधवाओं को पेंशन के भुगतान हेतु 29.53 करोड़ की व्यवस्था की गई। 53 हजार विकलांगों के भरण-पोषण हेतु 7.45 करोड़ रूपये मंजूर किए गए। प्रदेश भर में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पांच लाख व्यक्तियों तक पहुंचाया गया। इस पर हर वर्ष 60 करोड़ :पए का खर्च आया। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 401 रूपए प्रतिमाह से बंढ़ाकर 500 रूपए कर दी गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं के लिए सौ :पए प्रतिमाह पेंशन की व्यवस्था की गई जिससे 35 हजार परिवार लाभांवित हुए। रिक्शा-आटो रिक्शा चालकों व मछली-पालकों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू की गई। होमगार्डो के लिए भी बीमा योजना शुरू की गई।

लगभग 13.5 लाख जरूरतमंद छात्रों के लिए 35 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति योजना लागू की गई। अनतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि एक हजार रूपए से बढ़ाकर दस हजार :पए कर दी गई। 35 वर्ष से कम उम्र की विधवाओं से विवाह पर 11 हजार रूपये के अनुदान की व्यवस्था की गई। प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक वर्ग को सुरक्षा उपलब्ध कराने और उसकी आर्थिक खुशहाली के लिए गंभीरता से प्रयासरत थी। उसने 57 हजार बुनकरों के 22 करोड़ रूपये के ऋण माफ कर दिए। दंगे रोकने के लिए शांति सुरक्षा बल की बटालियनें गठित की गई। 1984 में भड़के दंगों में मृत सिखों की विधवाओं की पांच सौ रूपये प्रतिमाह पेंशन दी गई। अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। निजी क्षेत्र के बुनकरों व रंगाई, छपाई करने वाले व्यक्तियों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ पहुंचाया गया। बुनकरों को उचित दर पर कच्चा माल उपलब्ध कराने व निर्मित माल की बिक्री बढ़ाने की व्यवस्था भी की गई।[4] सरकार ने युवकों के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए। वर्ष 1991-92 के बजट में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने हेतु 50 करोड़ रूपये की विशेष निधि को स्थापना की गई। रोजगार उत्पन्न करने के लिए हर विकास खंड में कम से कम 30 औद्योगिक इकाइयां लगाने का फैसला किया गया।

राज्य में महिलाओं के लिए नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायतों में 30 प्रतिशत पदों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया। महिला उद्यमियों को स्वरोजगार की ओर उन्मुख करने के लिए मार्जिन मनी ऋण योजना लागू की गई जिसके अंतर्गत 30 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई। श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण किया गया। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी एवं आगरा जनपद चुने गऐ। महिलाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम समर्थन योजना भी चलाई गई।

औद्योगिक विकास व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में चुंगी समाप्त कर दी गई। लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए तीन लाख लघु खादी व ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना का निर्णय किया गया। इनसें 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने मध्यम व बड़े उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहन दिया। औरैया में गैस क्रेकर परियोजना व पेट्रो-रसायन परिसर की स्थापना, बुंदेलखंड में तेलशोधक कारखाना, बांदा में फ्लोर ग्लास

4 - डा0 आर0 पी0 त्रिपाठी- मुलायम सिंह यादव, रचना और संघर्ष- पृष्ठ 84-85

परियोजना की स्थापना, आदि की दिशा में सरकार प्रयासरत रही। प्रदेश सरकार ने नोएडा की भांति जौनपुर-सतहरिया व गोरखपुर-सहजनवां में औद्योगिक क्षेत्र के विकास की भी योजना बनाई।

मुलायम सरकार की अन्य प्रमुखं उपलब्धियों में दो नये जनपदों पड़रौना व भदोही की स्थापना, कश्मीर से आये आर्थिक विस्थापितों के परिवारों को पुनर्वास हेतु प्रति परिवार 750 रूप ये की मासिक आर्थिक सहायता देना व चौकीदारों का वेतन 25 रूपये से बढ़कर सौ रूपए प्रतिमाह करना शामिल है। मुलायम सिंह सरकार ने समस्त प्रशासनिक कामकाज हिंदी में करने का ऐतिहासिक फैसला किया और प्रादेशिक सेवाओं में चयन के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी। साथ ही प्रदेश में दूसरे राज्यों की भाषाओं के पठन-पाठन हेतु आठ जनपदों में विशेष व्यवस्था की गई।[5]

2-बदलाव के लिए संघर्ष

उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू यादव, महाराष्ट्र में शरद पवार और तमिलनाडु में करुणानिधि की सरकार बन जाने का साफ मतलब था कि पहली बार राष्ट्रीय पैमाने पर एक गैर-ब्राह्मण राजनीतिक संस्कृति का उदय हो चुका है। ये सभी मुख्यमंत्री विभिन्न दलों के होने के बावजूद पिछड़े वर्ग के थे। इस परिस्थिति से बनने वाले राजनीतिक दबाव और घोषणा पत्र में लिखित मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाले वायदे का नैतिक दबाव प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को मजबूर कर रहे थे कि वे वह ऐतिहासिक कदम उठा ही दें जिसे कांग्रेस टालती आ रही थी। लोकदल के नेता के रूप में मुलायम सिंह मंडल सिफारिशों को लागू करवाने के लिए जेल यात्रा कर चुके थे।

मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का वायदा जनता दल के चुनाव घोषणा पत्र का प्रमुख तत्व था। सदियों से शोषित और सामाजिक दृष्टि से दयनीय जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग को मंडल आयोग की रपट में न्याय और सुखद भविश्य की आशांए दिखाइ दे रही थीं। आयोग ने अनुसूचित जाति व जनजाति के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी। जनता दल के चुनावी वायदों से इस तबके की जनता की आशाएं बंधी थीं और उन्होंने उसे सत्ता मे लाने में प्रमुख भूमिका निभाई। किंतु उसकी उम्मीदें जल्दी ही टूटने

---

5 - डा0 आर0 पी0 त्रिपाठी- मुलायम सिंह यादव, रचना और संघर्ष , पृष्ठ 86

लगीं, क्योंकि जनता दल नेतृत्व में बैठे सामंती तत्वो व कांग्रेसी विचारधारा से निकल कर आए लोग सामाजिक महापरिवर्तन की आंधी का सामना करने को तैयार नहीं थे। समाज के शोषित वर्ग के प्रति उनकी प्रतिबद्धताएं वोट बटोरने तक ही सीमित थीं और उनका कोई इरादा नहीं था। दूसरी ओर, मुलायम सिंह समेत समाजवादी पृष्ठभूमि वाले नेता इस दिशा में तत्काल कदम उठाए जाने के प्रबल समर्थक थे। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में पार्टी के नेतृत्व पर उनकी पकड़ नहीं थी, इसलिए अपनी तमाम चिंताओं के बावजूद के विवश थे।[6]

मंडल आयोग का गठन 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था और आयोग ने दिसंबर 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी रपट सौंप दी थी। श्रीमती गांधी वैसे तो दलितों व शोषितों की राजनीति करती थीं और अपने आपको इस वर्ग की सबसे बड़ी हितचिंतक के रूप में प्रचारित करती थीं, किंतु पिछड़े वर्ग के वास्तविक कल्याण हेतु प्रस्तुत की गई मंडल आयोग की सिफारिशों की उन्होंने पूरी तरह उपेक्षा की। उनके बाद सत्ता में आये उनके पुत्र राजीव गांधी ने भी इन्हें लागू करने की कोई परवाह नहीं की। इसे देखते हुए जनता पार्टी व लोकदल ने पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष छेड़ा और मुलायम सिंह ने इसमें विशेष भूमिका निभाई। दूसरी ओर जनमोर्चा की पृष्ठभूमि वाले नेताओं ने, जो उस समय कांग्रेस सरकार में जिम्मेदार पदों पर कार्यरत थे और सरकार की नीतियों पर प्रभाव डालने की स्थिति में थे, इस मामले में चुप्पी साधे रखी। पूरे दस वर्ष की अवधि में उन्होंने आयोग की सिफारिशों के समर्थन में दो शब्द भी नहीं कहे और चुपचाप सत्ता का सुख भोगते रहे। बाद में यही नेता मजबूरी में कांग्रेस (इ) छोड़ कर जनमोर्चा में और फिर जनता दल में आये तो उनकी मूलभूत विचारधारा में कांग्रेसी और सामंती तत्व ज्यों के त्यों मौजूद थे। यह अलग बात थी कि तत्कालीन परिस्थितियों में जनता दल पर उनका नियंत्रण मजबूत हो गया था।

जनता दल में सत्तारूढ़ होने के बाद भी जब मंडल आयोग की रपट की उपेक्षा जारी रही तो पिछड़े व दलित वर्गों में निराशा व आक्रोश की भावना पैदा हुई। जनता की आकांक्षाओं को धूमिल होते देखकर समाजवादी नेताओं का चिंतित होना स्वाभाविक था। उन्होंने केंद्र सरकार पर आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए दबाव डाला। मुलायम सिंह व अन्य नेताओं का मानना था कि इन्हें लागू किए बिना पिछड़े वर्ग को वास्तविक सामाजिक न्याय दिलाना संभव नहीं है और

---

6 - डा0 आर0 पी0 त्रिपाठी- मुलायम सिंह यादव, रचना और संघर्ष, पृष्ठ 102

जन आक्रोश को खाली आश्वासनों के सहारे दबाया नहीं जा सकता । वे प्रख्यात समाजवादी नेता डा0 राममनोहर लोहिया के सिद्धांतों के अनुगामी थे, जिन्होंने पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिये जाने को परिवर्तन के औजार के रूप में सदैव समर्थन किया। जनता दल नेतृत्व ने जब बहुसंख्यक वर्ग की आकांक्षाओं की उपेक्षा जारी रखी तो मुलायम सिंह को जनता से कहना पड़ा कि शायद अब भी उसे अपने लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है, हालांकि अब केंद्र में कांग्रेस (इ) की सरकार नहीं रह गई है। यह अजीब विडंबना है कि मंडल आयोग की रपट की घनघोर उपेक्षा करने और उसे अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करने वाले नेता आज पिछड़ों के सबसे बड़े हितचिंतक होने का दावा कर रहे हैं।

जनता दल सरकार का कामकाज करने का लापरवाही भरा ढर्रा, जनता की आकांक्षाओं के प्रति उपेक्षा भाव और जनाधार व सिद्धांत वाले नेताओं का प्रभाव सीमित करने की कोशिशों के कारण जनता दल में असहमति की आवाजें उठने लगीं। तत्कालीन उपप्रधानमंत्री देवीलाल ने ग्रामीण भारत व किसानों की उपेक्षा का मुद्दा उठाया और समाजवादियों ने पिछड़े वर्ग के लिए न्याय मांगा। लेकिन जोड़-तोड़ व सिद्धांतहीनता की क्षुद्र राजनीति में विश्वास रखने वाले जनमोर्चा गुट के नेताओं ने, जिनके साथ में पार्टी नेतृत्व का दारोमदार था, इसे सकारात्मक भावना से नहीं लिया। उन्हें लगा कि किसानों व पिछड़ों की बात करने वाले पार्टी नेताओं का राजनीतिक कद छोटा करने की जरूरत है, अन्यथा वे आगे चल कर लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच सकते हैं और ऐसी हालत में उनकी कुटिलतापूर्ण राजनीति विफल हो सकती है। पार्टी नेतृत्व की मनमानी का पहला शिकार उपप्रधानमंत्री देवीलाल हुए जिन्हें पहली अगस्त 1990 की रात को अपमानजनक ढंग से पद से हटा दिया गया।

देवीलाल ने नौ अगस्त को नई दिल्ली के बोट क्लब पर रैली का आयोजन करने की घोषणा की जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार को किसान शक्ति से परिचित कराना और किसानों की उपेक्षा समाप्त करने पर विवश करना था। यह रैली देवीलाल की राजनैतिक हैसियत और जनता में उनकी लोकप्रियता की परिचायक भी सिद्ध होने वाली थी। रैली को विफल करने, देवीलाल के उठायेसमस्त मुद्दों को अप्रासंगिक करार देने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की रपट लागू करने की घोषणा की जिसे तब तक उन्होंने पूरी तरह उपेक्षित कर रखा था। ऐसा करते समय उन्होंने धूर्त राजनीतिक चालबाजी और मनमानी का परिचय दिया

और सरकार के समर्थक दलों-भाजपा व कम्युनिस्ट पार्टियों से भी राय मशविरा करने की आवश्यकता नहीं समझी। इतना ही नहीं, उन्होंने इतना महत्वपूर्ण निर्णय पूरी तरह व्यक्तिगत रुप से लिया और उसे सरकार के सामूहिक फैसले का रूप नहीं लेने दिया। इसका कारण स्पष्ट था- श्री सिंह आयोग की रपट का संपूर्ण श्रेय स्वयं लेना चाहते थे। लेकिन उनकी इस स्वार्थवृत्ति का देश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।

सभी प्रमुख पार्टियों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के तौर-तरीकों का विरोध किया।हालांकि उनमें से कोई भी मंडल आयोग की रपट लागू किये जाने की खुलेआम आलोचना करने को तैयार नहीं, पर वे इस कार्य का संपूर्ण राजनीतिक श्रेय एक व्यक्ति विशेष को देने पर भी सहमत नहीं थें इसका परिणाम यह हुआ कि इन दलों ने सरकार और उसके फैसले का परोक्ष विरोध शुरू कर दिया। रातोंरात आरक्षण विरोधी संगठनों की फसल उग आई और संपूर्ण उत्तर भारत में हिंसक आंदोलन शुरू हो गया। सवर्ण वर्ग के निराश युवकों ने आत्मदाह करने शुरू कर दिये। इधर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के दो सदस्यों राम विलास पासवान और शरद यादव को पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में पेश किया और इस वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन उनके अदूरदर्शितापूर्ण व उत्तेजक बयानों ने आग में घी का काम किया। आरक्षण विरोधी आंदोलन दिन पर दिन जोर पकड़ता गया और राजधानी दिल्ली समेत देश के अनेक क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पंगु होकर रह गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्थिति में सुधार लाने या आंदोलनकारियों व अन्य राजनैतिक दलों से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उन्हें पिछड़े वर्ग की अधिक से अधिक सहानुभूति और समर्थन जुटा लेने का लालच था। उनका विचार था कि आंदोलन जितना भड़केगा, अगड़ी और पिछड़ी जातियों में विभेद जितना बढ़ेगा, पिछड़ी जातियां उसी अनुपात में उनके समर्थन में एकजुट होंगी।

मंडल आयोग का मुद्दा श्री सिंह के लिए राजनीतिक लाभ उठाने से अधिक कुछ नहीं था, यह बात बाद में उनके द्वारा की गई घोषणाओं से स्पष्ट हो गई। उन्होंने आयोग की सिफारिशें लागू करने का मामला राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया जिसके बाद उनकी अपनी पार्टी की ओड़ीशा सरकार ने ऐसी घोषणाएं कीं। श्री सिंह ने शिक्षण संस्थाओं व कई विशिष्ट सेवाओं को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने, पदोन्नतियों में आरक्षण लागू न करने जैसी घोषणाएं कीं जिनसे इस बारे में उनके इरादों पर शक पैदा होता है। इन घोषाणाओं से मंडल आयोग की रपट की

आत्मा ही नष्ट हो गई। और उनके उद्देश्य काफी सीमित हो गये। ये घोषणाएं श्री सिंह ने सामाजिक न्याय की विरोधी शक्तियों के तुष्टीकरण के लिए कीं। साथ ही उन्होंने उच्चतम न्यायालय से मंडल आयोग की रपट लागू करने पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाने का अनुरोध कर इस मुद्दे को लंबी अदालती प्रक्रिया के हवाले छोड़ दिया। इस तरह उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ किए बिना ही उसका समर्थन बटोरने की कुटिलतापूर्ण चालें चली दूसरी ओर मंडल आयोग के मामले में मुलायम सिंह का दृष्टिकोण एकदम अलग था। वे उसकी सिफारिशों के प्रबल समर्थक थे और उन्हें बिना किसी छेड़छाड के लागू करवाने पर जोर दे रहे थे। दूसरी ओर उनका यह भी मानना था कि इस मामले को इस तरह न उछाला जाए कि अगड़े वर्ग के नौजवानों में हताशा व आक्रोश फैले। शरद यादव व राम विलास पासवान ने जिस टकराव के अंदाज में भाषण दिए और पिछड़ों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया उसके वे पूरी तरह खिलाफ थे। मुलायम सिंह चाहते थे कि अगड़े वर्ग को मंडल आयोग की सिफारिशें स्वेच्छा से स्वीकार करने के लिए मनाया जाए। वे अपनी सभाओं में लोगों को समझाते थे कि पिछड़े वर्ग के साथ सदियों से अन्याय होता आया है और अब उसे अपने विकास का एक अवसर दिया ही जाना चाहिए। उच्च वर्ग को चाहिए कि वह उदारता से काम लेते हुए पिछड़े वर्ग को उसका जायज हक हासिल करने दे। मुलायम सिंह के विचारों का लोगों पर काफी असर पड़ा और प्रदेश में उसके विशाल आकार और जनसंख्या के अनुपात में उतनी हिंसा व उतने आत्मदाह नहीं हुए जितने कि अन्य प्रदेशों और दिल्ली में।

पिछड़े व हरिजन वर्ग को न्याय दिलाने के लिए मुलायम सिंह की प्रतिबद्धता कोई अचानक पैदा नहीं हो गई थी, बल्कि वे अपने राजनीतिक जीवन के आरंभ से ही इस लक्ष्य के प्रति समर्पित थे 1977 में जनता पार्टी की सरकार में सहकारिता मंत्री के रूप में जब उन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की तबभी उन्होंने इस दिशा में कदम उठाए थे। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक के माध्यम से उन्होंने सहकारी समितियों के चुनावों में हरिजन और निर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। इसी प्रकार जनता पार्टी के सत्ता से हटने के बाद उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करवाने के लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया था। जब जनता दल सरकार ने केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बाद संसद व विधानसभओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि दस वर्ष बढ़ाने के लिए कदम

उठाए तो श्री यादव ने उसका पूरा समर्थन किया। इसके खिलाफ उठे आंदोलनों का उन्होंने कठोर जवाब दिया।

जब केंद्र ने के मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का मामला प्रदेश सरकारों पर छोड़ दिया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कोई समय नष्ट किए अक्टूबर 1990 के पहले सप्ताह से राज्य सरकार की नौकरियों में कुल आरक्षण का कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 62 प्रतिशत कर दिया। राज्य में अनुसूचित जाति व जनजाति के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था चल रही थी जिसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि 15 प्रतिशत आरक्षण भी राज्य में जनता पार्टी की सरकार के समय 20 अगस्त 1977 को लागू किया गया था। यह व्यवस्था सरकारी नौकरियों में पदोन्नतियों के मामलों में भी लागू थी, पर 30 सितंबर 1981 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पदोन्नतियों में आरक्षण समाप्त कर दिया था। आज वही विश्वनाथ प्रताप सिंह पिछड़े वर्ग के मसीहा का चोला धारण कर चुके हैं।

मुलायम सिंह का मानना था कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देना अत्यंत आवश्यक है, पर ऊंची जातियों के गरीबों व पिछड़ों की केवल इस कारण उपेक्षा नहीं की जा सकती कि उनका जन्म पिछड़े वर्ग में नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति समाज में सर्वाधिक पिछड़ती हुई है, पर उनके साथ अब तक न्याय नहीं हुआ है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की भांति संकीर्ण दृष्टिकोण से काम लेने के बाजय उन्होंने उदार और व्यापक नजरिया अपनाया। 31 मार्च 1991 को श्री यादव ने प्रदेश की सरकारी नौकरियों में ऊंची जातियों के पिछड़ों को आठ प्रतिशत, महिलाओं को तीन प्रतिशत और पिछड़े पहाड़ी प्रदेश के लोगों को दो प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। इस तरह राज्य की प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में कुल आरक्षण कोटा 70 प्रतिशत और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 68 प्रतिशत हो गया। मुख्यमंत्री के रूप में श्री यादव ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजों में भी पिछड़ी जातियों के आरक्षण की सुविधा देने की घोषणा की। इस तरह उन्होंने समाज के सभी शोषित वर्गों को वास्तविक रूप से न्याय दिलाने व उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए गंभीर व ईमानदार प्रयास किए। उन्होंने वोटों की राजनीति की खातिर आरक्षण का इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न जातियों का आपस में लड़ाने के बजाय सामाजिक एकात्मकता बनाए रखते हुए अपने दायित्व पूरे करने को वरीयता

दी। यही वजह है कि आज श्री यादव धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक बदलाव के संघर्ष के प्रतीक बन गए हैं।[7]

3-समाजवादी पार्टी ही क्यों

समाजवादी पार्टी यो तो काग्रेस समाजवादी पार्टी के नाम से 1934 ई0 में ही पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में अचार्य नरेन्द्र देव जी के सभापतित्व में बनाई गई थी, परन्तु इसके पहले ही वाराणसी (उ0 प्र0), बिहार, दिल्ली, पंजाब और बम्बई में समाजवादी संगठन को कुछ लोगों ने बनाया था। इसके पहले कांग्रेस पार्टी 1884 ई0 में, 1925 ई0 में कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ,एवं हिन्दुमहा सभा आदि पार्टिया बन चुकी थीं। 1950 ई0 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का राजनीतिक मंच के रूप में जनसंघ की स्थापना हुई। उस समय इसका नाम कांग्रेस समाजवादी पार्टी था।काँग्रेस नाम इसलिये जोड़ा गया था क्योंकि देश उस समय गुलाम था और गुलाम देश में समाजवाद की स्थापना करना हमारे लिये सम्भव नहीं था। उस समय काँग्रेस देश की गुलामी को खत्म करने का एक बड़ा मंच था। उस मंच से अलग रहकर हमारे लिये सम्भव नहीं कि हम आजादी हासिल कर सकें।इसलिये काँग्रेस को सबल बनाकर समाजवादी विचार का प्रचार-प्रसार करने का उद्देश्य हमारा था। उस समय श्री जय प्रकाश नारायण ने स्थापना सम्मेलन में कहा था "हम यह नहीं कहते है कि कांग्रेस को समाजवाद का पूरा कार्यक्रम स्वीकार करना चाहिए। किंतु हम यह जरूर कहते और चाहते है कि कांग्रेस को कम से कम एक ऐसा आर्थिक कार्यक्रम तैयार कर स्वीकार कर ही लेना चाहिये जिसे काम में लाने पर जनता को शोषण से मुक्ति मिल सके और राजनैतिक, आर्थिक सत्ता इनके हाथों में आ जाये। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऐसा ही कार्यक्रम देश के सामने रख रही है। पार्टी का वह कार्यक्रम क्या हो? मूल उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त स्वराज्य सरकार को और क्या-क्या कार्यक्रम करने हैं, जिससे जनता को पूरी आर्थिक आजादी प्राप्त हो सकें और यह शोषण अन्याय, दुख, दरिद्रता और अज्ञानता से मुक्ति पा जाये।

इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए उस सम्मेलन में एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। उस सम्मेलन में ही जय प्रकाश नारायण के अतिरिक्त सर्वश्री आचार्य नरेन्द्र देव, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्द्धन, मीनू

---

7 - डा0 आर0 पी0 त्रिपाठी- मुलायम सिंह यादव, रचना और संघर्ष पृष्ठ 110

मसानी, डा0 राम मनोहर लोहिया, सेठ दामोदर स्वरुप मोहन लाल गौतम, फरीदुल हक अंसारी मुन्शी अहमद दीन, अशोक मेहता शिवनाथ बनर्जी, गंगाशरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और बिहार के एक दर्जन लोग थे। महिलाओं में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, श्रीमती सत्यवती देवी (दिल्ली), श्रीमती मालती चौधरी (कटक) आदि कई महिलाएं थीं। पार्टी का एक मूल आधार सिद्धांत होता है और उसी के सन्दर्भ में तय की गयी नीति और बनाये कार्यक्रम के अनुसार पार्टी चलती है उसके बाद पार्टी के कई तरह के स्वरूप उभरे परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो 1952 में नये संविधान के अनुसार वयस्क मताधिकार के आधार पर देशव्यापी पहला चुनाव हुआ, उसमें पार्टी को वोट तो 10 प्रतिशत अवश्य पड़ा, परन्तु लोकसभा और विधानसभाओं में पार्टी को बहुत कम सीट मिलीं। इससे पार्टी के शीर्ष नेताओं पर बुरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने काँग्रेस से टूटकर कृषक मजदूर प्रजा पार्टी का जो गठन किया था, उसमें विलय कर समाजवादी पार्टी का नाम प्रजा समाजवादी पार्टी रख दिया। 1947 के बाद पार्टी ने 'कांग्रेस' शब्द को हटाकर मात्र समाजवादी पार्टी के रूप में काम किया परन्तु कांग्रेस से निकले जमात के साथ मिलने पर पार्टी के सिद्धांत में मिलावट आ गयी। फलस्वरूप कई तरह की फूट कई बार पार्टी में हुई। उसके बाद का इतिहास विचारों के आपसी संघर्ष का भी रहा डा0 राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता और जयप्रकाश नारायण के विचारों में टकराहट होती रही। आचार्य नरेन्द्र देव ही एक ऐसे सर्वमान्य नेता थे जो इसे ठीक कर सकते थे परन्तु वे अपने गिरते स्वास्थ्य और अनुशासन प्रियता के चलते कई जगह चुप रह गये या ममतावश कठोर निर्णय न ले सके।

बाद में डा0 राम मनोहर लोहिया ने इसे समझा और उन्होंने पंचमढ़ी सम्मेलन में समाजवादी सिद्धांत, नीति और कार्यक्रम का एक स्पष्ट रूप देश के सामने रखा। जो पार्टी में विघटन हुए थे उसका फिर मिलन हो गया और संयुक्त समाजवादी पार्टी के नाम से पार्टी का गठन हो गया। इस पार्टी से भी एक अच्छी खासी जमात सत्ता में साझेदारी के लिये काँग्रेस पार्टी में चली गयी। जिसका नेतृत्व श्री अशोक मेहता ने किया और उन्होंने एक थीसिस "पिछड़ी अर्थनीति की बाध्यता" शीर्षक से देश के सामने रखी। जो समाजवादी बचें वे डा0 राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में संघर्षरत रहे। लेकिन डा0 राम मनोहर लोहिया ने गैर काँग्रेसवाद का नारा देकर एक बार काँग्रेस के एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया। इस प्रयास में अच्छी खासी सफलता मिली। फलस्वरूप पंजाब से बंगाल तक देश के नौ राज्यों में पहले-पहले गैर

काँग्रेसी सरकारें बन गयीं। सरकारें बन तो गयीं, परन्तु सारे राज्यों में भिन्न-भिन्न पार्टियों की मिली-जुली सरकारें रही और सबके मुख्यमंत्री दल-बदलू काँग्रेसी ही रहे। इससे सरकार द्वारा कोई मूलभूत परिवर्तन का काम नहीं हो सका। इसका बहुत बुरा असर समाजवादी पार्टी के ऊपर भी पड़ा। बिहार विधानसभा में काँग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ही थी। उसमें सत्ता विरोध के चलते फूट हो गयी और समाजवादियों ने ही बड़ी संख्या में टूटकर शोषित दल का गठन कर श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल के नेतृत्व में काँग्रेस की मदद से बिहार में सरकार बनाने का काम किया। जो संविद सरकार समाजवादियों की थी, जिसने बिहार के भीषण अकाल में बहुत ही सराहनीय काम किया था, उसके जब रचनात्मक काम करने का समय आया तो अपने ही घर के चिराग से अपने ही घर में आग लग गयी। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी 1976 ई0 तक चलती रही और भिन्न-भिन्न जगहों में इसके नेतृत्व में शोषण के खिलाफ जातीय विषमता के खिलाफ गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ ग्रामीण व गरीबों के कष्ट के खिलाफ, कारगर आन्दोलन होते रहे।

1974 में विद्यार्थियों का आन्दोलन बिहार में प्रारम्भ हुआ, उसे जय प्रकाश नारायण का नेतृत्व मिल जाने के कारण एक जन-आन्दोलन का स्वरूप हासिल कर लिया। जय प्रकाश नारायण भू-दान आन्दोलन से निराश हो गये थे। इस आन्दोलन से उनको भी प्रेरणा मिली और ढलती उम्र में भी युवा आन्दोलन का बड़े उत्साह के साथ नेतृत्व दिया। फलस्वरूप कांग्रेस की सरकारें हिल गयीं और इसी बीच श्रीमती इन्दिरा गाँधी समाजवादी नेता राज नारायण से इलाहाबाद हाई कोर्ट से चुनाव का मुकदमा हार गयीं। जहाँ श्रीमती गाँधी को सदन की सदस्यता समाप्त होने से अपने पद से इस्तीफा देना था वहाँ पद की रक्षा के लिये कुर्सी मोह में पड़कर आपातकाल की घोषणा देश में कर दीं। फलस्वरूप एक ही दिन में हजारों विरोधी पक्ष के नेता और कुछ कांग्रेस के भी नेता जो इन्दिरा गाँधी के इस कार्य के विरोधी थे, उनकी गिरफ्तारी हो गयी। 1977 में आपातकालीन घोषणा हटा ली गयी और ये सभी नेता जेल से छोड़ दिये गये। देश की अधिकांश जनता इन्दिरा गाँधी के इस अत्याचार के विरोध में चली गयी और जय प्रकाश नारायण के आह्वान पर जिन पार्टियों के लोग इस आन्दोलन के शरीक हुए वे सब मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े। उस चुनाव में इंन्दिरा गाँधी और उसकी पार्टी की पराजय हो गयी और दिल्ली में सर्वप्रथम एक गैर काँग्रेसी सरकार का गठन हो गया। श्री जयप्रकाश नारायण के दबाव

से जनता पार्टी का गठन किया गयां समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी का पूर्ण विलय जनता पार्टी में कर लिया। आज की भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ के नाम से थी। जनसंघ का तो जनता पार्टी में अवश्य विलयन हुआ परन्तु उसकी मूल प्रमाण आर0 एस0 एस0 ज्यों का त्यों बनी रहीं। जनता पार्टी की जो सरकार बनी, उसके भी प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई बनाये गये। मोरारजी देसाई में अनेंकों गुण थे परन्तु इन चार पार्टीयों के मिले हुए संगगठन को चलाने में वे सक्षम साबित नहीं हो सके। अब इसमें किसका कितना दोष रहा यह आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। मेरी राय में यह पार्टी नकारात्मक कार्यक्रम को लेकर बनी थी। इसके आगे ठोस सिद्धांत नहीं था। केवल एक लक्ष्य था, कांग्रेस को सत्ता से हटा देना। कम ही दिनों में आपसी विरोध के चलते यह सरकार टूट गयी और फिर श्रीमती गाँधी पुनः सरकार बनाने में सफल हो गयीं। समाजवादी विचार के लोग भिन्न-भिन्न जगह में बिखरे थे और मायूसी की स्थिति में पड़े हुए थे।

समाजवादी पार्टी ने स्वतंत्रता सग्राम से लेकर आज तक अपनी पार्टी को जो भी क्षति पहुंचाई हो परन्तु देश को हमेशा एक नयी दिशा देने का काम किया है। सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को तब हुआ जब 1977 में पार्टी ने अपने को समाप्त कर जनता पार्टी में विलय कर दिया।जनता पार्टी में एक राय नहीं थी और उसमें मिलने वाली और उसमें मिलकर जिन पार्टियों ने एक पार्टी बनायी थी वे सब के सब अपने को अलग गिरोह बनाकर काम कर रहे थे। इसका जो नतीजा हुआ वह देश के सामने है। समाजवादी विचार के जो लोग थे उनमें से अधिकाश को घुटन हो रहा था और कुछ सत्ता के मोह में कुछ पाकर प्रसन्न भी थें यह स्थिति 1977 से 1991 तक बनी रही, इस बीच भिन्न-भिन्न नाम से कई दल बने जिसमें समाजवादी लोग भी घूमते रह गये। 1992 के अन्त में कुछ समाजवादी विचार के लोगो ने इकटठे होकर इस स्थिति पर विचार किया और श्री मुलायम सिंह के नेतृत्व में पुनः समाजवादी पार्टी का गठन किया। इस गठन के बाद इसका प्रथम सम्मेलन जो लखनऊ में हुआ उसमें यह साफ निर्णय लिया गया कि भविष्य में समाजवादी पार्टी किसी के साथ विलय नहीं करेगी परन्तु कार्यक्रम के आधार पर समयानुसार राष्ट्रहित में समझौता करने को तैयार रहेगी। समाजवाद पार्टी के गठन से इस देश और बाहर के जिन लोगों ने समझा था कि समाजवादी पार्टी समाप्त हो गयी और अन्य मायूस होकर अनमनस्यता की स्थिति में चले गये थे उनमें भी कुछ आशा का संचार हुआ। इस पार्टी के

संगठन का वर्ग चरित्र, थोड़ा साम्यवादी पार्टी से मिलता है परन्तु रूस के विघटन के बाद और दुनिया के कई कम्युनिस्ट देशों की सरकारों और पार्टियों के पतन के बाद जो एक प्रचार विश्वव्यापी शुरू हुआ है कि समाजवादी सिद्धांत के दर्शन उसके आर्थिक और राजनीतिक स्थिति विफल हो चुकी है, और दुनिया के विकास का एकमात्र पुंजीवादी अर्थ नीति जिसका मुख्य आधार मुक्त व्यापार और अनियंत्रित अर्थव्यवस्था है, यही केवल सार्थक है और रहेगा। परन्तु यह भ्रम है। समाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्र देव और डा0 राममनोहर लोहिया ने आज से 50 वर्ष पहले यह भविष्य वाणी की थी कि जिस रास्ते से रूस में सरकार और पार्टी चलाई जा रही है यह अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें जनतांत्रिक अधिकारों पर भी पाबन्दी है, और यह एक तरह से पार्टी तानाशाही के आधार पर चलाई जा रही है। रूस के समाजवादी व्यवस्था के पतन के अनेकों कारण हैं परन्तु उसमें से मुख्य कारण यह भी एक रहा है। आज जहां समाजवादी व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टीयों द्वारा चलाई गयी है वहां भी अर्न्तविरोध के चलते गडबडियां हुई हैं। और जो अभी पूंजीवादी व्यवस्था के अधीन मुक्त और भू.मंडलीकरण, उदारीकरण के आधार पर मुक्त पूंजी निवेश का काम दुनिया में चल रहा है इसके भीतर भी अर्न्तविरोध मौजूद हैं। इस अंर्तविरोध का ज्वलन्त उदाहरण अधिकांश लोगो की बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी व अनियंत्रित अर्थव्यवस्था विधिव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति समाज में नैतिक मूल्यों का पतन, और अराजकता की स्थिति का सन्देह सारे विचारशील लोगों को दिग्भ्रमित करता रहा है। इस स्थिति में लोकतांत्रिक समाजवाद ही एक मात्र रास्ता (विकल्प) दिखलाई पड़ता है।

देश में आज भी कुछ समाजवादी लोग अलग-अलग भिन्न-भिन्न मोर्चा वगैरह बनाकर गोष्ठी आदि का काम कर लेते हैं। जिसमें उड़ीसा के श्री किशन पटनायक और महाराष्ट्र के कुछ पुराने समाजवादी लोग राष्ट्र सेवादल के साथ गोष्ठी आदि करते हैं। ये सभी लोग एक समाजवादी संगठन बनाने की चाह जरूर रखते है परन्तु वैसा कर नहीं पाते है। जो संगठन श्री मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में बना है उसके संविधान में पार्टी का लक्ष्य और उद्देश्य ये हैः-

1- समाजवादी पार्टी की भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा और श्रद्धा है। गाँधी जी और डा0 लोहिया के आदर्शो से प्रेरण लेकर समाजवादी पार्टी लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में आस्था रखेगी। समाजवादी पार्टी का विश्वास ऐसी राज व्यवस्था में है,

जिसमें आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीयकरण निश्चित रूप से हो। पार्टी शान्तिमय तथा लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध प्रकट करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है, इसमे सत्याग्रह तथा शान्तिपूर्ण विरोध शामिल है।

2- धर्म पर आधारित राज्य की अवधारणा का समाजवादी पार्टी विरोध करती है और धर्म पर आधारित राज्य में आस्था रखने वाले किसी भी संगठन का कोई भी सदस्य समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकेगा।

इससे यह साफ पता चलता है कि आज भी दुनिया में समाजवादी पार्टी का जो सिद्धांत होना चाहिये वह इन वाक्यों में निहित हैं यों किसी भी पार्टी का प्राण उसका सिद्धांत होता हैं सिद्धांत को कैसे कार्यरूप में परिणित किया जाये, इसके लिये पार्टी की नीति होती है और उसी नीति के अनुरूप समय, परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति और निवासियों जो किसी भी तरह के शोषण के शिकार हैं, उनकी स्थिति में सुधार और बदलाव लाने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इसलिये किसी पार्टी को समझने के लिए सिद्धांत नीति और उसके द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम को जान लेना आवश्यक ही नही अनिवार्य भी है। आज अपने देश में असली रूप में समाजवादी पार्टी के केवल इसी पार्टी को माना जा सकता है। इस समाजवादी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र सबसे सबल उत्तर प्रदेश में है। जिसकी जनसंख्या करीब 17 करोड़ की है। चुनाव के दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ही है। देश के कुल 28 राज्यों में से केवल पूर्वांचल के आसाम से निकाल कर कुछ छोटे राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में इसके राज्य संगठन हैं और संगठन का आधार सदस्यता ही है। उसी आधार पर पार्टी का संगठनात्मक ढाँचा खड़ा किया जा सकता है।अभी 4 व 5 जनवरी सन् 2002 को पार्टी का पंचम राष्ट्रीय सम्मेल कानपुर में सम्पन्न हुआ है पार्टी का सदस्य तीन वर्षो के लिए 10 रुपया शुल्क देकर बन जाता है और जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी के 50 साधारण सदस्यों की भर्ती करें, कार्यशील सदस्य माना जायेगा और पार्टी का पदाधिकारी वही सदस्य हो सकता हैं । इस पार्टी ने प्रारम्भ से ही अब तक अनेकों संघर्ष किये हैं और लोकसभा से लेकर ग्रम पंचायतों तक अनेकों चुनाव लड़े हैं। चुनाव के नतीजे भी आज की परिस्थिति में अच्छे ही कहे जा सकते है। परन्तु जितना अच्छा होना चाहिये, उतना अच्छा नहीं माना जा सकता है। इसके लिये संगठन को और अधिक सिद्धांतनिष्ठ सबल और संघर्षशील बनाना होगा। ऐसा तभी होगा जब डा0 राम मनोहर

लोहिया के बताये "फावड़ा-जेल-वोट" के कार्यक्रम को आधार मानकर चला जाय। फावड़ा का मतलब शहर या गॉव में रचनात्मक कार्य और श्रम से है, जेल का मतलब किसी भी तरह के अन्याय के विरूद्ध संघर्ष से है और जब दोनो काम निष्ठापूर्वक किया जायेगा तभी वोट की लड़ाई में भी विश्वास पूर्वक कम खर्चे में जीत हासिल की जा सकती है। इसी को अधिकांश समाजवादी साथी, उल्टे समझ बैठे हैं। वे वोट को ही आगे रखकर सभी कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेते हैं और बातचीत में भी बताते हैं कि ऐसा करने से वोट के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। नतीजा होता है कि रचनात्मक कार्य और किसी भी तरह के अन्याय के प्रतिकार का कार्य पीछे छूट जाता है और वोट के स्वार्थ में हम असली उद्देश्य प्राप्ति से पिछड़े जाते हैं। आज जब न केवल अपने देश बल्कि दुनिया को जनतांत्रिक समाजवादी समाज की आवश्यकता है, तब पार्टी कार्यकर्ताओं की सोच सब तरह से दुरूस्त होना चाहिये। रूस की समाजवादी सरकार के पतन के बाद जिसे वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी चलाती थी, उसकी कजोरी उजागर हो चुकी है और फलस्वरूप यूरोप के छोटे-छोटे देशों में जो उनके बताये रास्ते पर चलने वाली सरकारे थीं, वह भी समाप्त हो गयी हैं। अब दुनिया के मात्र तीन देशों में चीन, वियतनाम और अमेरिका के बगल के छोटे से देश क्यूबा में कम्युनिस्ट पाटी की सरकार चल रही है, परन्तु उसमें भी दुनिया की नयी अर्थनीति का बड़ा प्रभाव पड़ गया है। वहाँ भी मार्क्स, लेनिन, माओत्सेतुंग और होचिनमिन के बताये रास्ते से अलग होकर अर्थनीति चलायी जा रही हैं इसका फल यह है कि दुनिया के पूँजीवादी और नव-साम्राज्यवादी देशों के समाज में भी अंतर्विरोधी है और गरीबी-अमीरों की खाई बढ़ती जा रही है। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित सरकारे जहां है, वहां भी गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ रही है। इस अंतर्विरोध के चलते कई तरह की समस्याएं आज खड़ी हो चुकी हैं। दुनिया में इन समस्याओं के समाधान के लिये नये ढंग से कुछ बुद्धिजीवी लोग समाजवाद की व्याख्या कर रहे हैं। मार्क्स ने जिसे प्रारम्भिक अवस्था में सर्वहारा की तानाशाही का नाम दिया था, अब उसकी जगह पर जनतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया जाने लगा है। अगर एक वाक्य में कहें तो केवल हमारी समाजवादी पार्टी का सिद्धांत ही शुद्ध रूप में जनतांत्रिक समाजवादी है।

समाजवादी पार्टी के मूर्धन्य नीतिकार आचार्य नरेन्द्र देव ने करीब 60 वर्ष पहले कहा था-जनतंत्र के बिना समाजवाद नहीं चल सकता है और उसी समय राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध ज्ञाता हेराल्ड लास्की ने कहा था बिना आर्थिक समानता के जनतंत्र भी सम्भव नहीं है। इन दोनों

महापुरूषों के कहे वाक्यों के अनुसार और सत्ता के विकेन्द्रीयकरण तथा चौखम्भ राज्य की कल्पना के प्रणेता डा0 राम मनोहर लोहिया शान्तिप्रिय संघर्ष के रास्ते पर चलकर नई दुनिया के समाज निमार्ण के प्रणेता महात्मा गॉधी ने भी केवल कहा ही नहीं था बल्कि उसका भिन्न-भिन्न जगहो में प्रयोग भी शुरू किया था। अब इन नेताओं में से कोई भी हमारे बीच में नहीं है परन्तु उनका सिद्धांत, उनकी बतायी नीति और उनका कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी को इन नेताओं के बताये रास्ते पर चलकर अपने संगठन को चुस्त-दुरूस्त बनाना चाहिये। अगर हम संगठन को इन महापुरूषों के बताये रास्ते के अनुसार खड़ा करते और चलाते हैं तो न केवल अपने देश भारत को बल्कि दुनिया के शोषित पीड़ित समाज को दलन-दोहन और दास्त्व से मुक्त कराकर एक समतामूलकर समाज की रचना को फलीभूत कर सकते हैं। आज के इतिहास की यही पुकार है। काश हमारे पुराने और नये साथी अपने हित को पीछे रखकर समाज और देश के हित को आगे रखकर अग्रसर होते तो वह समय दूर नही है कि हम आज की दुःखी और पीड़ित मानवता को सही रास्ते पर ले चलने में सफल हो जाते।

जिस समाजवाद का नाम लोग भूल रहे थे आज श्री मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सभी के जबान और दिलदिमाग को प्रभावित कर रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का वर्ग चरित्र एक जैसा है। थोड़ा सा फर्क साम्प्रदायिक विचरों का है। समाजवादी पार्टी के बारे में जो लोग यह कहते हैं कि यह जातिवादी पार्टी है वे या तो अज्ञान है या जान बूझकर पार्टी को बदनाम करने के लिए इस बात का प्रचार करते हैं। देश की जो जनसंख्या है उसमें जो हजारो वर्षो से पिछड़े और दलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से ही केवल वंचित ही नहीं रखे गये थे बल्कि उन्हे सब तरह से समाज में हीन समझा जाता था, अपवाद स्वरूप कहीं -कहीं इसके विपरीत उदाहरण मिलते हैं, परन्तु आम तौर पर स्थिति अच्छी नहीं थी। अभी उन लोंगो में भी जागृति आयी है और वे भी अब सत्ता में साझेदारी की लालसा लेकर खड़े हो रहे हैं। इसे नापसन्द करने वाले लोग इस तरह का भ्रामक प्रचार कर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे है। डा0 राममनोहर लोहिया ने 'विशेष अवसर का सिद्धांत' चलाकर इस देश की राजनीति को जो एक नई दिशा दिया है समाजवादी पार्टी उसी दिशा को आगे बढ़ाने में प्रयास रत है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का केवल वर्ग चरत्रि ही अलग नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनितिक मतभेद भी है। भारतीय जनता

पार्टी से समाजवादी पार्टी को केवल साम्प्रदायिकता के चलते मतभेद नहीं है उसके चलते उस पार्टी के पुंजीवादी समर्थक नीति, गरीब विरोधी काम, आर्थिक अनुदांरता की नीति और अर्न्तराष्ट्रीय जगत में अमेरिका जैसे पूंजीवादी राष्ट्र के पीछे चलने की नीति से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा मतभेद है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति से जोड़कर राजनैतिक हिंसा का कार्य किया है बल्कि इस देश को खंडित करने का उस पार्टी का प्रयास है। जहां तक क्षेत्रिय पार्टीयों का सवाल है उससे समाजवादी पार्टी को क्षेत्रिय विकास के मामले में कोई मतभेद नहीं है परन्तु राष्ट्रीय मुद्दो पर उनमें जहां खामियां है उस पर समाजवादी पार्टी को अवश्य मतभेद है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को अपना कार्यक्रम तेजी से चलाकर अपने स्वरूप को न केवल निखारने बल्कि देश के गरीबो चाहे व किसी भी जाति के हों उनको एक दिशा देने का काम करना है ।समाजवादी पार्टी के लिए आने वाला समय एक विकट परीक्षा का समय है इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे अपने संगठन को कैडर वेस (मासपार्टी) का रूप देना चाहिए। ऐसा काम वियतनाम के नेता श्री होचितमीन ने कम्युनिस्ट होते हुए अपने संगठन के लिए किया था। यह एक गम्भीर संगठन के स्वरूप का मुद्दा है। समाजवादी पार्टी को गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार करना है।[8]

4-समाजवादी पार्टी का गठन

यह एक बड़ी व्यंग्य पूर्ण स्थिति है कि भारत में प्रत्येक संक्रमण-काल में समाजवादियों ने समय की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए नया रूप और नया संगठन बनाया। यह भी एक विचित्र संयोग है कि कृष्ण की गीता के समान समाजवाद हमेशा कुरूक्षेत्र के मैदान से ही पुनर्व्याख्यायित होता रहा और उसकी मर्यादाओं और सीमाओं का नये सिरे से निर्धारण किया गया। 1977 के बाद 1989 में केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश में जो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थीं, जिसमें समाजवादी नये सपने, नये संकल्प के साथ शामिल थे, अन्तर्विरोध का शिकार होकर बिखर गयीं। इस बार मूल प्रश्न साम्प्रदायिकता का था। समाजवादी मूल्यों के पक्षधर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री के नाते जब साम्प्रदायिकता के झंझावात से जूझ रहे थे, उनके बहुतेरे समाजवादी साथियों ने उनका साथ नहीं दिया। नयी व्यवस्था का सपना बिखर गया, निराशा का माहौल पैदा हो गया। लेकिन यह एक सुखद संयोग था कि इस अंधकार से घिरे हुए वातावरण में

8 - कपिल देव सिंह- सपा ही क्यो, समाजवादी बुलेटिन, दिस0 2002, पृष्ठ 27

पूरे साहस और वर्चस्व के साथ मुलायम सिंह ने यह घोषित किया कि वह लोहिया के सिद्धांतों के आधार पर नयी सोशलिस्ट पार्टी का गठन करेंगे। यही नहीं, उन्होंने अपना हाथ उठाकर समस्त राजनैतिक पार्टियों से पृथक डॉ0 लोहिया के सिद्धान्तों में अपना विचार व्यक्त किया। मुलायम सिंह की इस घोषण के साथ ही संघर्ष का दोतरफा रूप हो गया। एक ओर साम्प्रदायिकता के विष से लड़ना चालू रहा और दूसरी ओर सामाजिक न्याय के लिए शोषण, भ्रष्टाचार औरअलगाववाद के खिलाफ मोर्चा बनाया गया। कर्म के साथ-साथ आचरण बनाने का सिद्धान्त केवल डॉ0 लोहिया की समाजवादी दृष्टि में मिलता है। इसीलिए सम्प्रदायवाद से लड़ने के लिए जरूरी था कि वह अपनी पार्टी को ऐसी बनायें कि उसमें धार्मिक उन्माद की काट ही नहीं बल्कि समाजवादी नीतियों पर आधारित ऐसी राजनीतिक परम्परा की शुरूआत भी हो जिससे इन दोनों विरोधी तत्वों का असली चेहरा सामने आ जाय।[9]

मुलायम सिंह की घोषणा सुनकर कोई भी कह सकता है कि उनका यह कदम एक सही समय में एक सही दिशा की ओर उठा है। किन्तु प्रत्येक सही कदम कितनी और समस्याएँ उठा देता है, इसे गहराई से समझने की जरूरत होती है। समाजवादी पार्टी के अनेक रूप हैं किन्तु जब कोई कहता है कि वह लोहिया के विचारों के आधार पर समाजवादी पार्टी का गठन करेगा तो आने वाली तस्वीर उलट जाती है। लोहियावादी समाजवाद का अर्थ है चौखम्भा राज। चौखम्भा राज का अर्थ है ग्राम पंचायत का गठन । ग्राम पंचायतों के गठन का मतलब है केन्द्र में स्थापित केन्द्रीकरण में विश्वास रखने वाली सत्ता से सीधी टक्कर। इस सीधी टक्कर का अर्थ होता है पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को उलटकर एक नयी शुरूआत करना । यही नहीं, लोहियावादी समाजवाद का मतलब है समता प्रधान समाज के निर्माण को प्राथमिकता देना। समतावादी समाज के प्रति प्रतिबद्ध होने का अर्थ है सम्प्रदायहीन समाज की प्रक्रिया शुरू करना। सम्प्रदायवाद के विरोध का अर्थ है उन प्रतिक्रियावादी एवं अलगाववादी शक्तियों से टक्कर लेना। इसीलिए जब मुलायम सिंह ने लोहियावादी समाजवदी पार्टी के गठन की घोषणा की तो लोहिया के समर्थकों में खुशी की एक लहर जरूर दौड़ी किन्तु उसी के साथ समस्याओं की जटिलताओं ने उदासी का वातावरण पैदा कर दिया। मन में शंका पैदा हुई। लगा कि शायद मुलायम सिंह चौतरफा हमले का सामना करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। लोहियावादी समजावादी सेना

9 - लक्ष्मी कांत वर्मा-समाजवादी आन्दोलन लोहियावाद के बाद , पृष्ठ 143

बिखरी हुई थी, समस्याओं की चुनौतियाँ तात्कालिक थीं। खासकर उग्र हिन्दुत्व और बहुसंख्यक उन्माद अपनी पराकाष्ठा पर था। इनसे टक्कर लेना सहज काम नहीं था क्योंकि 1989 से लेकर 1993 के बीच कांग्रेस का निहित स्वार्थ वाला चरित्र पूरी विषमता को तटस्थ होकर देख रहा था और साम्प्रदायिक ताकतों के भविष्य के बारे में वह किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं था। यह बात मुलायम सिंह से छिपी नहीं थी।निश्चय ही उनके मन में वस्तुस्थिति की वास्तविकता को लेकर उहापोह की स्थिति उत्पन्न हुई होगी किन्तु जो प्रसंशनीय बात है वह यह कि इन सब खतरों के बावजूद उन्होंने लोहिया के विचारों के आधार पर संगठन तैयार करने का फैसला ले ही लिया।

उनकी इस घोषणा के बाद प्रायः सभी राजनीतिक पार्टियाँ सतर्कता के साथ समाजवादी आन्दोलन के भविष्य के बारे में सोचने लगीं। पत्र-पत्रिकाओं में जब प्रतिक्रियाएं आई तो लोग हंसे। साम्प्रदायिकता में विश्वास करने वाले लोग कुछ चौकन्ने जरूर किन्तु समस्त स्थितियों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करके उन्होंने मुलायम सिंह के सामर्थ्य को कम, उनकी असमर्थता या सीमाओं का गुणगान अधिक किया। वे यह भूल गये कि आखिर मुलायम सिंह ने डॉ0 राम मनोहर लोहिया के विचारों के प्रति आस्था व्यक्त की है। साम्प्रदायिक ताकतों तो तोड़ने का साहस जुटाना कोई मामूली बात नहीं है। शायद इसीलिए साम्प्रदायिक शाक्तियों ने अपनी शक्ति के प्रति आस्था जताने के बजाय दूसरे की कमजोरी जता कर उसे हतोत्साहित करने का प्रयास किया। लेकिन जिस प्रकार की निष्ठा और विश्वास की पकड़ मुलायम सिंह में है वह इन छोटी-मोटी उलझनों में पकड़कर समाप्त कैसे होती ? अपने संकल्प के अनुसार बचे खुचे साथियों को लेकर वह साम्प्रदायिकता के विरूद्ध मोर्चाबंदी करने में जुट गये।

जब मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी संगठित करने की घोषणा की थी तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी जल्दी इस काम को अंजाम देने में सफल होंगे। जब सारे प्रदेश और देश का भ्रमण करके समाजवादी आन्दोलन को पुनर्गठित करने का कार्य अकेले अपने दम पर करने की योजना में वह लगे थे उसी समय उन्होंने यह घोषित कर दिया था कि समाजवादी संगठन पिछड़े वर्ग के लोगों, दलितों और निर्वलों तथा असहाय लोगों के पक्ष में काम करेगा और गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग दमघोंटू वातावरण में जी रहे हैं उन्हें स्वावलम्बी बनाने की कोशिश की जायेगी

आखिर मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का पुनर्गठन कर ही डाला। वैसे समाजवादी पार्टी का पुनर्जन्म अवश्यम्भावी था। अच्छा हुआ कि समय की चुनौतियों को स्वीकार करके यह संगठन मुलायम सिंह द्वारा हुआ क्योंकि वह जोखिम उठाने वाले राजनीतिज्ञ है और समाजवाद का दूसरा नाम है जोखिम उठाने वाला वाद। यह जोखिम यों ही नहीं उठाया जाता। इसके लिए समझ और साहस दोनों की जरूरत है। कभी समझ होती है पर साहस नहीं होता और कभी साहस तो दुःसाहस के बराबर होता है पर समझ नहीं होती। साहसी को समझ धीरे-धीरे आ सकती है मगर निष्कर्म होकर न तो साहस ही आता है और न समझ मुलायम सिंह में साहस तो है ही और इस स्थापना सम्मेलन से यह भी स्पष्ट हो गया कि उनके पास अखिल भारतीय स्तर पर संगठन खड़ा करने की क्षमता भी है।[10]

5-समाजवादी पार्टी के सिद्धान्त, वक्तव्य एवं कार्यक्रम

आजादी के 45 सालों के बाद जनता की हालत और भी बिगड़ गयी है। गरीबी बढ़ती जा रही, कीमतें बढ़ रही है और बेरोजगारी ने महामारी का रूप ले लिया है। कृषि भूमि पर बोझ बरदास्त के बाहर हो गया है। गांवों का विकास बहुत धीमा है। उद्योग और खेती की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में घटी है। शिक्षा का स्तर गिर गया है। शहरों का विकास भी सुनियोजित नहीं है और लोग सड़कों के किनारे सोने को विवश है। हर जगह भ्रष्टाचार है और ऊपर से नीचे तक कुशासन चल रहा है। समाज के सभी अंग हताश, उदास और दुखी हैं।

हम अपने इतिहास के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गये हैं जहां हमारी प्रतिष्ठा हीनतम् हो चुकी है। दूसरे देश हमारे आंतरिक मामलों में बिना डर के दखल दे सकते हैं। देश के अन्दर साम्प्रदायिक शक्तियां राष्ट्र को तोड़ने में लगी हैं। सिद्धान्तहीनता और मूल्यहीनता ने समाज को जकड़ लिया है। आर्थिक विकास की दौड़ में दूसरे देश हमसे कहीं आगे निकल गये हैं।विश्व में भारत की आर्थिक दशा सबसे गिरी हुई है। जनता में आशा और उत्साह के बजाय अनिश्चितता, असुरक्षाऔर उदासीनता की भावना छाती जा रही है।

किसान और मजदूर पूरी तरह टूट गया हैं निर्धन, दलित और पिछड़ा उपेक्षित है। अल्पसंख्यक आतंकित हैं, भयभीत हैं।

---

10 - लक्ष्मी कान्त वर्मा- समाजवादी आन्दोलन लोहिया के बाद, पृष्ठ 148

भारत की नग्न वास्तविकता के वे पांच लाख गांव है जिनमें भारत की आबादी का 80 प्रतिशत रहता है। जिनमें आर्थिक जीवन क्षमता का नितान्त अभाव है। उन 5 लाख गांवों के साथ ही साथ वे शहरी गन्दी बस्तियां भी है जिनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है औरअपने दबाव से नागरिक के सभी अवशेषों को मिटाती जा रही है।

इस बिगड़ती हुई हालत को रोकने के लिए राष्ट्रहित एवं जन कल्याण को सर्वोपरि मानते हुये समाजवादी पार्टी निम्न सिद्धान्तों एवं कार्यक्रमों पर चलकर देश को नई दिशा देने का प्रयत्न करेगी।

सिद्धान्त

1. कार्यक्रम मूल सिद्धान्तों का अल्पकालिक रूप होता है, वैसे ही जैस अन्तिम लक्ष्य कई क्रमिक कार्यक्रमों का दीर्घकालीन जोड़ होता है। देश में राजनीतिक बहस और प्रचार अब तक अन्तिम लक्ष्यों पर केन्द्रित रहे हैं और अपेक्षित या तात्कालिक कार्यक्रमों की उपेक्षा हुई है। "आर्थिक और सामाजिक समानता", "वर्गविहीन और वर्णविंहीन समाज", "शोषण का अन्त और मकान का न्यूनतम स्तर", "स्वतंत्रता, मूल्य और अच्छाई", इस तरह की शब्दावली आसानी से शब्दाडम्बर का रूप ले लेती है, और इन्हें सभी मंचों पर सुना जा सकता है। शब्दों का बिना मतलब प्रयोग होने लगता है।
2. मंजिल जो धुंधली, अस्पष्ट रहती है, यदि उस तक पहुंचने का रास्ता साफ-साफ न बताया गया हो, तो उसे 'कर्णमधुर लेकिन निरर्थक बातों से भरा जा सकता है। अतः समाजवादी पार्टी अन्तिम सिद्धान्तों के स्पष्ट निरूपण के साथ-साथ निश्चित और ठोस कार्यक्रमों पर भी आग्रह करती हैं इससे सरकार के लिए कथनी और करनी के बीच गहरी खाई रखना सम्भव नहीं होगा और लोग अन्य राजनीतिक दलों से अलग समाजवादी पार्टी को सार्थक विस्तार से समझ भी सकेंगे।
3. यह जरूरी है कि समाजवादी पार्टी समता, सामाजिक स्वामित्व, लोकतंत्र और विकेन्द्रीकरण जैसे शब्दों के अर्थ निश्चित करे। इस प्रकार समता का सम्पत्ति और आमदनी के सन्दर्भ में एक ठोस मतलब होना चाहिए, राष्ट्र के अन्दर और राष्ट्रों के बीच भी। समता के ऐसे ठोस अर्थ में अधिकतम और न्यूनतम आमदनियों का

अनुपात बांधना होगा, तय करना होगा कि निजी स्वामित्व के किन रूपों की इजाजत दी जा सकती है और पहले कदम के रूप में व्यवस्था करनी होगी कि हर राष्ट्र के युद्ध बजट का कुछ निश्चित प्रतिशत समतापूर्ण विश्व का निर्माण करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय निधि में दिया जाये।

4. उत्पादन के सारे ऐसे साधनों का जिनमें वेतनभोगी मजदूरों से काम लिया जाता हो, सामाजीकरण होगा। निजी स्वामित्व ऐसी सम्पत्ति तक सीमित होगा जिनमें सामान्यतः वेतनभोगी मजदूर न लगें। सामाजिक स्वामित्व राज्य के विभिन्न गठनों के अनुरूप गांव से लेकर केन्द्र तक विभिन्न स्तरों पर होगा।[11] सामाजिक स्वामित्व की उपलब्धि का एक क्रमिक कार्यक्रम इस आधार पर चलाया जायेगा कि कार्यक्रमों के पहले चरण में कम से कम बैंकों और अन्य वित्त संस्थाओं सहित, सभी बड़े उद्योग-धंधों का सामाजीकरण हो। इसी प्रकार, पांच व्यक्तियों का एक परिवार बिना मजदूर लगाये या मशीनों का इस्तेमाल किये, जितनी जमीन जोत सकता है, उसकी तीन गुनी तक जमीन किसानों और भूमिहीन मजदूरों में बांट दी जायेगी। नाजायज ढंग से निजी स्वामित्व में ली गयी जमीन गांव को वापस मिलेगी।

5. समाजवादी पार्टी सहकारिता के सिद्धान्त में और हमारे आर्थिक जीवन के अधिकाधिक बढ़ते हुए हिस्सों पर सहकारिता को लागू करने में विश्वास करती है। परस्पर सहायता और आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त को लागू करने की जरूरत न सिर्फ उपभोक्ता सहकार में है, बल्कि ऋण, खेतिहर उत्पादन की बिक्री, खेती, कुटीर और छोटे उद्योगों में भी है। किन्तु समाजवादी पार्टी सहकारिता आन्दोलन पर नौकरशाही प्रभुत्व के और उसे स्थिर स्वार्थों व शासक वर्गों का सेवक बनाने की चेष्टाओं विरूद्ध है। समाजवादी व्यवस्था में समाजिक स्वामित्व के रुपों में सहकारिता का महत्वपूर्ण स्थान होगा।

6. आमदनी और खर्च की बराबरी का सीधा अनुपात भी रखना होगा क्योंकि उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व के अंतर्गत भी आराम और ऐश के लिए ऊंची तनख्वाहें और भत्ते लेने वाले नौकरशाहों, प्रबन्धकों और राजनीतिक नेताओं का

11 - रजनीकान्त वर्मा-समाजवादी पार्टी के सिद्धांत, वकतव्य एवं कार्यक्रम से उद्धत पृष्ठ 24

वर्ग बढ़ सकता है और स्वतंत्र पेशों के सफल लोग भी विशाल मात्रा में धन कमा या खर्च कर सकते हैं। सभी आमदनियों और खर्चों को ऐसे अनुपात में बांधा जायेगा कि अधिकतम सीमा न्यूनतम के दस गुने से अधिक न हो।

7. लोकतंत्र का अर्थ, ठोस सन्दर्भ में, केवल कुछ ऐसे मूल्यों के बारे में बाग्जाल ही ना रहे, जिनका निरर्थकता की हद तक साधारणीकरण कर दिया गया हो, बल्कि लोकतांत्रिक आदर्श को मूर्त करने वाले कुछ ठोस सिद्धान्तों पर आधारित होकर कार्य में मार्गदर्शन करें। तर्क और बहस के द्वारा जनमत को बदलने की सम्भावना लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है और भाषण की स्वतंत्रता उसका सार है। आज के युग में लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है विकेन्द्रीकरण, और उसका अर्थ राजनीतिक व आर्थिक दोनों ही सन्दर्भो में तय करना होगा राजनैतिक संदर्भ में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की छोटी इकाइयों के लिये सुनिश्चित राजनैतिक सत्ता और आर्थिक सन्दर्भ में ऐसी व्यवस्था और ऐसी मशीनें जो उत्पादन की प्रक्रिया के नियंत्रण की ज्यादा समझ प्रदान करें।

8. इसके लिए प्रशासन का पुनर्गठन करना होगा ताकि वह नौकरशाही या शक्ति या धन की सेवा के उपयुक्त नहीं वरन् उत्पादन आवश्यकताओं और कुशल अर्थव्यवस्था के उपयुक्त बने। छोटे पैमाने के उद्योगों की पद्धति के समान ही ऐसे राज्य की आवश्यकता है, जिसमें शक्ति अधिकाधिक प्रत्यक्ष, लोकतंत्र की छोटी इकाइयों में हो। जहां भी सम्भव होगा, नौकरशाही द्वारा शासन के स्थान पर चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन की पद्धति चलायी जायेगी। गांव, शहर या जिला जैसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाइयां गणराज्य की प्रभुसत्ता में भागीदार होंगी, और शक्तियों के उपयुक्त विभाजन और गठन की किसी भी योजना में उन्हें उतनी ही ऊंची सवैधानिक हैसियत दी जायेगी जितनी केन्द्रीय अंगों को।

9. लोकतंत्र हर हालत में समाजवाद के विचारों और कार्यक्रमों का मूलाधार रहेगा। लोकतंत्र का मतलब है चुनी हुई सभा के प्रति प्रशासन का अनिवार्य उत्तरदायित्व। इसका यह भी अर्थ है कि व्यक्ति, दल, शासन और राज्य के अलग-अलग सीमित व्यक्तित्व को स्वीकार करके उनका आदर किया जाय। ये चारों श्रेणियां

राजनीतिक कार्यवाही की माध्यम हैं। उनके अलगाव की सीमाओं को तोड़ने से और इस अलगाव के निश्चित नियमों के उल्लंघन से लोकतंत्र खत्म हो जाता है।

10. हमारे देश में नौकरशाही तथा पूंजीवाद ने रोग को अधिक बढ़ा दिया है। औद्योगिक या खेतिहर उत्पादन की अपेक्षा सट्टेबाजी और व्यापारी लेन-देन में मुनाफा अब भी बहुत ज्यादा है। शासनतंत्र शैतान की आंत जैसा बढ़ता जाता है और उसका काम उत्पादन की अपेक्षा उपदेश देना, सिखाना, नियमन, हस्तक्षेप करना और आमतौर पर एक खास पक्ष के लोगों को रोजगार दिलाना है। सफेदपोशी और हुक्मरानी पर आधारित सभ्यता को नौकरशाही और सामन्ती पूंजीवाद ने सर्वथा बांझ बना दिया है। समाजवादी पार्टी ऐसा क्रान्तिकारी दल है जिसे भारतीय इतिहास के सदियों से जमे हुए कूड़े को सामाजिक उत्पीड़न औरआर्थिक शोषण की परत को, जिसकी अभिव्यक्ति वर्ग और वर्ण के विभिन्न मिश्रण में होती है और जिसे परम्परागत धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से पोषण मिलता है, साफ करना है। वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा ने भीख मांगने को शारीरिक श्रम से अधिक आदरणीय बनाया है और कर्म सिद्धांत नये कर्म से छुटकारा पाना चाहता है यद्यपि उसे ज्ञात है कि पुराने कर्मों का संचित फल तो भोगना ही पड़ता है। इन दोनों ने मिलकर ऐसी सभ्यता निर्मित की है, जिसमें विचार के कठोर अनुशासन की अपेक्षा कर्म का आलस प्राप्त करना कहीं ज्यादा आसान है।

11. पूंजीवाद ने मानवजाति को दो हिस्सों में बांट दिया है- (i) तीसवें अक्षांश के उत्तर में रहने वाले लोग जिन्हें खेती और उद्योग में विज्ञान के पूंजीवादी उपयोग का लाभ मिलता है, और (ii) उसके दक्षिण में रहने वाले दुनिया के दो तिहाई वंचित रंगीन लोग जिनके उत्पादन के साधनों को नयी पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था ने क्षति पहुंचायी है। पूंजीवाद ने जहां उत्पादन के साधनों और उत्पादन के संबंधों के बीच केन्द्रित पूंजी के मालिकों और देशी सर्वहारा के बीच संघर्ष पैदा किया है, वहीं उसने दुनिया के एक तिहाई हिस्से में उत्पादन के साधनों की विशालता और दो तिहाई दुनिया में इन साधनों के ह्रास का इससे भी बड़ा आन्तर्विरोध पैदा किया है। उसने पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अस्ट्रेलिया में अपनी

औपनिवेशिक शाखाओं को जहां अभूतपूर्व समृद्धि प्रदान की, वहीं उसने एशिया, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में मौत का सन्नाटा कायम किया, जिसमें इन क्षेत्रों की आबादियां बढ़ी और उत्पादन के साधन बिगड़े। दुनिया के दो-तिहाई हिस्से में पूंजी-निर्माण का काम इतना बड़ा है कि निजी पूंजी इस काम को नहीं कर सकतीं। पूंजीवाद की दो राक्षसी सन्तानें रहीं हैं-युद्ध और गरीबी। दो-तिहाई मानव जाति के लिए गरीबी, और शेष के लिए युद्ध। पूंजीवाद में अपनी इन सन्तानों को नष्ट करने की क्षमता नहीं है।

12. दुनिया के दो-तिहाई हिस्से से पूंजीवाद और सामन्तशाही को मिटाने के बारे में कोई सन्देह या हिचक नहीं होनी चाहिए। दुनिया के इस हिस्से में पूंजीवाद का अर्थ शरीर और मन दोनों की अधिकाधिक गरीबी ही हो सकता है। यह केवल मुनाफे के लिए उत्पादन कर सकता है और नयी अल्पविकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में मुनाफे की गुंजाइस नहीं। निश्चय ही भोजन, मकान और औजार ऐसे उपादान नहीं हैं जिनसे मामूली आदमी धन उत्पन्न कर सकें, जो कि वनस्पति तेल, दवा, सिनेमा, और सबसे अधिक सट्टेबाजी में इसकी गुंजाइस है।

13. साम्यवादी सिद्धांत जिस रूप में प्रतिपादित एवं विकसित किया गया था, उसकी सफलता पर प्रश्नचिन्ह डा0 राम मनोहर लोहिया ने पहले ही लगा दिया था। पूर्वी योराप एंव सोवियत संघ की घटनाएं डा0 लोहिया की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध कर रही हैं। उन्होंने कहा था-"कोई नया समेकित सिद्धांत ही मानव जाति को नयी आशा और नयी सभ्यता प्रदान कर सकता है।" ऐसा सिद्धांत केवल समाजवाद का सिद्धांत ही हो सकता है।

14. समाजवाद के सिद्धांत को आधार प्रदान करने के साथ-साथ ऐसी कार्य पद्धतियों का निरूपण भी उतना ही आवश्यक है जिनसे प्रेरणा सिद्धांत को मूर्तरूप दिया जा सके। सभी कार्यों का लक्ष्य होना चाहिए जनता के संकल्प का संगठन और उसकी अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय जीवन का पुनर्निर्माण। समाजवादी पार्टी को निरन्तर कोशिशि करनी चाहिए कि वह जनता का प्रवक्ता,उसके संकल्प का संगठक, अन्याय का प्रतिरोध करने वाला, और पुनर्निर्माण करने वाला बने। उसे हमेशा

तैयार रहना चाहिए कि जनमत को प्रबुद्ध बनाने के लिए रचनात्मक कार्यों में हिस्सा लें और उससे खुद भी सीखें तथा अन्याय का प्रतिरोध करें। कार्य की तीन पद्धतियां-जिनके प्रतीक है फावड़ा, वोट और जेल। सत्ता से बाहर रहने पर, वर्तमान में भी अपनी चाहे कितनी भी थोड़ी उपलब्धियों से यह दिखाना चाहिए कि सत्तारूढ़ होने पर वह क्या करेगा?

15. सभी छोटे-छोटे रचनात्मक कार्य सचमुच क्रान्तिकारी कार्यकलापों को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। क्रान्ति कभी भी संसदीय कार्यवाही तक सीमित नहीं हो सकती। वोट जनता के संकल्प की सर्वोच्च अभिव्यक्ति होता है लेकिन उसका मौका बरसों में एकबार आता है। मगर वोट के पूरक के रूप में सिविल नाफरमानी द्वारा या वर्ग संघर्ष के किसी कार्य को तात्कालिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। झूठ और हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न कभी भविष्य के काल्पनिक स्वास्थ्य के लिए वर्तमान हत्या को उचित ठहराने की चेष्टा करनी चाहिए।[12]

16. हमारे देश में एक ओर सरकारी हिंसा-क्रूरता और बिना मुकदमा चलाये बहुसंख्यक लोगों की गिरफ्तारी, निहत्थी भीड़ों पर पुलिस का गोली चलाना आदि होते रहे हैं तथा दूसरी ओर लोगों का लम्बे अर्से तक चुपचाप सहना और अचानक सामूहिक हिंसा और जंगलीपन का विस्फोट जारी रहा है। व्यक्तिगत और सामूहिक सिविल नाफरमानी का भारत के सार्वजनिक जीवन में कोई कारगर योग नहीं रहा है। समाजवादियों को निर्णायक रीति से सिविल नाफरमानी को अमल में लाना चाहिए और इस पुराने विश्वास को गलत साबित करना चाहिए कि बल प्रयोग के बिना वर्तमान व्यवस्था को उल्टना सम्भव नहीं।

17. समाजवादी पार्टी मानती है कि नयी मानव सभ्यता के निर्माण की दृष्टि से पूंजीवाद और साम्यवाद समान रूप से निरर्थक हैं। हमारा प्रयास होगा कि समतापूर्ण जगत में केवल मनुष्य की सभ्यता निर्मित हो। ऐसी दुनिया केवल इस सिद्धांत के आधार पर बनायी जा सकती है कि मनुष्य न केवल एक राष्ट्र के अन्दर, बल्कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच भी समान है।

---

12 - रजनीकान्त वर्मा समाजवादी पार्टी के सिद्धांत, वकतव्य एवं कार्यक्रम से उद्धृत, पृष्ठ 28

18.समाजवादी पार्टी मानती है कि शस्त्रों को होड़ सारी दुनिया की अर्थ व्यवस्था पर भारी बोझ बन चुकी है। इस पर खर्च होने वाला बेहिसाब धन दुनिया के अल्प विकसित देशों के विकास पर खर्च करके सम्पूर्ण मानवता को गरीबी, भुखमरी और विनाश से बचाया जा सकता है। इस हेतु निरस्त्रीकरण जरूरी है।

19.दुनिया में वास्तविक और कारगर निरस्त्रीकरण तभी हो सकता है जब विश्व में समता स्थापित हो। मानव जाति के विकसित एक-तिहाई हिस्से की उत्पादक शक्तियों की वजह से जो घोर विषमता है, वह गम्भीर आर्थिक असन्तुलन उत्पन्न करती है जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के संघर्ष होते हैं और विशेषाधिकार-प्राप्त हिस्सों के धन को बचाने के लिए शस्त्रीकरण की होड़ चल पड़ती है।

20.वर्तमान में विदेशी सहायता, न केवल पाने वालों के लिए अपमानजनक और खतरनाक है, बल्कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी काफी नहीं हो सकती। ऐसी सहायता निश्चित ही पिछड़े देशों को भ्रष्ट करती है और निरपवाद ही यथास्थिति की शक्तियों को सत्तारूढ़ रखती है। विश्व बैंक और विश्व मुद्राकोष जैसी संस्थाओं पर भी पूंजीवादी ताकतों का पूरा नियंत्रण हो गया है। इसलिए इन संस्थओं से मिलने वाली सहायता एवं ऋण विकासशील देशों की सम्प्रभुता के लिए खतरनाक साबित हो रही है।समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सम्मान एवं सम्प्रभुता की कीमत पर मिलने वाले किसी भी कर्ज एवं सहायता का विरोध करती है।

21. समाजवाद के सिद्धांत को अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर और दृढ़ता के साथ अमल में लाने पर ही नयी विश्व व्यवस्था का प्रादुर्भव हो सकता है। इस युग में समाजवाद का सर्वव्यापी सिद्धांत और उस पर किया गया अमल निम्न सात क्रान्तियों के द्वारा व्यक्त होना चाहिए।

1. नर-नारी की समानता के लिए
2. चमड़ी-रंग पर रची असमानताओं के खिलाफ,
3. जन्मजात और जाति प्रथा की विषमताओं के खिलाफ,
4. परदेशी ग़ुलामी के खिलाफ और विश्व लोक राज के लिए,

5. निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए
6. निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ।
7. अस्त्र-शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए।

22. राष्ट्र के सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को विशेष अवसर प्रदान करने के सिद्धांत को समाजवादी पार्टी मान्यता प्रदान करती है।पार्टी की मान्यता है कि जब समाज के दलित अल्पसंख्यक एवं पिछडे विशेष अवसर प्राप्त करके अन्य वर्गों के बराबर खड़े नहीं होंगे-समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो सकगी।
23. धर्म निरपेक्षता या सर्व-धर्म संम्भाव के सिद्धान्त को समाजवादी पार्टी स्वीकार करती है तथा धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन करने वाली साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ निरन्तर संघर्ष करने के लिए पार्टी कृत संकल्प है। अनेक धर्मावलम्बियों वाले इस विशाल देश को "सर्व धर्म सम्भाव" की भावना के द्वारा ही एकता के सूत्र में बांधे रखा जा सकता है।[13]

कार्यक्रम

हमारे राष्ट्रीय मामलों में आ चुके वर्तमान संकट के कई पहलू बढ़ती आबादी, अन्न की सतत् कमी, निरन्तर बढ़ती कीमतें, हमेशा बढ़ती गैरबराबरी, धन का कुवितरण और बढ़ता भ्रष्टाचार और नौकरशाही का बढ़ता शिकंजा आदि।

आर्थिक विकास के मामले में भी हमारा देश दूसरे देशों से बहुत पिछड़ा हुआ है। वक्ती उपाय और अधिक तालमेल बैठाने से यह संकट दूर नहीं होगा। इसके लिए बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है।

वर्तमान पूंजीवादी-सामन्ती व्यवस्था और नौकरशाही का नाजायज प्रभुत्व देश को और चौपट कर रहा है। पार्टी को इन मामलों में वर्ग-संघर्ष तेज करना होगा और सामूहिक तथा व्यक्तिगत सिविल नाफरमानी को व्यापक रूप देना होगा ताकि राज्य का चरित्र, राजनीतिक तथा

13 - रजनीकान्त वर्मा समाजवादी पार्टी के सिद्धांत, वकतव्य एवं कार्यक्रम से उद्धृत, पृष्ठ 30

आर्थिक संस्थाएं बुनियादी तौर पर बदली जा सकें। यहां प्रस्तुत कार्यक्रम और राजनीतिक दिशा पार्टी को आने वाले संघर्ष में महत्वपूर्ण भागेदारी करने लायक बनायेंगे।

नियोजन

1. वर्तमान आर्थिक नियोजन का पूरा दिवालियापन नीचे लिखी बातों से बिल्कुल साफ है:-

   (क) खेती और अनाज की पैदावार में गतिरोध,

   (ख) ओद्योगिक प्रगति में गिरावट,

   (ग) बेकारी की लगातार बढ़ोत्तरी,

   (घ) रहन-सहन ने स्तर तथा आमदनी में बढ़ती विषमता जिसके कारण एक फीसदी अल्पसंख्यक द्वारा राष्ट्रीय आमदनी के बड़े हिस्से की खपत।

2. इस विषम परिस्थिति से देश को छुटकारा दिलाने के लिए चौतरफा पूंजीकरण के प्रयास की आवश्यकता है, जो केवल बराबरी के वातावरण में ही सम्भव है। अधिकतम बराबरी, पूरी सादगी और अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता आदि ऐसे पूंजीकरण के प्रयास की कुछ अनिवार्य शर्तें हैं जिनके बिना आर्थिक तरक्की की गति में तेजी नहीं आ सकती। कुछ आर्थिक विकास अवश्य हुआ है किन्तु नये स्वतंत्र हुए देशों की तुलना में और अपनी जरूरतों के सन्दर्भ में यह प्रगति महत्वहीन ही है। समाजवादी पार्टी सबसे पहले बराबरी पर आधारित क्रान्ति, और खेत-कारखानों में काम करने वालों के अन्दर आदर्श की भावना जगाकर पूंजीकरण और विकास को तेज करने का प्रयास करेगी।

3. भारत को नियोजन के लिए दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है-भारतीय जन के एक छोटे तबके को क्रमिक ढंग से विकसित करते हुए आधुनिक पश्चिमी स्तर तक पहुंचाना या सारे जनगण के लिए सम्मानीय जीवन स्तर उपलब्ध कराना, इसमें समय चाहे कितना लगे, विकास चाहे कितनी भी कम आंखों के सामने आये, समाजवादी पार्टी दूसरे रास्ते की वकालत करती है। समाजवादी नियोजन में बुनियादी उत्पादन ढांचे के निर्माण और गांवों में पीने का पानी तथा सौचालय की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का कार्य सर्वोत्तम प्राथमिकता पर

होगा। इस नियोजन में सत्तर प्रतिशत धन गांवों के विकास पर खर्च करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

आमदनी में क्षेत्रीय विषमता

1. देश की आबादी में उच्च स्तरीय एक फीसदी और निम्न स्तरी 60 फीसदी, की शहरी क्षेत्रों की, विकसित प्रदेशों एवं क्षेत्रों की प्रति इकाई तथा पिछड़े हुए उपेक्षित क्षेत्रों की आमदनी के बीच जबरदस्त विषमताएं भी हैं।
2. यह विषमता मुख्यतः विदेशी शासन के उस दृष्टिकोण का परिणाम है जिसके अनुसार उसने 50 से 150 वर्षों तक केवल उन्हीं क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास किया जो या तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के केन्द्र बन सकते थे या राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाने में सहायक हो सकते थे।आजाद भारत में भी इस ढांचे को सचमुच बदलने का कोई वास्तविक प्रयास अभी तक नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी जागरूक प्रयास द्वारा ऐसी नयी दिशा देगी। ताकि यह असन्तुलन जल्दी समाप्त हो।

बराबरी

1. समाजवाद का प्रधान लक्ष्य बराबरी लाना है। इसलिये समाजवादी पार्टी बराबरी को ठोस रूप प्रदान करने की चेष्टा करेगी और अपनी इस चेष्टा में वह विभिन्न उपायों, कर और आमदनी की नीतियों और राष्ट्रीयकरण आदि का उपयोग करेगी। पार्टी सारी गैर बराबरियों को एक और दस के अनुपात में लाने का प्रयास करेगी। इसी में आय और खर्च की सीमा बांधने का मतलब होगा-जमा धन और सम्पत्ति की भी सीमा बांधना। मंत्रियों एवं विधायकों, भूतपूर्व राजाओं और व्यापारियों अर्थात देश की शक्तिशाली लोगों की सम्पत्ति के कम से कम एक भाग का राष्ट्रीयकरण करके इसकी शुरूआत करनी होगी। पार्टी की राय में 1:10 का अनुपात कायम होने पर उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
2. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मुफ्त होगी, साथ ही साथ सबको समान रूप से शिक्षा मिलेगी। विशेष प्रकार के सभी प्राथमिक स्कूल खत्म किये जायेंगे।

पूंजी संचय

1. समाजवादी निर्माण का प्रश्न मूलतः पूंजी संचय का प्रश्न है, हमारा विश्वास है कि सादगी, त्याग और अधिकतम सम्भव बराबरी के आधार पर ही इस समस्या का सामना किया जा सकता है।
2. पूंजी कर, व्यय कर, आमदनी और सम्पत्ति पर सीमा, ऐच्छिक श्रम आदि के द्वारा भारत के खेती और उद्योग-धन्धों के पुनः निर्माण के लिये साधन एकत्र किये जायेंगे। तेजी से आर्थिक विकास होने पर पूंजीकरण के लिये अधिकाधिक साधन उपलब्ध होंगे और अन्ततः सामान्य लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा।

संविधान में संशोधन

1. समाजवादी पार्टी नीचे लिखी बातों को मद्देनजर रखकर संविधान में संशोधन करेगीः-

   (क) सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु।

   (ख) राजनैतिक और शासकीय ढांचे को प्रजातांत्रिक स्वरुप प्रदान करने के लिये।

   (ग) सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिए।

   (घ) नागरिक आजादी पर लगे प्रतिबन्धों को दूर करने के लिए।
2. संविधान में सभी स्थानीय और स्वायत्त संस्थानों के हितों को परिभाषित करने के लिए नई व्यवस्थाएं जोड़ेगी तथा पिछड़ों को विशेष अधिकार देगी।[14]

नागरकि आजादी

1. सेना, सशस्त्र कान्स्टेबुलरी, पुलिस नीति निर्धारण करने वाले शासकीय और प्रबन्धक अफसरों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों को राजकीय दलों में शामिल होने का अधिकार होगा।
2. सभी सार्वजनिक क्षेत्र, रेलवे, तथा अर्द्धसरकारी कर्मचारियों के राजनैतिक और प्रजातांत्रिक अधिकारियों पर लगे सारे बन्धनों को उठा लिया जायेगा।

---

14 - रजनीकान्त वर्मा-समाजवादी पार्टी के सिद्धांत, वकतव्य एवं कार्यक्रम से उद्धृत पृष्ठ 34

3. साधारण पुलिस कर्मचारियों को अपनी शिकायतें दूर करने के लिए संगठन बनाने का अधिकार होगा।
4. अपराध सम्बन्धी कानूनों में इस प्रकार सुधार किया जायेगा जिससे किसी नागरिक को जबर्दस्ती डराया, धमकाया तथा अनुचित ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सके।
5. जल्दी और सस्ता न्याय दिलाने के लिए अदालती कार्यवाही में सुधार किया जायेगा।
6. न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया जायेगा और निकटतम मजिसट्रेट के सामने 24 घण्टे के भीतर पेश किये जाने जैसी व्यवस्थओं को कठोरता से लागू किया जायेगा।

विकेन्द्रीकरण

समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को ठोस रुप देने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन करेगी।

(क) पंचायतीराज व्यवस्था तथा स्थानीय निकायों के चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के जरिये कराये जायेंगे। पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों, औरतों, हरिजनों, आदिवासी और अन्य पिछडे. समूहों के हितों की रक्षा के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(ख) योजना तथा विकास पर होने वाला कम से कम पच्चीस प्रतिशत सरकारी खर्च स्वायत्त संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

(ग) अत्यधिक आबादी वाले शहरी केन्द्रों में, नये उद्योगों की स्थापना पर विशेष अपवादों को छोड़कर रोक लगायी जायेगी।

(घ) देश के अन्तरीय क्षेत्रों में कारखानों को इस तरह से फैलाया जायेगा। ताकि सारे देश में औद्योगिक विकास समान रुप से फैलाया जा सके और शहरों में आबादी का अस्वस्थ जमाव न हो सके।

(च) शहरों की सभी खुली जमीन व बड़े खुले मैदान, पर नगरपालिकाओं का कब्जा होगा और उनका सही इस्तेमाल दवाखानों, स्कूल, क्रीड़ा मैदान और सार्वजनिक बगीचों के लिए किया जायेगा।

खेती (कृषि)

1. समाजवादी पार्टी का विश्वास है कि गांवों के विकास के वगैर शहरों का विकास सम्भव नहीं है। इसलिए प्राथमिकताओं में सबसे पहले खेती उसके बाद कुटीर, छोटे उद्योग तथा अन्त में भारी उद्योग होंगे।
2. समाजवादी पार्टी कृषि के चहुँमुखी विकास करने को प्राथमिकता देती है।
3. कृषि उत्पादन में वृद्धि तभी सम्भव है जब उत्पादन के तीन कारकों-भूमि, श्रम एवं पूंजी में से किसी एक की मात्रा में वृद्धि की जाय अथवा खेती में नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाये।
4. भूमि का आकार सैदव स्थित रहा है, न यह बढ़ाया जा सकता है और न घटाया देश में श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और आधुनिक व मशीन रहित तकनीकों के प्रयोग से अधिक श्रम शक्ति को खेती में खपाया जा सकता है। लेकिन इसकी भी एक सीमा है। यदि कृषि उपज से ज्यादा आय प्राप्त हो तो इससे पूरे देश का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा।
5. अकृषि क्षेत्रों में समानता लाने के लिए कृषि से उद्योग की ओर श्रमशक्ति का बहाव तब तक जारी रखना पड़ेगा जब तक कृषि व्यवसाय में लगे श्रमिक की आय अकृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों की आय के बराबर न हो जाय।
6. भू-क्षरण, कृषि उत्पादन घटने का प्रमुख कारण रहा है। यदि इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो कृषि भूमि की उत्पादन शक्ति समाप्त हो जायेगी। अतः भूमि के उपयोग से भी ज्यादा जरूरी है-भूमि संरक्षण। समाजवादी पार्टी भूमि सरंक्षण के लिए ठोस एवं विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगी।
7. नयी जमीन पर खेती करने के लिए भूमि सेना का गठन किया जायेगा।
8. खेत मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय होगी और उसे लागू करने की व्यवस्था की जायेगी।
9. खेती की पैदावार के पूरक के रूप में आम, अमरूद जैसे मौसमी फलों के उत्पादन को बढावा दिया जायेगा। पहाड़ी क्षेत्रों विशेषकर हिमालय की पहाड़ियों में सरकारी व्यवस्था होगी। सरकार पशुपालन और डेरी उद्योग को भी प्रोत्साहन देगी।

10.किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फसल बीमा की योजना लागू की जायेगी।

11.खेत मजदूरों, हरिजनों, आदिवासियों और साधनहीन स्त्रियों को कर्ज के बोझ से मुक्त कर दिया जायेगा।

12.अलाभकर जोतों के किसानों और खेत मजदूरों को उनकी पसन्द के अनुसार दुधारू गया या भैंस उपलब्ध करायी जायेगी। समाजवादी पार्टी का विश्वास है कि ग्रामीण अंचल में एक दुधारू गाय या भैंस से एक परिवार का भरण पोषण सम्भव हो सकता है।[15]

सिंचाई एवं बिजली

1. खेती से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए गरीब किसानों को सिंचाई की सुविधा मुफ्त होगी तथा दूसरे किसानों के लिए सस्ती सिंचाई सुविधा की व्यवस्था करना समाजवादी पार्टी के नियोजन का लक्ष्य होगा ।
2. छोटी और बड़ी मध्यम हर प्रकार की सिंचाई की ऐसी योजनाएं कार्यान्वित की जायेगी। जिससे 7 वर्ष के अन्दर तथा सम्भव कोई भी खेती असिंचित न रहे।
3. समाजवादी पार्टी चाहती है कि बिजली गांव-गांव पहुंचे। निजी नमकूपों के लिए बिजली कनेक्शनों को शीर्ष वरीयता दी जायेगी तथा सिंचाई के लिए प्रयोग में आने वाली बिजली की दरें तुलनात्मक रूप से कम होगी।

जंगल और आदिवासी

1. वर्तमान कठोर जंगल कानूनों से आदिवासियों को मुक्त किया जायेगा, जंगल अफसरों और पुलिस द्वारा उनको तंग किया जाना खत्म होगा और जंगल की उचित व्यवस्था करने में आदिवासियों को हिस्सेदार और जिम्मेदार बनाया जायेगा।
2. जलाने की लकड़ी, पत्ते आदि लेने के लिए आदिवासियों के अधिकारों का आदर किया जायेगा।
3. जिन आदिवासी जमीनों पर पहले खेती होती थी, और उन्हें जंगल क्षेत्र में ले लिया गया, उन्हें वापस कर दिया जायेगा।

---

15 - रजनीकान्त वर्मा -समाजवादी पार्टी के सिद्धांत, वकतव्य एवं कार्यक्रम से उद्धृत, पृष्ठ 37

4. पुर्नप्राप्ति जमीनों में बसाने को आदिवासियों और हरिजनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. आदिवासियों और हरिजनों को मकान बनाने क लिए नयी जमीनें दी जायेंगी।

बाढ़ और अकाल

1. अकाल ग्रस्त इलाकों में सरकार मुफ्त भोजन की व्यवस्था करेगी, चाहे वह मात्र जीवन-रक्षा योग्य ही हो।
2. पुरानी दुर्भिक्ष संहिताओं के स्थान पर एक व्यापक दुर्भिक्ष कानून होना चाहिए, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार लोगों को भोजन देने की अपनी जिम्मेदारी को संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों के सन्दर्भ में स्वीकार करे। प्राकृतिक मृत्यु और भूख से मृत्यु जैसे शब्द साफ-साफ परिभाषित हों।
3. सरकार बार-बार आने वाली बाढ़ों के कारणों का पूरा पता लगाकर उनको रोकने के पर्याप्त उपाय करेगी। मकान, पशु, खेत और अन्य सम्पत्ति का नुकसान होने पर पूरा मुआवजा देने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

भ्रष्टाचार

1. प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अवकाश प्राप्त होने अथवा करने के बाद निजी कम्पनियों में नौकरी स्वीकार करने पर पाबन्दी होगी।
2. हाइकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट का कोई न्यायधीश न्यायिक कार्यों के अलावा किसी और सरकारी नौकरी पर नहीं लगाया जायेगा।
3. किसी भी मंत्री या प्रशासनिक कर्मचारी के एक पीढ़ी तक के रिश्तेदार का लाइसेंस या परमिट आदि के लिए प्रार्थना पत्र नहीं स्वीकार किया जायेगा।

दाम-नीति

समाजवादी पार्टी एक सुसंगठित कल्याणकारी दाम नीति लागू करेगी जिसमें मुख्य पहलू होंगे:-

(क) रोजमर्रा की जरुरतों की कारखानों में बनी चीजों का दाम लागत खर्चे के डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगां इसमे सभी कर और मुनाफे शामिल होंगे।

(ख) दो फसलों के बीच अनाज के दामों में मौजूदा विस्तृत उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण किया जायेगा। इस उतार-चढ़ाव को सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं होने दिया जायेगा।

(ग) कारखानों के और खेती के दामों में संतुलन स्थापित किया जायेगा।

(च) संतुलन के इसी सिद्धान्त का आग्रह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जायेगा ताकि अमीर देशों द्वारा गरीब खेतिहर देशों का शोषण कम हो।

(छ) अनाज के थोक व्यापार का सामाजीकरण किया जायेगा।

(ज) थोक व्यापार का समाजीकरण इस प्रकार होगा कि छोटे फुटकर व्यापारियों की सेवाएं राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति में लगायी जा सकें।

(ञ) समाजवादी पार्टी छोटे व्यापारी और फुटकर विक्रेता की मित्र है। जो आज सरकारी नियंत्रणों और नियमों से परेशान रहने के अतिरिक्त, बड़े पूंजीपतियों और वितरकों, के हथकण्डों के भी शिकार होते हैं।

(झ) जब तक देश से भूख को खत्म नहीं कर दिया जाता, भोजन की वस्तुओं का निर्यात बन्द कर दिया जायेगा।

(त) अनाज और खाने-पीने की वस्तुओं पर से बिक्री कर समाप्त कर दिया जायेगा[16]

मिलावट

भोजन-सामग्री और दवाओं में मिलावट ऐसा जुर्म हो जिसकी सख्त और लम्बी सजा मिले।

उद्योग

1. समाजवादी पार्टी ऐसे हर प्रकार के उत्पादन के साधनों और व्यापारों के सामाजीकरण के पक्ष में है जिसमें पगारी मजदूर काम करते हों लेकिन ऐसा सामाजीकरण क्रमिक होगा।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के बारे समाजवादी पार्टी समझती है कि सार्वजनिक क्षेत्र अफसरों और मामूली मजूदरों के बीच आमदनियों और सुविधाओं की असहनीय विषमताएं कायम कर रहा है। पार्टी सार्वजनिक क्षेत्रों के इन दोषों को दूर कर लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के आधार पर उसका पुनर्गठन करेगी।

16 - रजनीकान्त वर्मा-समाजवादी पार्टी के सिद्धांत, वकतव्य एवं कार्यक्रम से उद्धृत, पृष्ठ 40

3. भारत की विदेशी सहायता पर बढ़ती हुई निर्भरता विदेशी पूंजी विनियोग में भारी वृद्धि और भारतीय व्यापार प्रतिष्ठानों से विदेशी फर्मो का गठजोड़ भारत के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं।

4. समाजवादी पार्टी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के भारत में बेरोकटोक प्रवेश को भारत की आर्थिक अजादी के लिए सबसे गम्भीर खतरा मानती है। इसलिये पार्टी देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रेवश पर पूर्ण प्रतिबन्ध का समर्थन करती है।

औद्योगीकरण और रोज़गार

औद्योकिगरण में मानव श्रम का स्थान मशीन ले लेती हैं आज देश में जहां पूंजी अल्प मात्रा में उपलब्ध है वहां मानव श्रम प्रचुर मात्रा में है। पूंजी पर ब्याज की तुलना में मजदूरी काफी कम है जिसकी वजह से मशीनों की अपेक्षा श्रम सस्ता पड़ता है। ऐसी स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था का आधार विकेन्द्रित छोटे पैमाने के श्रम, प्रधान उद्योगों और पूंजी की बचत करने वाली तकनीकों को बनाना चाहिए न कि शहरों में स्थित बड़े पैमाने के उद्योगों को जिनमें बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है।

समाजवादी पार्टी उद्योगों के निश्चित वर्गीकरण के पक्ष में है। यह वर्गीकरण इस प्रकार का हो कि जिन वसतुओं का उत्पादन करने में कुटीर उद्योग असमर्थ हो उनका ही उत्पादन छोटे, पैमाने के उद्योग करे और छोटे पैमाने के उद्योग जिन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते उसका उत्पादन का अधिकार मध्यम श्रेणी के उद्योग को दिया जाये। और ऐसी वस्तुओं का निर्माण बड़े उद्योग करें जिनको बनाने में मध्यम श्रेणी के उद्योग असमर्थ हों।

इस वर्गीकृत व्यवस्था से रोजगार का स्तर अधिकतम किया जा सकता है। कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में (बारह) 12 गुना ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।

मजदूर

1. समाजवादी पार्टी एक प्रबल संगठित मजदूर आन्दोलन का निर्माण चाहती है और इस बात के लिए अथक प्रयास करेगी कि सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग एक प्रजातांत्रिक आधार पर गठित मजदूर संगठन के अन्तर्गत कार्य करे।

2. इस प्रकार मजदूर आन्दोलन की एकता मजदूर वर्ग को सम्मानजनक समझौतों के लिए ताकतवार आधार प्रदान करेगी और मजदूर आन्दोलनों के प्रयासों में एक लड़ाकू तीखापन पैदा करेगी।

3. इस उद्देश्य के लिए पार्टी का पहला कदम होगा कि पार्टी से सम्बद्ध संगठनों को एक ताकवर मजदूर संघ में ढाले जो एक रचनात्मक/जुझारू समाजवादी आधार पर चले।

4. समाजवादी पार्टी मजदूर आन्दोलन में सुधार कर उसे पुनः संगठित करेगी, भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करेगी, राजनीति विरोधी अलगाव के दृष्टिकोण से जूझेगी और उचित आन्तरिक चुनावों पर आग्रह करेगी।

5. एक मजदूर नीति की दिशा में पार्टी मजदूर वर्ग को उसका उचित अधिकार दिलाने के लिए निम्नलिखित प्रगतिशील कदम उठायेगी।

(क) विभिन्न संगठित उद्योगों के संगठित क्षेत्रों में अलग अलग वेतन मंडल नियुक्त किया जायेगा।

(ख) समूचे असंगठित क्षेत्र के लिए नयूनतम मजदूरी निर्धारण समितियां बनायी जायेंगी।

(ग) बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव को खत्म करने के लिए मंहगाई भत्ता को जीवन निर्वाह के खर्चे से सम्बद्ध किया जायेगा।

(घ) सरकारी तथा अर्द्धसरकारी कर्मचारियों की आचरण संहिता के नियमों में संशोधन किया जायेगा।

(द) एक व्यापक कानून बनाया जायेगा जिसके अन्तर्गतः

1. मजदूर यूनियनों को अनिवार्य मान्यता दी जायेगी,
2. समय समय पर मजदूरों के मतदान द्वारा प्रतिद्वन्दी यूनियनों की प्रतिनिधित्व का विवाद हल किया जायेगा।
3. हड़ताल तोड़क कार्यवाहियों पर रोक लगायी जायेगी, लेकिन व्यर्थ हड़ताल पर पाबन्दी होगी।
4. मनचाही मुअत्तलियों तथा बर्खास्तगियों को रोककर रोजगार की सुरक्षा की जायेगी, लेकिन व्यर्थ नेतागिरी भी नहीं चलने दी जायेगी।

6. माहवारी आमदनी का एक प्रतिशत मजदूर संगठनों की मेम्बरी का न्यूनतम शुल्क होगा।

(त) कार्य शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ताकि अधिक से अधिक प्रबन्धक कर्मचारी मजदूर वर्ग से ही पदोन्नत किये जा सकें।

6. पार्टी बुढ़ापे की पेंशन और बेकारी से राहत की ऐसी योजनाएं बनायेगी जो धीरे-धीरे सारी जनसंख्या पर लागू होगी।

7. उन्हीं मजदूर यूनियनों को मान्यता दी जायेगी जो कामगार और देश के हित की बात करेंगी।

शिक्षा

1. निरक्षता निश्चित स्वरुप से 7 वर्ष की अवधि से दूर कर दी जायेगी और साक्षरता सेना गठित की जायेगी।
2. शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जायेगा। वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा। अनुसंधान तथा वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति को, न कि भाषा पर सतही अधिकार को लक्ष्य बनाया जायेगा।
3. शिक्षा के अवसर का विस्तार होगा। अगर आवश्यकता हुई तो प्रातःकालीन और सायंकालीन कक्षाएं चलायी जायेंगी। नौकरियों में तरजीह के सिद्धांत का यह अभिप्राय न होगा कि किसी को अवसर न मिले। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और
4. अनुसंधान कार्य का पुनः संगठन किया जायेगा और उपलब्ध सुविधाओं द्वारा ऐसे उद्योग धन्धों में विज्ञान के उपयोग तथा लघु इकाई यंत्रों को प्रोत्साहित किया जायेगा जो (क) रोजगार में वृद्धि, (ख) विकेन्द्रीकंरण तथा (ग) ग्रामीण विकास में सहायक बन सके।
5. किसी भी मजहब के नाम पर चलने वाली संस्थाओं को कोई राजकीय सहायता नहीं मिलेगी।
6. सरकारी स्कूलों के अध्यापकों और निजी स्कूलों के बीच वेतन क्रम और सुविधाओं की असमानताओं को दूर किया जायेगा।

6. समाजवादी पार्टी शिक्षा जगत में नकल की प्रवृत्ति का विरोध करती है और इसको रोकने के लिए परम्परागत तरीकों को प्रभावी ढंग से लागू करने की हामी है। भावना पैदा होगी, वह देश के लिए आने वाले दिनों में एक आत्मघाती कदम होगा। ऐसा पार्टी का विश्वास है। इसलिए पार्टी ऐसे सभी अवांछनीय सरकारी कानूनों, अध्यादेशों को तत्काल समाप्त करने की पक्षधर है।
7. समाजवादी पार्टी सबको शिक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसलिए की आबादी वाले हर गांव में एक पक्का प्राइमरी स्कूल तथा हर दो प्राइमरी स्कूलों के बीच एक जूनियर हाईस्कूल स्थापित करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर हो ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना है।
8. समाजवादी पार्टी हर बलाक मुख्यालय पर कन्याओं के लिये एक इण्टर कालेज खोले जाने की प्रबल पक्षधर है।
9. समाजवाद पार्टी शिक्षा क्षेत्र में नकल को अभिशाप मानती है।[17]

जाति का खात्मा

1 असमानता के खिलाफ संघर्ष का एक आयाम इस देश में जाति पांति से भी जुड़ा हुआ है। राजनीतिक व आर्थिक समानता सामाजिक क्षेत्र से जुड़ कर ही हो सकती है। सामन्तवादी, पूंजवादी शोषण के खिलाफ छेड़ा गया वर्ग संघर्ष तभी सफल हो सकता है जबकि सामाजिक समानता के साथ उसे जोड़ा जा सके।

2 यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि समानता व समान अवसर एक ही चीज नहीं है। एक ऐसे समाज में जिसके भीतर जन्म के आधार पर विभिन्न स्तर बन जाते हो, समान अवसर का सिद्धांत समाज में समता पैदा नहीं कर सकता। औरत, शूद्र, हरिजन, आदिवासी और पिछड़ी जातियो जिनमें अल्पसंख्यक भी सम्मिलित हैं, को सभी सामाजिक व्यवसायों राजनीतिक एवं शासकीय नेतृत्व स्थानों में विशेष अवसर के सिद्धान्त पर 60% से 70%

17 - रजनीकान्त वर्मा-समाजवादी पार्टी के सिद्धांत, वकतव्य एवं कार्यक्रम से उद्धत पृष्ठ 44

आरक्षण तब तक मिले जब तक जातिगत विद्या-बुद्धि-संस्कार की भिन्नता मिट नहीं जाती।

3 आज पिछड़े वर्गों में, हरिजन, आदिवासी, हिन्दुओं की पिछड़ी जातियां, औरत तथा अल्पसंख्यक माने जा सकते हैं। ये आज की पूरी आबादी में 80 प्रतिशत या और भी अधिक हैं।

4 आर्थिक शोषण के खिलाफ और आर्थिक असमानता के लिए किया गया संघर्ष, आमदनी की अधिकतम सीमा तथा जमीन के बंटवारे की लड़ाई, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ऊंची जातियों द्वारा समाज की बहुसंख्या के शोषण के विरूद्ध जन भाषा का प्रसार, निश्चित ही बराबरी के समाज के निर्माण में प्रबल सहायक सिद्ध होंगे लेकिन इसे साकार रूप देने के लिए पिछड़ों को विशेष अवसर देने का सिद्धांत अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।

5 महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों को एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 60 से 70 फीसदी आरक्षण का इसीलिए समाजवादी पार्टी समर्थन करती है।

7. समाजवादी पार्टी अपने ईमानदार इरादों की शुरूआत के लिए इस सिद्धांत को अपनी पार्टी की समितियों के निर्माण में तथा विभिन्न विधान मंडलों, नगरपालिकाओं और नियमों के लिए उम्मीदवारों के चयन में लागू करेगी।

8. विशेष छात्रावास की सुविधाएं, छात्रवृत्तियां, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें आदि की व्यवस्था पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जिनमें छात्राएं भी शामिल हैं, की जायेगी।

औरत और युवक

1. समाजवादी नियोजन में प्रथम स्थान गांवों में शौचालयों तथा पीने के साफ पानी के नलों की व्यवस्था को दिया जायेगा जिससे ग्रामीण औरतों के अपमानजनक कष्ट का निवारण हो सके।

2. सरकार युवक केन्द्रों की शृंखला कायम करेगी, खेल कूद और शारीरिक व्यायाम को प्रोत्साहन देगी ताकि ओलाम्पिक खेलों में भारत के प्रदर्शन में सुधार हो सके।
3. काम करने वाली मजदूर औरतों के लिए शहरों में सस्ते आवासों की व्यवस्था की जायेगी।
4. अनतर्जातीय विवाह सरकारी नौकरियों के लिए एक अतिरिक्त योग्यता मानी जायेगी।

भाषा नीति

1. भाषा का सवाल साधारण जनता की नजर से देखा जायेगा।
2. समाजवादी पार्टी सार्वजनिक जीवन से अंग्रेजी का तत्काल वहिष्कार चाहती है।
3. अंग्रेजी का सतत् प्रयोग शिक्षा के शीघ्र प्रसार के लिए बाधक बनता है। पूरा प्रशासकीय तंत्र थोड़े से लोगों में सीमित रह जाता है तथा विशाल जनसंख्या प्रशासन में शामिल होने से वंचित रह जाती है। यह बराबर एक राष्ट्रीय अपमान की याद हमारे दिलों में ताजा रखती है। और बहुत बड़ी जनसंख्या में एक हीन भाव बनाये रखती है तथा थोड़े लोगों में एक दर्द का भाव पैदा करती है।
4. अंग्रेजी को हटाना प्रजातांत्रिक मांग है। भाषावार प्रान्तों के निर्माण के सिद्धांत की एक अनिवार्य शर्त उन प्रान्तों में वहां के क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की हो जाती है। इसके बिना आधार पर प्रान्तों का विभाजन एक बेमानी बात हो जाती है।
5. भाषा के सवाल को निम्नलिखित आधार पर हल किया जाना चाहिएः-

(क) प्रान्तीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाएं, अंग्रेजी के स्थान पर प्रशासन व शिक्षा का और उच्च न्यायालय व अन्य अदालतों के कार्य का माध्यम बनेंगी।

(ख) अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग वैकल्पिक रहेगा।

(ग) हिन्दी भाषी प्रदेशों में अंग्रेजी के स्थान पर प्रशासकीय व शिक्षा के माध्यम का स्थान हिन्दी लेगी।

(घ) केन्द्रीय स्तर पर अहिन्दी क्षेत्रों में अंग्रेजी का स्थान सभी विभागों में हिन्दी लेगी। अहिन्दी प्रदेशों के लिए यदि वे ऐसा चाहें अंग्रेजी केन्द्रीय व्यवहार की भाषा हो

सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी चाहती है कि अहिन्दी क्षेत्रों में केन्द्रीय कार्यालयों में काम-काज में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग हो और अंग्रेजी तत्काल हटे। समाजवादी पार्टी इस बात को साफ कर देना चाहती है कि अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी थोपने का कोई सवाल ही नहीं हैं।

(च) अहिन्दी प्रदेशों में कुछ ऐसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने चाहिए जिनमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो।

(छ) स्कूलों व कालेजों में अंग्रेजी अनिवार्य विषय न होगी। अंग्रेजी के ज्ञान की कमी बड़े से बड़े ओहदे के लिए कभी बाधा न बनेगी।

(ज) समाजवादी पार्टी इस बात को नहीं मानती कि अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान की खिड़की अंग्रेजी है। यह अन्य विदेशी भाषाओं जैसे रुसी, जापानी, चीनी, जर्मन आदि को प्रोत्साहन देगी तथा सीधे इन्हीं भाषाओं से हिन्दुस्तानी भाषाओं में अनुवाद को प्रोत्साहित करेगी।

(झ) पार्टी संसदीय कार्यवाही में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में स्वानुवाद की व्यवस्था चाहेगी ताकि सभी अहिन्दी भाषी सदस्य अपनी क्षेत्रीय भाषा का उपयोग कर सकें।

6. हर क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के उपयोग से ही ये सम्पन्न बनायी जा सकती हैं। उनकी सम्पन्नता की प्रतीक्षा करने में वे कभी भी सम्पन्न नहीं हो सकतीं। समाजवादी पार्टी की राय में भारतीय भाषाओं में अपने संस्कृति, प्रकृति तथा फारसी के उत्तराधिकार के साथ महान भाषा के सभी तत्व वर्तमान है। जरूरत है कि आधुनिक कार्यों में उनका प्रयोग चालू हो।

धर्मनिपेक्षता

भारत एक धर्मनिपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसमें उन शक्तियों, और संगठनों का कोई औचित्य नहीं है जो भारतीय संविधान के इन आधारभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण करते हैं। कुछ दल एवं संगठन देश में साम्प्रदायिक उन्माद फैलाकर देश को तोड़ने का प्रयास करने में जुट हैं। उनका न संविधान में विश्वास है न न्याय पालिका में । ऐसी साम्प्रदायिक ताकतें धर्म आधारित राजनीति में विश्वास करती हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि सरकार

संविधान एवं कानून से चलती है न कि आस्था से।समाजवादी पार्टी ऐसी साम्प्रदायिक शक्तियों के विरूद्ध जनसंघर्ष का एलान करती है।

विदेश नीति

समाजवादी पार्टी का मानना है कि विदेशनीति का निर्धारण करते समय राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिये।

दुर्भाग्य से आजादी के बाद से विदेश नीति को गलत दिशा की तरफ मोड़ दिया गया। चाहे कश्मीर का मामला अपनी तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजने का हो, तिब्बत पर चीन का स्वामित्व स्वीकार करने का हो, या श्रीलंका में शन्ति सेना भेजने का सवाल हो ये कदम पूरी तरह गलत सिद्ध हुये हैं।

हमारे संबंध पड़ोसी देशों से अच्छे नहीं हैं। चीन तथा पाकिस्तान के कब्जे में आज भी हमारी भूमि हैं। समाजवादी पार्टी देश को आर्थिक एवं समाजिक मोर्चे पर पूरी तरह आत्म निर्भर बनाकर अपने खोये हुये सम्मान को वापस पाने का प्रयास करेगी।

सोवियत संघ ने विघटन के बाद अमेरिका के एकाधिकार का मुकाबला सशक्त गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के द्वारा ही संभव है। भारत जो इस आन्दोलन के जनक के रूप में जाना जाता था अपने नेतृत्व की अदूरदर्शिता से इस आन्दोलन का नेता नहीं रह गया है।

समाजवादी पार्टी का मानना है कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन में सक्रिय भूमिका अदा करके भारत इसे नेतृत्व प्रदान कर सकता है और पूंजीवादी देशों द्वारा विकासशील देशों के शोषण को रोक सकता है।

समाजवादी पार्टी सभी पड़ोसी देशों से मथुर सम्बन्धों की पक्षधर है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों के नियमन के लिये आज भी 'पंचशली' के सिद्धान्तों को सर्वथा उपयुक्त मानती है। आपसी द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सीमा विवाद को हल करके खोयी हुयी जमीन को वापस पाने के लिए भारत की तरफ से शीघ्र एवं सक्रिय प्रयास किये जाने का पार्टी समर्थन करती है।

मंडल आयोग

समाज के पिछडे वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिये समाजवादी पार्टी मंडल आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को न्यायालय में अनिश्चित काल तक उलझाये रखने की कुटिल नीति का समाजवादी पार्टी घोर विरोध करती है।[18]

18 - रजनीकान्त वर्मा-समाजवादी पार्टी के सिद्धांत, वकतव्य एवं कार्यक्रम से उद्धृत, पृष्ठ 48

लोक सभा चुनाव में 1996-99 तक संक्षिप्त विवरण तालिका
लोक सभा निर्वाचन 1998
दलवार स्थिति

कुल सीट - 543
घोषित - 535

वर्ष 1996			वर्ष 1998	
1.	भारतीय जनता पार्टी	162	**भाजपा एवं सहयोगी दल**	
2.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	138	भारतीय जनता पार्टी	177
3.	जनता दल	29	अन्ना द्रमुक	18
4.	भारतीय कम्युनिस्ट (एम)	32	समता पार्टी	12
5.	तमिल मनीला कांग्रेस (मू)	20	बीजू जनता दल	9
6.	समाजवादी पार्टी	17	शिरोमणि अकाली दल	8
7.	तेलगुदेशम पार्टी	17	तृणमूल कांग्रेस	7
8.	द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	16	शिव सेना	6
9.	राष्ट्रीय जनता दल	16	पट्टलि मक्कल काच्ची (पीएमके)	4
10.	शिव सेना	15	मारू मलारची द्रमुक (एम डी एमके)	3
11.	मा0 कम्युनिष्ट	12	लोकशक्ति	3
12.	बहुजन समाजपार्टी	11	हरियाणा विकास पार्टी	1
13.	शिरोमणि अकाली	8	जनता पार्टी	1
14.	समता पार्टी	5	कुल (भाजपा और सहयोगी दल)	249
15.	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्टपार्टी	5	**कांग्रेस और सहयोगी दल**	
16.	असम गण परिषद	5	कांग्रेस	141
17.	आल इंडिया इंदिरा कांग्रेस (तिवारी)	4	राष्ट्रीय जनता दल	17
18.	आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक	2	रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया	4
19.	हरियाणा विकास पार्टी	3	मुस्लिम लीग	2
20.	समाजवादी जनता पार्टी	3	केरल कांग्रेस (एम)	1
21.	मुस्लिम लीग	2	कुल (कांग्रेस और सहयोगी दल)	165
22.	मजलिस ए इत्तिहादुल मुसलमान	1	**संयुक्त मोर्चा**	
23.	अटोनोमिस स्टेट डिमांड कमेटी	1	मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी	32
24.	झारखण्ड मुक्तिमोर्चा	1	समाजवादी पार्टी	20
25.	महाराष्ट्र गोमान्तक पार्टी	1	तेलगुदेशम	12
26.	केरल कांग्रेस (एम)	1	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	9
27.	सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट	1	जनता दल	6
28.	यूनाइटेड गोवा डेमोक्रेटिक पार्टी	1	द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम	6
29.	भा0 कि0 कामगार पार्टी	1	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	5
30.	निर्दलीय	9	तमिल मनीला कांग्रेस (एम)	3
31.	मनोनीत	2	फारवर्ड ब्लाक	2
32.	रिक्त	3	धर्मरिपेक्ष कांग्रेस	1
	कुल	544	कुल	96

निर्दलीय व अन्य

बहुजन समाज पार्टी	5		मजलिसे इ मुसलमीन	1	UDF
अरूणाचंल कांग्रेस	2	BJP	रा0 जनता पार्टी	1	CONG
समाजवादी जनता पार्टी	1	UDF	यू0 डे0 पा0	1	
आटोनामस स्टेट डी-का	1	UDF	हरियाणा लोकदल	4	BJP
सिक्किम-डे प्रा	1		तमिल राजीव कांग्रेस	1	BJP
यू0 एम0 एफ0	1	UDF	निर्दलीय	6	
			कुल	25	

UTTAR PRADESH

LOK SABHA GENERAL ELECTION – 1998

SUMMARY OF ASSEMBLY SEGMENT WISE DETAILED RESULTS

Total Parliamentary Constituencies : - 85

Total No. of Assembly Segments :- 425

PARTY NAME	No of Assembly won
BHARATIYA JANTA PARTY (BJP)	252
BHARATIYA KISAN KAMGAR PARTY (BKKGP)	2
BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP)	32
INDIAN NATIONAL CONGRESS (INS)	9
INDEPENDENT (IND)	7
SAMATA PARTY (SAP)	6
SAMAJWADI JANTA PARTY (RASHTRIYA) (SJP)	3
SAMAJWADI PARTY (SP)	114
Grand Total :-	**425**

UTTAR PRADESH

Lok Sabha General Elections 1999

Assembly Segment Wise Party Performance

Name of Party	No of assembly segments leading
Samajwadi Party	129
Bharatiya Janata Party	125
Bahujan Samaj Party	88
Indian National Congress	43
Rashtriya Lok Dal	14
Akhil Bhartiya Lok Tantrik Congress	10
Independent	6
Samajwadi Janta Party (Rashtriya)	5
Apna Dal	3
Janata Dal (United)	2
Total Assembly Segments :	**425**

(N) Party wise Female Candidates Performance

	PARTY NAME	Contested	Won
PSJP	Parivartan Samaj Party	2	
BKD	Bahujan Kranti Dal	1	
BRPP	Bharatiya Republican Paksha	2	
AJBP	Ajeya Bharat Party	3	
IND	Independent	17	1
AD	Apna Dal	1	
UKKD	Uttarakhand Kranti Dal	1	
CPI	Communist Party of India	1	
INC	Indian National Congress	14	3
BSP	Bahujan Samaj Party	3	1
SP	Samajwadi Party	9	3
BJP	Bharatiya Janata Party	5	1
CP(ML)(L)	Communist Party of India	1	
AIMLF	All India Muslim Forum	1	
RPI	Republican Party of India	1	
		63	9

(O)Party Wise Winning and runner up statistics

	PARTY NAME	ContestedAt	1st Position	At IInd Position
BJP	Bharatiya janata Party	77	29	35
SP	Samajwadi Party	84	26	22
BSP	Bahujan Samaj Party	85	14	15
INC	Indian National Congress	76	10	08
IND	Independent	610	1	0
RLD	Rashtriya Lok Dal	7	2	3
ABTC	Akhil Bhartiya Lok Tantrik Congress	4	2	1
JD(U)	Janata Dal (United)	2		1
SJP(R)	Samajwadi Janata Party (Rastriya)	2	1	

General Election -1999

Party wise Performance ***Uttar Pradesh***

PARTYNAME		candidates Contested	Won	Vote Secured	Percent 1999	Secured 1998
BJP	Bharatiya Janata Party	17	29	15019970	27.64%	36.49%
SP	Samajwadi Party	84	26	13078686	24.05%	28.69%
BSP	Bahujan Samaj Party	85	14	12001855	22.08%	20.91%
INC	Indian National Congress	76	10	8001649	14.72%	6.02%
IND	Independent	610	1	1965727	3.62%	2.79%
RLD	Rashtriya Lok Dal	7	2	1352694	2.49%	
AD	Apna Dal	45		841429	1.55%	0.94%
ABLTC	Akhil Bhartiya Lok Tantrik Congress	4	2	818713	1.51%	
JD (U)	Janata Dal (United)	2		321294	0.59%	
SJP (R)	Samajwadi Janta Party (Rashtriya)	2	1	249621	0.46%	0.47%
CPI	Communist Party of India	11		150516	0.28%	0.18%
NLP	National Loktantrik Party	27		127382	0.23%	0.25%
AJBP	Ajeya Bharat Party	44		48316	0.09%	0.03%
JD(S)	Janata Dal (Secular)	18		46943	0.09%	
CPI(ML)(L)	Communist Party of India (Marxist-Lennini)	9		38076	0.07%	0.05%
PMSP	Pragatisheel Manav Samaj Party	6		36920	0.07%	0.01%
SHS	Shivsena	16		29610	0.05%	0.05%
BRPP	Bhartiya Republican Paksha	9		25713	0.05%	
UKKD	Uttarakhand Kranti Dal	4		14302	0.03%	0.05%
JP	Janata Party	2		14214	0.03%	
CPM	Communist Party of India (Marxist)	2		13884	0.03%	0.22%
SSD	Shoshit Samaj Dal	4		12795	0.02%	0.00%
JSAP	Jan Satta Party	4		11024	0.02%	
AIMLF	All India Muslim Forum	3		10007	0.02%	0.00%
LS	Lok Shakti	3		9244	0.02%	0.01%
PSJP	Parivartan Samaj Party	6		7963	0.01%	
MUL	Muslim League Kerala State Committee	5		7851	0.01%	0.00%
BSD	Bhartiya Samaj Dal	1		7607	0.01%	

General Elections-1999

Party Wise performance ***Uttar Pradesh***

	PARTYNAME	Candidates Contested	Won	VoteSecured	Percent 1999	Secure 1998
ABJS	Akhil Bharatiya Jan Sangh	1		7403	0.01%	0.00%
ASP	Ambedkar Samaj Party	8		7260	0.01%	
ABBP	Akhil Bhartiya Berozgaar Party	3		7134	0.01%	0.00%
LSWP	Loktantrik Samajwadi Party	2		6854	0.01%	0.01%
ABHM	Akhil Bharat Hindu Mahasabha	3		6219	0.01%	0.00%
GSP	Gareebian Samaj Party	2		4725	0.01%	0.00%
RPI	Republican Party of India	3		4514	0.01%	0.00%
RUD	Rashtriya Unnatisheel Dal	1		4104	0.01%	
BND	Bhartiya Naujawan Dal	1		3895	0.01%	
SVSP	Savan Samaj Party	1		3663	0.01%	
IUML	Indian Union Muslim League	1		3069	0.01%	0.00%
AIRKC	All India Rajiv Krantikari Congress	2		2993	0.01%	
BLKD	Bharatiya Lok Kalyan Dal	1		2896	0.01%	
BBMKD	Bharatiya Berozgar Mazdoor Kisan Dal	1		2706	0.00%	
GGP	Gondvana Gantantra Party	1		2455	0.00%	0.01%
JKNPP	J & K National Panthers Party	1		1998	0.00%	
HDVP	Hind Vikas Party	1		1641	0.00%	
RSD	Rashtriya Sawarn Dal	1		1407	0.00%	
SSJP	Sanatan Samaj Party	1		1333	0.00%	
ABLTP	Akhil Bharatiya Loktantra Party	1		1265	0.00%	0.00%
BKD	Bahujan Kranti Dal	1		1218	0.00%	0.00%
RAM	Rashtriya Aikta Manch	1		1169	0.00%	0.00%
BKD(J)	Bahujan Kranti Dal (Jal)	1		957	0.00%	0.00%
PSP	Prapat School Party	1		858	0.00%	
BNJS	Bharat Nav Jyoti Sangh	1		806	0.00%	
AIMF	All India Minorities Front	1		628	0.00%	
ABP	Ambedkarbadi Party	1		543	0.00%	
KRD	Kranti Kal	1		344	0.00%	0.00%
ABSR	Akhil Bharatiya Shivsena Rashtrawadi	1		244	0.00%	

Lok Sabha General Election – 1999

State At A Glance

a.	Total Electorates	:	10,31,33,770	
b.	Total Votes Polled	:	5,50,78,345	(53.40%)
c.	Total Valid Votes Polled	:	5,43,48,306	(98.67%)
d.	Total Invalid Votes Polled	:	7,30,039	(1.33%)

Statistics of Electoral data and Candidate performance

(A)	Maximum Contesting Candidates	:	33 - GONDA	(32 Candidates)
(B)	Minimum Contesting Candidates	:	75 – HATHRAS	(6 Candidates)
(C)	Maximum Electoral Constituency	:	79 – HAPUR	(1577173)
(D)	Minimum Electoral Constituency	:	3 – ALMORA	(971789)
(E)	Highest Polling %age	:	13 – PILIBHIT	(66.33%)
(F)	Lowest Polling %age	:	77 – KHURJA (SC) 01 – TEHRI GARWAL	(38.9%)
(G)	Candidates getting maximum Votes	:	MANEKA GANDHI FROM 13 PILIBHIT	(4,33,421)
(H)	Largest Winning Margin	:	SONIA GANDHI (INC) DR. SANJAY SINGH (BJP) 300012 votes [25-AMETHI]	Defeated by
(I)	Lowest Winning Margin	:	PYARE LAL SANKHWAR (BSP) ARUN KUMAR KORI (SP) 105 votes [63 GHATAMPUR (SC)]	Defeated by
(J)	Total number of Candidates	:	1208	
(K)	Total Candidates whose deposits Forfeited	:	963	
(L)	Total number of Female Candidates	:	63	
(M)	Total Female Elected	:	9	

<u>विधान सभा चुनाव वर्ष,96 के मुकाबले लोकसभा चुनाव वर्ष 99 में विधान सभा क्षेत्रवार ब.स. पा./ समाजवादी पार्टी की स्थिति का एक तुलनात्मक अध्ययन</u>

<u>ब. स. पा. में 1996 में 67 विधान सभा क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की थी जिसमें से वर्ष 99 में सम्पन्न चुनाव परिणामों के अनुसार :-</u>

अ- 32 क्षेत्रों में अपनी जीत बरकरार रखी, 35 क्षेत्र अन्य दलों के हाथों खोये

19 क्षेत्रों में द्वितीय स्थान पर रही,

13 क्षेत्रों में तृतीय स्थान पर रही,

03 क्षेत्रों में चतुर्थ स्थान पर रही।

ब- समाजवादी पार्टी ने 14 क्षेत्र ब. स. पा. से छीने

भा. ज. पा. ने 10 क्षेत्र बसपा. से छीने

कांग्रेस ने 5 क्षेत्र ब.स.पा. से छीने

लोकतांत्रिक कांग्रेस ने क्षेत्र बसपा ने छीना

जनता दल (यू) ने 2 क्षेत्र ब.स.पा. से छीने

स.ज.पा. ने क्षेत्र ब.स.सपा.से छीना

लोकदल ने क्षेत्र ब.स.पा. से छीना

निर्दल ने क्षेत्र बसपा से छीना

....

कुल छिने क्षेत्रों का योग 35

....

<u>समाजवादी पार्टी ने वर्ष 1996 में 20 क्षेत्रों में **अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए थे। इन क्षेत्रों में तालमेल के तहत अन्य दलों के प्रत्याशियों ने बसपा का मुकाबला किया।**</u>

<u>वर्ष 99 में एक विधान सभा क्षेत्र मा0 चन्द्र शेखर जी के क्षेत्र में था जहां स.पा. ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। स.पा. ने केवल 66 स्थानों पर संघर्ष किया।</u>

अ- 14 क्षेत्रो बसपा से छीने

23 क्षेत्रों में द्वितीय स्थान पर रही

23 क्षेत्रों में तृतीय स्थान पर रही

06 क्षेत्रों में चतुर्थ स्थान पर रही

स्रोत- समाजवादी पार्टी कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ 19 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ

अध्याय—५

समाजवादी पार्टी के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक बिन्दु

अध्याय 5
समाजवादी पार्टी के सामाजिक, राजनितिक एवं आर्थिक विचार बिन्दु

1.स्थापना सम्मेलन

समाजवादी पार्टी का दो दिवसीय स्थापना सम्मेलन 4–5 नवम्बर 1992 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्पन्न हुआ।

अध्यक्षीय भाषण–

समाजवादी पार्टी के स्थापना सम्मेलन में 4 नवम्बर 1992 को श्री मुलायम सिंह यादव जी ने सम्मेलन को सम्बोधिक करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि–

समाजवादी साथियों,

लखनऊ की इस सर जमीन पर जो सदियों से भाईचारा, आपसी सहयोग, एक साथ मिलकर रहने की परम्परा तथा आजादी, आत्म सम्मान और इंसाफ के लिए मर–मिटने की तबीयत के लिए इतिहास में मशहूर रही है, भारत के कोने–कोने से आये समाजवादी साथियों का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या से मिला यह शहर राम राज्य की कल्पना को हमेशा साकार करता रहा है जहाँ आदमी को आदमी की शक्ल में देखा जाता रहा है। अवध के नबाबों ने भी वही संस्कृति अपनाकर यह साबित कर दिया था कि भारत का यह हिस्सा, उन संकुचित विचारधाराओं से बहुत आगे है जो मजहबी उन्माद या अलगाववाद के प्रतीक हैं।

1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में हिन्दू और मुसलमानों द्वारा एक जुट होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की दास्तान को पढ़कर मन रोमांच हो आता है। तात्या टोपे, बेगम हजरत महल औ झांसी की रानी, भारत के उस दिल की धड़कन की गुनगुनाहट हैं जिन्हें राष्ट्रीयता, आजादी और आत्म सम्मान के लिए शहादत देने के लिए सदैव याद किया जाएगा।

ऐसी धरती पर आज भारत के समाजवादी लगभग 20 वर्ष बाद समाजवाद के नाम पर एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। यह गुजरे हुए 15–20

साल भारत के इतिहास के बड़े ही खट्टे–मीठे साल थे। 1977 में लोकनायक जय प्रकाश नारायण के आह्वान पर जनता पार्टी बनी थी। हमने उस लाल झंडे को जिसको लेकर हमारे नेता जय प्रकाश, नरेन्द्र देव, डा0 राम मनोहर लोहिया, यूसूफ मेहर अली जैसे लोगों ने समता वाले समाज की रचना के लिये जन आंदोलन चलाये थे, जनता पार्टी को सौंप दिया था। हमारा लक्ष्य है, सत्ता हासिल करके जनहित में उस व्यवस्था को बदलें जिससे गरीब को रोटी, बेकार को काम और राष्ट्र को सम्मान हासिल हो।

जनता पार्टी जब बनी थी, हमारा मन साफ था। हमने बड़ी ईमानदारी से इस पार्टी को जन–जन तक पहुँचाने का काम किया। सोशलिस्टों का जनहित में लगातार संघर्ष और डा0 लोहिया के विचारों के आधार पर जन–मानस को बदलने की भूमिका रही है। हमें याद है जब 1962 में डा0 लोहिया, भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से फूलपुर के संसदीय क्षेत्र के चुनाव में जाकर टकराये थे, उस समय देश में एक नई लहर का आगमन हुआ था। लोहिया ने उस चुनाव में कहा था कि मैं एक चट्टान से टकरा रहा हूँ। मैं जानता हूँ चट्टान को तोड़ नहीं पाऊँगा लेकिन उसको चटका जरूर दूँगा। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस को हराकर बनी थी वह लोहिया के उस अभियान का नतीजा था जो 1962 में उन्होंने शुरू किया था। जनता पार्टी जब बनी थी उस समय उन्होंने ऐसे दल भी थे जो सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जा मिले थें। एक ऐसा दल भी जनता पार्टी में आकर मिल गया था जिसके सोच का नतीजा, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की हत्या थी। हमने उस पर भी यकीन किया था, क्योंकि हमारा मानना रहा है कि भूल आदमी ही करता है और अपने कों सुधारने का मौका उसे मिलना चाहिये।

हमारी ईमानदारी ही हमारे लिये घातक बन बैठी। जनता पार्टी की सरकार के टूटने का कारण यही रहा कि गैर समाजवादी जो जनता पार्टी में शामिल हुये थे, उनका लक्ष्य था सत्ता का उपयोग करो और अपने घटक को मजबूत बनाकर जनता पार्टी को तोड़ दो। इसी क्रम में जनता पार्टी की सरकार टूटी और जनता पार्टी भी बिखरी क्योंकि सत्ता का उपयोग व्यवस्था बदलने के लिए नहीं किया गया था।

1977 से लेकर 1991 तक का दौर समाजवादियों के भटकन का दौर रहा है। हर बार मजहबी तनाव फैलाने वाले दल ने यह प्रयास किया कि देश के अंदर फिरकापरस्ती बढे, हिन्दू–सिख, हिन्दू–मुसलमान, हिन्दू–ईसाई के बीच तनाव बढ़े, दंगा, हिंसा और मारकाट हो तथा धार्मिक उन्माद को बढ़ाकर सत्ता प्राप्त की जाय। 1977 से 1990 के बीच भाजपा ने यही किया। फलस्वरूप अलगाव, टूट और हिंसा का शिकार सारा देश होता रहा और आज भी देश उसी दौर से गुजर रहा है।

यह एक विडम्बना ही रही कि इस बीच चार–चार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, दिल्ली की कुर्सी पर बैठे। लेकिन अपने को प्रगतिशील कहलाने वाले प्रधानमंत्रियों ने भी व्यवस्था बदलने के लिये, एक भी कदम नहीं उठाया।

उस उथल–पुथल के दौर में, सबसे ज्यादा हमला सोशलिस्टों पर किया गया क्योंकि यथास्थितिवादी यह जानते थे कि समाजवादी अगर एकजुट रहे तब तब्दीली की आँधी को रोका नहीं जा सकता। अतः उनका प्रयास, समाजवादियों को तोड़ने का लगातार चलता रहा जो आज भी जारी है।

भारत की दुर्दशा का एक कारण समाजवादियों का विखराव भी रहा है। समाजवादी जब तक एक–जुट थे, सरकार और समाज, दोनों पर उनका अंकुश रहता था। सरकार की जनविरोधी नीतियों का जहाँ एक तरफ समाजवादी विरोध करते थे वहीं विकल्प भी सामने रखते थे और उसके लिए जनमानस बनाने का अभियान भी चलाते थे।

यहाँ देश के सभी समाजवादियों का ध्यान एक कुटिल साजिश की तरफ आकर्षित करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। वह साजिश है देश के इतिहास से समाजवादियों के गौरवशाली योगदान को मिटाने की। भारत छोड़ो आन्दोलन की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर संसद के केन्द्रीय हाल में राष्ट्रपति द्वारा पढ़े गये भाषण में डा0 लोहिया का नाम तक नहीं लिया गया। जिस लोहिया के बगैर भारत छोड़ो आन्दोलन निर्जीव हो गया होता उसे याद न करना महज एक भूल नहीं कहा जा सकता है। यह एक सोची समझी साजिश का एक अंग है जिसके तहत लोहिया के अलावा जय प्रकाश, यूसूफ मेहर अली, कर्पूरी ठाकुर, राज नारायण तथा राम सेवक यादव जैसे महान समाजवादियों द्वारा भारत के पुनर्निमाण के लिये किये गये योगदान को

नकारने का प्रयास किया जा रहा है। हम इन नेताओं के शानदार इतिहास को देश की एक बेशकीमती धरोहर मानते हैं और इसके स्वतन्त्र अस्तित्व को बनाये रखने के लिये बचनबद्ध हैं।

1948 से 1975 तक समाजवादियों का शानदार इतिहास रहा है। समाजवादियों ने ही जन आनदोलन चलाकर, यह मांग की थी कि अलाभकर खेती पर से लगान हटाया जाये, सबसे ज्यादा और सबसे कम आमदनी के बीच का फर्क एक और दस के बीच हो–हमारा नारा था–

"सौ से कम, न हजार से ज्यादा
सोशलिस्टों का यही तकाजा।"

भारतीय भाषाओं को स्थापित करने की मांग, हमीं ने की थी। अंग्रेजी हटाओ, भारतीय भाषाओं को लाओं का नारा समाजवादियों ने ही दिया था।

भारत–पाक की जनता के बीच सद्भावना पैदा करने का, तिब्बत को आजाद कराने का, गोवा से पुर्तगाली साम्राज्यवादियों को हटाकर गोवा स्वतन्त्र कराने का, नेपाल में जनतंत्र की स्थापना की, स्वेज कैनाल पर अंग्रेजी हमले के मिश्र के राष्ट्रपति के साथ खड़े होने का, अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ स्वयं डा0 लोहिया द्वारा सत्याग्रह करने का, एशिया के समाजवादियों को एक मंच पर लाने का, दामों की लूट बंद करके एक दाम नीति बनाने का तथा भारत में 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत विशेष अवसर, दलितों, पिछड़ों,औरतो तथा अल्पसंख्यकों को देने का तथा खर्च पर बंदिश लगाने का, ऐसे जानदार अभियान थे जिसके सामने मजहबी जुनून फैलाकर, सत्ता पर काबिज होने वालों के मंसूबे बराबर परास्त होते रहे। साथ ही कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता तथा उस समय के प्रधानमंत्री चाहे जवाहर लाल नेहरू रहे हों या इंदिरा गाँधी पर भी अंकुश लगाने में समाजवादी सफल रहे हैं।

लोहिया ने राजनीति को गाँव के लोगों तक पहुँचाकर उन्हें समाजवादी विचारधारा से जोड़ दिया था। लोकसभा में जब लोहिया ने तीन आना बनाम 15 आना की बहस के माध्यम से यह उजागर कर दिया था कि भारत की गरीब जनता की तीन आना रोज की आमदनी है, तब सारा देश चौंक पड़ा था। बड़े–बड़े अर्थशास्त्री भी सकते में आ गये थे।

समाजवादियों ने जनमानस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चाहे विधान सभा रही हो या लोकसभा, सोशलिस्टों ने इन पंचायतों को जनता के दुःख, दर्द, आशा और विश्वास का दर्पण बनाने का प्रयास किया था।

जहाँ देश की ऐसी हालत है, वहीं कुछ राजनैतिक दल इस कोढ़ में खाज का काम कर रहे हैं। जरूरत तो इस बात की है कि देश की अर्थ व्यवस्था को सुधार कर करोड़ों बेरोजगार लोगों को काम दिया जाये। उत्पादन बढ़ाया जाये, परती और ऊसर जमीन को खेती लायक बनाया जाये, पशुधन को बढ़ाकर गाँव वालों को पशु दिया जाये, गाँव को स्वावलम्बी बनाने के लिये वहाँ सड़क, बिजली, स्कूल तथा अस्पताल का निर्माण किया जाये लेकिन केन्द्र की सरकार हो या प्रदेश की, ऐसा कुछ नहीं कर रही है।

ग्राम उद्योग, लघु उद्योग तथा पशुधन यही केन्द्र बिन्दु भारत के आर्थिक विकास के हो सकते हैं। सरकार यह भूलती जा रही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश शताब्दियों से रहा है। यहाँ की 85 प्रतिशत जनता, गाँवों में बसती है। उसका उत्थान गाँव के विकास से तथा खेती के विकास से ही सम्भव है। लेकिन इस तरफ न सरकार का ध्यान है और न अन्य राजनैतिक दलों का ही है। भाजपा रोटी और रोजगार की समस्या को हल करने के बजाय, धर्म और मजहब की भावना को भड़का कर देश के अंदर हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। यह ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय अखंडता के नाम पर, राष्ट्र को ही खंडित करने में जुटी है। ये वही लोग हैं जो उन नेताओं की तस्वीर लेकर चलते हैं जो आजादी के आंदोलन के विरोधी थे। जो अंग्रेजी हुकूमत के सलाहकार थे।

भाजपा इस देश और समाज को तोड़ने का षडयन्त्र कर रही है और कांग्रेस हर वक्त कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी परोक्ष रूप से इस साजिश में शामिल रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश की खुली लूट करने की छूट देने, तथाकथित उदार अर्थनीति के नाम पर पूंजीपतियों को और ज्यादा शोषण का मौका देने वाली कांग्रेसी नीतियों को भाजपा का समर्थन है। दोनों दल सत्ता बनाये रखने के लिये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कांग्रेस के सामने तो जरूरत से ज्यादा मजबूरी यह भी है कि वह अपनी पूंजीवादी नई आर्थिक नीतियों के लिये भाजपा के समर्थन की छिपी हुयी

इच्छा रखे हैं। राष्ट्रीय नीतियों को आर्थिक नीति सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसीलिए कांग्रेस जब भाजपा की समान आर्थिक नीतियो के निकट आने के लिये भाजपा के फांसीवादी जीवन–दर्शन को लोकशाही की नकली चादर ओढ़ाकर तालमेल के अवसरों की तलाश करती रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर भी भाजपा सरकार के खिलाफ कार्यवाही न करना कांग्रेस की इसी नीति का अंग था। ये राजनैतिक दल भारत के गरीब, सर्वहारा, किसान, मजदूर, नवजवान और महिलाओं के किस्मत पर कुंडली मारकर बैठै हैं और भ्रष्टाचार, हीनता, उत्पीड़न और बेकारी को जन्म देते जा रहे हैं।

समय आ गया है जब उनके आतंक से जनता को मुक्त कराया जाये। समाजवादी पार्टी इस अभियान का दूसरा नाम है।

होशियार और चैतन्य हो जायें। दुनिया की आबादी के 3/4 हिस्सा संसार के काले–पीले लोग हैं जो एशिया, अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारतीय उपमहाद्वीप में बसते हैं।

लगभग 6 अरब की संसार की आबादी में हम 5 अरब के लगभग हैं। हमारे पास धरती, खेत, खनिज पदार्थ, जंगल, पहाड़, समुद्र, जल, जीव–जन्तु और जनशक्ति है। हम मेहनत करना जानते हैं करते हैं फिर भी भूखे हैं। हमारी सम्पदा को चन्द मुट्ठी भर साम्राज्यवादी सदियों से लूट कर लेते जा रहे हैं। हमारे यहाँ भूख, बीमारी, बेकारी, और असंतोष है। हम अभाव का जीवन व्यतीत कर रहे हैं–आखिर क्यों? इस सवाल की तरफ ध्यान देना अब जरूरी है क्योंकि साम्राज्यवादी चाल अब हमारी सम्पदा को लूटने का विकराल रूप लेती जा रही है।

दुनियाँ के मंच पर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, साम्राज्यवादियों तथा पूंजीवादी ताकतों का हौसला बुलंद हो गया है। जिस सोवियत संघ को फासिस्ट हिटलर दूसरे महायुद्ध में परास्त नहीं कर पाया था, उसे अमरीका देखते–देखते तोड़ कर टुकड़ों में बाँटने में सफल हो गया।

मार्क्स के सपनों का रूस बिखर गया है और यूगोस्लाविया आज समता–साम्यवाद का प्रतीक न रहकर मजहबी उन्माद में जल रहा है। वहाँ हिंसा भड़काकर उस विकास की परिधियों को तहस–नहस किया जा रहा है

जो वहाँ की मेहनतकश जनता ने अपनी कुर्बानी से प्राप्त किया था। यही हाल लैटिन अमरीकी देशों, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया का है। लोगों को आपस में लड़ाकर साम्रज्यवादी ताकतें सारी दुनियाँ की पूँजी पर कब्जा करना चाहती हैं।

समाजवादी पार्टी, इस चुनौती को समझती है और संसार के रंगीन चमड़ी वाले लोगों, एशिया, अफ्रीका और अमरीका के काले लोगों का आवाह्न करती है कि वे साम्राज्यवादियों के बाँटो और लूटो" सिद्धान्त को समझें और एकजुट होकर इस शोषण के खिलाफ संघर्ष करने का मन बनायें।

भारतीय उपमहाद्वीप में असंतोष और हिंसा को समाप्त करने का हम आवाह्न करना चाहते हैं। पाकिस्तान की जनता को हम कहना चाहते हैं कि भारत की जनता के मन में पाकिस्तान के जन्म से लेकर आज तक कभी भी बुरी भावना नहीं रही है। हम चाहते हैं कि हम भाई–भाई की तरह रहे, दोनों देश तरक्की करें और अपने–अपने देश में फैली हुई गैर बराबरी, भुखमरी, बेकारी, हिंसा और आतंक के माहौल को समाप्त करें।

पाकिस्तान की जनता से हम यह अपील करना चाहते हैं कि वह अपनी सरकार पर दबाव डाले और आतंकवाद, जो पाकिस्तान की सीमा से भारत भेजा जा रहा है उस पर रोक लगाये। भारत–पाक का इतिहास एक है, हम एक महाद्वीप के बशिन्दे हैं। भारत की माटी की महक और गमक में नफरत कभी नहीं रही है। समाजवादी पार्टी भारत–पाक की जनता से अपील करती है कि वे भारत–पाक बंगला देश महासंघ बनाने के लिये पहल करे। भारत–पाक रिश्तों में मिठास भरने का यही सही कदम है। पिछले 45 वर्षों में भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण वे गाँव जो उत्पादन और खुशहाली के केन्द्र थे, आज वीरान और उजाड़ होते जा रहे हैं।

गाँव की पैदावार का दाम सरकार तय करती है। लेकिन कच्चा माल जो किसान पैदा करता है, वही जब कल कारखानों से सामान बनकर आता है तब सरकार उनके दाम पर अंकुश नहीं रखती है। नतीजा यह है कि किसान और उपभोक्ता दोनों पिस रहे हैं और पूँजीपति तथा आढ़तिया मनमाने ढंग से दामों की लूट करते जा रहे हैं।

बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल , ग्राम उद्योग, लघु उद्योग, पशुधन सबका अकाल गाँवों में है। इसके विपरीत शहर का तथाकथित विकास होता जा रहा है।

समाजवादी पार्टी इस प्रक्रिया को समाप्त करने का संकल्प करती है और वादा करती है कि आने वाले दिनों में हमारा प्रयास होगा कि गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह सब किया जाए जिससे गाँव खुशहाल हो।

आज गाँव की संस्कृति को बचाने आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार के नये–नये अवसर खोजने, अनाज का उत्पादन बढ़ाने, विदेशी सभ्यता से भारतीय संस्कृति को बचाने और जनतन्त्र को जनमुखी बनाने के लिए जरूरी हो गया है कि गाँव की तरफ चला जाये।

समाजवादी पार्टी गरीबो, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, ऊँची जाति के गरीब लोगों और नवजवानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी, एक आन्दोलन, एक लहर तथा, एक संकल्प है।

समाजवादी पार्टी अंगेजों की जगह मातृभाषा की पक्षधर है। भारत के गरीब तथा मेहनतकश तबकों के दिल की धड़कन है। उनके सपनों को साकार करने का माध्यम है।

हम जानते हैं कि हमारे पास साधन की कमी है। हमें दो मोर्चों पर एक साथ लड़कर अपना रास्ता बनाना है। दिल्ली तथा प्रदेश की सरकारें हमें पीड़ित करने पर आमादा हैं। साम्प्रदायिक शक्तियों और पूँजीवादी व्यवस्था, अंग्रेजी और विदेशी सभ्यता के नकलची लोगों का विरोध सहना है। लेकिन समाजवादी पार्टी देश की 2 प्रतिशत लोगों की पार्टी नहीं हैं। बल्कि यह पार्टी है भारत के 98 प्रतिशत उन लोगों की, जिनकी जिन्दगी में उल्लास की जगह उदासी ने ले ली है।

आज देश के लोग विभिन्न राजनैतिक दलों के खोखले नारो, सिद्धान्तहीनता व कार्यक्रम शून्यता से निराश हैं। जनता इस देश में ऐसा राजनैतिक विकल्प चाहती है जो उनकी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सके, जो बुराई के विरुद्ध छाती तानकर लगातार चलने वाली लड़ाई चला सके और वह राजनैतिक विकल्प है समाजवादी पार्टी।

हम सत्य के लिये आग्रह करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य समता वाले समाज की स्थापना है—हमारा संघर्ष सिविल नाफरमानी के नियमों के अनुसार होगा। हम जालिम के जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं, हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं, जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगे। हमें यकीन है समाजवादी पार्टी आज की उमस को खत्म करने में सफल होगी।[1]

राजनैतिक प्रस्ताव—

समाजवादी पार्टी के स्थापना सम्मेलन में जो राजनैतिक प्रस्ताव पास हुआ वह इस प्रकार है—

राष्ट्रीय सम्मेलन का दृढ़ मत है कि आजादी के 45 वर्ष बाद आज देश टूट के कगार पर है। आज साधारण भारतीय का आत्मबल टूट चुका है। वह निराश, उदास और कहीं क्रोध में है। सत्ता उसके लिए एक भयानक राक्षस की तरह है जो हर पल उसका शोषण करती जा रही है। गाँव वीरान हो रहे हैं। खेती और किसान उपेक्षित हैं। बेकारी सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है।

देश में सादगी की जगह विलासिता, अहिंसा की जगह हिंसा, आत्म सम्मान की जगह चाटुकारिता, स्वदेशी की जगह विदेशी चीजों की भूख, भाईचारा की जगह नफरत और उत्पादन की जगह विदेशी कर्ज ने ले ली है। सारा देश सत्ता के संरक्षण में अराजकता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।

सरकार, नौकरशाह और पूँजीपति का त्रिकोण एक दूसरे की रक्षा करते हुए लूट और अत्याचार को कायम रखने में एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रतिभूति घोटाले से जुड़े लोगों को बचाने के प्रयास इसी सन्दर्भ में देखने होंगे।

परिणाम स्वरूप असन्तोष की हवा चारों तरफ फैल रही है। भूख और अपमान के कारण विद्रोह एवं बदले की भावना सारे देश में व्यापक पैमाने पर फैलती जा रही है जिससे आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ रहा है।

सम्मेलन का मानना है कि राजनैतिक दल दिशाहीनता के शिकार हैं। कांग्रेस सरकार ने देश को महानगरीय संस्कृति, विदेशी कर्ज और विलासिता में आकण्ठ डुबो दिया है। खाद, डीजल, पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि करके देश में खाद्य उत्पादन को गिराने की मूर्खतापूर्ण कार्यवाही के

---

1. समाजवादी पार्टी के 'स्थापना सम्मेलन' लखनऊ में 4 नवम्बर 1992 को दिया गया अध्यक्षीय भाषण

साथ–साथ विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में खुली छूट देकर देश को पश्चिमी ताकतों का गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव में भारत का बजट और योजनाएं बनायी जा रही हैं।

पूँजीवादी ताकतों का न केवल देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप है बल्कि भारतीय विदेश नीति को भी प्रभावित किया जा रहा है।

पश्चिम एशिया में अरब देशों के समर्थन की भारत की स्पष्ट नीति थी। फिलिस्तीनियों को जब तक गृह देश न मिले, इजरायल को भारत द्वारा मान्यता दने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये था किन्तु यह दुखद सत्य है कि फिलिस्तीनी दर–दर मारे–मारे फिर रहे हैं, और भारत की सरकार ने अमेरिकी दबाव में इजरायल को मान्यता दे दी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस सरकार के इस कदम से असहमति व्यक्त करती है। सत्ता में आने के सौ दिन के भीतर मंहगाई कम करने का वादा करने वाली सरकार ने सौ फीसदी में ज्यादा कीमतें बढ़ा दी है। इससे कांग्रेस का नकली चेहरा बेनकाब हो गया है और उसका असली स्वरूप जो जन विरोधी है, जनता के सामने आ गया है।

असंगठित मजदूरों की दयनीय स्थिति को सुधारने तथा कर्मचारियों की छंटनी को रोकने का कार्य समाजवादी पार्टी करेगी। डंकल प्रस्तावों तथा एक्जिट पालिसी की काली छाया से देश के जनमानस को बचाने के लिये समाजवादी पार्टी कृत संकल्प है।

समाजवादी पार्टी का मत है कि देश की वर्तमान राजनैतिक स्थिति का सबसे दुखद पक्ष यह है कि राष्ट्रपिता के हत्यारों को भी सार्वजनिक जीवन में सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी है। राष्ट्रपिता पर प्रश्नचिन्ह लगाना विकृत मानसिकता का द्योतक है। राष्ट्रीय सम्मेलन का विश्वास है कि भाजपा नकली नारे उछालकर, देश में साम्प्रदायिक उन्माद फैलाकर मनुष्य–मनुष्य के बीच नफरत के बीज बोकर देश में खून खराबा कराकर दिल्ली की सत्ता हासिल करना चाहती है।

पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके, इतिहास को कुरूप करके तथा शहरों के नाम बदलकर साम्प्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने का लगातार प्रयास भाजपा द्वारा किया जा रहा है। इस दल के लोग "जातीय श्रेष्ठता' के फांसीवादी

सिद्धान्त को मानने वाले हैं। इसलिए इनका लोकतंत्रीय मान्यताओं एवं मानवीय संवेदनशीलता से कोई दूर का भी रिश्ता नहीं है।

रामकोला में अपने गन्ने का बकाया धन मांगने पर निहत्थे शान्तिप्रिय किसानों को बिजली गुल करके गोलियों से भून दिया गया। मध्य प्रदेश के जगदलपुर में आदिवासियों के हितों की बात करने पर वहाँ के मुख्यमंत्री के इशारे पर अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष को भाजपाइयों द्वारा नंगा करके जूतों की माला पहनाकर जगदलपुर की सड़कों पर घुमाया गया तथा शंकरगुहा नियोगी ही हत्या जैसे की गई, ये सभी घटनाएं भाजपा के फासिस्ट चरित्र एवं संवेदनहीनता के उदाहरण हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूंजीवादी ताकतें विकासशील देशों के शोषण में लगी हुई है। सोवियत संघ एवं पूर्वी–यूरोप की कम्युनिस्ट सरकारों के पतन एवं सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका का दुनिया की अर्थ व्यवस्था पर एकाधिकार हो गया है। यद्यपि समाजवादी पार्टी का मानना है कि सोवियत यूनियन एवं पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन का अर्थ मार्क्सवाद की असफलता नहीं है। यह मार्क्सवाद को गलत ढंग से लागू करने का परिणाम है। भारत को स्वावलम्बी बनने का प्रयास करना होगा ताकि तीसरे विश्व को मजबूत नेतृत्व देकर दुनिया की पूँजीवादी ताकतों द्वारा किये जा रहे विकासशील देशों के शोषण को रोका जा सके।[2]

2. समाजवादी पार्टी का दो दिवशीय राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 11–12 अक्टूबर 1994 को सम्पन्न हुआ। जिसकी अध्यक्षता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया।

3. तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन–

सपा का दो दिवशीय तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 27–28 जुलाई 1996 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मपन्न हुआ।

अध्यक्षीय भाषण–समाजवादी पार्टी के तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि–

2. सपा के स्थापना सम्मेलन, लखनऊ में, 5 नवम्बर 1992 को पारित राजनैतिक प्रस्ताव

साथियों,

लखनऊ की सरजमी पर आयोजित होने वाला यह सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस समय भारतीय राजनीति एक संक्रमण काल से गुजर रही है और एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से पूरे देश की राजनीति में जो कुछ बदलाव हुआ, उसके हम साक्षी भी है और भागीदार भी। बाबरी मस्जिद टूटने, साम्प्रदायिक दंगों और ऊँचे पदों पर भ्रष्टाचार के कारण हम पूरी दुनिया में बदनाम हो गये हैं। देश की राजनीति के शिखर पर बैठे हुये लोगों के ऊपर लगे हुये भ्रष्टाचारों के गम्भीर आरोपों के चलते सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले राजनेताओं की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गयी है। इस राजनैतिक अव्यवस्था और अस्थिरता का फायदा उठाकर कट्टरपंथी साम्प्रदायिक ताकतों ने अपनी जड़ों को और मजबूत कर लिया है। हालांकि वे भी भ्रष्टाचार के कटघरे में फंस चुके हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में उत्तर से दक्षिण तक मतदाताओं ने किसी एक राजनीतिक दल को समर्थन नहीं दिया है। इससे एक नकारात्मक राजनीति की भी शुरुआत हुई है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया है।

किसी एक दल के पूर्ण बहुमत के अभाव में क्षेत्रीय राजनैतिक दलों का महत्व बढ़ा है। वर्तमान लोकसभा त्रिशंकु अवश्य है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री एच0 डी0 देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार का एक नया और सार्थक प्रयोग सामने आया है। लोकसभा चुनाव का जनादेश जनाकांक्षाओं से सीधे जुड़े हुये क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के गठबंधन के पक्ष में है। ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए कुछ लोगों को केन्द्र की संयुक्त मोर्चा सरकार में परस्पर विरोध भले ही नजर आता हो लेकिन धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद को बचाने की देश की जनता द्वारा दी गयी जिम्मेदारी को पूरा करने का हर संभव प्रयास केन्द्र सरकार कर रही है। इसको तोड़ने की तमाम साजिशों के बावजूद सरकार चल रही है और धीरे–धीरे मजबूत भी होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के लिये सरकार में शामिल होना और सत्ता में भागीदारी करना ज़रूरी नहीं था। लेकिन हम संयुक्त मोर्चा को कमजोर नहीं

कर सकते थे क्योंकि यही जनादेश है और भारतीय राजनीति का यही भविष्य भी है।

लोकसभा के पिछले चुनाव में सभी दलों की ताकत सामने आयी है। लम्बे–लम्बे दावे करने वाली भारतीय जनता पार्टी की असलियत भी सामने आयी है। कुछ दिनों के लिये जब अल्पमत की सरकार दिल्ली की कुर्सी पर बैठी तो देश का राजनैतिक मानस घबरा गया। समाजवादी पार्टी को इस बात का गर्व है कि पार्टी ने उ0 प्र0 की सरहद में साम्प्रदायिकता के खिलाफ जो उद्घोष किया था वह राष्ट्रीय मुद्दा बना और देशी–विदेशी पूँजीवाद के दबाव के बावजूद भाजपा विरोधी लगभग सभी पार्टियों ने हिस्सेदारी एवं सहयोग के जरिये एक धर्मनिरपेक्ष शक्ति के हाथ में भारत की बागडोर सौंपी।

समाजवादी पार्टी साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष में इस घटना को एक शुभ लक्षण मानती है कि जो लड़ाई समाजवादी पार्टी अकेले लड़ती थी उस लड़ाई को देश की दो तिहाई जनता ने अपनी लड़ाई मान लिया है।

लोकसभा चुनाव के बाद नयी चर्चायें भी शुरू हुई है। एक बार फिर से कुछ लोग संविधान बदलने या प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव कराने जैसे सुझाव उछाल रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर बुनियादी सवालों को लेकर संविधान संशोधन के हम विरोधी नहीं हैं। संविधान सभा ने पूरी सूझबूझ के साथ संविधान बनाया था। इसकी संरचना में यह ध्यान रखा गया था कि भारत बहुभाषी, बहुधर्मी और बहुलतावादी देश है। इसलिए संविधान की रचना में कोई बुनियादी दोष नहीं है। इसी संविधान के कारण नागरिकों को राजनैतिक न्याय के साथ–साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय भी दिलाया जा सकता है। आज की परिस्थितियों में अगर कोई बदलाव जरूरी है तो राजनैतिक दलों और नेताओं के सोच में अपने सिद्धान्तों से समझौता करने के बजाय हमें धीरे–धीरे आगे बढ़ना मंजूर है। राष्ट्रीय राजनीति में हमारी यही पहचान है। चार साल पुरानी पार्टी और इतने राजनीतिक भूचालों के बीच जबकि चारों ओर से हमें निशाना बनाकर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, हमारी प्रगति धीमी लेकिन संतोषजनक है। हमें अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के आधार पर जनता का विश्वास जीतना है। हम एक लम्बी और निर्णायक लड़ाई के लिये तैयार हो रहे हैं। हमें जनता पार्टी नहीं बनना है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हमार लिये सबसे बड़ी चुनौती है। 1991 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 215 सीटें मिली थी लेकिन 1993 में समाजवादी पार्टी ने इस संख्या को घटाकर 176 पर ला दिया था और उ0प्र0 में समाजवादी पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। लेकिन कुछ अवसरवादी तत्वों के कारण जो साम्प्रदायिक शक्तियों के हाथ की कठपुतली बन बये थे और आज भी साम्प्रदायिक शक्तियों के हाथों में खेल रहे है, जनता की चुनी हुई सरकार अपदस्थ हो गई थी।

पिछले लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। उस समय भी यह प्रचार किया गया था कि बसपा से गठबंधन टूटने के कारण समाजवादी पार्टी का आधार कमजोर हो जाएगा और जनाधार कटकर दूसरे दलों के साथ चला जायेगा। बसपा ने समाजवादी पार्टी के जनाधार को तो खराब नहीं किया बल्कि कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करके भाजपा को लाभ पहुँचाने का काम अवश्य किया। हम देश की साम्प्रदायिकता विरोधी शक्तियों को आगाह करना चाहते हैं कि उ0प्र0 में बसपा का लक्ष्य भाजपा को हराना नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी को कमजोर करना है।

समाजवादी पार्टी का आधार हमारी नीतियां कार्यक्रम और उ0प्र0 में हमारी सरकार द्वारा किये गये काम हैं। 1993 में सरकार बनाने के तुरन्त बाद चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वायदों को हमने पूरा करना प्रारम्भ कर दिया था। शपथ लेने के आधे घंटे के अन्दर चुनाव घोषणा पत्र में किये गये लगभग एक दर्जन प्रमुख वायदों को पूरा किया था। नकल विरोधी कानून की वापसी , गाँवों को 16 घंटों की बिजली देना, किसानों को उपज का लाभकारी दाम दिलाना, मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देना, प्रजापति निषाद और दूसरे पिछड़े वर्गों को राहत देना, उर्दू को प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनान, 10 हजार अम्बेडकर ग्रामों की घोषणा और उस पर अमल करना, बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों का निर्माण जैसे कामों की एक लम्बी सूची है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ऐसी पहली सरकार थी जिसने एकमुश्त बुनियादी कामों पर ध्यान दिया और उन्हें संफल बनाया। लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद उन सारे विकास कार्यों को रोक दिया गया और अनेक कामों के लिये आवंटित किये गये धन को वापस

कर दिया गया। समाजवादी पार्टी आर्थिक रूप से ग्रामीण और कृषि विकास के लिए 70 प्रतिशत योजना के लिये धन देने की शुरु से वकालत करती रही है। मैं इस राय का हूँ कि इस देश में प्रकृतिक संसाधन, जनशक्ति और जमीन की उर्वरा शक्ति पर्याप्त है, जिससे अपना देश दुनिया का सबसे सम्पन्न देश बन सकता है लेकिन योजनाएं और प्रेरणायें प्रारम्भ से ही दिशाहीन रही और गांव पिछड़ते चले गये। समाजवादी पार्टी ने गांव का पैसा गांव पर खर्च करने की घोषणा और इस हेतु संघर्ष भी किया था। पार्टी देश और प्रदेश के आर्थिक ढांचे को ऐसी बनावट में ढालेगी ताकि न कोई वंचित रहे और न कोई ज्यादा संचित कर सके।

मैंने यह बात बार–बार दोहरायी है कि हमें सबको साथ–साथ लेकर चलना है। सबको जोड़कर समाज बदलना है और जन समर्थन के सहारे देश में सामाजिक परिवर्तन लाना समाजवादी पार्टी ने जातिवादी सोच और मानसिकता का सदा विरोध किया है। हमने कमजोरों, पिछड़ों, बुनकरो, व्यापारियों, अल्पसंख्यकों छात्रों और महिलाओं की लड़ाई लड़ी है। उनके साथ खड़े रहे, उनको आगे बढ़ने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। झूठे आरोप चाहे जितने लगाये जायें लेकिन सच बात यह है कि गरीब सवर्णों की लड़ाई भी समाजवादी पार्टी ही देश में लड़ी है। उनको राजनैतिक संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा देने का काम भी हमने किया है। पिछले चुनाव में इसका लाभ भी हमें मिला है और इस चुनाव में भी हमें इस वर्ग का भरपूर समर्थन मिलेगा। पिछली सरकार के दौरान हमने और हमारी सरकार ने बाबरी मस्जिद की रक्षा करके मुसलमानों के दिल की दहशत को दूर करने का काम तो किया ही था, भारत के संविधान की मर्यादाओं की रक्षा भी की थी। आज की समाजवादी पार्टी और हमने ही नहीं हमारे समाजवादी पुरखों विशेषकर डा0 लोहिया और राजनारायण के नेतृत्व में समाज जिनको अछूता कहता है उनको लेकर काशी विश्वनाथ मन्दिर में प्रवेश के समय भी समाजवादियों के शरीर और लोकप्रियता दोनों पर चोट आयी थी। बाबरी मस्जिद के आन्दोलन के समय भी मस्जिद बचाने में हमें अपनी लोकप्रियता जोखिम में डालनी पड़ी थी। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि समाज में जो लोग कमजोर हैं, चाहे वे अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े या महिलायें हो उनके अधिकारों को सुरक्षित

रखने और दिलाने के लिए जो शुरू से समाजवादी चरित्र रहा है उसकी निरन्तरता में कमी नहीं आने दूँगा। केवल वोट एवं लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि वक्त पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति देकर भी समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता कमजोर की मदद के लिए अन्त तक खड़ा रहेगा। विशेषकर अल्पसंख्यकों और दलितों की रक्षा के लिये।

बेरोजगार नौजवानों को चाहे वे किसी जाति वर्ग या धर्म के हो, हमें समाजवादी पार्टी के मंच पर खड़ा करना पड़ेगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने-अपने क्षेत्रों के कालेजों और विद्यालयों के छात्रों की संगठित टोलियां निकालनी पड़ेगी। यह दोनों शक्तियां मिलकर सामंती ताकतों, साम्प्रदायिक शक्तियों और चुनाव में धांधली करने वाले अफसरों का मुकाबला करेगी। बिना हिंसा को बढ़ावा दिये जनता को संगठित करके उनका मुकाबला करना पड़ेगा।

नौजवानों और छात्रों को अगले दो महीने प्रदेश को बचाने में लगाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को सभी वर्गों के एक-एक मतदाता के पास जाकर समझाना पड़ेगा कि साम्प्रदायिक शक्तियों से देश की एकता और अखण्डता को खतरा है और इसलिए समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को प्रेदश और देश की रक्षा के लिए प्रत्येक मतदाता से मदद करने का आग्रह करना पड़ेगा।[3]

राजनैतिक प्रस्ताव

समाजवादी पार्टी के तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में जो राजनैतिक प्रस्ताव पारित हुआ वह इस प्रकार है–

उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव सर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की राजनैतिक गतिविधियां पैंतरेबाजी की शक्ल मे सक्रिय हैं। यह जानते हुये भी कि उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या, मथुरा एवं काशी है तथा साम्प्रदायिकता के खिलाफ असली रणस्थली उत्तर प्रदेश ही है और समाजवादी पार्टी एवं उसके नेता मुलायम सिंह यादव ही इस साम्प्रदायिकता के खिलाफ सही अर्थों में संघर्ष कर रहे हैं और वे ही शिकस्त दे सकते हैं।

3 - सपा के तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में 27 जुलाई 1996 को दिया गया अध्यक्षीय भाषण

समाजवादी पार्टी यह घोषणा करती है कि दिल्ली में जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी है उस संयुक्त मोर्चे को साथ लेकर समाजवादी पार्टी साम्प्रदायिक शक्तियों को उ0प्र0 में नेस्तनाबूद करेगी। कुछ राजनैतिक शक्तियां साम्प्रदायिक शक्तियों से संघर्ष करने के बजाय समाजवादी पार्टी को येन केन प्रकारेण कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं।

समाजवादीं पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन उन सारी पैतरेंबाज शक्तियों को आगाह करना चाहती है कि अगर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश हुई तो उसका सीधा फायदा साम्प्रदायिक शक्तियों को मिलेगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश के सबन्ध में समाजवादी पार्टी के इस राष्ट्रीय सममेलन का स्पष्ट मत है कि साम्प्रदायिकता के खिलाफ जो हमारे साथ नहीं है, वह साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ है। कुछ राजनीतिक शक्तियां भाजपा विरोध के नाम पर उन लोगों से हाथ मिलाना चाहती हैं जो अपने वक्ती फायदे के लिये साम्प्रदायिक शक्तियों की कठपुतली बन जाती हैं। गाँधी को गाली देने वालों के साथ तथाकथित गाँधी भक्तों का समझौता कोई आश्चर्य की बात नही है। क्योंकि गाँधीवादी, गाँधी के स्वदेशी एवं स्वावलम्बन की नीतियों को तिलांजलि दे चुके हैं और उनके लिए गाँधी को गाली देने वाली शक्तियां अब परहेज की चीज नहीं है। गांधी को गोली मारने वालों का मुकाबला गाँधी को गाली देने वाले और गाँधी की नीतियों को तिलांजलि दे चुके लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिये देश एवं प्रदेश के सारे असली गाँधी भक्त एक जुट हों और उत्तर प्रदेश के चुनाव के माध्यम से सारे राष्ट्र को प्रतिबद्ध करे कि यह देश गाँधी जी का रहेगा या गाँधी विरोधियों या गाँधी के हत्यारों का?

इस देश में समाजवादी आन्दोलन का इतिहास बहुत पुराना है। प्रारम्भ के दिनों में देश के और विदेश के समाजवादियों ने समाजवाद के सिद्धांत को निरूपित करने के लिये समतामूलक समाज की कल्पना की थी और आदमी–आदमी की गैर बराबरी को समाप्त करने के लिये केवल पूँजीवदी व्यवस्था के खिलाफ वर्ग संघर्ष का नारा दिया था। दुनियाँ के कुछ हिस्सों में इस नारे को पकड़ा भी गया लेकिन बाद के दिनों में डा0 लोहिया ने भारत के दर्द को समझा कि इस देश में केवल पूंजी नहीं बल्कि जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था और भूगोल के आधार पर क्षेत्रीय विषमता भी गैर बराबरी के

कारण है। इसी आधार पर उन दिनों दलितों, पिछड़ों, महिलाओं (चाहे वे ब्राह्मण हो, ठाकुर या अन्य किसी भी जाति की हो) और गरीब मुसलमानों के लिये विशेष सुविधा की बहस छिड़ी थी। लाजमी है कि जब ऐसी बातें छिड़ती हैं तो आन्दोलन जहाँ एक तरफ आर्थिक गैर बराबरी खत्म करने के लिये वर्ग संघर्ष का रूप लेता है, वहाँ सामाजिक गैर बराबरी खत्म करने के लिये वर्ण संघर्ष का रूप ले लेता है और साथ ही क्षेत्रीय गैर बराबरी समाप्त करने के लिये कुछ मुकामी मुद्दे भी उभर कर आते हैं।

समाजवादी पार्टी एक ओर साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ संघर्षरत है तो दूसरी ओर गरीबी के खिलाफ जंग में सदियों से उपेक्षित लोगों के हकों की लड़ाई पूरी निष्ठा के साथ लड़ रही है। जन्म के आधार पर कमजोर लोगों जिनमें दलित, पिछड़े, गरीब मुसलमान और महिलायें हैं, के लिए लड़ाई का बिगुल जितनी ताकत से फूँक चुकी है उससे भी ज्यादा ताकत से आर्थिक क्षेत्र में जिन्स की पैदावार के नाम पर कमजोर शक्तियों को अधिकार दिलाने के लिये मैदान में उतरी हैं। कारखाने की पैदावार के मुकाबले खेती की पैदावार कमजोर है। कारखाना कच्चे माल का इस्तेमाल करने के नाम पर खेती का शोषण करते हैं। उ0प्र0 में गन्ना उत्पादकों की, विशेषकर जो दयनीय दशा है और जिस तरह से गन्ने के बकाया भुगतान के लिये किसानों को कभी–कभी लाठी गोली का मुकाबला करना पड़ता है। किसानों के संघर्ष को हर तरह से मद्द करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुये समाजवादी पार्टी यह स्पष्ट करना चाहती है कि जब तक कारखानों में उत्पादन और खेती में उत्पादन के दामों में लागत और लाभ दोनों पक्षों के बीच संतुलन कायम नहीं किया जायेगा, देश के गाँव और खेत शहरों के उपनिवेश बनकर रह जायेगे। समाजवादी पार्टी चौखम्भा राज में विश्वास करती है। ग्राम पंचायत की व्यवस्था को जो सत्ता की भागीदारी में विशेष रूप से कमजोर हैं, इसे विशेषाधिकार देकर प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती रही हैं और करती रहेंगी।

समाजवादी पार्टी जहाँ एक ओर समाज के दलित, गरीब, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन के नाम पर विशेष अवसर देने के निर्णय को कारगर बनाने के लिये संघर्षरत है वहीं देश के तमाम नौजवान को

चाहे वे किसी भी जाति, धर्म के हो उनके बेसहारापन को दूर करने के अवसर और काम करने के अधिकार को दिलाने का वायदा करती है। देश का कर्ता धर्ता एवं लम्बे अरसे से देश के युवाओं को आर्थिक रूप से बेसहारा और मानसिक रूप से लुंजपुंज बनाने की साजिश कर रहा है। इस साजिश के खिलाफ युवा पीढ़ी समय रहते संघर्ष करे। समाजवादी पार्टी उनके साथ है।

समाजवादी पार्टी आदमी के द्वारा आदमी के शोषण, पैदावार के द्वारा पैदावार के शोषण, एक क्षेत्र के द्वारा दूसरे क्षेत्र के शोषण, एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का विरोध करती है। पुराने उपनिवेशवाद के चलते बहुत सी विदेशी भाषायें नये स्वतन्त्रता प्राप्त किये देशों में वहाँ की मातृ भाषाओं और राष्ट्र भाषा का शोषण करती रहती है। मातृ भाषा के शोषण की प्रक्रिया के खिलाफ समाजवादी पार्टी संघर्षरत है और रहेगी।

समाजवादी पार्टी मजदूरों, छोटे दुकानदारों, बुनकरों, दस्तकारों और व्यापारियों के ऊपर भी होने वाले अन्याय का निराकरण करेगी। पड़ोसी देशों से सम्बन्ध सुधार कर डा0 लोहिया के सपनों के मुताबिक एक सांस्कृतिक भारत की कल्पना को साकार करेगी।

इनके बड़े मुद्‌दों को हासिल करने में राष्ट्रीय सम्मेलन कुछ राजनीतिक अड़चनों को देखकर चिन्तित है। यह सम्मेलन राष्ट्र की जनता को विशेषकर उत्तर प्रदेश की महान जनता और अपने कार्यकर्ताओं का आवाह्‌न करता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में वादों को सही ढंग से निभाया है और नये राष्ट्र के निर्माण के लिये समाज के वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की है तो पार्टी के कार्यकर्ता महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में अपना झण्डा गाड़ने के लिये कटिबद्ध हो जायें।[4]

प्रमुख सचिव की रिपोर्ट

समाजवादी पार्टी का स्थापना सम्मेलन (प्रथम सम्मेलन) 4, 5 नवम्बर 1992, द्वितीय सममेलन 11, 12 अक्टूबर 1994 और तृतीय सममेलन 27, 28 जुलाई 1996 को लखनऊ में ही हो रहा है। यह सम्मेलन दूसरे राज्य में

4 . सपा के 'तृतीय राष्ट्रीय सममेलन' लखनऊ में 28 जुलाई 1996 को पारित राजनैतिक प्रस्ताव"

करना था परन्तु जहाँ का निमंत्रण था वहाँ वर्षा के चलते दिक्कते थी, इस कारण यहाँ सम्मेलन करना पड़ा। यह सम्मेलन एक विशेष परिस्थिति में हो रहा है। आज देश एक नये राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है। दिल्ली ने सयुंक्त मोर्चा की सरकार एक कामन मीनिमम कार्यक्रम पर चल रही है। जिसमें समाजवादी पार्टी भी शरीक है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा० श्री मुलायग सिंह यादव सुरक्षा विभाग के मंत्री पद पर आसीन हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष मा० श्री जनेश्वर मिश्र जी, पार्टी के महामंत्री मा० श्री बेनी प्रसाद वर्मा, मंत्री मरिषद में और श्री सलीम शेरवानी राज्य मंत्री, केन्द्रीय मंत्री मंडल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्वतन्त्र प्रभार में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अतिरिक्त दोनों मंत्रियों के पास भी महत्वपूर्ण विभाग है। हमें विश्वास है कि हमारे ये नेता लोग मंत्री परिषद में अपनी योग्यता और कार्य कुशलता का परिचय देकर देश की जनता के सामने पार्टी की छवि को चमकाने का काम करेगे। पार्टी संगठन के करीब एक वर्ष के ही भीतर उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव हुआ और हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में बसपा तथा अन्य दलों की मदद से सरकार बनाने में सफल रही। बसपा तो विधान सभा चुनाव में भी साथ मिलकर लड़ी थी और उसे विगत विधान सभा चुनाव में प्राप्त 14 स्थानों की जगह 69 स्थान मिल गये थे। उस सरकार के नेता मा० श्री मुलायम सिंह यादव ही थे। उनके कुशल नेतृत्व में सरकार ने अल्प अवधि में ही प्रायः अपने सारे वादे पूरे कर लिये थे। इसी अवधि में सहकारिता, ग्रामीण पंचायतों, नगर पंचायतों और नगर निगमों के चुनाव में पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी सफलता मिली थी। इन चुनावों में हमारा किसी भी दल से समझौता नहीं था। पार्टी की बढ़ती हुई जनप्रियता से अन्य दलों के लोगों में जलन होना स्वाभाविक था। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी विफलता से बौखला गई थी। उनका दिल्ली राज का सपना साकार रूप पाने में उत्तर प्रदेश सरकार और इसके नेता को अपना सबसे बड़ा संकट मानता था जो आज भी उस पार्टी के कार्यों से साफ झलक रहा है। इस बीच बसपा का जो भी दंभ था वह टूट रहा था। उसके नेता भी सत्ता सुख अकेले किसी तरह पाने को लालायित थे। पार्टी और पार्टी नेता की बढ़ती शक्ति से जो बौखलाये लोग थे। वे मुलायम सिंह को गद्दी से

हटाना चाहते थे। इसमें कमोवेश भारतीय जनता पार्टी के साथ सबों की साजिश थी। इतना ही नहीं इसमें देशी और विदेशी पूंजीवादी साजिश भी काम कर रही थी। फलस्वरूप 1 जून 1995 को बसपा ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और 3 जून की अर्धरात्रि में उस समय के राज्यपाल महोदय ने सरकार भंग कर सुश्री मायावती की सरकार बनवा दिया। इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। 2 जून की एक छोटी सी घटना को बड़ा भयावह रूप देकर प्रचारित किया गया। इसके पीछे निहित स्वार्थ पूर्णरूपेण था। यह सरकार मात्र चार महीने चली, परन्तु इसने जितना ओछा और घिनौना कार्य किया, उसे जनतांत्रिक व्यवस्था का कलंक ही कहा जायेगा। इसके बारे में जितना भी कहा जायेगा वह कम ही होगा। इसी बीच पार्टी का दूसरा सम्मेलन हुआ। उसी सममेलन द्वारा गठित वतमान पार्टी संगठन है। उस सम्मेलन के बाद से अब तक की मुख्य–मुख्य पार्टी कार्यो की जानकारी दिया जा रहा है।

पार्टी संगठन प्रायः देश के सभी राज्यों में कुछ न कुछ बन गया है। परन्तु वह सब जगह कारगर नहीं है। अगले कार्यक्रम की सूची में पार्टी को इसे प्रथम स्थान देना चाहिये। आज पार्टी का मुख्य रूप से जनाधार उत्तर प्रदेश में हैं। पार्टी अध्यक्ष मा0 श्री मुलायम सिंह अभी उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता हो गये हैं। इनके और राज्य पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में यहाँ की पार्टी सब तरह से सक्रिय है। कमी नीचे की इकाइयों को सक्रिय बनाये रखने की है। सरकार गिरने के बाद नई सरकार जिस तरह संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध बनाई गई उसके विरोध का निर्णय पार्टी ने लिया। सुश्री मायावती की सरकार ने शान्तिपूर्ण विरोध पर भी पाबन्दी लगाई। फलस्वरूप हमारे हजारों कार्यकर्ता सरकारी जुल्म के शिकार बने। फिर भी कार्यकर्ता साहस पूर्वक लड़ते रहे। नवम्बर 17 को राजभवन के घेराव का शानदार कार्यक्रम था। असमय की भयावह वर्षा के बाद भी हमारे हजारों साथी लखनऊ तरह–तरह की बाधाओं के बाद आ गये। उन्होंने भिन्न–भिन्न स्थानों पर सरकारी कानून को तोड़ा। कई जगह लाठी भी चले। हमारे पार्टी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अनेकों नेता लखनऊ में गिरफ्तार किये गये। सारा उत्तर प्रदेश पुलिस कैम्प बन गया था। सारे राज्य में पचास हजार से अधिक गिरफ्तारियां

हुई थीं। हमारी पार्टी के शायद ही कोई नेता बच सके थे। इसमें युवा संगठनों का काम सराहनीय रहा था। पुनः 2 मार्च 1996 को दिल्ली रैली लाल किला के मैदान में हुई। यह अपने में अभूतपूर्व थी। इसमें देश भर से लोग आये थे परन्तु इसे सफल बनाने का सारा श्रेय उत्तर प्रदेश को जाता है। इसे सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अधिक प्रयास किया था। इस रैली ने देश के सामने पार्टी की शक्ति को उजागर किया। इसके पहले जिलों और मंडलीय अनेकों रैलियाँ हुई थी। युवा संगठनों के द्वारा राज्यपाल के सामने जो प्रदर्शन किया गया था। उसमें हमारे दर्जनों साथी गंभीर रूप से घायल हुये थे फिर भी उनका मनोबल ऊँचा था। इस बीच महिला संगठन, युवा संगठन और पार्टी संगठन द्वारा उपेक्षित अति पिछड़ी जातियों, व्यापारियों आदि के अनेकों प्रदर्शन तथा सम्मेलन किये गये।

लोकसभा का चुनाव आया। मुख्यरूप से हम उत्तर प्रदेश में कम्युनिष्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और जनता दल के साथ मोर्चा बना कर चुनाव लड़े। चुनाव हम देश के कई राज्यों में लड़े। पार्टी उत्तर प्रदेश में कुल 64 लोकसभा क्षेत्र में लड़ी थी। हम यहाँ 16 स्थान पर जीते हैं। इस लोकसभा चुनाव से सबक ले कर आगे बढ़ना है। अभी उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव सामने है। मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिश्रम सराहनीय और साथियों के लिये अनुकरणीय है। अभी उत्तर प्रदेश पार्टी द्वारा राज्य के करीब 42 जिलों में रैलियां की गई है। चार प्रमंडलों को छोड़ सभी प्रमंडलों में कार्यकर्ता सममेलन हो चुका है। सहकारिता, पंचायत, जिला पंचायत और नगर पंचायत तथा निगमों में जो अपने पार्टी के पदाधिकारी जीते हैं–उनकी बैठकें हो गई हैं। इन बैठकों की उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक थी। भूतपूर्व जीते–हारे विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और जीते, हारे सांसदों की बैठक भी हमने की है।[5]

4. विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन–

समाजवादी पार्टी कार्य दो द्विवसीय विशेष राष्ट्रीय धिवेशन 19–20 अप्रैल 1998 को महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई के औरंगाबाद में सम्पन्न हुआ।

---

5. सपा के तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, लखनऊ में, 28 जुलाई 1996 को पेश प्रमुख सचिव की रिपोर्ट

अध्यक्षीय भाषण–

भारत की आर्थिक राजधानी मुम्बई में समाजवादी पार्टी का यह राष्ट्रीय विशेष अधिवेशन सम्पन्न हो रहा है। कई द्वीपों जैसें स्थानों पर बसी मुम्बई देश के विभिन्न धर्मों, संस्कृतियो, आस्थाओं और रीति रिवाजों का केन्द्र है। देश के प्रायः सभी प्रदेशों के लेागों ने इसके भव्य–सुन्दर स्वरूप को गढ़ा है। साम्प्रदायिक फासिस्टवादी ताकतों ने यद्यपि समय–समय पर इसके इस स्वरूप को विगाड़ने की नाकाम कोशिश जरुर की है किन्तु लघु भारत का यह स्वरूप अपने पूर्ण यौवन पर बना हुआ है और भविष्य में भी बना रहेगा।

आर्थिक गतिविधियों के अतिरिक्त आजादी की लड़ाई में भी मुम्बई का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। "भारत छोड़ों"आन्दोलन का जयघोष मुम्बई से ही हुआ था। महाराष्ट्र ने ही 42 के आन्दोलन के दौरान जिलों में स्वतंन्त्र सरकार स्थापित करने का संदेश पूरे देश को दिया था।

मुम्बई और महाराष्ट्र ने देश को महान समाजवादी नेता दिये, जिन्होने स्वतन्त्रता तथा समाजवादी आन्दोलन को अभूतपूर्व गति प्रदान की जिसमें मेहर अली, अच्युत पटवर्धन, एन0जी0 गोरे, एस0एम0 जोशी, मधुलिमेय सरीखे ऐसे नक्षत्र रहे और जो हमेशा अपनी आभा से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगें।

केन्द्रीय सरकार के गठन, राष्ट्रीय एजेण्डा, भाजपा के भ्रामक प्रचार तथा देश के कुछ राजनैतिक पार्टियों के आचरण ने देश की संस्कृति और लोकतंत्र की आत्मा को समाप्त कर देने की व्यूह रचना कर दी है। राष्ट्रीय एजेण्डा एक फर्जी दस्तावेज है। फर्जी दस्तांवेज की आड़ में भाजपा अपनी देश–तोड़क नीतियों के दुष्चक्र को चलायेगी। लेकिन देश नहीं चल सकता। देश चलाने और लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम रखने के लिये नैतिकता–सच्चाई और ईमानदारी के लिये सच्ची निष्ठा आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी देश की राजनीति के खतरनाक मोड़ पर इन सब बुनियादी बातों पर देश की जनता को सचेत करने और भ्रम की स्थिति को समाप्त करने का अपना नैतिक दायित्व मानती है।

हाल मे हुए लोकसभा के चुनाव परिणामों, उसके बाद विभिन्न राजनैतिक दलों की बुद्धि विलास बैठकों के सिलसिलों तथा भाजपा के नेतृत्त्व में बनी सरकार ने ऐसे चिन्ताजनक प्रश्न पैदा कर दिये हैं जिनके उत्तरों का दायित्व गैर साम्प्रदायिक लोकतांत्रिक दलों के ऊपर है। समाजवादी पार्टी को साम्प्रदायिक विरोधी मुहिम को देश व्यापी बनाने में अहम भूमिका का निर्वहन किया है और कठिन परिश्रम के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। कि समाजवादी पार्टी जहां समता से समृद्धि और समृद्धि से समता के सिद्धान्त के प्रति समर्पित और इसके लिये व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक मानती हैं,वहीं देश में लोकतन्त्र विरोधी फासिस्टवादी ताकतों को समाप्त करने के लिये संकल्पबद्ध है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक बात तो साफ हुई कि देश की जनता ने साम्प्रदायिक द्वेष पैदा करने वाली लोकतन्त्र विरोधी भाजपा को स्वीकार नहीं किया है। झूठ, फरेब, धांधलेबाजी और अफवाहों ने यद्यपि धर्मनिरपेक्ष ताकतों की सीटें जरुर कम कर दी लेकिन भाजपा, कमोवेश पूर्व की स्थिति पर ही स्थिर हो गयी। भाजपा–शिवसेना मिलाकर पिछली लोकसभा की सदस्य संख्या में केवल 6 सदस्य बढ़ा पाये हैं। देश की मीडिया ने तो पत्रकारिता के सारे उसूलों और शिष्टाचार को तिलांजलि दे दी थी। चुनावपूर्व आकलन तथा चुनाव के दौरान किये गये सर्वेक्षणों ने तो झूठ के सारे रिकार्ड तोड़ दिये। ऐसी परिस्थितियों में आये चुनाव परिणामों से निराश होने की तो आवश्यकता नहीं लेकिन संतोष न करके सभी लोकतान्त्रिक और देश की एकता बनाये रखने के लिये प्रतिबद्ध दलों को गम्भीरता के साथ अपनी कमियों की समीक्षा और उनकों दूर करने के उपाय खोजने चाहिए।

मैनें पूर्व में कहा कि देश की जनता ने भाजपा को स्वीकार नहीं किया है। भाजपा के नेतृत्त्व में बनी सरकार उन दलों और व्यक्तियों के सहयोग के कारण से बनी हैं, जिन्होनें भाजपा की मूलभूत सम्प्रदायवादी नीतियों से अपने को अलग करके जनता से धर्मनिरपेक्षता के मुखौटे लगाकर वोट मांगे और प्राप्त किये। इन नकली धर्मनिरपेक्ष दलों कों पहचानने मे भारी चूक हुई और यहां हम सभी गैर साम्प्रदायिक दलों और व्यक्तियों को अपनी गलती स्वीकारनी होगी कि हम जनता के सामने इन लोगों के नकाब को उतार कर असली चेहरा पहचनवां देने में नाकामयाब हुए। जनता और धर्मनिरपेक्ष ताकतों

को सबसे बड़ा धोखा "तेलगु देशम पार्टी" से मिला है। इसके नेता तो संयुक्त मोर्चा के संयोजक भी थे और उन्होंने संयुक्त मोर्चा और धर्मनिरपेक्षता को बड़ा आघात दिया, लेकिन आश्चर्य तो इस बात पर है कि भाजपा की सरकार को विश्वास मत प्राप्ति के मतदान में साथ देकर बेशर्मी के साथ धर्मनिरपेक्षता का नारा दे रहे हैं और भाजपा को साम्प्रदायिक दल भी बता रहे हैं। यह सर्वविदित है कि तेलगु देशम के भाजपा के साथ चले जाने पर दल में बगावत आ गयी है। मैं तेलगु देशम के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि जो धर्मनिरपेक्षता के उसूल के लिये लड़ाई लड़ रहे हैं। अवसरवादिता और भ्रष्ट आचरण बढ़ रहा है। राजनीतिज्ञों की कथनी और करनी में भेद के चलते ही जनता के मन में लोकतन्त्र के प्रति आस्था में गिरावट आई है। ऐसी बातों और हरकतों को भविष्य में नहीं रोका गया तो हमारा लोकतन्त्र खतरे में पड़ सकता है। गैर सम्प्रदायिक सरकार के गठन के मामले में केन्द्र में पहले कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिये था क्यों कि संयुक्त मोर्चा के सभी घटकों से लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक थी लेकिन इसके ढुलमुल रवैये और नेताओं के स्पष्ट और सामूहिक कथनों के आभाव से कांग्रेस के एकमत न होने का संदेश देश को मिला। समाजवादी पार्टी के ठीक समय स्पष्ट वक्तव्यों के अनुसार यदि कांग्रेस ने निर्णय लिये होते तो केन्द्र सरकार की दूसरी ही तस्वीर होती।

लेकिन संयुक्त मोर्चे के कुछ घटकों ने भी यथा समय आवश्यक सक्रियता नहीं दिखाई। कुछ दल के नेताओं के अर्न्तविरोध मुखर होकर सामने आये। धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन को लेकर भी परस्पर विरोधी बयान आये। इस प्रकार केन्द्र सरकार बन जरुर गयी है लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह अल्पजीवी सरकार है बशर्ते धर्मनिरपेक्षता की सभी ताकतें स्पष्ट नीति, त्वरित निर्णय तथा अपने किये फैसलों पर अमल करने लिये कटिबद्ध हो जायें । केन्द्रीय सरकार ने एक राष्ट्रीय ऐजेन्डा जारी किया है इसे ही वे कार्यक्रम बता रहे हैं उक्त एजेण्डे में न तो जनहित के ठोस कार्यक्रम है और ना ही अमल करने की कोई रुपरेखा है। केवल सद इच्छाओं की घोषणायें हैं। उसमें एक आयोग गठन करने की बात कही गयी हैं जो संविधान की समीक्षा करेगा उस समीक्षा का क्या उद्देश्य है यह भी स्पष्ट नही

हैं। एक बार फिर से संविधान बदलने की बात उछाली गयी है समाजवादी पार्टी आवश्यकता पड़ने पर बुनियादी सवालों को लेकर, संविधान में संसोधन करने की विरोधी नहीं है। संविधान सभा ने पूर्ण सूझ–बूझ के साथ संविधान बनाया था। इसको बनाते समय यह ध्यान रखा था कि भारत एक बहुभाषी, बहुधर्मी तथा बहुलतावादी देश है। संविधान की रचना मे कोई बुनियादी दोष नहीं है। इसी संविधान के अर्न्तगत नागरिकों को राजनैतिक अधिकार के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाया जा सकता है। आज की परिस्थितियों में अगर कोई बदलाव अपेक्षित है तो राजनैतिक दलों और नेताओं के सोच में बदलाव लाना आवश्यक है। राजनैतिक दलों की कथनी करनी के फरक को खत्म करना होगा और स्पष्ट नीति और ठोस कार्यक्रम के जरिये राजनीति करनी होगी। यह कार्य संविधान के बदल देने से नहीं वरन् राजनैतिक दलों के मंथन और चरित्र से होगा। समाजवादी पार्टी ने लगातार इस बात को दोहराया है कि अपने सिद्धान्तों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे भले ही हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार कुछ धीमी हो। राष्ट्रीय राजनीति में हमारी यही पहचान है। संविधान समीक्षा के लिये आयोग के गठन के पीछे कई खतरे छिपे हुए हैं। यह संघ परिवार द्वारा हिटलर के उसूलों और कार्य शैली अपनाने का नमूना है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सत्ता पर काबिज होकर संविधान में संसोधन कर जिस प्रकार हिटलर ने तानाशाही स्थापित की थी, उसी प्रकार संघ परिवार तानाशाही स्थापित कर देश की एकता, संस्कृति और लोकतन्त्र को समाप्त करने साजिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी को इस बात का गर्व है कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरहद में साम्प्रदायिकता के खिलाफ जो उद्घोष किया था, वह राष्ट्रीय मुद्दा बना और देशी –विदेशी पूंजीवाद के दबाव के बावजूद साम्प्रदायिक दलों की हिस्सेदारी और सहयोग के जरियें एक धर्मनिरपेक्ष शक्ति का संयोजन हो पाया। समाजवादी पार्टी साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष की इस घटना को एक शुभ लक्षण मानती है कि जो लड़ाई समाजवादी पार्टी ने अकेले शुरू की थी उस लड़ाई को देश की दो तिहाई जनता ने अपनी लड़ाई मान लिया है समाजवादी पार्टी के सामने वृहत्तर उद्देश्य एवं लक्ष्य है। समाजवादी पार्टी ने महात्मा गाँधी, से करुणा, डा0 लोहिया से संघर्ष, और व्यवस्था–परिवर्तन तथा चरण सिंह से

कृषि उन्मुख नीतियों को लेकर नये समाजवादी भारत का निमार्ण करने के लिये संकल्प किया है। समाजवादी पार्टी का नजरिया साफ है कि देश का विकास यहां के किसानों बुनकरों, दस्तकारों कामगारों और देश के लिये समर्पित बुद्धिजीवी के द्वारा ही हो सकता है। बाहर से पूँजी लाकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विकास को जवाबदेही नहीं दी जा सकती। साम्रज्यवादी देश विकासशील देशों का शोषण करने के नये नये रास्ते अख्तियार कर है। हमारे देश मे किसानों की उपज तथा देश की प्राकृतिक सम्पदा पर कब्जा जमाने की कार्यवाही हो रही है। बासमती चावल का लिये गये पेटेन्ट को रद्द करने तथा देश की जड़ी–बुटियों के पेटेन्ट हासिल करने की साजिशों का समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ विरोध करेगी। देश की प्रगति मे सबकी साझेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इसके लिये दलितों, पिछड़ों अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को विशेष अवसर प्रदत्त करना आवश्यक है। समृद्धि से समानता लाने के संकल्प से सभी को न्याय उपलब्ध कराना होगा। समाजवादी पार्टी ने जातिवादी सोच और मानसिकता का सदा विरोध किया है और कमजोरों, पिछड़ो, बुनकरों, व्यापारियों, अल्पसंख्यकों, छात्रों और महिलाओं की लड़ाई को लड़ी है और वह हकीकत है कि गरीब सवर्णों की लड़ाई भी समाजवादी पार्टी ने ही देश मे लड़ी है। हमारे द्वारा ही गठित "कौशिक समिति" की सिफारिश के आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण गरीब सवर्णों को देने के लिये संविधान में संसोधन करने की मांग समाजवादी पार्टी न की है।

समाजवादी पार्टी, देश की उन्नति और देश में समानता के लिये देशी भाषाओं में राज–काज चलाने को अनिवार्य मानती है।

इस देश मे समाजवादी आन्दोलन का इतिहास बहुत पुराना है शुरु के दिनों में देश और विदेश के समाजवादियों ने समाजवाद के सिद्धान्त को निरुपित करने के लिये समता मूलक समाज की कल्पना की थी और आदमी–आदमी की गैरबराबरी को समाप्त करने के लिये केवल पूँजीवादी व्यवस्था के खिलाफ वर्ग संघर्ष का नारा दिया था। दुनिया के कुछ हिस्सों में इस नारे को पकड़ा भी गया लेकिन बाद के दिनों मे डा० राम मनोहर लोहिया

ने भारत के दर्द को समझा कि इस देश मे केवल पूंजी नहीं बल्कि जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था और भूगोल के आधार पर क्षेत्रीय विषमता भी गैर बराबरी के मारक कारण हैं। और इसी आधार पर समाजवादी आन्दोलन ने दलितो, पिछड़ों महिलाओं और गरीब मुसलमानों के लिये विशेष अवसर के सिद्धान्त को अंगीकार किया। समाजवादी पार्टी पूंजी के आधार पर विषमता, जन्म के आधार पर विषमता एवं क्षेत्र के आधार पर विषमता को खत्म करने के लिए बिगुल बजाया है। देश की जनता ने महसूस कर लिया है कि इन तीनों विषमताओं के खिलाफ जब जिहाद छिड़ा है तो निहित स्वार्थ वाली शक्तियाँ अपने बचाव के लिये तरह–तरह के षड़यन्त्र रचती हैं। सम्प्रदायवाद उसी से निकला जहरीला कीड़ा है। इन विषमताओं को खत्म करने की लड़ाई के साथ–साथ सम्प्रदायवाद के जहरीजा कीड़े को खत्म करने की लड़ाई को लड़ना होगा।

भाजपा सरकार के छिपे ऐजेण्डे से देश के सामने जहां और कई संकट आयेंगे, वही अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई के सबंध में उनकी नीतियाँ बड़ी घातक है। राष्ट्रीय एजेण्डा की बातों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि भाजपा गठन के लोग ऐलान के साथ आयोध्या, काशी, मथुरा, कॉमन सिविल कोड और 370 धारा हटाने के मुद्दों की वकालत कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के साथ अलगाव– दुराव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अल्पसंख्यकों –विशेष कर मुसलमानों को न0–2 का नागरिक मानने की भाजपा की नीति का पूरी ताकत से विरोध करना समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का प्रथम कर्त्तव्य है। भाजपा के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार के बनते ही विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक–तनाव पैदा हुआ है।

समाजवादी पार्टी एक ओर साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ संघर्षरत है तो दूसरी ओर गरीबी के खिलाफ जंग मे सदियों से उपेक्षित लोगों के हकों की लड़ाई पूरी निष्ठा के साथ लड़ रही है। समाजवादी पार्टी जन्म के आधार पर कमजोर लोगों, दलित, पिछड़े गरीब मुसलमान और महिलाओं के लिये लड़ाई का बिगुल जितनी ताकत से फूँक चुकी है उससे भी ज्यादा ताकत से आर्थिक क्षेत्र में उतरी है। कारखाने की पैदावार के मुकाबले खेती की पैदावार

कमजोर है। कारखाने कच्चे माल के इस्तेमाल करने के नाम पर खेती का शोषण करते हैं। जब तक कारखानों के बने माल और खेती के उत्पाद के दामों में लागत और लाभ दोनों पक्षों के बीच सन्तुलन कायम नहीं किया जायेगा देश के गांव और खेत शहरों के उपनिवेश बन कर रह जायेंगे।

जिस देश में जन्म के आधार पर इन्सान और पैदावार के आधार पर वस्तुयें कमजोर और बेसहारा होने के नाते मजबूत के हाथों से मार खाते है। उस देश में सर्वाधिक कमजोर और बेसहारा होने के नाते बच्चों और नौजवानों के लिये मार खाना उनकी नियति बन जाती है। दुनियां में सबसे अधिक मार खाने वाले भारतीय बच्चे और बेसहारा भारत के नौजवान हैं। समाजवादी पार्टी जहां एक ओर समाज के दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन के लिए विशेष अवसर देने के निर्णय को कारगर बनाने के लिए संर्घषरत हैं वहीं देश के नौजवानों के बेसहारापन को दूर करके काम के अधिकार को दिलाने की लड़ाई का ऐलान करती है।

समाजवादी पार्टी विदेशी निर्भरता के खिलाफ है, पार्टी सहयोगी विश्व व्यवस्था की बात जरूर करती है। लेकिन विदेशी–ऋण लेने के खिलाफ है। विदेशी ऋण से देश की स्वायत्ता समाप्त होती है। और विकास की दिशा गलत राह ले लेती है। समाजवादी पार्टी आर्थिक विकास की परिभाषा गरीबी और पूरी आबादी को काम पर लगाने से ही होगा जिससे भूख,, भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति हो सकती है।

समाजवादी पार्टी नयी विश्व दृष्टि का निर्माण करना चाहती है, संयुक्त राष्ट्रसंघ से जुड़ी विश्व संस्थाएं अब पचास वर्ष पुरानी हो चुकी हैं। उनकी सार्थकता और प्रसांगिकता तो समाप्त हो ही चुकी है, वैसे भी समानता और विश्व बन्धुत्व के उद्देश्य की पूर्ति यह संस्थाएं नहीं करती थी। भेद–भाव की भावना, और बड़े देशों के हित साधने की वरीयता के कारण गरीब देशों के विकास को गति देने में असफल रही है। समानता के आधार पर विश्व पंचायत का निर्माण करना, समाजवादी आन्दोलन की कामना रही है।

भारत प्रायद्वीप को शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनाने के लिए डॉ0 राममनोहर लोहिया ने भारत–पाक–बांगलादेश महासंघ बनाने का सपना

संजोया था। तीनों देशों के विकास के लिए समाजवादी पार्टी सन्दर्भित महा संघ बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगी। हमारी नीति अपने सभी पड़ोसी देशों से मधुर सम्बन्ध बनाये रखने की है। और सभी समस्याओं का निदान वार्ता के जरिये करने की है। यद्यपि हम हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन वर्तमान में सीमाओं की स्थिति को देखते हुए हमें मुह तोड़ जबाव देने के लिए पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद रहना चाहिए। इसके लिए तैयारी में हमें किसी भी देश के दबाव या नाराजगी की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान को किसी देश के बहकावे में आकर हथियारों के दौड़ में नही शामिल होना चाहिए शान्ति और सार्मजस्य कायम रख, अपने देश की गरीबी खत्म करने और आर्थिक विकास को गति प्रदान करनी चाहिए।

प्रतिनिधि साथियों, इस गुरुतर कार्य–सम्पन्नता का भार हम सबके ऊपर है। इस महान दायित्व की पूर्ति के लिए एक सशक्त, सक्षम और अनुशासित संगठन होना परम आवश्यक है। इस सम्मेलन में मुझे विश्वास है, आप ऐसा संगठन बनाने के लिए ठोस निर्णय लेंगे।[6]

5. चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन

समाजवादी पार्टी का तीन दिवसीय चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन 29–31 जनवरी 1999को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में सम्पन्न हुआ।

अध्यक्षीय भाषण–

समाजवादी पार्टी के चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन कें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने अध्यक्षतीय भाषण में कहा कि–

प्रतिनिधि साथियों,मध्यप्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। सच्चे अर्थ में यह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक समन्वय का प्रतिनिधित्व करता है। सात विशाल राज्यों से घिरा यह प्रदेश उत्तर में चम्बल और दक्षिण में नर्मदा

---

6 - समाजवादी पार्टी के विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन मुम्बई में 19 अप्रैल 1998 को दिया गया अध्यक्षीय भाषण

से पोषित है। इसका वर्तमान राजनीतिक स्वरूप नया है लेकिन इस इलाके का वर्णन चीनी यात्री फाह्यान ने भी अपनी किताब में किया है। इसकी राजधानी भोपाल जो नवाबी आन में पली और बढ़ी थी, आज भी अपनी खूबसूरती और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है।

मध्य प्रदेश की महान जनता का स्वागत और अभिनन्दन मैं इस लिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने विधान सभा के पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक दिया है और पहली बार समाजवादी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए अपने मन में स्थान बनाया है। हमारे कार्यकर्ताओ और समर्थकों की मेहनत से विधान सभा में हमें चार स्थान मिले हैं। मैं इसे एक बहुत अच्छी शुरूआत मानता हूँ। तीन राज्यों में पराजय के बाद भाजपा में यदि लोकतांत्रिक परम्पराओं के प्रति थोड़ा भी सम्मान होता तो केन्द्र की सरकार को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए था। इन राज्यों में जनता का फैसला भाजपा की साम्प्रदायिक नीतियों, भ्रष्ट आचरण और निकम्मे प्रशासन के खिलाफ था। इन चुनावों में जीत के कारण कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत के बारे में भ्रम हो गया है क्योंकि इन तीनों राज्यों में जनता के सामने कांग्रेस के अलावा कोई ठोस विकल्प नहीं था। मैं मध्य प्रदेश और पूरे देश की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि राजनैतिक ध्रवीकरण के प्रयास मे गैर भाजपा और गैर कांग्रेस शक्तियों को एक साथ खड़ा करने का भरपूर प्रयास होगा। इस कोशिश में समाजवादी पार्टी का यह सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा और अगले चुनाव में जनता को भाजपा और कांग्रेस से अलग कोई विकल्प चुनने में परेशानी नहीं होगी।

समाजवादी पार्टी का यह राष्ट्रीय सम्मेलन ऐसे नाजुक समय पर हो रहा है जब पूरा देश राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अराजकता के दौर से गुजर रहा है। देश की राजनैतिक हालत का विश्लेषण करते हुए हमें यह भी खास तौर से देखना पड़ेगा कि आज की दशा पैदा करने के जिम्मेदार कौन है? मैं आपको याद दिलाता हूँ कि पिछले वर्ष ठीक इसी समय जब बारहवीं लोक सभा के चुलाव की तैयारी हो रही थी तब से इस एक वर्ष में देश में जो कुछ बिगड़ा और बर्बाद हुआ है उसका गहराई से मनथन करना पड़ेगा। एक ओर केवल 11 महीने में भारतीय जनता पार्टी की

केन्द्र सरकार ने आर्थिक गुलामी, देश व्यापी अराजकता, साम्प्रदायिकता, अपसंस्कृति, असहिष्णुता और चारों ओर सामाजिक असुरक्षा को फैलाया है या दूसरी ओर हमें यह भी जनता के सामने मंजूर करना पड़ेगा कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस ताकतें एक साथ नहीं रह सकीं। वे लोग जो साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहें थे अचानक सत्तालोलुप क्यों हो गये?

इक्कीसवीं सदी में इस देश के किसानों, नौजवानों, अल्पसंख्यको, महिलाओं, मजदूरों और दलितों के सामने हम किस रूप में खड़े होना चाहते हैं। ये सभी लोग हमसे पूछेंगे कि देश के बिगड़ते हालात को रोकने के लिए हमने क्या किया है? उस समय उनके सामने हम जवाबदेह होंगे। हम दूसरे दलों की तरह झूठ–सच बोलकर बच नहीं सकते। हमें इसी सम्मेलन में विचार करके समूची परिस्थियों से लड़ने के लिए देश व्यापी संघर्ष की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। समाजवादी राजनीति के प्रेरणा पुरूष डा0 राम मनोहर लोहिया का यह वाक्य हमें बराबर याद रखना चाहिए "जिन्दा कौमें पांच साल तक इन्तजार नहीं करतीं" और आजकल तो यह इंतजार घटकर मुश्किल से दो साल रह गया है।

पिछने 11 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहर ढ़ाया है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस जमात को सरकार मानना ही हास्यास्पद है। आज तक कोई एक भी फैसला सरकार सर्वसम्मति से नहीं ले सकी है। इतना बड़ा माखौल पहले कभी नहीं हुआ। गुजरात हो या कर्नाटक, जम्मू कश्मीर हो या असम, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, अल्पसंख्यकों को घेरकर हमले किये जा रहे हैं। मुम्बई, दिल्ली और दूसरे राज्यों से मुसलमानों को बंगलादेशी बताकर बाहर निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में मुस्लिम युवकों की हत्यायें हुयी हैं। महान मुस्लिम विद्वान अलीमियां के घर पर छापा मारा गया। ईसाई स्कूलों, मिशनरियों और अस्पतालों पर हमले की पूरी रपट अल्पसंख्यक आयोग ने गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इसके बावजूद गृहमंत्री, भारत सरकार, का यह कहना कि मुद्दे को बेकार उछाला जा रहा है, देश के अल्पसंख्यकों का खुला अपमान है। प्रधानमंत्री हमला करने वाले संगठनों को दण्डित करने बजाय धर्मान्तरण पर

बहस की बात उठाकर देश को गुमराह कर रहे हैं। गृहमंत्री की धमकियों के बावजूद हत्यायें न कश्मीर में रूकी हैं, न दिल्ली में और न असम में। इस सरकार में शामिल दलों के नेता और केन्द्रीय मंत्री खुलेआम जिस तरह संविधान और देश की चिन्ता किये बिना लूटने और माहौल बिगाड़ने में लगे हैं उसको देखते हुए क्या इस सरकार को एक मिनट भी सत्ता में बने रहने देना चाहिए? अपनी सरकार का झूठ और निकम्मापन छिपाने के लिए राष्ट्रपति तक को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि बिहार की सरकार भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने नामंजूर कर दिया था।

भाजपा गठबन्धन के सत्ता में आने के बाद से देश के अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों तथा ईसाईयों की मानसिकता जिस बेचैनी, आतंक और घबराहट के दौर से गुजर रही है, उसे हम शिद्दत के साथ महसूस करते हैं। वर्तमान सरकार के राष्ट्रीय एजेण्डे और स्वदेशी की पोल खुल गयी है। राष्ट्रीय एजेण्डा एक फर्जी दस्तावेज साबित हुआ है। भाजपा के नेताओं, संघ परिवार के पदाधिकारियों तथा भाजपा के प्रदेश के मुख्यमंत्री, काशी, अयोध्या, मथुरा, कामन सिविल कानून तथा धारा 370 को हटाने के अपने मुद्दों पर कायम हैं।

यह बिल्कुल सही बात है कि आजादी के बाद कांग्रेस तथा भाजपा शासन में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों की घोर उपेक्षा हुई है। उनका व्यापार तथा परम्परागत उद्योग धन्धे चौपट हो गये हैं। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादात निरन्तर घटी है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के बावजूद मुसलमानों की संस्कृति, भाषा–लिपि पर निरनतर प्रहार हो रहे हैं। हमारी मान्यता है कि देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखने तथा देश की समृद्धि के लिए यह जरूरी है कि सरकारी नौकरियों, पुलिस बलों एवं सेना की भर्ती में मुसलमानों की उपेक्षा पर विराम लगे और उनके परम्परागत उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन दिया जाय। राष्ट्रीय एकता से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर इस सरकार ने घोर साम्प्रदायिक रूख अख्तियार किया है। कश्मीर के संबन्ध में गृहमंत्री के अविवेक पूर्ण बयानों से वहां स्थिति और बिगड़ी है। आतंकवादी गतिविधियां तथा उनके परिक्षेत्र की बढ़ोत्तरी रोकने में सरकार नाकामयाब हुई है। समाजवादी पार्टी का मानना है

कि कश्मीर की स्थिति वहां की जनता का विश्वास जीकर तथा दृढ़ संकल्पबद्धता के साथ ही सुधारी जा सकती है, जिसके लिए एक वृहद राष्ट्रीय दृष्टिकोंण का अनुसरण करना होगा। मौजूदा सरकार कश्मीर के मामले में एक संकीर्ण साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का अनुसरण कर रही है।

देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था किस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है इसका अंदाजा इस उदाहरण से लगाया जा सकता है कि देश का रक्षा मंत्री अपने नौसेना प्रमुख को बर्खास्त करते हुए उसे देश के लिए खतरा बता रहा है और बर्खास्त नौसेना रंक्षामंत्री सहित पूरी सरकार को बेईमान और झूठा घोषित कर रहा है। सरकार की यह असफलता देश के प्रति एक बेहद गंभीर अपराध है जो पहले कभी नहीं हुआ। पूरी दुनियां में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हमारी सेनाओं की इस धटना से प्रतिष्ठा घटी है, मनोबल टूटा है। ऐसी स्थिति में सीमाओं की पहरेदारी कर रहे हमारे बहादुर सैनिक या तटों की रक्षा करने वाले नौसैनिक अपने पूरे मनोबल से क्या देश की रक्षा कर सकेंगे?

आर्थिक मोर्चे की हलात भयावह है। केन्द्र और लगभग सभी राज्य सरकारें दिवालियां होने के कगार पर पहुँच गयी हैं। आजादी के बाद से देश में अर्थव्यवस्था की यह सबसे बुरी दशा है। इस सरकार में मंदी, मंहगाई और मुद्रास्फीति बढ़ी है। रूपये की कीमत आधी हो गई है। बजट में किये गये आर्थिक सुधार के सभी दावे झूठे साबित हो चुके हैं। कोयला, स्टील, पेट्रोलियम जैसे आधारभूत उद्योगों का उत्पादन लगातार गिरा है। एक साल पहले जो व्यापार घाटा 150 अरब से भी कम था वह अब बढ़कर 300 अरब से अधिक हो गया है। पिछले तीन महीनों में निर्यात 4 प्रतिशत घटा है और विदेशों से आयात करके आने वाले सामानों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने20 प्रतिशत निर्यात का लक्ष्य खुद घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है योजना के मदों में कटौती हो रही है और गैर योजना व्यय लगातार बढ़ रहा है। विदेशी कर्ज 4000 अरब रूपया हो गया है और देशी कर्ज अलग है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति और व बैंकों के कामकाज में गिरावट तथा घोटालों को लेकर बार–बार गंभीर चेतावनी दी है भुगतान का संतुलन पिछले वर्षों में सबसे अधिक गंभीर दशा में है, राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक ने कर्ज देने से

मना कर दिया है। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन नहीं है और सरकार के साथ ही बैंको, यूनिट ट्रस्ट और सरकारी बांडों पर से भी लोगों का भरोसा उठ चुका है।

आर्थिक उदारवाद के नाम पर विश्वव्यापार समझौता कांग्रेस सरकार ने ही देश पर थोपा था और आज भी संसद में जब समाजवादी पार्टी एवं अन्य दल इसके विरोध में खड़े हैं तो कांग्रेस पेटेंट कानून, बीमा नियमन कानून में संशोधन पास करने के लिए भाजपा को समर्थन दे रही है। अभी राज्यों में भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक लाकर किसानों को खेती की जमीन से बेदखल करके बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देने का षडयंन्त्र किया जा रहा है। पिछले वर्षों में इन विदेशी कम्पनियों के लिए लगभग सौ कानून बदले गये हैं जरूरत न होने के बावजूद हमे समझौते के तहत अनाज खरीदना पड़ रहा है। इन कम्पनियों के दबाव में इस सरकार ने तीन सौ चालीस वसतुओं को नियंत्रित सूची से हटाकर खुले आयात की सूची में रख दिया है। पेटेंट कानून पास होने से 25 हजार देशी दवा कम्पनियां जो लगभग 6 हजार करोड़ रूपये सालाना का व्यापार करती हैं समाप्त हो जायेंगी या उन पर विदेशी कम्पनियों का कब्जा हो जायेगा। विश्व व्यापार संगठन को लेकर सरकार की मजबूरी चाहे जो हो लेकिन क्या हम अपने देश के गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की जिन्दगी की कीमत पर यह कानून पास करेंगे? पिछले ग्यारह महीनों में कुल मिलाकर इस सरकार की आर्थिक उपलब्धि यह है कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। देशी उद्योगों में भारी मंदी चल रही है। लघु उद्योगों जिससे रोजगार के अवसर बनते हैं और बुनकरों तथा हथकरघा उद्योग में लगे लाखों लोगों का रोजगार खतरे मे पड़ने जा रहा है। दस करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं और मध्यम वर्ग के लगभग 40 प्रतिशत लोग महंगाई के कारण अब दो बार की जगह केवल एक बार खाने के लिए मजबूर हैं।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें 76 प्रतिशत से अधिक लोग खेती के कार्य में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की स्पष्ट मान्यता है कि भारत की तरक्की किसानों की तरक्की के साथ जुड़ी हुई है। जब तक देश के किसानों की समृद्धि नहीं होगी देश गरीब बना रहेगा। लेकिन खेद की बात है

कि हमारे किसानों की दयनीय स्थिति है। उनकी उपज का लाभपरक मूल्य तो क्या लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता जबकि उसे अपनी जरूरत की मीलों में बनने वाली वस्तुएं मंहगे दामों में लेनी पड़ती हैं। बीज, खाद, पानी आदि खेती की आवश्यकता पूरी नहीं की जाती। लेकिन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाने पर भारत की सरकार ने किसानों को निरीह और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मोहताज बना देने का दुष्चक्र चला दिया है। विश्व व्यापार संगठन के निर्देशों के अनुसार भारत सरकार पेटेन्ट कानून को बदल रही है। हमारे देश के बीजों पर विदेशी कम्पनियों ने पेटेन्ट हासिल कर लिया है जिसके कारण बोजों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अधिकार हो जायेगा। बीज उनसे ही लेनें पड़ेंगे और उनके द्वारा निर्धारित मनमाने दामों पर । इस दुष्चक्र का दूसरा खतरनाक पहलू यह है कि देश में गेहूँ–चीनी आदि जैसे चीजों का भरपूर उत्पादन होने पर भी भारत सरकार को विदेशी गेहूँ और चीनी जैसी वस्तुओं का आयात अनिवार्यतः करना होगा और नतीजा होगा कि किसान को उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पायेगा।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चंगुल से बचने के लिए हम विश्वव्यापार संगठन की सदस्यता से अलग होना अनिवार्य मानते हैं। साथ ही किसानों को उत्तम बीज, खाद तथा पानी उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व मानते हैं। किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिले, मील में बनने वाली वस्तुओं और किसान की उपज के मूल्यों में उचित अनुपात कायम हो तथा मील में बनने वाली वस्तुओं की कीमतें लागत खर्च से ड्योढ़े से ज्यादा न हों तभी किसान और देश तरक्की कर सकता है।

सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण हमारे देश के उद्योगों में भारी मन्दी का दौर चल रहा हैं। नये उद्योगों के जरिये बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है बुनकरों की स्थिति दयनीय हो गयी हैं। उनको सूत उचित मूल्यों और समय पर उपलब्ध नहीं होता और न ही उनके उत्पादन के लिए बाजार बुनकरों को मीटर के हिसाब से नहीं वरन् प्रति हार्सपॉवर पर निश्चित रेट पर विद्युत अपुर्ति की जानी चाहिऐ। संघ परिवार तथा पुलिस की गठजोड़ से कुरेशी समुदाय का जबर्दस्त उत्पीड़न किया जा रहा है। नियम सम्मत उनके व्यापार में बाधा डाली जा रही है।

समाजवादी पार्टी देश में एक समतामूलक व्यवस्था और एक नई राजनीतिक कार्य संस्कृति लाने के लिए अपने संकल्प को दोहराती है। हम भोगवादी संस्कृति और असमान पोषक व्यवस्था को समाप्त कर समता और समृद्धि स्थापित करना चाहते हैं। देश के विकास और उन्नति में अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, नौजवानों, बुनकरों और किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी संस्थाओं का सम्मान तथा उनकी स्वतंत्रता ही देश का भविष्य सुखद बनायेंगे। सहकारी संस्थाओं, जिला पंचायतों को निरीह बनाये जाने तथा नगरपालिकाओं से लेकर कुलपतियों एवं राज्यपालों के मनोनयन तक ऐसे उपक्रम किये जा रहे हैं और ऐसे लोग मनोनीत किये जा रहे हैं जो पद की गरिमा और अस्मिता को लज्जित कर रहे हैं। भाजपा के द्वारा बिहार के मामलों में जिस निर्लज्जता के साथ वहां की सरकार को बर्खास्त करने के हथकण्डे अपनाये गये और आज भी जिस घिनौने तरीके से दुष्प्रयास किये जा रहे हैं, वे निन्दनीय और भर्त्सना करने योग्य हैं। बिहार के राज्यपाल तथा केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा जिस प्रकार के बयान दिये जा रहे हैं वे जनतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय प्रणाली की व्यवसथा के विरुद्ध, संविधान की भावना के प्रतिकूल तथा स्थापित मान्य परम्पराओं की अवहेलना करने वाले हैं। बेशरमाई की हद यह है कि महामहिम राष्ट्र पति के तथा बिहार में अभी हुए उप चुनावों के जनता के फैसलों के बाद भी केन्द्रीय सरकार के मंत्री और बिहार के राज्यपाल बिहार सरकार के खिलाफ बयान देते जा रहे हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में हुए दंगों पर श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट को भाजपा शिवसेना सरकार द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार करके, रिपोर्ट के खिलाफ जिस तरह मुसलमानों पर आरोप लगाये हैं और जस्टिस श्रीकृष्ण पर मुसलमान समर्थक होने का आरोप लगाया है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है।

आजादी के आन्दोलन के दौरान बनाई गई हमारी विदेश नीति की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संदेह की नजर से देखी जा रही है। हमारी शान्तिप्रियता की छवि नष्ट हुई है और तटस्थ तथा विकासशील देश हम पर अविश्वास करने लगे हैं। सरकार ने जिस गलत ढंग से पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था उससे देश का आर्थिक संकट और गम्भीर हुआ। पड़ोसी

देशों से हमारे सम्बन्ध अधिक खराब हुये हैं और सामरिक क्षेत्र के मामलों में भारत की सर्वोच्चता घटकर पाकिस्तान के बराबर आ गई है। आणविक क्लब का सदस्य बनना तो दूर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य बनने की संभावना भी खत्म हो गई है। इस एक घटना के कारण पाकिस्तान, चीन और अमेरिका भारत के खिलाफ मजबूती से एकजुट होकर खड़े हो गये हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर यह सबसे बड़ी असफलता है। अमेरिका, जापान और उन सभी देशों की, जिन्होंने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये हैं मैं उनकी निन्दा करता हूँ।

भारतीय जनता पार्टी को बारहवीं लोकसभा के चुनाव में बहुमत नहीं मिला था। उस समय मैंने यह कहा था कि अधिक सीटें जीतने के बावजूद इनको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह पार्टी संविधान की धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में विश्वास नहीं करती। यह किसी से छिपा नहीं है कि भाजपा का दो सीट से लगभग एक सौ अस्सी सीट तक पहुंचाने का आधार राम जन्मभूमि मन्दिर का आन्दोलन रहा है। इसी दौर में सबसे बड़े साम्प्रदायकि दंगे हुये हैं। बाबरी मस्जिद ध्वंस करने के बाद अपनी साम्प्रदायिकता का बड़ा जाल फैलाकर भाजपा ने अपना कथित हिन्दू जनाधार बनाया था। उसके पीछे कोई राजनैतिक या आर्थिक दर्शन नहीं था। उस समय मैंने यह कहा था कि देश के हित में भाजपा को रोकने के लिए हम साझा कार्यक्रमों के आधार पर कांग्रेस का समर्थन करेंगे, क्योंकि हम भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को कम अपराधी मानते हैं। बाद में मार्क्सवादी और दूसरे वामपंथी दलों ने भी इस पर अपनी सहमति दी थी। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति श्री के0आर0 नारायणन से मिलकर यह कह दिया कि कांग्रेस सरकार नहीं बनायेगी। इसी मध्य प्रदेश में काग्रेस का पंचमढ़ी में जो सम्मेलन हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी की निन्दा की गयी थी। अब जाकर यह रहस्य खुला है कि उस समय कांग्रेस ने सरकार क्यों नहीं बनायी? और आज जबकि भाजपा सरकार ने देश को राजनैतिक अराजकता, भ्रष्टाचार और आर्थिक गुलामी के कगार पर खड़ा कर दिया है, तब भी कांग्रेस भाजपा सरकार को क्यों नहीं गिराना चाहती? सच्चाई यह है कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के पूरक बन गये हैं। पेटेन्ट, बीमा और

दूसरे विधेयक को जिस तरह संसद में काग्रेस समर्थन दे रही है उसके बाद दोनों में गुणात्मक फर्क देखने की कोशिश करना भारी गलती होगी। सन 1949 ई0 और सन् 1999 अर्थात 50 वर्ष में मन्दिर–मस्जिद मुद्दे को लेकर भाजपा सत्ता में पहुँची है। उसके लिए कांग्रेस और केवल कांग्रेस जिम्मेदार है। मूर्तियां रखने का काम, ताला खुलवाने का काम कांग्रेस ने किया था। सिलान्यास कांग्रेस ने कराया था। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार आयोध्या से शुरू किया था। बाबरी मस्जिद तोड़ दिये जाने के बाद तथा राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद नया मंन्दिर बनवाने तक क्या कांग्रेस की सरकार चुप नहीं थी ? इन सारी घटनाओं के पीछे पहले प्रधानमंत्री कौन और बाद दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? अब फिर कांग्रेस भी ठीक वहीं कर रही है इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि गुजरात में इसाइयों पर हमले की पुष्टि होने के बाद लोक सभा में विपक्ष के नेता द्वारा गुजरात सरकार को बर्खास्त करने की मांग के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष भाजपा सरकार को बर्खास्त नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि अटल बिहारी बाजपेयी को जयललिता या ममता बनर्जी के मुकाबले कांग्रेस पर अधिक भरोसा है।

अल्पसंख्यकों के सवाल पर जो रवैया कांग्रेस ने दिखाया है उससे किसी को यह भ्रम नहीं रहना चाहिए। मुसलमानों, इसाइयों या सिक्खों की हिफाजत का यह कांग्रेस का केवल मुखौटा है, असली चेहरा नहीं। कांग्रेस बिल्कुल बदली नहीं है। इसी मध्य प्रदेश के झबुआ जिले में क्रिश्चियन ननों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई थीं। दो करोड़ से अधिक ईसाई समुदाय और पूरी दुनियां के ईसाइयों ने गहरा रोष व्यक्त किया था। यहां की कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कांग्रेस और भाजपा के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। जिसका पर्दाफास करना जरूरी है। ऐसे राजनैतिक महौल में इस देश के संविधान, साम्प्रदायिक सदभावना और अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का विशेष उत्तरदायित्व उन लोगों पर है जो देश भर में तीसरी ताकत के रूप में पहचाने जाते हैं। जो अपने अहंकारों में चूर होकर खुद बिखर कर हाशिये पर पहुँच गये हैं। इस नाजुक दौर में यदि हमने अपने निजी और दलीय हितों से ऊपर उठकर देश को बचाने का काम नहीं किया तो अगली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी।

देश के तीन नये राज्यों के गठन के सवाल को भाजपा सरकार की गलत नीति, जिसमें काग्रेस पार्टी की सहमति है ने उलझाकर देश में फिर से क्षैतिजता के आधार राज्यों के पुनर्गठन जैसे मामलों पर विवाद खड़ा करने का माहौल बना दिया है। इससे नये राज्यों के सृजन का सिलसिला बन्द न होकर क्षैतिजता तथा अन्य बातों के आधार पर और राज्य बनाये जाने की मांग उठती रहेगी तथा आन्दोलन होते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्र के अतिरिक्त मैदानी क्षेत्र तथा हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर को शामिल करने तथा बिहार की जनता की आंकाक्षाओं के विपरीत वनांचल प्रदेश के सृजन का विरोध करेगी। भाजपा सरकार के आने के बाद एक बार फिर हिन्दी प्रदेशों को काटने और बाटने की शाजिस तेज हुई है।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान अंग्रेजी का महत्व अधिक तीब्रता से बढ़ा। और मातृ भाषाओं तथा क्षेत्रीय बोलियों की उपेक्षा की जा रही है। सन् 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग और भाषाओं के आधार पर प्रान्तों की रचना का प्रयोग कांग्रेस सरकार ने किया था। उसके नतीजे सबके शामने हैं। राजनैतिक पहचान के नाम पर वोटों की राजनीति का खतरनाक खेल शुरू हुआ है। इसको समझाना पड़ेगा। आर्थिक विकास के लिए अगर कोई नया राज्य बनाया जाता है तो यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसमें सभी पक्षों की सहमति हो। उसका दुष्परिणाम उन राज्य को न भोगना पड़े जिसका विभाजन किया गया है। राजनीति का यह खेल विकास के लिए कम चुनाव के लिए ज्यादा है। यह खेल बेनकाब करना पड़ेगा। क्योंकि इस असन्तोष में अराजकता के बीज छिपे हुये हैं। पूरे देश के राजनैतिक नक्शे को एक आम सहमति के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए।

हमारे देश में काग्रेस द्वारा उलझाया हुआ भाषा का सवाल आज भी वैसा ही बना हुआ है। भाजपा की सरकार देशी भाषाओं की घोर उपेक्षा कर रही है। भाषा नीति का सवला एक गम्भीर सवाल है। जिस पर फौरन ध्यान देना जरूरी है। हमे यह तय करना पड़ेगा कि हम और कितने दिन अंग्रेजी को अपने राष्ट्र भाषा के रूप में बरकरार रखेंगे। आजादी के पचास वर्ष बाद भी हिन्दी, उर्दू और सभी भारतीय भाषाएं अग्रेजी की गुलाम हैं। इसके कारण हमारी राष्ट्रीय एकता को सबसे अधिक चोट पहुँची है। अग्रेजी की गुलामी के

खिलाफ दो सौ साल तक लगातार लड़ने वाले राज्यों में अंग्रेजी पढ़ाने वाले स्कूल तेजी से बढ़ रहे हैं। यह इस लिए हुआ है कि अंग्रेजी जो पहले उच्च शिक्षा और सत्ता की भाषा थी, उसे अब विदेशी कम्पनियों ने उपभोक्ता बाजार की भाषा बना दिया है। केन्द्र की सरकारों ने जानबूझ कर भारतीय भाषाओं के खिलाफ अग्रेजी को बढ़ावा दिया है। किसी भी स्वाभिमानी और स्वतंत्र देश के लिए इससे अधिक अपमान जनक बात नहीं हो सकती कि वह अपनी राज्य भाषा और मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा और सरकार को न चला सके। सन् 1815 में जर्मनी के आजादी के बाद केवल एक वर्ष में "विस्मार्क" जर्मन को राजभाषा बना दिया और 1917 में रूस की क्रान्ति के बाद रुसी भाषा फौरन लागू की गयी थी। यह कितना अपमान जनक है कि फ्रांस की संसद कानून बनाकर अंग्रेजी के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा दे और भारत की संसद अपने सर्वसमस्त से पारित प्रस्ताव को संघ लोकसेवा आयोग से लागू न करवा सके, जबकि दिल्ली में शाहजहाँ रोड पर आयोग के दफ्तर के सामने पिछले दस साल से चल रहे आन्दोलन और धरना का समर्थन सभी राजनेता कर चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी संसद में इसे उठा चुके हैं। समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प करती है। महत्मा गांधी ने जिस तरह साम्प्रदायकि सद्भावना, स्वदेशी और अंग्रेजी के खिलाफ लड़ाई क्षेड़ी थी, वहीं काम फिर से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भूमिकाएं इस देश को आर्थिक और राजनैतिक के साथ सांस्कृतिक गुलामी की ओर ले जा रही हैं।

हमारा देश हमेशा से धर्मनिर्पेक्षता तथा उदारता को मानने वाला रहा है। हजारों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियां देश में आती रही हैं और मूल संस्कृति में शामिल होती रही हैं। भारत अनेक धर्मों, भाषाओं, रहने–सहने की प्रणालियों और रीति–रिवाजों का देश है। अपनी सद्भावना और सामंजस्य के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। धर्म, भाषा, जाति, प्रदेश, रीति–रिवाज, रहने–सहने की प्रणालियों आदि की मान्यताएं राष्ट्रीय निन्दा के ही अन्तर्गत हैं और राष्ट्रीय निष्ठा न तो विभिन्न मान्यताओं को कुचलती हैं और न ही ये मान्यताएं राष्ट्रीय निष्ठा में बाधक होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अन्ध, क्रूर, राष्ट्रीय प्रेम की तथाकथित निष्ठा

भारत के सर्वधर्म सम्भाव तथा उदारता के मूलभूत चरित्र को नष्ट भ्रष्ट करना चाहती है। कभी वन्दे मातरम्, कभी सरस्वती वन्दना जैसे मसलों तथा उपासना पद्धति के मामलों को उठाकर देश की एकता को खण्डित करने की चेष्टा हो रही है। भारत के नेतृत्व वाली सरकार से राष्ट्रीय निष्ठा और लोकतंत्र खतरे में पड़ा है। राष्ट्र की एकता, धर्म निरपेक्षता, सर्वधर्म सम्भाव तथा लोकतंत्र को बचाये रखने के लिए हर प्रकार तैयार रहना चाहिए।

समाजवादी पार्टी अनुसूचित जातियों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्याकों, महिलाओं के लिए विशेष अवसर के सिद्धान्त को मान्य करते हुए इनको विकास की दौड़ में शामिल होने लायक बनने तक उन्हें नौकरियों, व्यापार तथा राजनीति में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराती है। राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से यह वर्ग सदियों से उपेक्षाओं के कारण बहुत पिछड़े हैं, फिलहाल समान अवसर के उसूल, के बिना देश की आर्थिक, सामाजिक उन्नति में इनकी भागीदारी हो ही नहीं सकती। जब तक सभी वर्गों की तरक्की नहीं होती देश तरक्की नहीं कर सकता।

महिलाएं जो सदियों से उपेक्षित रही हैं, आज भी अपना सही हक नहीं पा रही हैं। उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पार्टी संसद तथा विधान सभाओं में महिलाओं के आरक्षण को एक सही कदम मानती है। लेकिन हमारा मानना है कि 33 प्रतिशत आरक्षण एक असन्तुलन पैदा करेगा। फिलहाल उनके लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उचित होगा और उसके साथ ही महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग, मुस्लिम, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी महिलाओं के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था समाज में समरसता और संतुलित विकास के लिए आवश्यक है।

फिल्मों, रंगमंच, चित्रकला से जुड़े कलाकारों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। खास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को वहाँ के उद्योग, व्यापार भाग रहे हैं। दूसरे राज्यों से रोजी, रोटी कमाने गये लोग आतंकित किये जा रहे है। श्री कृष्ण आयोग ने अपनी रपट में साफ–साफ शिवसेना को दोषी ठहराया है। लेकिन सरकार बेशर्मी से उसे ठुकरा चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट और हाकी टीमों के दौरों को निशाना बनाकर पूरे देश में एक नया साम्प्रदायिक

तनाव पैदा किया जा रहा है किन्तु सरकार के घड़ियालू आँसू उसकी साजिश में शामिल होने के सबूत हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर साम्प्रदायिक उपद्रव किये गये तो कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा।

केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी संगठन देश की खेल, कला, व सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी शर्मनाक हमले कर रहे हैं। आर्ट गैलरी में तोड़–फोड़, किसी फिल्म के प्रदर्शन के विरोध में सिनेमा घरों को जलाना, श्री दिलीप कुमार जैसे प्रतिष्ठित कलाकर के घर पर हमला करने तक ही सीमित नहीं है। बकायदा घोषणा करके वीडियो फोटोग्राफरों की उपस्थित में दिल्ली स्थित स्टेडियम में क्रिकेट पिच खोद दी गयी और सरकार ने कार्यवाही के नाम पर क्रिकेट मैंच को दिल्ली के स्थान पर चेन्नई कराने का फैसला कर दिया। इसी तरह की आराजकता के चलते क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर पर हमला करके विध्वंस किया गया। राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक ट्राफियों को नष्ट कर दिया गया और सरकार ने अपने सहयोगियों की हरकतों के सामने आत्म समर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अपना कार्यालय भाजपा शासित प्रान्त से हटाकर कलकत्ता ले जाना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें भाजपा का समर्थन व संरक्षण प्राप्त है, जो यह अत्यंत खतरनाक बात है। मामला उस समय और भी गम्भीर तथा साफ हो जाता है जब भाजपा नेता कहते हैं कि कला, खेल व सांस्कृतिक मूल्यों पर चोट करने वाले ऐसे संगठनों से भाजपा अपने सम्बन्ध नहीं तोड़ेगी।

गुजरात की कहानी पूरे देश में उजागर हो चुकी है। वहाँ भाजपा सरकार की साम्प्रदायिकता का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि ठीक 25 दिसम्बर के पवित्र दिन को चर्चों पर हमले किये गये। लूट, हत्यायें, आतंक, अत्याचार और साम्प्रदायिकता का एक साथ नजारा भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में है। "सरस्वती वंदना और वंदे मातरम्" का मुद्दा उठाकर तनाव फैलाने की कोशिशों को समाजवादी पार्टी ने विफल कर दिया।

विदेशी ताकते इस देश को बंटा हुआ देखना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी के प्रयास से देश की दो बड़ी ताकतें हिन्दुओ और मुसलमाओं के बीच निकटता बढ़ी है, खास तौर से पिछड़ी और कमजोर ताकतों के साथ, इस ताकत के सहारे विदेशी प्रभावों और खासतौर से अंग्रेजी और अंग्रेजियत के

खिलाफ मुहिम चलायी जाय। यह एकता 1857 की तरह मजबूत होगी। जिस समय दोनों ताकतों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी।

राष्ट्रीय दलों से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। केवल एक चुनाव जीतने और जैसे–तैसे सरकार बनाने की दौड़ है। लोकतंत्र में जनता जिसको अवसर देती है उसे शासन चलाने का अधिकार है। लेकिन अगर हिटलर की तरह सत्ता को हथियाकर उसका इस्तेमाल देश के संविधान, देश की एकता और साम्प्रदायकि सौहार्द को नष्ट करने के लिए किया जाय तो संघर्ष के अलावा क्या रास्ता है? यदि भाजपा और कांग्रेस मिलकर इस देश के किसानों, मजदूरों और उद्योगों को विदेशी कम्पनियों के हाथों बेचना चाहेंगी तो देश के नौजवानों, किसानों और छात्रों को खड़ा करके मुकाबला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह लड़ाई लम्बी है इसकी रणनीति बनाने और उसको कार्यान्वित करने के लिए जिस संकल्प शंक्ति की जरूरत है उस शक्ति को जगाने के लिए मैं आप सब का आह्वान करता हूँ।[7]

राजनैतिक प्रस्ताव –

समाजवादी पार्टी के चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन में जो राजनैतिक प्रस्ताव पास किया गया। वह इस प्रकार है–

समाजवादी पार्टी के हम सभी साथी विगत अप्रैल महीने में मुम्बई में मिले थें। तब तक केन्द्र में 26 प्रतिशत से भी कम वोट पाने वाली भाजपा नें राजनैतिक तिकड़म, जोड़–तोड़ व धनबल से कतिपय पिछलग्गुओं की मद्द से केन्द्र में अपनी सरकार बना ली थी। सपा ने देश की जनता को तभी भाजपा की संकीर्ण मानसिकता से आगाह किया था। हमें विश्वास था कि भाजपा और उसके पिछलग्गुओं की जमात का तथाकथित राष्ट्रीय एजेण्डा एक धोखा है। भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का नारा एक राष्ट्रीय छल है। विगत 11 महीने के शासन में भारतीय समाज की विघटनकारी शक्तियाँ बलवान हुई हैं। देश साम्प्रदायिकता के घोर दलदल में फंस गया है। केन्द्र सरकार के आर्शीवाद और गृहमंत्रालय की साठ–गांठ से अल्पसंख्यक समुदाय पर बर्बर

7. सपा के "चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन" भोपाल में 29 जनवरी 1999 को दिया गया अध्यक्षीय भाषण)

आक्रमण प्रारम्भ हो गये हैं। मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों पर घिनौने आकमण राजस्थान, महाराष्ट, गुजरात और कर्नाटक में हुए। इन आकमणों में संघ परिवार के संगठनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भाजपा अपनी पुरानी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के मुख से साम्प्रदायिक सौहार्द, बहुरंगी संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा का राग अलापती रही और अपने सहयोगी संस्थाओं को आकमण करने के लिये उकसाती रही। भाजपा शासित राज्यों के शिक्षामंत्री व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री वन्दे मातरम् को अनिवार्य करने; पाठ्य पुस्तकों को बदलकर उनमें साम्प्रदायिक रंग चढ़ाने, महाराष्ट में जिलों के नाम बदलकर अल्पसंख्यक वर्गों को चिढ़ाने, उत्तेजित करने और उनकी आस्थाओं पर हमले करते रहें और केन्द्रीय सरकार के जिम्मेदार मुखिया व कर्ता धर्ता इन कुकृत्य की सौहार्दपूर्ण आलोचना कर अपने कर्त्वय की इतिश्री करते रहे। भाजपा के इस दोगली, दोमुंही राजनीति का सिलसिला बाबरी मस्जिद शहादत से प्रारम्भ होकर चिकमंगलूर के धर्मस्थल के कब्जे की नापाक कोशिश करते हुए इसाई समुदाय के ऊपर संगठित हमले तक पहुँचा है।

भाजपा के लचर, दब्बू विघटनकारी आंतरिक नीति के कारण सम्पूर्ण देश आराजकता के महासागर में डूब गया है। भारत के सम्पूर्ण पर्वोत्तर राज्य उग्रवाद की ज्वाला से झुलस रहे हैं। अलगाववादी ताकतों का पूर्वोत्तर भारत केन्द्र स्थल बन गया है। जम्मू और काश्मीर में सीमा पार से प्रोत्साहित उग्रवाद, अलगाववाद मानों वहां रच बस गया है। पश्चिमोत्तर, पर्वोत्तर राज्य केन्द्र सरकार की लचर मानसिकता के कारण भारत के मुख्य समाज से अलग थलग होने की स्थिति में हैं। देश के मध्य भाग में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों पर होने वाले संगठित आकमण ने इन क्षेत्रों की जनता में भय और आतंक का वातावरण तैयार किया है । इसलिये सपा की राय में इन क्षेत्रों में पनपने वाले उग्रवाद का निस्तारण भाजपा की संकीर्ण मानसिकता के कारण संभव नहीं है।भाजपा शासित राज्यों में विगड़ते साम्प्रदायिक सौहार्द ने अलगाववादी शक्तियों को ताकतवर बनाया है।देश के महानगरों में कानून व्यवस्था ने एक गम्भीर मोड़ ले लिया है। भारत की राजधानी दिल्ली व भारत की आर्थिक नगरी मुम्बई सीमा पार अन्तर्राष्टीय माफिया गिरोहों के चंगुल में हो गयो है।

भाजपा की संकीर्ण मानसिकता वाली सरकार अन्तर्राष्ट्रीय माफिया गिरोह के समक्ष नतमस्तक है और उसके नेता तो उक्त गतिविधियों को नेस्तानाबूत करने के बजाय उसका भी राजनैतिक इस्तेमाल अपने राजनैतिक विरोधियों के दमन के लिये कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का यह सम्मेलन केन्द्र की नपुंसक घरेलू नीति की तीव्र स्वर से भर्त्सना करता है।

भारत के प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री अर्न्तराष्टीय पूँजी निवेशों के सम्मेलन में बीमा क्षेत्र में विदेशी पूँजी विनिवेश के लिए दरवाजा खोल देने की महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं जबकि संसद का शीतकालीन अधिवेशन चल रहा था। प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री देश के धन्ना सेठों को अपने घर में बुलाकर देश की आर्थिक नीति के बारे में दिशा निर्देश लेते हैं।भारत के आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून के 1981 के विषेश उपबन्धो को समाप्त कर भारत की सरकार मुनाफाखोरों और जवा खोरो को जनता की खुली लूट के लिए प्रोत्साहित करती है जिसके करण निर्भिक भाव से समाज के लुटेरों ने आम जनता को बर्बरतापूर्वक लूटा। सपा का यह राष्ट्रीय सम्मेलन अर्न्तराष्ट्रीय पूँजीवाद के भण्डारवाद व देशी धन्ना सेठों की वफादार भाजपाई सरकार से जंग करने के लिये देश की जनता से एकजुट होने का आह्वान करता है।

समाजवादी पार्टी की राय है कि देश का लोकतंत्र सर्वाधिक संकट के दौर में प्रवेश कर गया है। बिहार के मामले में केन्द्रीय सरकार जनतांत्रिक मूल्यों को तहस–नहस करने के लिए तुली हुई है। बिहार की जनता द्वारा चुनी गयी और विधान सभा का पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार को बर्खास्त करने के लिये जिन हथकण्डों को अपना रही है। उससे लोकतन्त्र की मर्यादा खत्म हो रही है। बेशरमाई की हद तो यह है कि यह महामहिम राष्ट्रपति तथा अभी हाल में हुए बिहार के उप चुनावों से जनता के फैसलों के बाद भी केन्द्रीय सरकार के मंत्रीगण बिहार सरकार को भंग करने के बयान दे रहे हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र, में हुए दंगों पर श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट को भाजपा, शिवसेना सरकार द्वारा पूरी तरह अस्वीकार करके रिपोर्ट के खिलाफ जिस तरह मुसलमानों पर आरोप लगायें है और जस्टिस श्रीकृष्ण पर मुसलमान समर्थक होने का आरोप लगाया है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये घातक

है। श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के रुख ने भविष्य में गठित होने वाले न्यायायिक जांच आयोगों की विश्सनीयता को समाप्त कर दिया है और यह भाजपा की लोकतंत्र विरोधी फासिस्टवादी मानसिकता का ज्वलन्त उदाहरण है।

भारत में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिनका अपनी सरकार और पिछलग्गू दलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जिसके कारण देश का सम्मान दुनियां में घटा है। विश्व के विकासशील राष्ट्रों ने भी भारत से मुंह मोड़ लिया है और पड़ौसी देशों के साथ कटुतापूर्ण संबंध बने हैं। विश्व में आणविक शक्ति बनने और भारत के अन्दर राष्ट्रीयता का उन्माद पैदा कर अपने सियासी विरोधियों को समाप्त करने की दूषित मानसिकता के कारण मई में पोखरण में दो विस्फोट किया गया। विपक्षी दलों को विश्वास में लिये बिना और विश्व स्तर पर अपने परम्परागत मित्र देशों को विश्वास में लिये बिना जिस बचकाने ढंग से भारत सरकार ने इतने बड़े संवेदनशील प्रकरण को हल करने की कोशिश की, उससे भारत विश्व स्तर पर अलग थलग पड़ गया। भारत पर जबर्दस्त आर्थिक दबाव बढे, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की पहल करने का जिन देशों का वचन था वे अपने वचन से पीछे हटे। अपनी नाक बचाने के लिए अमेरिकी विदेश उपमंत्री के पीछे–पीछे भारत के नुमाइन्दा पूरी दुनियां में घूमते रहे और अंततः विश्व पंचायत में भारत के प्रधानमंत्री को देश को विश्वास में लिए बिना सी0 टी0 बी0 टी0 जैसी संधि पर हस्ताक्षर करने का वचन देना पड़ा। समाजवादी पार्टी ऐसी किसी भी अर्न्तराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने के विरूद्ध है जिसका सीधा असर भारत की दूरगामी सुरक्षा पर पड़ता है। सपा का यह सम्मेलन भारत सरकार को कड़ी चेतावनी देना चाहता है कि अपनी लचर और दब्बू नीति के कारण भारत को स्थायी रूप से सुरक्षात्मक मामलों में विश्व की ताकतवर जमातों के हवाले न कर दें,

भारत की वर्तमान कमजोर सरकार के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है। संविधानेत्तर संगठनों ने भारत सरकार पर अपना दबदबा कायम करने का प्रयास बढ़ाये हैं। भाजपा ने येन केन प्रकारेण अपनी गद्दी बचाए रखने के

लिये राजनैतिक भ्रष्ट्राचारियों से सन्धि स्थापित किये है अपने राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे उछालकर उन्हें अपमानित और राजनैतिक रूप से कमजोर करने के षड़यन्त्र किये गये और दूसरी तरफ अपने सहयोगियों को भ्रष्टाचार करने के लिये अभयदान दिया गया। लोकपाल विधेयक व सर्तकता आयोग विधेयकों का प्रचार तो बहुत किया गया लेकिन उसे अधिनियम का रूप देने की कोई पहल नहीं की गयी। भ्रष्ट और बदनाम सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ जांच करने वाले जांच अधिकारियों को राज सत्ता के बल पर अपने पदों से हटाया गया अथवा स्थानान्तरित किया गया, जिसके चलते योग्य, निष्पक्ष, ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिरा और भ्रष्टाचारी उत्साहित हुए। भाजपा की सोची समझी रणनीति के तहत संसद की सर्वोच्चता को चुनौती मिलने लगी। भाजपा की स्पष्ट राय संसदीय प्रणाली को समाप्त कर राष्ट्रपति प्रणाली लाने की है क्योकि संसदीय प्रणाली में विगत 50 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद समाज की दबी पिछड़ी जातियों ने भी अपने ताकत की बदौलत राज सत्ता में अपना थोड़ा हिस्सा प्राप्त किया है। राष्ट्रपति प्रणाली समाज के कमजोर वर्गो के राज सत्ता में हिस्सेदारी का निषेध है। भारत की न्यायपालिका अपनी सक्रियता के बहाने जिस भद्दे ढंग से भारत के संसद की सर्वोच्चता को चुनौती देती रहती है, उससे सपा की आशंका सच साबित होती है। भारतीय न्यायपालिका अपनी सीमाओं का नये ढंग से अतिक्रमण कर रही है। जन नेताओं को बदनाम करना संवैधानिक धाराओं को अपनी रुचि के अनुसार भाष्य करना, राजनैतिक मामलों में पसंदीदा फैसला मानों न्यायपालिका का दैनिक कार्य हो गया है। उत्तर प्रदेश में दल--बदल जैसे घिनौने कृत्य का कोई फैसला न देना, मुलायम सिंह यादव सरकार की मनमानी बर्खास्तगी पर चार वर्षों बाद भी संवैधानिक बैंच न बैठाना, लालू प्रसाद की जमानत की दरख्वास्त पर महीनों कोई निर्णय न देना, इसके ज्वलन्त उदाहरण है। लोकतंत्र में जनता सभी का मूल्यांकन करती है, न्यायपालिका का भी, जजों का भी।

सपा की स्पष्ट राय है कि भारत की संघर्षशील बहादुर जनता भाजपा की गैर जबाबदेह, अक्षम सरकार से छुटकारा हेतु कृत संकल्प है। अभी हाल में तीन राज्यों के चुनाव परिणाम जनता के अभिमत के स्पष्ट संकेत है। भारत सरकार

इस जनादेश को राज्य सरकारों के खिलाफ अभिमत मानकर जनमानस को झुठलाना चाहती है। किन्तु अन्दर से आशंकित भी है, लेकिन हिन्दुत्व एजेंण्डा ही भाजपा का एकसूत्रीय एजेण्डा है। इसलिये सपा देश के वृहत्तर हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की सुरक्षा और अखण्डता के लिये केन्द्र सरकार की लंगड़ी सरकार को तुरन्त अपदस्थ करने के लिये संकल्पबद्ध है। तीन राज्यों की जनता ने इस राय को और मजबूती दी है। किन्तु इन राज्यों के नकारात्मक वोट प्राप्त करने के बाद की कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, भाई, भतीजावाद, दामों की लूट बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी ने उसे अपने पक्ष में अभिमत मानकर चुनाव की उन उपलब्धियों पर पानी डाल दिया।सपा के बार बार आश्वासनों के बावजूद काँग्रेस पार्टी ने केन्द्रीय भाजपा और उसके पिछलग्गुओं की सरकार को हटाने में कोई पहल नहीं की अपितु विगत संसद के सत्र में सरकार चलाने मे भरपूर सकारात्मक भूमिका निभायी। बीमा विधेयक और पेटेन्ट विधेयक, जो भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी आर्थिक गुलामी के प्रतीक हैं, उन्हें पास कराने में अग्रिम भूमिका निभायी। पेटेंट विधेयक पर तो राज्यसभा में उनके पक्ष में मतदान किया और बदले में उनसे जोड़ तोड़ करके लोकसभा उपाध्यक्ष का पद हथिया लिया । राजस्थान, दिल्ली मध्य प्रदेश, में सरकार बनाने से पगलाई काँग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा से मिलकर विभिन्न राज्यों में अपने दल के राज्यपालों की नौकरी बचा रही है, केवल बोफोर्स केस के बहुप्रचारित रक्षा सौदा घूस काण्ड का पर्दा न उठ सके, इसलिये तमाम घोटालों के जाल में फंसी काँग्रेस पार्टी भाजपा से निर्णायक और महत्वपूर्ण संघर्ष करने से भाग रही है, समाजवादी पार्टी राष्ट्र के समक्ष आयी चुनैती का मुकाबला करने के लिये कटिबद्ध है।

विदेशी ताकतों की साजिश इस देश को बाँटने की है। संघ, भाजपा एवं विश्व हिन्दू परिषद की कुत्सित मानसिकता के बावजूद सपा के प्रयास से देश की दो बड़ी ताकतों हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच गहरी निकटता बढ़ी है। अल्पसंख्यकों, दलितों एवं पिछड़ों की मदद से विदेशी प्रभावों और खास तौर से अंग्रेजी और अंग्रेजियत के खिलाफ देश भर में मुहिम चलाने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी की राय है कि भाषा, जाति और आर्थिक गुलामी के सवालों पर भाजपा और कांग्रेस का वर्ग चरित्र एक है। यह दोनों

दल विदेशी भाषा की गुलामी, परम्परागत वर्णीय समाज व्यवस्था के पोषक और अर्न्तराष्ट्रीय व देशी पूंजीवाद के गुलाम है। सपा भारतीय भाषाओं के पक्ष में जाति विनाश के लिये आर्थिक दासता के खिलाफ ऐतिहासिक संग्राम के लिये अपनी वचन बद्धता दुहराती है। इसे पूरा करने के लिये राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक मोर्चा का गठन एक लघु प्रयास है। सपा का यह राष्ट्रीय सम्मेलन सहमना वैचारिक शक्तियों से आग्रह करना चाहता है कि सपा के इस निर्णायक समाज और देश बनाओं आन्दोलन में सहयोगी बनें और इसके लिये यह सम्मेलन देश के राजनैतिक क्षितिज पर एक तीसरी शक्ति के गठन को कांग्रेस और भाजपा, देशी विदेशी पूंजीवाद, असमानता पोषक व्यवस्था तथा अलगाववाद और लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ जिहाद बोलकर देश के सामने एक सक्षम विकल्प रख सके । लेकिन सम्मेलन तीसरी शक्ति के पक्षधरों, विशेषकर वामपंथी दलों से कहना चाहता है कि इसके गठन में व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी पसन्द नापसन्द को मुद्दा न बनायें।[8]

6.पॉंचवां राष्ट्रीय सम्मेलन

अध्यक्षीय भाषण –

सपा के पांचवां राष्ट्रीय सम्मेलन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमुलायम सिंह यादव जी ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि– आप जानते हैं कि कानपुर एक ऐतिहासिक शहर है। हलांकि कानपुर को एक बड़े शहर के रूप में दो सौ साल पहले अंग्रेजो ने ही बसाया था लेकिन 1857 में आजादी के पहले संग्राम के दौरान अंग्रेजों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अंग्रेजो ने अपने लोगों की हत्या का जबरदस्त बदला लिया था। बिठूर का, जो हमारे धार्मिक, आध्यात्मिक केन्द्र के साथ–साथ नाना साहब पेशवा की कर्मभूमि थी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व, मध्य और बुन्देल खंड को जोड़ने वाला यह शहर हमारी आर्थिक और राजनैतिक समृद्धि का केन्द्र रहा है। शिक्षा, साहित्य,उद्योग और पत्रकारिता का बड़ा केन्द्र रहा है और आज भी है। हमारे श्रमिक आन्दोलन के

---

8 - सपा के 'चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन' भोपाल में31 जनवरी 1999 को पारित राजनैतिक प्रस्ताव

इतिहास में कानपुर का नाम पूरे देश में चर्चित रहा है। महान बलिदानी गणेश शंकर विद्यार्थी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन,कामरेड राम आसरे,आयोध्या नाथ के साथ सैकड़ों महान लोगों ने हर क्षेत्र में योगदान किया है। जहाँ तक कानपुर समाजवादी आन्दोलन का भी बड़ा केन्द्र रहा है कानपुर में 1946 में काँग्रेस समाजवादी पार्टी को लेकर आचार्य नरेन्द्र देव काँग्रेस से अलग हुए थे वहीं से भारतीय राजनीति में समाजवादी आन्दोलन की धारा अलग से प्रवाहित हुई थी। आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण की प्रेरणा और विरासत से ही समाजवादी पार्टी बढ़ी है और आज भी निरन्तर संघर्ष कर रही है। ऐसे ऐतिहासिक नगर में आप सभी साथियों का स्वागत और अभिनन्दन है।

आजादी के बाद का सबसे खतरनाक दौर–

देश आजकल कितने गम्भीर संकटों से गुजर रहा है। यह खतरा राजनितिक, आर्थिक और सामाजिक भी है। देश की सीमायें सुरक्षित नहीं हैं और देश में आन्तरिक विद्रोह जैसी स्थितियां बन गयी हैं। उग्रवादी, आतंकवादी और साम्प्रदायिक ताकतें लगातार मजबूत और हिंसक हो गयी हैं। अपराधी और भ्रष्टाचारी लोग राजनीति तथा खासकर सत्ताधारी दलों में घुसकर उन पर कब्जा कर रहे हैं और यह सबसे बड़ी चिन्ता तथा खतरे की बात हो गयी है कि भारत में लोकतन्त्र बचेगा या नहीं? एक देश के रूप में क्या हमारी पहचान खत्म हो जायेगी? सबसे ताजा उदाहरण संसद पर हुआ हमला है। आतंकवादी संसद के अन्दर घुस जाते तो उनका निशाना देश की राजनीतिक नेतृत्व था। सभी नेताओं और संसद के सदस्यों को एक साथ समाप्त करना चाहते थे। हमारे 9 बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने तेरह दिसम्बर को अपनी कुर्बानी देकर देश को बचा लिया था। उनकी बहादुरी और देशभक्ति की जितनी तारीफ की जाये वह कम है । लेकिन असली सवाल यह है कि यहां तक नौबत कैसे पहुँची। यह पहली घटना नहीं है। आतंकवाद के हमलों का पूरा इतिहास है। बीस साल में आतंकवादियों के हमलों में एक लाख से ज्यादा लोग मारे गये हैं। केवल पिछले तीन साल में मारे गये लोगों की संख्या बीस हजार से ज्यादा हैं।इसके लिये जिम्मेदार कौन है? तीन साल से

इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चल रही है।इस सरकार ने देश को राजनीतिक और आर्थिक गुलामी के कगार पर पहुँचा दिया है।

इस सरकार ने पिछले तीन सालों में चुनावों में जीत के लिये देश की सुरक्षा और आजदी को भी दाँव पर लगा दिया है। यह आरोप नहीं है इसके पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं। सारी दुनियाँ को पता था कि भारत के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है। इन्दिरा गाँधी ने इसे 1974 में दिखा दिया था। उसके बाद परमाणु बम का परीक्षण शक्ति वाला देश बनवा दिया। आज सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर भारत –पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा तो ऐटमी हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। सबसे पहले मैने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आंतकवादियों को तैयार करने वाले जो प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया जाये। आज तो वे केन्द्र भी शायद पाक अधिकृत कश्मीर से हटा दिये गये हैं। अब युद्ध के लिये भारत को बहुत सोच– समझकर कदम उठाना पड़ेगा दूसरी घटना कारगिल पर आक्रमण को लेकर हुई। कारगिल का युद्ध इस सरकार की असावधानी और गलत नीतियों के कारण हुआ था। उसको जीतने के लिये हमारी बहादुर सेनाओं ने कितना बड़ा बलिदान दिया था यह इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। सभी राजनीतिक मतभेद भुलाकर पूरा देश सेनाओं के पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया था लेकिन पाकिस्तानी सैनिक घुसकर हमारी चौकियों पर कब्जा करते रहे और हमें पता ही नहीं चला, इसके लिये केन्द्रीय सरकार के अलावा कौंन जिम्मेदार है? कारगिल के मामले पर इसी सरकार ने जो जांच कमेटी गठित की थी उसकी रपट आ गयी है लेकिन सरकार उस पर बहस नहीं कराना चाहती है। कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ का पता इस सरकार को था या नही। इसने सूचनाओं को देश से क्यों छुपाया। आज भी जांच रपट पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों हो रही है, इन सवालों पर जवाब देने के बजाय 1999 के लोकसभा चुनाव में इस प्रकार सरकार ने कारगिल युद्ध को को भी भुनाया था शहीद सैंनिको के खून का तिलक अपने माथे पर लगाकर भाजपा ने बहुमत जुटाने की कोशिश की

थी लेकिन देश की जनता ने उसे नकार दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो उसी चुनाव में भाजपा को ठुकरा दिया था।

1998 में जब अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार लोकसभा में हार गयी थी उस समय अगर कांग्रेस ने देशहित में उदार सहयोग का रूख अपनाया होता तो यह सरकार दुबारा सत्ता में नहीं आ सकती थी लेकिन यह नहीं हो सका। पिछले दो साल में यह सरकार देश के लिये खतरा बन गयी है। पाकिस्तान के फौजी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ कारगिल युद्ध के लिये जिम्मेदार थे। उनको बातचीत के लिये बुलाने की क्या जरूरत थी। उससे क्या निकला? वे हमारी सीमाओं पर हमले करते रहे और भारत सरकार ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित करके सुरक्षा बलों के हाथ बांध दिये थे। उसी का नतीजा आज देश भोग रहा है। यह देश की जरूरत नहीं थी। यह अमेरिका का दबाव था। आज प्रधानमंत्री आँसू बहा रहे है कि युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। याद कीजिए जब नेपाल से हवाई जहाज का अपहरण हुआ था और कंधार में समझौता हुआ था । जैश–ए–मोहम्मद जिस पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग हो रही है। उसका संस्थापक अजहर मसूद जम्मू की जेल में बन्द था। उसे निकाल कर विदेश मंत्री जसवंत सिंह शाही ठाटबाट से अपने हवाई जहाज से कंधार पहुँचाने गये थे। अब गृहमंत्री कह रहे हैं कि यह एक भारी भूल थी। अगर सरकार खुद अपनी गलती मंजूर करती है तो इसकों बने रहने का क्या अधिकार है? इस सरकार के रहते देश और लोकतन्त्र की सुरक्षा नहीं हो सकती है।

जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है। डॉ० फारूख अब्दुल्ला उसके मुख्यमंत्री है । उनकी उपेक्षा करके सरकार आंतकवादी संगठनों से बातचीत क्यों चलाती है। उनको रिहा करती है योजना आयोग के उपाध्यक्ष कृष्ण चन्द्र पन्त को बातचीत के के लिये भेजती है और फिर पाकिस्तान से बातचीत करने लगती है क्यो? इसके पीछे अमेरिका दबाव है। यह एक खतरनाक संकेत है कि भारत की राजनीति और अर्थनीति पर अमेरिका का शिकंजा कसता जा रहा है। एक नई गुलामी का आरम्भ हो चुका है हमारी स्वायत्तता और प्रभुसत्ता पर हमला अमेरिका ने किया है। दूसरा हमला पाकिस्तान की सह पर

आतंकवादियों ने किया है। पिछले साल ग्यारह सितम्बर को अमेरिका पर आतंकवादियों का हमला हुआ । हमने हर मदद देने की कोशिश की, लेकिन जब 20 दिन बाद श्रीनगर में जम्मू काश्मीर विधान भवन पर आतंकवादियों ने जबरदस्त विस्फोट करके हमला किया, पचास से ज्यादा लोग मारे गये तो अमेरिका ने हमारी क्या मदद की? अभी संसद में हमला हुआ तो अमेरिका की यही कोशिश है कि वह पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू मे तौले। यह स्थित देश को मंजूर नहीं है और हमें पूरे देश को अमेरिका तथा बहराष्ट्रीय कम्पनियों की उन कोशिशों के खिलाफ जागरुक करना पड़ेगा अन्यथा हमारी आजादी फिर खतरे में पड़ जायेगी।

केन्द्रीय सरकार भ्रष्टाचार, घोटाला और देश की सम्पत्ति को नीलाम करने वाली सरकार साबित हुई। अखबारों और टी0वी चैनलों में आपने लगातार देखा है। यूनिट ट्रस्ट 64 काण्ड, तहलका काण्ड और ताबूत घोटाला काण्ड है। सरकार से हमने रक्षामंत्री जार्ज फर्नाडीज को हटाने की मांग नहीं की थी लेकिन जब यह घोषणा की गयी कि जांच कमेटी से पाक साफ साबित होने के बाद ही वह मंत्री बनेगे तो इतनी जल्दी क्या थी ? कैग की रपट से ताबूत खरीदने का जो हवाला है वह बेहद शर्मनाक हैं। अनेक घोटाले अभी सुर्खियों में नहीं आये हैं। सरकार ने इस वर्ष 2002 तक देश की सत्ताइस सरकारी कम्पनियों को नीलाम करके 52 हजार करोड़ रूपया उगाहने का फैसला किया है। इसके अलावा इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया जैसी प्रतिष्ठित और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कम्पनियों को भी बेचने की तैयारी है। दो करोड़ कर्मचारियों को बेरोजगार करने की साजिश शुरू हो गयी है। इन कम्पनियों को विदेशियों के हाथों बेचा जा रहा और उनमें जबरदस्त घोटाला है। माडर्न फूड्स, हिन्दुस्तान लीवर और एल्यूमिनियम बनाने वाली कम्पनी बाल्को को स्टार लाइट कम्पनी को बेचा गया है। अगर इन दोनों उद्योगों की बिकी की जांच कराई जाय तो देश के सामने सच्चाई आ जायेगी। दूसरा बड़ा गम्भीर मामला एक्सप्रेस हाई–वे बनाने का है। सारे ठेके विदेशी कम्पनियों को दिये जा रहे है। जो सड़क भारत के सबसे मशहूर ठेकेदार पांच करोड़ रूपया प्रति किलोमीटर की दर पर बनाने को तैयार हैं।

उसे मलेशिया की कम्पनी को 30 करोड़ की दर में दिया जा रहा है । ऐसे सैकड़ों मामले है जिनके लिये सरकार अपराधी है।

विश्व क्षितिज पर अब अमेरिका अकेला राजनीतिक खिलाड़ी बचा है, सोवियत संघ के विघटन के बाद सारा मैदान उसके हाथ में है। हमेशा अमेरिकी प्रयास रहा है कि भारत एक स्वावलम्बी और तटस्थ राष्ट्र के रुप में खड़ा न हो सके, उसके विदेश नीति का झुकाव सदैव पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। भारतीय सरकार ने अपने खराब दिनों के दोस्तों को नमस्कार कर लिया है। सबसे आत्मघाती कदम तो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की समाप्ति थी। विश्व के सभी घटनाकम पर भारत स्वतन्त्र, निरपेक्ष और निर्भीक राय रखने वाला देश माना जाता था। अब भारत भी अमेरिका के पिछलग्गू देशों की जमान के रूप में देखा जा रहा है। विश्व के विकासमान देश भारत से नेतृत्व की अपेक्षा रखते थे, वह अब समाप्त है। पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई0 एस0 आई0 के इशारे पर हमारा सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्य जम्मू कश्मीर आंतकवाद की साया में है और उस आई0 एस0 आई0 का ताना बाना तैयार करने मे अमेरिकी खुफिया तंत्र सी0 आई0 ए0 और एफ0 बी0 आई0 का आर्शीवाद है। आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा झारखण्ड, बिहार तथा सम्पूर्ण पर्वोत्तर उग्रवादियों की गिरफ्त में है। भारत सरकार की पूरी आन्तरिक सुरक्षा नीति विफल है। हमारे पड़ोसी वर्मा भूटान, नेपाल में उग्रवादियो को प्रशिक्षित करने के कैम्प हैं जो आई0 एस0 आई0 द्वारा संचालित हैं। इसे ध्वस्त करने की सार्मथ्य हमारी सरकार में नही हैं। अब तो हमारे पड़ोसी देशो पर भी उग्रवादी हिंसा ने कब्जा कर लिया है। भारत के पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक आंदोलन और तंत्र खड़ा करने में भारत की सदैव रूचि रही है और हमने राष्ट्रीय हित में न केवल उन आंदोलनों को प्रोत्साहित किया अपितु लोकतांत्रिक व्यवस्था को काफी सहारा दिया। इन पड़ोसी देशों में लोकतंत्र के विनाश से भारत की आन्तरिक शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। यह चिन्ता का विषय है कि भारत सरकार पड़ोसी देशों के लोकतांत्रिक शक्तियों से अपना रिश्ता तोड़कर सैनिक हुक्मरानों, संकीर्ण साम्प्रदायिक तत्वों और राजाओं से रिश्ते प्रगाढ़ करने में लगी है। इसका नतीजा न केवल पूर्वोत्तर राज्य अपितु बिहार और उत्तराँचल, उत्तर प्रदेश की लोकशान्ति खतरे में पड़ गयी है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के समृद्ध देशों ने व्यापारिक सुविधा के लिये गैट की स्थापना की था। भारत भी उसका संस्थापक देश थीं इसलिये विश्व को एक व्यापारिक छतरी में लाने के लिये गत शताब्दी के अन्तिम दशक में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गयी। दुनियाँ के व्यापार नियन्ता और एकमात्र खिलाड़ी 'यूरो' अमेरिकी समुदाय के लोग बन गये,उनके इशारे पर अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था का भूमण्डलीकरण करा दिया। काँग्रेसी नेताओं ने नई व्यवस्था का ढोल खूब पीटा, लेकिन उसी व्यवस्था को जिसकी तब भाजपाईयों ने कड़ी निन्दा की थी, सरकार आने के बाद उसकी धारावाहिकता की गति को और तीव्र कर दिया । 13 दिन के लिये दिल्ली में वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1996 में एक सरकार बनी। अपना बहुमत सिद्ध करने के पूर्व ही अमेरिका की बिजली बनाने वाली एक बड़ी कम्पनी एनरॉन को महाराष्ट्र के दाभोल में विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की काउन्टर गारन्टी दे दी, जबकि वहाँ के काँग्रेस मुख्यमंत्री शरद पवार ने जब इस कम्पनी को न्योता भेजा तो भाजपाईयों ने उसका तीव्र विरोध किया था। एनरॉन को काउन्टर गारन्टी भाजपा ने केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को संकेत देने के लिये किया था कि हम सत्ता में आये तो आपकी सेवा में काँग्रेस से आगे बढ़कर हाजिर रहेंगे। फिर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपना आर्शीवाद भाजपा को भी दे दिया। आज उस कम्पनी क्या हाल है? न केवल विश्व के लाखों लोगों का पैसा खाकर वह कम्पनी दिवालिया हो गयी, अपितु दाभोल की महंगी बिजली खरीद कर इस देश का सम्पन्न राज्य महाराष्ट्र भी तारे गिन रहा है उसकी आर्थिक हालत भी खस्ता हो गयी। अब एनरॉन पावर कम्पनी इस देश के बैंको और वित्तीय संस्थानो का 4 हजार करोड़ रुपये डूबा रही है।

भाजपा की सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के बहाने देश को समृद्ध देशों के हाथ बंधक बना दिया । बेरोकटोक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश ने देश की खेती, उद्योग, व्यापार सभी का विनाश कर दिया। खेती का उत्पादन लगातार घटाव की ओर है। देशी सभी कारखानों में ताले लग रहे हैं। भारत में तैयार होने वाले कपड़े के खिलाफ यूरोप–अमेरिका में एण्टी डम्पिंग कानून लगा है। इसका परिणाम है कि कपड़े के विश्व व्यापार में भारत की 4 प्रतिशत

हिस्सेदारी अब कम होती जा रही है। विदेशी खाद्यान्न अपनी खपत के 15 प्रतिशत आयात करती है, खाद्य तेल, चीनी चावल दाल ही नहीं दूध और अण्डा भी बाहर से मंगाया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने मांस की सबसे बड़ी खपत वाला देश भारत को घोषित कर दिया । धीरे–धीरे भारत की सभी रोजगारपरक धन्धों पर विदेशियों का कब्जा होने की तैयारी है जिससे भारत के हक में केवल कंगाली और लाचारी बचने वाली है। इसलिये भारत धीरे–धीरे विश्व के गरीब देशों की कोटि में आ रहा है।

भारत में खाद्यान्न के गोदाम भरे हैं। 10 लाख टन अनाज का भण्डार तो सड़ गया दूसरी तरफ देश के विभिन्न हिस्सों में उपज का लाभकारी मूल्य न मिलने से किसान आत्म हत्या को मजबूर है तो दूसरी तरफ उड़ीसा , मध्यप्रदेश, के विभिन्न हिस्सों में भूख से मौते हो रही है। दूर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि संवेदनशून्य प्रधानमंत्री ने भूख से होने वाली मौतो को अखबारनवीसों की गढ़ी कहानी कहकर झुठला दिया है। गरीबी की भयावह स्थिति का आंकलन इसी आशय से किया जा सकता है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में भूख और कुपोषण से एक वर्ष में 8हजार बच्चे मर गये, राजस्थान के 32 मे से 31 जिले अकाल की चपेट में हैं। नई आर्थिक नीति के सबसे बड़े झण्डावर्दार आन्ध्र के मुख्यमंत्री हैं। उनका दावा है कि सूचना क्रान्ति सबसे पहले उनके आंगन में आई, लेकिन वहाँ सैकड़ो बुनकर रोजी–रोटी के अभाव में आत्म हत्या किये। किसानों द्वारा आत्महत्याओं का सिलसिला सबसे पहले आन्ध्र में ही शुरू हुआ था। वहां के लाचार युवक और ग्रामीण हाथ में हथियार लेकर बगावत का शंख फूंक दिए हें, तो उनको नक्सली कहकर पकड़–पकड़ कर हत्यायें की जा रही हैं। संवेदनहीनता नई अर्थव्यवस्था का मूल तत्व है। "अमीर को और अधिक अमीर बनाओ–लाचार की कंगाली शीर्ष तक पहुँचाओ।"

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल यानी अपराधियों का जमघट

उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव के बाद दो बहनों– भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई । जब यह सरकार बनी तो बसपा की तुलना में भाजपा के विधायकों की संख्या तिगुनी थी लेकिन भाजपा ने सरकार का नेतृत्व बसपा को दे दिया। इसलिए वह किसी

भी कीमत पर सरकार बनाने के लिए आतुर थी । उसकी बस एक ही चाहत थी कि किसी तरह भी हो सरकार में आ जाओ। सो बसपा के नेतृत्व को स्वीकार कर सरकार बना ली । यह भाजपा ने इसके बावजूद किया कि बसपा,ने उसे पहले एक जबर्दस्त धोखा दिया था। धोखा देना इस पार्टी के घोषणा– पत्र का हिस्सा है भी परन्तु छह महीने सरकार चलाने और प्रदेश भर में जम कर लूटपाट मचाने और हरिजन एक्ट के नाम पर अत्याचार मचाने के बाद अपनी आदत के मुताबिक बसपा ने भाजपा को फिर डंक मार दिया। सर्मथन वापस ले लिया । लेकिन भाजपा को किसी भी कीमत पर सत्ता में रहना था सेा उसने कई विपक्षी दलों में भारी तोड़–फोड़ मचाई, विपक्षी दल तोड़ दिये गयें। टूटकर आने वाले सारे विधायकों केा मंत्री बना दिया। सत्ता के दुरुपयोग का ऐसा नाटक इससे पहले कभी इस प्रदेश में नही हुआ था। नजीता यह हुआ कि मंत्रिमंडल वास्तव में अपराधियों और भ्रष्ट लोगों का झुंड बन गया। जो अपराधी जेल से बाहर थे। उन सबके सरगना मंत्री बन गये यानी चोरों को कोतवाल बना दिया गया। जिनकी पुलिस को कल तलाश थी, उन्हें पुलिस को सलूट मारने को बाध्य होना पड़ गया।यह सब उस भाजपा की कृपा थी, जो अपने को देशभक्त, रामभक्त और साफ– सुथरी राजनीति का प्रवक्ता बताती थी। इन मंत्रियों के किस्से इतने है कि एक किताब इन पर लिख दी जाय।

मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले एक इन्टरब्यू में कहा है कि उनकी सरकार में अब कोई अपराधी या भ्रष्ट मंत्री नहीं है । मैं आपको तीन साल पहले के लिये चलता हूँ। भाजपा के एक बड़े नेता है– कुशाभाऊ ठाकरे इन्होने एक प्रेस कांफ्रेंस से खुलेआम स्वीकार किया कि प्रदेश सरकार में अपराधी छवि के लोग मंत्री हैं। कुछ समय पहले समजवादी पार्टी ने एक सांसद को इसलिये पार्टी से निकाल दिया कि उन पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप था। जब तक ये सांसद हमारे साथ थे तो यह आरोप लगता था कि उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में यही कुशाभाऊ ठाकरे बाकायदा उपस्थित हुए। अब वे सांसद अपराधी छवि के नहीं रहे अब वे भाजपा के छतरी के नीचे चले गये हैं।

कितने अपराधी सरकार में है। मुख्यमंत्री में और उनकी पार्टी में हिम्मत है और वे वाकई अपराधीकरण के खिलाफ है तो स्पेशल टास्क फोर्स की वह रिपोर्ट सार्वजानिक कर दें, जिसमें मंत्रियों और अपराधियों की साठ–गांठ का कच्चा चिट्ठा मौजूद है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। प्रदेश के लोकायुक्त पिछले साल 4 मई को लखनऊमें एक संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें बाकायदा कहा कि प्रदेश में कुशासन बढ़ रहा है लोकायुक्त संगठन को पर्याप्त ताकत नहीं दी जा रही है। जिसकी वजह से हम पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं यह हाल है उस भाजपा का जो सालों से लोकपाल विधेयक और लोकायुक्त की रिपोर्ट विधान सभा में इस बहाने से नहीं रखी गई कि उसका अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने वाला कोई नहीं है।

घोटाले और घपले–

यहाँ से लेकर दिल्ली तक की केन्द्रीय सरकार घोटालों और घपलों की सरकारें हैं। शेयर घोटाला, यूनिट ट्रस्ट घोटाला एवं कस्टम घोटाला तथा न जाने कितने घोटाले इस सरकार में हो चुके हैं। कुछ समय पहले खबर छपी थी कि वृद्धावस्था पेंशन की रकम बड़े पैमाने पर हड़प ली गयी। कोई एक लाख ऐसे लोगों को पेंशन बाँट दी गयी जो अब इस दुनिया में है ही नहीं । बुढे लोगों को पेशन देने की योजना हमारी सरकार ने प्रारम्भ की थी। लेकिन अब इसके नाम पर घोटाले हो रहें हैं। गरीब बच्चों को वजीफा देने की योजना भी भ्रष्टाचार में डूबी दी गयी।

मै पिछले पांच साल में हुए कुछ घोटालों का जिक्र करना चाहता हूँ।सबसे पहला है अम्बेडकर पार्क घोटाला भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस घोटाले का पूरा पदाफार्श कर दिया गया। बाताया यह गया कि करीब 100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। उस पर कोई कार्यवाही करना तो दूर रहा भाजपा के एक असरदार मंत्री ने अभी हाल में इस घोटाले से सबको बरी करने का ऐलान कर दिया। इस सरकार के लिये अब सी0 ए0 जी0 की रिपोर्ट के भी कोई मायने नहीं रह गये हैं एक और घोटाला है फ्लोटपम्प घोटाला।जाँच सी0 बी0 आई0 ने किया और पूरा मामला

पकड़ लिया लेकिन मामले को दबा दिया गया क्योकि जिन दो पार्टियों की मिलीभगत से यह घोटाला हुआ था, उन्हे आगे फिर गठबन्धन करना पड़ सकता है और भाजपा अपने इस पूराने और भविष्य के सहयोगी को नाराज नही करना चाहती। एक और है सहकारिता घोटाला। 1200 करोड़ रुपये का यह घोटाला भी सरकारी फाइलों में दबा पड़ा है। जब उसके उजागर होने का खतरा सामने आया तो भाजपा सरकार ने हमारी पार्टी के उन तमाम नेताओं को सहकारी समितियों से बेदखल कर दिया जो इसकी जड़ में पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक है पिकप घोटाला और दूसरा है मण्डी घोटाला।सारे घोटाले इसी भाजपा व उसके सहयोगियों की देन है और भ्रष्टाचार की बड़ी–बड़ी बातें करने वाली भाजपा ने उन्हें दफनाकर रख दिया है।

यह है उस पार्टी की सरकार के मंत्रियों की थोड़ी सी सत्यकथाएं, जो अपने को देशभक्त, रामभक्त, ईमानदार तो कभी साफ–सुथरा बताते हुए नहीं थकते।

मंत्रियों की राजसी ठाटबाट–

भाजपा सरकार के मंत्री पूरी तरह स्वयं सेवक है स्वयं सेवक मायने जो सिर्फ अपनी सेवा करना जाने। इनके मंत्रियों ने खुद अपनी सेवा करने में सारे रिकार्ड तोड़ दिये। आज से लगभग 15 साल पहले प्रदेश के मंत्रियों का कुछ खर्च लगभग 70–75 लाख सालाना होता था। 1994–95 में यह खर्च बढ़कर एक करोड़ हुआ। आज के मंत्रियों की फौज पर ढ़ाई करोड़ रुपया हर महीने यह बात केवल उनकी है, जो बाकायदा मंत्री है। इसके अलावा 50 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इनका खर्च अलग है। आज प्रदेश में जो गठबन्धन सरकार चला रहा है, उसमें कई ऐसे दल शामिल हैं जिनमें कोई विधायक नहीं हैं सारे के सारे मंत्री रोजाना ढाई लाख रुपया जेब खर्च में उड़ा देते हैं यह जेब खर्च वे सरकारी खजाने से ले रहे हैं। उस खजाने से जिसमें प्रदेश की आम जनता का पैसा जमा होता है।

भाजपा सत्ता में बनी रही, इसकी बहुत भारी कीमत प्रदेश की जनता को चुकानी पड़ी रही है। नतीजा यह हो रहा है कि प्रदेश सरकार पर

कर्ज का भारी बोझ लदता जा रहा है। आज प्रदेश सरकार पर पूरे 88 हजार करोड़ का कर्ज है। 31 मार्च 1999 को यह 56 हजार करोड़ था लेकिन यानी इन तीन सालों में कर्ज में 32 हजार करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है। प्रदेश सरकार का 95 फीसदी खर्च ऐसी मदों पर हो रहा है जो अनुत्पादक मदें कहलाती हैं। यानी जिनसे प्रदेश के और उसके लोगों के विकास में कोई मदद नही मिलती। केवल 5 प्रतिशत खर्च ही उत्पादक कामों में लगा है।

प्रदेश की हालत बिहार जैसी–

सौ मंत्रियों की फौज वाली यह सरकार खुद तो कमजोर है ही, प्रदेश को भी कमजोर कर रही है। अभी दो महीने पहले तक के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में करीब साढ़े चार करोड़ बेराजगार युवा हैं। इनमें से 70 फीसदी शिक्षित बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं, जिनकी संख्या करीब 80 लाख है। यह केवल वे वेरोजगार हैं जिन्होने नौकरी के लिये अपनी पंजीकरण कराया हुआ है। इसके अलावा न जाने कितने ग्रामीण युवा बेरोजगार घूम रहे हैं।

प्रदेश में गरीबी की सीमा–रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बराबर बढ़ रही हैं। वास्तव में प्रदेश में दो वर्गों की ही संख्या बढ़ रही है। सरकार में मंत्रियों की और शहरों–गांवों में गरीबों की आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर 100 में 38 लोग ऐसे हैं, जिन्हें गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश मे दो करोड़ 5 लाख लोग गरीब कहलाने लायक भी नही हैं। वे उससे भी नीचे की श्रेणी में हैं।

पूँजी निवेश के मामले मे 18 प्रमुख राज्यों मे उत्तर प्रदेश सोलहवें नम्बर पर हैं सामाजिक सेक्टर के विकास यानी शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य जैसे कार्यकमों के मामले में भी अपना प्रदेश 18 में से 14 नम्बर पर है। हाल मे कराये गये एक विस्तृत सर्वेक्षण से यह बाता उभरकर सामने आई है कि जहाँ तक सम्पन्नता का सवाल है अपने प्रदेश 17वें नम्बर पर हैं बिहार से वह जरा सा ही आगे है। सर्वेक्षण राजीव गाँधी इन्स्टीट्यूट फॉर कन्टेम्पेरेरी स्टडीज ने भारतीय उद्योग संघ के लिए किया है।

कानून व्यवस्था :

जिस प्रदेश में अपराधी तत्व सरकार में मंत्री हो। उनका काम अपहरण कराकर फिरौती लेना हो, उसमें कानून व्यवस्था की सहज ही कल्पना की जा सकती है। संघ परिवार के लोग ,खुद अयोध्या के विवादित स्थल पर जबरन घुस जाते हों, उसमें कानून व्यवस्था के हालत खराब नहीं होंगे तो और क्या होगा?

कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल किसी ने न तो कभी देखा था। और न ही सुना था। भाजपा के ही एक नेता की, जिसे मंत्री का दर्जा प्राप्त था, कानपुर देहात में एक पुलिस थाने के अन्दर हत्या कर दी गयी। जिस सरकार के राज में पुलिस थाने ही असुरक्षित हो, उसमें कानून व्यवस्था के हालात बताने की क्या कुछ जरूरत है। यहाँ मंत्री तक अपनी जान थाने के अन्दर घुसकर भी नहीं बचा सकते तो आम आदमी की बात क्या की जाय?

उपरोक्त सर्वेक्षण के दौरान यह बात उभरकर सामने आयी कानून व्यवस्था के मामलें में भी देश के 18 राज्यों में से अपना प्रदेश 17वें नम्बर पर है। बस बिहार थोड़ा सा नीचे इससे है। वरना यह प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में असम राज्य से भी पीछे है।

एक तरफ उत्तर प्रदेश को बी0 जे0 पी0 के कुशासन ने पूरी तरह चौपट कर दिया है दूसरी तरफ निर्धारित अवधि से ज्यादा समय तक सत्ता का सुख भोगने के बाद भी येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने की साजिश चल रही है। भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश का चुनाव टालने के लिये सीमा पर युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। जबकि सारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात के खिलाफ है। जब सरकार को कार्यवाहीं करनी चाहिए थी तब उन्होंने अवसर गँवा दिये। लेकिन भाजपा को देश के हित से भी ऊपर पार्टी हित नजर आता है और पार्टी हित के लिए भाजपाई कुछ भी कर सकते हैं। कारगिल यूद्ध के बाद भी उत्तर प्रदेश की बुद्धिमान जनता ने भाजपा को करारी शिकस्त दी थी। भाजपा चाहे जो षडयंत्र करे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकेगी।

साथियों, पूरा देश और खासकर उत्तर प्रदेश बेहद खतरनाक साजिशों का शिकार बनाया जा रहा है। इसमें भाजपा और उसके सहयोगी दलों का हाथ है। उनके लिये चुनाव जीवन–मरण का प्रश्न है तो हमारे लिये भी साम्प्रदायिकता को रोकना, अल्पसंख्यकों, किसानों, नौजवानों और समाज के वंचित लोगों की रक्षा करना हमारी जिन्दगी और मौत का सवाल बन गया है। इस गम्भीर आर्थिक संकट के समय चुनाव हो रहे हैं और मैं अपने नौजवानों,युवाओं महिलाओं तथा कार्यकारिणी के सभी साथियों का आह्वान करता हूँ कि अगले चुनाव में भाजपा और उनके साथियों को हटाना उनके कारनामों को आम लोगों तक पहुँचाना और उनके हमलो का सामना करना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। साम्प्रदायिकता को रोकना राष्ट्र सेवा है। इसके लिये कुछ भी बलिदान करने के लिये तैयार रहना चाहिए। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हम दोनों मोर्चों पर काम करेंगें । आतंकवाद से लड़ने के लिये लोगों को तैयार भी करेंगे और सरकार के संरक्षण में खड़ी साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने का काम करेंगें । प्रदेश की जनता तैयार है। देश भर हुए पिछले चुनाव में भाजपा हारी। राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र जैसे गढ़ों में भाजपा हार चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी इस बार समाजवादी पार्टी से उसकी हार तय है। हमें यह संकल्प शक्ति जगानी है इस अधिवेशन से इस अभियान को पूरा करना है।[9]

राजनैतिक प्रस्ताव–

आजादी की लड़ाई के गर्भ से समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ। रूस की क्रान्ति और वामपन्थी विचारों से प्रभावित नौजवानों ने सन् 1934 में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया जो कांग्रेश संगठन के अन्तर्गत ही काम करता था क्योंकि आजादी की लड़ाई का कांग्रेस ही सबसे बड़ा मंच था। किसानों, नौजवानों और मजदूरो का संगठन बनाकर देश व्यापी संषर्ष छेड़ा गया। समाजवादी विचारों, कार्यक्रमों और संषर्षो के कारण कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण और जनाधार बढ़ा। समाजवादियों का महत्व भी बड़ा।

---

9 - समाजवादी पाटी का पांचवा राष्ट्रीय सम्मेलन कानपुर में, तीन जनवरी 2002 को दिया गया अध्यक्षीय भाषण

1942 के आन्दोलन का नेतृत्व समाजवादियों ने किया और जब एक तरफ डा0 लोहिया आजाद रेडियो के जरिये आन्दोलन चला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जेल की दीवार फांदकर जयप्रकाश नारायण जी अपने कुछ साथियों के साथ निकले और डा0 लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण इस संषर्ध में एक साथ हो गये। इन लोगों ने आन्दोलन को नयी गति दी। आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ। डा0 लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेन्द्र देव ने कहा है कि गांधी जी की चुप्पी और हम समाजवादियों का निष्क्रिय विरोध देश के विभाजन को रोक नहीं पाया। सन् 1948 में कांग्रेस से अलग समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। परिस्थितियों के कारण समाजवादी पार्टी का किसान मजदूर पार्टी से एका हो गया और तभी से सिद्धान्तों का विचलन शुरू हुआ। जनता पार्टी बनने के बाद तो समाजवादी सिद्धान्तों और लक्ष्यों से हम दूर चने गये क्योंकि जनता पार्टी का लक्ष्य कांग्रेस को हटाकर सत्ता हासिल करना था। पहले सरकार बनी और बाद में पार्टी। इसलिए सिद्धान्तों के प्रति कोई आग्रह नहीं था। बिना सिद्धान्त के सत्ता न तो टिकाऊ होती है और न ही परिवर्तनकारी। इसका नतीजा यह जरूर हुआ कि समाजवादी पार्टी का संगठन और आन्दोलन छिन्न–भिन्न हो गया। लोंगो में जबर्दस्त हताशा हुई। सन् 1992 के अन्त में माननीय मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी गठित कर जोखिम उठाया। आज हम यहां सपा के पांचवे राष्ट्रीय सम्मेलन में मील रहे है।

आज भरत अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में है। विखटनकारी शक्तियां देश की आन्तरिक एकता को चुनौती दे रही हैं, पड़ोसी देशों से मधुर सम्बन्ध इतिहास का शिष्य हो गया है। राजनैतिक और प्रशासकीय भ्रष्टाचार सीमा लांघ चुका है। दुश्मन देशों के समक्ष भारत घुटनाटेक हालत में है, किसान, मजदूर, बुनकर, छात्र, नौजवान, छोटे व्यापारी और मध्यम उद्योगपति तबाही की मार झेल रहे हैं। देशी–विदेशी कर्जो के बोझ से देश की कमर टूट रही है, देश की बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से आर्थिक नीतियों मे सहयोग लेकर भाजपा के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन सरकार इस देश की कृषि, उद्योग सभी कुछ नष्ट कर भारत की सम्पूर्ण व्यवस्था को विश्व की महान पूंजीवादी व्यवस्था के सुपुर्द कर रही है।

समाजवादी पार्टी आर्थिक और समाजिक गैर बराबरी के विरूद्ध बराबर संघर्ष करती रही है। हरिजन, आदिवासी, महिला, पिछड़े एवं मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की पक्षधर रही है। मण्डल कमीशन की सिफरिशों को सबसे पहले ईमानदारी से मुलायम सिंह यादव ने ही अपने मुख्यमंत्रित्व काल में लागू किया और गरीब सवर्णों को भी आरक्षण देने की पेशकश की।

आजादी के बाद भारत आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक खतरे के चौराहे पर खड़ा है। भूमण्डलीकरण, निजीकरण, बाजारीकरण और उदारीकरण की नीतियों को भाजपा सरकार द्वारा अपनाये जाने के कारण देश में गरीबी, गैर बराबरी एवं बेरोजगारी बढ़ी है औार इसी के साथ–साथ धर्मान्धता, आतंकवाद और अपराध भी बढ़े हैं। इस समय तो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। सभी गरीब एवं विकासशील देश अमेरिका और महाशक्तियों के उपनिवेश बनते जा रहे हैं और उनकी सत्ता और नीतियाँ उन्हीं द्वारा संचालित होती हैं। इस समय दुनियाँ में आर्थिक साम्राज्यवाद पनप रहा है। इन नीतियों के फलस्वरूप हमारी आजादी और सम्प्रभुता भी खतरे में है। अभी हाल की घटनाओं में अमेरिकी बमबारी, यूरोपीय देशों की एकजुटता अैर अफगानिस्तान के सत्ता परिवर्तन ने अमेरिकी प्रभाव, शक्ति एवं वर्चस्व को प्रमाणित किया है और आज वे विश्व व्यवस्था के नियन्ता बन गये हैं। आतंकवाद के विरूद्ध छेड़े गये विश्वव्यापी अभियान में दुनियां से आतंकवाद समाप्त करने की अपेक्षा यूरोपीय देशों के हित एवं बदले की भावना सर्वोपरि है। व्यापक लक्ष्य और समग्र दृष्टि का आभाव है। जिस प्रकार से हथियारों की होड़ मची हुयी है, हथियारों और मादक पदार्थों का व्यापार खुले रूप से फल–फूल रहा है तथा दूसरे देशों में आतंकवाद एवं अपराधिक कृत्यों से सरकारों को अस्थिर बनाने का दौर चल रहा है, इसके चलते आतंकवाद को समाप्त करने और युद्ध को रोकने की इमानदारी नहीं दिखायी पड़ती।

स्वतन्त्र, सृजनात्मक एवं तटस्थ विदेश नीति चलाने में वर्तमान सरकार विफल रही है और अमेरिका की पिछलग्गू बन गयी है। हम अपनी पहल खोते जा रहे हैं और इसलिये दूनियां से भी हमारे कोई मित्र नहीं रहा। हमारी कूटनीतिक विफलता भी इसका कारण है। पड़ोसी देशों से भी हमारे रिश्ते

अच्छे नहीं हैं, जबकि हमें उनका नेतृत्व करना चाहिए था। पाकिस्तान से तो रिस्ते बराबर विगड़ते ही जा रहे हैं और अब तो युद्ध की स्थिति बन गयी है। सरकार की पाकिस्तान के सम्बन्ध में कभी कोई ठोस एवं दीर्घकालिक नीति नहीं रही है। दृष्टि और लक्ष्य का भी अभाव है।

लालकिला, जम्मू–कश्मीर की विधान सभा तथा संसद भवन पर आतंकवादी–आत्मघाती हमला बर्बर और जघन्य है। सम्मेलन इसकी घोर निन्दा करता है और इसे भारत और लोकतन्त्र पर हमला मानता है। इसलिये इस संकट के दौर में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय एकता और आजादी की रक्षा के लिए उठाए गये कदम के साथ एकजुटता प्रदर्शित करती है। लेकिन इसके लिये यह बहुत जरूरी है कि शासक दल या गठबंधन अपनी नीयत और नीतियों को बदले और उनके संगठनों द्वारा चलाये जा रहे आतंकवाद पर सख्ती से अंकुश लगाये। क्योंकि यह संम्मेलन मानता है कि बाहरी आतंकवाद आन्तरिक आतंकवाद से खाद पाकर पनपता और उग्र रूप धारण करता है।

आज दुनियां राजनीतिक दृष्टि से तीन हिस्सों मे बंटी है। विकसित, विकासशील एवं अति पिछड़े देश हैं। विकसित देश इन अति पिछड़े देशों की सही मायने में कोई मदद नहीं करते और धर्मान्धिता बढ़ रही है तथा राजनीति में भी विकृतियां आ रही हैं। समाजवादी पार्टी इन विकृतियों को समाप्त करना चाहती है।

पिछले दो वर्षो में भारत की वर्तमान सरकार ने देश के संकट को और बढाया है। संविधान के बुनियादी ढांचें के साथ छेड़–छाड़, इतिहास को बदलने व बिगड़ाने तथा शिक्षा के भगवाकरण की नीति, देश मे संघ परिवार के विचारों को मूर्त रूप देने की साजिस है। यह सरकार भूमण्डलीकरण की नीतियों के दर्शन पर ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थनीति चला रही है, जिसमें केवल आबादी के एक तिहाई हिस्से का ही हित ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि वे ही बाजार का हिस्सा बनते है। मुफ्त या सस्ती और समान शिक्षा एवं चिकित्सा शेष दो तिहाई आबादी के निए असम्भव हो गये हैं।

अयोध्या में राम मन्दिर के विवादित गर्भ में जबरन प्रवेश, बार–बार मन्दिर निर्माण की घोषणा, ताज महल परिसर को विकृत करने की कोशिश तथा विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल एवं युवा मोर्चा के क्रिया कलापों से

हिन्दू एजेण्डे को जिन्दा रख रही है। इस सरकार की दृष्टी सोच एवं आचरण साम्प्रदायिक है। गांधी जी की हत्या से लेकर बाबरी मस्जिद के ध्वंस और राम मन्दिर निर्माण की बात ये सभी इसी साम्प्रदायिक सोच के नतीजे हैं।

भजपा गठबंधन का वर्तमान शासन भ्रष्टतम शासन साबित हो चुका है। रक्षा सौदा में उच्चतम स्तर के भ्रष्टाचार देश की सुरक्षा के लिए जबर्दस्त खतरा है। तहलका डॉट कॉम ने ऊंचें स्तर के भष्ट्राचार को साफ तौर से उजागर कर दिया है। सेना द्वारा कराई गयी जांच ने 'तहलका' द्वारा नामित सेना के अधिकारियों को दोषी पाया है लेकिन सरकार आयोग गठित कर जांच कराने से मामले को खींचले जाने की कोशिश कर रही है। ऊपरी स्तर के भ्रष्टाचार ने पूरे देश में निचले स्तर तक पहुंचा दिया है। रिश्वतखोरी, भाई–भतीजावाद से देश की जनता त्राहि–त्राहि कर रही है। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट के खुलासे के बाद तो यह सरकार कफन चोरो की सरकार साबित हुई है। कारगिल की लड़ाई में भारत के सपूतों के शहीद हो जाने पर उनके पार्थिव शरीर को लाने ले जाने के लिए जो कांफीन (अर्थियां) खरीदी गयी उनके तथा अन्य सैन्य समानों मे करोडों रूपये की हेरा–फेरी ने देश को हतप्रद्र कर दिया है। भ्रष्टाचार को एक नया आयाम देते हुए आज भी यह सरकार विरोधी दलों के सांसदों को घूस और लालच देकर दल–बदल कराके सभी नैतिक मानदण्डों को तिलाजंलि देने में जुटी है और इसके निशाने पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी है।

इतिहास बदलने की दृष्टि को रखते हुए पाठ्य–पुस्तकों में परिवर्तन किया जा रहा है। संघ की विचारधारा हिन्दू र्धम को सवोत्कृष्ट धर्म मानती है। साथ ही धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को अल्पसंख्यकों के पक्ष में मानती है। जबकी यह बात जगजाहिर है कि और स्वंय सिद्ध है कि भारतीय संस्कृति और इतिहास उदारता, बहुलता, विविधता तथा सर्वधर्म समभाव का हामी और पोषक रहा है। इसके साथ ही पाठ्य–पुस्तकों में नैतिकता के पाठ के नाम पर पोंगापंथी, कट्टरवादी तथा असहिष्णु विचारों के विष को बालकों के दिमाग में बिठाना चाहती है। नैंतिक शिक्षा को धर्म से जोड़ना संकीर्ण एवं प्रतिक्रया वादी कदम है दुनिया के सभी धर्मों, सम्प्रदायों में नैतिकता और अच्छे आचरण

की सीख मिलती है, पर केवल एक विशेष धर्म से जोड़ना एक प्रतिगामी एवं संकीर्ण सोच का परिणाम है

समाजवादी पार्टी शिक्षा में ऐसे विष तत्वों के लाए जाने वाले कदम की निन्दा करती है और इसका डटकर विरोध करने का निश्चय करती है। भारती जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजपार्टी आदि पार्टियां यथास्थिति वादी एवं सडन की पार्टियां है समाजवादी पार्टी का उनसे मौलिक सैद्धान्तिक मतभेद है समाजवादी पार्टी समाजवाद में विश्वास करती है। केवल समाजवादी विचार ही आज दुनिया के सभी शोषित एवं दलित लोगों के लिए आदर्श विचार है

समाजवादी पार्टी का लक्ष्य केवल सरकार बनाना ही नही बल्कि लाखों बेरोजगार युवकों को रोजगार की गारण्टी देना भी है क्यों कि पार्टी का विश्वास है कि गरीबी से बेरोजगारी पैदा नही होती बल्कि बेरोजगारी से गरीबी पैदा होती है इसलिए अगर गरीबी को हटाना है तो बेरोजगारी हटानी होगी समाजवादी पार्टी का यह राष्ट्रीय सम्मेलन पार्टी के कार्यकर्ताओ का आह्यवान करता है कि सरकार के किसान, मजदूर, व्यापारी, अल्पसख्यक, दलित एवं पिछड़ो कि विरोधी मानसिकता का पर्दाफाश करे तथा आने वाले चुनाव मे समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम करें।[10]

आर्थिक प्रस्ताव –: समाजवादी पार्टी के पांचवे राष्ट्रीय सम्मेलन कानपुर में जो आर्थिक प्रस्ताव पारित हुआ वह इस प्रकार है–

समाजवादी पार्टी का यह राष्ट्रीय सम्मेलन देश की निरन्तर बिगड़ती आर्थिक हालत पर चिन्ता प्रकट करता है। समाजवादी पार्टी याद दिलाना चाहती है कि गुलामी के दिनों में भी भारत की गणना एक समृद्ध देश के रूप में होती थी। इस देश का कपड़ा, दस्तकारी, चीनी व लघु उद्योग आधारित सामान उपयोग में आने वाली वस्तुओं की विश्व बाजार में पूछ थी। अंग्रेजी साम्राज्य शाही ने प्रथम प्रहार इस देश की दस्तकारी और हाथ से तैयार होने वाने कपड़े पर किया। धीरे–धीरे भारत की विश्व व्यापार में साझेदारी कम होने लगी। भारत विश्व व्यापार की प्रमुख संस्था गैट के संसथपक देशों में एक था। विगत शताब्दी के अन्तिम दशक में जो साम्राज्यवादी और पूँजीवादी का

10. समाजवादी पार्टी के 'पांचवां राष्ट्रीय सम्मेलन' कानपुर में 4 जनवरी 2002 को पारित राजनैतिक प्रस्ताव

अन्तिम चरण था उस दौर में पूँजीवाद–साम्राज्यवाद के विकल्प के रूप में आई सोवियत पद्धति की मार्क्सवादी व केन्द्रीभूत लोकशाही का भी पतन होने लगा। पूँजीवाद अपने नये कलेवर में उदारवाद, भूमण्डलीकरण आदि नारों के साथ विश्व व्यापार संगठन बनाया गया और उसके छतरी तले विश्व के सभी विकसित, अर्द्धविकसित, विकासमान और गरीब देशों को लाकर "सह नौ भुनक्तु" के नारे के साथ विश्व के सभी संसाधनों पर कब्जा जमा और लूट की व्यवस्था चलाते रहने का अभियान शुरू हुआ। समाजवादी आन्दोलन के कोख में जन्मे नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय पूँजीवाद के इस मरिच रूप को ठीक से पहचाना तथा देश और विश्व की जनता को सजग और सावधान करने के लिये फिर से समाजवादी आंदोलन को पुनर्जीवित किया।

समाजवादी पार्टी इस बात को गम्भीरता पूर्वक नोट करती है कि भूमण्डलीकरण की व्यवसथ लागू होने के 10 वर्ष के भीतर विश्व की एक तिहाई जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे चली गयी अर्थात 1 डालर प्रतिदिन की आमदनी पर गुजर बसर करने वालों की संख्या दो अरब हो गयी है। नई अर्थव्यवस्था के ध्वज वाहकों ने 10 वर्ष की समीक्षा के बाद पाया कि सर्वाधिक गरीब लोगों की टोली दक्षिण एशिया में बसती है और अकेले भारत में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। वास्तविकता यह है कि यह संख्या इससे बहुत ज्यादा है। 'अल्टरनेटिव इकोनोमिक सर्वे' के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वालों की संख्या भारत में लगभग 75 करोड़ है। 20 करोड़ लोग तो घोर निर्धनता और अभाव की जिन्दगी जीने को विवश हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दरिद्रतम देश नाइजीरिया और बंगलादेश हैं। इस विश्व बाजार व्यवस्था का यूरोपीय देशों ने सीधी रणनीति के तहत इस्तेमान किया चूँकि 19वीं शताब्दी के साम्राज्यवादी युग में दुनियाँ की दौलत को लूटकर अपने को दौलतमंद बनाने का उनका पुराना अभ्यास था। इसलिये उन्होंने तत्काल यूरोपीय व्यापार संघ मजबूत किया। अब तो अपनी सभी मुद्राएं खत्म कर एक मुद्रा यूरो के माध्यम से काम चलाने लगे, आपस में वीजा की व्यवसथ खत्म की, जर्मनी का एकीकरण कराया और रेल, सड़क, वायु मार्ग ऐक कर लिया। 19वीं सताब्दी के विश्व लुटेरे विश्व बाजार की लूट का मजा

उड़ाये थे। फिर उनकी अर्थव्यवस्था चमक उठी। गरीब मुल्कों की कीमत पर फिर से वे अमेरिका, जापान, चीन से टक्कर लेने को तैयार हैं। 10 वर्ष की नई व्यवस्था के बाद देशों को तरक्की के मामले में रेटिंग हुई है। इसके अनुसार फिनलैण्ड विश्व का नम्बर एक धनी देश उसने अमेरिका को दो पर कर दिया, नार्वे, स्वीडन, जर्मनी इनकी अर्थव्यस्था उछाल मार रही है और एशिया का आर्थिक रिमौर्य कहा जाने वाला जापान का 21 वें स्थान पर अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। विश्व का दो नम्बर का दानी सिंगापुर 4 के स्थान पर, मलेशिया 24वें से 30वें स्थान पर और आबादी के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा देश भारत 48वें स्थान से गिरकर अब 57वें नम्बर पर है, केवल वैज्ञानिक और इंजीनियर की दृष्टि से भारत का 4वाँ स्थान था। आज यूरोप के देश अपने देश के कृषि उत्पादन पर प्रति हेक्टेयर 40000 रूपये की इतनी सब्सिडी दे रहे हैं जा अफ्रीकी देशों के वार्षिक बजट के बराबर है विश्व व्यापार संगठन यूरोप एवं अमेरिका द्वारा अपने कृषि की सब्सिडी खत्म या कम नहीं कर रहा है लेकिन हमारी सरकार कृषि पर से सब्सिडी खत्म करती जा रही है। फलस्वरूप सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश कहने वाला भारत विश्व खाद्यान्न व्यापार में मात्र 1 प्रतिशत साझेदारी रखता है। समाजवादी पार्टी सम्पूर्ण विश्व व खास तौर से भारतीय जन को नई भूमण्डलीकरण की व्यवस्था से फिर एक बार सावधान करना चाहती है। विदेशी कम्पनियाँ हमारे देश में उद्योंग–व्यापार एवं खेती पर कब्जा करती जा रही है। कारगिल कम्पनी नमक तथा अन्य वस्तुओं पर वर्चस्व बढ़ा रही है। मेकडोवल कम्पनी होटल व्यवसाय को कब्जा रही है तथा मोसांटो कम्पनी कपास की खेती तथा अन्य अनेक विदेशी कम्पनियों ने भारत में देशी उद्योग, व्यवसाय एवं व्यापार पर धावा बोल कर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है।

समाजवादी पार्टी का सम्मेलन घोर निन्दा करती है कि भाजपा ने काँग्रेस से सौ कदम आगे बढ़कर नई अर्थनीति को स्वीकार कर लिया है और भारत के धरातल की कठिनाइयों को समझे बिना लूट का अर्थतंत्र देश में लाद दिया है। इस नई अर्थनीति से भारत में बेकारी बढ़ती जा रही है। और अन्न की कम होती खपत ने देश के आर्थिक ढाँचे को तोड़कर रख दिया है। आज भी सरकार और योजनाओं का जोर उदारीकरण की प्रक्रिया को तेज

करने पर आयोग के नये दस्तावेज कहते हैं कि भारत के गोदामों में अनाज सड़ने का कारण जनता के खानपान में बदलाव है। अब जनता दूध, अण्डे, फल खाने लगी, इसलिये अन्न की खपत कम है और उत्पादन ज्यादा है। अतः प्रधानमंत्री भी कहते हैं देश में भुखमरी की खबरें मीडिया तंत्र द्वारा फैलाया गया झूठ है। देश के किसान अन्न उपजाना बंद कर फल–फूल की खेती करें घुटनाटेक नेतृत्व और पूँजीवाद के जरखरीद गुलाम भारतीय अफसर इस देश को खुली आँख से देखना नही चाहते। देश में दुर्भिक्ष, अकाल और बढ़ती बेकारों की फौज ने देश की बहुसंख्यक आबादी को कंगाल बना दिया है। लगभग 30 करोड़ लोगों को एक वक्त का भोजन जुटाना कठिन है। अन्न खरीदने की उनकी सामर्थ्य समाप्त है। देश के समाजवादी देश की गरीब, बेरोजगार कंगाल जनता से एकजुट होकर जनता के इन दुश्मनों को तत्काल गद्दी से उतारने का आह्वान करती है।

भारत की निरन्तर प्रति व्यक्ति आमदनी गिर रही है। देश की तरक्की की रफ्तार 5 प्रतिशत कैद है जबकि पड़ौसी देश चीन की हमसे अधिक आबादी के बावजूद पिछले 20 वर्षों से 7 फीसदी के हिसाब से बढ़ रही है। उसका प्रमुख कारण है कि उसने अपने देश की कृषि सुधार पर बल दिया। कृषि क्षेत्र इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आजादी के समय देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 50 प्रतिशत था। सन् 1970 में घटकर 44 प्रतिशत रह गया था और 2000 में केवल 24 प्रतिशत। आजादी के समय भी कृषि क्षैत्र पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या देश की जनसंख्या के 76 प्रतिशत थी और आज भी लगभग उतनी ही है। लेकिन देश के कुल उत्पाद मे उसकी भागीदारी घटकर आधी से भी कम रह गयी है। किसानों की तबाही का इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है। नई अर्थव्यवस्था आने के बाद सारा सरकारी जोर औद्योगीकरण पर रहा, परिणामतः न उद्योग बढ़ा न खेती। समाजवादी पार्टी इस बात को समझती है कि खेती ही सबसे अधिक रोजगार पैदा करती है। विगत दो वर्षों में खाद्यान्न की उपज 10 लाख टन के हिसाब से कम हो रही है। खाद की खपत में कमी, खेती लायक जमीन में कमी, किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य न मीलना, विश्व की खाद्यान्न व्यापारिक संस्थाओं का भारत में जबरन प्रवेश आदि ऐसे कारण हैं, जिससे खेती और

उससे जुड़ी गतिविधियाँ कम होती जा रही है। खेती के बाद का जो उसी से जुड़ा क्षेत्र है, कपड़ा तथा लघु उद्योगों जिसमें सबसे अधिक लोग काम में लगे थे, आज 403 कपड़ा मीलें बंद हो गयीं तथा कई लाख लघु इकांइयां बंद हो गयीं । चीन की खेती तथा लघु उद्योग की भारी उन्नति के हमले के शिकार दक्षिण एशिया के गरीब देश ही होंगे, भारत उससे सबसे अधिक प्रभावित होगा– जो अभी से देश के बाजार में दृष्टिगोचर हो रहा है।

भारत सरकार ने गत वर्ष लगभग हर क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिये हैं। इससे हमारे देशी उद्योग धन्धों तथा उससे जुड़े करोड़ों लोगों का भविष्य पूरी तरह अन्धकारमय हो गया है। विदेशी कम्पनियों ने हमारे बाजारें को, विदेशी गाय–माँस, सुअर–माँस, अण्डा, गेहूँ, बाजरा, चावल, तेल, दूध, मक्खन और तरह–तरह के अन्य खाने के तथा अय्याशी के सामानों से पाट दिया है। पश्चिमी पूँजीवादी उपभोक्ता संस्कृति हमारी आर्थिक रीढ़ को तोड़कर सांस्कृतिक विरासत को भी नष्ट–भ्रष्ट करने पर आमादा है और यह सब हो रहा है राष्ट्रवाद एवं भारतीय संस्कृति के तथाकथित ठेकेदारों की सरकार के रहते, उसके सक्रिय सहयोग एवं सहमति से।

भारत में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बेरोक–टोक प्रवेश से देश के 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत लोग तो तड़क –भड़क की दुनियाँ का मजा ले सकेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में देश के 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग अभाव एवं गरीबी का जीवन जीने को लाचार एवं विवश होंगे।

वर्तमान सरकार की जन विरोधी गतिविधियाँ यहीं तक सीमित नही हैं। अब वह तेजी से डिसइन्वेस्टमेन्ट मंत्रालय बनाकर सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय महत्व के उपक्रमों को औंने–पौंने दामों पर बेच रही है। देश के उपलब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों के शेयर विदेशी कम्पनियों को कम रेट पर बेचकर उनमें हमारी भागीदारी को निर्णायक स्तर तक घटाकर बेचने की तैयारी है। ओ० एन० जी० सी० जैसे लाभ में चल रहे निगम के शेयर बहुत बड़ी संख्या में कम दाम पर विदेशी कम्पनियों को बेच दिये हैं। अरबों रूपयों की सम्पत्ति जो विभिन्न संस्थानों एवं कल–कारखानों के रूप में है, देशी विदेशी कम्पनियों को कौड़ी के मोल में बेचा जा रहा है। मार्डन फूड एवं बालकों जैसी लाभ पर

चलने वाली कम्पनियों को मिटटी के मोल निजी कम्पनियों को बेंच दिया जा रहा है। आई0 टी0 डी0 सी0 के अनेंक होटलों को मिटटी के मोल बेंच दिया जा रहा है। इन सौदो में सैकड़ों करोड़ रूपयें के कमीशन की बात लोंगों की जुबान पर है। स्टील आँफ इण्डिया को भी बेचने की तैयारी है। उदारीकरण, भूमण्डलीकरण, बाजारीकरण एवं निजीकरण के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा देश को बेचने एवं देश के आत्म–सम्मान को गिरवी रखने का काम बेशर्मी के साथ किया जा रहा है।

समाजवादी पार्टी को इस बात खेद है कि सबसे अधिक स्वदेशी और स्वावलम्बन का राग अलापने वाली भाजपा के राज में देशी विदेशी कर्ज बढ़ा है। देश पर आन्तरिक कर्ज का बोझ 10 लाख करोड़ के आस–पास और विदेशी कर्ज लगभग 5 लाख करोड़ है। भाजपा सरकार के आने के बाद सम्पूर्ण कर्ज तीन वर्ष में दूना हुआ है। हमारे बजट का 45 प्रतिशत कर्ज अदायगी में जा रहा है। केन्द्रीय सरकार प्रांतीय सरकार के सम्मिलित जो और इनकी गारण्टी पर मीले कर्जो को जोड़ दिया जाय तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 85 प्रतिशत है। इस तरह सम्पूर्ण देश की अर्थव्यस्था कर्ज के बोझ से दबकर मरने वाली है। सरकार के ठाट–बाट, शान–शौकत, फिजूलखर्ची भी उसी प्रकार से बढ़ रही है। सभी पड़ोसी देशो के साथ कटुतापूर्ण संबंधों के नाते रक्षा का बजट हर साल बढ़ाना पड़ रहा है। देश में निरक्षरता, बीमारी, लाचारी बढ़ रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में व्यय करने के निये निरन्तर पैसों का आभाव है। देश की तरक्की की बुनियाद रेल, सड़क, वायु, मार्ग, विजली इसके स्थान नये संसाधनों के आभाव में हम निरन्तर अधोगति की ओर जा रहे हैं।

समाजवादी पार्टी इन सभी चीजो का विकल्प स्वदेशी, स्वावलम्बन और समाजवादी अर्थ तंत्र को मानती है। देश की तरक्की गें सभी की सागान साझेदारी, सभी को उत्पादन करने के अवसर और साधन दिये बिना इस देश अथवा विश्व का कल्याण संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन समाजवादी समाज की रचना के लिये अपने को समर्पित करते हुए देश के शासकों को आगाह करता है कि उन्होंने शीघ्र आँखें नहीं खोली तो पूरा देश अराजकता, लूट, मारकाट में सराबोर हो जाएगा। देश की बेरोजगार और लाचार जनता खुले रूप से सामने आकर पूरी व्यवस्था को भंग करने के लिये

विवश होगी। देश के कुछ हिस्सों में बढ रही हिंसक घटनाएं इसका संकेत दे रही हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन की यह राय है कि देश को बचाने भाजपा शासन से मुक्ति दिलाना परम आवश्यक है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह सम्मेलन कार्यकर्ताओं का आह्वान करता है कि घर–घर जाकर भाजपा के काले–कारनामों का पर्दाफाश करें और "करो का मरो" की भावना से चुनावी महासमर में कूदने का काम करें।[11]

11 - सपा के 'पांचवे राष्ट्रीय सम्मेलन' कानपुर में 4 जनवरी 2002 को पारित आर्थिक प्रस्ताव।[11]

निष्कर्ष

भारत में तो समाजवाद किसी न किसी रुप में बहुत पहलें से ही विद्यमान हैं, वैदिक ग्रन्थों में जिस प्रकार से सभी प्राणियों की सहज समानता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुत्व की भावना को उजागर किया गया है उससे सहज ही उसका अनुमान लगाया जा सकता हैं। बौध ग्रन्थ तथा महाभारत में इसके सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता हैं कि भारती ग्रन्थों में समाजवादी विचारों के मूलतत्व विद्यमान थे लेकिन अर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के दर्शन के रुप में समाजवाद भारत में पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरुप ही विकसित और लोकप्रिय हुआ।

समाजवाद की वर्तमान विचारधारा तो 19वीं शताब्दी में विकसित हुई। सन्1807 राबर्ट ओवेन के अनुयायियों के लिए अंग्रेजी भाषा में समाजवादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति तथा पूंजीवाद ने समाज में इतनी अधिक विषमता पैदा कर दी कि उसी के प्रतिक्रिया स्वरुप समाजवाद की विचारधारा पैदा हुई इस प्रकार समाजवाद की विचारधारा भी अपने आप में एक प्रतिक्रियात्मक विचारधारा है। बीसवीं शताब्दी में विश्व के राजनीतिक और सामाजिक चिन्तन को सबसे अधिक समाजवादी विचारधारा ने ही प्रभावित किया है। वर्तमान में तो समाजवाद एक प्रभावशाली आन्दोलन तथा एक क्रान्तिकारी सिद्धान्त के रुप में गतिमान है। समाजवाद को सही रुप में स्पष्ट करना एक कठिन कार्य है क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार समाजवाद की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। अरस्तू से लेकर महात्मा गांधी तक ने समाजवाद के विषय में भिन्न विचार व्यक्त किये हैं।

19वीं शताब्दी के आरम्भ में समाजवादी विचारों का जो विकास इंग्लैण्ड और फ्रांस में तीव्रगति से हुआ वह कोई स्थाई परिणाम के बिना ही 19वीं शताब्दी के मध्य में ही कुछ समय के लिए स्थिर हो गयी। इसके बाद इस विचारधारा का विकास जर्मनी में बहुत तीव्रगति से हुआ क्योंकि वहाँ के समाज संगठन का ढांचा परम्परावादी सामन्तवादी व कुलीन तंत्री आधार पर संगठित था। इस विचारधारा के विकास में पूर्व के विचारकों ने काफी सहयोग दिया।

कार्ल मार्क्स से पूर्व का समाजवाद काल्पनिक समाजवाद कहा जाता हैं, क्योंकि वह इतिहास के किसी दर्शन पर आधारति नहीं था। समाजवादी विचारधारा को वैज्ञानिक स्वरुप प्रदान करने में कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का काफी योगदान रहा हैं। मानव समाज की नवीन

व्याख्या उसके द्वारा ही की गयी मार्क्स ने किसी नवीन विचार का प्रतिपादन नहीं किया बल्कि पूर्व सिद्धान्तों का प्रवर्तक था। उसे श्रमिकों का मसीहा और उसके ग्रन्थ 'दास कैपिटल' को आधुनिक बाइबिल कहा जाता है। मार्क्स ने ऐंगेल्स के साथ मिलकर समाजवाद के वैज्ञानिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करके आधुनिक रुप प्रदान किया। मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक इसलिए कहा गया है कि उसने एक ऐसा आन्दोलन चलाया जिसका एक निश्चित सिद्धान्त था और उस समय चल रहे निराधार समाजवादी आन्दोलन को एक आधार प्रदान किया। उसके पूर्व जो समाजवादी विचारधाराएं थी, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से उन पर धार्मिक अथवा भौतिक प्रभाव अवश्य था। जब समाजवाद वैज्ञानिक रुप में सामने आया तब जनता धार्मिक-विश्वासों से विमुख होने लगी थी, मार्क्सवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारत में समाजवाद का विकास राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि पर हुआ जिन प्रारम्भिक चिन्तकों ने राष्ट्रवादी भूमि तैयार करने में प्रमुख भूमिका अदा की उसमें राजाराम मोहनराय दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण परमंहस के नाम उल्लेखनीय है।

दयानन्द सरस्वती मूलतः एक समाज सुधारक थे किन्तु उनके विचारों में समाजवादी धारण और दर्शन के प्रमुख बिन्दु मिलते हैं।

विवेकानन्द भारत में पहले एसे विचारक थे जिन्होंने भारतीय इतिहास की समाजशास्त्रीय दृष्टि से यथार्थवादी व्याख्या की। उन्होंने जो भारत की व्याख्या की वह स्वरुप में अंशतः मार्क्सवादी भी है, किन्तु वह उनके अपने ढंग की मार्क्सवादी है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने दास कैपिटल अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र पढ़ी थी। स्वामी विवेकानन्द उस अर्थ में समाजवादी नहीं थे जिस अर्थ में हम आधुनिक किसी राजनीति दार्शनिक को समाजवादी कहते है। उनकी दृष्टि में समाजवादी कोई एकदम निर्दोष या आदर्श व्यवस्था नहीं थी।

1920 से 1947 ई0 तक भारतीय राजनीतिक युग गाँधी युग कहलाता है। महात्मा गाँधी ने 1920 ई0 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन एवं कांग्रेस की नीतियों को एक नई दिशा प्रदान की। गाँधी जी की समाजवादी कल्पना का मूल आधार नैतिक हैं उनका समाजवाद मानवीय समाजवाद है जो वैज्ञानिक समाजवाद से भिन्न है उनके समाजवाद में वर्ग संघ की हिंसात्मक क्रान्ति और औद्योगिकरण का गौण स्थान है। वे समाजवाद की स्थापना के लिए सत्य, प्रेम, अहिंसा, सत्याग्रह ग्रामोद्धार, पुनर्मिाण एवं ट्रस्टिशिप आदि बातों को विशेष महत्व देते है।

पं0 जवाहर लाल नेहरु को कांग्रेसी नेताओं में प्रमुख समाजवादी के रुप में स्वीकार किया जाता हैं विद्यार्थी जीवन में वे इंग्लैण्ड में फेबियनवादी समाजवाद के सम्पर्क में आये तथापि मूलतः राष्ट्रवादी ही रहे। 1927 ई0 में नेहरु जी द्वारा रुस की यात्रा की और वहाँ साम्यवादियों की उपलब्धियों को प्रत्यक्षतः देखा तभी से उनके अन्दर समाजवाद के प्रति रुचि बढ़ने लगी। नेहरु जी के समाजवादी चिन्तन का क्रमबद्ध विकास सन् 1929 के लाहौर (अधिवेशन से प्रारम्भ होता है,) जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किया। अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने स्वीकार किया कि मैं एक समाजवादी और लोकतन्त्रवादी हूँ। उन्होंने समाजवाद और राष्ट्रवाद में समन्वय स्थापित किया। समाजवाद के मुद्दे पर उनका गाँधी के अतिरिक्त नरेन्द्र देव, जय प्रकाश नारायण, सुभाष चन्द्र बोस, डा0 राजेन्द्र प्रसाद, बल्लभ भाई पटेल, एम0 एन0 राय आदि नेताओं से उनका वैचारिक मतभेद हुआ। स्वाधीनता के बाद भी नेहरु जी की समाजवादी चिन्तन में प्रजातान्त्रिक समाजवाद की झलक दिखाई पड़ता है।

आचार्य नरेन्द्र देव समाजवाद के प्रारम्भिक चिन्तकों में से थें बीसवीं शताब्दी के प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात जब समाजवादी विचारों का हमारे देश में विकास होने लगा नरेन्द्र देव ने इसे न केवल स्वीकार किया वरन् आगे बढ़ाने में भी अग्रणी रहे।

भारतीय समाजवाद के प्रणेताओं में डा0 राम मनोहल लोहिया को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वे एक लड़ाकू व्यक्तित्व वाले प्रखर समाजवादी माने जाते हैं। जर्मनी में उन्हें समाजवाद की प्रेरणता प्राप्त हुई जब वे बर्लिन विश्वविद्यालय में 'नमक और सत्याग्रह' पर शोध कर रहे थे। बाद में वहाँ से पी0 एच0 डी0 की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने स्वयं लिख कि सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि भारत का समाजवादी आन्दोलन अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकता है। या उसे सदैव दक्षिण या वामपंथी वैशाखियों की जरुरत पड़ती रहेगी।

डा0 लोहिया ने सर्वप्रथम अपने समाजवादी विचारों का प्रतिपादन एक सम्पादक के रुप में किया उन्होंने लिखा कि "समाजवादियों को साम्यवादियों या उदारवादियों के साथ मित्रता के संबंध रखने चाहिए। केवल इसी तरह विश्वभर में और भारत में एक सहज और सृजनात्मक समाजवाद की रचना होगी। द्वितीय विश्व युद्ध में डा0 लोहिया ने अपना एक चार सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध किया। भारत के अन्य समाजवादियों के समान लोहिया भी मार्क्सवाद से प्रभावित हुए। उन्होंने कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक

समाजवाद का महान व्याख्याकार माना है। उन्होंने मार्क्स के पूंजी संचय संबंधी सिद्धान्त, पूंजीवादी एकाधिकार तथा श्रम के समाजीकरण को स्वीकार किया और उसके वर्ग संघर्ष तथा विश्व क्रान्ति को मान्यता नहीं दी। लोहिया मार्क्सवाद के बारे में विचार करके भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढ़ालने के पक्षधर रहे हैं। लोहिया ने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल एक नया समाजवादी चिन्तन विकसित करने का प्रयास किया। उनके समाजवादी चिन्तन के मौलिक आधार में क्रान्तिकरण, सात क्रान्तियां, चौखम्भा योजना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, जातिप्रथा उन्मूलन, नारी समस्या, साम्प्रदायिकता आदि सामाजिक प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त किये।

सम्पूर्णानन्द की गणना कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापकों में की जाती है वे भारतीय सस्कृति के आदर्श से अनुप्रेरित होने के कारण मार्क्सवाद और लेनिनवाद को स्वीकार नहीं किये। उनके ऊपर गांधीवाद का गहरा प्रभाव था। वे गाँधीवाद और साम्यवाद में समन्वय स्थापित करने के इच्छुक थे उनके चिन्तन में समाजवाद के स्थान पर सर्वोदय शब्द अधिक उपयुक्त लगता था। उनके अनुसार समाजवाद केवल मात्र शोषण का अन्त करने का एक राजनीतिक या आर्थिक चिन्तन नहीं है, वरन वह तो मानव के सम्पूर्ण जीवन की दृष्टि है। लोकतंत्र में उनका दृढ़ विश्वास था।उनके अनुसार लोकतंत्र और समाजवाद के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं है। उन्होंने डा0 लोहिया के विचार से सहमति रखते हुए कहा कि "समाजवाद न आने पर फासीवाद आयेगा या साम्यवाद अनेक विद्वानों ने सम्पूर्णानन्द के समाजवादी चिन्तन को वेदान्ती समाजवादी संज्ञा दी है।

अशोक मेहता ने सामाजिक लोकतंत्र और लोकतान्त्रिक समाजवाद को भारतीय समाजवाद का आधार बनाया। वे पूंजीवाद को एक बुराई के रुप में स्वीकार करते थें उनका आर्थिक चिन्तन काफी समृद्ध था। वे आर्थिक क्रान्ति के प्रवर्तक थे और उसे वे जीवन की पुर्नव्यवस्था की संज्ञा देते थे।

जय प्रकाश नारायण की मार्क्सवाद में पूर्ण आस्था थी। जे0 पी0 ने समाजवाद के सम्बन्ध में कहा था कि समाजवाद केवल एक रुप है, एक सिद्धान्त है और वह मार्क्सवाद है। जे0 पी0 के ऊपर गाँधी जी के व्यक्तिवाद का काफी प्रभाव पड़ा। जे0 पी0 ने वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता को स्वीकार्य करते हुए युवा वर्ग का आह्वान किया कि वह हरिजनों एवं भूमिहीनों को वर्ग के आधार पर संगठित करने का बीड़ा उठाये। इस विचार से यह ध्वनि निकलती है कि उनकी

विचारधारा एक नये दौर से गुजरी है। जय प्रकाश नारायण ने वर्गों के प्रादुर्भाव में सामाजिक विषमता को आर्थिक तत्व से संबद्ध किया है आर्थिक तत्व वर्ग अभ्युदय के लिए केवल पूर्ण रुपेण केवल उत्तरदायी नहीं हो सकता।

वर्ग अभ्युदय के सबंध में डॉ0 लोहिया एवं जे0 पी0 में काफी साम्यता है।जे0 पी0 गाँधी के मार्ग पर चलकर देश में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक-सांस्कृतिक परिवर्तन लाना चाहते थें। इसी कारण उन्होंने 'सम्पूर्ण क्रान्ति' का नारा दिया सम्पूर्ण क्रान्ति जे0 पी0 का अपना मौलिक विचार नहीं है, जे0 पी0 की सम्पूर्ण क्रान्ति में वे सभी पहलू शामिल है। जिसकी कल्पना डा0 लोहिया ने सप्तक्रान्ति के रुप में की थी।

इस देश में 1885 से लेकर देश के स्वतन्त्र होने से पूर्व तक कांग्रेस पार्टी का एक छात्र आधिपत्य था। उसी के नेतृत्व में इस मूल्क में कई आन्दोलनों का संचालन भी किया गया। जब कांग्रेस पार्टी में गाँधी, पटेल नेहरु तथा सुभाष चन्द्रबोस का पदार्पण हुआ। तब देश की स्थिति में भी काफी बदलाव आ गया था।

सन् 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा हिन्दू महासभा का गठन किया गया। लेकिन इसमें सभी लोगों एवं संगठनों का अपनी-अपनी सोच एवं विचारधाराएं थीं लेकिन कहीं न कहीं 1848 के साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रभाव पड़ा। भारत में 1922 से 1939 तक समाजवादी अन्दोलन काफी तीव्र रहा है। इसके पीछे भी साम्यवादी धारणा काम कर रही थी।

कांग्रेस के अन्दर भी कई प्रकार के सोचवाले लोग मौजूद थे। किन्तु दक्षिणपंथी सोच हावी थी। इसी के परिणाम स्वरुप प्रगतिशील एवं समाजवादी नेताओं में अधिकारिक नेतृत्व दक्षिणपंथ की नीतियों एवं कार्यवाहियों के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया। सर्वप्रथम कांग्रेस की गैर प्रगतिशील एवं कठमुल्लावादी नीति के विरोध में बिहार में कुछ कांग्रेसियों ने 1931 में समाजवादी संघ की स्थापना कीं पुनः अखिल भारतीय स्तर पर समाजवादी दल बनायें समाजवादी विचार को आगे बढ़ाने के बारे में गतिविधियाँ तेज हो गयी। इसी का परिणम हुआ कि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेन्द्र देव जी की अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गयी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के निर्माण में जिन नेताओं का सक्रिय सहयोग रहा उसमें जय प्रकाश नारायण अशोक मेहता, आचार्य नरेन्द्र देव, डॉ0 राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, एम0 आर0 मसानी, एन0 जी0 गोरे, एस0 एम0 जोशी, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसूफ मेहर अली, गंगाशरण

सिंह तथा कमला चटोपाध्याय आदि थे। बाद में अन्य कांग्रेसी और अन्य विचारधारा से सम्बद्ध नेताओं ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। पं0 जवाहर लाल नेहरु और सुभाष चन्द्र बोस ने भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नीतियों का समर्थन करते थे, लेकिन इससे सक्रिय रुप से सम्बद्ध नहीं हो पाये थे। गाँधी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सदैव विरोधी रहे क्योंकि उनके लिए वर्ग संघर्ष सदैव असहमति का विषय ही बना रहा।

यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की इच्छा तो थी कि कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन आये। किन्तु उससे सम्बद्ध रहकर ही कांग्रेस समाजवादी अपनी गति विधियों को संचालित करना चाहते थे वे लोग कांग्रेस की बुनियादी नितियों को बनाये रखना चाहते थे, तथा कांग्रेस को समाजवादी मूल्यों से आबद्ध भी करना चाहते थे। कांग्रेस समाजवादी वैज्ञानिक समाजवाद के स्थान पर कांग्रेस की नीतियों में समाजवादी सुधार के लिए कृत संकल्प थे। पार्टी की नीतियाँ सदस्यों के पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। इसलिए पार्टी अन्त तक सार्वजनिक, शाश्वत, मौलिक व नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्धारण में असफल रहीं। प्रमुख रुप से जिन राजनीतिक विचारधाराओं का उसमें प्रतिनिधित्व था उसमें मार्क्सवादी और समाजवादी फेबियन विचारधारा, तथा उदारवादी समाजवादी विचारधारा थीं वे पार्टी के अन्दर अपनी-अपनी विचारधाराओं को स्थापित करना चाहते थे। और लगातार राजनीतिक मतभेद बने रहे। इसी मतभेद के चलते अशोक मेहता, डा0 लोहिया तथा अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं ने पार्टी की कार्यकारिणी से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान इन घटकों में इतने अधिक मतभेद बढ़ गये कि आगे एक साथ बने रहना असम्भव हो गया और अन्ततः सभी घटक बिखर गये।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी अस्तित्व 1934 से 1947 तक बना रहा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद के दृष्टिकोंण को अपनाने का प्रयास नहीं किया, व्यवहारिक रुप में तने बिल्कुल ही नही। युवा आन्दोलन के नेतृत्व पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना निश्चय ही वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होने कारण हुई और इस बात को हमेशा ध्यान में रखा गया कि कांग्रेस के बाहर उसका न तो कोई अस्तित्व है और न ही वह चेष्टा करेगी। जब तक पार्टी का अस्तित्व रहा वह किसी भी हालत में कांग्रेस को छोड़ने को तैयार नही थी। इसका परिणाम था पार्टी हर मोर्चे पर असफल रही। कांग्रेस

समाजवादी पार्टी की असफलता और पतन काफी सीमा तक वापपंथी दलों से उसके सबंधों के कारण भी हुई दक्षिणपंथी तत्व उसे सन्देह की दृष्टि से देखते थे तथा वामपंथी दल उसे वैज्ञानिक समाजवाद से अत्याधिक दूर मानते थे।

कांग्रेस संविधान संशोधन के बाद स्वतन्त्र कांग्रेस समाजवाद पार्टी का निर्माण हुआ। नासिक सम्मेलन 1949 में आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में हुआ। नासिक सम्मेलन में पार्टी के स्वरुप, संगठन और उसकी रीति-नीति के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

1952 में लोक सभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग स्वतंत्र रुपसे चुनाव लड़ी थी। 1952 के चुनाव में जनता में वामपंथी प्रवृत्ति को देखकर उन्होंने 1955 के समाजवादी सामाजिक ढांचे की चर्चा करना शुरु कर दिया था। संसद में भी एक प्रस्ताव पास समाजवाद के लक्ष्य को स्वीकार किया गया। और बाद में संविधान के प्रस्तावना में भी 'समाजवाद' शब्द को जोड़ा गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1955 में पारित प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के सहयोग के मुद्दे पर विचार उभर गया। इस हद तक गया कि अन्ततः पार्टी विभाजन के कगार पर पहुँच गयी। क्योंकि मधुलिमये डा0 मनोहर लोहिया तथा उनके सहयोगियों को पार्टी से निकाल दिया गया। इसलिए डा0 लोहिया ने दिस0 1955 में अलग से समाजवादी पार्टी की घोषण कर दी। परिणाम यह हुआ कि 1962 के आम चुनाव प्रजा समाजवादी पार्टी तथा समाजवादी पार्टी दोनों को नुकसान हुआ और आम जन मानस में एक गलत संदेश गया। इसमें दोनों ही पर्टियों ने अपनी कमजोरियों को चिन्हित किया।

डा0 लोहिया ने 1964 में पुनः अशोक मेहता के कांग्रेस में चले जाने के बाद समाजवादी एकता का प्रस्ताव रखा।इसके बाद संयुक्त समाजवादी दल का निर्माण हुआ। इसलिए समाजवादी आन्दोलन का दूसरा दौर 1964 से 1974 तक रहा और यह दौर घटना प्रधान भी रहा।

1974 के अगस्त महीने में चौ0 चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय लोकदल की स्थापना हुई। इसमें भारतीय क्रान्ति दल (बी0 के0 डी0), स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रीय लोक तान्त्रिक दल, संसोपा, उत्कल कांग्रेस, किसान मजदूर पार्टी, राष्ट्रीय लोक तान्त्रिकदल और पंजाब खेतिहर जमींदार सभा शामिल हुई।

इसके बाद समाजवादी आन्दोलन का अगला दौर 1974 से 1977 तक रहा। इसके अन्तर्गत इंदिरा गाँधी की कांग्रेस सरकार द्वारा पूरे देश में आपातकालीन स्थिति लागू कर दी गयी और विरोधी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बन्द कर दिया गया पुनः आपात कालीन समाप्ति के बाद 1977 में आम चुनाव की घोषणा कर दी गयी। कांग्रेस के विकल्प के रुप में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 के आम चुनाव में पूर्ण बहुमत भी मिला तथा जनता पार्टी की सरकार बन गयी। सरकार में कई विचारधारा के लोग शमिल थे। इस कारण ज्यादा दिनों तक यह सरकार नहीं चल पायी। इसके बाद जनता पार्टी सरकार में अन्तर्विरोध अधिक बढ़ गये तथा सरकार गिर गयी।

1980 के आम चुनाव में कांग्रेस (आई) कांग्रेस (यू) तथा लोकदल जिसे चरण सिंह तथा समाजवादियों ने खड़ा किया था। जनता पार्टी जिसमें मूलरुप से जनसंघ और जगजीवन राम एवं चन्द्रशेखर जैसे कुछ कांग्रेसी बचे हुए थे तथा सी0 पी0 आई0 और सी0 पी0 एम0। जनता पार्टी की शासन विहीनता, दूरदर्शिता का अभाव तथा लगातार चलने वाले आपसी झगड़ों से उबकर लोग एक बार फिर कांग्रेस की ओर इन्दिरा की तरफ देखने लगे।

31 अक्टूबर 1984 को इन्दिरा गाँधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गाँधी को प्रधानमंत्री बनाया गया तथा समय से पहले 24 से 27 दिसम्बर 1984 में आम चुनाव कराया गया। उसमें कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा बहुमत मिला।

1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। इस चुनाव में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रुप में उभर कर आयी। भाजपा तथा वापंथी पार्टियों ने राष्ट्रीय मोर्चा को बाहर से समर्थन की घोषणा की।इसके साथ ही साथ कई प्रान्तों में भी जनता दल की सरकार बनी। केन्द्र में ऐसे लोग भी शामिल थे जो आते महत्वाकांक्षी थे। इसमें अन्यदलों से आये लोग ही इस केन्द्र में थे तथा प्रभावी भी थें लेकिन यह सरकार भी अपने अन्तर्कलह से उबर नहीं पायी थी तथा मण्डल कमीशन लागू किये जाने के पर भाजपा अपना समर्थन वापस ले लिया तथा सरकार अल्पमत में आ गयी।

निष्कर्ष रुप में यह कहा जा सकता है कि 1934 से लेकर 1991 तक समाजवादी विचारधरा एवं आन्दोलन उतार-चढाव के दौर से गुजरा है। जिन समाजवादी अवधारणओं को

लेकर इसका गठन हुआ था, यह अपने मुकाम तक नहीं जा सका है। और सीधा-सीधा इसका कारण समाजवादियों का बिखराव रहा है।

1977 से 1990 का दौर दिशाहीन एवं नेतृत्व विहीन रहा है घटक दल के रुप मे जरुर अस्तित्व रहा है लेकिन विचारधारा एवं दिशा के स्तर पर लुप्त प्राय रहा है। जनता पार्टी के गठन के समय उसमें जब समाजवादी पार्टी अपने को विलीन कर दी कही न कही वह एक गलत फैसला था। क्योंकि व्यवहार में ये बात साबित हो चुकी हैं

वर्तमान स्थिति पर यदि दृष्टि डाली जाय तो अजीब स्थिति पैदा हो गयी है। बहुत से ऐसे दल हैं जो अपने को लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी होने का दावा तो करते है लेकिन व्यवहार मे कुछ अलग ही तथा केन्द्र और कई प्रदेशों में भाजपा के साथ मिलकर सरकार भी चला रहे हैं। जो कि विशुद्ध रुप से एक साम्प्रदायिक दल है। क्यों वह हमेशा विवादास्पद मुद्दों जैस धारा 370 की समाप्ति, कामन सिविल कोड, अयोध्या, मथुरा तथा काशी समेत कई मुद्दों को उठा रही है। 1992 के बाद से देश में साम्प्रदायकि माहौल बढ़ गया है लेकिन तथा कथित समाजवादी उन्ही ताकतों को मजबूत कर रहे हैं।

दूसरी और एक बार पुनः लगभग 18 साल की शून्यता के बाद श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में नवम्बर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। यह पार्टी डा0 राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेन्द्र देव तथा चौधरी चरण सिंह के सपनों को लेकर आगे बढ़ने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है। इस देश में एक बार पुनः समाजवादी मूल्यों को स्थापित करने तथा समाजवादी आन्दोलन का पुनर्गठन करने का प्रयास कर रही है। इस पार्टी की दिशा तो ठीक है किन्तु बहुत सी संभावनाए अभी भविष्य के गर्त में है। यदि इस पार्टी का नेतृत्व पिछले पचास वर्ष के समाजवादी आन्दोलन उसके संगठन कार्यशैली एवं बिखराव के कारणों का अध्यक्ष कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो पार्टी को मजबूती प्रदान होने की पूरा सम्भावनाएं है यदि ऐसा नही किया गया तो पिछले इतिहास के दौहराने की स्थितियां भी बलवान बनी रहेंगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

हिन्दी की पुस्तकें

क्रम	लेखक	पुस्तक का नाम	प्रकाशन
1.	डॉ0 राम मनोहर लोहिया	समाजवादी आन्दोलन का इतिहास	समता विद्यालय न्यास प्रकाशन, 1969
2.	वही,	समाजवादी एकता	समाजवादी प्रकाशन हैदराबाद
3.	वही,	क्रान्तिकरण लोहिया साहित्य, 17	नव हिन्द प्रकाशन हैदराबाद, 1967
4.	वही,	धर्म पर एक दृष्टि	वही, 1966
5.	वही,	भाषा	वही,1964
6.	वही,	कंचन मुक्ति	वही, 1956
7.	वही,	निजी और साहित्य क्षेत्र, 14	वही, 1966
8.	वही,	जाति प्रथा	वही, 1964
9.	वही,	समाजवाद की अर्थनीति	प्रथम संस्करण वही,1968
10.	वही,	समाजवादी एकता	लोहिया साहित्य,1
11.	वही,	हिन्दू और मुसलमान	समता विद्यालय न्यास प्रकाशन, 1964
12.	वही,	सिविल नाफरमानी सिद्धान्त और अमल	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी प्रकाशन, हैदराबाद, 1960
13.	वही,	सात क्रान्तियाँ, लोहिया साहित्य, 19	वही, 1966
14.	वही,	भारत-चीन व उत्तरी सीमाएँ	नव हिन्द प्रकाशन हैदराबाद, 1963
15.	ओम प्रकाश केलकर (सं0)	राम मनोहर लोहिया जीवन और दर्शन	चेतन साहित्य प्रकाशन, फैजाबाद, 1968
16.	डॉ0 एस0 एल0 वर्मा	राजनीतिक चिन्तन	मिनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1999
17.	हरिभाऊ उपाध्याय	गाँधीवादी समाजवाद	हिन्दी प्रकाशन, इलाहाबद, 1953
18.	बी0 बी0 रमन मूर्ति	गाँधी इसोन्शियल राइटिंगस	गॉधी पीठ फाउन्डेशन, नई दिल्ली, 1970

19.	सी0 ई0 एम0 जोड़	आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त प्रवेशिका (सं0 अम्बादत्त पंत)	आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई, कलक्ता, मद्रास-1957
20.	स्वामी दया नन्द सरस्वती	सत्यार्थ प्रकाश	सावर्देशिक प्रकाशन
21.	डा0 शोभाशंकर	आधुनिक भारतीय	लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली-1972
22.	पट्टाभि सीता रमैया	कांग्रेस का इतिहास, प्रथम तीन खण्ड	सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली-1946
23.	रामधारी सिंह 'दिनकर'	संस्कृत के चार अध्याय	लोक भारतीय प्रकाशन एम0 जी0 मार्ग, इलाहाबाद-1999
24.	रामवृक्ष वेनीपुरी	जय प्रकाश की विचारधारा	बेनीपुरी प्रकाशन, मुजफ्पुर, 1967
25.	आचार्य नरेन्द्र देव	राष्ट्रीयता और समाजवाद	प्रथम संस्करण सन् 1949, तृतीयज्ञान मंण्डल, वाराणसी ऋ 1973
26.	वही	समाजवाद का मूल आधार और कार्य	पद्या पब्लिकेशन, बम्बई, 1946
27.	इन्दुमति केलकर	लोहिया-सिद्धान्त और कर्म	नव हिन्द प्रकाशन हैदराबाद, 1963
28.	अध्यक्ष माओत्से तुंग की विचारोक्तिया		विचार प्रकाशन, कानपुर, 1967
29.	अध्यक्ष माओत्से तुंग	चुनी हुई कृतियाँ	चार खण्ड, विचार प्रकाशन, कानपुर, 1969
30.	ओंकार शरद	लोहिया	राजरंजना प्रकाशन इलाहाबाद, 1967
31.	ओंकार शरद (सं0)	लोहिया के विचार	लोकभारती, इलाहाबाद 1969
32.	कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक ऐंगेल्स	स्वतंत्रता संग्राम	नई दिल्ली, 1963
33.	कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक ऐंगेल्स	कम्यूनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	वही, 1974
34.	कार्ल मार्क्स	पूँजी, तीन खण्ड	प्रगति प्रकाशन, मास्को
35.	कोकर	आधुनिक राजनीतिक चिन्तन	आगरा, 1960

36.	गाँधी, मोहन दास करमचन्द	गाँधी-आत्मकथा	वही, 1970
37.	जवाहरलाल नेहरु	मेरी कहानी	सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली, 1965
38.	वहीं,	कुछ पुरानी चिटिठ्या	वही, 1960
39.	वही,	विश्व इतिहास की झलक, दो खण्ड	वही, 1974
40.	जय प्रकाश नारायण	जय प्रकाश नारायण के विचार (सं0)	लोकभारती, इलाहाबाद, 1977
41.	महादेव प्रसाद वर्मा	आधुनिक राजनीति के विभिन्न वाद	चैतन्य पब्लि0 हाउस, इलाहाबाद , 1965
42.	रजनी पामदत्त	आज का भारत	मैकमिलन, नई दिल्ली, 1977
43.	ब्ला0 ई0 लेनिन	संकलित रचनाएँ, चार खण्ड	प्रगति प्रकाशन, मास्को-1969
44.	वही	साम्राज्यवाद पूँजीवाद की चरम अवस्था	विदेशीप्रकाशन गृह, मास्को।
45.	वी0 अफनास्येव	मार्क्सवादी दर्शन	वही, 1972
46.	डॉ0 वि0 प्रसाद वर्मा	पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा का इतिहास	हिन्दी समिति लखनऊ, 1964
47.	शोभा शंकर	आधुनिक भारतीय समाजवादी चिन्तन	साहित्य भवन, इलाहाबाद, 1960
48.	सम्पूर्णानन्द	समाजवाद	भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता, 1964
49.	डॉ0 रघुवंश	"जय प्रकाश नारायण के विचार"	लोकतंत्र प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 1977
50.	प्रो0 यशपाल	"मार्क्सवाद"	विप्लव प्रकाशन, लखनऊ, 1976
51.	राय, डॉ0 सत्या एम0	"भारत में उपनिवेश वाद ' और राष्ट्रवाद"	हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली-2000

52.	डॉ0 आर0 पी0 त्रिपाठी	मुलायम सिंह यादव रचना और संघर्ष	प्रथम संस्करण 1993 डॉ0 लोहिया ट्रस्ट लखनऊ द्वारा प्रकाशित
53.	लक्ष्मी कांत वर्मा	समाजवादी आन्दोलन लोहिया के बाद	प्रकाशक, अतुल बगाई, निदेशक सूचना और जनसंचार विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश प्रथम संस्करण मार्च 1995
54.	रजनी कांत वर्मा	समाजवादी पार्टी ही क्यों	समाजवादी पार्टी के सिद्धान्त वक्तव्य एवं कार्यक्रम

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अंग्रजी की पुस्तके

क्रम	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम	प्रकाशन
1.	डॉ0 राम मनोहर लोहिया	आस्पेक्ट्स आफ सोशलिस्ट पार्टी	बम्बई, 6 टुलच रोड
2.	जय प्रकाश नारायण	सोशलिज्म, सर्वोदय एण्ड डेमोक्रेसी	एशिया पब्लि0, बम्बई, 1964
3.	वही,	टुवर्डस टोटल रेवोल्यूशन	पॉपुलर प्रकाशन पदमा पब्लिकेशन
4.	वही,	डेमोक्रेटिक सोशलिज्म	सोशलिस्ट पार्टी
5.	डॉ0 राम मनोहर	लोहिया मार्क्स, गाँधी एण्ड सोशलिज्म हैदराबाद,	नव हिन्द प्रकाशन हैदराबाद, 1933
6.	वही,	विल टू पावर एण्ड अदर राइटिंग्स	वही, 1956
7.	जय प्रकाश नारायण	टुवर्डस न्यू सोसाइटी	दि आफिस आफ इण्डियन अफेयर्स, दिल्ली, 1958
8.	वही,	टुवर्डस स्ट्रगल (स0 यूसूफ मेहर अली)	पदमा पब्लि0 बम्बई, 1946
9.	वही,	ह्वाई सोशलिज्म	अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, वाराणसी, 1936
10.	जी0 डी0 एच0 कोल	ए हिस्ट्री आफ सोशलिस्ट थाट 5 वल्यूम	लन्दन, 1953-57
11.	वही,	सोशल थ्योरी	न्यूयार्क, 1920
12.	वही,	सोशल थाट-दि फोर रनर्स फोर रनर्स	मैकमिलन, लन्दन, 1953
13.	जी0 एस0 भार्गव	लीडर्स आफ दि लेफ्ट	मेहरअली बुक क्लब, बम्बई, 1951
14.	एल0 पी0 सिन्हा	दि लेफ्ट विंग्स इन इण्डिया	न्यू पब्लि0 मुजफ्रपुर, 1965
15.	पं0 जवाहर लाल नेहरू	गिल्मिस ऑफ दि वर्ड हिस्ट्री	लंदन, लिन्डसे डूरुमंड ,1938
16.	वही,	एन् आटोबायोग्राफी	एलाइडष पब्लिशर्स, बम्बई, 1962
17.	वही,	दि यूनिटी आफ इण्डिया	लंदन, लिन्डसे डूरुमंड सोवियत रसिया, ला

			जनरल प्रेस इलाहाबाद
18.	वही,	नेहरु आन सोशलिज्म	पर्सपेक्टिव पब्लि0 1954
19.	जे0 बी0 कृपलानी	क्लास स्ट्रगल	काशी, ए0 बी0 एस0 एस0 एस0 प्रकाशन, 1959
20.	डोरोथी नार्मन (सं0)	नेहरु दि फस्ट सिक्सटी इयर्स	एशिया पब्लि0 बम्बई, 1965
21.	जी0 डी0 तेंदलुकर	महात्मा (गाँधी),8 खण्ड	बम्बई , 1961
22.	राय अखिलेन्द्र प्रसाद	सोशिलिस्ट थाट इन मार्डन इण्डिया	मिनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1975
23.	अशोक मेहता	डेमोक्रेटिक सोशलिज्म	भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1954
24.	वही,	इक्लोनामिक प्लानिंग इन इण्डिया	यंग इण्डिया, नई दिल्ली, 1970
25.	वही,	सोशलिज्म एण्ड गॉधीज्म	बम्बई, 1935
26.	दि सेमीनार आन सोशलिज्म (सं0)		नेहरु मेमोरियल लाइब्रेरी, नई दिल्ली, 1970
27.	दि कम्पलीट वर्क्स आफ स्वामी विवेकान्द, 8 व्ल्यूम		अल्मोड़ा, अद्वैत आश्रम
28.	नरेन्द्र देव	सोशलिज्म एण्ड दि नेशनल रेवोल्यूशन	पदमा पब्लि बम्बई, 1947
29.	वी0 डी0 कौशिक	दि कांग्रेस आइ डियोलोजी एण्ड प्रोग्राम	अलाइड पब्लिशर्स, बम्बई, 1964
30.	प्रेम भसीन	सोशलिज्म इन इण्डिया	यंग एशिया प0, नई दिल्ली, 1969
31.	वी0 आर0 पुरोहित	हिन्दू रिवाइवलिज्म	साथी, सागर
32.	बर्नाड शा	एसेज इन फेबियन सोशलिज्म	कान्सटेवन, लन्दन 1949
33.	भगवानदास	एन्सीएन्ट वर्सेज माडर्न साइन्टीफिक सोशलिज्म	मद्रास, 1910
34.	मधुलिमये	ह्वाई संयुक्त सोशलिस्ट	पॉपुलर प्रकाशन बम्बई
35.	मित्रा, एम0 एन0 (सं0)	इण्डियन एनुअल रजिस्टर (1919-1947)	कलकत्ता
36.	माइकेल ब्रेचर	नेहरु ए पोलिटिकल बायोग्राफी	आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, 1959

37.	सुभाष चन्द्र बोस	दि इण्डियन स्ट्रगल	एशिया पब्लि0 बम्बई, 1964
38.	एम0 एन0 मित्रा (सं0)	इण्डियन एनुअल रजिस्टर	कलकत्ता ,द एनुअल रजिस्टर आफिस
39.	वी0 पी0 वर्मा	पोलिटिकल फिलासफी आफ गाँधी एण्ड सर्वोदय	आगरा, 1981
40.	मीनू मसानी	दि कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया	डेरेक वर्सो, वायल लंदन, 1954
41.	जी0 एस0 भागर्व	लीडर्स आफ दि लेफ्ट	मैहर अली बुक क्लब बम्बई, 1951
42.	बनार्ड शा	एसेज इन फेबियन सोशलिस्ट	पॉपुलर प्रकाशन, नई कलकत्ता
43.	लेनिन	ए0 बायो ग्राफी	प्रगति प्रकाशन, मास्कों 1969
44.	वहीं,	मटीरियालिज्म एण्ड इम्पीरिओक्रटिसज्म	वही, पृष्ठ 1940
45.	लैडलर, हैरी	हिस्ट्री आफ सोशलिज्म	राउटलेज, 1968
46.	वी0 पी0 रमनमूर्ति (सं0)	इण्डियन एनुअल रजिस्टर (1919-1947)	कलक्ता
47.	शंकर घोष	सोशलिज्म एण्ड कम्मुनिज्म इन इण्डिया	कलक्त्ता, 1971 एलाइट पब्लि0
48.	वही,	सलेक्टैड वर्क्स आफ माओत्से तुंग	नवजातक, कलकत्ता, 1973
49.	एम0 गाँधी	कैपिटल एण्ड लेबर	भारतीय विद्याभवन बम्बई, 1970
50.	वही	रिकन्स्ट्रक्शन	वही, पृष्ठ 1956
51.	मधु दंडवते	एवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसीज एंड पर्स पेक्टिव 1934-1984	बम्बई, 1986
52.	हरि किशोर सिंह	ए हिस्ट्री ऑफ द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी	लखनऊ, 1959
53.	हेरी डब्ल्यू 0 लैडलर	हिस्ट्री आफ सोशलिज्म	स्लेज कीगेनपाल, लन्दन, 1961
54.	वही,	सोश एण्ड एक्नामिक मूवमेन्ट्स	
55.	लाल, मुकुट बिहारी	ब्लू प्रिन्ट आफ ए डेमोक्रेटिक प्रोग्राम	तारा प्रिटिंग वर्क्स, वाराणसी, 1965
56.	सम्पूर्णानन्द	दि टेन्टेटिव सोशलिस्ट प्रोग्राम फार इण्डिया	वाराणसी

57.	एलैक्जेण्डर ग्रे	दि सोशलिस्ट ट्रेडीशन	लॉगमेन्स एण्ड ग्रीन, लंदन, 1948
58.	निकाल्स नूगेंट	राजीव गॉधी सन आफ ए डाइनेस्टि	नई दिल्ली, 1991
59.	सीमा मुस्तफा	द लोनली प्रोफेट-वी0 पी0 सिंह, ए पोलीटिकल बायोग्राफी,	नई दिल्ली, 1995
60.	ज्यों द्रेजे एण्ड अमर्त्यसेन,	इण्डियाः इकोनामिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल अपार्चुनिटी	दिल्ली, 1996

हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ

1. यंग इण्डिया- 20-1-1920, 15-11-1927, 20-11-1929, 29-3-1927
2. हरिजन-29-6-1935, 28-8-1940, 13-7-1947, 26-1-1952, 25-1-1952, 20-12-1952
3. जन- दिसम्बर, 1967, प्रकाशक-गौड़ मुरो हरि, नई दिल्ली
4. जन- मार्च 1968 प्रकाशक-गौड़मुरो हरि, नई दिल्ली
5. जन -मई 1968 प्रकाशक-गोड़ मुरो हरि, नई दिल्ली
6. जनवाणी,आचार्य नरेन्द्र देव काशी विद्यापीठ, वाराणसी,
7. धर्मचुग 30 सितम्बर 1977 सम्पूर्ण क्रान्ति विशेषांक टाइम्स आफ इण्डिया नई दिल्ली
8. सम्पदा, समाजवाद अंक दिस0 1970, आशोक प्रकाशन मन्दिर दिल्ली
9. समाजवादी मेमार, 1956 नव हिन्द प्रकाशन, हैदराबाद
10. स्मारिका, चौथा राज्य सम्मेलन रीवा मध्यप्रदेश, समाजवाद पार्टी दिसम्बर 1970
11. सोवियद दर्पण (सम्पादक) अनोपी, बेनुण, सोवियत संघ प्रकाशन मई 1977
12. सोशलिस्ट पार्टी सिद्धान्त और कर्म, 1956, सोशलिस्ट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, हैदराबाद
13. समाजवादी बुलेटिन, संपादक (आलोक मेहता) लोहिया ट्रस्ट, लखनऊ दिसम्बर 2002

रिपोर्टस एण्ड डाक्युमेन्टस

1. आल इण्डिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, III कान्फ्रेंस, बम्बई, 1973
2. दि पालिसी "स्टेटमेन्ट आफ सोशलिस्ट पार्टी, कानुपर, 1947
3. आल इण्डिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कान्फ्रेंस, कानपुर, 1947
4. वही,I, नासिक, 1948
5. वही, II, पटना, 1949
6. वही, III, मद्रास, 1950
7. वही, विशेष कन्वेन्शन, पंचमढ़ी, 1952
8. वही, प्रजा शोसलिस्ट, पार्टी,I, कान्फ्रेंस, इलाहाबाद, 1953
9. वही, II, कांफ्रेंस, गया 1955
10. वही,III, कांफ्रेंस, बंगलोर, 1956
11. वही, I, पूना, 1958
12. वही, I, बम्बई, 1959
13. वही, I, कांफ्रेंस भोपाल, 1963
14. वही, II कांफ्रेंस, भोपाल, 1963
15. वही, III, कांफ्रेंस, वाराणसी, 1965
16. वही, IX, कांफ्रेंस, कानपुर, 1967-68
17. समाजवादी पार्टी का स्थापना सम्मेलन नव0 1992 लखनऊ
18. वही, द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन -अक्टू0 1994 लखनऊ
19. वही, तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन- जुलाई 1996 लखनऊ
20. वही, चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन- जनवरी, 1999 भोपाल
21. वही, पंचम राष्ट्रीय सम्मेलन- जनवरी, 2002, कानपुर